एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना

आर्थिक विकास

जून 2016

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना

(28 अप्रैल, 2016 को हुई एनसीआर योजना बोर्ड की योजना समिति की 65वीं बैठक में स्वीकृत)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार कोर-4 बी, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना

बीके त्रिपाठी आईएएस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
सदस्य सचिव

प्राक्कथन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भाग लेने वाले राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से की गई थी। एनसीआर एक अंतर-राज्यीय क्षेत्र की अनूठी व्यवस्था है और दुनिया में महानगरीय क्षेत्रीय विकास का एक मॉडल बन गया है। यह 62.2% के शहरीकरण लेबल के साथ दुनिया के सबसे बड़े बहु-राज्य, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में से एक है, जिसका 2021 तक 73.3% तक पहुंचने की उम्मीद है। एनसीआर 53,817 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है जिसमें एनसीटी-दिल्ली; हरियाणा उप क्षेत्र के 13 जिले; उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के 7 जिले और राजस्थान उपक्षेत्र के दो जिले शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूरे उत्तर भारत के लिए आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। लगातार बदलती वित्तीय/मौद्रिक नीति; आर्थिक विकास पर प्रभाव डालने वाले विधान; एक निश्चित क्षेत्रफल/क्षेत्र आदि रोजगार की स्थिति जैसी विभिन्न आर्थिक ताकतों के कारण एनसीआर की आर्थिक संरचना तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कुछ भौतिक/स्थानिक ताकतें हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो का केंद्रीय एनसीआर कस्बों तक विस्तार; दिल्ली को एनसीआर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे; एनसीटी-दिल्ली के आसपास परिधीय एक्सप्रेसवे; दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी); डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी); विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), औद्योगिक राज्यों/टाउनशिप आदि का विकास जिन्होंने एनसीआर की अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए, भौतिक और आर्थिक ताकतों के आलोक में एनसीआर के बदलते आर्थिक आधार का विश्लेषण और आकलन करना और उसके बाद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से विकास की भविष्य की दिशाओं को दिशा देने के लिए नीतियों और प्रस्तावों की सिफारिश करना अनिवार्य है।

जैसा कि (एनसीआरपीबी) अधिनियम 1985 द्वारा अनिवार्य है, एनसीआर योजना बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए क्षेत्रीय योजना- 2021 (आरपी 2021) तैयार करता है। आरपी-2021 निपटान प्रणाली, आर्थिक गतिविधियों, परिवहन, दूरसंचार, क्षेत्रीय भूमि उपयोग, बिजली और पानी, सामाजिक बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, विरासत और पर्यटन जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित एक अंतर-संबंधित नीतिगत ढांचा है।

क्षेत्रीय योजना मैक्रो स्तर पर एक व्यापक नीति दस्तावेज है। क्षेत्रीय योजना की नीतियों और प्रस्तावों को उप-क्षेत्रीय योजनाओं और मास्टर/विकास योजनाओं जैसे निचले पदानुक्रम योजनाओं में भाग लेने वाली एनसीआर की राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत किया जाना है। हालांकि, एनसीआर भाग लेने की स्थिति में सहायता के लिए, एनसीआर योजना बोर्ड ने मौजूदा स्थिति को व्यापक रूप से मूल्यांकन करने, मुद्दों/समस्या क्षेत्रों की पहचान करने और उसके बाद समग्र विकास के लिए रणनीतियों/सिफारिशों/कार्य योजना तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना

आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए, एनसीआर योजना बोर्ड ने "एनसीआर के अर्थशास्त्र प्रोफाइल का अध्ययन" किया, जिसे सभी भाग लेने वाले राज्यों और उनके विभाग/एजेंसियों, संबंधित मंत्रालय/केंद्र सरकार और अन्य एजेंसियों आदि के विभाग के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया था। उक्त अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों और मसौदा सिफारिशों पर भी सभी हितधारकों के साथ 8.5.2015 को आयोजित एक कार्यशाला में चर्चा की गई थी। इसके बाद, एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल के अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट भी सभी संबंधितों को दी गई थी।

एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल के अध्ययन के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर, एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए एक कार्यात्मक योजना का मसौदा तैयार किया गया था और इसे बोर्ड की वैधानिक योजना समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था। योजना समिति ने 28/4/2016 को आयोजित अपनी 65वीं बैठक में इस पर विचार किया और विस्तृत चर्चा के बाद उक्त कार्यात्मक योजना को मंजूरी दी गई।

एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना ने आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं/संकेतकों, जैसे सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय; कार्यबल वितरण; औद्योगिक विकास; ग्रामीण अर्थव्यवस्था; अनौपचारिक क्षेत्र; एनसीआर में शामिल राज्यों के नीतिगत ढांचा, आदि की बारीकी से जांच की है। कार्यात्मक योजना न केवल आर्थिक विकास के एक निश्चित संकेतक के विभिन्न श्रेणियों/क्षेत्रों के संदर्भ में गहन विश्लेषण प्रदान करती है, बल्कि इसमें उसका स्थानिक विश्लेषण भी शामिल है, जो उन स्थानों की पहचान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जो अधिकतम समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इसलिए इसमें ज्यादा हस्तक्षेप की जरुरत है।

एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए यह कार्यात्मक योजना क्लस्टर विशिष्ट, क्षेत्र विशिष्ट और उप-क्षेत्र और जिला विशिष्ट दोनों, विस्तृत मुद्दों और सिफारिशों के लिए प्रदान करती है। कार्यात्मक योजना किसी विशेष क्षेत्र/जिले/उप-क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की एक सूची भी प्रदान करती है। हालांकि, इन प्रस्तावों को वास्तविकता में बदलने के लिए, उन्हें भाग लेने वाले राज्यों और उनकी संबंधित एजेंसियों द्वारा विस्तृत तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता; उन्हें लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र; अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं आदि के साथ संमिलन के माध्यम से वित्त पोषण के स्रोत की पहचान करना के माध्यम से विस्तृत करना होगा। इसी तरह केंद्रीय मंत्रालयों को इस योजना को अपनी संबंधित योजनाओं के साथ एकीकृत करना होगा। मैं एनसीआर में भाग लेने वाले राज्यों से इस कार्यात्मक योजना को आधार के रूप में लेने और एनसीआर के संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशों को लागू करने का आग्रह करता हूं।

मैं एनसीआर योजना बोर्ड को "एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना" तैयार करने के प्रयास के लिए बधाई देता हूं, जो एक स्थायी तरीके से एनसीआर के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना

मुझे विश्वास है कि भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों और उनकी एजेंसियों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और लोगों के उत्साहजनक सहयोग से, यह कार्यात्मक योजना एनसीआर में आर्थिक विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देगी।

बीके त्रिपाठी
सदस्य सचिव
एनसीआर योजना बोर्ड

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

राजीव मल्होत्रा

सलाहकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

अभिस्वीकृति

आर्थिक विकास से संबंधित क्षेत्रीय योजना-2021 की व्यापक नीतियों और प्रस्तावों का विवरण देकर भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों के मार्गदर्शन के लिए एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। यह योजना व्यक्तियों और संस्थाओं के एक सदस्य के ठोस प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने योजना को सफलतापूर्वक तैयार करने और प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सबसे पहले मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव श्री बीके त्रिपाठी का आभारी हूं, जो इस कार्यात्मक योजना को तैयार करने के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति हैं। मैं उनका आभारी हूं कि उनके दृष्टिकोण, निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के बिना यह योजना पूरी नहीं हो सकती थी।

मैं केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और भाग लेने वाले एनसीआर राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों/विभागों द्वारा किये गए सच्चे सहयोग और निरंतर मदद को स्वीकार करता हूं। मैं एनसीआर के चार उप-क्षेत्रों के एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठों के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने समय पर ढंग से डेटा प्रदान करने के साथ-साथ अध्ययन में मूल्यवान इनपुट प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ कुशलतापूर्वक समन्वय किया है।

मैं सलाहकार, मैसर्स एपेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, के लिए ईमानदारी से सराहना करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से एनसीआरपीबी द्वारा एनसीआर की आर्थिक रूपरेखा का अध्ययन किया गया। उक्त अध्ययन के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर वर्तमान कार्यात्मक योजना तैयार की गई है।

अंत में, मैं एनसीआर योजना बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के ठोस प्रयासों को स्वीकार करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रयास को सफल बनाया है और जिसके परिणामस्वरूप एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना का प्रकाशन हुआ है। मैं एनसीआर योजना बोर्ड की टीम को धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से श्री जे.एन. बर्मन, सलाहकार, एनसीआरपीबी; और पूर्व निदेशक (तकनीकी), एनसीआरपीबी; सुश्री रुचि गुप्ता, संयुक्त निदेशक (तकनीकी), एनसीआरपीबी; और श्री पार्थ प्रतिम नाथ, उप निदेशक (तकनीकी) एनसीआरपीबी, जिनकी कड़ी मेहनत ने इस कार्यात्मक योजना की तैयारी को संभव बनाया है।

राजीव मल्होत्रा
सलाहकार, एनसीआर योजना बोर्ड
और पूर्व मुख्य क्षेत्रीय योजनाकार,
एनसीआर योजना बोर्ड

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

विषय-वस्तु

विषय-वस्तु....i

तालिकाओं की सूची.... vi

आंकड़ों की सूची....x

मानचित्रों की सूची....xiii

अनुबंधों की सूची....xiv

परिवर्णी शब्द और संक्षिप्ताक्षरों की सूची....xvi

कार्यकारी सारांश.... xviii

1. परिचय....1

1.1 पृष्ठभूमि....1

1.2 एनसीआर के लिए आर्थिक विकास के लिए एक कार्यात्मक योजना की आवश्यकता....1

1.3 उद्देश्य और दायरा....2

1.4 कार्यप्रणाली....2

1.5 डेटा सीमा....3

1.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)....3

1.7 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजनाएं....5

1.8 एनसीआर प्रोफाइल का सारांश....7

1.8.1 विकास अंतर....7

1.8.2 उद्योग....7

1.8.3 बंदोबस्त पैटर्न....7

1.8.4 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित बंदोबस्त पैटर्न....8

1.9 कार्यात्मक योजना का अध्यायीकरण....9

2. सकल घरेलू उत्पाद और आय विश्लेषण....10

2.1 पृष्ठभूमि.... 10

2.2 एनसीआर अर्थव्यवस्था के रुझान और संरचना.... 11

2.2.1 एनसीआर जीडीपी रुझान.... 11

2.2.2 एनसीआर में प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) रुझान.... 20

2.3 एनसीआर क्षेत्रवार रुझान.... 24

2.4 जीडीपी का अनुमान.... 29

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

3. कर्मचारी 33

3.1 पृष्ठभूमि 33

3.2 एनसीआर में श्रमिकों का वितरण 33

3.3 कर्मचारी भागीदारी दर 34

3.3.1 एनसीआर और उप-क्षेत्र स्तर पर कर्मचारी का श्रेणीवार वितरण 34

3.3.2 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कर्मचारी का वितरण 37

3.3.3 मुख्य, सीमांत और गैर-श्रमिकों का वितरण 38

3.3.4 एनसीआर में श्रमिकों का श्रेणीवार वितरण 43

3.3.5 क्षेत्र/जिलावार कर्मचारी 45

3.4 हरियाणा उप-क्षेत्र 46

3.4.1 2001 में हरियाणा उप-क्षेत्र में कर्मचारी का वितरण 46

3.4.2 हरियाणा उप-क्षेत्र में कर्मचारी और गैर-श्रमिक, 2011 52

3.4.3 हरियाणा उप-क्षेत्र में श्रमिक और गैर-श्रमिक, 2011 52

3.4.4 हरियाणा उप-क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या 55

3.5 राजस्थान उप-क्षेत्र 55

3.5.1 2001 में राजस्थान उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण 55

3.5.2 राजस्थान उप-क्षेत्र में श्रमिक और गैर-श्रमिक, 2011 57

3.5.3 राजस्थान उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण, 2011 58

3.6 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र 59

3.6.1 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण, 2001 59

3.6.2 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में कामगार और गैर-कामगार, 2011 62

3.6.3 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण, 2011 64

3.7 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र 65

3.7.1 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण, 2001 65

3.7.2 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में कामगार और गैर-कामगार, 2011 69

3.7.3 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण: 2011 71

3.8 2021 और 2031 के लिए रोजगार अनुमान 72

4. औद्योगिक विकास 74

4.1 पृष्ठभूमि 74

4.2 बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों का विविधीकरण और विकास के निर्धारक 76

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

4.2.1 एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र ... 77
4.2.2 हरियाणा उप-क्षेत्र ... 82
4.2.3 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र ... 88
4.2.4 राजस्थान उप-क्षेत्र ... 92
4.3 औद्योगिक समूह ... 98
4.3.1 पृष्ठभूमि ... 98
4.3.2 एनसीआर में समूह ... 100
4.4 महत्वपूर्ण समूह प्रोफाइल ... 102
4.4.1 विनिर्माण समूह प्रोफाइल ... 102
4.4.2 सेवा समूह प्रोफाइल ...
4.5 क्लस्टरों का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण ... 107
4.5.1 ऑटो और इंजीनियरिंग समूह ... 107
4.5.2 वस्त्र समूह ... 107
4.6 एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ... 108
5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ... 111
5.1 पृष्ठभूमि ... 111
5.2 एनसीआर में ग्रामीण कर्मचारी और व्यवसाय ... 112
5.3 ग्रामीण एनसीआर में मण्डी और विपणन अवसंरचना ... 117
5.4 एनसीआर में कृषि प्रसंस्करण उद्योग ... 119
5.4.1 एनसीआर में वर्तमान स्थिति ... 119
5.4.2 एनसीआर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए प्रमुख चुनौतियां ... 121
5.5 ग्रामीण एनसीआर में सरकारी कार्यक्रम ... 121
5.6 एनसीआर ग्रामीण अर्थव्यवस्था: प्रमुख मुद्दे ... 122
6. अनौपचारिक क्षेत्र ... 124
6.1 पृष्ठभूमि ... 124
6.2 अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा ... 125
6.3 अनौपचारिक क्षेत्र पर डेटा ... 126
6.4 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में असंगठित विनिर्माण और अनौपचारिक सेवा क्षेत्र……128
6.4.1 पृष्ठभूमि ... 126
6.4.2 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में असंगठित विनिर्माण क्षेत्र ... 128

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

6.4.3 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में अनौपचारिक सेवा क्षेत्र 129
6.5 अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यम और रोजगार 130
6.5.1 अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम 130
6.6 निष्कर्ष 133
7. नीति ढांचा 134
7.1 पृष्ठभूमि 134
7.2 भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 134
7.2.1 मेक इन इंडिया 134
7.2.2 स्किल इंडिया 135
7.2.3 डिजिटल इंडिया 136
7.3 एनसीआर और उप-क्षेत्रीय योजनाओं के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का नीतिगत ढांचा 136
7.3.1 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 137
7.3.2 उप-क्षेत्रीय योजनाएँ 142
7.4 उप-क्षेत्रों में आर्थिक विकास और प्रमुख परियोजनाओं के लिए एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की नीतियां 146
7.4.1 एनसीटी-दिल्ली 146
7.4.2 हरियाणा 148
7.4.3 उत्तर प्रदेश 159
7.4.4 राजस्थान 166
7.4.5 डीएमआईसी परियोजना के तहत जापान से निवेश के साथ प्रारंभिक पक्षी परियोजनाओं की सूची 169
7.5 एनसीआर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 171
7.6 निष्कर्ष 172
8. मुद्दे और सिफारिशें 173
8.1 प्रमुख मुद्दे - पृष्ठभूमि 173
8.2 मुद्दे 174
8.2.1 एनसीआर में आर्थिक विकास के स्तर में व्यापक बदलाव 174
8.2.2 कर्मचारी 174
8.2.3 औद्योगिक विकास 176
8.2.4 ग्रामीण अर्थव्यवस्था 177

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

8.2.5 अनौपचारिक क्षेत्र 178

8.2.6 जिला स्तर पर एकसमान जीडीपी डेटा 178

8.3 उप-क्षेत्रवार मुद्दे 178

8.3.1 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र 179

8.3.2 हरियाणा उप-क्षेत्र 179

8.3.3 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र 179

8.3.4 राजस्थान उप-क्षेत्र 180

8.4 नीति प्रतिक्रिया 180

8.4.1 पृष्ठभूमि 180

8.4.2 पर्यावरण प्रदूषण 180

8.4.3 उपठेकेदार और प्रमुख संबंधों की प्रकृति बदलना 180

8.4.4 नैनो प्रौद्योगिकी 181

8.4.5 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) 181

8.5 सिफारिशें 182

8.5.1 क्षेत्र विशेष की सिफारिशें 182

8.5.2 समूह विशेष अनुशंसाएं 167

8.6 उप-क्षेत्रवार सिफारिशें 184

8.6.1 हरियाणा उप-क्षेत्र 184

8.6.2 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र 186

8.6.3 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र 188

8.6.4 राजस्थान उप-क्षेत्र 188

8.7 एनसीआर में भारी, मध्यम और लघु उद्योग, बीपीओ, आईटी क्षेत्र, वाणिज्य के स्थान 189

8.8 थोक व्यापार का स्थान 197

8.9 सुझाई गई परियोजनाएं 198

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका सूची

तालिका 1-1: एनसीआर में जनसंख्या का उप-क्षेत्रवार वितरण....4

तालिका 1-2: एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित बस्तियों का छह स्तरीय पदानुक्रम....7

तालिका 1-3: एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 के अनुसार एनसीआर में प्रस्तावित मेट्रो और क्षेत्रीय केंद्र....7

तालिका 2-1: 2004-05 से 2009-10 तक एनसीआर का जिलावार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (2004-05 के स्थिर कीमतों पर) (रुपये मिलियन में)....12

तालिका 2-2: 2004-05 से 2009-10 तक (2004-05 के स्थिर कीमतों पर) एनसीआर के सकल घरेलू उत्पाद का उप-क्षेत्रवार एएजीआर (रुपये मिलियन में)....16

तालिका 2-4: 2004-2005 से 2009-10 तक (2004-05 के स्थिर कीमतों पर) हरियाणा उप-क्षेत्र की जीडीपी की जिलावार वार्षिक वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष)....17

तालिका 2-5: 2004-2005 से 2009-10 तक हरियाणा उप-क्षेत्र का जिला-वार सकल घरेलू उत्पाद (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) (मिलियन रुपये में)....18

तालिका 2-6: 2004- 2005 से 2009-10 तक (लगातार 2004-05 कीमतों पर) हरियाणा उप-क्षेत्र की जीडीपी की जिलावार वार्षिक वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष)....18

तालिका 2-7: 2004-05 से 2009-10 तक लगातार (2004-05) कीमतों पर एनसीआर की जिला और उप-क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय)....19

तालिका 2-8: प्रति व्यक्ति आय सीमा के सीएजीआर के साथ एनसीआर में जिलों के नाम और संख्या....20

तालिका 2-9: स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार योगदान (1999-2000) (रुपये मिलियन में)....23

तालिका 2-10: 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर....24

तालिका 2-11: 2001 से 2008 की अवधि के लिए एनसीआर के राजस्थान उप-क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर....25

तालिका 2-12: 2000-01 से 2007-08 की अवधि के लिए हरियाणा उप-क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर....26

तालिका 2-13: उत्तर प्रदेश की जीडीपी संरचना वर्ष 2008-09 के लिए स्थिर (2004-05) कीमतों पर उप-क्षेत्र (करोड़ में)....27

तालिका 2-14: 2000-01 से 2007-08 की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर....27

तालिका 2-15: 2009-10 के लिए एनसीआर का सकल घरेलू उत्पाद और 2021 और 2031 के लिए स्थिर (2004-05) कीमतों पर अनुमानित जीडीपी -....30

तालिका 3-1: 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमिकों की कुल संख्या में एनसीआर का भाग

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

…………………………………………………………………………….32

तालिका 3-2: एनसीआर में श्रमिकों की कुल संख्या में उप-क्षेत्रों का हिस्सा 33

तालिका 3-3: एनसीआर की कर्मचारी भागीदारी दर, 1971-2011 33

तालिका 3-4: एनसीआर और उप-क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या: 2011 33

तालिका 3-5: एनसीआर में मुख्य कर्मचारी का वितरण (1971, 1991 और 2001) 34

तालिका 3-6: एनसीआर और उप-क्षेत्रों में मुख्य श्रमिकों का वितरण: 2001 36

तालिका 3-7: 2011 में उप-क्षेत्रवार ग्रामीण और शहरी कर्मचारी भागीदारी दर 38

तालिका 3-8: एनसीआर में जिलेवार कर्मचारी की भागीदारी दर: 2011 38

तालिका 3-9: उप-क्षेत्रवार श्रमिक वार एनसीआर में श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा: 2011 42

तालिका 3-10: 2001 में श्रेणीवार कुल श्रमिकों का वितरण 43

तालिका 3-11: 2001 की जनगणना के अनुसार कुल कर्मचारी का क्षेत्रवार विवरण 46

तालिका 3-12: हरियाणा उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण (1971, 1991 और 2001)……………………….47

तालिका 3-13: 2001 में हरियाणा उप-क्षेत्र में मुख्य श्रमिकों की जिलेवार व्यावसायिक प्रोफ़ाइल………………..49

तालिका 3-14: हरियाणा उप-क्षेत्र में जिलेवार श्रमिक और गैर-श्रमिक: 2011 52

तालिका 3-15: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कर्मचारी का प्रतिशत वितरण 54

तालिका 3-16: राजस्थान उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण (1971, 1991 और 2001)……………………..54

तालिका 3-17: राजस्थान उप-क्षेत्र में श्रमिक और गैर-श्रमिक, 2011 56

तालिका 3-18: एनसीटी-दिल्ली में श्रेणीवार मुख्य श्रमिक, 2001 57

तालिका 3-19: दिल्ली उप-क्षेत्र में जिलेवार श्रमिक और गैर-श्रमिक, 2011 60

तालिका 3-20: उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण (1971, 1991 और 2001) 62

तालिका 3-21: उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र 2001 में जिला स्तर पर श्रेणीवार कर्मचारी का वितरण 63

तालिका 3-22: उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र, 2011 में जिलेवार श्रमिक और गैर श्रमिक 66

तालिका 3-23: 2021 और 2031 के लिए कार्य के अनुसार रोजगार का अनुमान 68

तालिका 3-24: 2001 से 2021 और 2031 तक कार्य के अनुसार कर्मचारी की वृद्धि 69

तालिका 4-1: एनसीआर में परिचालन SEZs की सूची (5 दिसंबर, 2014 तक) 70

तालिका 4-2: एनसीआर में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां, रोजगार और निवेश (2010-11)……………………. 72

तालिका 4-3: एनसीटी-दिल्ली में कार्यरत कारखानों की संख्या: 2008 74

तालिका 4-4: एनसीटी-दिल्ली में कारखानों में कार्यरत श्रमिक: 2008 76

तालिका 4-5: 2010-11 में हरियाणा उप-क्षेत्र में जिलेवार पंजीकृत फैक्ट्रियां 78

तालिका 4-

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

6: हरियाणा उप-क्षेत्र में 2004-05 से 2010-11 के बीच पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की वृद्धि 79

तालिका 4-7: 2008-09 में हरियाणा उप-क्षेत्र में पंजीकृत उद्योग.. 80

तालिका 4-8: हरियाणा उप-क्षेत्र में 2004-05 से 2010-11 के बीच पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की वृद्धि………81

तालिका 4-9: 2010-11 में औद्योगिक उत्पादन क्षमता या इकाइयों की संख्या और रोजगार का जिलेवार हिस्सा 84

तालिका 4-10: अलवर जिले में रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र-2010 86

तालिका 4-11: राजस्थान उप-क्षेत्र में भिवाड़ी, कुशखेड़ा और चौपांकी में श्रेणीवार इकाइयों की संख्या 87

तालिका 4-12: अलवर जिले में 2010-11 में एमएसएमई में औद्योगिक इकाइयों की प्रकार-वार संख्या, निवेश और रोजगार 88

तालिका 4-13: एनसीआर में औद्योगिक समूह.. 92

तालिका 4-14: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण.. 99

तालिका 4-15: एनसीआर में एसएसआई और बड़ी और मध्यम इकाइयों की संख्या: मार्च 2011 100

Tतालिका 5-1: 2011 में ग्रामीण जनसंख्या और कर्मचारी..102

तालिका 5-2: एनसीआर उप-क्षेत्रों में ग्रामीण कर्मचारी का वितरण 103

तालिका 5-3: एनसीआर में ग्रामीण कर्मचारी का वितरण (1971, 1991 और 2001) 104

तालिका 5-4: ग्रामीण एनसीआर में गैर-कृषि रोजगार: 2005 105

तालिका 5-5: एलक्यू एनसीआर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार द्वारा व्यक्तियों की संख्या-2005.............106

तालिका 5-6: एनसीआर-2010 में जिलेवार प्रमुख ग्रामीण बाजार, उप-यार्ड और कोल्ड स्टोरेज………..........107

तालिका 5-7: एनसीआर में जिलेवार/उप-क्षेत्रवार मंडियां: 2010 108

तालिका 5-8: कृषि प्रसंस्करण के जिलेवार प्रमुख क्षेत्र...109

तालिका 5-9: आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम .111

तालिका 5-10: एनसीआर के जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में 2011-12 के दौरान किए गए व्यय की स्थिति (करोड़ रुपये में) 111

तालिका 6-1: अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का अनुमान...114

तालिका 6-2: एनसीटी-दिल्ली में असंगठित विनिर्माण उद्यम 117

तालिका 6-3: दिल्ली में अनौपचारिक सेवा क्षेत्र...118

तालिका 6-4: सेवा क्षेत्र में उद्यमों का श्रेणीवार वितरण 118

तालिका 6-5: एनसीआर-2005 में प्रकार के अनुसार उद्यमों की संख्या...119

तालिका 6-6: कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में रोजगार 121

तालिका 7-1: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिसूचित निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 152

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 7-2: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कार्यात्मक एनईपीजेड........152

तालिका 7-3: अप्रैल 2000 से मार्च 2015 तक एनसीआर में एफडीआई अंतर्वाह........156

तालिका 8-1: एलक्यू जीडीपी 2000-01 और 2005-06........159

तालिका 8-2: खेती में लगे श्रमिक (खेती करने वाले और कृषि मजदूर)........161

तालिका 8-3: महत्वपूर्ण मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक केंद्र........176

तालिका 8-4: थोक व्यापार के लिए प्रस्तावित स्थान........179

तालिका 8-5: एनसीआर में प्रस्तावित औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं........180

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

आंकड़ों की सूची

चित्र 2.1: एनसीआर का उप-क्षेत्रवार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (2004-05 की कीमतों पर लगातार) (मिलियन रुपये में) 12

चित्र 2.2: एनसीआर और भारत के 2005-06 से 2009-10 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि दर (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) 13

चित्र 2.3: 2004-05 से 2009-10 तक एनसीआर के सकल घरेलू उत्पाद का एएजीआर (लगातार 2004-05 कीमतों पर) 13

चित्र 2.4: 2005-06 से 2009-10 के दौरान यूपी राज्य और एनसीआर के यूपी उप-क्षेत्र के बीच लगातार (2004-05) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि दर 14

चित्र 2.5: 2005-06 से 2009-10 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि दर एनसीआर के राजस्थान और राजस्थान उप-क्षेत्र 15

चित्र 2.6: 2005-06 से 2009-10 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि दर एनसीआर के हरियाणा और हरियाणा उप-क्षेत्र (2004-05 की कीमतों पर) 15

चित्र 2.7: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 2005-06 से 2009-10 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) 16

चित्र 2.8: 2004-2005 से 2009-10 तक (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र का जिला-वार सकल घरेलू उत्पाद लाख रुपए में 17

चित्र 2.9: 2004-05 से 2009-10 तक हरियाणा उप-क्षेत्र (लगातार 2004-05 कीमतों पर) का जिला-वार सकल घरेलू उत्पाद लाख रुपए में 18

चित्र 2.10: 2004-05 से 2009-10 तक लगातार 2004-05 कीमतों पर एनसीआर की उप-क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय 20

चित्र 2.11: 2004-05 से 2009-10 तक लगातार 2004-05 कीमतों पर एनसीआर की उप-क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय 21

चित्र 2.12: उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के लिए 2004-05 से 2009-10 तक लगातार 2004-05 कीमतों पर जिलेवार प्रति व्यक्ति आय रुपये में 22

चित्र 2.13: 2004-05 से 2009-10 के समय में हरियाणा उप-क्षेत्र के लिए लगातार (2004-05) कीमतों पर जिलेवार प्रति व्यक्ति आय रुपये में 22

चित्र 2.14: 2007-08 में एनसीआर क्षेत्रीय-जीडीपी 24

चित्र 2.15: 2009-10 के लिए एनसीटी दिल्ली में सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रीय संघटन 25

चित्र 2.16: एनसीआर के राजस्थान उप-क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रीय संरचना 26

चित्र 2.17: 2007-08 में एनसीआर के हरियाणा उप-क्षेत्र में जीडीपी की क्षेत्रीय संरचना.........27

चित्र 2.18: वर्ष 2008-09 के लिए स्थिर (2004-05) कीमतों पर उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के जीडीपी की क्षेत्रीय संरचना 28

चित्र 3.1: 2001 में एनसीआर में कर्मचारी का वितरण 37

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 3.2: 2011 में एनसीआर में कुल कर्मचारी में मुख्य और सीमांत श्रमिकों का उप-क्षेत्रवार हिस्सा 39
चित्र 3.3: एनसीआर में मुख्य और सीमांत श्रमिकों का उप-क्षेत्रवार प्रतिशत हिस्सा 42
चित्र 3.4: 2001 में सभी रोजगार श्रेणियों में श्रमिकों का वितरण... 44
चित्र 3.5: 2001 में हरियाणा उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का श्रेणीवार वितरण 48
चित्र 3.6: हरियाणा उप-क्षेत्र में मुख्य श्रमिकों की जिलेवार व्यावसायिक प्रोफ़ाइल, 2001..................................51
चित्र 3.7: हरियाणा उप-क्षेत्र में कुल श्रमिकों की जिलेवार व्यावसायिक प्रोफ़ाइल: 2011.....................................52
चित्र 3.8: हरियाणा उप-क्षेत्र में श्रमिकों, गैर-श्रमिकों और जनसंख्या की जिलेवार संरचना, 2011 53
चित्र 3.9: 2001 में राजस्थान उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण 55
चित्र 3.10: राजस्थान उप-क्षेत्र में कुल श्रमिकों की व्यावसायिक प्रोफ़ाइल, 2011 56
चित्र 3.11: राजस्थान उप-क्षेत्र में कुल श्रमिक और गैर-श्रमिक: 2011 56
चित्र 3.12: 2001 में दिल्ली उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण 58
चित्र 3.13: एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र के विभिन्न जिलों में श्रेणीवार श्रमिकों का वितरण: 2001 59
चित्र 3.14: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल श्रमिकों, गैर-श्रमिकों और जनसंख्या की जिलेवार संरचना, 2011 61
चित्र 3.15: एनसीटी दिल्ली में कुल कर्मचारी की जिलेवार व्यावसायिक रूपरेखा, 2011 61
चित्र 3.16: 2001 में उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण.. 63
चित्र 3.17: 2001 में सभी श्रमिकों का श्रेणीवार जिलावार वितरण.. 65
चित्र 3.18: 2011 में एनसीआर के उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में श्रमिकों, गैर-श्रमिकों और जनसंख्या की जिलेवार संरचना 67
चित्र 3.19: 2011 में उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में कुल श्रमिकों की जिलेवार व्यावसायिक प्रोफ़ाइल 67
चित्र 4.1: 1981-2008 के दौरान एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में पंजीकृत कारखाने 73
चित्र 4.2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में माध्यमिक या विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (2004-05 की कीमतों पर) 2004-05 से 2009-10 तक (लाख रुपये में) 73
चित्र 4.3: एनसीटी-दिल्ली में कार्यरत कारखानों की संख्या: 2008 75
चित्र 4.4: एनसीटी-दिल्ली में कारखानों में कार्यरत श्रमिक: 2008.. 77
चित्र 4.5: 2010-11 में जिलेवार पंजीकृत कारखाने हरियाणा उप-क्षेत्र.. 78
चित्र 4.6: हरियाणा उप-क्षेत्र में 2004-05 से 2010-11 के बीच पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की वृद्धि............... 79
चित्र 4.7: 2010-11 में हरियाणा उप-क्षेत्र में पंजीकृत कारखानों में जिलेवार रोजगार.. 80
चित्र 4.8: 2008-09 में हरियाणा उप-क्षेत्र में पंजीकृत उद्योग.. 81
चित्र 4.9: 2003-04 से 2008-09 में हरियाणा उप-क्षेत्र में पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन
.... 82
चित्र 4.10: 2010-11 में उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में जिलेवार औद्योगिक इकाइयों की संख्या.................................... 83

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.11: 2005-06 में जिलेवार औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा.. 83

चित्र 4.12: 2010-11 में औद्योगिक उत्पादन क्षमता या इकाइयों की संख्या का जिलेवार हिस्सा 84

चित्र 4.13: 2010-11 में उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में जिलेवार औद्योगिक रोजगार... 85

चित्र 4.14: पंजीकृत उद्योग, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र 2005- 06 में उद्योगवार श्रमिक - 85

चित्र 4.15: 2010-11 में अलवर जिले में क्षेत्रवार मौजूदा एमएसएमई 89

चित्र 4.16: 2010-11 में अलवर जिले में एमएसएमई में औद्योगिक श्रमिकों का क्षेत्रवार रोजगार 89

चित्र 4.17: वर्ष 2010-11 के दौरान अलवर जिले में क्षेत्रवार निवेश रुपये लाख में... 90

चित्र 4.18: एनसीआर में समूहों की संख्या: 2010-11 92

चित्र 4.19: एनसीआर में औद्योगिक समूहों में रोजगार... 93

चित्र 5.1: 2011 में एनसीआर में ग्रामीण कर्मचारी वितरण...104

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मानचित्रों की सूची

मानचित्र 1.1: एनसीआर संघटक क्षेत्र.....5
मानचित्र 3.1: वर्ष 2011 में एनसीआर में जिलेवार श्रमिकों की भागीदारी दर.....40
मानचित्र 3.2: 2011 में एनसीआर में जिलेवार कर्मचारी संरचना.....41
मानचित्र 3.3: 2011 में चार श्रेणियों में एनसीआर में जिलेवार व्यावसायिक प्रोफाइल.....45
मानचित्र 7.1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नीति क्षेत्र.....127
मानचित्र 7.2: डीएमआईसी-हरियाणा में प्रस्तावित विकास नोड्स के लिए स्थान मानचित्र.....142
मानचित्र 7.3: केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर परियोजनाएं.....143
मानचित्र 7.4: डीएमआईसी - उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित विकास नोड के लिए स्थान मानचित्र.....148
मानचित्र 7.5: डीएमआईसी-राजस्थान में प्रस्तावित विकास नोड्स के लिए स्थान मानचित्र.....155
मानचित्र 8.1: जिलेवार आर्थिक केंद्र.....175

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक 1. 1: आर्थिक और विकास संकेतक और जीडीपी अनुमानों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तरीके. 185

अनुलग्नक 2. 1: 2013-14 में भारत के राज्यों और एनसीआर की जीडीपी....189

अनुलग्नक 2. 2: 2013-14 में भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय....190

अनुलग्नक 2. 3: 2004-05 से 2009-10 तक जीडीपी के सीएजीआर की गणना और 2011, 2016, 2021, 2026, 2031 के लिए जीडीपी का अनुमान....191

अनुलग्नक 2. 4: स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का क्षेत्रवार योगदान (रुपये लाखों में)....192

अनुबंध 2. 5: 1999-2000 में एनसीआर की जीडीपी लगातार कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये लाखों में 193

अनुलग्नक 2.6: 2000-01 में एनसीआर का जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये लाखों में. 194

अनुलग्नक 2.7: 2001-02 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये लाखों में 195

अनुलग्नक 2.8: 2002-03 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये लाखों में 196

अनुलग्नक 2.9: 2003-04 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये लाखों में 197

अनुलग्नक 2. 10: 2004-05 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये लाखों में 198

अनुलग्नक 2.11: 2005-06 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये लाखों में 199

अनुबंध 2.12: 2006-07 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये लाखों में 200

अनुलग्नक 2.13: 2007-08 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये लाखों में 201

अनुलग्नक 3. 1: 2001 में एनसीआर में कुल कर्मचारी का वितरण और भागीदारी दर....202

अनुलग्नक 3. 2: 2001 में एनसीआर में मुख्य कर्मचारी का वितरण और भागीदारी दर 204

अनुलग्नक 3. 3: 2001 में एनसीआर में सीमांत कर्मचारी का वितरण और भागीदारी दर....205

अनुलग्नक 3. 4: 2001 में एनसीआर में शहरी कर्मचारी का वितरण और भागीदारी दर....206

अनुलग्नक 3. 5: 2001 में नौ श्रेणियों में एनसीआर में ग्रामीण कर्मचारी का वितरण और भागीदारी दर 207

अनुलग्नक 3.6: 2011 में श्रमिकों का मुख्य और सीमांत के रूप में वितरण और गांव तथा शहर में अलग कर दिया गया है 208

अनुलग्नक 3. 7: 2011 में कुल कर्मचारी, जनसंख्या और ग्रामीण और शहरी में भागीदारी का वितरण 210

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

अनुलग्नक 3. 8: एनसीआर की जनसंख्या का अनुमान (रुपये लाख में)......212

अनुलग्नक 3. 9: वर्तमान भागीदारी दर (2001) के आधार पर एनसीआर में कर्मचारी (2021) का प्रक्षेपण......213

अनुलग्नक 3. 10: वर्तमान भागीदारी दर (2001) के आधार पर एनसीआर में कर्मचारी (2031) का प्रक्षेपण......214

अनुलग्नक 3. 11: एनसीआर में कर्मचारी का प्रक्षेपण (2021) (समायोजित भागीदारी दर)......215

अनुलग्नक 3. 12: एनसीआर में कर्मचारी का प्रक्षेपण (2031) (समायोजित भागीदारी दर)......216

अनुलग्नक 4. 1: एनसीआर में एसईजेड जहां एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक मंजूरी दी गई है 217

अनुलग्नक 4. 2: एनसीआर में औद्योगिक संपदा......220

अनुलग्नक 4. 3: एनसीआर में औद्योगिक समूहों की जिलेवार सूची......223

अनुलग्नक 6. 1: एनसीआर शहरी क्षेत्रों में प्रकार के अनुसार उद्यमों की संख्या - 2005......225

अनुलग्नक 6. 2: एनसीआर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार के अनुसार उद्यमों की संख्या-2005......226

अनुलग्नक 6. 3: एनसीआर शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों की संख्या -2005......227

अनुलग्नक 6. 4: एनसीआर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों की संख्या-2005......228

अनुलग्नक 6. 5: एनसीआर -2005 में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों की संख्या का हिस्सा......229

अनुलग्नक 8. 1: स्थान भागफल और वृद्धि दर 2000-01 से 2005-06......230

अनुलग्नक 8. 2: 2005-06 में एनसीआर में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों (1999-00) के प्राथमिक क्षेत्र का एलक्यू और 2000-01 से 2005-06 तक एलक्यू में परिवर्तन 231

अनुलग्नक 8. 3: 2005-06 में एनसीआर में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों (1999-00) के द्वितीयक क्षेत्र का एलक्यू और 2000-01 से 2005-06 तक एलक्यू में परिवर्तन......232

अनुलग्नक 8. 4: 2005-06 में एनसीआर में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों (1999-00) के तृतीयक क्षेत्र का एलक्यू और 2000-01 से 2005-06 तक एलक्यू में परिवर्तन......233

अनुलग्नक 8. 5: 2005 में एनसीआर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों का एलक्यू......234

अनुलग्नक 8. 6: 2005 में एनसीआर शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों का एलक्यू......235

अनुलग्नक 8. 7: 2005 में एनसीआर में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों का एलक्यू......236

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

परिवर्णी शब्द और संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एएसआई	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
बीपीओ	व्यापार प्रक्रिया बाहरी स्रोत से सेवाएँ प्राप्त करना
सीबीए	समूह आधारित दृष्टिकोण
सीएफसी	सामान्य सुविधा केंद्र
सीआरएम	ग्राहक संबंध प्रबंधन
डीसीबी	दिल्ली छावनी बोर्ड
डीडीए	दिल्ली विकास प्राधिकरण
डीडीपी	मरुस्थल विकास कार्यक्रम
डीएफसी	समर्पित फ्रेट कॉरिडोर
डीजीईटी	रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय
डीजीआईडी	दिल्ली सरकार उद्योग विभाग
डीएमई	निर्देशिका निर्माण उद्यम
डीएमआईसी	दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
डीआरडीबी	दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड
डीएससी	दादरी-सूरजपुर-छलेरा
डीएसआईआईडी सी	दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम
ईपीसीएच	हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद
ईआरपी	उदयम संसाधन योजना
एफसीए	फरीदाबाद परिसर प्रशासन
जीडीपी	सकल घरेलु उत्पाद
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीटीजेड	ड्यूश गेसेलशाफ्ट फ्यूर टेक्नीश ज़ुसामेनरबीट
एचएच	हाउस होल्ड उद्योग
एचएसआईआईडी सी	हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम
आई एंड एफ सी	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
आईएवाई	इंदिरा आवास योजना
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीआरवी	ग्रामीण गांवों का एकीकृत विकास
आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईटी	सूचान प्रौद्योगिकी
आईटीईएस	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं
आईडब्ल्यूडीपी	एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाएं
केएमपी	कुंडली-मानेसर-पलवल
एमसीडी	दिल्ली नगर निगम

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

एमएनसी	बहुराष्ट्रीय कंपनी
एमपीएलएडीएस	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
नैसकॉम	सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का राष्ट्रीय संघ
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीटी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनडीएमसी	नई दिल्ली नगर समिति
एनडीएमई	गैर निर्देशिका निर्माण उद्यम
एनईपीजेड	नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र

एनएनपी	सकल राष्ट्रीय उत्पाद
एनओआईडीए	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
नरेगा	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एनआरईजीएस	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
ओएएमईएस	खुद का निर्माण उद्यम
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
पीपीडीसी	प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
रीको	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम
आरएमएआई	भारत के ग्रामीण विपणन संघ
आरएसवीवाई	राष्ट्रीय सम विकास योजना
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसजीआरवाई	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एसजीएसवाई	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एसएमई	लघु मध्यम उद्यम
एसएसआई	लघु उद्योग
टीयूएफ	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूनिडो	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
यूपी	उत्तर प्रदेश
यूएसडी	यूनाइटेड स्टेट का डॉलर

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

कार्यपालक सारांश

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) पूरे उत्तर भारत के लिए आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। कई आर्थिक ताकतों जैसे आर्थिक/राजकोषीय नीति में बदलाव, कानून, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निजीकरण आदि के कारण एनसीआर की आर्थिक संरचना में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभाव एनसीआर की अर्थव्यवस्था को तेजी से आकार दे रहे हैं। कुछ अवसंरचना विकासात्मक बल हैं जिन्होंने एनसीआर की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है, जैसे दिल्ली मेट्रो का केंद्रीय एनसीआर शहरों तक विस्तार, दिल्ली को एनसीआर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण, आगामी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), औद्योगिक संपदा/टाउनशिप आदि का विकास। एनसीआर के लगातार बदलते आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, आर्थिक और ढांचागत ताकतों के आलोक में एनसीआर के बदलते आर्थिक आधार का विश्लेषण और आकलन करना और उसके बाद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से विकास की भविष्य की दिशाओं को दिशा देने के लिए नीतियों और प्रस्तावों की सिफारिश करना उचित है।

एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना का उद्देश्य उपर्युक्त आवश्यकता का जवाब देना है, जिसका समग्र उद्देश्य निर्णय निर्माताओं को स्थायी भविष्य के विकास के रुझान की पहचान करना और इनके लिए पर्याप्त योजना प्रतिक्रिया तैयार करना है।

उद्देश्य और कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना का उद्देश्य भाग लेने वाले राज्यों के मार्गदर्शन के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की व्यापक नीतियों और प्रस्तावों का विस्तार करना है। एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा सलाहकार के माध्यम से आयोजित एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल के अध्ययन के विश्लेषण और निष्कर्षों के आधार पर कार्यात्मक योजना तैयार की गई है।

एनसीआर की आर्थिक संरचना से संबंधित विभिन्न संकेतकों से संबंधित संक्षिप्त निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

- एनसीआर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2009-10 में स्थिर (2004-05) कीमतों पर भारत की जीडीपी रु. 45,160.70 बिलियन, जबकि इसी अवधि के लिए एनसीआर की जीडीपी रु 3,193.40 बिलियन, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% है।
- एनसीआर के भीतर, दिल्ली एनसीआर के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार सबसे बड़ा योगदानकर्ता (2004-05 से 2009-10 तक दर्ज 50% से अधिक) रहा है।
- हरियाणा उप-क्षेत्र ने उच्चतम औसत वार्षिक वृद्धि दर (12.40%) दर्ज की है, इसके बाद 2005-06 से

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

009-10 की अवधि में एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र (11.50%), राजस्थान उप-क्षेत्र (9.60%) और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (8.7%) है। जबकि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत 8.74% और एनसीआर का 11.20% था।

- यह देखा गया है कि 2009-10 के दौरान बागपत, झज्जर, मेवात, पलवल और रोहतक जिलों में जीडीपी के आंकड़े 50,000 मिलियन रुपये से नीचे दर्ज किए गए हैं।
- 2009-10 के दौरान, गौतमबुद्ध नगर (141,557 मिलियन रुपये) और गुड़गांव (269,906 मिलियन रुपये) जिलों ने उच्चतम जीडीपी दर्ज किया है, जबकि बागपत और मेवात जिलों ने क्रमशः उत्तर प्रदेश और हरियाणा उप-क्षेत्र में सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद दर्ज किया है। मेवात जिले ने एनसीआर के सभी जिलों में सबसे कम जीडीपी भी दर्ज किया है। इसके अलावा, बागपत और मेवात ने 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान लगातार सबसे कम जीडीपी आंकड़े दर्ज किए हैं।

प्रति व्यक्ति आय

- एनसीआर के विभिन्न उप-क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में व्यापक अंतर है। 2009-10 के दौरान एनसीआर औसत (59,264 रुपये) और राष्ट्रीय औसत (33,901 रुपये) के मुकाबलेएनसीटी-दिल्ली ने उच्चतम प्रति व्यक्ति आय (98,262 रुपये), इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र (74,457 रुपये), उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (35,036 रुपये) और राजस्थान उप-क्षेत्र (29,300 रुपये) दर्ज की।
- गुड़गांव जिले ने 2009-10 के दौरान एनसीआर में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय (2,29,208 रुपये) दर्ज की है, इसके बाद फरीदाबाद (106,896 रुपये), पानीपत (79,047 रुपये), गौतमबुद्ध नगर (71,961 रुपये) का स्थान है। गौरतलब है कि यूपी के सभी जिलों में गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर उप-क्षेत्र (बुलंदशहर: 23,909 रुपये, मेरठ: 25,536 रुपये, हापुड़ सहित गाजियाबाद: 26,426 रुपये और बागपत: 27,348 रुपये); राजस्थान उप-क्षेत्र का अलवर जिला (29,300 रुपये); और हरियाणा उप-क्षेत्र के मेवात जिले (27,327 रुपये) में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय से कम दर्ज की गई है।

क्षेत्रीय रुझान

- एनसीआर में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान घट रहा है। 2007-08 में, तृतीयक क्षेत्र का एनसीआर के जीडीपी में लगभग 67% हिस्सा था, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र (25%) और शेष प्राथमिक क्षेत्र (8%) का हिस्सा था। एनसीआर अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना में बदलाव के कारणों को एक तरफ तेजी से शहरीकरण और कृषि और संबंधित गतिविधियों में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; तो दूसरी ओर सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- गुड़गांव और गौतमबुद्ध नगर जिलों में उच्च प्रति व्यक्ति आय मुख्य रूप से आईटी और आईटीईएस के विकास के लिए जिम्मेदार हो सकती है, जबकि पानीपत जिला तेजी से एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में उभर रहा है। एनसीटी-दिल्ली विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए मुख्य केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों में कृषि का प्रभुत्व है, दूसरी ओर हरियाणा उप-क्षेत्र उद्योगों और सर्विस क्षेत्र के विकास का मिश्रण है।

कर्मचारी

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

- एनसीआर में 2011 में कुल 157.35 लाख श्रमिक दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सबसे अधिक संख्या में श्रमिक (43.07%) एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (36.77%), हरियाणा उप-क्षेत्र (28.29%) और राजस्थान उप-क्षेत्र (13.17%) में हैं।
- 2011 में, राजस्थान उप-क्षेत्र ने उच्चतम कर्मचारी भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) 46.50% दर्ज की है, जबकि अन्य सभी उप-क्षेत्रों में लगभग 33% डब्ल्यूपीआर दर्ज किया गया है। राजस्थान उप-क्षेत्र में उच्च डब्ल्यूपीआर को कृषि गतिविधियों में लगे श्रमिकों के उच्च अनुपात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- एनसीआर में (भारत की जनगणना 2001 में वर्गीकरण के अनुसार) काश्तकारों और खेतिहर मजदूरों ने कर्मचारी का सबसे बड़ा हिस्सा (25.53%) का गठन किया, इसके बाद निर्माण श्रमिकों (16%) का स्थान है। एनसीआर में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है और तृतीयक (सेवा) और द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 1971 में 44.3% से घटकर 2001 में 29.06% हो गया है, जबकि माध्यमिक क्षेत्र का हिस्सा 1971 में 18.98% से बढ़कर 2001 में 42.63% हो गया है। प्राथमिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात एनसीटी-दिल्ली में सबसे कम है। प्राथमिक क्षेत्र के भीतर, काश्तकारों और खेतिहर मजदूरों की हिस्सेदारी 1971 में 42.98% से घटकर 2001 में 25.53% हो गई, जबकि माध्यमिक क्षेत्र में निर्माण का हिस्सा 1971 में 2.77% से बढ़कर 2001 में 16.2% हो गया है।
- उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों की उच्चतम एकाग्रता दर्ज की गई है। 2001 में, एनसीआर, यूपी उप-क्षेत्र में कृषि गतिविधियों (खेती करने वाले और खेतिहर मजदूर) और पशुधन और वानिकी गतिविधियों में लगे कुल श्रमिकों में से 40.64% (खेती करने वाले और खेतिहर मजदूर) और 43.06% (पशुधन और वानिकी) दर्ज किए गए हैं। इन श्रेणियों में एनसीआर में यूपी के भीतर उप-क्षेत्र, बुलंदशहर जिले में सबसे अधिक हिस्सेदारी [40.44% (किसान और खेतिहर मजदूरों) में लगे श्रमिकों और 55.08% (पशुधन और वानिकी) गतिविधियों में यूपी उप-क्षेत्र] में दर्ज की गई है।
- सेवा में गुड़गांव जिले की कुल श्रमिक आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है; विनिर्माण में फरीदाबाद; और कृषि गतिविधियों में अलवर है।
- 2011 में, राजस्थान उप-क्षेत्र में सीमांत श्रमिकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक (30.97%) है, इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र (20.27%) और यूपी उप-क्षेत्र (19.88%), जबकि एनसीटी-दिल्ली में सबसे कम हिस्सा (5.01%) दर्ज किया है। 2011 में एनसीआर में सीमांत श्रमिकों के वितरण के मामले में, यूपी उप-क्षेत्र (एनसीआर में कुल सीमांत श्रमिकों का 37.91%) में सबसे अधिक एकाग्रता देखी गई है, इसके बाद हरियाणा (29.75%) और राजस्थान (21.16%) उप-क्षेत्र हैं, जबकि एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में सबसे कम एकाग्रता (11.18%) दर्ज की गई है। यूपी के भीतर उप-क्षेत्र, बुलंदशहर जिले में उच्चतम एकाग्रता (30.38%) दर्ज की गई है, इसके बाद गाजियाबाद में हापुड़ (28.22%) और मेरठ (21.06%) शामिल हैं।

औद्योगिक विकास

संगठित औद्योगिक क्षेत्र जिसमें एनसीआर में बड़ी और मध्यम इकाइयां और लघु उद्योग (एसएसआई) शामिल हैं, दोनों क्षैतिज (इकाइयों की संख्या) और लंबवत (विभिन्न उद्योगों की वृद्धि) दोनों विकसित हुए हैं। हरियाणा उप-क्षेत्र विनिर्माण उद्योगों के केंद्र के रूप में उभरा है। 2010-11 में, हरियाणा उप-क्षेत्र में कुल 60,674 नंबर दर्ज किए गए। पंजीकृत इकाइयों में कुल 5,94,467 कर्मचारी कार्यरत हैं। हरियाणा उप-क्षेत्र के भीतर, गुड़गांव जिले में इकाइयों के साथ-साथ रोजगार (22,491 इकाइयों में 3,29,340 श्रमिक) में सबसे अधिक एकाग्रता दर्ज की गई है, इसके बाद फरीदाबाद (17,291 इकाइयों में 1,04,452 श्रमिक) और सोनीपत (8,743 इकाइयों में 59,707 श्रमिक) हैं। इकाइयों की श्रेणी के संदर्भ में, 'पहनने के परिधान, ड्रेसिंग और फर की रंगाई' ने 2003-04 से 2008-09 के बीच

इकाइयों

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

की संख्या में उच्चतम (63.03%) वृद्धि दर्ज की है, इसके बाद 'खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ' (38.42%) है। यूपी उप-क्षेत्र ने 2010-11 में कुल 70,601 पंजीकृत इकाइयों में कार्यरत कुल 4,55,955 श्रमिकों को दर्ज किया गया है। विद्युत मशीनरी, धातु उत्पाद और पुर्जे, रासायनिक उत्पाद और पुर्जे, कपड़ा उत्पाद यूपी उप-क्षेत्र की प्रमुख इकाइयाँ हैं। हापुड़ सहित गाजियाबाद में इकाइयों के साथ-साथ रोजगार (45,282 इकाइयों में 2,26,824 श्रमिक) की उच्चतम एकाग्रता दर्ज की गई है, इसके बाद गौतमबुद्ध नगर (9,880 इकाइयों में 1,41,295 श्रमिक) हैं। गौतमबुद्ध नगर में उच्च रोजगार एकाग्रता को आईटी और आईटीईएस और आर एंड डी में इकाइयों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। राजस्थान उप-क्षेत्र के मामले में, 57,379 इकाइयों ने 2010-11 में प्रमुख समूहों में 15,06,572 श्रमिकों को रोजगार दिया, जिनमें ऑटो कंपोनेंट और कपड़ा इकाइयों का योगदान सबसे अधिक था।

एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में 8,219 औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कुल 3,78,361 कर्मचारी दर्ज किए गए हैं। 2011 के दौरान उच्च स्तर के रोजगार में योगदान देने वाली औद्योगिक इकाइयां कपड़ा उत्पाद (36%) हैं, इसके बाद धातु उत्पाद और मशीनरी के पुर्जे (19%) हैं। यह देखा गया है कि 2007 से 2011 की अवधि के दौरान, एनसीटी-दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों की संख्या के साथ-साथ रोजगार में धीमी दर से वृद्धि हुई है। यह एनसीटी-दिल्ली से विभिन्न प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने/स्थानांतरित करने से संबंधित 2005 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में हो सकता है। इसका कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने में इकाइयों की अक्षमता को भी माना जा सकता है। दिल्ली में कई औद्योगिक इकाइयां पड़ोसी राज्यों में चली गयी गई हैं। नियामक और प्रशासनिक हस्तक्षेप के अलावा, जिसने एनसीटी-दिल्ली में बड़े / मध्यम पैमाने के उद्योगों के विस्तार / विकास पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाया, एसएसआई और छोटे क्षेत्र में विनियमन और शक्तिशाली बाजार शक्तियों की कमी ने एक अहस्तक्षेप को जन्म दिया है। जिसके कारण विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में बहुत छोटे और छोटे उद्योगों का विकास हुआ।

प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर मेरठ (ऑटो पार्ट्स, पावर लूम और स्पोर्ट्स गुड्स), नोएडा (आईटी / आईटीईएस, रेडीमेड गारमेंट, जनरल इंजीनियरिंग, ऑटो), गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, एनसीटी-दिल्ली (ओखला रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर) में स्थित हैं। , गुड़गांव (आईटी / आईटीईएस, ऑटो कंपोनेंट), मानेसर, बावल, फरीदाबाद (सामान्य इंजीनियरिंग), कुंडली, मुरथल और पानीपत (टेक्सटाइल)। एनसीआर में 50 से अधिक औद्योगिक क्लस्टर हैं, इसके अलावा एनसीटी-दिल्ली में कई सूक्ष्म उद्यम एकाग्रता हैं। उपर्युक्त औद्योगिक समूहों में कार्यरत व्यक्तियों की अनुमानित संख्या लगभग 10,02,090 मिलियन रुपये के कुल कारोबार के साथ लगभग एक मिलियन है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण आबादी एनसीआर में कुल जनसंख्या का 37.41% है। राजस्थान उप-क्षेत्र में ग्रामीण आबादी का अनुपात सबसे अधिक (82.19%) है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्रों में भी, काफी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों (क्रमशः 56.73% और 51.71%) में रहती है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली में ग्रामीण जनसंख्या नगण्य (2.50%) है।

एनसीआर की कुल ग्रामीण आबादी में ग्रामीण कामगार 36.13 प्रतिशत (62.26 लाख) हैं, जिनमें से 58.41% खेती करने वाले और खेतिहर मजदूर (खेतीकर्ता: 39.87% और खेतिहर मजदूर: 18.54%) हैं। कर्मचारी वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण कर्मचारी का अनुपात राजस्थान उप-क्षेत्र (87.09%) में सबसे अधिक है, इसके बाद हरियाणा (57.10%), उत्तर प्रदेश (52.96%) और एनसीटी-दिल्ली (2.33%) उप-क्षेत्रों का स्थान है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

कर्मचारी में क्षेत्रवार वृद्धि के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 1971 से 2001 की अवधि के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात 44.3% से घटकर 37.29% हो गया, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात 18.98% से बढ़कर 34.35% हो गया। इसी अवधि में तृतीयक क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात 36.72 प्रतिशत से घटकर 28.37 प्रतिशत हो गया।

यह देखा गया है कि एनसीआर में ग्रामीण बुनियादी ढांचे, मार्केट यार्ड के मामले में, कोल्ड स्टोरेज की मांग में काफी कमी है। एनसीआर में 65 विनियमित बाजार, 74 सब यार्ड और 261 कोल्ड स्टोरेज हैं। एनसीआर के हरियाणा उप-क्षेत्र में सबसे अधिक विनियमित बाजार और यार्ड स्थित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में सबसे अधिक कोल्ड स्टोरेज दर्ज किए गए हैं, इसके बाद एनसीटी-दिल्ली का स्थान है। एनसीआर के सभी जिलों में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज मेरठ में हैं।

एनसीआर में 23 प्रमुख फल और सब्जी बाजार हैं। सबसे अधिक बाजार उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के बुलंदशहर जिले में हैं। चारा बाजार हरियाणा और एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्रों में बनाये गए हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र

एनसीआर स्तर पर, 2005 में 15.64 लाख अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम थे। कुल 8.30 लाख स्वयं के खाता उद्यम (ओएई) हैं, जिनमें से 0.58 लाख कृषि क्षेत्र में हैं और शेष 7.72 लाख गैर-कृषि क्षेत्रों में हैं।

उप-क्षेत्र स्तर पर, एनसीटी-दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों (7.58 लाख) की उच्चतम एकाग्रता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (3.96 लाख), हरियाणा (3.21 लाख) और राजस्थान उप-क्षेत्र में (0.89 लाख) है। क्षेत्र स्तर के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में, कुल उद्यमों का लगभग 99.47% (7,54,453) गैर-कृषि कार्यों में है, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान उप-क्षेत्रों में यह अनुपात क्रमश: 88.43% (3,50,200), 94.87% (3,04,660) और 90.42% (80,952) है।

एनसीटी-दिल्ली में, विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में लगभग 9.38% योगदान है, जिसमें से 7% असंगठित क्षेत्र द्वारा और 2.38% संगठित विनिर्माण क्षेत्र से आता है। 2006-2007 में एनएसएस सर्वेक्षण (62वें दौर) के अनुसार, असंगठित विनिर्माण उद्यमों की कुल संख्या लगभग 1 लाख थी। कुल उद्यमों में से, 20.30% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे, और 79.70% दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। असंगठित विनिर्माण उद्यमों की कुल संख्या में परिधान, ड्रेसिंग और रंगाई उद्यमों का योगदान 28.29% है, इसके बाद फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद इकाइयों का निर्माण (22.00%) और फर्नीचर निर्माण इकाइयों का (7.25%) है। एनएसएस के आंकड़ों (2005-06) के अनुसार, असंगठित विनिर्माण उद्यमों द्वारा सृजित कुल रोजगार लगभग 4.82 लाख था।

जिला स्तर पर, एनसीटी-दिल्ली के बाद, मेरठ में उद्यमों की अधिकतम (1.19 लाख) संख्या है, इसके बाद गाजियाबाद (1.18 लाख) का स्थान है। हरियाणा उप-क्षेत्र के झज्जर जिले में सबसे कम उद्यम (24,469) हैं। गौतमबुद्ध नगर में भी कृषि क्षेत्र (तालिका 6.5 देखें) में ओएई की संख्या सबसे अधिक है।

नीतिगत ढांचा

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी), ईस्टर्न (कुंडली-गाजियाबाद-पलवल) और वेस्टर्न (कुंडली-मानेसर-पलवल) पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसी क्षेत्रीय स्तर पर कुछ परियोजनाएं हैं, जो एनसीआर के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ चैनलाइज भी करेगा। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि का

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

एनसीआर के आर्थिक विकास के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

एनसीआर भाग लेने वाले राज्यों ने विभिन्न औद्योगिक, निवेश और स्थान विकास नीतियां भी तैयार की हैं। एनसीटी-दिल्ली नीतियां मुख्य रूप से कौशल आधारित उच्च तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि हरियाणा की नीतियां मुख्य रूप से पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करके विनिर्माण गतिविधियों के विकास के लिए एक उपयुक्त कारोबारी माहौल प्रदान करने पर केंद्रित हैं। हाल ही में, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के विकास सहित नई फर्मों के लिए कई प्रोत्साहन और प्रलोभन प्रदान करता है। राजस्थान सरकार नए उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास सहित वित्तीय और अन्य लाभ प्रदान करती है। लघु उद्योग विकास के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण सभी उप-क्षेत्रों के लिए समान है।

मुद्दे

- **एनसीआर में आर्थिक विकास के स्तर में व्यापक बदलाव:** एनसीआर के उप-क्षेत्रों में जीडीपी वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में असमानता में व्यापक भिन्नता है। हरियाणा उप-क्षेत्र एनसीआर में सबसे तेज दर से बढ़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों की विकास दर एनसीआर की तुलना में कम है। उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में हापुड़ और बागपत सहित बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद जिलों में माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में पर्याप्त हस्तक्षेप की कमी के कारण; हरियाणा उप-क्षेत्र में मेवात जिला; और राजस्थान उप-क्षेत्र के अलवर जिले में निम्न सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज की गई है। 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान बागपत और मेवात ने लगातार सबसे कम जीडीपी आंकड़े दर्ज किए हैं।

- **कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न रोजगार:** एनसीआर में प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में श्रमिकों का पर्याप्त हिस्सा लगा हुआ है। राजस्थान उप-क्षेत्र ने सबसे अधिक 77% हिस्सा दर्ज किया है, इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र में 52%, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में लगभग 48% है। इसके अलावा, राजस्थान उप-क्षेत्र (65.30%), हरियाणा उप-क्षेत्र (34.09%) और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (31.81%) में कृषि गतिविधियों (खेती करने वाले और खेतिहर मजदूरों) में लगे श्रमिकों का अनुपात महत्वपूर्ण है। यह माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों की तुलना में समग्र सकल घरेलू उत्पाद में कम योगदान देने के अलावा अपर्याप्त प्रति व्यक्ति आय के साथ-साथ उत्पादक पूर्णकालिक रोजगार की कमी की ओर जाता है।

- **मुख्य कर्मचारी का असमान वितरण:** कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का हिस्सा राजस्थान उप-क्षेत्र में सबसे अधिक है, इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र और यूपी उप-क्षेत्र में है। हालांकि, सीमांत श्रमिकों की एकाग्रता के मामले में, यूपी उप-क्षेत्र सबसे अधिक है, जिसमें हापुड़ और मेरठ सहित बुलंदशहर, गाजियाबाद जिलों में सीमांत श्रमिक ज्यादातर केंद्रित हैं।

- **औद्योगिक विकास:** एनसीआर के अधिकांश औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों में देखे गए प्रमुख मुद्दे अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता बिजली आपूर्ति सहित सामान्य सुविधा केंद्र हैं; प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रभावी उपचार और निपटान के बुनियादी ढांचे की कमी; तत्काल आसपास के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की सीमित उपलब्धता और कर्मचारी की सामान्य कमी; महत्वपूर्ण समर्थन प्रणाली की कमी जैसे कि सामान्य सुविधाओं के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यमों को फलना-फूलना मुश्किल हो जाता है; जो भूमि अधिग्रहण और भूमि की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे; और एसईजेड/ईपीजेड योजना के अनुसार विकसित करने में असमर्थ हैं।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

पानीपत, मेरठ, गाजियाबाद आदि जैसे पारंपरिक/पुराने औद्योगिक समूहों का अपर्याप्त/पुराना तकनीकी आधार उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपर्याप्त तकनीकी, वित्तीय, कौशल विकास और विपणन सहायता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह देखा गया है कि उद्यम निर्माण की वृद्धि दर, खासकर बुलंदशहर, झज्जर, अलवर और सोनीपत जैसे जिलों में तुलनात्मक रूप से धीमी है।

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था:** प्रमुख मुद्दा एनसीआर के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित गैर-कृषि क्षेत्र के रोजगार से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियों में लगे श्रमिकों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रमिकों की तुलना में नगण्य है। एक अन्य प्रमुख मुद्दा अपर्याप्त ग्रामीण बुनियादी ढांचा जैसे मंडी और विपणन सुविधाएं, सामान्य भंडारण और शीत भंडारण सुविधाएं और अपर्याप्त भोजन, फल और सब्जियां प्रसंस्करण सुविधाएं/उद्योग हैं।

- **अनौपचारिक क्षेत्र:** सूक्ष्म उद्यमों सहित अनौपचारिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्दा लगे हुए श्रमिकों के अपर्याप्त कौशल आधार से संबंधित है। साथ ही, स्ट्रीट वेंडिंग, जो अनौपचारिक गतिविधियों का एक प्रमुख घटक है, को उनकी आजीविका की निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक शहरी नियोजन तंत्र में एकीकृत करने की जरूरत है।

- **जिला स्तर पर एक समान जीडीपी डेटा:** एनसीआर में एक समान जिला स्तर के जीडीपी डेटा का अभाव तुलना और अनुकूलता में समस्या उत्पन्न करता है।

सिफारिशें

सामान्य:

- **एनसीआर में संतुलित आर्थिक विकास:** माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के विकास में हस्तक्षेप, विशेष रूप से उन जिलों में, जिन्होंने लगातार कम जीडीपी दर्ज की है, प्रति व्यक्ति आय, जैसे बागपत, मेवात, बुलंदशहर, आदि को भी जीडीपी में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार और इस तरह व्यापक असमानता को कम करने और एनसीआर के संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में योगदान देता है।

- **सीमांत श्रमिकों का रोजगार सृजन और मुख्यधारा:** गैर-कृषि गतिविधियों में श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, उप-क्षेत्रों में, विशेष रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, छोटे पैमाने का समर्थन करने के लिए एक सुविधाजनक कारोबारी माहौल बनाने की आवश्यकता है। उद्योग (एसएसआई), जिनमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। इन उप-क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रभावी रोजगार नीति तैयार करने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कौशल उन्नयन और पूर्णकालिक उत्पादक रोजगार प्रदान करके सीमांत श्रमिकों की मुख्यधारा को सुनिश्चित किया जाना है।

- **औद्योगिक विकास:** एनसीआर में औद्योगिक क्षेत्र के स्थिर और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक समूहों / क्षेत्रों में पर्याप्त और कुशल बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण तंत्र के साथ-साथ

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तकनीकी और कौशल उन्नयन का प्रावधान पूर्वापेक्षा है। 2000 से सेवा क्षेत्र पर एनसीआर में शामिल राज्यों द्वारा जोर दिया जा रहा है, इसके साथ ही, विनिर्माण क्षेत्र में उचित नीति संरचना और हस्तक्षेप विकसित करने की जरुरत है। बुलंदशहर, झज्जर, अलवर और सोनीपत जिलों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने की भी जरुरत है। यह अनुशंसा की जाती है कि विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में औद्योगिक गतिविधियों के लिए संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, विशेष रूप से कपड़ा, ऑटो घटक, सामान्य इंजीनियरिंग, खेल के सामान आदि में अपनाया जाना चाहिए। सभी एमएसएमई में अनौपचारिक कर्मचारी के लिए क्लस्टरों की सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) तक पहुंच होनी चाहिए। पानीपत, मेरठ, गाजियाबाद आदि जैसे पारंपरिक/पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्जीवित करने के लिए तकनीकी और कौशल उन्नयन उपायों सहित कठोर और नरम उपायों के संयोजन की सिफारिश की जाती है।

विशेष रूप से तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में आर्थिक विकास में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। वर्तमान में, एनसीआर के कुछ हिस्सों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए एक अच्छा आधार है, उदाहरण के लिए राय (सोनीपत), रोहतक और ग्रेटर नोएडा में ज्ञान और नवाचार केंद्र। हालांकि, यह सिफारिस की जाती है कि एनसीआर में ऐसे और केंद्र स्थापित किए जाएं।

- **क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा विकास:** पूर्वी और पश्चिमी (केएमपी) पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी), इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स (आईएफसी), एक्सप्रेसवे, रेलवे आदि सहित प्रस्तावित अतिरिक्त परिवहन संपर्क जैसी क्षेत्रीय अवसंरचना और एनसीआर में औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए मौजूद औद्योगिक संवर्धन को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है, खासकर मेवात, बागपत, अलवर, झज्जर, रेवाड़ी आदि जैसे क्षेत्रों में जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं।

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था:** यह सिफारिस की जाती है कि एनसीआर के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए मूल्य वर्धित ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कोल्ड स्टोरेज, कॉमन स्टोरेज, मंडियों आदि को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाए।

क्षेत्र-विशिष्ट सिफारिशें::

- कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग:
  - हरियाणा उप-क्षेत्र में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना
    o बागवानी उपज के लिए यूपी उप-क्षेत्र के बुलंदशहर जिले और हरियाणा उप-क्षेत्र में झज्जर जिले में फल और सब्जी प्रसंस्करण पार्क की स्थापना।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी**
  - यह सिफारिस की जाती है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित एसईजेड के संचालन के लिए उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप किए जाएं।
  - एनसीटी-दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में सॉफ्टवेयर विकास (विशेषकर एनसीटी-दिल्ली के मामले में गहनता की आवश्यकता है)।
- **ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स**
  - कुशल कर्मचारी और बुनियादी ढांचे जैसे श्रमिकों के छात्रावास आदि के प्रावधान सहित ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट्स के लिए आईएमटी मानेसर और बावल में प्रेरित क्लस्टर।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

- ऑटो-पार्क (जैसे अलवर में आगामी ऑटो-पार्क) और अनुसंधान संस्थानों (जैसे हरियाणा में आगामी राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण, अनुसंधान और विकास बुनियादी ढांचा परियोजना) के लिए स्थापित किए जाने वाले फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज सहित सहायता बुनियादी ढांचे का पर्याप्त स्तर।
- फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, मेरठ और अलवर के लिए ऑटो कंपोनेंट उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा सहयोग।

- **हथकरघा, होजरी, कपड़ा और वस्त्र निर्माण**
  - भारत सरकार की निर्यात योजना के लिए परिधान पार्क के तहत गुड़गांव एसईजेड और बरही (सोनीपत) में परिधान पार्क।
  - पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन सेंटर।
  - वस्त्रों के प्रचार के लिए गुड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र।
  - अलवर जिले में टेक्सटाइल पार्क।
  - फरीदाबाद और गाजियाबाद जिलों में रंगाई घर।
  - ओखला में वस्त्र कौशल विकास केंद्र।
- **जूते, चमड़े के वस्त्र और सहायक उपकरण**
  - हरियाणा के बहादुरगढ़ में चमड़ा विकास के लिए बुनियादी ढांचा।
- **सामान्य इंजीनियरिंग**
  - फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव में मौजूदा सामान्य इंजीनियरिंग समूहों/क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।
- **लॉजिस्टिक्स**
  - डीएफसी और डीएमआईसी परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्रों का हिस्सा शामिल है, यह सिफारिस की जाती है कि इन उप-क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स (आईएफसी) जैसे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाएंगे।

क्लस्टर विशिष्ट सिफारिशें

- **ऑटो-कंपोनेंट (मेरठ, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा):** उन्नत उपकरणों की शुरूआत, शॉप फ्लोर प्रथाओं के सुधार, गुणवत्ता प्रणालियों को शामिल करने और सूक्ष्म या लघु इकाइयों के लिए,जहां पूर्ण स्वचालन नहीं किया गया है वहां मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी उन्नयन की एक मजबूत आवश्यकता है।
- **हथकरघा और पावरलूम (पानीपत और मेरठ):** यह सिफारिस की जाती है कि डिजाइन इनपुट, श्रमिकों के कौशल उन्नयन और बेहतर रंगाई प्रथाओं में हस्तक्षेप निरंतर तरीके से किया जाए। साथ ही, इन क्लस्टरों के लिए प्रत्यक्ष बाजार संपर्क स्थापित करने की सिफारिश की गई है।
- **खेल के सामान (मेरठ):** क्लस्टर में विनिर्मित वस्तुओं के मौजूदा सेट के भीतर तकनीकी उन्नयन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि और प्रोत्साहन के साथ-साथ नए खेल क्षेत्रों में विविधता लाने की अपार संभावनाएं हैं।
- **कपड़ा (ओखला, गुड़गांव):** गुणवत्ता में सुधार, तकनीकी उन्नयन, कौशल वृद्धि और उद्यमियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की गई है। यह भी सिफारिस की जाती है कि सॉफ्ट गतिविधियों जैसे कटिंग रूम लेआउट और वर्कफ़्लो; अनुत्पादक निर्माण; कर्मचारी प्रशिक्षण; और उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से उत्पादन में सुधार किया जाना चाहिए।
- **सामान्य इंजीनियरिंग (फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव):** यह सिफारिस की जाती है कि इकाइयों को पर्याप्त सहायता दिया जाए, जो कि ज्यादातर एमएसएमई प्रकृति में हैं, विशेष रूप से विपणन पहल, प्रौद्योगिकी

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

और कच्चे माल की उपलब्धता के क्षेत्रों में।

उप-क्षेत्रवार सिफारिशें::

एनसीटी-दिल्ली

- सॉफ्टवेयर, बीपीओ, संचार और जैव प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख मूल्यवर्धित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां।
- औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा (सड़कें, पानी, स्वच्छता आदि)।
- क्लस्टर आधारित शिल्प नीतियां।

हरियाणा उप-क्षेत्र

- औद्योगिक क्लस्टरों/क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, जिसमें बहादुरगढ़, फरीदाबाद, पानीपत आदि जैसे औद्योगिक शहरों में पर्यावरण प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए निर्बाध और गुणवत्ता बिजली आपूर्ति, सड़कों और पानी की आपूर्ति और बुनियादी ढांचे / सुविधाएं शामिल हैं। यह भी सिफारिश की जाती है कि उपयुक्त नीतियां तैयार की जाएं। और मेवात, झज्जर और रेवाड़ी जैसे जिलों में औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किए जाएं जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं।
- कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- केएमपी एक्सप्रेसवे जैसी क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना।
- प्रमुख औद्योगिक समूहों में क्लस्टर विकास कार्यक्रमों को अपनाकर एमएसएमई इकाइयों की सहायता करना।

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

- यह सिफारिस की जाती है कि पारंपरिक/पुराने औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए। यह भी सिफारिश की जाती है कि बागपत और बुलंदशहर जैसे जिलों में औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार की जाएं और आवश्यक हस्तक्षेप किए जाएं।
- विशेष रूप से मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के लिए सामान्य बुनियादी ढाँचा (बिजली, सड़कें, आदि) प्रदान करने की आवश्यकता है।
- गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़भाड़ और प्रदूषण को दूर करने की जरुरत है।
- मेरठ के औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए विशेष पैकेज।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए व्यापक नीति।
- गैर-कृषि गतिविधियों के आधुनिकीकरण के अवसरों का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता; तथा
- खुर्जा, गाजियाबाद आदि में पारंपरिक शिल्प समूहों के लिए तकनीकी और विपणन सहायता सहित उचित बुनियादी ढांचा।

राजस्थान उप-क्षेत्र

- निर्माण गतिविधियों के लिए मजबूत सहायता बुनियादी ढांचे के साथ प्रेरित क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से पहले से मौजूद और आगामी क्षेत्रों में अर्थात (i) भिवाड़ी-टपूकड़ा-खुशखेड़ा कॉम्प्लेक्स, (ii) अलवर और (iii) शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ कॉम्प्लेक्स
- ग्रीनफील्ड ऑटो और टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। भारत दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन और जापान के बाद एशिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह न केवल आंतरिक सुधारों की श्रृंखला है बल्कि वैश्वीकरण की शक्तिशाली ताकतें भी नई अर्थव्यवस्था को आकार दे रही हैं। अब ध्यान शहरी केंद्रों के विकास की ओर बढ़ रहा है जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 60% से अधिक का योगदान करते हैं। हालांकि, वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तेजी से कम हुआ है। वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की अर्थव्यवस्था को तेजी से आकार दे रहे हैं। तृतीयक क्षेत्र तेजी से एनसीआर में प्रमुख क्षेत्र बनता जा रहा है।

2011 की वेल्थ रिपोर्ट में दिल्ली को विश्व स्तर पर 37वें स्थान पर रखा गया है, जो एनसीआर का केंद्र बिंदु है। आर्थिक गतिविधि के मामले में, दिल्ली (विश्व स्तर पर 39 वें स्थान पर) जकार्ता और जोहान्सबर्ग जैसे शहरों से ऊपर है। वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली को अगले 10 वर्षों में रैंक में और ऊपर जाना है। मर्सर की रैंकिंग के अनुसार, दिल्ली भारत का सबसे महंगा शहर है और विश्व स्तर पर 85वें स्थान पर है, इसके बाद मुंबई (95) और बैंगलोर (185) का स्थान है।

एनसीआर में आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति तेजी से विकसित हो रही है। बेहतर बुनियादी ढांचे, जैसे दिल्ली मेट्रो की शुरूआत और केंद्रीय एनसीआर में इसके विस्तार कार्य, एक्सप्रेसवे का निर्माण, सड़कों में निवेश और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर जैसे अन्य बुनियादी ढांचे, इंडस्ट्रियल एस्टेट/मॉडल इंडस्ट्रियल टाउनशिप/एसईजेड आदि को लगाने से एनसीआर के भीतर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने की उम्मीद है। तृतीयक क्षेत्र और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की बढ़ती एकाग्रता एनसीआर में रोजगार और आय के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रही है। एनसीआर के लगातार बदलते आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, आर्थिक/राजकोषीय नीतियों के साथ-साथ एनसीआर में आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण और आकलन करना और विकास की भविष्य की दिशाओं का सुझाव देना अनिवार्य है।

1.2 एनसीआर के लिए आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना की आवश्यकता

1989 में अधिसूचित क्षेत्रीय योजना-2001, ने "एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित क्षेत्र के महत्व की कल्पना की, जिससे दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों और अप्रवासियों का फैलाव हुआ, जिससे एक प्रबंधनीय दिल्ली बन गई"। योजना ने "केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के भीतर रोजगार के अवसरों के सृजन पर सख्त नियंत्रण की नीति, दिल्ली महानगर क्षेत्र में मध्यम नियंत्रण और, एनसीआर के भीतर दिल्ली महानगर क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव दिया"।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अब 17.9.2005 को अधिसूचित एनसीआर के लिए परिप्रेक्ष्य वर्ष 2021 के लिए एक क्षेत्रीय योजना तैयार की है। दिल्ली के प्रतिबंधित विकास की नीति की समीक्षा की गई है और क्षेत्रीय योजना-2021 का प्रस्ताव है कि "दिल्ली द्वारा उत्पन्न विकासात्मक आवेग और समूह अर्थव्यवस्थाओं के प्रसार का उपयोग एनसीआर के सामंजस्यपूर्ण, संतुलित और भाग लेने वाले राज्यों के प्रभावी सहयोग के साथ एनसीआर के पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अनुपात-आर्थिक विकास"से किया जाये।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

आर्थिक नीति में परिवर्तन; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और सरकार के आकार घटाने की प्रक्रिया; उद्योग के लिए सब्सिडी और कर प्रोत्साहनों का उन्मूलन आवश्यक उपकरणों के एक सेट के रूप में कार्य करेगा जिसके साथ एनसीआर की आर्थिक संरचना एक महत्वपूर्ण तरीके से तेजी से परिवर्तन से गुजरेगी। इसके अलावा, नए विकास, जैसे दिल्ली मेट्रो की शुरूआत और मध्य एनसीआर में इसके विस्तार, पश्चिमी परिधीय (केएमपी) और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे का निर्माण, और अन्य एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और औद्योगिक विकास एस्टेट्स/मॉडल इंडस्ट्रियल टाउनशिप/एसईजेड और नए कस्बों आदि का एनसीआर की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

चूंकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक अत्यधिक एकत्रित शहरी क्षेत्र है, इसलिए एनसीआर के व्यवस्थित आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सिटी क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को भी लागू किया जा सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एनसीआर में आर्थिक विकास की गतिशीलता को समझना और विश्लेषण करना और त्वरित और सतत आर्थिक विकास के लिए सिफारिशें करने के लिए आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना तैयार करना जरुरी है।

1.3 उद्देश्य और दायरा

एनसीआर के लिए आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना का उद्देश्य एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों के मार्गदर्शन के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की व्यापक नीतियों और प्रस्तावों का विवरण देना है।

इस कार्यात्मक योजना ने एनसीआर के विभिन्न तत्वों की स्थानिक-आर्थिक विशेषताओं का विश्लेषण किया है जिसमें आय स्तरों, संस्थानों, औद्योगिक विकास, उद्योग समूहों, वर्तमान और भविष्य के नए विकास, अनौपचारिक गतिविधियों के स्तर, एनसीआर की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, भविष्य के विकास, क्षेत्रों, समूहों के लिए कार्य योजना, विभिन्न औद्योगिक स्थानों और निवेश नीतियों, औद्योगिक स्थलों और सेवा क्षेत्र के विकास पर सुझाव, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर इसके प्रभाव के साथ भविष्य के विकास के लिए रणनीति और कार्य योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1.4 कार्यप्रणाली

एनसीआर के लिए आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना सलाहकार के माध्यम से एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा आयोजित एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल (दिनांक 01.10.2013 और 24.11.2015 की अधिसूचनाओं से पहले एनसीआर के क्षेत्र को कवर करते हुए) के अध्ययन के विश्लेषण और निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई है। अध्ययन भारत सरकार और भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित डेटा/सूचना के साथ-साथ विभिन्न उद्योग संघों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर आयोजित किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, एनसीआर भाग लेने वाले राज्यों और उनके विभागों/एजेंसियों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई थी। अध्ययन के प्रारूप निष्कर्षों और सिफारिशों पर 08.05.2015 को आयोजित एक हितधारकों की कार्यशाला में भी चर्चा की गई थी। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त विचारों/टिप्पणियों/सुझावों को संबोधित/सम्मिलित करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल के अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट को बाद में परामर्श समीक्षा समिति (सीआरसी) द्वारा 14.08.2015 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था।

योजना में उपयोग किए गए जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, कार्य भागीदारी दर आदि जैसे विभिन्न संकेतकों के

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

साथ-साथ जीडीपी अनुमानों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों और विधियों का विवरण अनुबंध-1.1 में दिया गया है।

1.5 डेटा सीमा

डेटा की उपलब्धता से संबंधित बाधाएं, विशेष रूप से चुनिंदा विकास संकेतकों पर विभिन्न उप-क्षेत्रों के बीच तुलना करने के संदर्भ में थीं।

इसके अलावा, कुछ मामलों में, कुछ मापदंडों का समय श्रृंखला विश्लेषण संभव नहीं है। इसलिए, कुछ मामलों में, निष्कर्ष दो बिंदुओं पर डेटा निर्धारित करने तक सीमित हैं। जिला स्तरीय जीडीपी के आंकड़े 2004-05 से 2009-10 तक उपलब्ध हैं; एनसीआर उप-क्षेत्रों और जिलों का विश्लेषण इस अवधि तक सीमित है।

1.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीटी-दिल्ली, हरियाणा के नौ जिले, उत्तर प्रदेश के छह जिले और राजस्थान का एक जिला शामिल है। क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 34,144 वर्ग किमी (मानचित्र 2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्रीय योजना-2021: संघटक क्षेत्र) है। क्षेत्रीय योजना-2021 की तैयारी के बाद, कुछ जिलों को भाग लेने वाले राज्यों द्वारा विभाजित और पुनर्गठित किया गया था। प्रशासनिक इकाइयाँ और उनके भूमि क्षेत्र इस प्रकार हैं (मानचित्र 1.1):

a) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (1,483 वर्ग किमी) एनसीआर के कुल क्षेत्रफल का 4.4% है।
b) हरियाणा उप-क्षेत्र का क्षेत्रफल 13,428 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 30.3% और एनसीआर के 39.3% क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, मेवात और पलवल जिले शामिल हैं।
c) राजस्थान उप-क्षेत्र में अलवर जिला शामिल है जिसका क्षेत्रफल 8,380 वर्ग किमी है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.5% और एनसीआर के क्षेत्रफल का 24.5% है।
d) उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 10,853 वर्ग किमी है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ जिलों को मिलाकर राज्य के क्षेत्रफल का 4.5% और एनसीआर के 31.8% क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।

भारत सरकार ने दिनांक 1.10.2013 की गजट अधिसूचना के तहत हरियाणा राज्य के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले को एनसीआर में जोड़ा है। इसके बाद, भारत सरकार ने 24.11.2015 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा राज्य के जींद और करनाल जिलों और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले को एनसीआर में जोड़ा है। तदनुसार, अब हरियाणा उप-क्षेत्र में 13 जिले हैं, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में सात जिले हैं और राजस्थान उप-क्षेत्र में एनसीआर में दो जिले हैं। हरियाणा उप-क्षेत्र का क्षेत्रफल 25,327 वर्ग किमी है, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र का क्षेत्रफल 13,560 वर्ग किमी है। और राजस्थान उप-क्षेत्र का क्षेत्रफल 13,447 वर्ग किमी है। अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप, एनसीआर का क्षेत्रफल 53,817 वर्ग किमी है।

एनसीआर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनसीआर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% योगदान देता है। यह दुनिया के सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में से एक के रूप में विकसित हो रहा है।

---

[1] नए जोड़े गए जिलों भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, भरतपुर और मुजफ्फरनगर को छोड़कर।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार एनसीआर की जनसंख्या लगभग 460 लाख है। एनसीटी के उप-क्षेत्रों- दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एनसीआर की आबादी का क्रमशः 36.44, 23.95, 7.98% और 31.64 प्रतिशत हिस्सा है (देखें तालिका 1.1)

तालिका 1-1: एनसीआर में जनसंख्या का उप-क्षेत्रवार वितरण

	जनसंख्या				दशकीय वृद्धि (%)			2011 में जनसंख्या का हिस्सा (%)
वर्ष	**1981**	**1991**	**2001**	**2011**	**1981-1991**	**1991-2001**	**2001-11**	**2011**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	62,20,406	94,20,644	1,38,50,507	1,67,87,941	51.45	47.02	21.21	36.44
राजस्थान उप-क्षेत्र	17,55,575	22,96,580	29,92,592	36,74,179	30.82	30.31	22.78	7.98
हरियाणा उप-क्षेत्र	49,38,541	66,43,604	86,87,050	1,10,31,515	34.53	30.76	26.99	23.95
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	69,68,646	90,01,704	1,15,70,117	1,45,75,668	29.17	28.53	25.98	31.64
एनसीआर	**1,98,83,168**	**2,73,62,532**	**3,71,00,266**	**4,60,69,303**	**37.62**	**35.59**	**24.18**	**100**

स्रोत: एनसीआर से क्षेत्रीय योजना-*2021*, भारत की जनगणना *1981, 1991, 2001* और *2011*

2011 में, एनसीटी दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या सघनता 167.88 लाख थी और राजस्थान उप-क्षेत्र में सबसे कम 36.74 लाख थी।

2001-11 में अधिकतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हरियाणा उप-क्षेत्र (26.99%) में दर्ज की गई थी, इसके बाद उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (25.98%) और राजस्थान उप-क्षेत्र (22.78%) थे। इस अवधि में न्यूनतम दशकीय वृद्धि एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र (21.21%) में दर्ज की गई थी।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मानचित्र 1.1: एनसीआर संघटक क्षेत्र

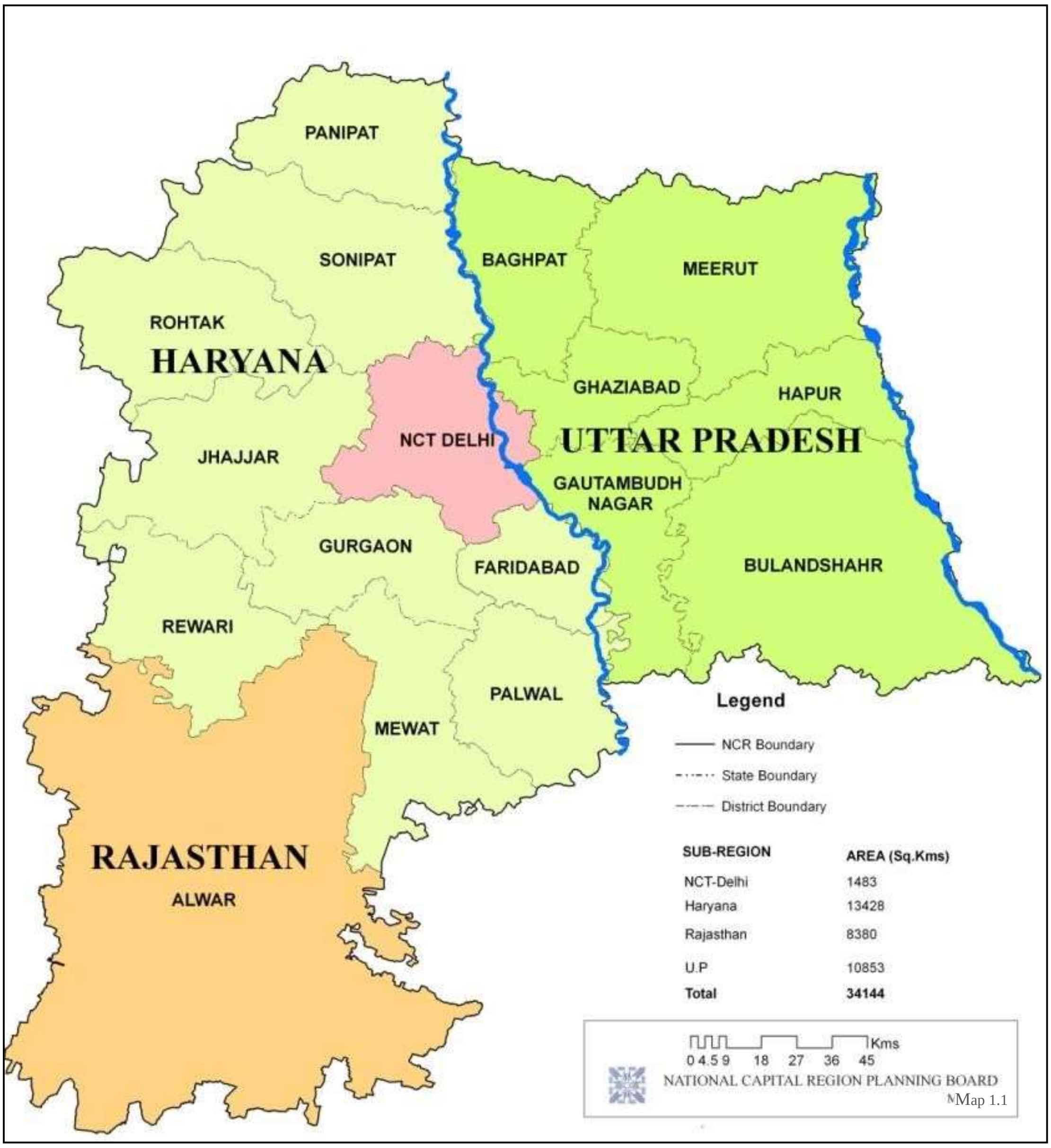

1.7 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजनाएं

एनसीआर योजना बोर्ड ने एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2001 तैयार की जिसे 1989 में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, एनसीआरपीबी ने एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 भी तैयार की है जिसे 2005 में अधिसूचित किया गया था और वर्तमान में लागू है। एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

क्षेत्रीय योजना-2021 का उद्देश्य अधिनियम, 1985 की धारा 10, उप-धारा (2) के अनुसार "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देना" है।

उपरोक्त उद्देश्य के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की गई है:

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

(चित्र अनुवाद)

पानीपत सोनीपत बागपत मेरठ रोहतक हरियाणा झज्झर एनसीटी दिल्ली गाज़ियाबाद हापुड़
उत्तर प्रदेश गौतमबुध नगर बुलंदशहर गुड़गांव फरीदाबाद रेवाड़ी पलवल मेवात राजस्थान अलवर
प्रमुख
एनसीआर सीमा
राज्य सीमा
जिला सीमा

उप-क्षेत्र	क्षेत्रफल वर्ग किमी
एनसीटी- दिल्ली	1483
हरियाणा	13428
राजस्थान	8380
यूपी	10853
योग	34144

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
मानचित्र 1.1

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

i राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आर्थिक विकास आवेग को अवशोषित करने में सक्षम क्षेत्रीय बस्तियों की पहचान और विकास द्वारा भविष्य के विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार प्रदान करना।
ii कुशल और आर्थिक रेल और सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (जन परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करना जो भूमि उपयोग के साथ अच्छी तरह से एकीकृत हैं।
iii एनसीआर के विकास की प्रक्रिया में होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना
iv शहरी ढांचागत सुविधाओं जैसे परिवहन, बिजली, संचार, पेयजल, सीवरेज, जल निकासी, आदि के साथ चयनित शहरी बस्तियों का विकास करना, जो दिल्ली के एनसीटी के साथ तुलनीय है।
v अच्छी कृषि भूमि की रक्षा और संरक्षण और शहरी उपयोग के लिए अनुत्पादक भूमि का उपयोग करने के लिए तर्कसंगत भूमि उपयोग पैटर्न प्रदान करना।
vi जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना।
vii संसाधन जुटाने के मौजूदा तरीकों की दक्षता में सुधार करना और संसाधन जुटाने के नवीन तरीकों को अपनाना और निजी निवेश को वांछित दिशा में सुविधाजनक बनाना, आकर्षित करना और मार्गदर्शन करना।

1.8 एनसीआर प्रोफाइल का सारांश

1.8.1 विकास अंतर

एनसीआर के सभी घटकों के बीच तुलनात्मक डेटा इंगित करता है कि उनके विकास पैटर्न में उल्लेखनीय अंतर हैं। नोएडा और गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में रोहतक, झज्जर और अलवर जैसे अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है। एनसीआर को एक सतत क्षेत्र के रूप में विकसित करने के दीर्घकालिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं को देखना आवश्यक है। किए गए विश्लेषण और "सिटी मेयर्स" द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, गाजियाबाद और फरीदाबाद 2006 से 2020 तक दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों और शहरी क्षेत्रों में से हैं और क्रमशः दूसरे और आठवें स्थान पर हैं।

1.8.2 उद्योग

एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी और मध्यम दोनों इकाइयों के साथ-साथ लघु उद्योग और छोटी असंगठित इकाइयां (एसएसआई) शामिल हैं। एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्र में मात्रा के साथ-साथ इकाइयों की संख्या दोनों में वृद्धि हुई है। हरियाणा उप-क्षेत्र में, मशीन टूल्स का निर्माण करने वाली इकाइयां, धातु उत्पादों से युक्त इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रिक मशीनरी के हिस्से उच्चतम प्रतिशत वितरण दिखाते हैं। यूपी उप-क्षेत्र के मामले में, विद्युत मशीनरी, धातु उत्पाद और पुर्जे, रासायनिक उत्पाद, कपड़ा उत्पाद प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान उप-क्षेत्र में, धातु उत्पाद और पुर्जे, कपड़ा उत्पाद और परिवहन उपकरण के साथ-साथ गैर-धातु खनिज उत्पाद, रसायन और बुनियादी धातु उत्पाद प्रमुख क्षेत्र हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास के साधन के रूप में ग्रामीण औद्योगीकरण की भी आवश्यकता है, क्योंकि इससे कृषि उत्पादकता में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में प्रमुख कृषि-प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ-साथ पारंपरिक कौशल स्तरों (शिल्प और हथकरघा) का उपयोग करने की जरुरत है।

1.8.3 निपटान पैटर्न

(a) शहरी बस्तियां

2011 की जनगणना के अनुसार, इस क्षेत्र में शहरी बस्तियों की संख्या 2001 में 108 से बढ़कर 2011 में 168 हो

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

गई। इनमें से, 2011 में 22 क्लास- I शहर (दिल्ली मेट्रोपोलिस सहित), 13 क्लास- II शहर, 41 क्लास- III, 43 क्लास-IV, 44 क्लास-V और 5 क्लास-VI शहर हैं। प्रथम श्रेणी के शहरों में इस क्षेत्र की कुल शहरी आबादी का लगभग 89% हिस्सा था। शेष शहरी आबादी को क्लास-VI से क्लास-II के 146 शहरों में बांटा गया था। अकेले दिल्ली शहरी समूह क्षेत्र की कुल शहरी आबादी का लगभग 57% हिस्सा है। क्षेत्र के भीतर महानगरीय शहरों (दस लाख से अधिक जनसंख्या) की संख्या 1991 में एक (दिल्ली) से बढ़कर 2001 में तीन (दिल्ली, मेरठ और फरीदाबाद) हो गई और 2011 में चार (दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और मेरठ) हो गई। हरियाणा उप-क्षेत्र में 65, राजस्थान उप-क्षेत्र में 16 और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में 86 शहरी बस्तियां हैं। एनसीआर में दिल्ली एनसीटी को छोड़कर, हरियाणा उप-क्षेत्र में आठ क्लास-I शहरी केंद्र, राजस्थान उप-क्षेत्र में दो क्लास-I शहरी केंद्र और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में 11 क्लास-I शहरी केंद्र हैं।

(b) ग्रामीण बस्तियां

2011 की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न आकार की 7,206 ग्रामीण बस्तियां हैं। इनमें से 103 दिल्ली के एनसीटी में, 2199 हरियाणा उप क्षेत्र में, 2021 राजस्थान में और 2,883 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में थे। 2011 में एनसीआर में 172 लाख से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, जो एनसीआर में कुल आबादी का लगभग 37% है।

1.8.4 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित निपटान पैटर्न

एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में छह स्तरीय बंदोबस्त प्रणाली यानी मेट्रो केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, उप-क्षेत्रीय केंद्र, सेवा केंद्र, केंद्रीय गांव और बुनियादी गांव का प्रस्ताव किया गया है। जनसंख्या सीमा के साथ बस्तियों का छह स्तरीय पदानुक्रम तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1-2: एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित बस्तियों का छह स्तरीय पदानुक्रम

1. मेट्रो केंद्र	10 लाख और उससे अधिक
2. क्षेत्रीय केंद्र	3 - 10 लाख
3. उप-क्षेत्रीय केंद्र	0.5 - 3 लाख
4. सेवा केंद्र	10,000 से 50,000
5. केन्द्रीय ग्राम	5,000 से 10,000
6. सामान्य ग्राम	5,000 से कम

स्रोत: एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021,

क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित मेट्रो और क्षेत्रीय केंद्र तालिका 1.3 में दिए गए हैं।

तालिका 1-3: एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 के अनुसार एनसीआर में प्रस्तावित मेट्रो और क्षेत्रीय केंद्र

क्रम संख्या	उप क्षेत्र	मेट्रो केंद्र (शहर/परिसर)	क्षेत्रीय केंद्र (शहर/परिसर)
1	हरियाणा उप-क्षेत्र	• फरीदाबाद-बल्लभगढ़ • गुड़गांव-मानेसर • सोनीपत-कुंडली	• बहादुरगढ़ • पानीपत • रोहतक • पलवल • रेवाड़ी

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

क्रम संख्या	उप क्षेत्र	मेट्रो केंद्र (शहर/परिसर)	क्षेत्रीय केंद्र (शहर/परिसर)
2	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	• गाजियाबाद-लोनी • नोएडा • ग्रेटर नोएडा	• हापुड़-पिलखुवा • बुलंदशहर-खुर्जा • बागपत-बड़ौत
		• मेरठ	
3	राजस्थान उप-क्षेत्र	-	• अलवर • ग्रेटर भिवाड़ी • शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़

स्रोत: एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021

मेट्रो केंद्र पूंजी कार्यों और गतिविधियों को आकर्षित करने और एनसीटी दिल्ली से जनसंख्या फैलाव में मदद करने के लिए शक्तिशाली विकास नोड्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। उनकी विशेष कार्यात्मक स्थिति और आकार के कारण, इन कस्बों/परिसरों में राजधानी की तुलना में उच्च स्तर के सामाजिक, भौतिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। दिल्ली और अन्य मेट्रो केंद्रों और एनसीआर कस्बों के साथ एक कुशल अंतर-शहरी जन परिवहन प्रणाली, साथ ही परिवहन और संचार संपर्क प्रदान करने की जरुरत है। संबंधित भाग लेने वाले राज्यों और उनकी एजेंसियों को इन मेट्रो केंद्रों में न केवल आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की जरुरत होगी, बल्कि निजी क्षेत्र के निवेश की सुविधा भी होगी।

प्रस्तावित क्षेत्रीय केंद्र, जो अच्छी तरह से स्थापित शहरी केंद्र हैं, जो अत्यधिक विशिष्ट माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों द्वारा चिह्नित हैं और नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं, जो सामान्य रूप से अन्य निचले क्रम के केंद्रों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इन केंद्रों को उन्नत औद्योगिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए विकसित किया जा रहा है और इसमें प्रशासनिक और उच्च स्तरीय सेवा कार्यों की एकाग्रता होगी, जो कि निवेश के आकर्षण और अनुकूल जीवन और कामकाजी वातावरण के निर्माण पर तेजी से गतिशील प्रभाव डालने की उम्मीद है।

एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 ने निपटान प्रणाली के विकास के लिए रणनीति तैयार की है। एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित एक सुगठित क्षेत्रीय बंदोबस्त प्रणाली का विकास वांछित है, जहां दिल्ली और क्षेत्र के अन्य शहरों/नगरों को उनकी क्षमता तक बढ़ने की अनुमति दी जाएगी ताकि विकास क्षमता का उपयोग किया जा सके। उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, मजबूत परिवहन और संचार संपर्क, उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक और वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण आज की जरूरत है। नई टाउनशिप को प्रमुख परिवहन कॉरिडोर, प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और नई जमीन पर अन्य उपयुक्त स्थानों के साथ नोड्स के रूप में स्थापित किया जा सकता है। दूसरे, क्षेत्र में छोटे और मध्यम शहरों का विकास, भी आवश्यक है क्योंकि वे उप-क्षेत्रीय केंद्र या सेवा केंद्र हैं। ये शहर स्थानीय उत्पादों पर आधारित शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं, कृषि विस्तार सेवाओं और कृषि उद्योगों तक पहुंच प्रदान करके अपने ग्रामीण भीतरी इलाकों के सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक उपयुक्त पदानुक्रम में सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण विकास को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो आगे उत्पादन को प्रोत्साहित करता है और ग्रामीण आबादी की आय में वृद्धि करता है, अर्थव्यवस्था में विविधता लाता है। इसलिए, एनसीआर के ग्रामीण क्षेत्रों को रहने और काम करने के लिए आकर्षक बनाना और शहरी केंद्रों की ओर पलायन को रोकने में मदद करता है।

1.5 कार्यात्मक योजना का अध्यायीकरण

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए कार्यात्मक योजना में आठ अध्याय शामिल हैं। प्रत्येक अध्याय संबंधित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की रूपरेखा सारांश के साथ शुरू होता है। अध्यायों की रूपरेखा नीचे दी गई है।

अध्याय 1: परिचय पृष्ठभूमि प्रदान करता है और विधि और दृष्टिकोण को कवर करता है।

अध्याय 2: जीडीपी और आय विश्लेषण एनसीआर में जीडीपी वृद्धि के रुझान, विशेष रूप से उप-क्षेत्र और जिला स्तरों पर प्रस्तुत करते हैं; यह एनसीआर के विभिन्न उप-सेटों के बीच विकास असमानताओं की बेहतर समझ देता है। अध्याय में उप-क्षेत्रीय स्तर पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी) और प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी भी शामिल है।

अध्याय 3: एनसीआर में कर्मचारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के स्तर पर प्रकाश डालता है।

अध्याय 4: एनसीआर में औद्योगिक विकास जिला और उप-क्षेत्र स्तर पर एनसीआर में औद्योगिक विकास की स्थिति को प्रस्तुत करता है। यह अध्याय एनसीआर में प्रमुख औद्योगिक समूहों को भी स्कैन करता है और एनसीआर अर्थव्यवस्था में उनके महत्व को रेखांकित करता है।

अध्याय 5: एनसीआर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ग्रामीण विकास पर विभिन्न सरकारी योजनाओं सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चालकों को प्रस्तुत करती है। यह अध्याय ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद बुनियादी ढांचे के आकार और प्रकारों का विवरण देता है जो कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों का सहायता करते हैं।

अध्याय 6: अनौपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, उसके आकार, विकास और एनसीआर में चुनौतियों की रूपरेखा प्रदान करता है।

अध्याय 7: एनसीआर के लिए नीति ढांचा उप-क्षेत्रीय सरकारों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों की समीक्षा करता है और सूचीबद्ध करता है।

अध्याय 8: मुद्दे और सिफारिशें: एनसीआर के सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख निष्कर्षों, पहचाने गए मुद्दों और सिफारिशों की रूपरेखा देता है। अध्याय विभिन्न स्थानों पर की जा रही परियोजनाओं से सबक भी प्रस्तुत करता है।

2. सकल घरेलू उत्पाद और आय विश्लेषण

2.1 पृष्ठभूमि

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को संदर्भित करता है। सकल घरेलू उत्पाद को सार्वभौमिक रूप से विकास के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वीकार किया जाता है। एनसीआर की आर्थिक मजबूती को समझने के लिए जिला स्तर पर जीडीपी का योग किया गया है। जिला स्तरीय जीडीपी अनुमान एनसीआर घटक राज्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं और इसलिए, जीडीपी की गणना के दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। इसके अलावा, तुलनीय जिला सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े 2009-10 तक उपलब्ध हैं और इसलिए, एनसीआर और इसके घटक उप-क्षेत्रों में जीडीपी प्रवृत्तियों में स्थिति और परिवर्तन इस अवधि तक सीमित हैं।[2]

राष्ट्रीय जीडीपी में एनसीआर का महत्वपूर्ण योगदान है। 2009-10 में स्थिर (2004-05) कीमतों पर भारत की जीडीपी 45,160.70 अरब रुपये थी, जबकि इसी अवधि के लिए एनसीआर की जीडीपी 3,193.40 अरब रुपये थी, जो 7.1 फीसदी

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

थी। वर्ष 2009-10 में, भारत के जीडीपी में सीएसओ के अनुसार 8.6% की वृद्धि दर देखी गई है और वर्ष 2013-14 में कुल जीडीपी 57417.91 अरब रुपये दर्ज किया गया था। एनसीआर में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर (11.2%) 2004-05 से 2009-10 के दौरान भारत (8.7%) की तुलना में अधिक है। एनसीआर के 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के जीडीपी आंकड़ों का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

एनसीआर तेजी से एक विश्व स्तरीय क्षेत्र के रूप में उभर रहा है और यह भारत के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। एनसीआर अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित थी, जिसका जीडीपी (2007-08) का 66% हिस्सा था। एनसीआर में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में क्षेत्रीय विकास के विश्लेषण से पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तेजी से घट रहा है जबकि तृतीयक या सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। स्थिर (2004-05) कीमतों और मौजूदा कीमतों (2013-14) दोनों पर भारत, राज्यों और एनसीआर की जीडीपी अनुबंध-2.1 में दी गई है। स्थिर (2004-05) कीमतों और मौजूदा कीमतों (2013-14) दोनों पर राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अनुबंध-2.2 में दी गई है। जैसा कि अनुलग्नक 2.1 और अनुलग्नक 2.2 से देखा गया है, वर्ष 2013-14 के लिए स्थिर (2004-05) कीमतों पर विभिन्न राज्यों के जीडीपी की तुलना में एनसीआर भारत के जीडीपी में छठा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। 2009-10 के दौरान स्थिर (2004- 05) कीमतों पर एनसीआर में प्रति व्यक्ति आय (59,264/- रुपये) राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय (39,904/- रुपये) से वर्ष 2013-14 के लिए बहुत अधिक है।.

2.2 एनसीआर अर्थव्यवस्था के रुझान और संरचना

2.2.1 एनसीआर जीडीपी रुझान

(a) एनसीआर और उप-क्षेत्रीय स्तर पर जीडीपी रुझान

एनसीआर के विभिन्न उप-क्षेत्रों में, एनसीटी-दिल्ली ने क्रमशः हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद दर्ज किया (तालिका 2.1 देखें)। एनसीआर जिलों (एनसीटी-दिल्ली को छोड़कर) में, गुड़गांव में फरीदाबाद के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी है, जबकि मेवात में सबसे कम जीडीपी है।

---

[2] एनसीआर के सभी जिलों के लिए केवल 2009-10 तक जिला स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद का तुलनीय डेटा उपलब्ध था। हालांकि, कुछ जिलों और उप क्षेत्रों के मामले में 2013-14 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 2-1: 2004-05 से 2009-10 तक एनसीआर का जिलावार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) (रुपये मिलियन में)

उप-क्षेत्र/जिला	**सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)**					
	2004-05	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**
मेरठ	71,760.60	81,598.94	85,739.00	91,741.00	93,859.00	101,255.00
बागपत	29,072.70	28,550.69	30,676.00	32,878.00	34,721.00	38,426.00
गाजियाबाद + हापुड़	89,271.38	97,684.35	16,073.00	24,786.00	131,284.00	36,476.00
गौतमबुद्ध नगर	73,533.04	75,276.19	17,302.00	126,290.00	131,114.00	141,557.00
बुलंदशहर	68,799.56	66,288.34	74,341.00	78,725.00	83,337.00	88,740.00
यूपी उप-क्षेत्र	**332,437.28**	**349,398.51**	**224,131.00**	**354,420.00**	**474316**	**406,454.00**
एनसीआर के लिए %	17.41%	16.71%	9.43%	13.56%	16.43%	12.73%
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**1,003,245**	**110,4061**	**1,240,796**	**1,379,609**	**1,557,911**	**1,698,390**
एनसीआर के लिए %	52.53%	52.79%	52.20%	52.77%	53.96%	53.18%
अलवर	77,420.30	77,425.70	90,451.30	93,576.10	10,109.80	121,901.00
राजस्थान उप-क्षेत्र	**77,420.30**	**77,425.70**	**90,451.30**	**93,576.10**	**10,109.80**	**121,901**
एनसीआर के लिए %	4.05%	3.70%	3.81%	3.58%	0.35%	3.82%
फरीदाबाद	1,11,351.30	21,775.90	36,363.00	51,289.00	1,62,484.00	1,90,015.00
गुडगाँव	66,984.40	1,80,864.00	2,02,167.00	2,27,494.00	2,42,418.00	2,69,906.00
झज्जर	28,356.30	30,757.10	34,253.00	36,861.00	40,157.00	44,948.00
पानीपत	65,641.00	72,170.50	79,053.00	88,334.00	00,821.00	99,298.00
रेवाड़ी	43,623.80	47,154.90	51,646.00	56,207.00	60,465.00	65,931.00
रोहतक	32,447.20	34,565.70	37,593.00	40,121.00	41,931.00	47,052.00
सोनीपत	48,414.20	52,734.50	58,440.00	62,898.00	68,729.00	77,068.00
मेवात	-	20,637.40	21,934.00	23,363.00	27,919.00	29,968.00
पलवल	-	-	-	-	-	42,546.50
हरियाणा उप-क्षेत्र	**285,466.9**	**279,796**	**319,282**	**359,073**	**239,201**	**406,811.5**
एनसीआर के लिए %	14.95%	13.38%	13.43%	13.74%	8.28%	12.74%
कुल एनसीआर	**1,909,921**	**2,091,545**	**2,376,825**	**2,614,171**	**2,887,262**	**3,193,474.3**

स्रोत: दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण, 2012-13; आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा; आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान; updes.up.nic.in

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

उप-क्षेत्रवार जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि एनसीआर का जीडीपी 2004-05 से 2009-10 तक दोगुना हो गया (स्थिर कीमतों पर, यानी 2004-05), जिसमें एनसीटी-दिल्ली का हिस्सा सबसे अधिक है, इसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का स्थान है।

एनसीटी-दिल्ली की जीडीपी अन्य उप-क्षेत्रों की संयुक्त जीडीपी के लगभग बराबर है। 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान, हरियाणा का जीडीपी लगभग दोगुना हो गया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली का लगभग 1.7 गुना बढ़ गया है। हरियाणा उप-क्षेत्र की जीडीपी विशेषकर 2004-2005 के बाद अन्य उप-क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ी, (चित्र 2.1 देखें)। राजस्थान उप-क्षेत्र की जीडीपी बहुत धीमी गति से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा उप-क्षेत्रों ने 2006-07 तक लगभग समान तर्ज पर जीडीपी के रुझान की सूचना दी, जिसके बाद जब हरियाणा उप-क्षेत्र ने बेहतर प्रगति करना शुरू किया, शायद इस समय में गुड़गांव और मानेसर में भारी निवेश के कारण प्रवृत्ति बदल गई। 2004-05 तक, चार उप-क्षेत्रों में जीडीपी में वृद्धि दर में अंतर तुलनात्मक रूप से संकीर्ण था; हालाँकि, यह अंतर 2005-06 के बाद व्यापक हो गया।

चित्र 2.1: एनसीआर का उप-क्षेत्रवार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (लगातार 2004- 05 कीमतों पर) (रुपये मिलियन में)

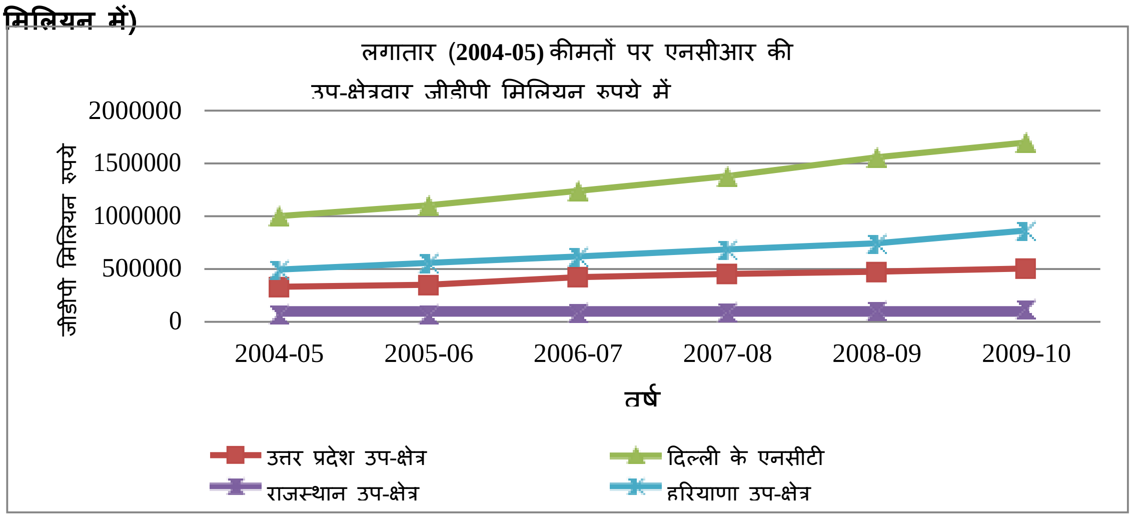

2004-05 से 2009-10 तक राष्ट्रीय स्तर, एनसीआर और चार उप-क्षेत्रों में जीडीपी की वार्षिक औसत वृद्धि दर (एएजीआर) का तुलनात्मक विश्लेषण इंगित करता है कि एनसीआर के जीडीपी का एएजीआर पहले की तुलना में अधिक (11.2%) था। भारत (8.7%)। हरियाणा उप-क्षेत्र (12.4%) ने जीडीपी में अधिकतम एएजीआर दर्ज किया, इसके बाद एनसीटी-दिल्ली (11.5%), राजस्थान (9.6%) और उत्तर प्रदेश (8.7%) के उप-क्षेत्र हैं। यह भी देखा गया है कि राजस्थान (9.6%) और उत्तर प्रदेश (8.7%) उप-क्षेत्रों ने जीडीपी के समान एएजीआर दर्ज किया है (तालिका 2.2, चित्र 2.2 और चित्र 2.3 देखें)।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों का एएजीआर (क्रमशः 12.4%; 8.7% और 9.6%) उनके संबंधित राज्यों (क्रमशः 9.86%, 6.81% और 7.63%) की तुलना में अधिक था। वर्ष 2006-07 में एनसीआर की जीडीपी की उच्चतम वृद्धि दर 13.64% दर्ज की गई है। वर्ष 2005-06 में एनसीआर और भारत दोनों की जीडीपी की वृद्धि दर क्रमशः 9.51% और 9.48%% पर सबसे पास थी और अगले वर्ष 2006-07 में क्रमशः 13.64% और 9.57% पर सबसे अधिक थी (तालिका 2.2 देखें, चित्र 2.2 और चित्र 2.3)।

तालिका 2-2: 2004-05 से 2009-10 तक (लगातार 2004-05 कीमतों पर) एनसीआर के सकल घरेलू उत्पाद का उप-क्षेत्रवार एएजीआर

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

उप-क्षेत्र/राज्य	साल दर साल%	साल दर साल%	साल दर साल%	साल दर साल%	साल दर साल%	
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	एएजीआर
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	5.10	21.39	7.14	4.38	6.78	8.7
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	10.05	12.38	11.19	12.92	9.02	11.5
राजस्थान उप-क्षेत्र	0.01	16.82	3.45	17.67	10.71	9.6

उप-क्षेत्र/राज्य	साल दर साल%	साल दर साल%	साल दर साल%	साल दर साल%	साल दर साल%	
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	एएजीआर
हरियाणा उप-क्षेत्र	12.85	10.84	10.48	8.50	16.4	12.4
एनसीआर	**9.51**	**13.64**	**9.99**	**10.45**	**9.13**	**11.2**
उत्तर प्रदेश राज्य	**6.51**	**8.07**	**7.32**	**6.99**	**6.58**	**6.81**
राजस्थान राज्य	**6.68**	**11.67**	**5.14**	**9.09**	**6.70**	**7.63**
हरियाणा राज्य	**9.20**	**11.22**	**8.45**	**8.17**	**11.72**	**9.86**
भारत	**9.48**	**9.57**	**9.32**	**6.72**	**8.59**	**8.7**

स्रोत : दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13; आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा; आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान; updes.up.nic.in

चित्र 2.2: 2005-06 से 2009-10 के दौरान एनसीआर और भारत के जीडीपी की तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि दर (लगातार 2004-05 की कीमतों पर)

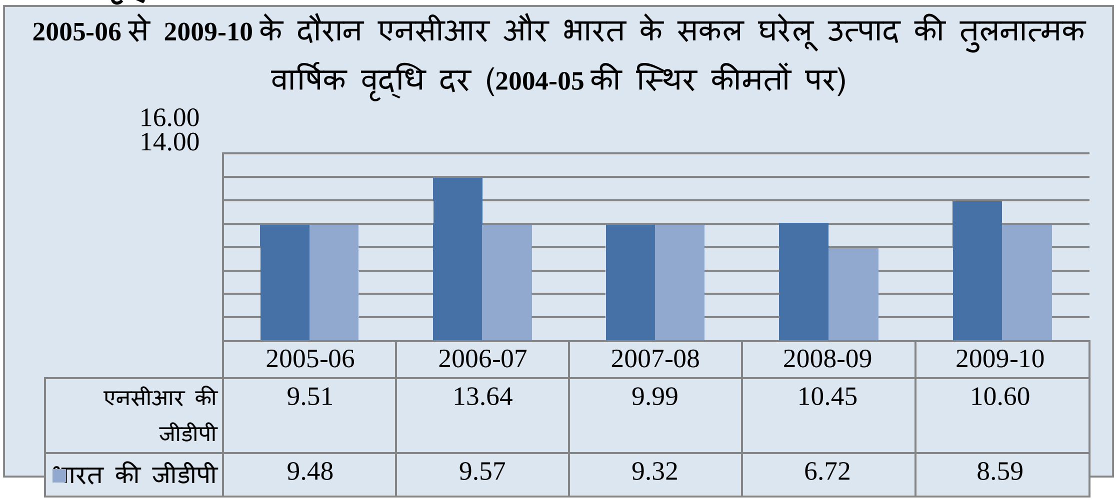

चित्र 2.3: 2004-05 से 2009-10 के दौरान एनसीआर के सकल घरेलू उत्पाद का एएजीआर (2004-05 की स्थिर कीमतों पर)

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

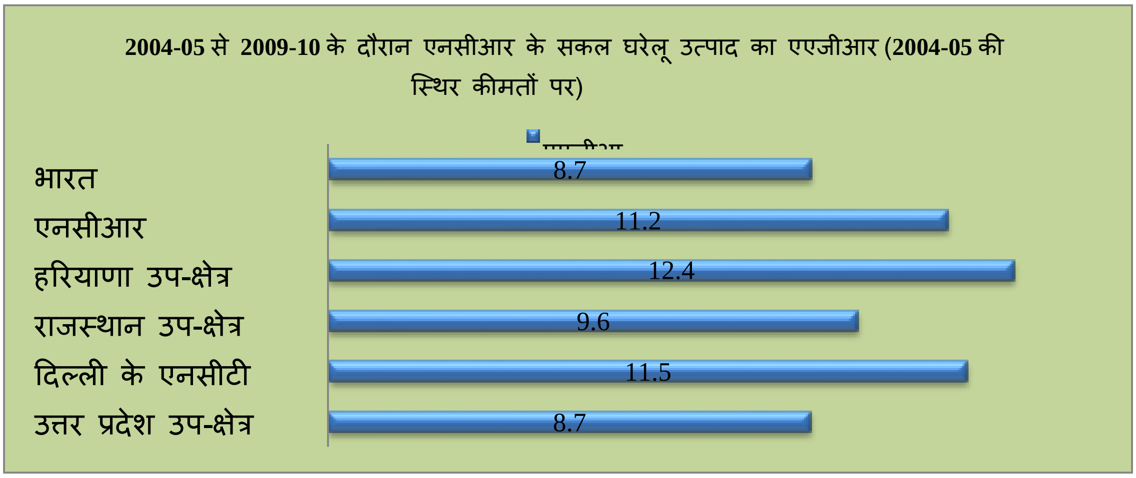

(b) एनसीआर घटक राज्यों और संबंधित उप-क्षेत्रों के बीच एएजीआर का तुलनात्मक विश्लेषण

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र ने वर्ष 2006-07 (21.39%) में उच्चतम वृद्धि दर्ज की और वर्ष 2008-09 (4.38%) में सबसे कम वृद्धि दर्ज की। हालांकि, उत्तर प्रदेश राज्य ने 2006-07 और 2009-10 को छोड़कर, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र की तुलना में जीडीपी में उच्च वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की। यह भी देखा गया है कि 2009-10 में दोनों यूपी उप-क्षेत्र और यूपी राज्य ने जीडीपी की क्रमशः 6.78% और 6.58% वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की (चित्र 2.4 देखें)।

चित्र 2.4: 2005-06 से 2009-10 के दौरान जीडीपी की तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि दर उत्तर प्रदेश राज्य और एनसीआर के उप-क्षेत्र के बीच स्थिर (2004-05) कीमतों पर

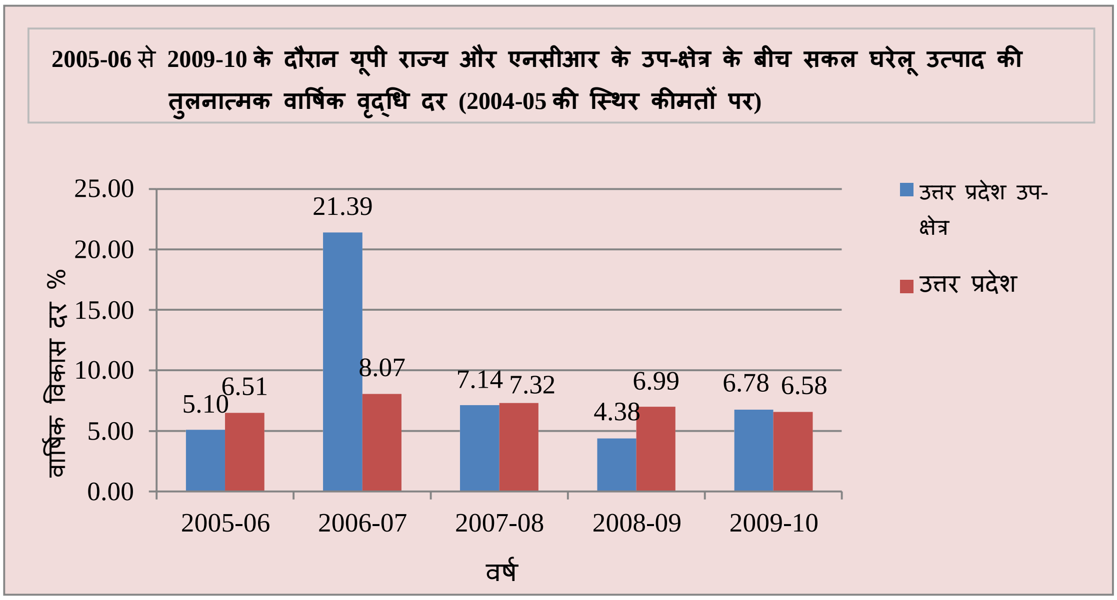

राजस्थान उप-क्षेत्र ने 2005-06 में 0.01% ; 2006-07 में 16.82%; 2007-08 में 3.45%; 2008-09 में 17.67% और 2009-10 में 10.71 % की एजीआर के साथ वार्षिक विकास दर में व्यापक भिन्नता दर्ज की है।
2005-06 में 6.68% ; 2006-07 में 11.67%; 2007-08 में 5.14%; 2008-09 में 9.09% और 2009-10 में 6.70% के एजीआर के साथ राजस्थान राज्य में भी इसी तरह की भिन्नता दर्ज की गई है। राजस्थान उप-क्षेत्र ने 2005-06 और 2007-08 को छोड़कर, राजस्थान राज्य की तुलना में जीडीपी में उच्च वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की (चित्र 2.5 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 2.5: 2005-06 से 2009-10 के दौरान राजस्थान और राजस्थान के एनसीआर उप-क्षेत्र के जीडीपी की तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि दर

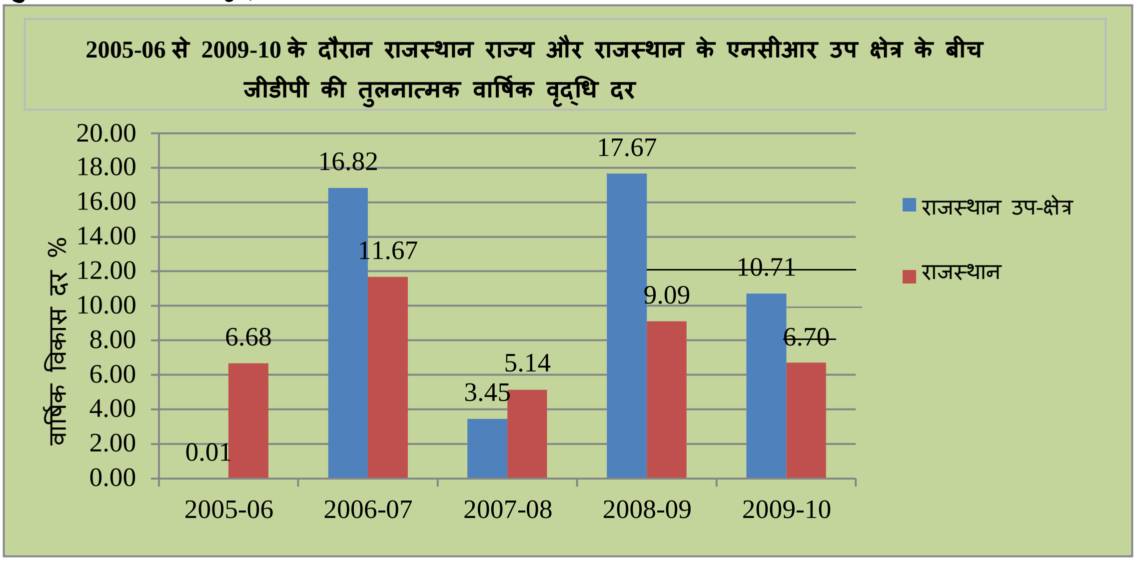

क्रमशः 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 की अवधि के लिए 9.20%, 11.22%, 8.45%, 8.17% और 11.72% की तुलना में हरियाणा उप-क्षेत्र में जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 12.85%, 10.84%, 10.48%, 8.50% और 10.64% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ तुलनात्मक रूप से सुसंगत विकास प्रदर्शित करता है,(चित्र 2.6 देखें)।

चित्र 2.6: 2005-06 से 2009-10 के दौरान एनसीआर के हरियाणा और हरियाणा उप-क्षेत्र के जीडीपी की तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि दर (2004-05 की कीमतों पर)

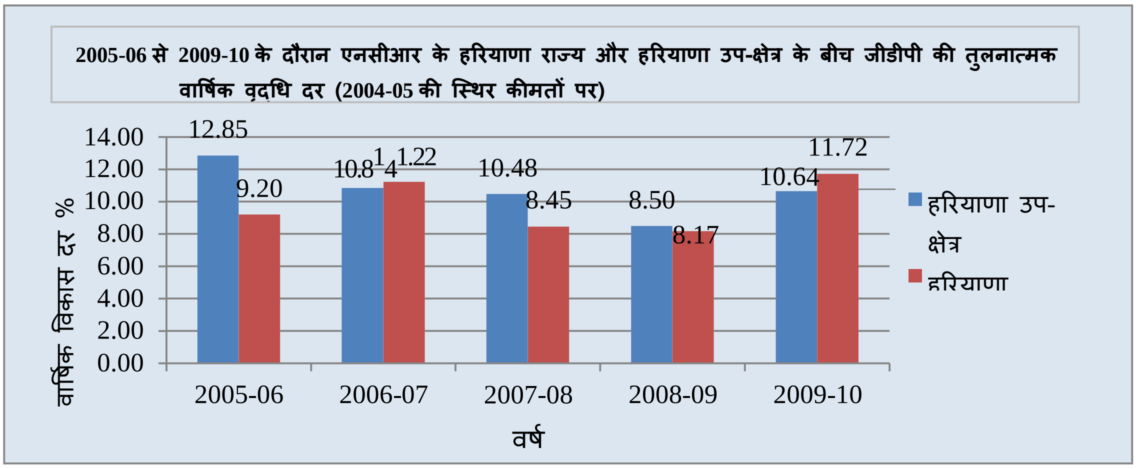

एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र की जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 2005-06 में 10.05% की सकारात्मक शुरुआत हुई थी; 2006-07 में यह 12.38% था, जो आने वाले वर्ष में 11.19% था, 2008-09 में फिर से बढ़कर 12.92% हो गया, लेकिन 2009-10 में घटकर सिर्फ 9% से थोड़ा ऊपर रह गया। जबकि उच्चतम वृद्धि दर 2009-10 में 12.92% पर देखी गई थी, जोकि वृद्धि की गति धीमी थी (चित्र 2.7 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 2.7: एनसीटी दिल्ली की 2005-06 से 2009-10 के दौरान जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर (लगातार 2004-05 की कीमतों पर)

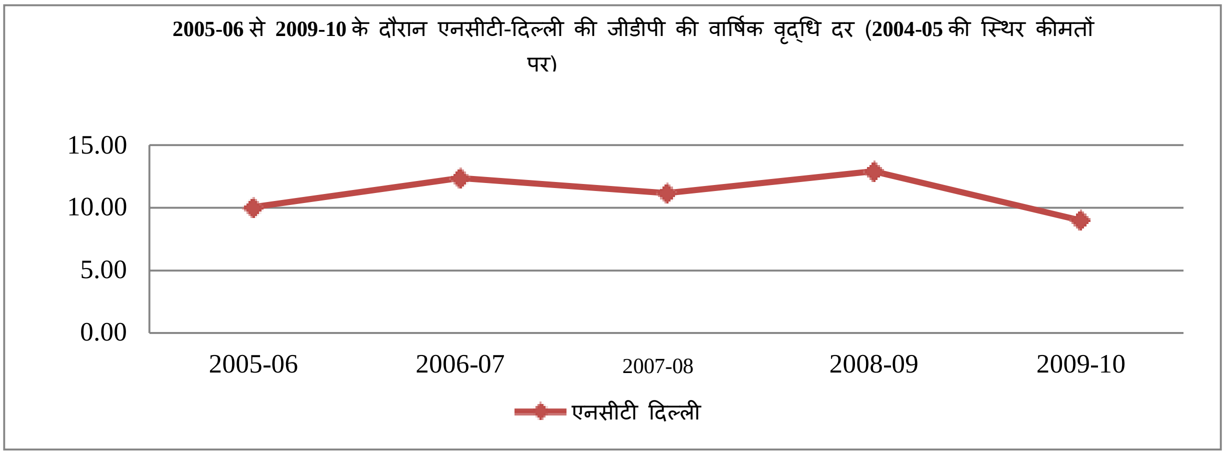

(c) संबंधित उप-क्षेत्रों में जीडीपी का जिला-वार तुलनात्मक विश्लेषण

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

2009-10 में सबसे ज्यादा जीडीपी गौतमबुद्ध नगर (1,41,557.06 मिलियन रुपये) में दर्ज की गई, जो बागपत (8,426.16 मिलियन रुपये) से लगभग चार गुना ज्यादा थी। मेरठ, गाजियाबाद (हापुड़ सहित) और गौतमबुद्ध नगर जिलों में जीडीपी क्रमशः 1,01,254.56 मिलियन रुपये, 1,36,475.9 मिलियन रुपये और 1,41,557.06 मिलियन रुपये पर प्रतिस्पर्धी थे। बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ के जीडीपी की वृद्धि ने 2005-10 के दौरान समान विकास पैटर्न दिखाया। गौतमबुद्ध नगर ने अन्य जिलों की तुलना में जीडीपी की उच्चतम वृद्धि दर्ज की है, जिसमें जीडीपी में 2004-05 और 2009-10 के बीच 68,024.02 मिलियन रुपये की वृद्धि हुई है। 2004-05 में सबसे कम जीडीपी बागपत जिले में 29,072.2 मिलियन रुपये दर्ज किया गया है। बाद के वर्षों में भी, बागपत जिले में जीडीपी की वृद्धि कम रही, जो 38,426.16 मिलियन रुपये तक पहुंच गई (तालिका 2.3 और 2.4 और चित्र 2.8 देखें)।

तालिका 2-3: 2004-2005 से 2009-10 तक उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र का जिला-वार जीडीपी (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) (मिलियन रुपये में)

जिला	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
मेरठ	71,760.60	81,598.94	85,739.16	91,741.39	93,859.36	101,254.56
बागपत	29,072.70	8,550.69	30,675.61	32,878.24	34,721.48	38,426.16
गाजियाबाद+हापुड़	89,271.38	97,684.35	1,16,072.75	1,24,785.67	1,31,283.90	1,36,475.90
गौतमबुद्ध नगर	73,533.04	75,276.19	1,17,301.88	1,26,289.94	1,31,114.00	1,41,557.06
बुलंदशहर	68,799.56	66,288.34	74,341.09	78,724.65	83,337.35	88,739.50

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, *<updes.up.nic.in>*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 2-4: 2004-2005 से 2009-10 तक (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) हरियाणा उप-क्षेत्र की जीडीपी की जिलावार वार्षिक वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष)

जिला	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**
मेरठ	13.71%	5.07%	7.00%	2.31%	7.88%
बागपत	-1.80%	7.44%	7.18%	5.61%	10.67%
गाजियाबाद+हापुड़	9.42%	18.82%	7.51%	5.21%	3.95%
गौतमबुद्ध नगर	2.37%	55.83%	7.66%	3.82%	7.96%
बुलंदशहर	-3.65%	12.15%	5.90%	5.86%	6.48%

चित्र 2.8: 2004-2005 से 2009-10 तक (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र का जिला-वार जीडीपी रुपए मिलियन में

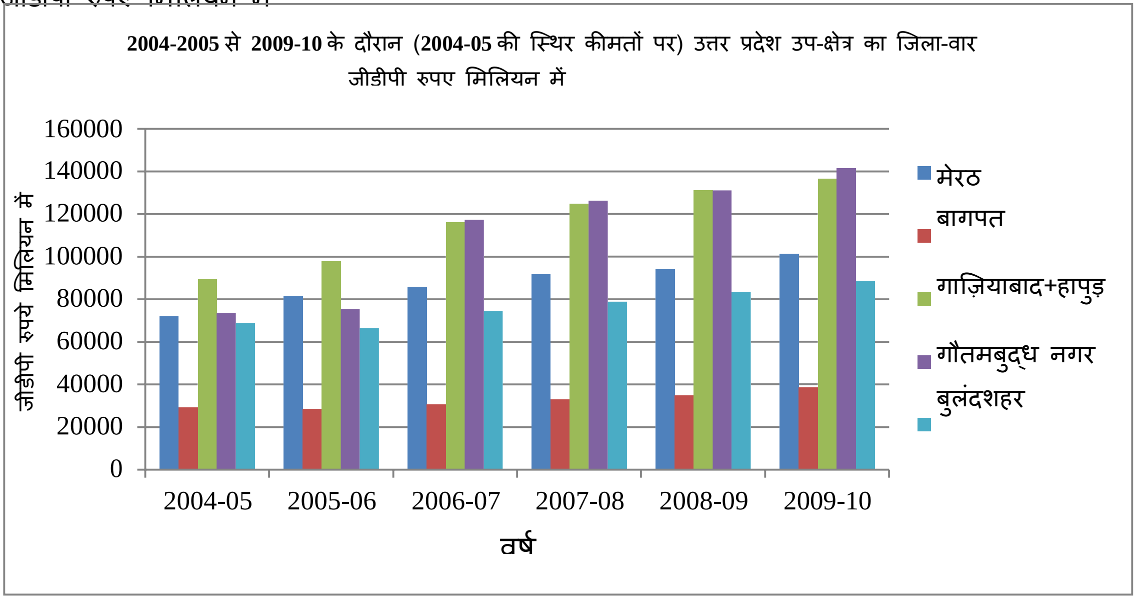

हरियाणा उप-क्षेत्र

2009-10 में गुड़गांव ने हरियाणा उप-क्षेत्र के जीडीपी में 2,69,905.5 मिलियन रुपये की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है; वर्ष 2006 में मेवात को एक अलग जिले के रूप में बनाया गया था। 2005-06 से 2009-10 के दौरान, हरियाणा उप-क्षेत्र के जीडीपी में मेवात जिले का हिस्सा सबसे कम रहा है। पलवल, जो एक नव निर्मित जिला भी है, ने वर्ष 2009-10 में 42,546.5 मिलियन रुपये की जीडीपी दर्ज की है। वर्ष 2009-10 के दौरान पानीपत (99,297.5 मिलियन रुपये), सोनीपत (77,067.6 मिलियन रुपये), रेवाड़ी (65,930.6 मिलियन रुपये) और रोहतक (47,052.3 मिलियन रुपये) की तुलना में फरीदाबाद हरियाणा उप-क्षेत्र के कुल सकल घरेलू उत्पाद में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और 2009-10 में 1,90,014.60 मिलियन रुपये का सकल घरेलू उत्पाद दर्ज किया है। (तालिका 2.5 और 2.6 और चित्र 2.9 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 2-5: 2004-2005 से 2009-10 तक हरियाणा उप-क्षेत्र का जिला-वार जीडीपी (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) (रुपये मिलियन में)

जिला	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
फरीदाबाद	1,11,351.3	1,21,775.9	1,36,362.8	1,51,289.1	1,62,483.8	1,90,014.6
गुडगाँव	1,66,984.4	1,80,864	2,02,167	2,27,493.5	2,42,417.8	2,69,905.5
झज्जर	28,356.3	30,757.1	34,252.7	36,861.3	40,157	44,947.9
पानीपत	65,641	72,170.5	79,052.8	88,334.2	1,00,821.3	99,297.5
रेवाड़ी	43,623.8	47,154.9	51,646.3	56,206.5	60,465.4	65,930.6
रोहतक	32,447.2	34,565.7	37,592.9	40,120.7	41,930.8	47,052.3
सोनीपत	48,414.2	52,734.5	58,439.5	62,897.9	68,729.4	77,067.6
मेवात	NA	20,637.4	21,933.9	23,362.9	27,919.4	29,967.8
पलवल	-	-	-	-	-	42,546.5

तालिका 2-6: 2004-2005 से 2009-10 तक (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) हरियाणा उप-क्षेत्र की जीडीपी की जिलावार वार्षिक वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष)

जिला/वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
फरीदाबाद	9.36	11.98	10.95	7.40	16.94
गुडगाँव	8.31	11.78	12.53	6.56	11.34
झज्जर	8.47	11.37	7.62	8.94	11.93
पानीपत	9.95	9.54	11.74	14.14	-1.51
रेवाड़ी	8.09	9.52	8.83	7.58	9.04
रोहतक	6.53	8.76	6.72	4.51	12.21
सोनीपत	8.92	10.82	7.63	9.27	12.13
मेवात	NA	6.28	6.52	19.50	7.34
हरियाणा उप-क्षेत्र	**12.85**	**10.84**	**10.48**	**8.50**	**16.40**

स्रोत: हरियाणा, आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग; योजना आयोग डेटा टेबल

चित्र 2.9: 2004-05 से 2009-10 तक हरियाणा उप-क्षेत्र (लगातार 2004-05 कीमतों पर) का जिला-वार जीडीपी रुपए मिलियन में

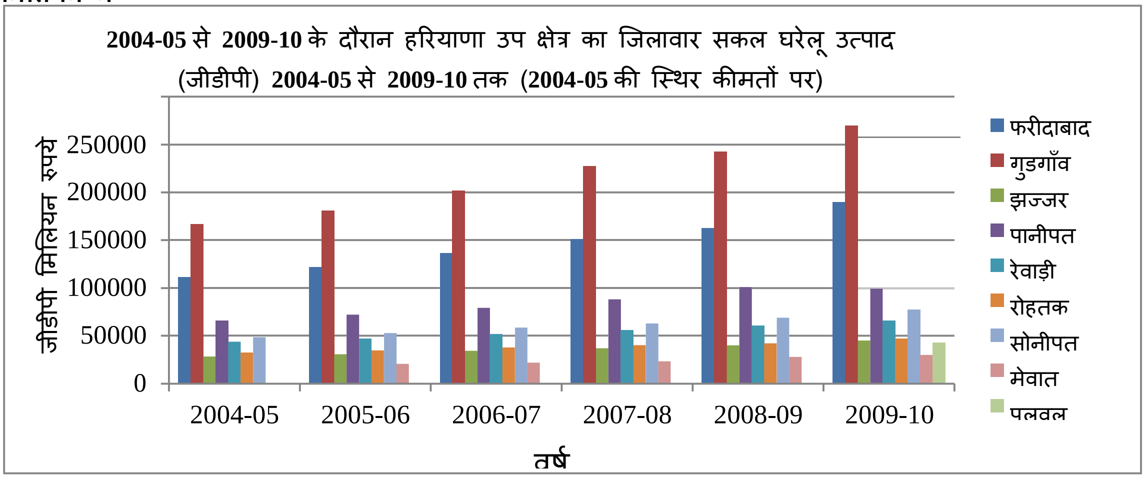

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

1999-2000 से 2007-08 तक जिला और उप-क्षेत्र स्तर पर एनसीआर की वर्ष-वार जीडीपी स्थिर कीमतों पर (मूल वर्ष 1999-2000) अनुलग्नक-2.5 से अनुबंध-2.13 में दी गई है।

2.2.2 एनसीआर में प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) रुझान

(a) एनसीआर और उप-क्षेत्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय

एनसीआर के विभिन्न उप-क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) में व्यापक भिन्नता है। 2009-10 में, एनसीटी-दिल्ली ने उच्चतम प्रति व्यक्ति आय (98,262 रुपये) दर्ज की, इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र (74,457 रुपये), उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (35,036 रुपये) और राजस्थान उप-क्षेत्र (29,300 रुपये) का स्थान रहा। एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र और हरियाणा उप-क्षेत्र का पीसीआई एनसीआर (59,264 रुपये) की तुलना में अधिक है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्रों में एनसीआर की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम है।

2004-05 और 2009-10 की अवधि के दौरान हरियाणा उप-क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय का उच्चतम सीएजीआर (10.65%) एनसीआर के अन्य उप-क्षेत्रों की तुलना में है और एनसीआर के सीएजीआर (8.86%) से अधिक है। दिल्ली के एनसीटी का सीएजीआर 9%, राजस्थान उप-क्षेत्र में 7.17% और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में 6.53% था। विभिन्न जिलों में, गुड़गांव (22.98%) ने अन्य सभी जिलों को पीछे छोड़ दिया, इसके बाद फरीदाबाद (20.78%) का स्थान रहा। उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में, गौतमबुद्ध नगर (9.77%) ने प्रति व्यक्ति आय का उच्चतम सीएजीआर दर्ज किया है, इसके बाद मेरठ (5.07%) और गाजियाबाद सहित हापुड़ (4.93%) है। अधिकांश एनसीआर जिले 1% -10% की सीमा में सीएजीआर की रिपोर्ट करते हैं, केवल गुड़गांव और फरीदाबाद अपवाद हैं।

हरियाणा और एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र उत्पादन, विनिर्माण, आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में शामिल बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एमएसएमई की उपस्थिति के साथ औद्योगिक क्षेत्र को काफी हद तक जीडीपी में योगदान करते हैं और इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय के स्तर को बढ़ाते हैं (तालिका 2.7 और 2.8 और चित्र 2.10 और 2.11 देखें)।

तालिका 2-7: 2004-05 से 2009-10 तक लगातार (2004- 05) कीमतों पर एनसीआर की जिला और उप-क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय

जिला/उप-क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	CAGR
एनसीटी दिल्ली	**63,877**	**69,128**	**76,243**	**83,243**	**91,845**	**98,262**	**9.00**
मेरठ	19,946.28	22,148.51	22,925.14	23,923.94	24,043.62	25,536.35	5.07
बागपत	21,779.58	21,090.75	22,471.80	23,776.14	24,937.65	27,348.20	4.66
गाजियाबाद+हापुड़	20,775.18	21,863.16	25,032.36	25,637.83	26,109.19	26,426.39	4.93
गौतमबुद्ध नगर	45,148.22	44,420.84	67,374.48	67,961.93	68,516.28	71,960.92	9.77
बुलंदशहर	20,051.06	18,903.35	20,922.42	21,737.87	22,750.01	23,909.02	3.58
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	**25,540.06**	**25,685.32**	**31,745.24**	**32,607.54**	**33,271.35**	**35,036.18**	**6.53**
फरीदाबाद	41,590	49,408	54,359	58,882	61,787	1,06,896	20.78
गुडगाँव	81,478	1,65,878	1,81,730	1,99,095	2,06,817	2,29,208	22.98
झज्जर	26,820	28,525	31,238	32,824	35,032	38,665	7.59
मेवात	NA	17,715	17,764	18,529	21,706	27,327	11.45
पानीपत	57,436	61,273	66,607	73,095	81,678	79,047	6.60
रेवाड़ी	46,259	50,036	52,634	55,463	58,120	63,075	6.40

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

जिला/उप-क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	CAGR
रोहतक	28,959	29,624	32,219	33,665	34,429	38,167	5.68
सोनीपत	31,723	33,441	36,879	38,747	41,496	46,071	7.75
पलवल						41,658	NA
हरियाणा उप-क्षेत्र	**44,895**	**54,487**	**59,179**	**63,788**	**67,633**	**74,457**	**10.65**
अलवर	20,721	20,423	23,522	23,638	27,030	29,300	7.17
राजस्थान उप-क्षेत्र	**20,721**	**20,423**	**23,522**	**23,638**	**27,030**	**29,300**	**7.17**
एनसीआर	**38,758**	**42,431**	**47,672**	**50,819**	**54,945**	**59,264**	**8.86**

स्रोत: उत्तर प्रदेश *<updes.up.nic.in>*, आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा; अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान

तालिका 2-8: प्रति व्यक्ति आय सीमा के सीएजीआर के साथ एनसीआर में जिलों के नाम और संख्या

सीएजीआर की रेंज	जिलों की संख्या	जिलों का नाम
1 से 5	4	बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़
5 से 10	9	मेरठ, रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत, अलवर, झज्जर, सोनीपत, एनसीटी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर
10 और उससे अधिक	3	फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात
लागू नहीं	1	पलवल

चित्र 2.10: 2004-05 से 2009-10 तक लगातार 2004-05 कीमतों पर एनसीआर की उप-क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय

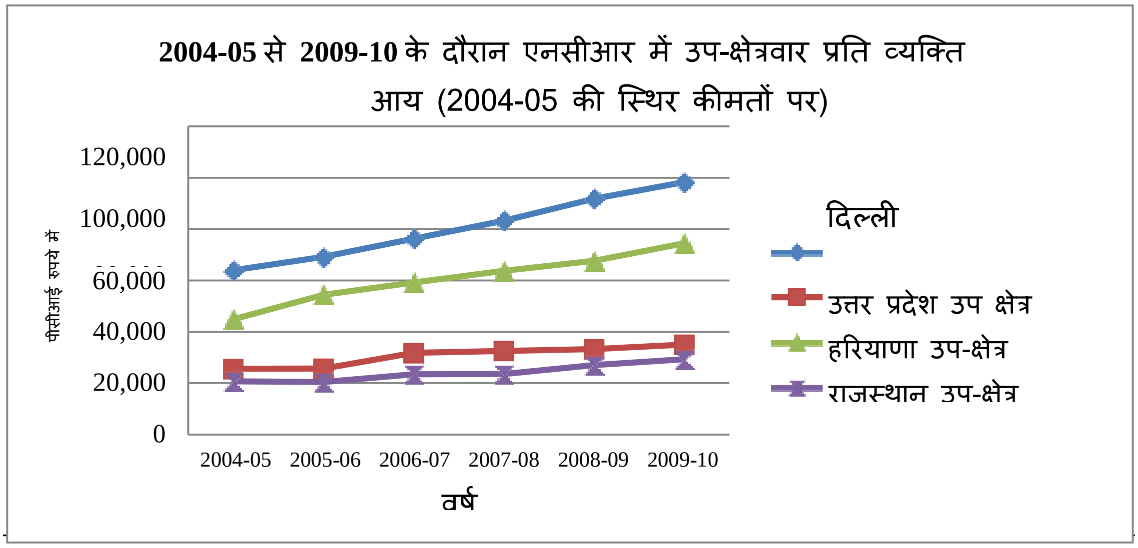

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 2.11: 2004-05 से 2009-10 तक लगातार 2004-05 कीमतों पर एनसीआर की उप-क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय

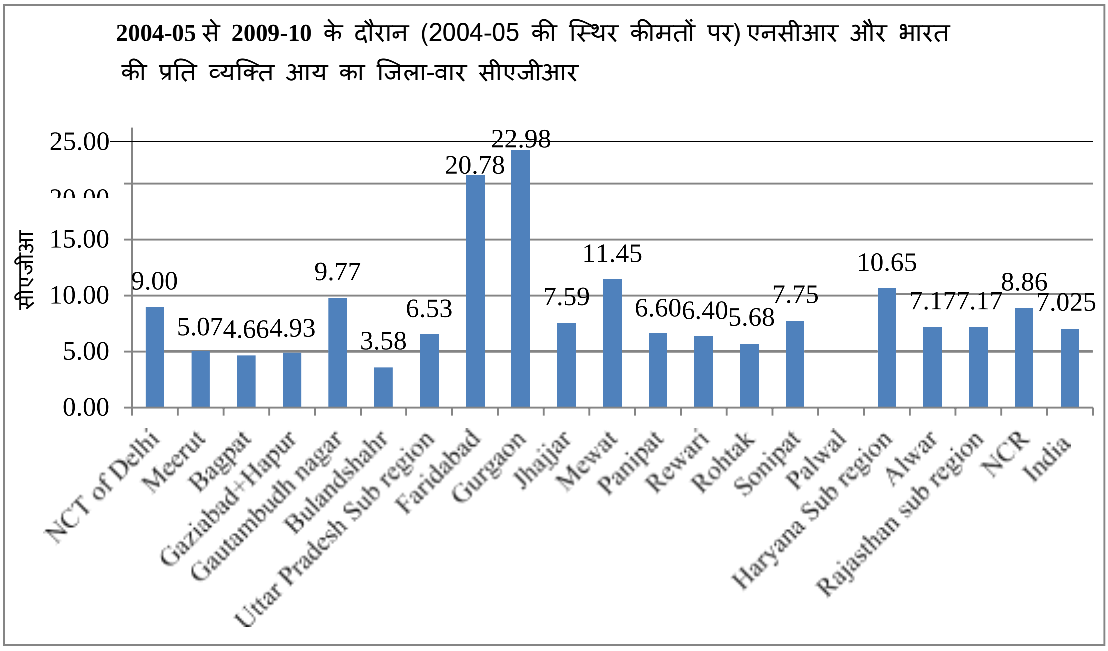

ऊपर वाले चित्र का अनुवाद

(एनसीटी दिल्ली मेरठ बागपत गाज़ियाबाद + हापुड़ गौतमबुद्ध नगर बुलंदशहर उत्तरप्रदेश उप क्षेत्र फरीदाबाद गुड़गांव झज्जर मेवात पानीपत रेवाड़ी रोहतक सोनीपत पलवल हरियाणा उप क्षेत्र अलवर राजस्थान उप क्षेत्र एनसीआर भारत)

(b) हरियाणा और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय का जिला-वार तुलनात्मक विश्लेषण

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

गौतमबुद्ध नगर की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के अन्य जिलों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में काफी अधिक थी। 2009-10 के दौरान, गौतमबुद्ध नगर (71,960.92 रुपये) ने उप-क्षेत्र में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय दर्ज की, जो 2005-06 तक उप-क्षेत्र के किसी भी अन्य जिले से लगभग दोगुना है और 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान अन्य जिलों के लगभग तीन गुना है। वर्ष 2009-10 में बुलंदशहर (23,909 रुपये) की प्रति व्यक्ति आय उप-क्षेत्र में सबसे कम है। गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के अन्य सभी जिलों ने 2009-10 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत (59,264 रुपये) प्रति व्यक्ति आय के आधे से भी कम दर्ज किया है (तालिका 2.7 और चित्र 2.12 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 2.12: उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के लिए 2004-05 से 2009-10 तक लगातार 2004-05 कीमतों पर जिलेवार प्रति व्यक्ति आय रुपये में

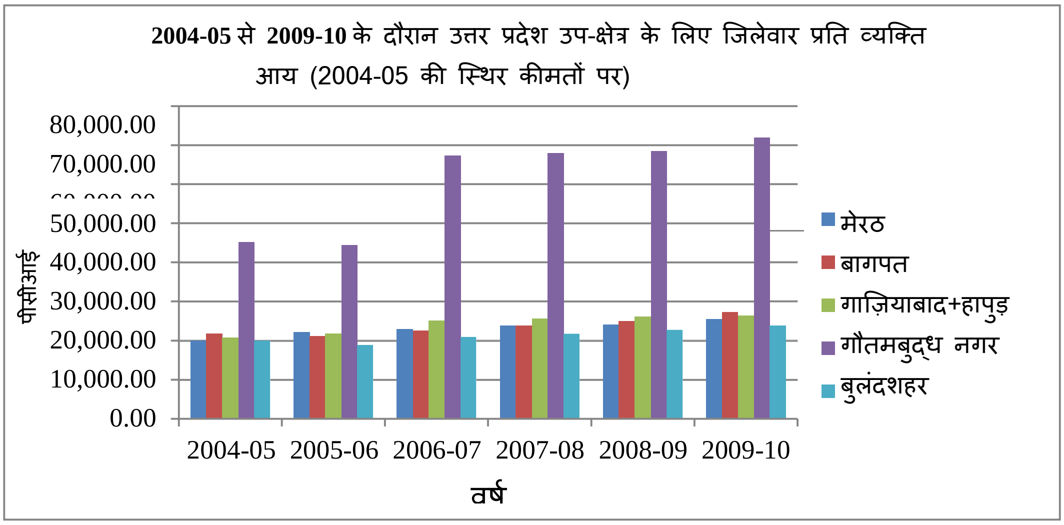

हरियाणा उप-क्षेत्र

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एनसीआर के हरियाणा उप-क्षेत्र में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गुड़गांव (2,29,208 रुपये) का है, इसके बाद फरीदाबाद (1,06,896 रुपये), पानीपत (79,047 रुपये) और रेवाड़ी (63,075 रुपये) का स्थान है, 2009-10 में मेवात की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम (27,327 रुपये) है। शेष चार जिलों में, रोहतक और झज्जर की प्रति व्यक्ति आय समान है, जो 38,000 रुपये से अधिक है, जबकि सोनीपत और पलवल की प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपये से अधिक है। 2005 के बाद, गुड़गांव जिले में प्रति व्यक्ति आय में कई गुना वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय रियल एस्टेट और आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के विकास को दिया जा सकता है (तालिका 2.7 और चित्र 2.13 देखें)।

चित्र 2.13: 2004-05 से 2009-10 की अवधि के लिए हरियाणा उप-क्षेत्र के लिए लगातार (2004-05) कीमतों पर जिलेवार प्रति व्यक्ति आय रुपये में

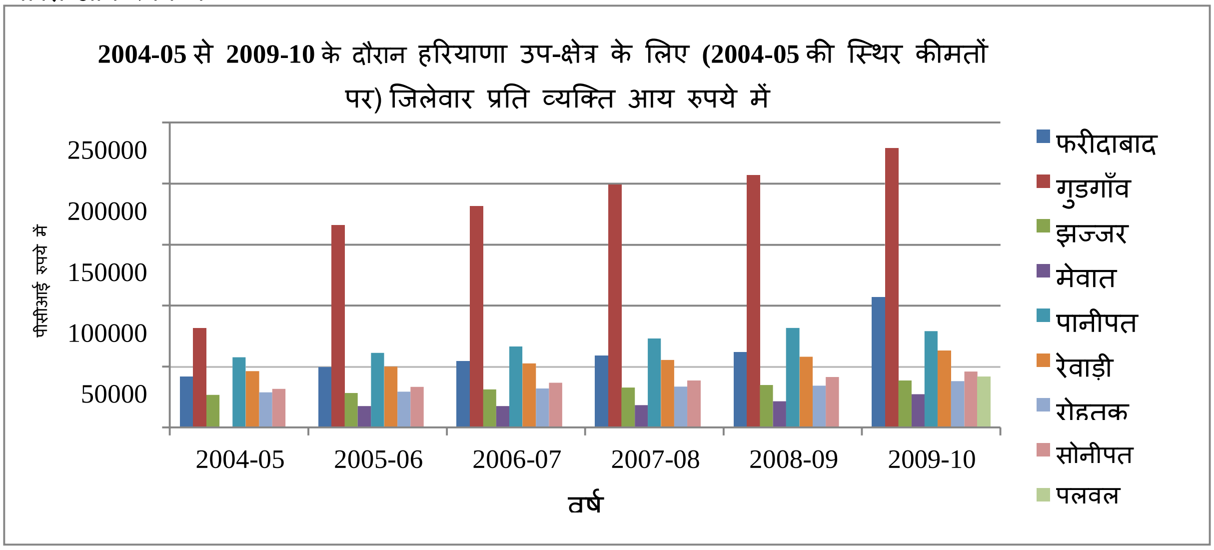

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

2.3 एनसीआर क्षेत्रवार रुझान

स्थिर कीमतों पर जीडीपी के क्षेत्रीय विकास का विश्लेषण इंगित करता है कि प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, पशुधन, मछली पकड़ने, वानिकी, खनन और उत्खनन से मिलकर) और द्वितीयक क्षेत्र (निर्माण, बिजली, गैस, जल-आपूर्ति से मिलकर) का योगदान एनसीआर में घटी है। 2007-08 में, तृतीयक क्षेत्र का एनसीआर के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 67% हिस्सा था, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र (25%) और शेष प्राथमिक क्षेत्र (8%) था। एनसीआर अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना में बदलाव के कारणों को एक तरफ तेजी से शहरीकरण और कृषि और संबंधित गतिविधियों में कमी और दूसरी ओर सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में काफी वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। (तालिका 2.11 और चित्र 2.14 देखें)।

तालिका 2-9: स्थिर कीमतों पर जीडीपी का क्षेत्रवार योगदान (1999-2000) (रुपये मिलियन में)

क्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
मुख्य	7,633	7,827	7,673	7,549	7,676	7,675	7,406	7,409	7,134
द्वितीयक	1,00,817	1,11,293	1,07871	1,24,232	1,24,448	1,50,117	1,67,832	1,79,558	1,87,879
तृतीयक	4,43,751	4,56,926	4,82,769	5,11,748	5,47,950	6,02,028	6,68,532	7,83,890	8,96,995
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**5,52,201**	**5,76,046**	**5,98,313**	**6,43,529**	**6,80,074**	**7,59,820**	**8,43,770**	**9,70,857**	**10,92,008**
मुख्य	14,896	14,535	15,804	12,066	20,237	17,939	16,865	20,815	20,984
द्वितीयक	16,781	15,802	14,001	16,195	17,638	19,320	20,109	21,920	31,140
तृतीयक	21,604	21,683	21,407	22,108	24,261	26,161	27,295	31,540	41,451
राजस्थान उप-क्षेत्र	**53,281**	**52,020**	**51,212**	**50,369**	**62,136**	**63,420**	**64,269**	**74,275**	**93,575****
मुख्य*	43,255	45,323	46,756	44,270	46,508	51,154	54,872	57,096	59,410
द्वितीयक*	91,077	97,664	1,06,578	1,13,300	1,25,539	1,40,025	1,56,879	1,71,792	1,88,123
तृतीयक*	93,986	1,28,788	1,46,565	1,63,675	1,79,952	2,01,663	2,35,574	2,74,645	3,20,195
हरियाणा उप-क्षेत्र	**2,28,318**	**2,71,775**	**2,99,899**	**3,21,245**	**3,51,999**	**3,92,842**	**4,47,325**	**5,03,532**	**5,67,728**
मुख्य	59,312	63,851	61,988	64,404	66,114	70,179	70,268	75,013	75,704
द्वितीयक	79,195	74,492	74,721	75,287	79,039	90,215	96,886	1,09,306	1,22,705
तृतीयक	80,017	90,562	93,284	96,885	1,02,323	1,10,678	1,18,032	1,25,823	1,35,858
यूपी उप-क्षेत्र	**2,18,524**	**2,28,905**	**2,29,993**	**2,36,576**	**2,47,476**	**2,71,072**	**2,85,186**	**3,10,142**	**3,34,266**
मुख्य	**1,25,096**	**1,31,536**	**1,32,221**	**1,28,289**	**1,40,536**	**1,46,947**	**1,49,410**	**1,60,333**	**1,63,231**
द्वितीयक	**2,87,870**	**2,99,251**	**3,03,171**	**3,29,014**	**3,46,619**	**3,99,446**	**4,43,059**	**4,82,576**	**5,29,846**
तृतीयक	**6,39,358**	**6,97,959**	**7,44,025**	**7,94,416**	**8,54,454**	**9,40,358**	**10,50,078**	**12,15,897**	**13,94,499**
एनसीआर	**10,52,324**	**11,28,746**	**11,79,417**	**12,51,719**	**13,41,609**	**14,86,751**	**16,42,547**	**18,58,806**	**20,87,577**

स्रोत: *www.planning Commission.nic.in* और *http://updes.up.nic.in/*

* यह इंगित करता है कि हरियाणा 2006 और 2007 में पिछले वर्षों के सीएजीआर पर डेटा बहिष्कृत किया गया है

** इंगित करता है कि राजस्थान में 2007 के आंकड़े 2004-05 के आधार मूल्य पर रहे हैं

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 2.14: 2007-08 में एनसीआर क्षेत्रीय-जीडीपी

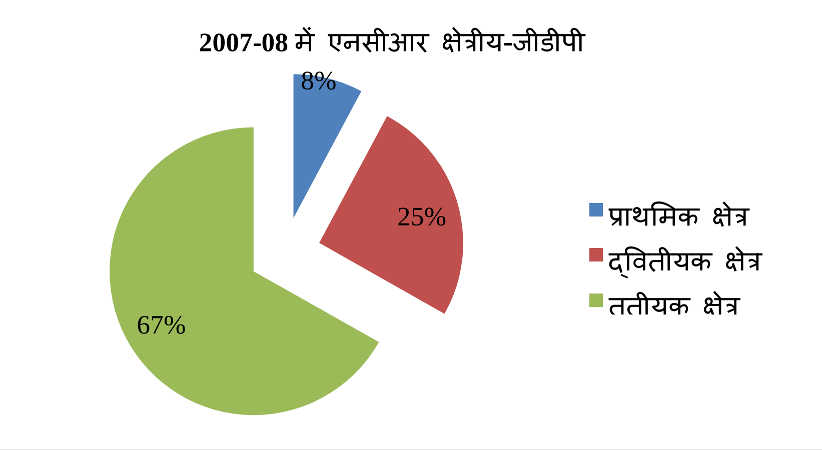

क्षेत्रीय रुझानों का उप-क्षेत्रवार विश्लेषण

एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र

क्षेत्रीय प्रवृत्तियों से संकेत मिलता है कि तृतीयक क्षेत्र एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र (कुल सकल घरेलू उत्पाद का 85%) के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदान देने वाला क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से परिवहन, संचार, अचल संपत्ति, वित्तीय सेवाएं, थोक व्यापार और अन्य व्यवसाय संबंधी सेवाएं शामिल हैं।

यद्यपि प्राथमिक क्षेत्र वर्ष 2005-06, 2007-08 और 2008-09 में नकारात्मक वृद्धि दर का अनुभव कर रहा है, लेकिन 2009-10 में 26.8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, माध्यमिक क्षेत्र के मामले में, 2005-06 से 2009-10 के दौरान 5%-6% के बीच स्थिर विकास दर का अनुभव किया है, 2006-07 में उच्च विकास दर (7.1%) दर्ज की गई है।

एनसीटी-दिल्ली के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में पिछले एक दशक में गिरावट आई है (2002-03 से 2007-08 के दौरान, कुल जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 1% से कम रहा है)। 2004-05 से 2009-10 तक, प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की एएजीआर देखी गई है, क्योंकि इसमें पिछले वर्षों में नकारात्मक सालाना वृद्धि हुई है। द्वितीयक क्षेत्र 5.4% के एएजीआर से बढ़ा है और एनसीटी-दिल्ली के जीडीपी में 14% हिस्सेदारी का योगदान दिया है। इस क्षेत्र ने अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है और इसी अवधि के लिए 13.1% का एएजीआर दर्ज किया है (तालिका 2.12 देखें)।

तालिका 2-10: 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र के जीडीपी की क्षेत्रवार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर

सेक्टर / फील्ड	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (R)	AAGR
प्राथमिक क्षेत्र	-3.8	1.1	-2.8	-0.6	26.8	3.2
द्वितीयक क्षेत्र	5.6	7.1	5.1	5.8	5.5	5.4
तृतीयक क्षेत्र	11.3	13.7	12.6	14.4	9.5	13.1
एनसीटी दिल्ली	10	12.4	11.2	12.9	9	11.5

स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली; राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान, दिल्ली, *2012-13*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 2.15: 2009-10 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जीडीपी का क्षेत्रीय संघटन

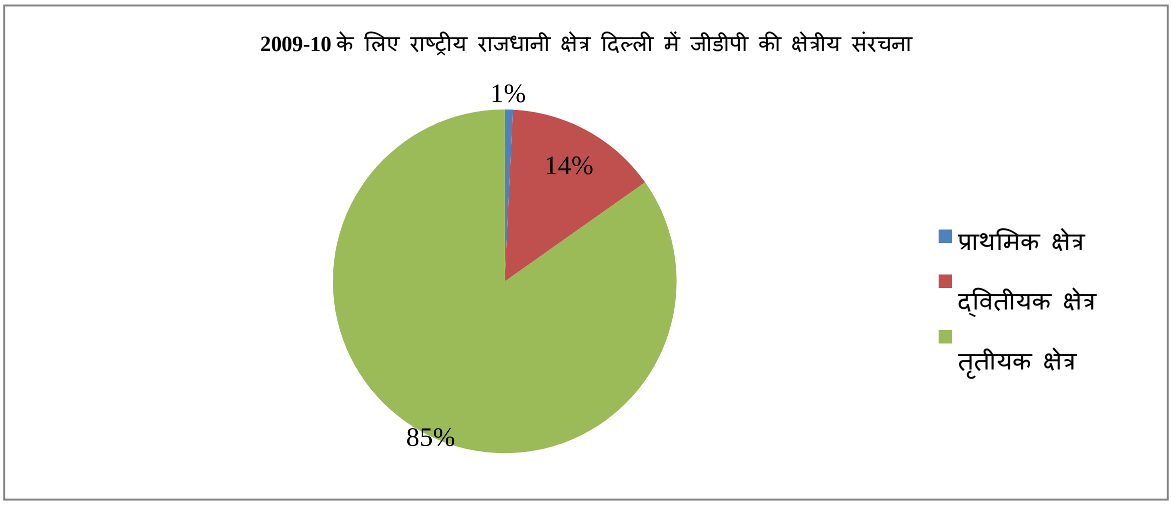

स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली; राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान, दिल्ली, *2012-13*

राजस्थान उप-क्षेत्र

राजस्थान उप-क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र (8 वर्षों के लिए 7.8% की औसत वृद्धि दर) में वृद्धि देखी गई है, जबकि माध्यमिक क्षेत्र में 9.5% की समान वृद्धि दर दर्ज की गई है और तृतीयक क्षेत्र में 7.3% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। इस प्रकार राजस्थान उप-क्षेत्र में, तीन क्षेत्रों के लिए वार्षिक औसत वृद्धि दर समान है।

प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर में व्यापक अंतर देखा गया है। 2001-02 और 2002-03 की अवधि के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में क्रमशः 8.7% और 23.7% की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। 2003-04 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर बहुत अधिक (67.7%) थी, जो 2004-05 के दौरान घटकर 11.4% हो गई। इसके बाद, 2005-06 (-6%) के दौरान विकास दर फिर से नकारात्मक थी और 2006-07 (23.4%) में फिर से सुधार हुआ, जबकि माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों ने क्रमशः 32% और 42% का योगदान दिया (तालिका 2.13 और चित्र 2.15 देखें)।

तालिका 2-11: 2001 से 2008 की अवधि के लिए एनसीआर के राजस्थान उप-क्षेत्र में जीडीपी की क्षेत्रवार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर

सेक्टर / फील्ड	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	AAGR
प्राथमिक क्षेत्र	-2.4	-8.7	-23.7	67.7	11.4	-6.0	23.4	0.8	7.8
द्वितीयक क्षेत्र	-5.8	11.4	15.7	8.9	-9.5	4.1	9.0	42.1	9.5
तृतीयक क्षेत्र	0.4	1.3	3.3	9.7	-7.8	4.3	15.6	31.4	7.3
राजस्थान उप-क्षेत्र	-2.4	1.6	-1.6	23.4	-2.1	1.3	15.6	26.0	7.7

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 2.16: एनसीआर के राजस्थान उप-क्षेत्र में जीडीपी की क्षेत्रीय संरचना

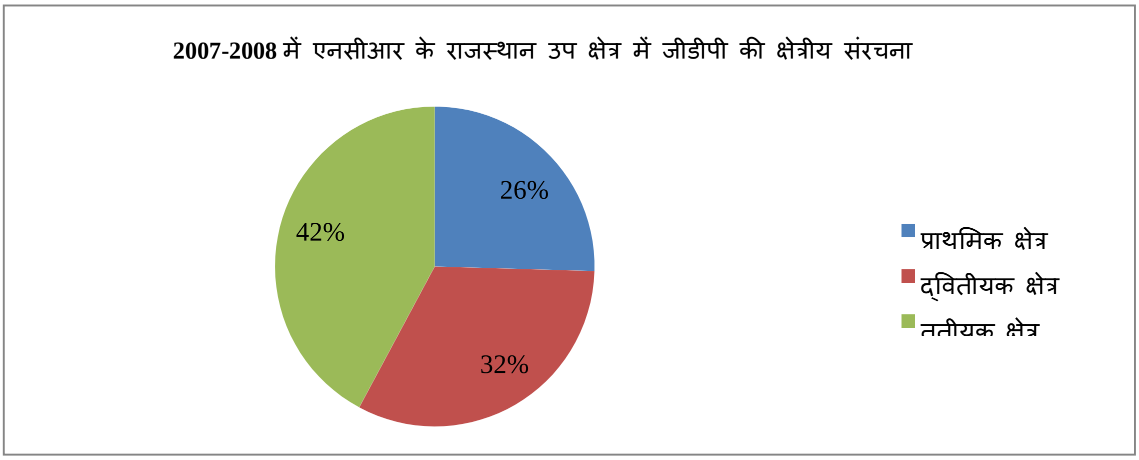

हरियाणा उप-क्षेत्र

हरियाणा उप-क्षेत्र में, रुझान 1999-2000 से 2007-2008 की अवधि के दौरान 10.3% की आठ वर्षों की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ तृतीयक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि का संकेत देते हैं। इसी अवधि में द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। हरियाणा उप-क्षेत्र 13.0% पर तीनों क्षेत्रों के लिए सामूहिक रूप से उच्चतम सीएजीआर प्रदर्शित करता है। 2000-2008 की अवधि में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों में 5.3% की सीएजीआर दर्ज की गई जबकि तृतीयक क्षेत्र में 9.8% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में लगातार गिरावट आ रही है जबकि समग्र हिस्सा तुलनात्मक रूप से नगण्य है।

सेकेंडरी सेक्टर ने 12.5 फीसदी की वृद्धि दर दर्ज की है, जिसका श्रेय रियल एस्टेट के बढ़ते विकास और ढांचागत परियोजनाओं को दिया जा सकता है। वर्ष 2007-08 में जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 33.1% था, जबकि तृतीयक क्षेत्र भी हरियाणा उप-क्षेत्र के समग्र सकल घरेलू उत्पाद के आधे से अधिक (56.4%) में योगदान करने वाले स्वस्थ विकास को दर्शाता है (चित्र 2.17 देखें)। विशेष रूप से पिछले दशक में माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि के संदर्भ में एनसीटी-दिल्ली और हरियाणा उप-क्षेत्र के जीडीपी विकास पैटर्न में समानताएं भी देखी गई हैं, (तालिका 2.14 और चित्र 2.17 देखें)।

तालिका 2-12: 2000-01 से 2007-08 की अवधि के लिए हरियाणा उप-क्षेत्र के जीडीपी की क्षेत्रवार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर

सेक्टर / फील्ड	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**AAGR**
प्राथमिक क्षेत्र	4.8	-3.2	-5.3	5.1	-10.0	7.3	4.1	4.1	0.8
द्वितीयक क्षेत्र	7.2	-9.1	6.3	10.8	-11.5	12.0	9.5	9.5	4.3
तृतीयक क्षेत्र	37.0	-13.8	11.7	9.9	-12.1	16.8	16.6	16.6	10.3
हरियाणा उप-क्षेत्र	**19.0**	**-10.3**	**7.1**	**9.6**	**-11.6**	**13.9**	**12.6**	**12.7**	**6.6**

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा; आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, उत्तर प्रदेश; आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, दिल्ली; आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, राजस्थान; योजना आयोग, भारत सरकार

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 2.17: 2007-08 में एनसीआर के हरियाणा उप-क्षेत्र में जीडीपी की क्षेत्रीय संरचना

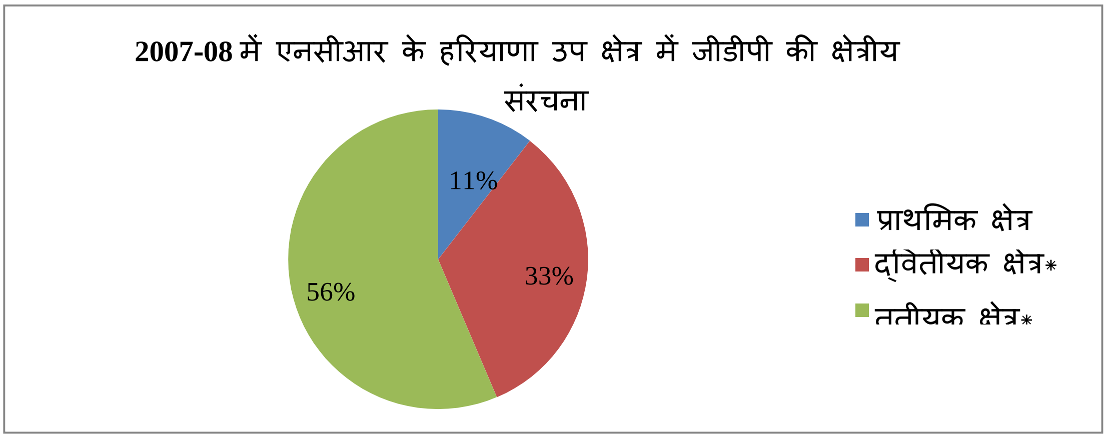

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

2008-09 में उप-क्षेत्र के जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने क्रमशः 18%, 40% और 42% का योगदान दिया (तालिका 2.11 देखें)। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र मुख्य रूप से गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद (हापुड़ सहित) के जिलों में विकसित किए गए हैं। उप क्षेत्र के जीडीपी में जिला बागपत का बहुत कम योगदान था, बशर्ते प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र से बेहतर हो (तालिका 2.15 और 2.16 और चित्र 2.18 देखें)।

तालिका 2-13: वर्ष 2008-09 के लिए स्थिर (2004-05) कीमतों पर यूपी उप-क्षेत्र की जीडीपी संरचना (करोड़ में)

सेक्टर / फील्ड	मेरठ	बागपत	गाज़ियाबाद +हापुड़	गौतमबुद्ध नगर	बुलदशहर	यूपी उप क्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्र	2,278.78	1,272.83	1,860.05	688	2,620.66	8,720.32
द्वितीयक क्षेत्र	2,707.88	587.92	5,113.81	8186.95	2,092.2	18,688.75
तृतीयक क्षेत्र	4,399.28	1,611.4	6,154.53	4236.44	3,620.88	20,022.5
जीडीपी	**9,385.94**	**3,472.15**	**13,128.39**	**13111.4**	**8,333.73**	**47,431.16**

स्रोत: *updes.up.nic.in*

तालिका 2-14: 2000-01 से 2007-08 की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के जीडीपी की क्षेत्रवार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर

सेक्टर / फील्ड	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	AAGR
प्राथमिक क्षेत्र	7.65%	-2.92%	3.90%	2.66%	6.15%	0.13%	6.75%	0.92%	3.15%
द्वितीयक क्षेत्र	-5.94%	0.31%	0.76%	4.98%	14.14%	7.39%	12.82%	12.26%	5.84%
तृतीयक क्षेत्र	13.18%	3.01%	3.86%	5.61%	8.17%	6.64%	6.60%	7.98%	6.88%
यूपी उप-क्षेत्र	4.75%	0.48%	2.86%	4.61%	9.53%	5.21%	8.75%	7.78%	5.50%

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 2.18: वर्ष 2008-09 के लिए स्थिर (2004-05) कीमतों पर उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के जीडीपी की क्षेत्रीय संरचना

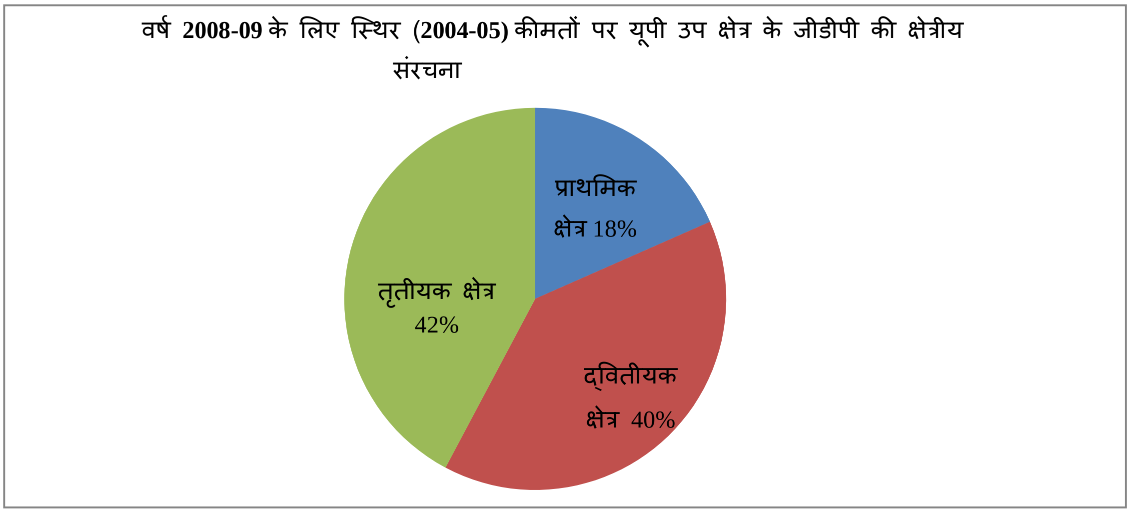

सभी उप-क्षेत्रों के लिए स्थिर मूल्यों (1999-2000) पर जीडीपी के क्षेत्र-वार योगदान का विवरण अनुलग्नक-2.4 में दिया गया है।

2.4 जीडीपी का अनुमान

वर्ष 2004-05 से 2009-2010 की अवधि के लिए गणना किए गए सीएजीआर के आधार पर 2004-05 से 2009-10 की स्थिर कीमतों पर हैंड्स-ऑफ परिदृश्य के साथ जीडीपी अनुमान वर्ष 2021 और 2031 के लिए बनाए गए हैं (अनुलग्नक-2.3 और तालिका 2.17 देखें)। विभिन्न कारकों के प्रभाव से अनुमानित आंकड़ों से विचलित हो सकते हैं। अभी भी अनुमानित आंकड़े क्षेत्र के आर्थिक विकास के रुझानों का एक उचित विचार देते हैं। चार सबसे महत्वपूर्ण कारकों का प्रभाव अर्थात्; भौतिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि, श्रम शक्ति में वृद्धि, मानव पूंजी विकास और तकनीकी प्रगति, एनसीआर की जीडीपी वृद्धि को प्रभावित करेगी।

2004-05 से 2009-10 तक सीएजीआर पर आधारित अनुमानों के अनुसार, 2021 और 2031 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों (2004-05) पर 2009-10 में जीडीपी के क्रमशः तीन गुना और नौ गुना हो जाएगी। 2031 तक, गुड़गांव और पानीपत 2009-10 के स्तर से जीडीपी में क्रमशः 7.5 गुना और 5.7 गुना वृद्धि दर्ज होगी (अनुबंध 2.3 और तालिका 2.17 देखें)।

एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र

एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र के जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का मुख्य योगदान है। मानव पूंजी विकास और तकनीकी प्रगति क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होंगे। एनसीटी-दिल्ली को हाई-टेक उद्योग और व्यापार केंद्र के केंद्र के रूप में विकसित करने से जीडीपी के उच्च स्तर को बढ़ावा मिलेगा। एनसीआर के संतुलित विकास से एनसीटी-दिल्ली में श्रमिकों का पलायन कम होगा। एनसीटी-दिल्ली की जीडीपी में 2021 तक 3.18 गुना और 2009-10 में जीडीपी के 9.13 गुना बढ़ने का अनुमान है, स्थिर (2004-05) कीमतों पर (तालिका 2.17 देखें)।

हरियाणा उप-क्षेत्र

हरियाणा उप-क्षेत्र के जीडीपी में 2021 तक 3.40 गुना और 2009-10 में जीडीपी के 10.35 गुना बढ़ने का अनुमान

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

है, स्थिर (2004-05) कीमतों पर (तालिका 2.17 देखें)।

गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों ने पहले ही उच्च स्तर का भौतिक पूंजी स्टॉक बना लिया है और प्रमुख उद्योग केंद्रों के रूप में उभरे हैं। आने वाले वर्षों में इसका इन दोनों जिलों के जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अनुमानित मूल्य को सकारात्मक तरीके से बदल देगा। हालांकि, उच्च जीडीपी का स्तर उच्च अचल संपत्ति की कीमतों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मजबूत आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के प्रवेश के कारण हो सकता है और जब तक इन उच्च स्तरों का प्रबंधन नहीं किया जाता है, अनुमानित जीडीपी कम हो सकता है।

बड़ी संख्या में शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों की उपस्थिति के कारण रोहतक और झज्जर जिलों में सकारात्मक विकास की संभावना है। अच्छी गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के विकास और दिल्ली से निकटता का मतलब है कि झज्जर दिल्ली के स्पिलओवर लाभों को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से स्थित है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र और उच्च स्तरीय शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान जैसी पहल इन जिलों को तकनीकी प्रगति के अगले स्तर तक ले जा सकती है।

रेवाड़ी और पानीपत जिलों में मुख्य रूप से आसपास के क्षेत्रों से कुशल श्रमिकों के प्रवास के कारण श्रमिकों की उपलब्धता में वृद्धि का अनुभव हो रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि केएमपी एक्सप्रेसवे, डीएमआईसी (रेवाड़ी के लिए) आदि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इन जिलों में और निवेश आकर्षित करेंगी।

मेवात और पलवल नव निर्मित जिले हैं। भौतिक और मानव पूंजी की उपलब्धता, नवाचार और प्रौद्योगिकी स्तर जैसे लगभग सभी मोर्चों पर मेवात पीछे है। हालांकि, पलवल जिले में भौतिक और मानवीय दोनों तरह की पर्याप्त पूंजी का निवेश किया जा रहा है जो जीडीपी विकास के उच्च स्तर के लिए आधार प्रदान कर सकता है।

सोनीपत जिले में बुनियादी ढांचे के विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास से संबंधित काफी बड़ी संख्या में पहल की जा रही है। इनका क्षेत्र के दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के जीडीपी में 2021 तक 2.52 गुना और 2009-10 में जीडीपी के 5.86 गुना स्थिर (2004-05) कीमतों पर बढ़ने का अनुमान है (तालिका 2.17 देखें)।

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद पहले से ही उच्च विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र (येडा) में आने वाली ढांचागत परियोजनाओं का जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

बागपत और मेरठ में विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं लेकिन मानव पूंजी विकास और तकनीकी प्रगति में कम हैं। नतीजतन, औसत जीडीपी विकास दर की उम्मीद है।

बुलंदशहर में भौतिक और मानव पूंजी की उपलब्धता का भी अभाव है, और कम तकनीकी प्रगति से सीमित है। जिले में शैक्षिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की अपर्याप्त संख्या है और सीएजीआर के वर्तमान कम स्तर पर जीडीपी वृद्धि की संभावना है।

राजस्थान उप-क्षेत्र

राजस्थान उप-क्षेत्र के जीडीपी में 2021 तक 2.71 गुना और 2009-10 में जीडीपी के 6.73 गुना स्थिर (2004-05) कीमतों पर बढ़ने का अनुमान है (तालिका 2.17 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

हालांकि जीडीपी विकास दर की वर्तमान दर कम है, राज्य सरकार इस उप-क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश कर रही है। सारांश,

- हरियाणा उप-क्षेत्र में उच्चतम सीएजीआर 11.77% (2004-05 और 2009-10 के बीच) दर्ज किया गया है जो दिल्ली के एनसीटी (11.10%) और पूरे एनसीआर के सीएजीआर से भी अधिक है।
- उक्त अवधि के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्रों के लिए सीएजीआर का अनुमान क्रमशः 9.50% और 8.78% लगाया गया है।
- दो जिले अर्थात, उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के बागपत और बुलंदशहर में 5% से अधिक सीएजीआर का प्रबंधन करने का अनुमान है।
- उपरोक्त अवधि के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले के जीडीपी का सीएजीआर उच्चतम (14.00%) है, इसके बाद फरीदाबाद (11.28%), गुड़गांव (10.08%), झज्जर (9.65%), मेवात (9.77%), सोनीपत (9.74%), गाजियाबाद (8.86%), पानीपत (8.63%), और रेवाड़ी (8.61%) जिले का स्थान है।
- एनसीटी-दिल्ली और हरियाणा उप-क्षेत्र में फरीदाबाद जिले और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में गौतमबुद्ध नगर जिले में पूरे एनसीआर की तुलना में अनुमानित सीएजीआर अधिक है।

तालिका 2-15: 2009-10 के लिए एनसीआर का जीडीपी और 2021 से 2031 के लिए स्थिर (2004-05) कीमतों पर अनुमानित जीडीपी

रूपया लाखों में

उप-क्षेत्र/जिला	**(2004-05) में** स्थिर कीमतों पर **2009-10 में** जीडीपी	**2004-05 और 2009-10 के** बीच सीएजीआर (%)	**2021 के** लिए अनुमानित जीडीपी	**2031 के** लिए अनुमानित जीडीपी
मेरठ	1,01,254.56	7.13	2,15,962	4,29,966
बागपत	38,426.16	5.74	70,980	1,24000
गाजियाबाद+हापुड़	1,36,475.9	8.86	3,47,226	8,11,521
गौतमबुद्ध नगर	1,41,557.06	14.00	5,98,025	22,16,243
बुलंदशहर	88,739.5	5.22	1,55,341	2,58,433
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र का योग	**5,06,453.18**	**8.78**	**12,78,687**	**29,67,724**
दिल्ली	16,98,389.8	11.10	54,07,842	1,54,98,318
दिल्ली उप-क्षेत्र का योग	**16,98,389.8**	**11.10**	**54,07,842**	**1,54,98,318**
अलवर	1,21,901	9.50	3,30,935	8,20,441
राजस्थान उप-क्षेत्र का योग	**1,21,901**	**9.50**	**3,30,935**	**8,20,441**
फरीदाबाद	1,90,014.6	11.28	6,15,728	17,92,966
गुड़गांव	2,69,905.5	10.08	7,76,230	20,27,973
झज्जर	44,947.9	9.65	1,23,834	3,11,144
पानीपत	99,297.5	8.63	2,46,841	5,64,863
रेवाड़ी	65,930.6	8.61	1,63,564	3,73,606
रोहतक	47,052.3	7.72	1,06,578	2,24,118
सोनीपत	77,067.6	9.74	2,14,314	5,43,060

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

उप-क्षेत्र/जिला	(2004-05) में स्थिर कीमतों पर 2009-10 में जीडीपी	2004-05 और 2009-10 के बीच सीएजीआर (%)	2021 के लिए अनुमानित जीडीपी	2031 के लिए अनुमानित जीडीपी
मेवात	29,967.8	9.77	83,590	2,12,400
पलवल	42,546.5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
हरियाणा उप-क्षेत्र का योग	**8,66,730.3**	**11.77**	**29,48,453**	**89,73,610**
कुल योग/एनसीआर	**3,19,3474.28**	**10.83**	**98,94,847**	**2,76,63,372**

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान*;* दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण, *2012-13;* अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग, हरियाणा*; updes.up.nic.in;* और एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल पर अध्ययन

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

3. कर्मचारी

3.1 पृष्ठभूमि

किसी अर्थव्यवस्था की संरचना को समझने के लिए रोजगार स्तर एक महत्वपूर्ण संकेतक है। योजना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, औद्योगिक विकास और जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हालांकि, रोजगार की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर से काफी कम थी।

हालांकि, 2008 के वैश्विक संकट से उबरने की भारत की क्षमता को काफी हद तक सरकार की हालिया नीतियों और ज्यादातर स्वतंत्र स्थिर स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, शिक्षित, कुशल और प्रशिक्षित युवा आबादी की उपलब्धता के कारण रोजगार में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। एनसीआर कर्मचारी की प्रमुख विशेषताओं और एनसीआर की अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव को समझना और अधिक रुचिकर होगा।

एनसीआर जनसंख्या और रोजगार के मामले में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। ऐतिहासिक रूप से, एनसीटी-दिल्ली न केवल दिल्ली में बढ़ते कर्मचारी के लिए बल्कि प्रवासी आबादी के लिए भी रोजगार सृजन का मुख्य केंद्र बना रहा। नतीजतन, एनसीआर की अर्थव्यवस्था को न केवल एनसीटी-दिल्ली में बल्कि एनसीआर के अन्य उप-क्षेत्रों में भी नए आगंतुकों को श्रम बल में लगाने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करने की जरुरत है। चूंकि एनसीआर भारत के शीर्ष पांच आर्थिक केंद्रों में से एक है, रोजगार के रुझान को समझना और एनसीआर में औपचारिक रोजगार के विकास के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय रोजगार और कर्मचारी के उभरते रुझानों को प्रस्तुत करता है।

3.2 एनसीआर में श्रमिकों का वितरण

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, एनसीआर भारत के कुल श्रमिकों का 3.27% है, जो 2001 में 3.23% से मामूली रूप से बढ़ा है (तालिका 3.1 देखें)। श्रमिकों की कुल संख्या के उप-क्षेत्रवार वितरण का विश्लेषण इंगित करता है कि एनसीटी-दिल्ली (43.07%) में एनसीआर में श्रमिकों की सबसे अधिक हिस्सेदारी है, इसके बाद उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (36.77%), हरियाणा उप-क्षेत्र (28.29%) है।) और राजस्थान उप-क्षेत्र (13.17%)। एनसीटी-दिल्ली में कुल श्रमिकों की संख्या 33.51% से बढ़कर 43.07% हो गई है, जिसने एनसीआर में उच्चतम विकास दर दर्ज की है, जिसका अर्थ है कि श्रमिकों की एकाग्रता मुख्य रूप से एनसीटी-दिल्ली में केंद्रित है।

तालिका 3-1: 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमिकों की कुल संख्या में एनसीआर का हिस्सा

वर्ष	एनसीआर	भारत	भारत में एनसीआर का हिस्सा %
2001	1,29,72,094	40,22,34,724	3.23%
2011	1,57,34,929	48,18,88,868	3.27%

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001 और 2011

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 3-2: एनसीआर में श्रमिकों की कुल संख्या में उप-क्षेत्रों का हिस्सा

वर्ष	एनसीआर	एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र		हरियाणा उप-क्षेत्र		राजस्थान उप-क्षेत्र		उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	
		श्रमिकों की संख्या	एनसीआर में % हिस्सा	श्रमिकों की संख्या	एनसीआर में % हिस्सा	श्रमिकों की संख्या	एनसीआर में % हिस्सा	श्रमिकों की संख्या	एनसीआर में % हिस्सा
2001	1,29,72,094	43,46,710	33.51%	34,14,662	26.32%	14,58,686	11.24%	37,52,036	28.92%
2011	1,57,34,929	55,87,049	43.07%	36,69,197	28.29%	17,08,542	13.17%	47,70,141	36.77%

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001 और 2011

3.3 कर्मचारी की भागीदारी दर

3.3.1 एनसीआर और उप-क्षेत्र स्तर पर कर्मचारी का श्रेणीवार वितरण

2011 के लिए एनसीआर में कर्मचारी भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) 34.15% है। यह देखा गया है कि 1991-2001 की अवधि के दौरान एनसीटी-दिल्ली में कर्मचारी की भागीदारी की प्रवृत्ति धीमी हो गई है, जबकि बाद में इसी अवधि के भीतर हरियाणा, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों के लिए इसमें वृद्धि हुई है। लेकिन बाद के दशक में, यानी 2001-2011 में, एनसीटी-दिल्ली में कर्मचारी भागीदारी दर में वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में यह वही रहा है, जबकि हरियाणा और राजस्थान के अन्य उप-क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान गिरावट देखी गई है। यह देखा गया है कि राजस्थान उप-क्षेत्र ने उच्चतम डब्लूपीआर (46.50) दर्ज किया है और हरियाणा उप-क्षेत्र ने सबसे कम डब्लूपीआर (33.26) दर्ज किया है (तालिका 3.3 देखें)।

तालिका 3-3: एनसीआर की कर्मचारी भागीदारी दर, 1971-2011

वर्ष	भारत	एनसी आर	एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	हरियाणा उप-क्षेत्र	राजस्थान उप-क्षेत्र	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र
1971	34.2	27.4	30.20	25.02	26.40	27.20
1981	35.7	28.7	31.80	27.70	25.60	27.00
1991	37.4	29.17	31.51	28.35	28.33	27.48
2001	39.1	34.20	29.14	39.69	49.31	32.75
2011	39.8	34.15	33.28	33.26	46.50	32.73

स्रोत: भारत की जनगणना, *1971, 1981, 1991, 2001, 2011*

2011 में, एनसीआर ने 15,734,929 का कुल कर्मचारी दर्ज किया है जिसमें एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र ने श्रमिकों की अधिकतम संख्या (587,049) का योगदान दिया है, जबकि राजस्थान उप-क्षेत्र में एनसीआर में कुल श्रमिकों का सबसे कम हिस्सा है, हालांकि इसमें अधिकतम डब्ल्यूपीआर है (देखें। तालिका 3.4)

तालिका 3-4: एनसीआर और उप-क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या: 2011

उप-क्षेत्र	कुल श्रमिक	%
हरियाणा उप-क्षेत्र	36,69,197	23.3
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	47,70,141	30.3
राजस्थान उप-क्षेत्र	17,08,542	10.9
एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र	55,87,049	35.5

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

एनसीआर	1,57,34,929	100

स्रोत: भारत की जनगणना, *2011*

यह देखा गया है कि 2001 में एनसीआर में कर्मचारियों और खेतिहर मजदूरों का सबसे बड़ा हिस्सा (25.53%) था, इसके बाद निर्माण श्रमिकों (16%) का नंबर आता है। एनसीआर में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है और तृतीयक (सेवा) और द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 1971 में 44.3% से घटकर 2001 में 29.06% हो गया है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 1971 में 18.98% से बढ़कर 2001 में 42.63% हो गया है। प्राथमिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात एनसीटी-दिल्ली में सबसे कम है। प्राथमिक क्षेत्र के भीतर, काश्तकारों और खेतिहर मजदूरों की हिस्सेदारी 1971 में 42.98% से घटकर 2001 में 25.53% हो गई, जबकि द्वितीयक क्षेत्र के भीतर निर्माण घटक का हिस्सा 1971 में 2.77% से बढ़कर 2001 में 16.2 हो गया (तालिका 3.5 और चित्र 3.1 को देखें)

तालिका 3-5: एनसीआर में मुख्य कर्मचारी का वितरण (1971, 1991 और 2001)

वर्ष	**1971**		**1991**		**2001**	
श्रमिकों की श्रेणी	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	**%**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
किसान	12,70,942	32.66	17,90,347	23.16	27,33,141*	25.53
कृषि मजदूर	4,01,725	10.32	8,21,188	10.62	-	-
पशुपालन, वानिकी आदि।	44,485	1.14	58,378	0.76	3,39,775	3.17
खनन और उत्खनन	6,457	0.17	13,884	0.18	38,098	0.36
उप-कुल प्राथमिक क्षेत्र	**17,23,609**	**44.3**	**26,83,797**	**34.71**	**31,11,014**	**29.06**
a) घरेलू उद्योग	1,66,572	4.28	1,28,661	1.66	7,73,216	7.22
b) घरेलू उद्योगों के अलावा	4,64,125	11.93	12,81,140	16.57	4,60,199	4.3
बिजली, गैस और पावर	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	7,08,680	6.62
निर्माण	1,07,937	2.77	3,54,049	4.58	17,34,125	16.2
ग्रामीण उद्योग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	8,86,977	8.29
उप-कुल द्वितीयक क्षेत्र	**7,38,634**	**18.98**	**17,63,850**	**22.81**	**45,63,197**	**42.63**
व्यापार एवं वाणिज्य	4,14,000	10.64	11,37,207	14.71	7,94,641	7.42
परिवहन, भंडारण और संचार	1,84,839	4.75	4,11,842	5.33	12,48,730	11.67
अन्य सेवाएं	8,29,850	21.33	17,34,993	22.44	9,92,787	9.28
उप-कुल तृतीयक क्षेत्र	**14,28,689**	**36.72**	**32,84,042**	**42.48**	**30,36,158**	**28.37**
कुल मुख्य श्रमिक	**38,90,932**	**100**	**77,31,689**	**100**	**1,07,03,664**	**100**

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

वर्ष	1971		1991		2001	
श्रमिकों की श्रेणी	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
भागीदारी अनुपात	**27.4**		**29**		**28.85**	

स्रोत: जनगणना *1971*, *1991* और *2001* भारत की जनगणना, * में कृषि श्रम भी शामिल है

उप-क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न श्रेणियों में श्रमिकों की एकाग्रता के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में खेती करने वालों और खेतिहर मजदूरों की संख्या सबसे अधिक (40.64%) है, इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र (35.56%) का स्थान है। निर्माण गतिविधि के मामले में, सबसे ज्यादा अधिकता एनसीटी-दिल्ली (58.92%) में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (21.68%) का है (तालिका 3.6 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 3-6: एनसीआर और उप-क्षेत्रों में मुख्य श्रमिकों का वितरण: 2001

उप-क्षेत्र	कृषि मजदूर और किसान		पशुपालन, वानिकी आदि		ग्रामीण उद्योग		खनन और उत्खनन		घरेलू उद्योग		घरेलू उद्योगों के अलावा		बिजली, गैस और पावर		निर्माण		व्यापार एवं वाणिज्य		परिवहन, भंडारण और संचार		अन्य सेवाएं		कुल मुख्य कर्मचारी	
	श्रमिक	%	**श्रमिक**	%	**श्रमिक**	%	**श्रमिक**	%	**श्रमिक**	%	**श्रमिक**	%	**श्रमिक**	%	**श्रमिक**	%	**श्रमिक**	%	**श्रमिक**	%	**श्रमिक**	%	**श्रमिक**	%
हरियाणा	9,72,007	35.56	1,23,965	36.48	1,57,144	17.72	15,346	40.28	1,77,695	22.98	1,18,260	25.7	1,54,406	21.79	2,72,617	15.72	1,35,515	17.05	2,14,100	17.15	1,75,002	17.63	25,16,057	23.51
उत्तर प्रदेश	11,10,693	40.64	1,46,294	43.06	2,24,482	25.31	3,348	8.79	1,58,564	20.51	1,02,794	22.34	1,72,967	24.41	3,75,954	21.68	1,58,929	20	2,78,696	22.32	1,89,783	19.12	29,22,504	27.3
राजस्थान	6,11,306	22.37	35,375	10.41	35,632	4.02	4,299	11.28	36,437	4.71	14,843	3.23	38,311	5.41	63,738	3.68	34,581	4.35	32,487	2.6	40,578	4.09	9,47,587	8.85
एनसीटी-दिल्ली	39,135	1.43	34,141	10.05	4,69,719	52.96	15,105	39.65	4,00,520	51.8	2,24,302	48.74	3,42,996	48.4	10,21,816	58.92	4,65,616	58.59	7,23,447	57.93	5,87,424	59.17	43,17,516	40.34
एनसीआर	**27,33,141**	**100**	**3,39,775**	**100**	**8,86,977**	**100**	**38,098**	**100**	**7,73,216**	**100**	**4,60,199**	**100**	**7,08,680**	**100**	**17,34,125**	**100**	**7,94,641**	**100**	**1,24,8730**	**100**	**9,92,787**	**100**	**1,07,03,664**	**100**

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001

2001 में कुल कर्मचारी (नौ श्रेणियां), मुख्य कर्मचारी, सीमांत कर्मचारी, शहरी कर्मचारी और ग्रामीण कर्मचारी का जिला-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-3.1 से अनुलग्नक-3.5 में दिया गया है। कर्मचारी के वितरण का विवरण (शहरी और ग्रामीण में अलग-अलग मुख्य और सीमांत में) और ग्रामीण और शहरी कर्मचारी की भागीदारी दर का विवरण क्रमशः अनुबंध-3.6 और 3.7 में दिया गया है।

चित्र 3.1: 2001 में एनसीआर में कर्मचारी का वितरण

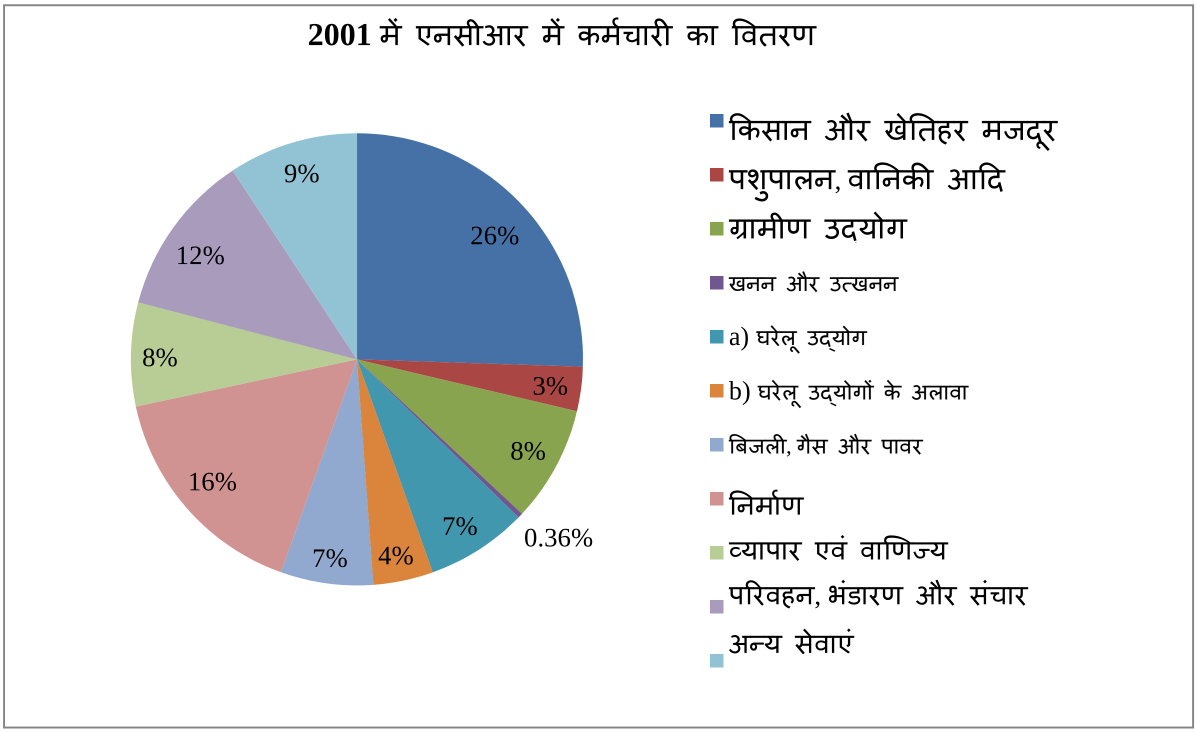

3.3.2 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कर्मचारी का वितरण

एनसीआर स्तर पर, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों (32.98%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (36.13%) में कर्मचारी भागीदारी दर अधिक है। ग्रामीण और शहरी कर्मचारी भागीदारी दर के बीच सबसे अधिक अंतर राजस्थान उप-क्षेत्र में देखा गया है, जहां शहरी डब्ल्यूपीआर (33.71%) की तुलना में ग्रामीण डब्ल्यूपीआर (49.27%) यानी 15.56% अधिक है। राजस्थान उप-क्षेत्र ने 46.50% पर सभी उप-क्षेत्रों में उच्चतम समग्र डब्ल्यूपीआर दर्ज किया है, इसके बाद एनसीटी-दिल्ली (33.28%), हरियाणा उप-क्षेत्र (33.26%) और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (32.73%) हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान उप-क्षेत्र ने उच्चतम डब्ल्यूपीआर (49.27%) दर्ज किया है और एनसीटी -दिल्ली ने सबसे कम डब्ल्यूपीआर (31.08%) दर्ज किया है, जिसका अर्थ है कि राजस्थान उप-क्षेत्र में कर्मचारी की एक उच्च प्राथमिक क्षेत्र संरचना और एनसीटी दिल्ली में कर्मचारी की उच्च तृतीयक क्षेत्र संरचना है। शहरी कर्मचारी की भागीदारी दर राजस्थान उप-क्षेत्र में सबसे अधिक 33.71% है, इसके बाद दिल्ली क्षेत्र में 33.34% और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में 32.07% है। हरियाणा उप-क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी कर्मचारी भागीदारी दर (0.50%) के बीच सबसे कम अंतर देखा गया है (तालिका 3.7 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 3-7: 2011 में उप-क्षेत्रवार ग्रामीण और शहरी कर्मचारी भागीदारी दर

क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	कुल
एनसीटी दिल्ली	31.08	33.34	33.28
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	33.34	32.07	32.73
हरियाणा उप-क्षेत्र	33.48	32.98	33.26
राजस्थान उप-क्षेत्र	49.27	33.71	46.50
एनसीआर	**36.13**	**32.98**	**34.15**

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल पर अध्ययन, भारत की जनगणना *2011*

3.3.3 मुख्य, सीमांत और गैर-श्रमिकों का वितरण

एनसीआर में कुल कर्मचारी में मुख्य और सीमांत श्रमिकों की उप-क्षेत्रवार हिस्सेदारी का विश्लेषण इंगित करता है कि मुख्य श्रमिकों का हिस्सा 84.11% से अधिक है और शेष 15.89% कुल कर्मचारी में सीमांत श्रमिक हैं। कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य कर्मचारियों की सबसे अधिक हिस्सेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उप-क्षेत्र (94.99%) में देखी गई है, इसके बाद उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (80.12%), हरियाणा उप-क्षेत्र 79.73% और राजस्थान उप-क्षेत्र (69.03%) का स्थान है।) एनसीआर के सभी उप क्षेत्रों में, कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों की हिस्सेदारी सीमांत श्रमिकों से अधिक है, एनसीटी-दिल्ली में मुख्य श्रमिकों (31.61%) और सीमांत श्रमिकों (1.67%) के बीच 29.95% का सबसे ज्यादा अंतर है। राजस्थान उप-क्षेत्र ने कुल श्रमिकों (30.97%) में सीमांत श्रमिकों का सबसे ज्यादा हिस्सा दर्ज किया है, इसके बाद हरियाणा (20.27%), उत्तर प्रदेश (19.88%) और एनसीटी-दिल्ली (5.01%) उप-क्षेत्र हैं। यह इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि राजस्थान उप-क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारी का काफी अधिक अनुपात प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है, जैसा कि बाद के खंड में बताया गया है।

हरियाणा उप-क्षेत्र में, सबसे कम डब्ल्यूपीआर मेवात जिले (26.62%) में देखा गया है, जैसा कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। रेवाड़ी जिले में सबसे अधिक कर्मचारी भागीदारी दर 37.15 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में, मेरठ में सबसे कम डब्ल्यूपीआर (31.67%) है। उच्चतम डब्ल्यूपीआर गौतमबुद्ध नगर में 34.53% पर देखा गया है, यह मुख्य रूप से जिले में हाल ही में अचल संपत्ति और आईटी क्षेत्र में उछाल के कारण हो सकता है।

एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में उच्चतम कर्मचारी भागीदारी दर नई दिल्ली जिले (41.93%) में है, जिसकी एनसीटी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर दोनों जिलों में सबसे कम 142,004 है। यह नई दिल्ली जिले में उद्योग और विनिर्माण आधारित रोजगार के अवसरों की कमी के कारण हो सकता है, इस प्रकार ये श्रमिक वर्ग के प्रवासियों को आकर्षित नहीं करते हैं। सबसे कम डब्ल्यूपीआर उत्तर-पूर्वी जिले (29.50%) में है, जिसकी जनसंख्या 22,41,624 (2011 की जनगणना के अनुसार) है। यह गुड़गांव और नोएडा जैसे जिले में उपलब्ध रोजगार के बढ़ते अवसरों के कारण हो सकता है, जो प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित करता है। समग्र रूप से, दिल्ली उप-क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र पर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की प्रधानता के कारण सीमांत-श्रमिकों की संख्या कम है (तालिका 3.8, चित्र 3.2 और मानचित्र 3.1 और 3.2 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 3-8: एनसीआर में जिलेवार कर्मचारी की भागीदारी दर: 2011

उप-क्षेत्र	जिला	जनसंख्या	कुल श्रमिक	कर्मचारी भागीदारी दर	मुख्य श्रमिक		सीमांत श्रमिक		गैर श्रमिक
					संख्या	कुल श्रमिकों का %	संख्या	कुल श्रमिकों का %	
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	उत्तर पश्चिम	36,56,539	11,88,545	32.50%	11,35,126	95.51%	53,419	4.49%	24,67,994
	उत्तर	8,87,978	2,96,446	33.38%	2,83,583	95.66%	12,863	4.34%	5,91,532
	उत्तर पूर्व	22,41,624	6,61,386	29.50%	6,22,443	94.11%	38,943	5.89%	15,80,238
	पूर्व	17,09,346	5,79,692	33.91%	5,55,026	95.74%	24,666	4.26%	11,29,654
	नई दिल्ली	1,42,004	59,541	41.93%	56,471	94.84%	3,070	5.16%	82,463
	केंद्रीय	5,82,320	2,07,374	35.61%	1,95,978	94.50%	11,396	5.50%	3,74,946
	पश्चिम	25,43,243	8,74,320	34.38%	8,39,621	96.03%	34,699	3.97%	16,68,923
	दक्षिण पश्चिम	22,92,958	7,95,352	34.69%	7,49,995	94.30%	45,357	5.70%	14,97,606
	दक्षिण	27,31,929	9,24,393	33.84%	8,69,086	94.02%	55,307	5.98%	18,07,536
	एनसीटी-दिल्ली	**1,67,87,941**	**55,87,049**	**33.28%**	**53,07,329**	**94.99%**	**2,79,720**	**5.01%**	**1,12,00,892**
हरियाणा उप-क्षेत्र	फरीदाबाद	18,09,733	5,79,229	32.01%	4,95,316	85.51%	83,913	14.49%	12,30,504
	गुडगाँव	15,14,432	5,44,716	35.97%	4,87,441	89.49%	57,275	10.51%	9,69,716
	रेवाड़ी	9,00,332	3,37,727	37.51%	2,50,219	74.09%	87,508	25.91%	5,62,605
	रोहतक	10,61,204	3,45,967	32.60%	2,88,949	83.52%	57,018	16.48%	7,15,237
	सोनीपत	14,50,001	5,23,179	36.08%	3,96,763	75.84%	1,26,416	24.16%	9,26,822
	पानीपत	12,05,437	4,12,318	34.20%	3,39,016	82.22%	73,302	17.78%	7,93,119
	झज्जर	9,58,405	3,26,534	34.07%	2,46,457	75.48%	80,077	24.52%	6,31,871
	मेवात	10,89,263	2,89,964	26.62%	2,04,178	70.41%	85,786	29.59%	7,99,299
	पलवल	10,42,708	3,09,563	29.69%	2,16,932	70.08%	92,631	29.92%	7,33,145
	हरियाणा उप-क्षेत्र	**1,10,31,515**	**36,69,197**	**33.26%**	**29,25,271**	**79.73%**	**7,43,926**	**20.27%**	**73,62,318**
राजस्थान उप-क्षेत्र	अलवर	36,74,179	17,08,542	46.50%	11,79,461	69.03%	5,29,081	30.97%	19,65,637
	राजस्थान उप-क्षेत्र	**36,74,179**	**17,08,542**	**46.50%**	**11,79,461**	**69.03%**	**5,29,081**	**30.97%**	**19,65,637**
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	बागपत	13,03,048	4,16,695	31.98%	3,34,519	80.28%	82,176	19.72%	8,86,353
	बुलंदशहर	34,99,171	11,73,260	33.53%	8,85,216	75.45%	2,88,044	24.55%	23,25,911
	गौतमबुद्ध नगर	16,48,115	5,69,109	34.53%	4,58,492	80.56%	1,10,617	19.44%	10,79,006

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

	गाजियाबाद + हापुड़	46,81,645	15,20,538	32.48%	12,52,911	82.40%	2,67,627	17.60%	31,61,107
	मेरठ	34,43,689	10,90,539	31.67%	8,90,810	81.69%	1,99,729	18.31%	23,53,150
	यूपी उप-क्षेत्र	**1,45,75,668**	**47,70,141**	**32.73%**	**38,21,948**	**80.12%**	**9,48,193**	**19.88%**	**98,05,527**
एनसीआर		**4,60,69,303**	**1,57,34,929**	**34.15%**	**1,32,34,009**	**84.11%**	**25,00,920**	**15.89%**	**3,03,34,374**

स्रोत: भारत की जनगणना, *2011*

चित्र 3.2: 2011 में एनसीआर में कुल कर्मचारी में मुख्य और सीमांत श्रमिकों का उप-क्षेत्रवार हिस्सा

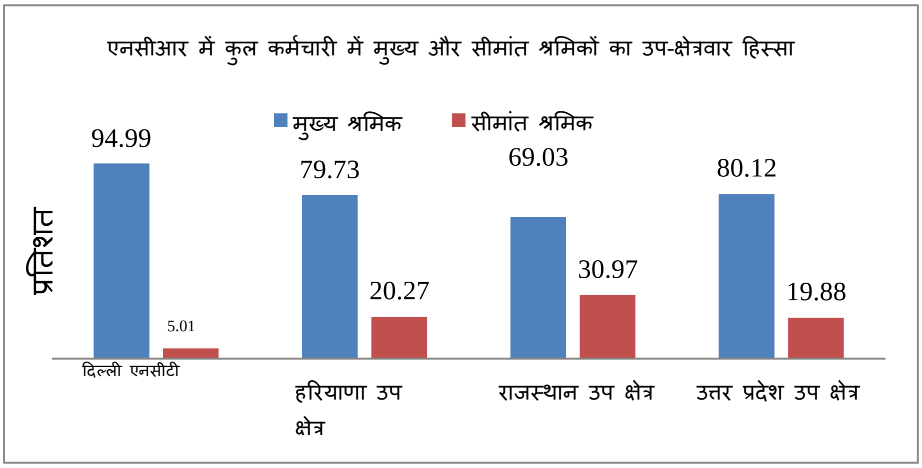

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मानचित्र 3.1: वर्ष 2011 में एनसीआर में जिलेवार श्रमिकों की भागीदारी दर

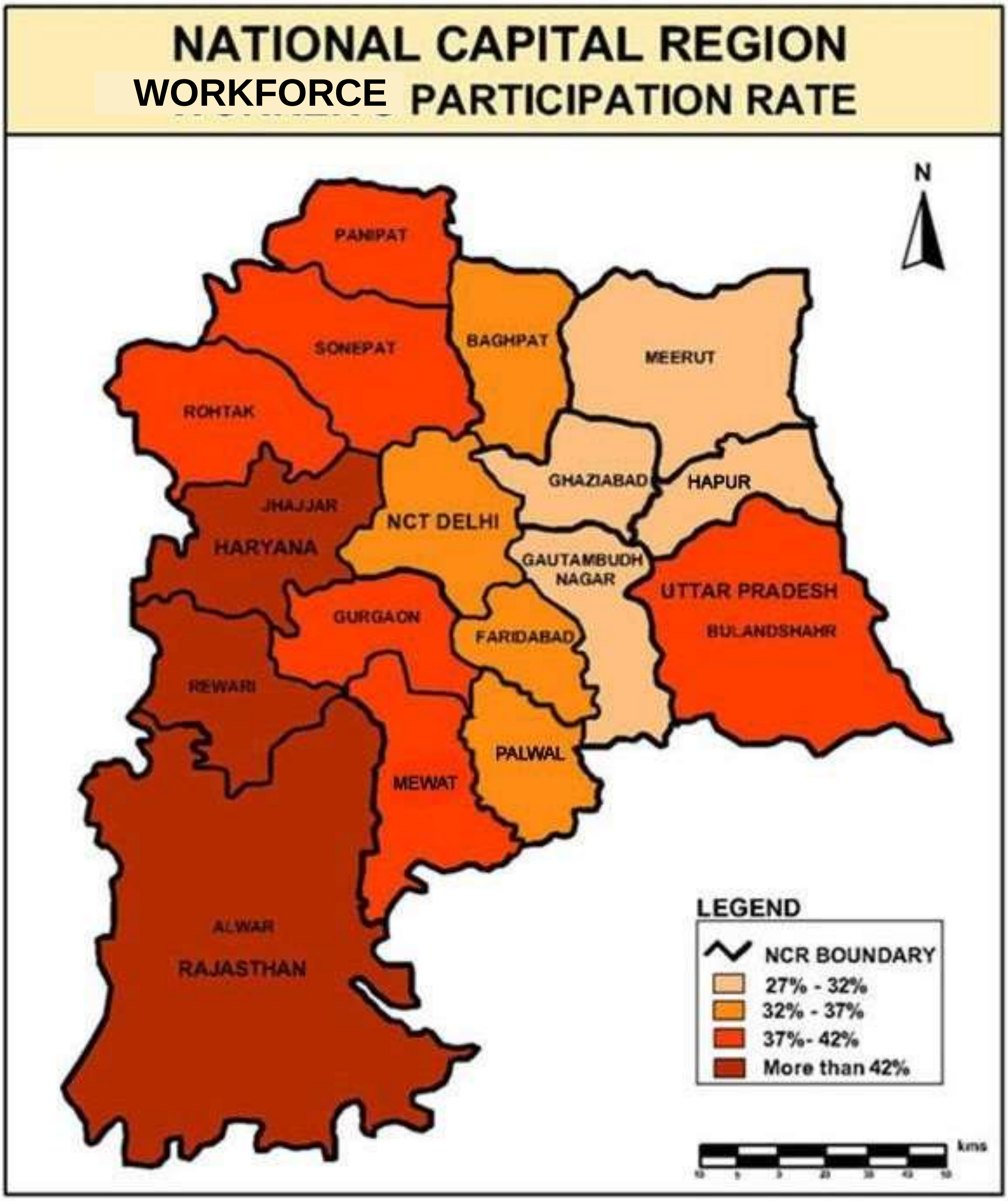

ऊपर वाले चित्र का अनुवाद

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्यबल भागीदारी दर

पानीपत सोनीपत बागपत मेरठ रोहतक झज्जर एनसीटी दिल्ली गाज़ियाबाद हापुड़ हरियाणा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर गुड़गांव फरीदाबाद रेवाड़ी पलवल मेवात अलवर राजस्थान

प्रसिद्ध

एनसीआर सीमा

(27% - 32% 32% - 37% 37% - 42% 42% से अधिक)

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मानचित्र 3.2: 2011 में एनसीआर में जिलेवार कर्मचारी की संरचना

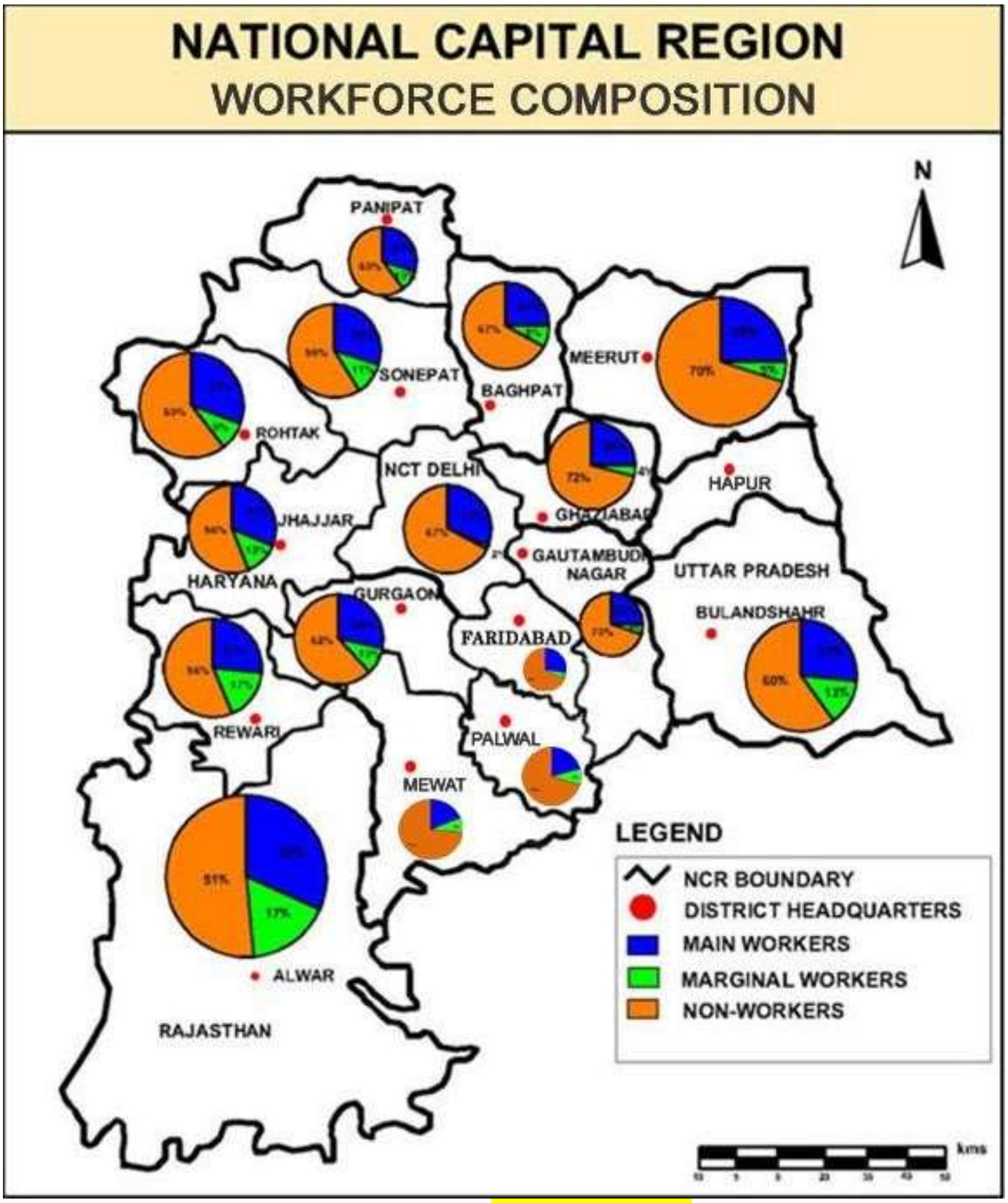

ऊपर वाले चित्र का अनुवाद

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्यबल की संरचना

पानीपत सोनीपत बागपत मेरठ रोहतक झज्जर एनसीटी दिल्ली गाज़ियाबाद हापुड़ हरियाणा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर गुड़गांव फरीदाबाद रेवाड़ी पलवल मेवात अलवर राजस्थान

प्रसिद्ध

एनसीआर सीमा

जिला मुख्यालय

मुख्य कार्यबल

सीमांत कार्यबल

गैर कार्यबल

2011 की जनगणना के अनुसार, एनसीआर में अधिकांश मुख्य कर्मचारी एनसीटी दिल्ली (40.10%) में केंद्रित हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (28.88%), हरियाणा उप-क्षेत्र (22.10%) और राजस्थान उप-क्षेत्र (8.91%) (तालिका 3.9 देखें) में हैं। सीमांत श्रमिकों के मामले में, एनसीटी-दिल्ली में सबसे कम अनुपात (11.18%) दर्ज किया गया है और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (37.91%), हरियाणा उप-क्षेत्र (29.75%) और राजस्थान उप-क्षेत्र (21.16%) में ज्यादा अधिकता देखी गई है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 3-9: उप-क्षेत्रवार श्रमिक वार एनसीआर में श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा: 2011

क्षेत्र	कुल श्रमिक	मुख्य श्रमिक	सीमांत श्रमिक
दिल्ली एनसीटी	35.51	40.10	11.18
हरियाणा उप क्षेत्र	23.32	22.10	29.75
राजस्थान उप क्षेत्र	10.86	8.91	21.16
उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	30.32	28.88	37.91
एनसीआर	**100.00**	**100.00**	**100.00**

स्रोत: भारत की जनगणना, *2011*

चित्र 3.3: एनसीआर में मुख्य और सीमांत श्रमिकों का उप-क्षेत्रवार प्रतिशत हिस्सा: 2011

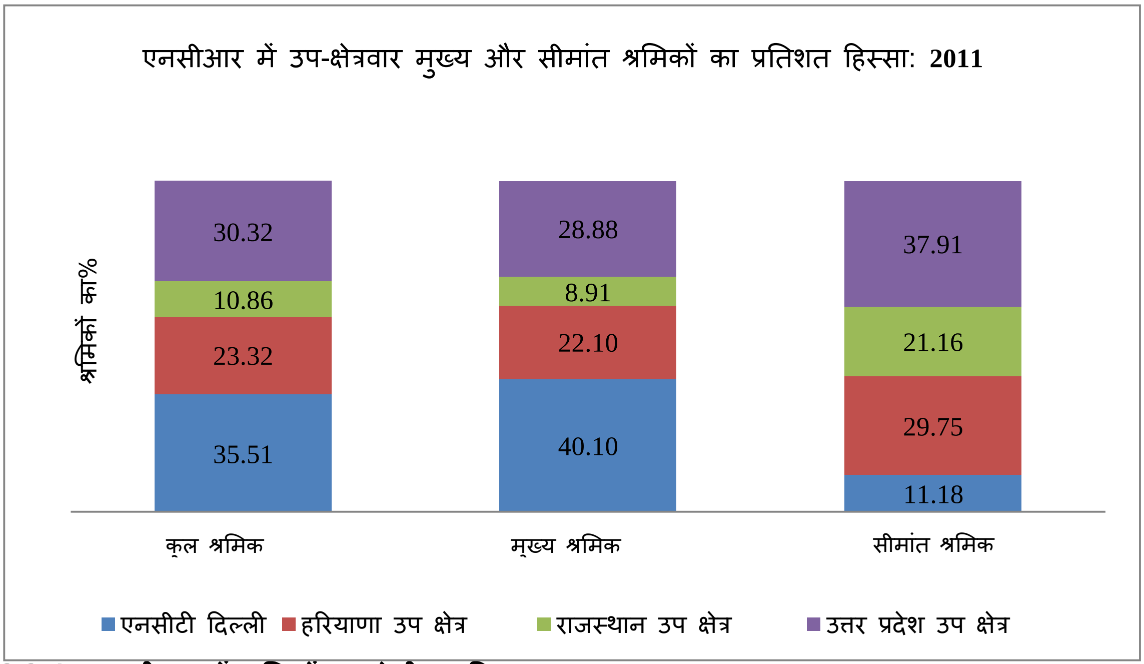

3.3.4 एनसीआर में श्रमिकों का श्रेणीवार वितरण

2001 में उप-क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारी वितरण को अलग करते हुए, अधिकांश श्रेणियों में, यह देखा गया है कि कृषि मजदूरों, खेती और पशुपालन, और वानिकी को छोड़कर, कर्मचारी में एनसीटी-दिल्ली का सबसे बड़ा हिस्सा है। एनसीटी-दिल्ली में परिवहन, भंडारण और संचार श्रेणी में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि, खेतिहर मजदूरों और खनन और उत्खनन श्रेणियों में श्रमिकों की संख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में सबसे अधिक खेतिहर मजदूर हैं और पशुपालन और वानिकी क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर है और खनन और उत्खनन श्रेणी में सबसे कम है।

सेक्टर स्तर पर, निर्माण श्रमिकों की उच्चतम अधिकता एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र (57%) और सबसे कम राजस्थान उप-क्षेत्र (4%) में दर्ज की गई है। इसी तरह के रुझान व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। खेती में लगे श्रमिकों और खेतिहर मजदूरों के लिए एक विपरीत प्रवृत्ति देखी गई है; जबकि कुल काश्तकारों और खेतिहर मजदूरों का 1.28% एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में स्थित है, उनमें से 24.87 प्रतिशत राजस्थान उप-क्षेत्र में स्थित हैं (तालिका 3.9 और चित्र 3.4 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 3-10: 2001 में श्रेणीवार कुल श्रमिकों का वितरण

श्रेणी	1	2	3		4	5			6	7	8	9		1 to 9		
	कृषि मजदूर	किसान	पशुपालन, वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	निर्माण, प्रसंस्करण			निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	अन्य सेवाएं		कुल श्रमिक	कुल जनसंख्या	भागीदारी दर
जिले						a) घरेलू उद्योग	b) घरेलू उद्योगों के अलावा	C) बिजली, गैस और पावर				वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं			
हरियाणा उप-क्षेत्र	417282	1130246	218955	193533	18025	228243	128313	201215	300451	145440	225948	112526	85611	3414662	8687050	39.31
%	12.22%	33.10%	6.41%	5.67%	0.53%	6.68%	3.76%	5.89%	8.80%	4.26%	6.62%	3.30%	2.51%	100.00%		
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	480625	1041911	255228	295045	3549	189430	121118	222669	420014	172696	316777	111410	98923	3752036	11567090	32.44
%	12.81%	27.77%	6.80%	7.86%	0.09%	5.05%	3.23%	5.93%	11.19%	4.60%	8.44%	2.97%	2.64%	100.00%		
राजस्थान उप-क्षेत्र	128442	905207	82083	45703	4992	43016	16809	45810	70538	37133	34937	29883	14778	1458686	2992592	48.74

%	8.81%	62.06%	5.63%	3.13%	0.34%	2.95%	1.15%	3.14%	4.84%	2.55%	2.40%	2.05%	1.01%	100.00%		
दिल्ली क्षेत्र	15773	37431	37353	512571	15873	419273	235541	395608	1061214	480580	738180	278482	341443	4346710	13850507	31.38
%	0.36%	0.86%	0.86%	11.79%	0.37%	9.65%	5.42%	9.10%	24.41%	11.06%	16.98%	6.41%	7.86%	100.00%		
एनसीआर	1042122	3114795	593619	1046852	42439	879962	501781	865302	1852217	835849	1315842	532301	540755	12972094	37097239	34.97

चित्र 3.4: 2001 में रोजगार श्रेणियों में श्रमिकों का वितरण

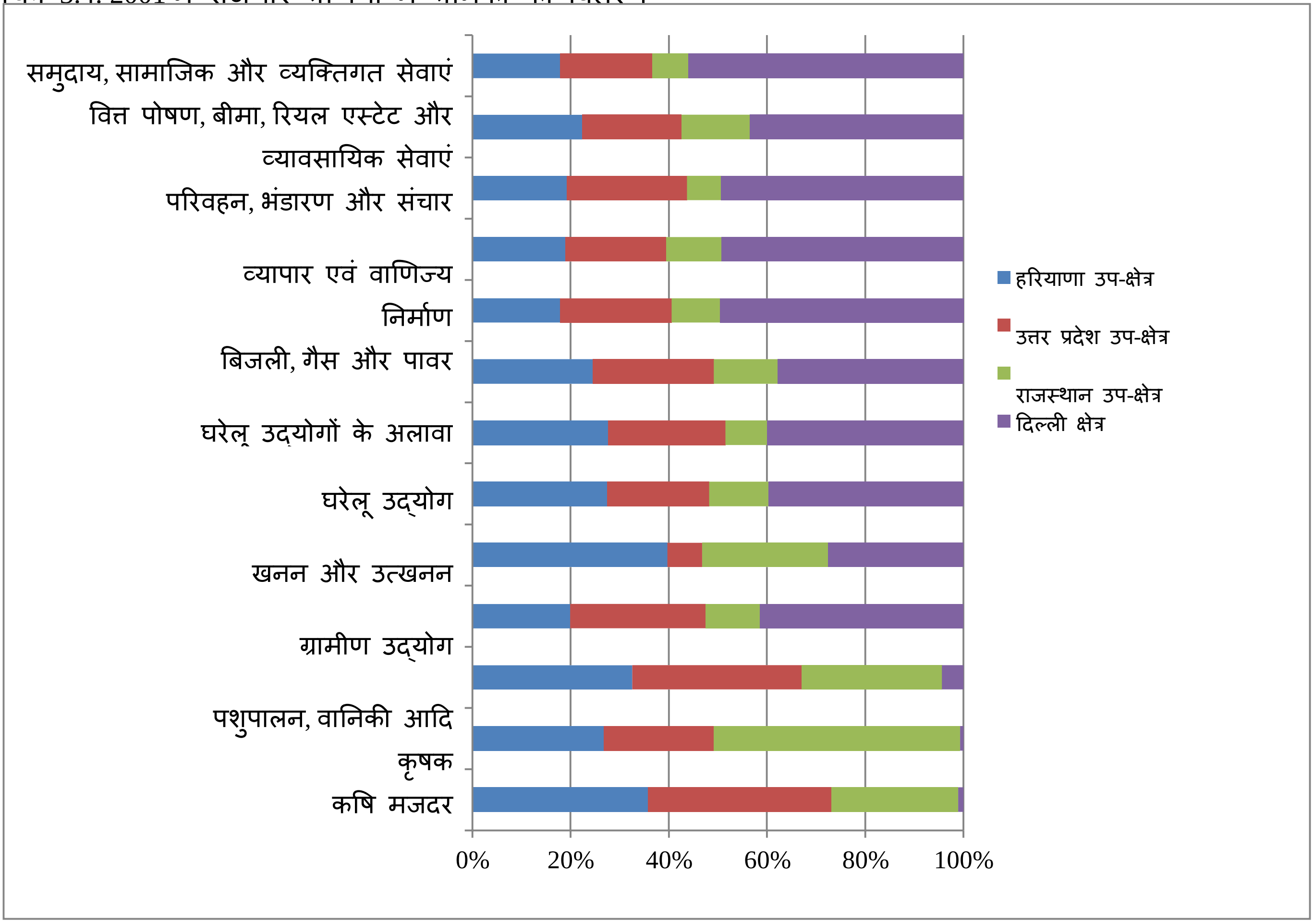

मानचित्र 3.3 2011 में एनसीआर में चार श्रेणियों, अर्थात किसान, कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग के श्रमिकों और अन्य श्रमिकों में वर्गीकृत श्रमिकों के जिलेवार व्यावसायिक प्रोफाइल को दर्शाता है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मानचित्र 3.3: 2011 में चार श्रेणियों में एनसीआर में जिलेवार व्यावसायिक प्रोफाइल

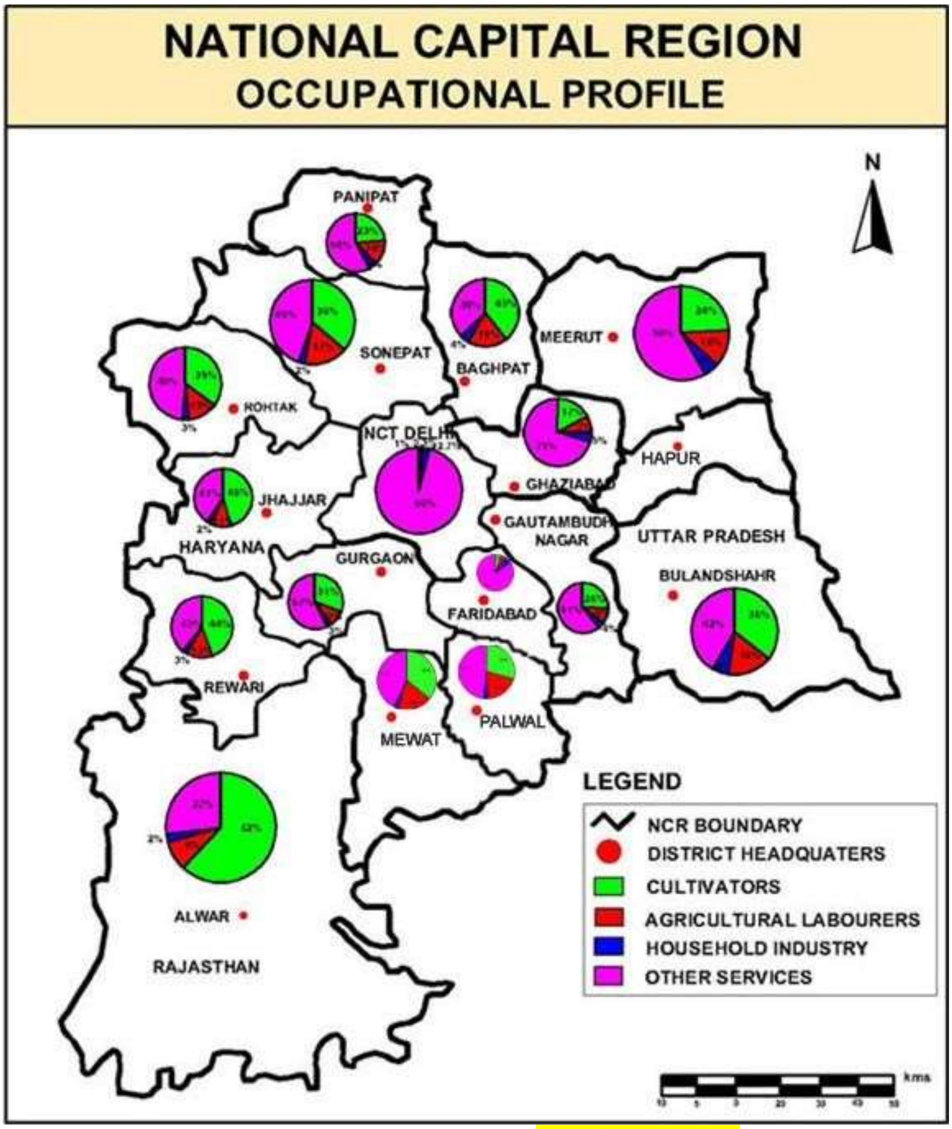

ऊपर वाले चित्र का अनुवाद

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
व्यावसायिक रूपरेखा
पानीपत सोनीपत बागपत मेरठ रोहतक झज्जर एनसीटी दिल्ली गाज़ियाबाद हापुड़ हरियाणा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर गुड़गांव फरीदाबाद रेवाड़ी पलवल मेवात अलवर राजस्थान
प्रसिद्ध
एनसीआर सीमा
जिला मुख्यालय
किसान
खेतिहर मजदूर
घरेलू उद्योग
अन्य सेवाएं

3.3.5 क्षेत्र/जिलावार कर्मचारी

2001 की जनगणना के अनुसार, एनसीआर में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कुल 1,29,72,094 कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल कामकाजी आबादी में, श्रमिकों का सबसे बड़ा अनुपात (45.02%) प्राथमिक क्षेत्र में, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र (31.60%) और सबसे कम (24.86%) तृतीयक क्षेत्र में (तालिका 3.11 देखें) कार्यरत है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों में, अधिकांश कर्मचारी प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, जबकि एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में कर्मचारी का सबसे बड़ा हिस्सा द्वितीयक क्षेत्र में लगा हुआ है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 3-11: 2001 की जनगणना के अनुसार कुल कर्मचारी का क्षेत्रवार विवरण

उप क्षेत्र	जिले / क्षेत्र	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र	कुल श्रमिक
हरियाणा उप-क्षेत्र	फरीदाबाद	3,59,491	268,460	1,57,005	7,85,762
	गुड़गाँव	3,62,923	1,55,938	1,17,704	6,29,658
	झज्जर	2,49,254	80,659	53,054	3,88,715
	पानीपत	2,39,535	96,869	450,735	3,82,801
	रेवाड़ी	2,26,185	61,306	41,957	3,33,622
	रोहतक	2,16,980	83,484	66,971	3,71,073
	सोनीपत	3,27,691	1,11,506	82,099	5,23,031
	हरियाणा उप-क्षेत्र का योग	**19,78,041**	**8,58,222**	**5,69,525**	**34,14,662**
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	बागपत	2,60,116	64,300	48,519	3,80,310
	बुलंदशहर	8,39,491	2,00,760	1,33,575	11,73,805
	गौतमबुद्धनगर	1,62,926	93,206	1,05,633	3,63,814
	गाज़ियाबाद	3,59,459	3,36,180	2,38,801	9,38,251
	मेरठ	4,54,366	2,58,785	1,73,278	8,95,856
	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र का योग	**20,76,358**	**9,53,231**	**6,99,806**	**37,52,036**
राजस्थान उप-क्षेत्र	अलवर	11,66,427	1,76,173	1,16,731	14,58,686
	राजस्थान उप-क्षेत्र का योग	**11,66,427**	**1,76,173**	**1,16,731**	**14,58,686**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	उत्तर पश्चिम	1,23,258	4,59,805	3,39,314	7,20,915
	उत्तर	28,596	1,32,507	96,700	2,56,596
	उत्तर पूर्व	89,315	2,59,363	1,51,041	5,00,425
	पूर्व	56,524	2,25,533	1,93,954	4,75,310
	नई दिल्ली	3,035	15,884	49,638	67,594
	केंद्रीय	36,238	1,16,178	76,524	2,23,851
	पश्चिम	79,614	3,68,398	2,78,566	7,20,915
	दक्षिण पश्चिम	74,455	2,24,921	3,02,247	6,02,546
	दक्षिण	1,15,643	3,09,047	3,50,701	7,78,558
	एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र का कुल	**6,19,001**	**21,11,636**	**18,38,685**	**43,46,710**
एनसीआर	एनसीआर में कुल श्रमिक	**58,39,827**	**40,99,262**	**32,24,747**	**1,29,72,094**
% हिस्सा		**45.02%**	**31.60%**	**24.86%**	**100.00%**

स्रोत: भारत की जनगणना, *2001*

3.4 हरियाणा उप-क्षेत्र

3.4.1 2001 में हरियाणा उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

उपक्षेत्र स्तर पर श्रेणीवार मुख्य श्रमिकों का वितरण

2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, कुल मुख्य श्रमिकों में से 38.63% खेती में लगे हुए हैं, इसके बाद निर्माण (10.84%) में लगे हैं। इसका श्रेय हरियाणा उप-क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण और संबंधित निर्माण गतिविधियों को दिया जा सकता है, विशेष रूप से एनसीटी-दिल्ली से सटे जिलों में और मध्य एनसीआर का हिस्सा हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि निर्माण में लगे श्रमिकों का अनुपात 1991-2001 के दौरान (1991 में 2.8% से 2001 में 10.84%) लगभग चार गुना बढ़ गया है। परिवहन, भंडारण और संचार में लगे श्रमिकों का अनुपात भी 1991-2001 के दौरान दोगुने से अधिक हो गया है (तालिका 3.12 देखें)।

तालिका 3-12: हरियाणा उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण (1971, 1991 और 2001)

वर्ष /	1971		1991		2001	
श्रमिकों की श्रेणी	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत
किसान	4,49,747	46.63	6,77,117	35.96	9,72,007*	38.63
कृषि मजदूर	1,32,687	13.76	2,86,950	15.24	-	-
पशुपालन, वानिकी आदि	9,447	0.98	13,605	0.72	1,23,965	4.93
ग्रामीण उद्योग	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	1,57,144	6.25
खनन और उत्खनन	2,501	0.26	4,462	0.24	15,346	0.61
निर्माण, प्रसंस्करण						
a) घरेलू उद्योग	38,723	4.01	26,371	1.4	1,77,695	7.06
b) घरेलू उद्योगों के अलावा	85,321	8.85	2,48,635	13.2	1,18,260	4.70
बिजली, गैस और पावर	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	1,54,406	6.14
निर्माण	19,355	2.01	52,744	2.8	2,72,617	10.84
व्यापार एवं वाणिज्य	64,931	6.73	1,64,767	8.75	1,35,515	5.39
परिवहन, भंडारण और संचार	24,512	2.54	71,813	3.81	2,14,100	8.51
अन्य सेवाएं	1,37,363	14.24	3,36,704	17.88	1,75,002	6.96
कुल मुख्य श्रमिक	**9,64,587**	**100**	**18,83,168**	**100**	**25,16,057**	**100.00**
जनसंख्या	38,55,568		66,43,604		86,87,050	
भागीदारी अनुपात	25.02		28.35		28.96	

स्रोत: जनगणना, *1971*, *1991* और *2001*, भारत सरकार,

*कृषि श्रमिक भी सम्मिलित हैं

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 3.5: 2001 में हरियाणा उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का श्रेणीवार वितरण

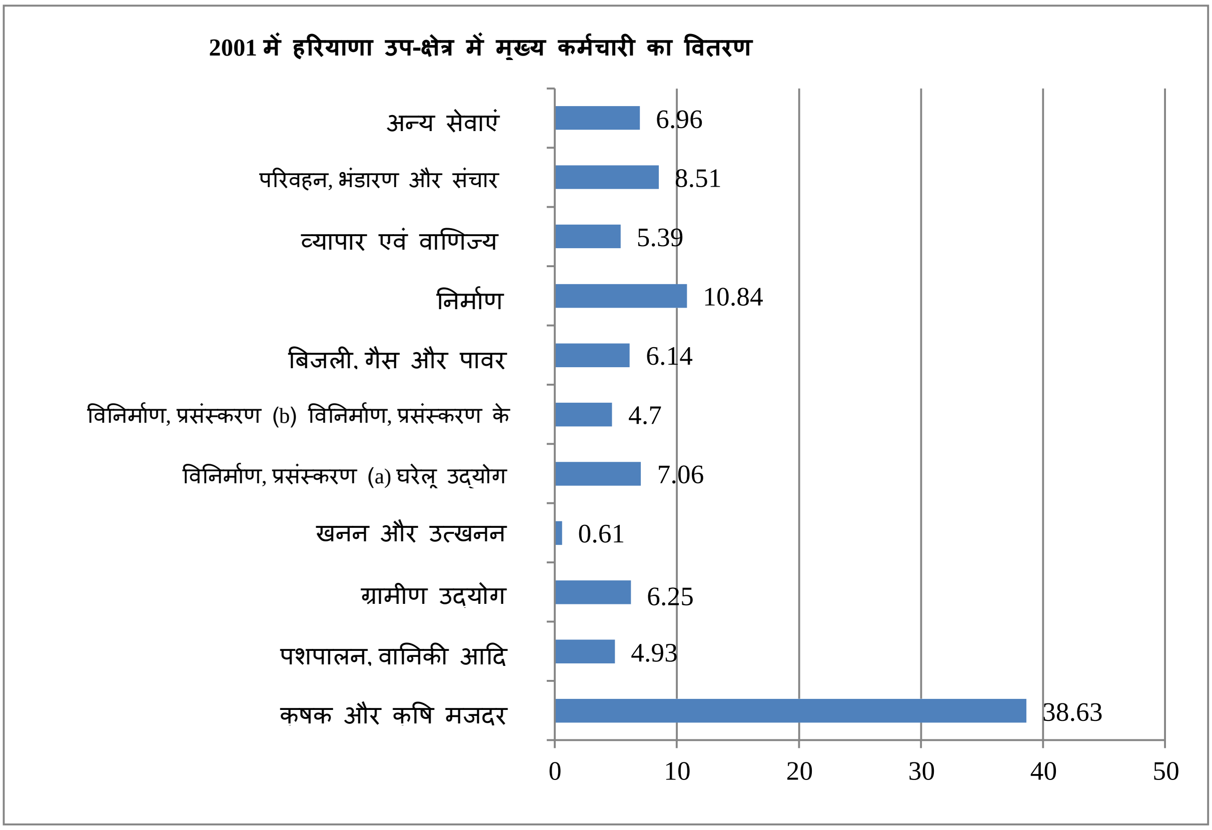

जिला स्तर पर श्रेणीवार श्रमिकों का वितरण

2001 में, कृषि उप-क्षेत्र के सभी छह जिलों के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत है, जिसके बाद घरेलू और अन्य सेवाएं हैं, जो अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की प्रधानता को दर्शाता है। उप-क्षेत्र में इन जिलों के लिए खेती, कृषि और गैर-घरेलू उद्योग तीन प्रमुख व्यावसायिक प्रोफाइल हैं, जबकि व्यापार और वाणिज्य और परिवहन सबसे नीचे हैं (तालिका 3.13 और चित्र 3.6 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 3-13: 2001 में हरियाणा उप-क्षेत्र में मुख्य श्रमिकों की जिलेवार व्यावसायिक प्रोफ़ाइल

राज्य	किसान	कृषि मजदूर	पशुपालन, वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	घरेलू उद्योग	घरेलू उद्योगों के अलावा	बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं
फरीदाबाद	1,86,403	82,175	46,513	39,924	4476	65,918	52,788	57,172	92,582	38,370	62,321	27,201	29,113
हरियाणा उप-क्षेत्र में हिस्सेदारी %	16.49%	19.69%	20.86%	20.63%	24.83%	28.88%	41.14%	28.41%	30.81%	26.38%	27.58%	24.17%	34.01%
गुड़गांव	1,95,768	57,928	72,640	25,719	10868	31,668	25,199	44,611	54,460	32,733	47,504	19,397	18,070
हरियाणा उप-क्षेत्र में हिस्सेदारी %	17.32%	13.88%	32.58%	13.29%	60.29%	13.87%	19.64%	22.17%	18.13%	22.51%	21.02%	17.24%	21.11%
झज्जर	1,77,377	44,844	15,765	11,027	241	37,547	7,217	15,602	20,293	14,025	22,031	10,505	6,493
हरियाणा उप-क्षेत्र में हिस्सेदारी %	15.69%	10.75%	7.07%	5.70%	1.34%	16.45%	5.62%	7.75%	6.75%	9.64%	9.75%	9.34%	7.58%
पानीपत	89,493	55,042	21,867	72,535	598	22,445	12,926	21,975	39,523	13,266	17,259	9,816	10,394

हरियाणा उप-क्षेत्र में हिस्सेदारी %	7.92%	13.19%	9.81%	37.48%	3.32%	9.83%	10.07%	10.92%	13.15%	9.12%	7.64%	8.72%	12.14%
रेवाड़ी	1,48,218	44,441	21,187	11,481	858	12,622	11,837	15,437	21,410	9,703	17,297	10,018	4,939
हरियाणा उप-क्षेत्र में % हिस्सेदारी	13.11%	10.65%	9.50%	5.93%	4.76%	5.53%	9.23%	7.67%	7.13%	6.67%	7.66%	8.90%	5.77%
रोहतक	1,43,314	45,462	14,530	13,379	295	21,377	6,158	21,724	34,225	16,835	25,553	16,602	7,981

जिला	**किसान**	**कृषि मजदूर**	**पशुपालन, वानिकी आदि**	**ग्रामीण उद्योग**	**खनन और उत्खनन**	**घरेलू उद्योग**	**घरेलू उद्योगों के अलावा**	**बिजली, गैस और पावर**	**निर्माण**	**व्यापार एवं वाणिज्य**	**परिवहन, भंडारण और संचार**	**वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं**	**समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं**
हरियाणा उप-क्षेत्र में हिस्सेदारी %	12.68%	10.89%	6.52%	6.91%	1.64%	9.37%	4.80%	10.80%	11.39%	11.58%	11.31%	14.75%	9.32%
सोनीपत	1,89,673	87,390	30,471	19,468	689	36,666	12,188	24,694	37,958	20,508	33,983	18,987	8,621
हरियाणा उप-क्षेत्र में हिस्सेदारी %	16.78%	20.94%	13.67%	10.06%	3.82%	16.06%	9.50%	12.27%	12.63%	14.10%	15.04%	16.87%	10.07%
हरियाणा उप-क्षेत्र	**11,30,246**	**4,17,282**	**2,22,973**	**1,93,533**	**18025**	**228243**	**128313**	**201215**	**3,00,451**	**1,45,440**	**2,25,948**	**1,12,526**	**85,611**

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001

चित्र 3.6: हरियाणा उप-क्षेत्र में मुख्य श्रमिकों की जिलेवार व्यावसायिक रूपरेखा, 2001

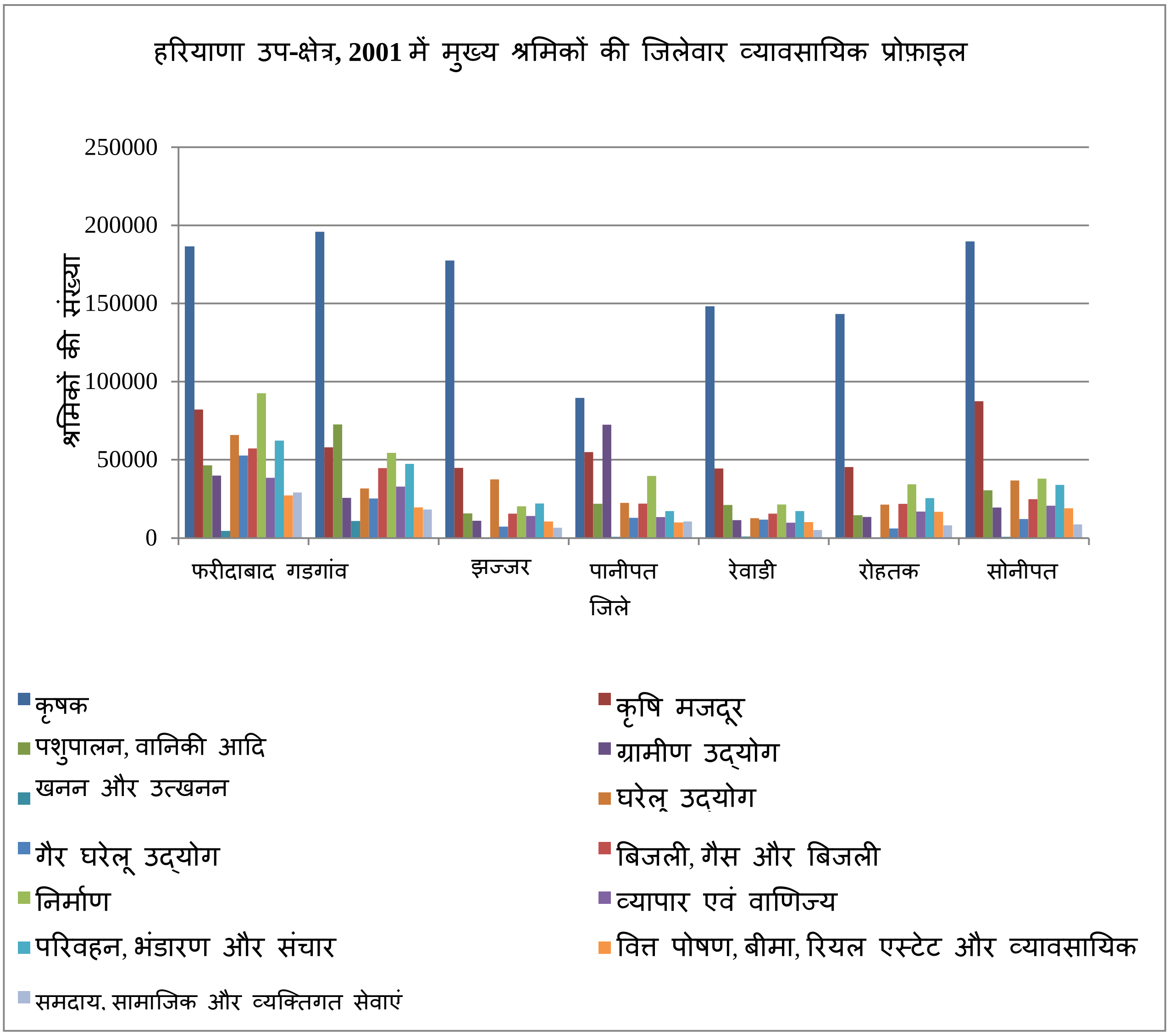

3.4.2 हरियाणा उप-क्षेत्र में कर्मचारी और गैर-श्रमिक, 2011

हरियाणा उप-क्षेत्र में अधिकांश श्रमिक तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों और घरेलू उद्योगों के अलावा खेती और अन्य कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। घरेलू उद्योग के मामले में, फरीदाबाद जिले में कार्यरत श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, जबकि मेवात जिले में इस श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों की सबसे कम संख्या दर्ज की गई है (चित्र 3.7 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 3.7: हरियाणा उप-क्षेत्र में कुल श्रमिकों की जिलेवार व्यावसायिक प्रोफ़ाइल: 2011

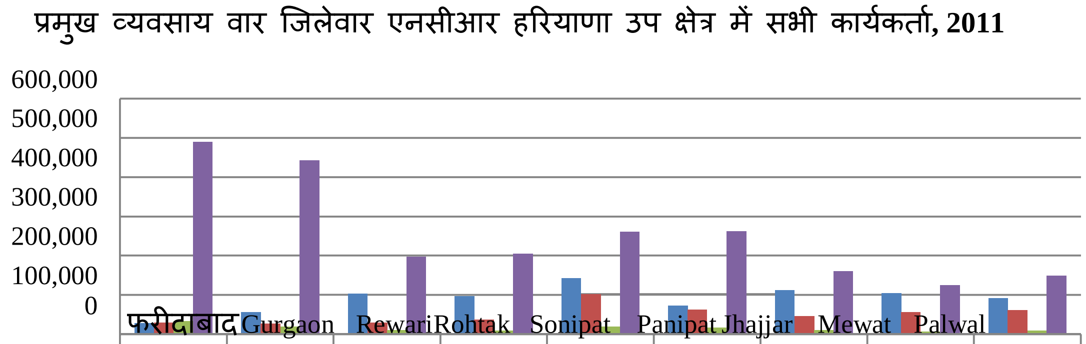

	फरीदाबाद	Gurgaon	Rewari	Rohtak	Sonipat	Panipat	Jhajjar	Mewat	Palwal
कृषक	27,705	56,046	102,698	95,732	142,344	72,120	112,389	104,237	91,506
कृषि श्रमिक	29,288	27,097	28,215	36,568	101,733	62,358	44,845	55,278	60,685
एचएच इंडस्ट्रीज	32,286	18,228	9,782	8,521	18,184	15,824	9,254	6,023	8,566
अन्य	489,950	443,345	197,032	205,146	260,918	262,016	160,046	124,426	148,806

स्रोत: भारत की जनगणना, *2011*

3.4.3 हरियाणा उप-क्षेत्र में श्रमिक और गैर-श्रमिक, 2011

हरियाणा उप-क्षेत्र में कुल 36.69 लाख श्रमिक हैं, जिनमें से 20.95 लाख ग्रामीण और 15.74 लाख शहरी श्रमिक हैं। फरीदाबाद जिले में श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या है, इसके बाद गुड़गांव जिले का स्थान है, जिसमें शहरी श्रमिक बहुत ज्यादा हैं। मेवात में सबसे कम श्रमिकों की संख्या दर्ज की गई है, जिसके बाद पलवल में ग्रामीण श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। हरियाणा उप-क्षेत्र में कुल 73.62 लाख गैर-कामकाजी आबादी है और उनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में हैं। यह देखा गया है कि फरीदाबाद जिले में गैर-श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक और मेवात जिले में सबसे कम है (तालिका 3.14 और चित्र 3.8 देखें)।

तालिका 3-14: हरियाणा उप-क्षेत्र में जिलेवार श्रमिक और गैर-श्रमिक: 2011

जिले	मुख्य कामगार			सीमांत कामगार			गैर कामगार			कुल श्रमिक (मुख्य + सीमांत)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
फरीदाबाद	84,456	4,10,860	4,95,316	22,302	61,611	83,913	2,64,120	9,66,384	12,30,504	1,06,758	4,72,471	5,79,229
हरियाणा उप-क्षेत्र में % हिस्सेदारी	5.54%	29.33%	16.93%	3.91%	35.58%	11.28%	6.34%	30.21%	16.71%	5.10%	30.02%	15.79%
गुडगाँव	1,24,933	3,62,508	4,87,441	33,529	23,746	57,275	3,13,717	6,55,999	9,69,716	1,58,462	3,86,254	5,44,716
हरियाणा उप-क्षेत्र में % हिस्सेदारी	8.195%	25.878%	16.663%	5.875%	13.712%	7.699%	7.535%	20.506%	13.171%	7.563%	24.539%	14.846%
रेवाड़ी	1,82,761	67,458	2,50,219	81,614	5,894	87,508	4,02,527	1,60,078	5,62,605	2,64,375	73,352	3,37,727

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

हरियाणा उप-क्षेत्र में % हिस्सेदारी	11.99%	4.82%	8.55%	14.30%	3.40%	11.76%	9.67%	5.00%	7.64%	12.62%	4.66%	9.20%
रोहतक	1,66,788	1,22,161	2,88,949	45,893	11,125	57,018	4,02,359	3,12,878	7,15,237	2,12,681	1,33,286	3,45,967

जिले	मुख्य कामगार			सीमांत कामगार			गैर कामगार			कुल श्रमिक (मुख्य + सीमांत)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
हरियाणा उप-क्षेत्र में % हिस्सेदारी	10.94%	8.72%	9.88%	8.04%	6.42%	7.66%	9.66%	9.78%	9.71%	10.15%	8.47%	9.43%
सोनीपत	2,71,676	1,25,087	3,96,763	1,04,512	21,904	1,26,416	6,20,449	3,06,373	9,26,822	3,76,188	1,46,991	5,23,179
हरियाणा उप-क्षेत्र में % हिस्सेदारी	17.82%	8.93%	13.56%	18.31%	12.65%	16.99%	14.90%	9.58%	12.59%	17.95%	9.34%	14.26%
पानीपत	1,67,683	1,71,333	3,39,016	54,248	19,054	73,302	4,28,421	3,64,698	7,93,119	2,21,931	1,90,387	4,12,318
हरियाणा उप-क्षेत्र में % हिस्सेदारी	11.00%	12.23%	11.59%	9.50%	11.00%	9.85%	10.29%	11.40%	10.77%	10.59%	12.10%	11.24%
झज्जर	1,82,688	63,769	2,46,457	71,145	8,932	80,077	4,61,233	1,70,638	6,31,871	2,53,833	72,701	3,26,534
हरियाणा उप-क्षेत्र में % हिस्सेदारी	11.98%	4.55%	8.43%	12.47%	5.16%	10.76%	11.08%	5.33%	8.58%	12.12%	4.62%	8.90%
मेवात	1,79,382	24,796	2,04,178	79,339	6,447	85,786	7,06,436	92,863	7,99,299	2,58,721	31,243	2,89,964
हरियाणा उप-क्षेत्र में % हिस्सेदारी	11.77%	1.77%	6.98%	13.90%	3.72%	11.53%	16.97%	2.90%	10.86%	12.35%	1.98%	7.90%
पलवल	1,64,067	52,865	2,16,932	78,161	14,470	92,631	5,63,936	1,69,209	7,33,145	2,42,228	67,335	3,09,563
हरियाणा उप-क्षेत्र में % हिस्सेदारी	10.76%	3.77%	7.42%	13.69%	8.36%	12.45%	13.55%	5.29%	9.96%	11.56%	4.28%	8.44%
हरियाणा उप-क्षेत्र में	**1,52,44,434**	**14,00,837**	**29,25,271**	**5,70,743**	**1,73,183**	**7,43,926**	**41,63,198**	**31,99,120**	**73,62,318**	**20,95,177**	**15,74,020**	**36,69,197**

स्रोत: भारत की जनगणना, *2011*, भारत सरकार

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 3.8: हरियाणा उप-क्षेत्र, 2011 में श्रमिकों, गैर-श्रमिकों और जनसंख्या की जिलेवार संरचना

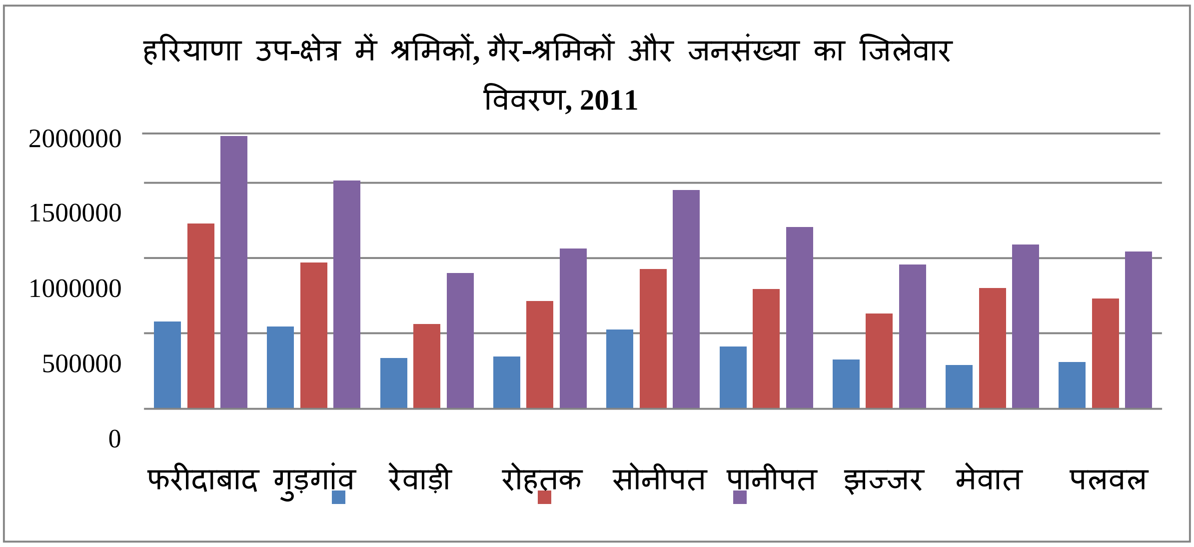

3.4.4 हरियाणा उप-क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या

उच्च विकास दर के कारण, फरीदाबाद और गुड़गांव जिले सबसे अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं जिन्हे इन जिलों में निजी क्षेत्र के रोजगार के उच्च हिस्से के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत जिलों में निजी क्षेत्र के रोजगार का हिस्सा क्रमशः 68%, 77% और 60% दर्ज किया गया। अन्य तीन जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी का एक बड़ा हिस्सा है (तालिका 3.15 देखें)।

तालिका 3-15: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कर्मचारी का प्रतिशत वितरण

जिले का नाम	निजी क्षेत्र (%)	सार्वजनिक क्षेत्र (%)
पानीपत	38.85	61.15
रेवाड़ी	51.92	48.08
सोनीपत	59.87	40.13
रोहतक	38.50	61.50
गुडगाँव	77.30	22.70
फरीदाबाद	67.96	32.04

स्रोत: हरियाणा का सांख्यिकीय सार, *2008-09*

3.5 राजस्थान उप-क्षेत्र

3.5.1 2001 में राजस्थान उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

उप-क्षेत्र स्तर पर श्रेणीवार श्रमिकों का वितरण:

राजस्थान उप-क्षेत्र ने पिछले तीन दशकों में कर्मचारी वितरण में बदलते रुझान देखे हैं। 1991-2001 की अवधि के दौरान, उप-क्षेत्र ने प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिकों (2.61 लाख से 6.47 लाख तक) में अधिकतम वृद्धि (47%) दर्ज की है (तालिका 3.16 और चित्र 3.9 देखें)। अधिकांश श्रमिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं, इसके बाद निर्माण कार्य में लगे हैं।

तालिका 3-16: राजस्थान उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण (1971, 1991 और 2001)

वर्ष/श्रमिकों की श्रेणी	1971		1991		2001	
	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत
किसान	1,35,956	63.08	2,22,065	54.58	6,11,306*	64.51
कृषि मजदूर	19,511	9.05	35,158	8.64	-	-
पशुपालन, वानिकी आदि	2,347	1.09	4,087	1	35,375	3.73
ग्रामीण उद्योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	35,632	3.76
खनन और उत्खनन	432	0.2	2,004	0.49	4,299	0.45
निर्माण, प्रसंस्करण						
a) घरेलू उद्योग	8,921	4.14	6,524	1.6	36,437	3.85
b) घरेलू उद्योगों के अलावा	5,299	2.46	34,083	8.38	14,843	1.57
बिजली, गैस और पावर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	38,311	4.04
निर्माण	2,558	1.19	8,611	2.12	63,738	6.73

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

वर्ष/श्रमिकों की श्रेणी	1971		1991		2001	
	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत
व्यापार एवं वाणिज्य	10,717	4.97	29,796	7.32	34,581	3.65
परिवहन, भंडारण और संचार	3,156	1.46	11,370	2.79	32,487	3.43
अन्य सेवाएं	26,624	12.35	53,142	13.06	40,578	4.28
कुल मुख्य श्रमिक	**2,15,521**	**100**	**4,06,840**	**100**	**9,47,587**	**100.00**
भागीदारी अनुपात	**26.4**		**28.33**		**31.66**	

स्रोत: भारत की जनगणना, *1971, 1991* और *2001*

*इसमें कृषि श्रमिक भी शामिल हैं

चित्र 3.9: 2001 में राजस्थान उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण

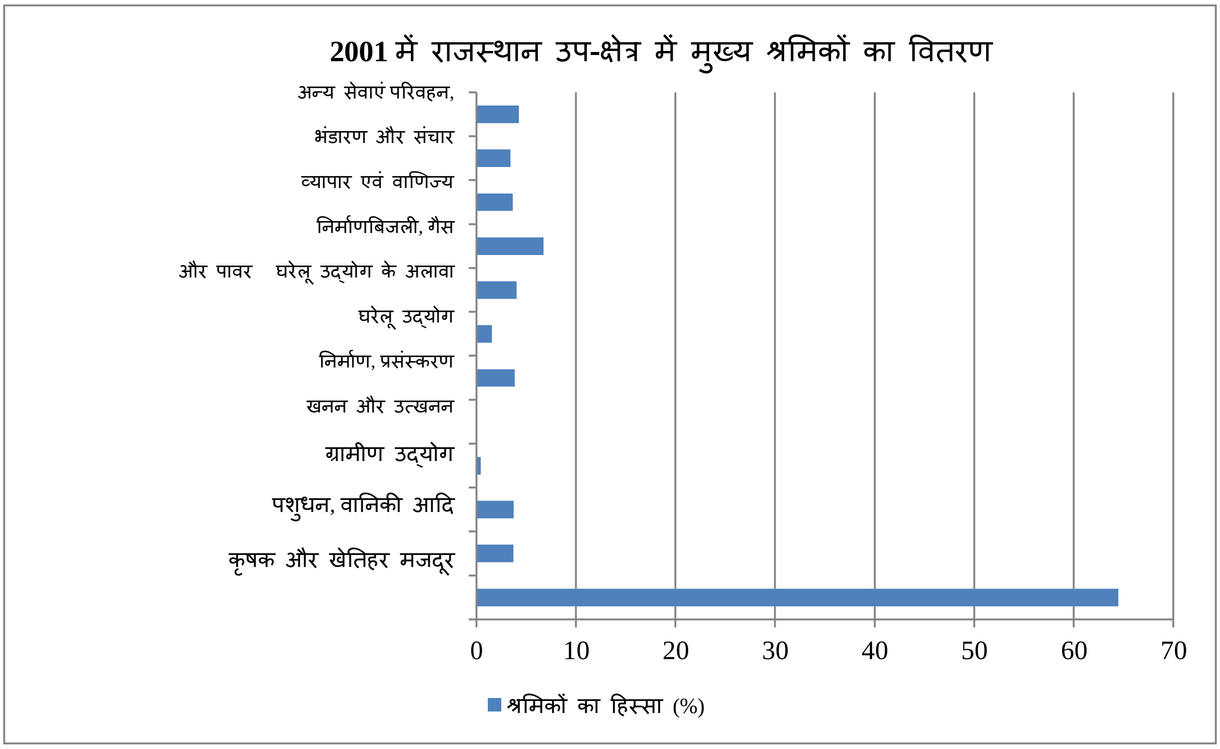

3.5.2 राजस्थान उप-क्षेत्र में श्रमिक और गैर-श्रमिक, 2011

2011 की जनगणना के अनुसार, उप क्षेत्र में किसान (8.99 लाख) और कृषि मजदूरों (2.17 लाख) सहित कृषि क्षेत्र में 11 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं (चित्र 3.10 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 3.10: राजस्थान उप-क्षेत्र, 2011 में कुल श्रमिकों की व्यावसायिक प्रोफ़ाइल

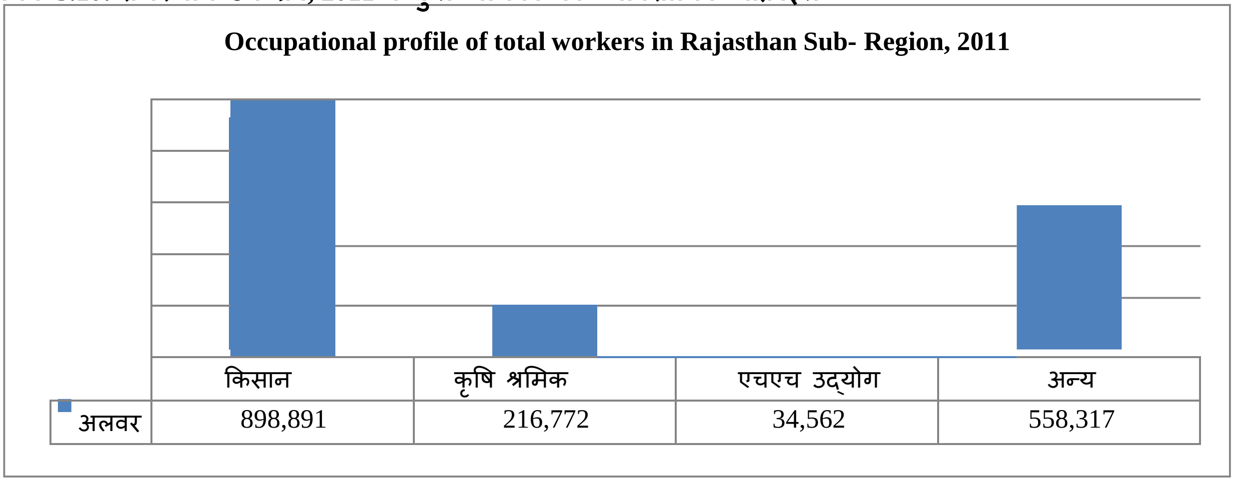

	किसान	कृषि श्रमिक	एचएच उद्योग	अन्य
अलवर	898,891	216,772	34,562	558,317

3.5.3 राजस्थान उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण, 2011

इस उप-क्षेत्र में अधिकांश कर्मचारी (मुख्य और सीमांत दोनों श्रमिक) 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों (87%) में हैं। ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्र श्रमिकों की तुलना में प्रच्छन्न श्रमिकों के रूप में कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है। सीमांत श्रमिकों के संदर्भ में, ग्रामीण सीमांत कर्मचारी कुल सीमांत कर्मचारी का 95% से अधिक है। गैर-श्रमिकों के संदर्भ में, ग्रामीण कर्मचारी घटक कुल गैर-कार्यशील आबादी का लगभग 78% योगदान देता है। उप-क्षेत्र की कुल जनसंख्या के संदर्भ में, गैर-श्रमिक कुल जनसंख्या का 53.5% है (तालिका 3.17 देखें)।

तालिका 3-17: राजस्थान उप-क्षेत्र में श्रमिक और गैर-श्रमिक, 2011

राज्य	मुख्य श्रमिक			सीमांत श्रमिक			गैर श्रमिक			Total Workers (Main + Marginal)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
अलवर	9,82,840	1,96,621	11,79,461	5,05,095	23,986	5,29,081	15,31,793	4,33,844	19,65,637	14,87,935	2,20,607	17,08,542
हिस्सा %	83.33%	16.67%	100.00%	95.47%	4.53%	100.00%	77.93%	22.07%	100.00%	87.09%	12.91%	100.00%

स्रोत: भारत की जनगणना, *2011*

चित्र 3.11: राजस्थान उप-क्षेत्र में कुल श्रमिक और गैर-श्रमिक: 2011

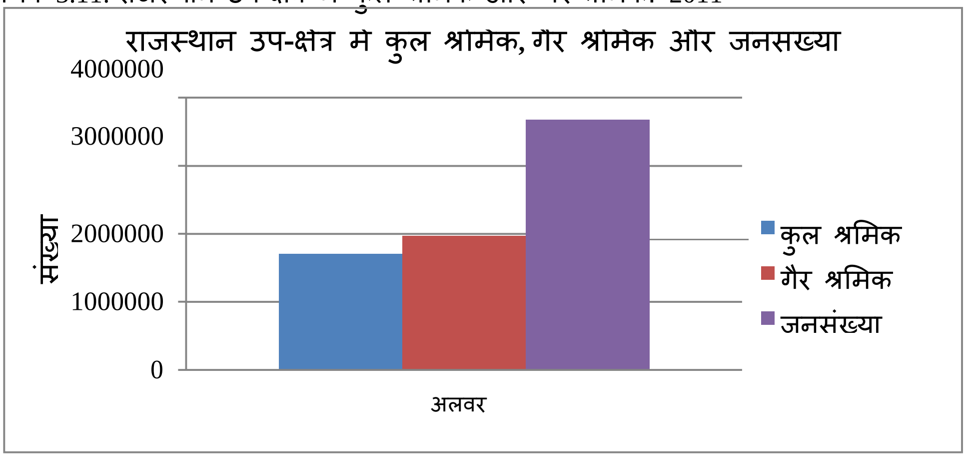

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

3.6 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र

3.6.1 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण, 2001

एनसीटी-दिल्ली में, कर्मचारी का उच्चतम अनुपात निर्माण (23.29%) में लगा हुआ है, इसके बाद 2001 में परिवहन, भंडारण और संचार (16.20%) और ग्रामीण उद्योग (10.98%) का स्थान है। इसका तात्पर्य है कि अधिकांश कर्मचारी द्वितीयक और तृतीयक (सेवा) क्षेत्र में लगे हुए हैं । कर्मचारी के स्थानिक वितरण के संदर्भ में, उनमें से अधिकांश उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिले और दक्षिणी दिल्ली जिले में हैं, जबकि इनमें से सबसे कम संख्या पश्चिमी दिल्ली जिले में है। द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्र उप-क्षेत्र में दूसरा प्रमुख नियोक्ता था और इस अवधि के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या सबसे कम थी। द्वितीयक क्षेत्र में, श्रमिकों की अधिकतम संख्या उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिले में केंद्रित थी, उसके बाद पश्चिमी दिल्ली जिले में, जबकि सबसे कम संख्या नई दिल्ली जिले में देखी गई। एनसीटी-दिल्ली में एनसीआर के सभी उप-क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या सबसे कम थी और उनमें से अधिकांश उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिले में और सबसे कम नई दिल्ली जिले में रहते हैं (तालिका 3.18, चित्र 3.12 और 3.13 देखें)।

तालिका 3-18: एनसीटी-दिल्ली में श्रेणीवार मुख्य श्रमिक, 2001

जिला	किसान	कृषि मजदूर	पशुपालन, वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	घरेलू उद्योग	घरेलू उद्योगों के अलावा	बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	कुल
उत्तर पश्चिम	6,823	14,125	9,580	88,917	3,813	1,08,210	45,846	86,464	2,19,285	1,01,070	1,18,926	56,330	62,988	**9,22,377**
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	43.26%	37.74%	25.65%	17.77%	24.02%	25.81%	19.46%	21.86%	20.66%	21.03%	16.11%	20.23%	18.45%	20.24%
उत्तर	1,163	1,477	1,651	23,621	684	24,327	14,000	16,153	78,027	31,972	30,942	15,597	18,189	**2,57,803**
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	7.37%	3.95%	4.42%	4.72%	4.31%	5.80%	5.94%	4.08%	7.35%	6.65%	4.19%	5.60%	5.33%	5.66%
उत्तर पूर्व	615	1,256	4,622	81,352	1,470	59,879	32,084	39,958	1,27,442	52,190	55,105	25,432	18,314	**4,99,719**
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	3.90%	3.36%	12.37%	16.26%	9.26%	14.28%	13.62%	10.10%	12.01%	10.86%	7.46%	9.13%	5.36%	10.97%
पूर्व	692	1,116	4,662	48,771	1,283	37,815	27,704	39,528	1,20,486	50,538	80,191	29,825	33,400	**4,76,011**

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	4.39%	2.98%	12.48%	9.75%	8.08%	9.02%	11.76%	9.99%	11.35%	10.52%	10.86%	10.71%	9.78%	10.45%
नई दिल्ली	84	105	292	2,466	88	1,460	1172	5,406	7,846	5,320	28,738	4,518	11,062	**68,557**
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	0.53%	0.28%	0.78%	0.49%	0.55%	0.35%	0.50%	1.37%	0.74%	1.11%	3.89%	1.62%	3.24%	1.50%
केंद्रीय	214	220	840	33,554	1,410	27,162	12,068	10,044	66,904	22,976	26,080	11,038	16,430	**2,28,940**
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	1.4%	0.6%	2.2%	6.7%	8.9%	6.5%	5.1%	2.5%	6.3%	4.8%	3.5%	4.0%	4.8%	5.0%
पश्चिम	837	2,998	2978	70,799	2,002	82,745	43,751	53,878	1,88,024	78,807	1,00,576	45,768	53,415	**7,26,578**
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	5.31%	8.01%	7.97%	14.15%	12.61%	19.74%	18.57%	13.62%	17.72%	16.40%	13.62%	16.43%	15.64%	15.94%
दक्षिण पश्चिम	3,603	14,128	6,654	48,218	1,852	37,930	24,973	59,174	1,02,844	64,858	1,55,943	36,804	44,642	**6,01,623**
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	22.84%	37.74%	17.81%	9.64%	11.67%	9.05%	10.60%	14.96%	9.69%	13.50%	21.13%	13.22%	13.07%	13.20%

जिला	किसान	कृषि मजदूर	पशुपालन, वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	घरेलू उद्योग	घरेलू उद्योगों के अलावा	बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	कुल
दक्षिण	1,742	2,006	6,074	1,02,550	3,271	39,745	33,943	85,003	1,50,356	72,849	1,41,679	53,170	83,003	**7,75,391**
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	11.04%	5.36%	16.26%	20.50%	20.61%	9.48%	14.41%	21.49%	14.17%	15.16%	19.19%	19.09%	24.31%	17.02%
एनसीटी-दिल्ली	**15,773**	**37,431**	**37,353**	**5,00,248**	**15,873**	**4,19,273**	**2,35,541**	**3,95,608**	**10,61,214**	**4,80,580**	**7,38,180**	**2,78,482**	**3,41,443**	**45,56,999**
% हिस्सा	**0.35%**	**0.82%**	**0.82%**	**10.98%**	**0.35%**	**9.20%**	**5.17%**	**8.68%**	**23.29%**	**10.55%**	**16.20%**	**6.11%**	**7.49%**	**100.00%**

स्रोत: भारत की जनगणना *2001*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 3.12: 2001 में एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण

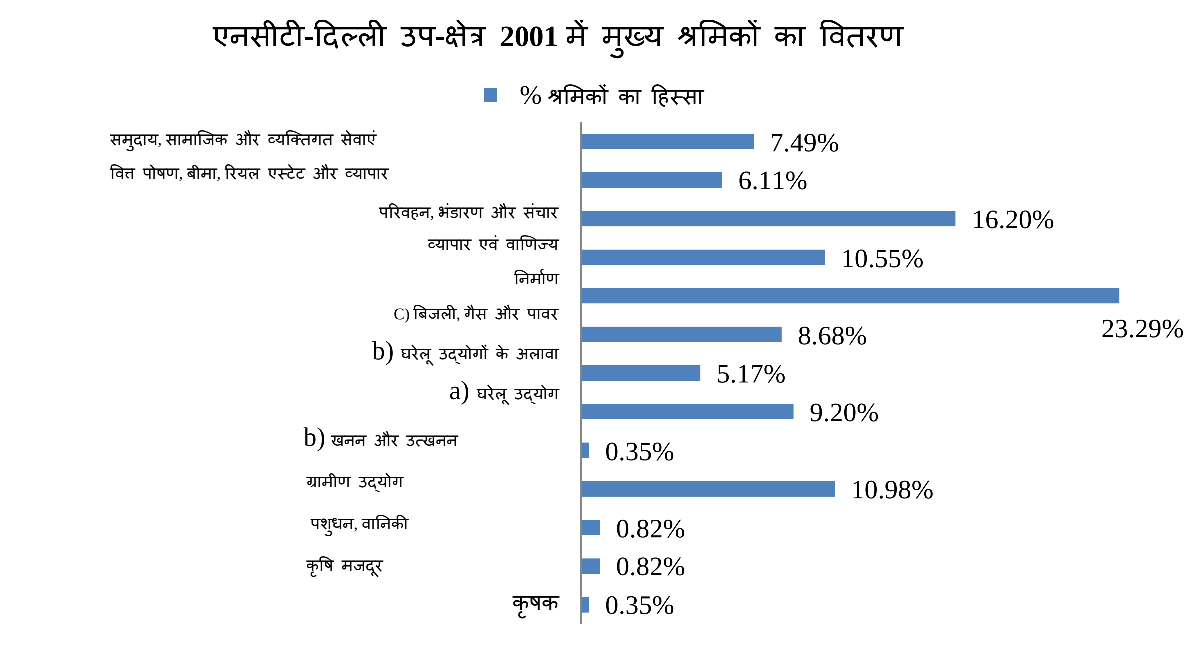

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र **3.13:** एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र के विभिन्न जिलों में श्रेणीवार श्रमिकों का वितरण: **2001**

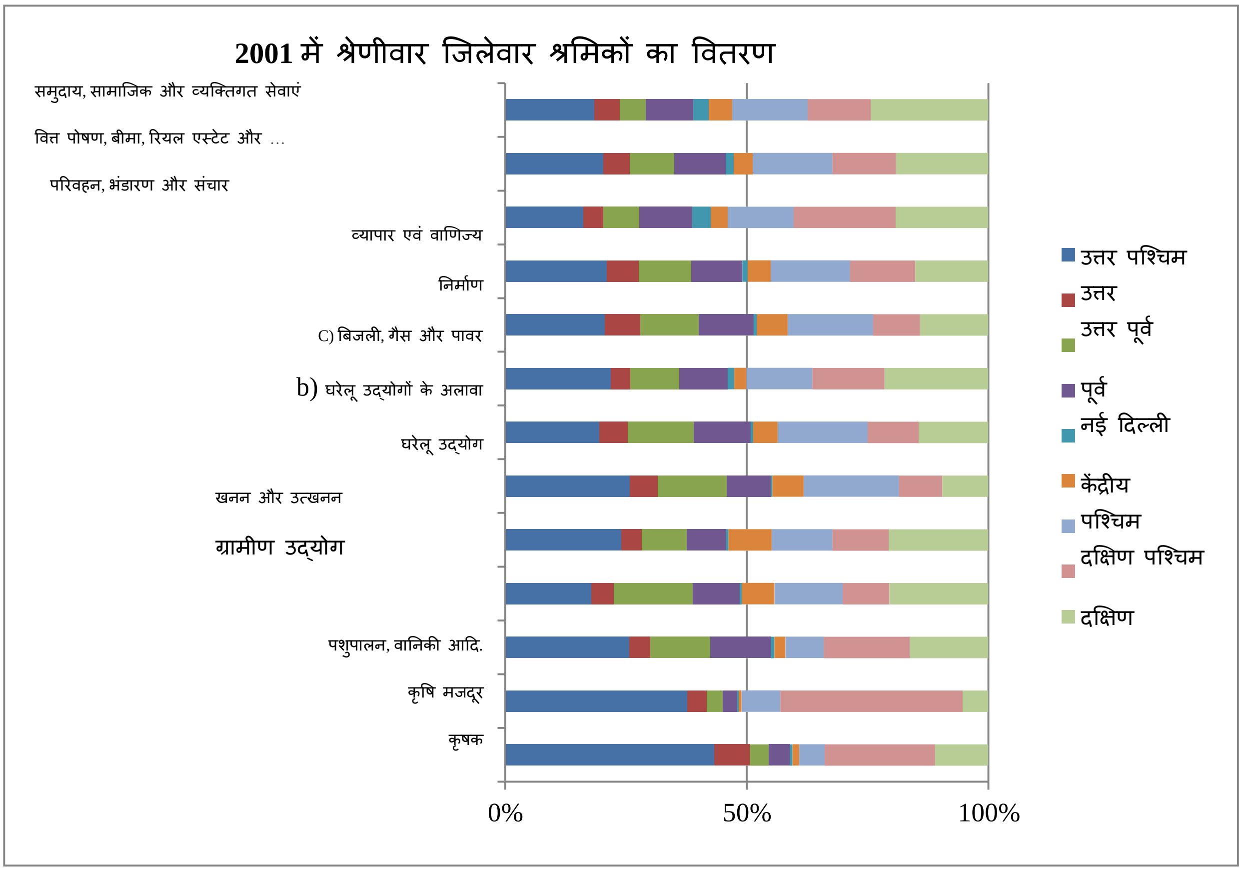

3.6.2 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में श्रमिक और गैर-श्रमिक, 2011

2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली उप-क्षेत्र के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, शहरी कर्मचारी कुल (मुख्य और सीमांत) श्रमिक बल पर हावी है। यह देखा गया है कि अधिकांश श्रमिक उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिले और दक्षिणी दिल्ली जिले में केंद्रित हैं; जबकि सबसे कम सघनता नई दिल्ली जिले में और उसके बाद मध्य दिल्ली जिले में दर्ज की गई है।

एनसीटी-दिल्ली में सीमांत श्रमिकों की कुल संख्या में पिछले कुछ वर्षों में नौकरी के अवसरों में वृद्धि के कारण जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। कुल कर्मचारी में यह वृद्धि, मुख्य और सीमांत दोनों में, मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों से बेरोजगार श्रमिकों के प्रवास के कारण है। एनसीटी-दिल्ली सरकार के योजना विभाग द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि एनसीटी-दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कर्मचारियों का 43% पड़ोसी राज्यों से है (तालिका 3.19 और चित्र 3.14 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 3-19: दिल्ली उप-क्षेत्र 2011 में जिलेवार श्रमिक और गैर-श्रमिक

जिला	मुख्य श्रमिक			सीमांत श्रमिक			गैर श्रमिक			कुल श्रमिक (मुख्य + सीमांत श्रमिक)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
उत्तर पश्चिम	61,679	10,73,447	11,35,126	5,813	47,606	53,419	1,46,458	23,21,536	24,67,994	67,492	11,21,053	11,88,545
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	52.05%	20.69%	21.39%	49.61%	17.76%	19.10%	50.71%	21.27%	22.03%	51.83%	20.54%	21.27%
उत्तर	5,052	2,78,531	2,83,583	226	12,637	12,863	12,468	5,79,064	5,91,532	5,278	2,91,168	2,96,446
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	4.26%	5.37%	5.34%	1.93%	4.72%	4.60%	4.32%	5.31%	5.28%	4.05%	5.34%	5.31%
उत्तर पूर्व	5,773	6,16,670	6,22,443	215	38,728	38,943	15,539	15,64,699	15,80,238	5,988	6,55,398	6,61,386
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	4.87%	11.88%	11.73%	1.83%	14.45%	13.92%	5.38%	14.34%	14.11%	4.60%	12.01%	11.84%
पूर्व	1,316	5,53,710	5,55,026	32	24,634	24,666	2,182	11,27,472	11,29,654	1,348	5,78,344	5,79,692
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	1.11%	10.67%	10.46%	0.27%	9.19%	8.82%	0.76%	10.33%	10.09%	1.04%	10.60%	10.38%
नई दिल्ली		56,471	56,471		3,070	3,070	0	82,463	82,463	0	59,541	59,541
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	0.00%	1.09%	1.06%	0.00%	1.15%	1.10%	0.00%	0.76%	0.74%	0.00%	1.09%	1.07%
केंद्रीय		1,95,978	1,95,978		11,396	11,396	0	3,74,946	3,74,946	0	2,07,374	2,07,374
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	0.00%	3.78%	3.69%	0.00%	4.25%	4.07%	0.00%	3.44%	3.35%	0.00%	3.80%	3.71%
पश्चिम	1680	8,37,941	8,39,621	166	34,533	34,699	4,574	16,64,349	16,68,923	1,846	8,72,474	8,74,320
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	1.42%	16.15%	15.82%	1.42%	12.89%	12.40%	1.58%	15.25%	14.90%	1.42%	15.99%	15.65%
दक्षिण पश्चिम	39,104	7,10,891	7,49,995	4,945	40,412	45,357	99,627	13,97,979	14,97,606	44,049	7,51,303	7,95,352
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	33.00%	13.70%	14.13%	42.20%	15.08%	16.22%	34.50%	12.81%	13.37%	33.82%	13.77%	14.24%
दक्षिण	3,906	8,65,180	8,69,086	320	54,987	55,307	7,967	17,99,569	18,07,536	4,226	9,20,167	9,24,393
एनसीटी-दिल्ली में % हिस्सा	3.30%	16.67%	16.38%	2.73%	20.52%	19.77%	2.76%	16.49%	16.14%	3.25%	16.86%	16.55%
दिल्ली के एनसीटी	**1,18,510**	**51,88,819**	**53,07,329**	**11,717**	**2,68,003**	**2,79,720**	**2,88,815**	**1,09,12,077**	**1,12,00,892**	**1,30,227**	**54,56,822**	**55,87,049**

स्रोत: भारत की जनगणना, *2011*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 3.14: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल श्रमिकों, गैर-श्रमिकों और जनसंख्या की जिलेवार संरचना, 2011

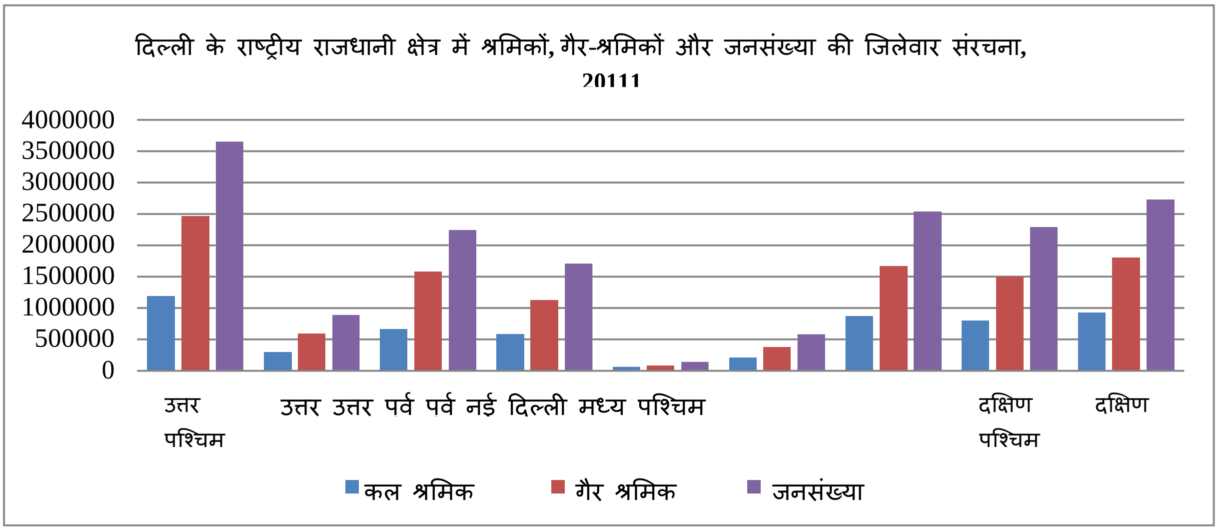

3.6.3 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण, 2011

उत्तर पश्चिमी दिल्ली में श्रमिकों की अधिकतम संख्या है, जिनमें से अधिकांश अन्य श्रमिक (11.27 लाख) हैं, इसके बाद घरेलू उद्योग के श्रमिक (35,896), कृषि मजदूर (39,475) और सबसे कम संख्या में किसान (11,433) हैं। एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र के सभी जिले समान पैटर्न की रिपोर्ट करते हैं, उत्तर और दक्षिण पश्चिम जिले को छोड़कर, जहां कृषि मजदूरों की तुलना में अधिक किसान हैं (चित्र 3.15 देखें)।

चित्र 3.15: एनसीटी-दिल्ली, 2011 में कुल श्रमिकों की जिलेवार व्यावसायिक रूपरेखा

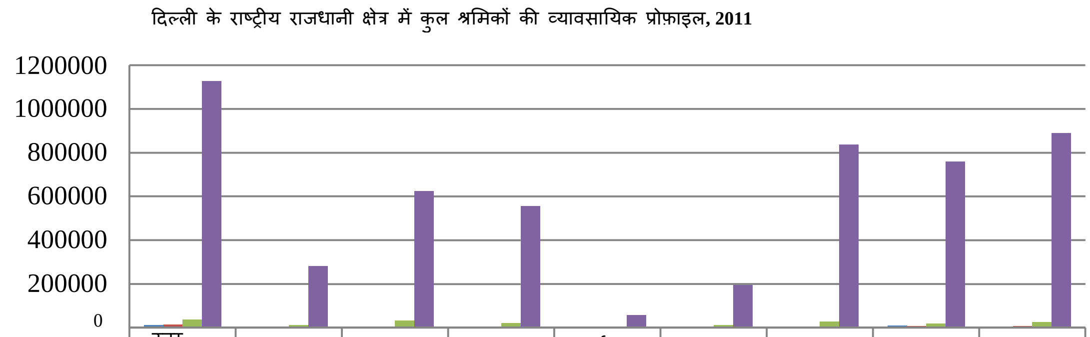

	उत्तर पश्चिम	उत्तर	उत्तर पूर्व	पूर्व	नई दिल्ली	मध्य	पश्चिम	दक्षिण पश्चिम	दक्षिण2
किसान	11433	2187	2235	1156	121	597	2952	9733	984
कृषि श्रमिक	13289	1791	2406	3094	275	601	4358	7753	5908
एचएच उद्योग	35896	11028	30738	19541	1030	10902	29022	18614	25081
अन्य	1127927	281440	626007	555901	58115	195274	837988	759252	890420

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

3.7 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

3.7.1 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण, 2001

उप-क्षेत्र स्तर पर श्रेणीवार श्रमिकों का वितरण:

2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, कुल मुख्य श्रमिकों में से 38.00% खेती में लगे हुए हैं, इसके बाद निर्माण (12.86%) का स्थान आता है। यह उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण और संबंधित निर्माण गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, खासकर उन जिलों में जो एनसीटी-दिल्ली से सटे हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 1991-2001 के दौरान निर्माण में लगे श्रमिकों के अनुपात में लगभग पांच गुना (1991 में 2.47% से 2001 में 12.86%) वृद्धि हुई है। परिवहन, भंडारण और संचार में लगे श्रमिकों का अनुपात भी 1991-2001 के दौरान लगभग तीन गुना हो गया है (तालिका 3.20 और चित्र 3.15 देखें)।

तालिका 3-20: उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण (1971, 1991 और 2001)

वर्ष	1971		1991		2001	
श्रमिकों की श्रेणी	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत
किसान	6,53,043	44.05	8,57,869	34.69	11,10,693	38.00
कृषि मजदूर	2,34,258	15.8	4,73,885	19.16	-	-
पशुपालन, वानिकी आदि	22,364	1.51	21,662	0.88	1,46,294	5.01
ग्रामीण उद्योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2,24,482	7.68
खनन और उत्खनन	460	0.03	376	0.02	3,348	0.11
निर्माण, प्रसंस्करण						
a) घरेलू उद्योग	90,998	6.14	53,978	2.18	1,58,564	5.43
b) घरेलू उद्योगों के अलावा	1,09,850	7.41	3,09,259	12.5	1,02,794	3.52
बिजली, गैस और पावर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,72,967	5.92
निर्माण	20,886	1.41	61,123	2.47	3,75,954	12.86
व्यापार एवं वाणिज्य	93,755	6.32	2,33,030	9.42	1,58,929	5.44
परिवहन, भंडारण और संचार	42,195	2.85	82,169	3.32	2,78,696	9.54
अन्य सेवाएं	2,14,618	14.48	3,79,953	15.36	1,89,783	6.49
कुल मुख्य कार्यकर्ता	**14,82,427**	**100**	**24,73,304**	**100**	**29,22,504**	**100.00**

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

जनसंख्या	54,40,296		90,01,704		1,15,67,090	
भागीदारी अनुपात	27.25		27.48		25.27	

स्रोत: भारत की जनगणना, *1971*, *1991* और *2001*, भारत सरकार,

*इसमें कृषि श्रमिक भी शामिल हैं

चित्र 3.16: 2001 में उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में मुख्य कर्मचारी का वितरण

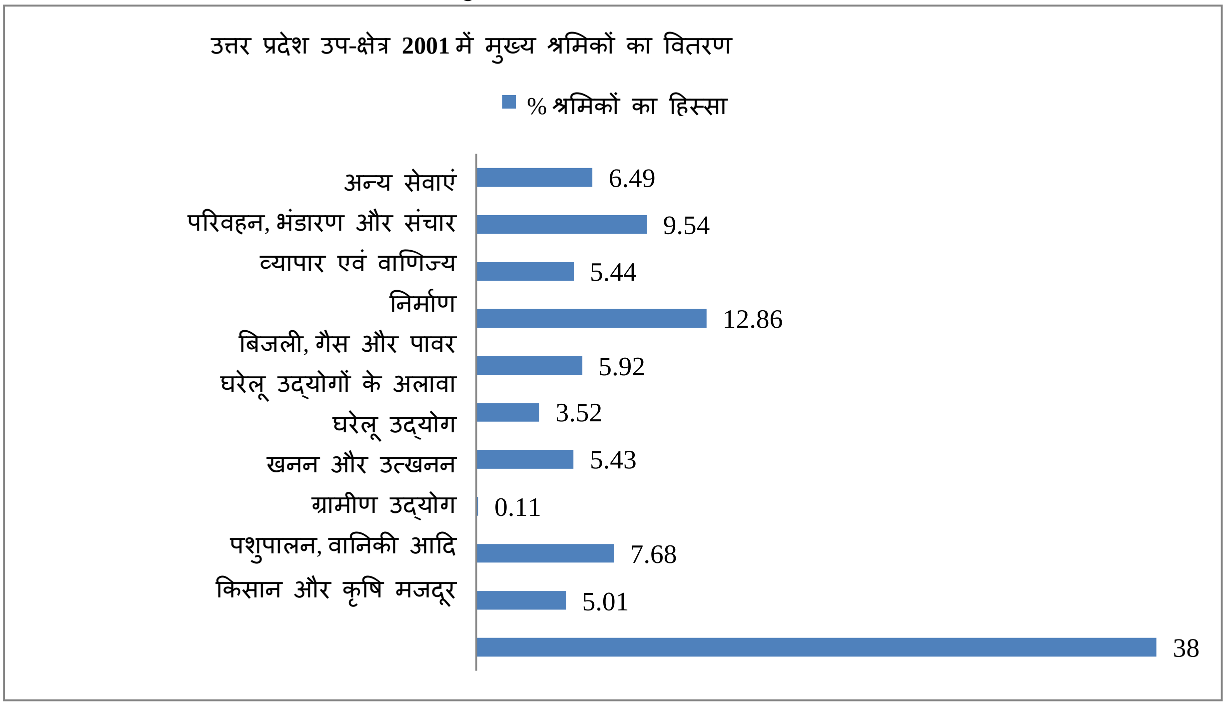

जिला स्तर पर श्रेणीवार श्रमिकों का वितरण:

गाजियाबाद जिला अधिकांश श्रेणियों के कर्मचारी में सबसे अधिक योगदान देता है, इसके बाद मेरठ और बुलंदशहर जिले हैं। बागपत जिला सभी श्रेणियों के कर्मचारी में सबसे कम योगदान देता है। गाजियाबाद जिला खनन और उत्खनन श्रेणी में कर्मचारी का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, इसके बाद गौतमबुद्धनगर जिला है। एकमात्र श्रेणियां, जो श्रमिक आबादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती हैं, वे हैं खेती और खेतिहर मजदूर जिनमें बुलंदशहर जिला सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, उसके बाद मेरठ जिला है (तालिका 3.21 और चित्र 3.16 देखें)।

तालिका 3-21: उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र 2001 में जिला स्तर पर श्रेणीवार कर्मचारी का वितरण

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

जिला	किसान	कृषि मजदूर	पशुपालन, वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	घरेलू उद्योग	घरेलू उद्योगों के अलावा	बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	कुल
बागपत	70,220	1,51,325	16,827	21,571	173	15,989	5,975	13,478	28,858	11,145	20,196	11,068	6110	3,72,935
यूपी उप-क्षेत्र में % हिस्सा	14.61%	14.52%	6.59%	7.31%	4.87%	8.44%	4.93%	6.05%	6.87%	6.45%	6.38%	9.93%	6.18%	

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

जिला	किसान	कृषि मजदूर	पशुपालन, वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	घरेलू उद्योग	घरेलू उद्योगों के अलावा	बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	कुल
बुलंदशहर	1,95,852	4,19,885	1,40,583	82,754	417	38,343	22,806	41,351	98,260	32,489	60,295	21,461	19330	11,73,826
यूपी उप-क्षेत्र में % हिस्सा	40.75%	40.30%	55.08%	28.05%	11.75%	20.24%	18.83%	18.57%	23.39%	18.81%	19.03%	19.26%	0.1,95,4045	
गौतम बुद्ध नगर	34,338	93,015	13,884	20,839	850	17,772	16,761	21,637	37,036	16,594	59,172	12,950	16,917	3,61,765
यूपी उप-क्षेत्र में % हिस्सा	7.14%	8.93%	5.44%	7.06%	23.95%	9.38%	13.84%	9.72%	8.82%	9.61%	18.68%	11.62%	17.10%	
गाजियाबाद	69,775	1,60,566	38,113	89,367	1,638	66,885	46,526	81,035	1,41,734	66,229	1,04,783	35,586	32,203	9,34,440
यूपी उप-क्षेत्र में % हिस्सा	14.52%	15.41%	14.93%	30.29%	46.15%	35.31%	38.41%	36.39%	33.75%	38.35%	33.08%	31.94%	32.55%	
मेरठ	1,10,440	2,17,120	45,821	80,514	471	50,441	29,050	65,168	1,14,126	46,239	72,331	30,345	24,363	8,86,429
यूपी उप-क्षेत्र में % हिस्सा	22.98%	20.84%	17.95%	27.29%	13.27%	26.63%	23.98%	29.27%	27.17%	26.77%	22.83%	27.24%	24.63%	
यूपी उप-क्षेत्र	**4,80,625**	**10,41,911**	**2,55,228**	**2,95,045**	**3,549**	**1,89,430**	**1,21,118**	**2,22,669**	**4,20,014**	**1,72,696**	**3,16,777**	**1,11,410**	**98,923**	**37,29,395**

स्रोत: भारत की जनगणना *2001*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 3.17: 2001 में सभी श्रमिकों का श्रेणीवार जिलावार वितरण

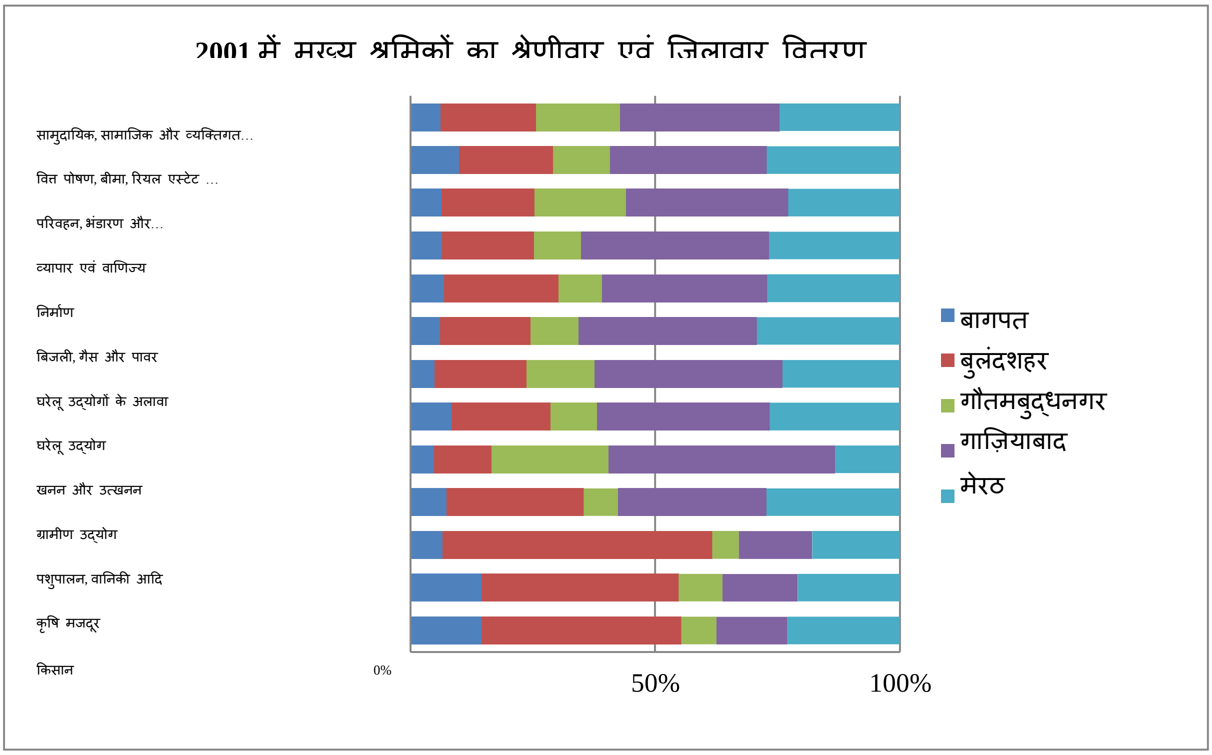

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001, भारत सरकार

3.7.2 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में श्रमिक और गैर-श्रमिक, 2011

2011 की जनगणना के अनुसार, उप-क्षेत्र में कुल 47.70 लाख श्रमिक हैं और उनमें से आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। गाजियाबाद (हापुड़ सहित) जिले में सबसे अधिक श्रमिक (15.20 लाख) दर्ज किए गए, जिनमें से 10.24 लाख शहरी क्षेत्र में और 4.96 लाख ग्रामीण क्षेत्र में थे। बागपत जिले में सबसे कम 4.17 लाख श्रमिकों की संख्या दर्ज की गई। उप-क्षेत्र में कुल 38.22 लाख और 9.48 लाख मुख्य और सीमांत श्रमिक थे। मुख्य श्रमिकों की अधिकतम संख्या गाजियाबाद जिले में और सबसे कम बागपत जिले में देखी गई, हालांकि बुलंदशहर जिले में सीमांत श्रमिकों की अधिकतम संख्या (2.88 लाख) और बागपत में सबसे कम (0.82 लाख) दर्ज की गई। उप-क्षेत्र में कुल 98.05 लाख गैर-श्रमिक दर्ज किए गए, जिनमें से आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। गैर-श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या गाजियाबाद जिले में दर्ज की गई, जिनमें से लगभग एक तिहाई शहरी क्षेत्रों में हैं। बागपत जिले में गैर-श्रमिकों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई, हालांकि यह देखा गया है कि उप-क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान जिले की न्यूनतम आबादी थी (तालिका 3.22 देखें)।

जिलेवार जनसंख्या का वितरण इंगित करता है कि गाजियाबाद (हापुड़ सहित) जिले में उप-क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या (46.81 लाख) थी, जहां अधिकतम श्रमिक (15.21 लाख) थे, जबकि बागपत जिले में न्यूनतम जनसंख्या (13.03 लाख) और उप-क्षेत्र में कुल श्रमिक (4.17 लाख) थे। (चित्र 3.18 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 3-22: उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में जिलेवार श्रमिक और गैर श्रमिक, 2011

जिला	मुख्य श्रमिक			सीमांत श्रमिक			गैर श्रमिक			कुल श्रमिक (मुख्य + सीमांत श्रमिक)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
बागपत	2,66,268	68,251	3,34,519	71,295	10,881	82,176	6,90,460	1,95,893	8,86,353	3,37,563	79,132	4,16,695
यूपी उप-क्षेत्र में % हिस्सा	13.99%	3.56%	8.75%	11.70%	3.21%	8.67%	13.74%	4.10%	9.04%	13.43%	3.51%	8.74%
बुलंदशहर	6,66,615	2,18,601	8,85,216	2,52,858	35,186	2,88,044	17,12,269	6,13,642	23,25,911	9,19,473	2,53,787	11,73,260
यूपी उप-क्षेत्र में % हिस्सा	35.02%	11.40%	23.16%	41.49%	10.39%	30.38%	34.08%	12.83%	23.72%	36.59%	11.24%	24.60%
गौतमबुद्धनगर	1,56,310	3,02,182	4,58,492	60,363	50,254	1,10,617	4,57,133	6,21,873	10,79,006	2,16,673	3,52,436	5,69,109
यूपी उप-क्षेत्र में % हिस्सा	8.21%	15.75%	12.00%	9.90%	14.84%	11.67%	9.10%	13.01%	11.00%	8.62%	15.62%	11.93%
गाजियाबाद + हापुड़	3,85,408	8,67,503	12,52,911	1,10,669	1,56,958	2,67,627	10,23,021	21,38,086	31,61,107	4,96,077	10,24,461	15,20,538
यूपी उप-क्षेत्र में % हिस्सा	20.25%	45.22%	32.78%	18.16%	46.34%	28.22%	20.36%	44.72%	32.24%	19.74%	45.39%	31.88%
मेरठ	4,29,083	4,61,727	8,90,810	1,14,283	85,446	1,99,729	11,41,141	12,12,009	23,53,150	5,43,366	5,47,173	10 ,90,539
यूपी उप-क्षेत्र में % हिस्सा	22.54%	24.07%	23.31%	18.75%	25.23%	21.06%	22.71%	25.35%	24.00%	21.62%	24.24%	22.86%
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	**19,03,684**	**19,18,264**	**38,21,948**	**6,09,468**	**3,38,725**	**9,48,193**	**50,24,024**	**47,81,503**	**98,05,527**	**25,13,152**	**22,56,989**	**47,70,141**

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, *2011*, भारत सरकार

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 3.18: 2011 में एनसीआर के उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में श्रमिकों, गैर-श्रमिकों और जनसंख्या की जिलेवार संरचना

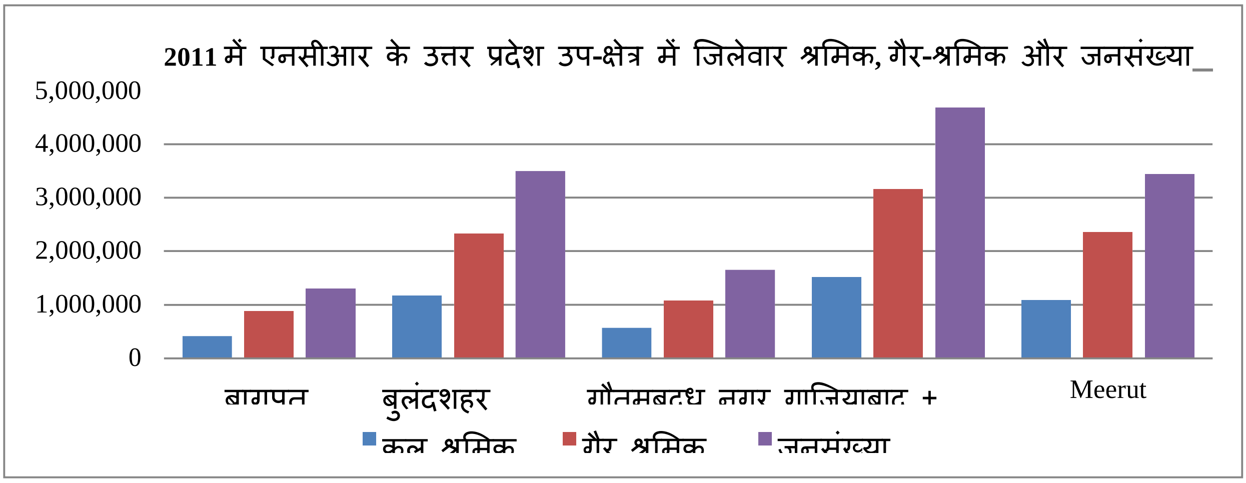

3.7.3 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में कर्मचारी वितरण: 2011

उप-क्षेत्र में किसानों और खेतिहर मजदूरों की संख्या के मामले में, बुलंदशहर जिले में सबसे अधिक काश्तकारों की संख्या दर्ज की गई, उसके बाद मेरठ जिले में और सबसे कम गौतमबुद्ध नगर जिले में, उसके बाद बागपत जिले में दर्ज किया गया। गाजियाबाद (हापुड़ सहित) जिले (11.54 लाख) में 2011 में उप क्षेत्र में औद्योगिक और तृतीयक क्षेत्र के श्रमिकों की अधिक संख्या है, इसके बाद मेरठ जिले (6.77 लाख), बुलंदशहर जिले (11.73 लाख) और सबसे कम बागपत जिले (1.97 लाख) की हैं। घरेलू उद्योगों के मामले में, गाजियाबाद जिले (83,672) ने सबसे अधिक श्रमिकों को दर्ज किया है, इसके बाद बुलंदशहर जिले (65,937), मेरठ जिले (63,096), गौतमबुद्ध नगर जिले (35,400) और बागपत जिले (20,347) (चित्र 3.19 देखें) का स्थान है।

चित्र 3.19: 2011 में उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में कुल श्रमिकों की जिलेवार व्यावसायिक प्रोफ़ाइल

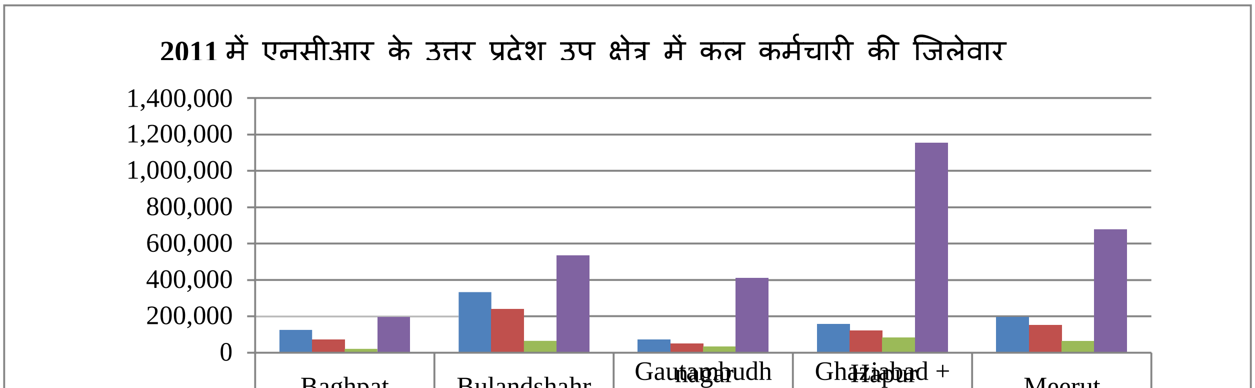

	Baghpat	Bulandshahr	Gautambudh nagar	Ghaziabad + Hapur	Meerut
किसान	124,718	332,475	72,668	158,868	196,068
कृषि श्रमिक	74,500	241,137	48,845	123,680	153,995
एचएच उद्योग	20,347	65,937	35,400	83,672	63,096
अन्य	197,130	533,711	412,196	1,154,318	677,380

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना, *2011*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

3.8 2021 से 2031 के लिए रोजगार अनुमान

एनसीआर में रोजगार का अनुमान दो परिदृश्यों पर आधारित है, अर्थात (a) निरंतर भागीदारी दर और (b) परिवर्तनीय भागीदारी दर। निरंतर भागीदारी दर के मामले में, रोजगार अनुमानों में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन के कारण हुआ। हालांकि, क्षेत्र की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण परिवर्तनशील भागीदारी के मामले में, विभिन्न श्रेणियों के तहत रोजगार के स्तर अलग-अलग होंगे। उम्मीद है कि आर्थिक ढांचे में बदलाव के कारण हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों के सभी जिलों में कृषि क्षेत्र में भागीदारी दर में 1 से 2 प्रतिशत अंक की गिरावट आने की संभावना है। वहीं औद्योगिक नीतियों और अन्य निवेश प्रभाव के कारण रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, बुलंदशहर और बागपत जिलों में विनिर्माण क्षेत्र में 1 से 2 प्रतिशत अंक की वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही उच्च स्तर की आर्थिक परिपक्वता वाले जिलों में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी दर जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और मेरठ में 1 से 2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होगी।

एनसीआर में कुल कर्मचारी 2001 में 131.55 लाख से बढ़कर 2021 में 194.75 लाख और 2031 में 234.12 लाख हो जाने का अनुमान है। कर्मचारी का उच्चतम हिस्सा कृषि गतिविधियों में नियोजित होने की उम्मीद है, इसके बाद 2021 और 2031 दोनों में निर्माण और निर्माण होगा। तालिका 3.23 देखें)।

वर्तमान (2001) भागीदारी दर और समायोजित भागीदारी दर के आधार पर 2021 और 2031 के लिए कर्मचारी का अनुमान क्रमशः अनुलग्नक-3.9 से अनुलग्नक-3.12 में दिया गया है।

तालिका 3-23: 2021 से 2031 के लिए गतिविधिवार रोजगार अनुमान

वर्ष	कृषि	खनन और	उत्पादन	बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और	सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	कुल
2001 वास्तविक	57,89,083	42,439	13,81,743	8,65,302	18,52,217	8,35,849	13,15,842	5,32,301	5,40,755	1,31,55,531
2021 लगातार भागीदारी दर	86,07,549	64,301	20,36,919	12,81,750	26,95,338	12,16,754	19,32,741	7,72,535	7,84,393	1,93,92,280

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

2021 समायोजित भागीदारी दर	78,87,272	64,301	21,96,595	12,81,750	29,20,969	13,88,529	19,53,202	9,97,889	7,84,393	1,94,74,900
2031 लगातार भागीदारी दर	1,04,49,079	74,841	24,42,944	15,39,133	32,03,048	14,43,364	23,09,591	9,16,913	9,27,448	2,33,06,361
2031 समायोजित भागीदारी दर	95,73,701	74,841	26,40,878	15,39,133	34,84,477	16,50,411	23,34,060	11,87,410	9,27448	2,34,12,359

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल पर अध्ययन

गतिविधि-वार कर्मचारी वृद्धि इंगित करती है कि एनसीआर में रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं, व्यापार और वाणिज्य और विनिर्माण की गतिविधियों में कर्मचारी के तेज दर से बढ़ने की संभावना है (तालिका 3.24 देखें)।

तालिका 3-24: 2001 से 2021 और 2031 तक गतिविधि के अनुसार कर्मचारी की वृद्धि

वर्ष	कृषि	खनन और उत्खनन	उत्पादन	बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	कुल
2001 से 2021 स्थिर (%प्रतिशत)	48.69	51.51	47.42	48.13	45.52	45.57	46.88	45.13	45.06	47.41
2001 से 2021 समायोजित (% age)	36.24	51.51	58.97	48.13	57.7	66.12	48.44	87.47	45.06	48.04
2001 से 2021 स्थिर (%प्रतिशत)	80.5	76.3	76.8	77.9	72.9	72.7	75.5	72.3	71.5	77.2
2001 से 2031 समायोजित (%प्रतिशत)	65.4	76.3	91.1	77.9	88.1	97.5	77.4	123.1	71.5	78

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल पर अध्ययन

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

4. औद्योगिक विकास

4.1 पृष्ठभूमि

एनसीआर में औद्योगिक गतिविधियां पिछले तीन-चार दशकों में विकसित हुई हैं। काफी हद तक, एनसीआर में औद्योगिक गतिविधि बड़ी और मध्यम इकाइयों, लघु-स्तरीय उद्योगों (एसएसआई) और छोटी असंगठित इकाइयों के अस्तित्व की विशेषता है।

एनसीआर में औद्योगीकरण उत्तर प्रदेश (सामान्य निर्माण), हरियाणा (ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथकरघा) और राजस्थान (संगमरमर, चमड़ा और कपड़ा) के उप-क्षेत्रों में केंद्रित है। यह क्षेत्र देश के कारों, मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टरों के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। विभिन्न औद्योगिक संपदाओं/मॉडल औद्योगिक कस्बों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास के माध्यम से एनसीआर और उसके आसपास औद्योगीकरण को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह देखा गया है कि एनसीआर में कई एसईजेड चालू हैं (तालिका 4.1 देखें)। एनसीआर में एसईजेड की सूची, जिन्हें एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक मंजूरी दी गई थी, अनुलग्नक-4.1 में दी गई है।

तालिका 4-1: एनसीआर में परिचालन सेज की सूची (5 दिसंबर, 2014 तक)

क्रमांक	एसईजेड का नाम	प्रकार
1	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	बहु उत्पाद
2	डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव	आईटी/आईटीईएस
3	डीएलएफ लिमिटेड गुड़गांव	आईटी/आईटीईएस
4	गुड़गांव इन्फोस्पेस लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
5	एचसीएल टेक्नोलॉजीज	आईटी/आईटीईएस
6	मोजर बेयर एसईजेड	सौर ऊर्जा उपकरण/सेल सहित गैर-पारंपरिक ऊर्जा
7	विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
8	सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
9	एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नोएडा	आईटी/आईटीईएस
10	अचविश सॉफ्टेक (मैसर्स फाल्कन कालटेक (प्रा.) लिमिटेड), नोएडा	आईटी/आईटीईएस
11	एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नोएडा	आईटी/आईटीईएस
12	अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, बुलंदशहर	एफटीडब्ल्यूजेड
13	अंसल सिटी और आईटी पार्क, नोएडा	आईटी/आईटीईएस
14	एएसएफ इन्सिग्निया एसईजेड प्रा. लिमिटेड (पूर्व में कैंटन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड) ग्राम गवल पहरि, तहसील सोहना गुड़गांव	आईटी/आईटीईएस
15	यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
16	अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस

स्रोत: भारत में एसईजेड, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, *sezindia.nic.in*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा प्रकाशित 2005 के आंकड़ों के अनुसार, एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में लगभग एक लाख निर्माण इकाइयाँ हैं, जिनमें लगभग छह लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश इकाइयाँ असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। यह अनुमान है कि असंगठित क्षेत्र की 97,636 निर्माण इकाइयां एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में 4.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देती हैं। 2005 में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में 1.2 लाख श्रमिकों को रोजगार देने वाले संगठित क्षेत्र में 3,312 इकाइयाँ हैं। एनसीटी-दिल्ली में परिधान और फर्नीचर निर्माताओं की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जिसके बाद विद्युत मशीनरी उत्पादन और मरम्मत सेवाएं हैं। दिल्ली में निर्माण मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर और कम कुशल है, जो दिल्ली को पड़ोसी उप-क्षेत्रों के प्रवासियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाता है, जिससे इसके संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ता है। दूसरी ओर, दिल्ली में रहने वाले कुशल लोग हर दिन गुड़गांव और नोएडा जैसे अन्य शहरों में काम करने के लिए आते हैं। इसके अलावा, प्रकृति में छोटे पैमाने पर होने के कारण, दिल्ली में इकाइयों को प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने में अपर्याप्त रूप से निवेश किया जाता है। इस उप-क्षेत्र में मजबूत लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र पूंजीगत वस्तुओं के लिए मरम्मत सेवाएं प्रदान करता है और मुख्य रूप से धातु उत्पादों, चमड़े और फर उत्पादों, लकड़ी के फर्नीचर, खाद्य प्रसंस्करण के निर्माण में लगा हुआ है।

राजस्थान उप-क्षेत्र का औद्योगिक प्रदर्शन ज्यादातर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा संचालित है। ये उद्यम मध्यम और बड़े उद्योगों द्वारा उत्पन्न रोजगार का सात गुना सृजन करते हैं, और इस प्रकार रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, उप-क्षेत्र में बड़ी संख्या में मध्यम और बड़ी इकाइयाँ भी हैं; राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (रीको) द्वारा विकसित 15 औद्योगिक क्षेत्रों में अलवर की 300 से अधिक मध्यम और बड़ी इकाइयाँ हैं। उप-क्षेत्र में मुख्य उद्योगों में कृषि उद्योग, सीमेंट उत्पाद, चीनी मिट्टी, खाद्य प्रसंस्करण, हाथ उपकरण, हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित कागज, रत्न और गहने, संगमरमर, तेल उद्योग और पत्थर उत्खनन शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में मजबूत माध्यमिक क्षेत्र तुलनात्मक रूप से विकसित औद्योगिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग के लिए 19% भूमि आरक्षित है। हापुड़ में एक एकीकृत कृषि-खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रस्तावित है। इसके अलावा, उप-क्षेत्र में लगभग 40 आईटी/आईटीईएस पार्क, एक नॉलेज पार्क और दो बायोटेक जोन भी प्रस्तावित हैं। डीएमआईसी परियोजना के तहत आईएल एंड एफएस, मिनरल एंड माइनिंग ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और मित्सुई (जापान) के सहयोग से एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन) भी प्रस्तावित किए गए हैं।

एनसीआर में महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत हैं। ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल, जनरल इंजीनियरिंग, पावरलूम, कारपेट आदि जैसे क्षेत्र में 40 से अधिक औद्योगिक केंद्र हैं। हालांकि, नियामक तंत्र ने काफी हद तक बड़े / मध्यम पैमाने के उद्योगों के विस्तार / विकास की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा, विनियमन की कमी और शक्तिशाली बाजार ताकतों ने एक असंगठित स्थिति पैदा कर दी जिसके परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र में कहीं भी और हर जगह, विशेष रूप से एनसीटी-दिल्ली में छोटे और छोटे उद्योग पनपने लगे। दूसरी ओर, दिल्ली को छोड़कर एनसीआर के बड़े हिस्से में, बड़े और मध्यम उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को आंशिक रूप से नियामक तंत्र और आंशिक रूप से ऐतिहासिक कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी)

डीएमआईसी एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य दिल्ली और मुंबई के बीच हाई-स्पीड कनेक्टिविटी

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

है। डीएमआईसी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) एनसीआर में बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक रूप से जोड़ा जायेगा। डीएमआईसी के तहत, एनसीआर में तीन निवेश क्षेत्र (आईआर) प्रस्तावित हैं, अर्थात्:

- दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में सामान्य निर्माण निवेश क्षेत्र के रूप में;
- मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र हरियाणा उप-क्षेत्र में ऑटो कॉम्पोनेन्ट/ऑटोमोबाइल निवेश क्षेत्र के रूप में; तथा
- सामान्य निर्माण/ऑटोमोबाइल/ऑटो कॉम्पोनेन्ट निवेश क्षेत्र के रूप में राजस्थान उप-क्षेत्र में खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र।

एनसीआर में डीएफसी के साथ-साथ दो महत्वपूर्ण जंक्शन रेवाड़ी-हिसार-लुधियाना/बठिंडा मार्गों से आने-जाने वाले यातायात के लिए रेवाड़ी हैं और तुगलकाबाद (और आईसीडी तुगलकाबाद) से यातायात के लिए पिरथला (तुगलकाबाद) हैं।

4.2 बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों का विविधीकरण और विकास के निर्धारक

एनसीआर में लगभग 1.52 लाख पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनमें लगभग 10.73 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इन इकाइयों में कुल निवेश लगभग 9,82,577 लाख रुपये है (तालिका 4.2 देखें)।

तालिका 4-2: एनसीआर में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां, रोजगार और निवेश (2010-11)

जिला / उप-क्षेत्र	इकाइयों की संख्या (मौजूदा पंजीकृत)	रोज़गार	निवेश (लाख रुपये में)
मेरठ	8,197	51,605	66,856.49
बागपत	2,613	12,665	9,386.09
गाज़ियाबाद	45,282	2,26,824	3,26,676.13
गौतमबुद्ध नगर	9,880	1,41,295	1,47,215.53
बुलंदशहर	4,629	23,566	2,465.1
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र का योग	**70,601**	**4,55,955**	**5,52,599.34**
दिल्ली	20,648	22,709	24,300
दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का योग	**20,648**	**22,709**	**24,300**
अलवर	551	NA	1,400
राजस्थान उप-क्षेत्र का योग	**551**	**0**	**1,400**
फरीदाबाद	17,291	1,04,452	1,89,517
पलवल	59	1,960	9,621.08
गुडगाँव	22,491	3,29,340	67,126
झज्जर	1,849	17,882	29,307
पानीपत	4,068	41,456	8,26,87.45
रेवाड़ी	1,370	30,313	11,200
रोहतक	4,761	8,201	10,592.96

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

सोनीपत	8,743	59,707	1,033.18
मेवात	42	1,156	3,193.28
हरियाणा उप-क्षेत्र का योग	**60,674**	**5,94,467**	**4,04,277.95**
कुल योग/एनसीआर	**1,52,474**	**10,73,131**	**9,82,577.29**

स्रोत: संबंधित जिलों के औद्योगिक प्रोफाइल, डीसी एमएसएमई, *http://dcmsme.gov.in/dips*

4.2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उप-क्षेत्र

एनसीटी-दिल्ली निर्माण क्षेत्र जीएसडीपी में लगभग 10% का योगदान देता है। पिछले चार दशकों में एनसीटी-दिल्ली में एसएसआई की अभूतपूर्व वृद्धि 1961 में 17,000 से 2000-01 में 1.29 लाख हुई है। वृद्धि मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में है, क्योंकि दिल्ली में नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में केवल 25,000 से 30,000 भूखंड / औद्योगिक इकाइयाँ हैं। वित्त वर्ष 2009-10 में उनका कुल उत्पादन स्थिर (2004-05) कीमतों पर 245300.2 मिलियन रुपये था। एनसीटी-दिल्ली में कारखानों में विकास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण इंगित करता है कि 1981-1991 की अवधि में कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई जिसके बाद 2005 तक क्रमिक वृद्धि हुई और फिर प्रवृत्तियों में गिरावट आई (चित्र 4.1 देखें)। हालांकि, एनसीटी-दिल्ली का औद्योगिक या निर्माण जीडीपी 2004-05 से 2009-10 तक बढ़ता रहा (नीचे चित्र 4.2 देखें)।

चित्र 4.1: 1981-2008 के दौरान एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में पंजीकृत फैक्ट्रियां

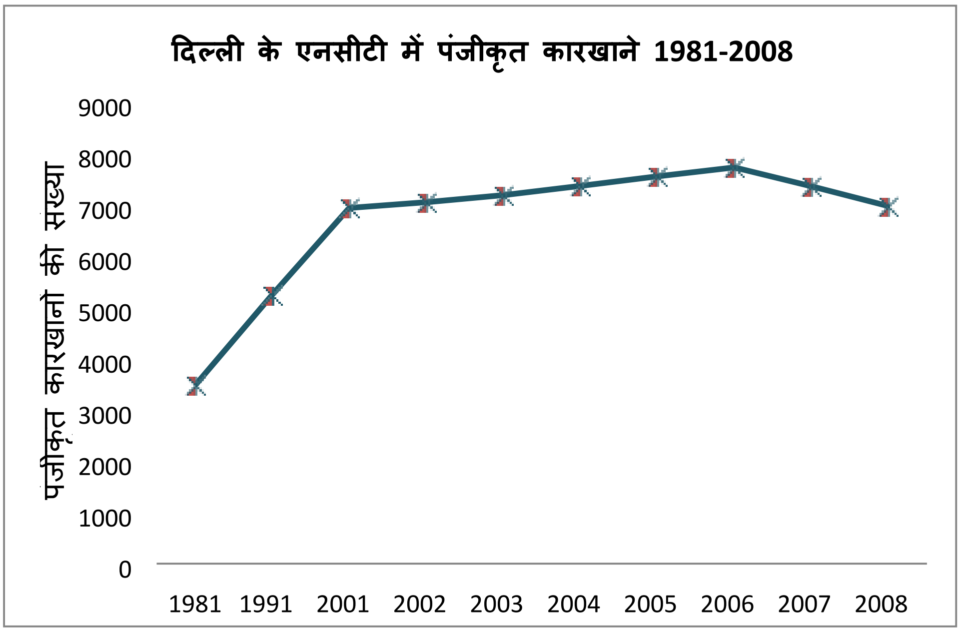

स्रोत: एनसीटी दिल्ली सरकार, दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण, ***2008-09***

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में माध्यमिक या निर्माण क्षेत्र का जीडीपी (लगातार 2004-05 की कीमतों पर) 2004-05 से 2009-10 तक (लाख रुपये में)

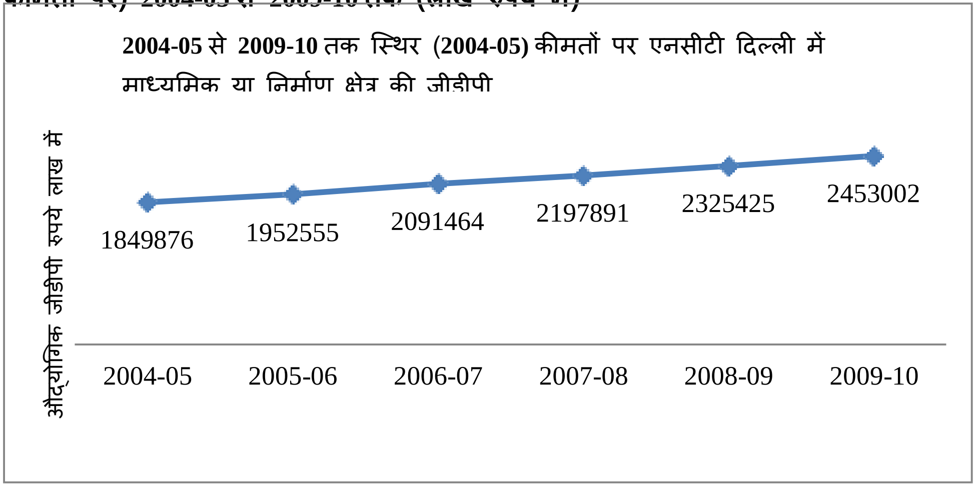

स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली; *2012-13* के दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

कार्यरत कारखानों की संरचना

2008 में एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों की संख्या और संरचना का विश्लेषण इंगित करता है कि काम करने वाले कारखानों की अधिकतम संख्या टेक्सटाइल (24%) के क्षेत्र में हैं, इसके बाद धातु उत्पादों और मशीनरी भागों (22%) का स्थान है। जबकि गैर-धातु उद्योग में संचालित कारखानों की न्यूनतम संख्या (तालिका 4.3 और चित्र 4.3 देखें)।

तालिका 4-3: एनसीटी-दिल्ली में कार्यरत कारखानों की संख्या: 2008

क्रम संख्या	कारखाने का प्रकार	कारखाने की संख्या
1	खाद्य उत्पाद	253
2	पेय पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	33
3	कपड़ा उत्पाद	1886
4	लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फिक्स्चर	247
5	कागज और कागज उत्पाद, मुद्रण, प्रकाशन और संबद्ध	646
6	चमड़ा और चमड़ा फर उत्पाद (मरम्मत को छोड़कर)	269
7	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद	528
8	रासायनिक और रासायनिक उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयले को छोड़कर)	295
9	गैर-धातु खनिज उत्पाद	79
10	मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग	522
11	धातु उत्पाद, मशीनरी के पुर्जे और परिवहन उपकरण-विद्युत उपकरणों सहित मशीन टूल्स	1723
12	बिजली, गैस, स्ट्रीम जल और आपूर्ति	83
13	ईंधन, रसायन, इत्र, चीनी मिट्टी की चीज़ें में थोक व्यापार	10
14	लोक प्रशासन और रक्षा सेवाएं	1
15	स्वच्छता सेवाएं	6
16	पूंजीगत सामान और मरम्मत सेवाओं की मरम्मत	439
17	विविध अनिर्दिष्ट समूह	901
18	कुल	**7921**

स्रोत: दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण, *2008-09*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.3: एनसीटी-दिल्ली में कार्यरत कारखानों की संख्या: 2008

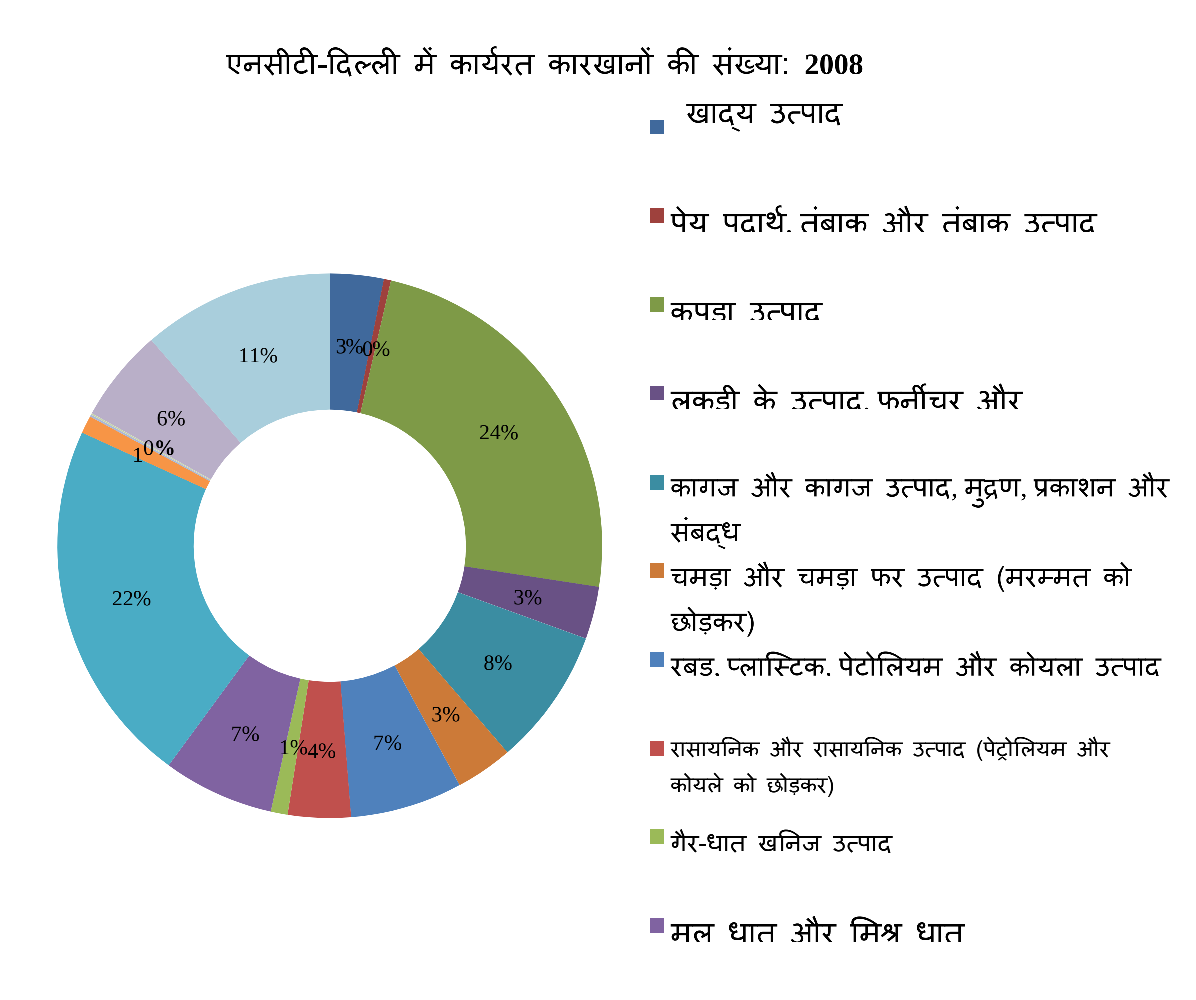

स्रोत: दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण, *2008-09*

औद्योगिक रोजगार: एनसीटी-दिल्ली

2008 में, औद्योगिक मजदूरों का सबसे बड़ा हिस्सा (36%) कपड़ा उत्पादों की श्रेणी में कार्यरत था, उसके बाद धातु उत्पाद, मशीनरी के पुर्जे और परिवहन उपकरण (चित्र 4.4 और तालिका 4.4 देखें)।

2005 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनसीटी-दिल्ली में विनिर्माण इकाइयाँ काफी हद तक प्रभावित हुईं, जिसमें प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने / स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। ऐतिहासिक रूप से, एनसीटी-दिल्ली में 33 औद्योगिक और फ्लैट कारखाने परिसर हैं (अनुलग्नक-4.2 देखें), जिनमें से केवल 20-25% नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं। आवासीय क्षेत्रों (मुख्य रूप से गैर-अनुरूप क्षेत्रों) से संचालित 27,000 से अधिक इकाइयों को बवाना, नरेला, बादली, मंगोलपुरी, ओखला, पटपड़गंज और शाहदरा जैसे नए स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए एक नई स्थानांतरण नीति (2006) तैयार की गई थी।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 4-4: एनसीटी-दिल्ली में कारखानों में कार्यरत श्रमिक: 2008

क्रम संख्या	कारखाने का प्रकार	श्रमिक
1	खाद्य उत्पाद	15,576
2	पेय पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	2,308
3	कपड़ा उत्पाद	1,31,050
4	लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फिक्स्चर	9,619
5	कागज और कागज उत्पाद, मुद्रण, प्रकाशन और संबद्ध	25,180
6	चमड़ा और चमड़ा फर उत्पाद (मरम्मत को छोड़कर)	11,620
7	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद	12,182
8	रासायनिक और रासायनिक उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयले को छोड़कर)	11,796
9	गैर-धातु खनिज उत्पाद	2,337
10	मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग	8,567
11	धातु उत्पाद, मशीनरी के पुर्जे और परिवहन उपकरण-विद्युत उपकरणों सहित मशीन टूल्स	68,839
12	बिजली, गैस, धारा जल और आपूर्ति	4,738
13	ईंधन, रसायन, इत्र, चीनी मिट्टी की चीज़ें में थोक व्यापार	90
14	लोक प्रशासन और रक्षा सेवाएं	45
15	स्वच्छता सेवाएं	86
16	पूंजीगत सामान और मरम्मत सेवाओं की मरम्मत	24,798
17	विविध अनिर्दिष्ट समूह	35,222
18	**कुल**	**3,64,053**

स्रोत: दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण, *2008-09*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.4: एनसीटी-दिल्ली में कारखानों में कार्यरत श्रमिक: 2008

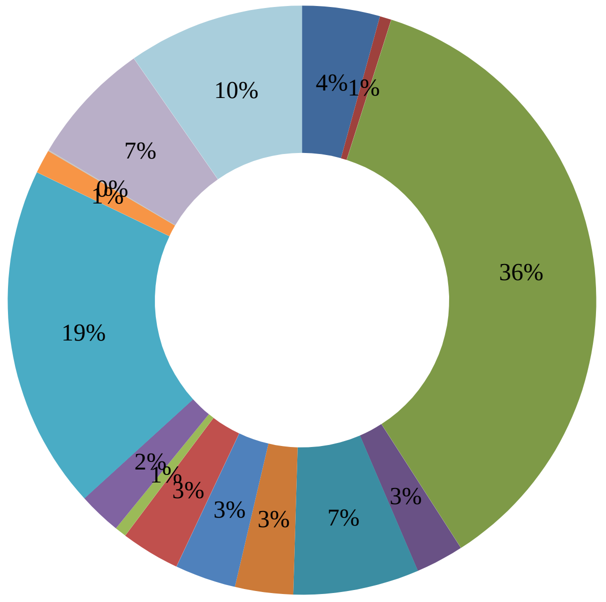

स्रोत: दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण, *2008-09*

एनसीटी-दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से 1970 के दशक में विकसित हुए थे और वर्षों से भौतिक बुनियादी ढांचे के मामले में काफी खराब स्थिति में हैं। शहर में औद्योगिक एस्टेट मुख्य रूप से तीन एजेंसियों - दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (डीएसआईडीसी), दिल्ली सरकार उद्योग विभाग (डीजीआईडी), और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के स्वामित्व में हैं। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 ने नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और पर्यावरण/प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों पर प्रकाश डाला है।

दिल्ली सरकार के योजना विभाग के अनुसार, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 70% औद्योगिक गतिविधि सघनता है। जवाहर नगर, करावल नगर, हैदरपुर, शालीमार गांव, न्यू मंडोली, बसई दारापुर, ख्याला, रिठाला और मुंडका।

4.2.2 हरियाणा उप-क्षेत्र

गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत जिले पारंपरिक रूप से औद्योगिक उत्पादन के मामले में मजबूत प्रदर्शनकर्ता रहे हैं। अतीत में, उप-क्षेत्र में विनिर्माण आधार में सुधार के लिए औद्योगिक विकास गतिविधियों पर बहुत जोर दिया गया है। नतीजतन, हरियाणा उप-क्षेत्र एक प्रमुख निर्माण/निर्यात केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि औद्योगिक एस्टेट, मॉडल औद्योगिक टाउनशिप, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फूड

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

पार्क, अपैरल पार्क, ऑटो क्लस्टर, इंजीनियरिंग क्लस्टर आदि का निर्माण। इन कदमों से जिन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ हुआ, वे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स , खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, बुनियादी धातु, प्रकाश इंजीनियरिंग, वस्त्र, मशीनरी, निर्माण सामग्री और वैज्ञानिक उपकरण हैं।

जिलेवार औद्योगिक इकाइयां

इस उप-क्षेत्र में, गुड़गांव जिले में पंजीकृत इकाइयों की अधिकतम संख्या (22,491) है, इसके बाद सबसे पुराने औद्योगिक शहरों में से एक, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, झज्जर और रेवाड़ी जिले हैं। पिछले 5-7 वर्षों में ऐसे कारखानों का अधिकांश विकास गुड़गांव जिले में केंद्रित रहा है। वहीं, पलवल (59) और मेवात (42), नव निर्मित जिलों में पंजीकृत कारखानों की संख्या सबसे कम है (तालिका 4.5 और चित्र 4.5 देखें)।

तालिका 4-5: 2010-11 में जिलेवार पंजीकृत फैक्ट्रियां हरियाणा उप-क्षेत्र

ज़िला	**2010-11 में पंजीकृत फैक्ट्रियां**
फरीदाबाद	17,291
पलवल	59
गुडगाँव	22,491
झज्जर	1,849
पानीपत	4,068
रेवाड़ी	1,370
रोहतक	4,761
सोनीपत	8,743
मेवात	42
कुल	**60,674**

स्रोत: जिलेवार औद्योगिक प्रोफाइल, डीसी एमएसएमई

चित्र 4.5: 2010-11 में जिलेवार पंजीकृत कारखाने हरियाणा उप-क्षेत्र

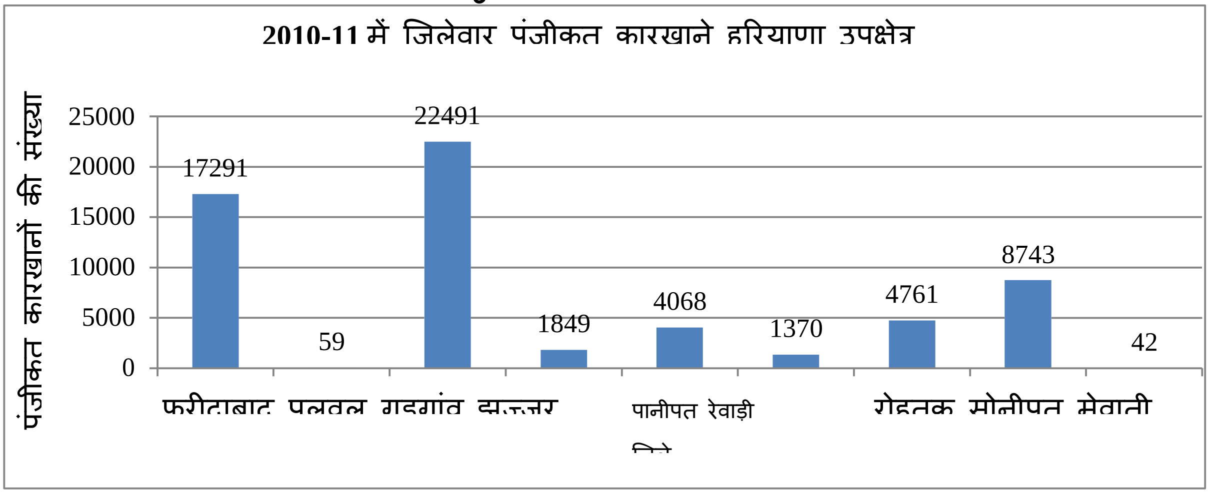

हरियाणा उप-क्षेत्र में 2004-05 से 2010-11 के बीच पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की वृद्धि का विश्लेषण इंगित

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

करता है कि 2010-11 में फरीदाबाद में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, इसके बाद इसी अवधि के लिए गुड़गांव और पानीपत में वृद्धि हुई है। पानीपत में विकास पूरे समय स्थिर रहा है, जबकि झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक और मेवात में नगण्य वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, गुड़गांव 2005-06 के दौरान पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है (तालिका 4.6 और चित्र 4.6 देखें)।

तालिका 4-6: हरियाणा उप-क्षेत्र में 2004-05 से 2010-11 के बीच पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की वृद्धि

जिले	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
फरीदाबाद	144	396	400	459	831	765	976
पलवल					4	28	27
गुडगाँव	227	324	544	718	436	651	582
झज्जर	34	26	24	108	92	79	97
पानीपत	18	40	75	108	147	252	278
रेवाड़ी	14	31	20	50	94	64	76
रोहतक	23	31	47	61	48	37	45
सोनीपत	55	113	224	276	453	194	189
मेवात			3	7	17	8	7

स्रोत: जिलेवार औद्योगिक प्रोफाइल, डीसी एमएसएमई

चित्र 4.6: हरियाणा उप-क्षेत्र में 2004-05 से 2010-11 के बीच पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की वृद्धि

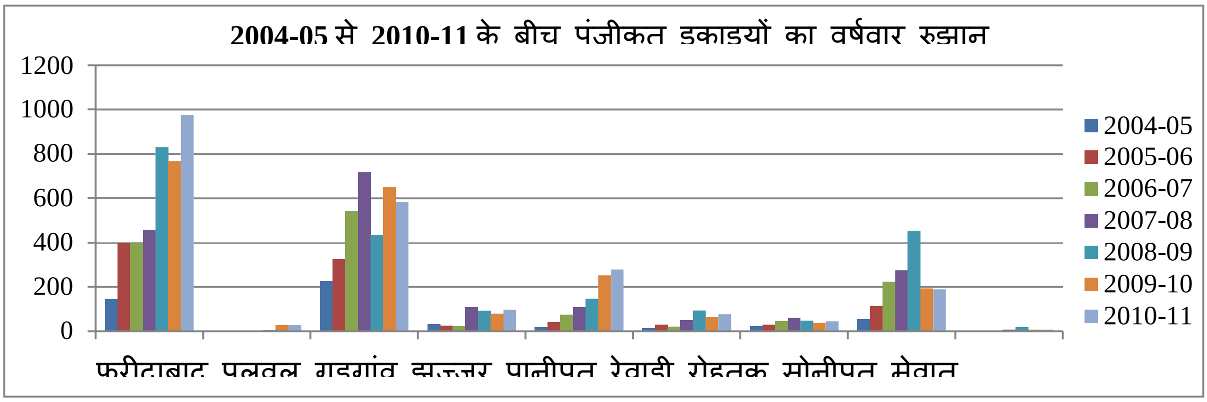

फैक्ट्रियों में कार्यरत जिलेवार श्रमिक

2010-11 में कारखाना रोजगार के मामले में, गुड़गांव जिले ने पंजीकृत कारखानों में सबसे अधिक (3,29,340) रोजगार दर्ज किया है, इसके बाद फरीदाबाद (1,04,452) और सोनीपत (59,707) हैं। गुड़गांव जिले में श्रमिकों की अधिक संख्या को गुड़गांव में उद्योगों की उच्च एकाग्रता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें आईटी / आईटीईएस जैसे उच्च रोजगार घनत्व हैं। गुड़गांव जिले में 2005-06 से रोजगार में तेजी दिखाई दे रही है (चित्र 4.7 देखें)

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.7: हरियाणा उप-क्षेत्र में 2010-11 में पंजीकृत कारखानों में जिलेवार रोजगार

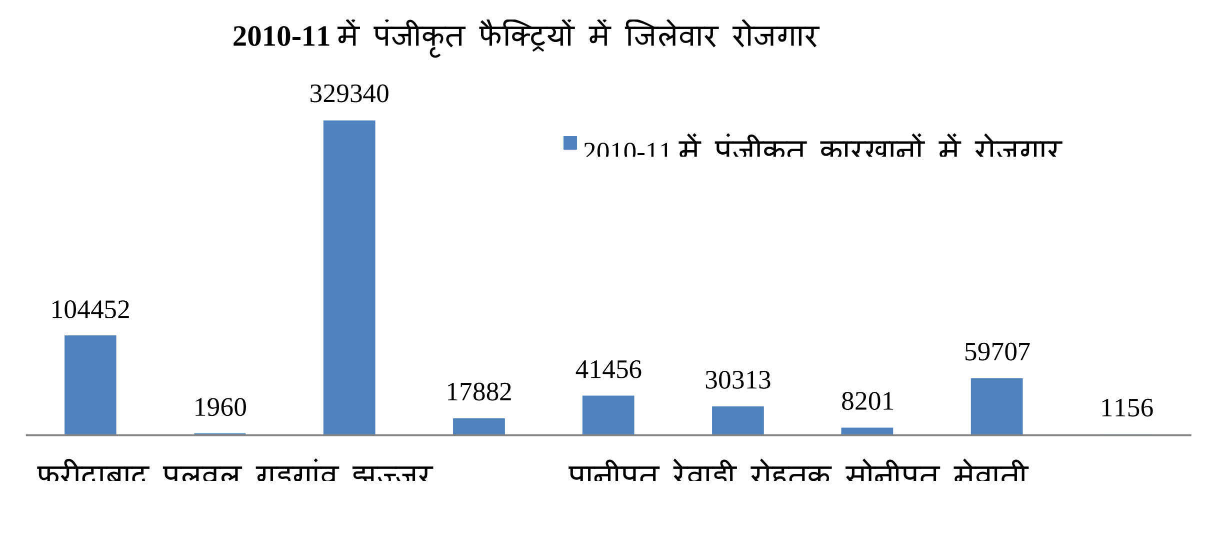

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

हरियाणा उप-क्षेत्र में 2008-09 में औद्योगिक समूहों की इकाइयों की संख्या का विश्लेषण। इंगित करता है कि कपड़ा और संबद्ध उत्पाद निर्माण इकाइयाँ हरियाणा में कारखानों की सूची में सबसे ऊपर हैं, इसके बाद मशीनरी और बुनियादी धातु उत्पाद निर्माण इकाइयाँ (मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और ऑटो-घटक आइटम) हैं। विकास के मामले में भी, कपड़ा और संबद्ध उत्पाद अन्य श्रेणियों से आगे निकल जाते हैं, जबकि खाद्य पदार्थ उद्योगों की विकास दर दूसरे स्थान पर है (तालिका 4.7 और चित्र 4.8 देखें)।

तालिका 4-7: हरियाणा उप-क्षेत्र 2008-09 में पंजीकृत उद्योग

क्रम संख्या	पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों का प्रकार	औद्योगिक इकाइयों की संख्या
1	खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	263
2	वस्त्रों का निर्माण	790
3	परिधान पहनना, ड्रेसिंग और फर की रंगाई करना	657
4	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद और कार्क, स्ट्रॉ और प्लेटिंग सामग्री के सामानों का निर्माण	163
5	कागज और कागज उत्पाद	108
6	रसायन और रासायनिक उत्पाद	344
7	रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	404
8	अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद	454
9	मूल धातु	528
10	मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद	535
11	मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी. 26	475
12	विद्युत मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी.	305
13	मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर	199
14	अन्य परिवहन उपकरण	128

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.8: हरियाणा उप-क्षेत्र में पंजीकृत उद्योग, 2008-09

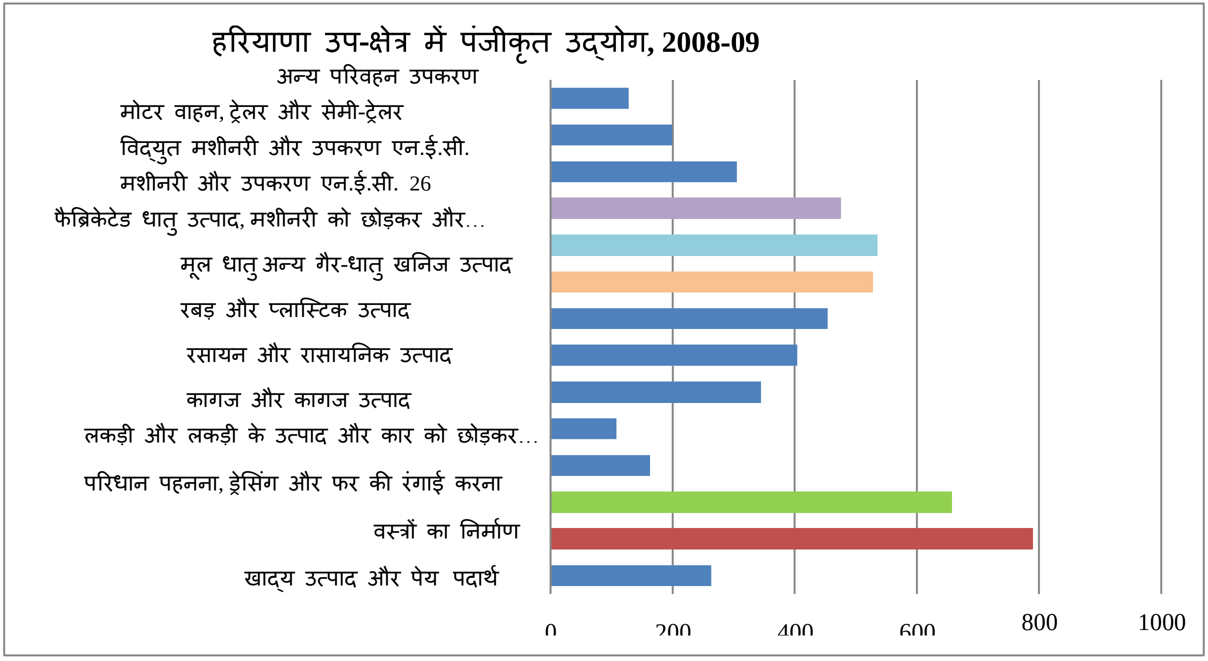

स्रोत: हरियाणा सरकार, हरियाणा का सांख्यिकीय सार, *2008-09*

2003-04 से 2008-09 के दौरान पंजीकृत निर्माण इकाइयों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन का विश्लेषण दर्शाता है कि फर उद्योग के परिधान, ड्रेसिंग और रंगाई में सबसे तेज दर से वृद्धि हुई है, इसके बाद खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों और मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध - ट्रेलर में हुयी है। कागज और कागज उत्पाद उद्योग में एक अन्य प्रमुख विशेषता दिखाई देती है, जहां इस अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि हुई है (तालिका 4.8 और चित्र 4.9 देखें)।

तालिका 4-8: हरियाणा उप-क्षेत्र में पंजीकृत निर्माण इकाइयों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, 2003-04 से 2008-09 तक

क्रम संख्या	पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों का प्रकार	% परिवर्तित
1	खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	38.42
2	वस्त्रों का निर्माण	9.12
3	परिधान पहनना, ड्रेसिंग और फर की रंगाई करना	63.03
4	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद और कार्क, स्ट्रॉ और प्लेटिंग सामग्री के लेखों का निर्माण	10.13
5	कागज और कागज उत्पाद	-27.03
6	रसायन और रासायनिक उत्पाद	17.81
7	रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	17.78
8	अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद	14.36
9	मूल धातु	10.92
10	मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद	14.07

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

11	मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी. 26	11.50
12	विद्युत मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी.	12.13
13	मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमि-ट्रेलर	24.37
14	अन्य परिवहन उपकरण	10.34

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.9: हरियाणा उप-क्षेत्र में पंजीकृत निर्माण इकाइयों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, **2003-04** से **2008-09** तक

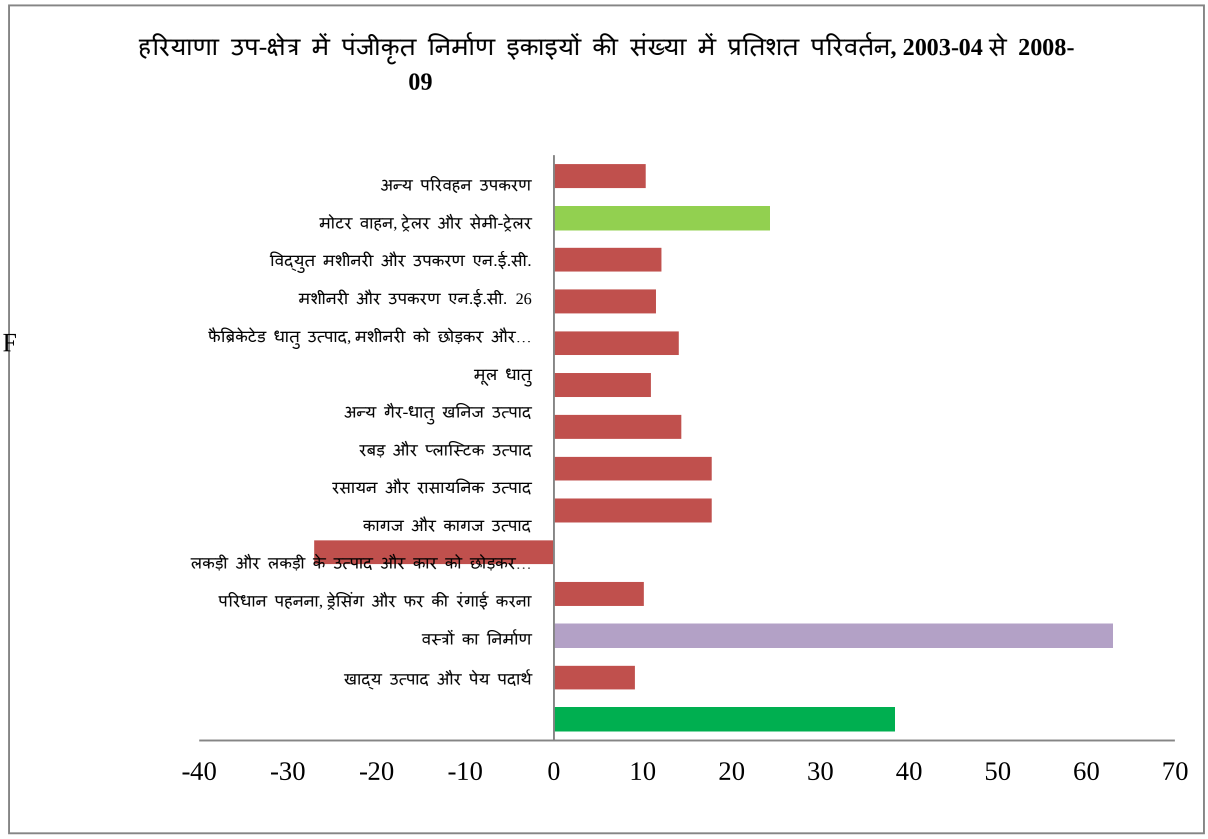

स्रोत: हरियाणा सरकार, हरियाणा का सांख्यिकीय सार, *2008-09*

4.2.3 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र जिलेवार

औद्योगिक इकाइयां

2010-11 के दौरान, गाजियाबाद (हापुड़ सहित) जिले में सबसे अधिक (45,282) उद्योग दर्ज किए गए, इसके बाद गौतमबुद्ध नगर जिले में (9,880), मेरठ जिले में (8,197), बुलंदशहर जिले में (4,629) और सबसे कम उद्योग बागपत जिले में (2,613) दर्ज किए गए। (चित्र 4.10 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.10: 2010-11 में उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में जिलेवार औद्योगिक इकाइयों की संख्या

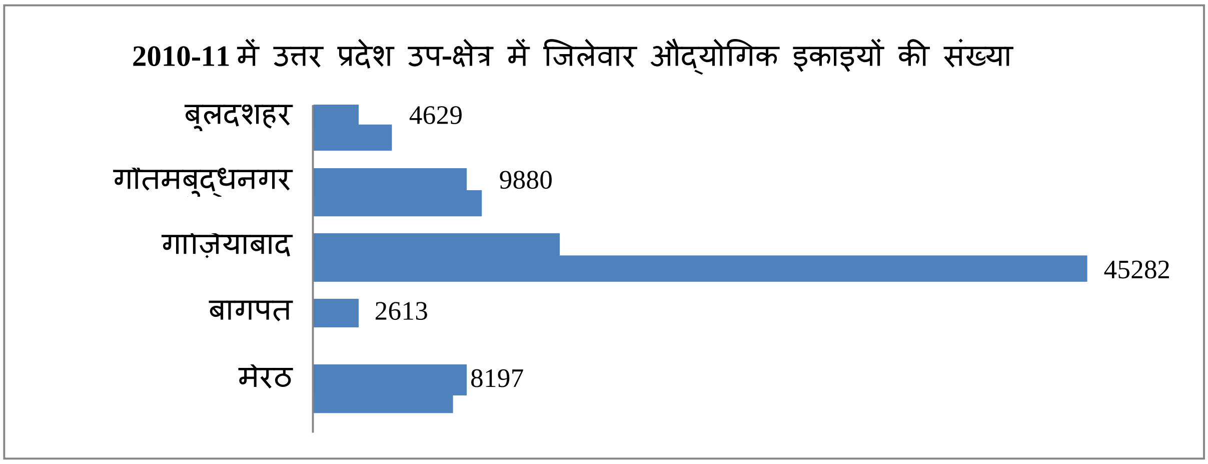

स्रोत: जिलेवार औद्योगिक प्रोफाइल, डीसी एमएसएमई

2005-06 में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा गौतमबुद्ध नगर में सबसे अधिक (83%) है, इसके बाद गाजियाबाद में (हापुड़ सहित) (13%), मेरठ में (2%) और बुलंदशहर जिले में (2%) है।), जो यह दर्शाता है कि उप-क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चित्र 4.11 देखें)।

चित्र 4.11: 2005-06 में औद्योगिक उत्पादन का जिलेवार हिस्सा

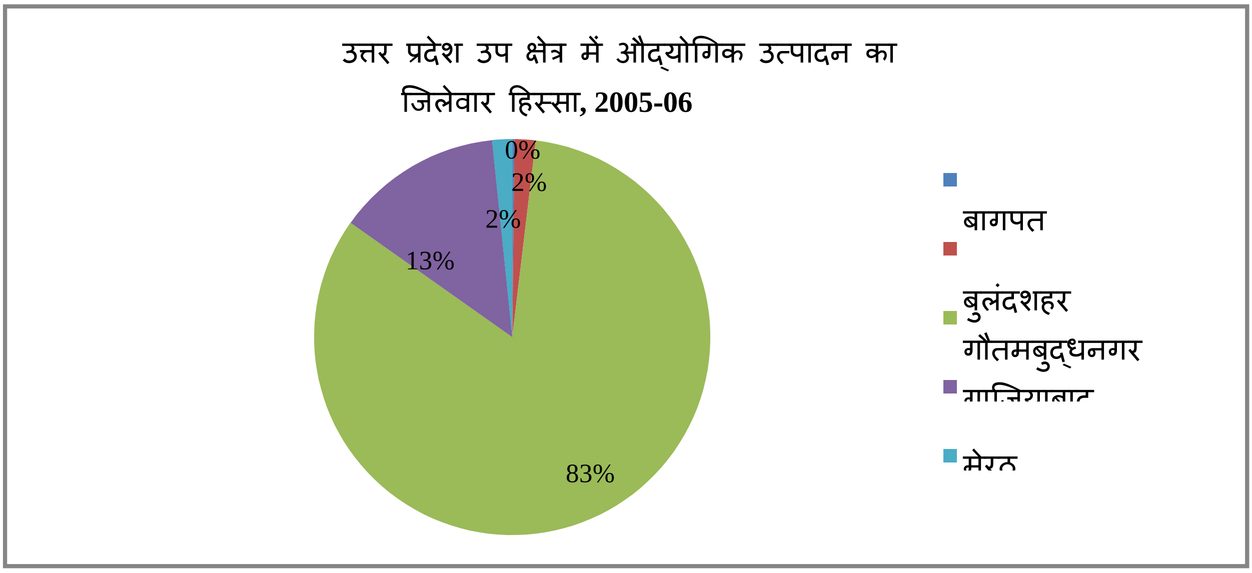

स्रोत: उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश *2005-06*

हालांकि, 2010-11 के दौरान, यह देखा गया है कि उप-क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन में गौतमबुद्ध नगर जिले का हिस्सा घटकर 64% हो गया है, जबकि मेरठ (12%), बुलंदशहर (6%) और बागपत जिले के (4%) हिस्से में वृद्धि हुई है। इसका श्रेय इस तथ्य को दिया जा सकता है कि 2005-06 से 2010-11 के दौरान मेरठ, बुलंदशहर आदि जिलों में कई छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग स्थापित किए गए हैं। यह भी हिस्सेदारी में गिरावट का एक

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

कारण हो सकता है। जिले में नए उद्योग स्थापित होने के बावजूद उपक्षेत्र में औद्योगिक क्षमता में गौतमबुद्ध नगर जिला (तालिका 4.9 और चित्र 4.12 देखें)।

तालिका **4-9: 2010-11** में औद्योगिक उत्पादन क्षमता या इकाइयों की संख्या और रोजगार का जिलेवार हिस्सा

जिला	इकाइयों की संख्या (मौजूदा पंजीकृत)	**2010-11** में रोजगार	निवेश (लाख रुपये में)
मेरठ	8,197	51,605	6,6856.49
बागपत	2,613	12,665	9,386.09
गाज़ियाबाद	45,282	2,26,824	3,26,676.13
गौतमबुद्ध नगर	9,880	1,41,295	1,47,215.53
बुलंदशहर	4,629	23566	2,465.1
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	**70,601**	**4,55,955**	**5,52,599.34**

स्रोत: जिलेवार औद्योगिक प्रोफाइल, डीसी एमएसएमई

चित्र 4.12: 2010-11 में जिलेवार औद्योगिक उत्पादन क्षमता या इकाइयों की संख्या का हिस्सा

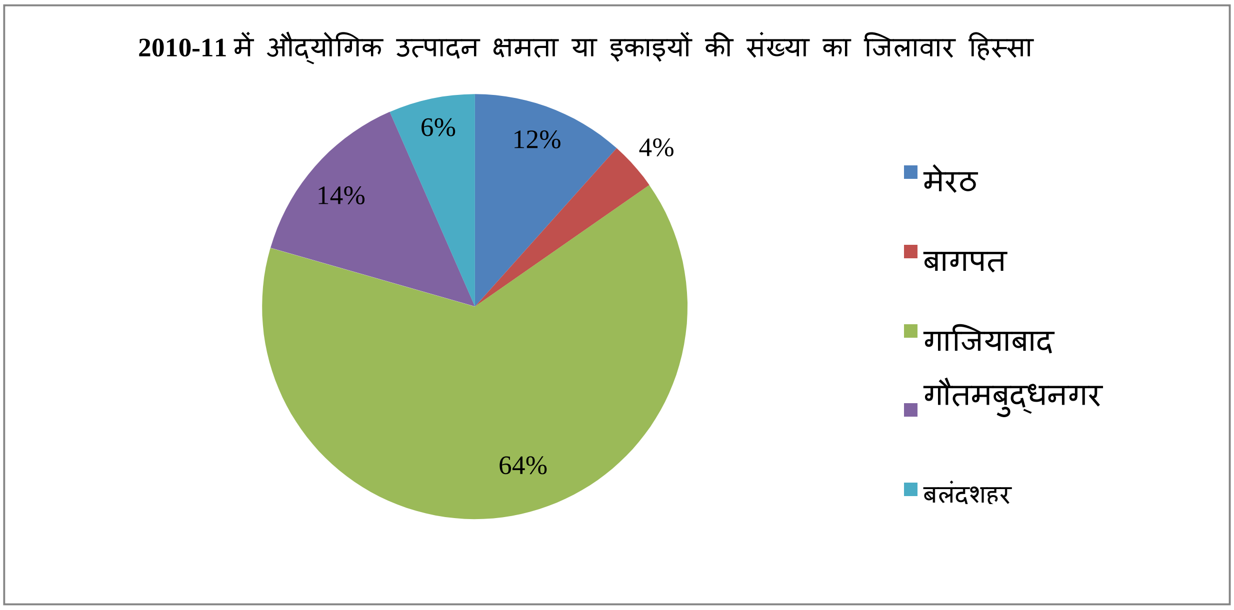

2010-11 में उद्योगों में जिलेवार श्रमिक

2010-11 में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों की संख्या के संदर्भ में, 2010-11 के दौरान गाजियाबाद (हापुड़ सहित) एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ अन्य जिलों से अधिक है (चित्र 4.13 देखें)। इस अवधि के दौरान, गाजियाबाद में 2,26,824 औद्योगिक श्रमिक थे, जो उप क्षेत्र में पंजीकृत इकाइयों वाले औद्योगिक श्रमिकों का लगभग आधा हिस्सा हैं। गौतमबुद्ध नगर उप-क्षेत्र (141,295) में दूसरे सबसे बड़े कर्मचारी के साथ दूसरे स्थान पर है, इसके बाद मेरठ (51,605), बुलंदशहर जिले (23,566) और सबसे कम बागपत जिले (12,665) है (चित्र 4.13 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.13: 2010-11 में उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में जिलेवार औद्योगिक रोजगार

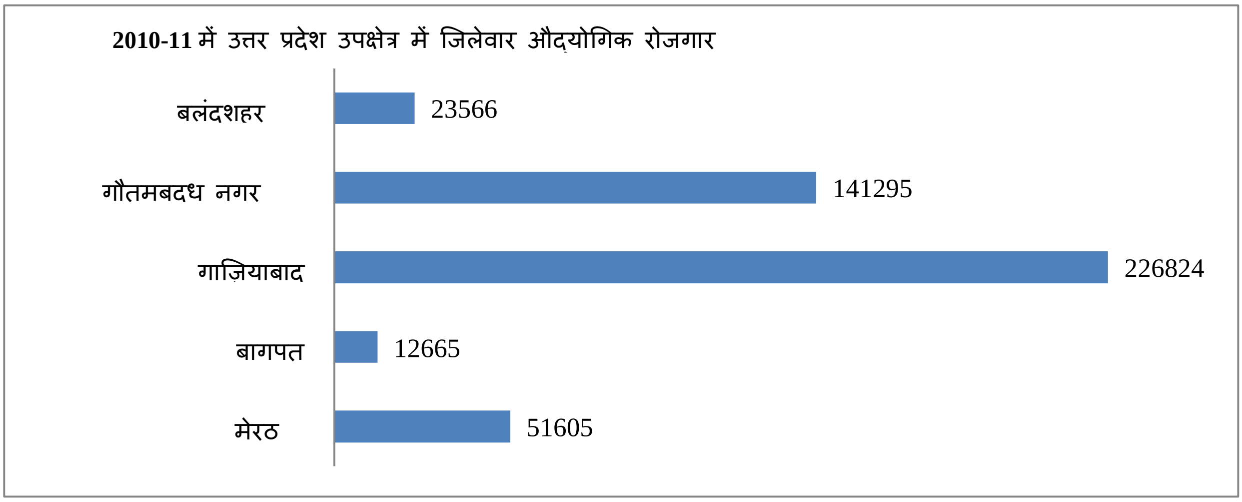

स्रोत: जिलेवार औद्योगिक प्रोफाइल, डीसी एमएसएमई

2005-06 में उत्तर प्रदेश में इकाइयों की श्रेणी-वार संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि परिधान, ड्रेसिंग और फर इकाइयों की रंगाई सबसे बड़ा हिस्सा है (चित्र 4.14 देखें)। चिकित्सा, शुद्धता और ऑप्टिकल उपकरणों, घड़ियों और क्लॉक के निर्माण जैसे उद्योगों में सबसे कम संख्या दर्ज की गई है।

चित्र 4.14: पंजीकृत उद्योग, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र 2005- 06 में उद्योगवार श्रमिक

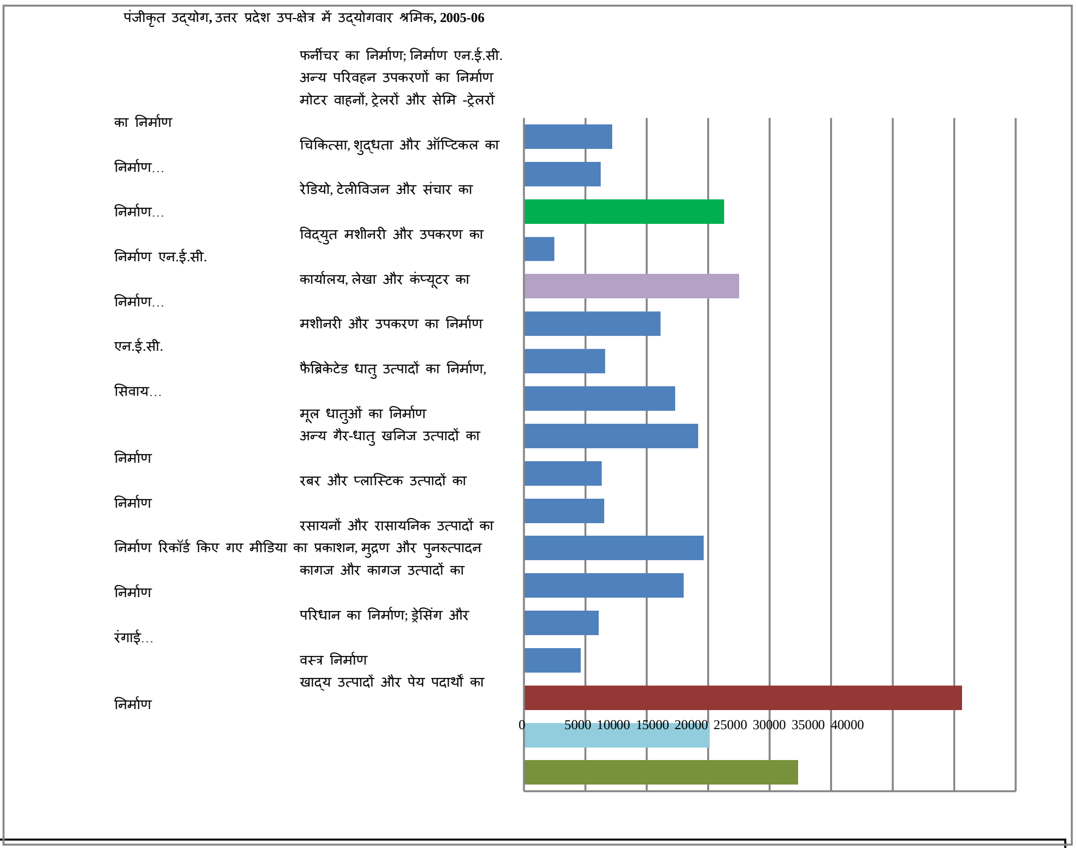

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

4.2.4 राजस्थान उप-क्षेत्र

परंपरागत रूप से, अलवर जिले में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि रही है। 1970 के दशक में भिवाड़ी को अपने पसंदीदा औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के राज्य सरकार के निर्णय के साथ, अर्थव्यवस्था का विविधीकरण धीरे-धीरे बढ़ गया। भिवाड़ी में औद्योगीकरण शुरू करने में रीको का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए, वर्षों से, कृषि गतिविधियों में रोजगार घट रहा है और तेजी से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ रहा है। वर्तमान में, अलवर जिले में रीको द्वारा विकसित बाईस से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं (तालिका 4.10 देखें)।

जिले के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान अलवर, भिवाड़ी, खुशखेड़ा और चौपांकी हैं। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र (एमआईए), अलवर को हाल ही में रीको द्वारा लगभग 213 ऑपरेटिंग उद्योगों के साथ स्थापित किया गया था, जो ज्यादातर खनिज-आधारित (88 इकाइयाँ) और रासायनिक (61) हैं। इनमें से 28 ऑपरेशन बड़े या मध्यम स्तर के हैं और शेष एसएसआई हैं। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 1079 एसएसआई, 225 मध्यम पैमाने की इकाइयों और 58 बड़े पैमाने की इकाइयों की उपस्थिति की रिपोर्ट करता है। भिवाड़ी-टपूकड़ा-खुशखेड़ा परिसर में आठ औद्योगिक क्षेत्र हैं (तालिका 4.11 देखें)।

तालिका 4-10: अलवर जिले में रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र-2010

क्रमांक	स्थान	एकड़ में कुल क्षेत्रफल
1	एमआईए	1,804.32
2	एम.आई.ए. एक्सटेंशन, अलवर	201.15
3	एग्रो फूड पार्क, एम.आई.ए. एक्सटेंशन अलवर	185.94
4	एमआईए (दक्षिण और पूर्व), अलवर	51.75
5	खेरली	8.41
6	राजगढ़	40.59
7	खैरथल	69.93
8	थानागाज़ि	33.12
9	ओल्ड इंडस्ट्रीज़ एरिया अलवर	179.76
10	बहरोड़	280.5
11	सोतानाला	151.91
12	भिवाड़ी फेज I से IV	2,138
13	खुशखेड़ा	825.83
14	आईआईडी, केंद्र खुशखेड़ा	151.77
15	पाथेरी	538.1

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

16	चोपांकी	802
17	टपूकडा	781.44
18	शाहजहांपुर	203.09
19	नीमराना (चरण I से III)	2,125.96
20	ईपीआईपी नीमराना	210.51
21	सारेखुर्द	94.55
22	मंजारा पथ (जापानी क्षेत्र)	1,166.33
	कुल	**12,045**

स्रोत: अलवर जिला प्रशासन, *alwar.nic.in*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 4-11: राजस्थान उप-क्षेत्र में भिवाड़ी, खुशखेड़ा और चोपांकी में श्रेणीवार इकाइयों की संख्या

क्रम संख्या	उत्पाद के प्रकार	भिवाड़ी (संख्या)	खुशखेड़ा (संख्या)	चौपांकी (संख्या)
1	ऑटो के पुर्जे, साइकिल के पुर्जे, सर्विस स्टेशन और संबंधित सामान	63	2	6
2	कास्टिंग और फोर्जिंग	22		
3	सिरेमिक, क्रॉकरी मोल्डिंग पाउडर, सीमेंट उत्पाद, संगमरमर उत्पाद और संबद्ध वस्तुएं	46	6	5
4	रसायन, सौंदर्य प्रसाधन और संबद्ध वस्तुएं	55	9	5
5	ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, सर्जिकल, चिकित्सा उपकरण, कीटनाशक, उर्वरक आदि।	28		3
6	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स केबल, बैटरी और संबद्ध आइटम	75	3	8
7	खाद्य उत्पाद, पोल्ट्री और मवेशी चारा, खनिज पानी, शीतल पेय आदि।	38	9	3
8	जनरल इंजीनियरिंग, बेयरिंग, डाई, फैब्रिकेशन आदि	16	6	13
9	कांच, लकड़ी का कागज और संबद्ध वस्तु	11		
10	आयरन स्टील	74	9	10
11	अलौह धातु, एल्यूमीनियम, बाथरूम फिटिंग	32		3
12	पैकेजिंग	51		6
13	पेंट्स और प्रिंटिंग इंक	18	4	3
14	प्लास्टिक	87	4	8
15	प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी आइटम	8		1
16	रबर, चमड़ा और फोम उत्पाद	45	3	5
16	कपड़ा, सूत, रेडीमेड गारमेंट्स आदि	34	4	2
17	विविध	75	4	5
18	अवर्गीकृत	567	24	100
	कुल	**1,455**	**87**	**183**

स्रोत: भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

राजस्थान उप-क्षेत्र में 2010-11 में एमएसएमई इकाइयों की श्रेणी-वार संख्या का विश्लेषण इंगित करता है कि इकाइयों की संख्या के मामले में, खाद्य उत्पादों ने उच्चतम (2,500) दर्ज किया, इसके बाद जूट, गांजा और मेस्टा कपड़ा (2,001) और पेय पदार्थ, तंबाकू उत्पाद (1,980) का स्थान रहा। हालांकि, नियोजित श्रमिकों की संख्या के मामले में, कागज उत्पादों और छपाई में उच्चतम (9800) दर्ज किया गया है, इसके बाद चमड़ा उत्पादों (9,300) और जूट, गांजा और मेस्टा कपड़ा (8,000) और ऊन, रेशम और सिस्थेटिक फाइबर (8,000) का स्थान है। तालिका 4.12 और चित्र 4.15 और 4.16 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 4-12: 2010-11 में अलवर जिले में एमएसएमई में औद्योगिक इकाइयों की प्रकार-वार संख्या, निवेश और रोजगार

औद्योगिक इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या	निवेश (लाख में)	रोज़गार
खाद्य उत्पाद	2,500	13,011	7,500
अन्य खाद्य पदार्थ	1,300	15,015.25	6,000
पेय, तंबाकू उत्पाद	1,980	10,015	5,580
सूती वस्त्र	20	9,015	600
ऊन, रेशम और सिंथेटिक फाइबर	1,541	20,001	8,000
जूट, भांग और मेस्टा कपड़ा	2,001	18,338	8,000
होजरी गारमेंट्स	1,260	7,338	6,500
लकड़ी उत्पाद	1,910	11,538	7,500
कागज उत्पाद और छपाई	1,620	9,538	9,800
चमड़ा उत्पाद	1,070	8,500	9,300
रबर और प्लास्टिक उत्पाद	1,600	7,500	5,750
रासायनिक और रासायनिक उत्पाद	1,700	11,300	6,800
गैर-धातु खनिज उत्पाद	1,480	12,600	5,800
मूल धातु उद्योग	1,270	14,800	4,000
बिजली के अलावा मशीनरी और पुर्जे	1,360	13,200	4,256
विद्युत मशीनरी और उपकरण	1,360	10,200	4,200
मरम्मत सेवाएं	570	14,200	6,500
अन्य	372	12,300	6,700
कुल	**24,914**	**2,18,409.25**	**1,12,786**

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.15: 2010-11 में अलवर जिले में क्षेत्रवार मौजूदा एमएसएमई

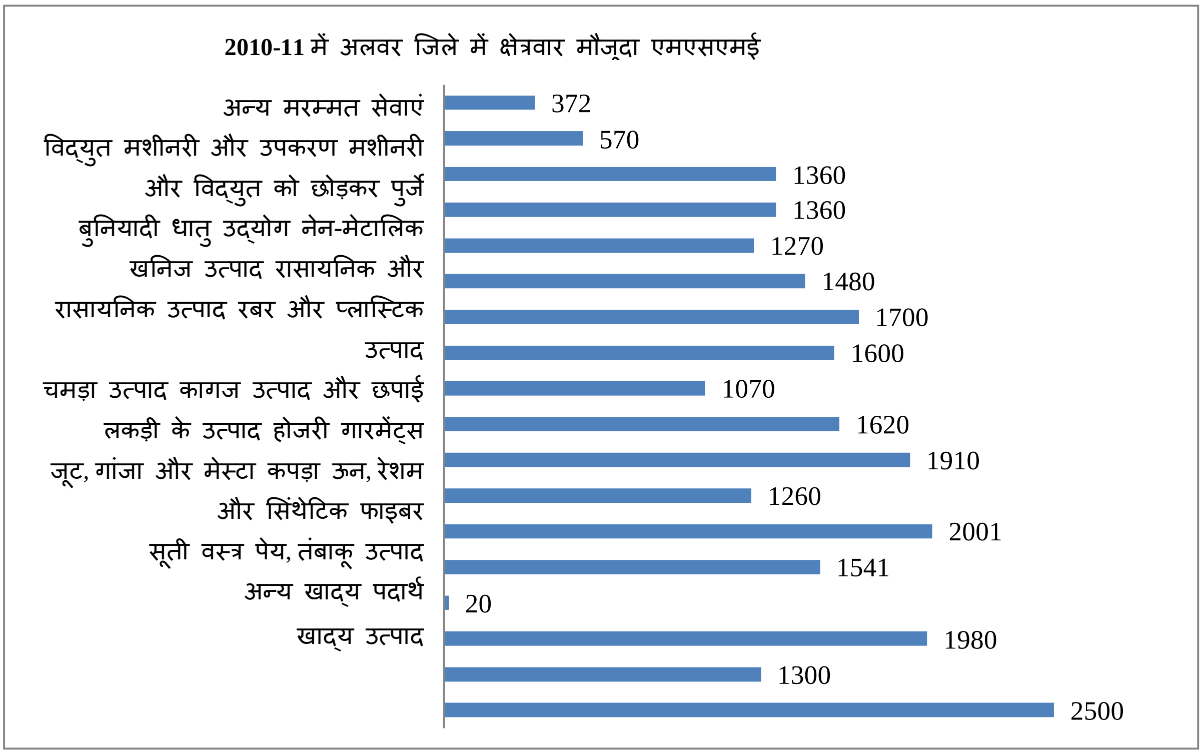

स्रोत: जिला औद्योगिक प्रोफाइल, अलवर जिला, डीसी एमएसएमई

चित्र 4.16: 2010-11 में अलवर जिले में एमएसएमई में औद्योगिक श्रमिकों का क्षेत्रवार रोजगार

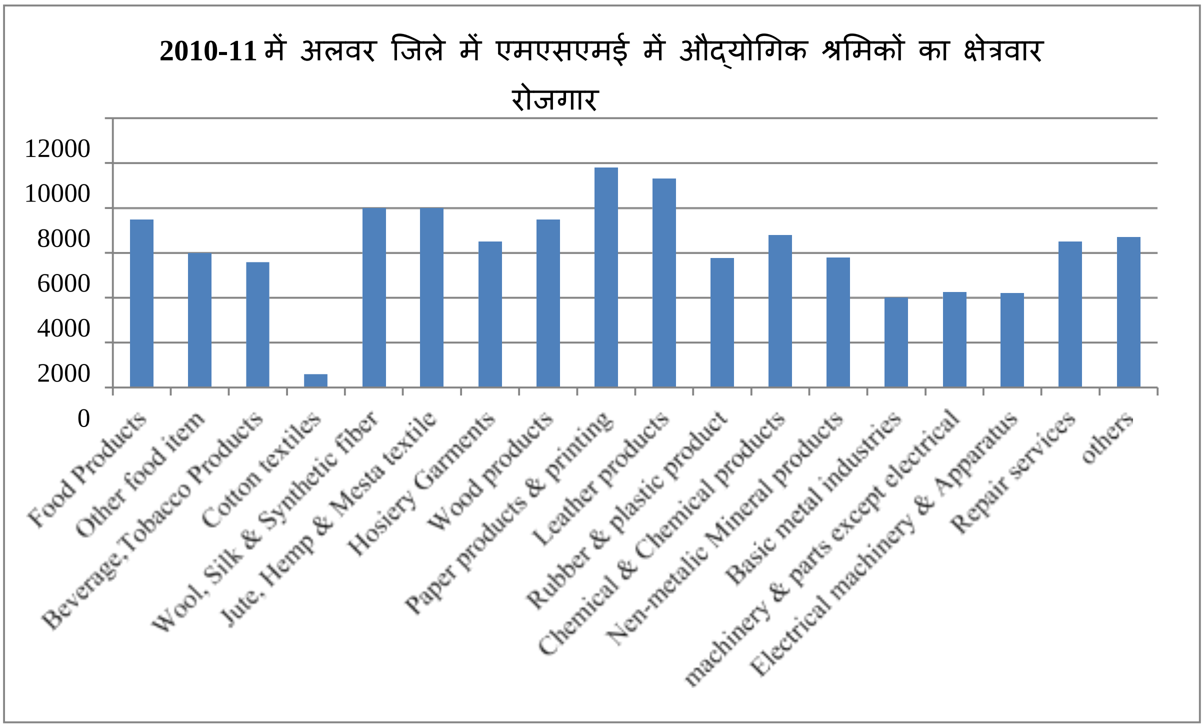

स्रोत: जिला औद्योगिक प्रोफाइल, अलवर जिला, डीसी एमएसएमई

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

ऊपर वाले चित्र का अनुवाद

खाद्य उत्पाद

अन्य खाद्य पदार्थ

पेय पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद

सूती वस्त्र

ऊन, रेशम और सिंथेटिक फाइबर

जूट, सन और मेस्टा कपड़ा

होजरी वस्त्र

लकड़ी के उत्पाद

कागज के उत्पाद और मुद्रण

चर्म उत्पाद

रबर और प्लास्टिक उत्पाद

रसायन और रासायनिक उत्पाद

गैर धात्विक खनिज उत्पाद

मूल धातु उद्योग

इलेक्ट्रिकल को छोड़कर मशीनरी और पुर्जे

विद्युत मशीनरी और उपकरण

मरम्मत सेवाएं

अन्य

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

राजस्थान उप-क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में निवेश के मामले में, ऊन, रेशम और सिंथेटिक इकाइयों में अधिकतम निवेश दर्ज किया है, इसके बाद जूट, गांजा और मेस्टा कपड़ा और सबसे कम होजरी परिधान इकाइयां हैं (तालिका 4.12 और चित्र 4.17 देखें)।

चित्र 4.17: वर्ष 2010-11 के दौरान अलवर जिले में क्षेत्रवार निवेश

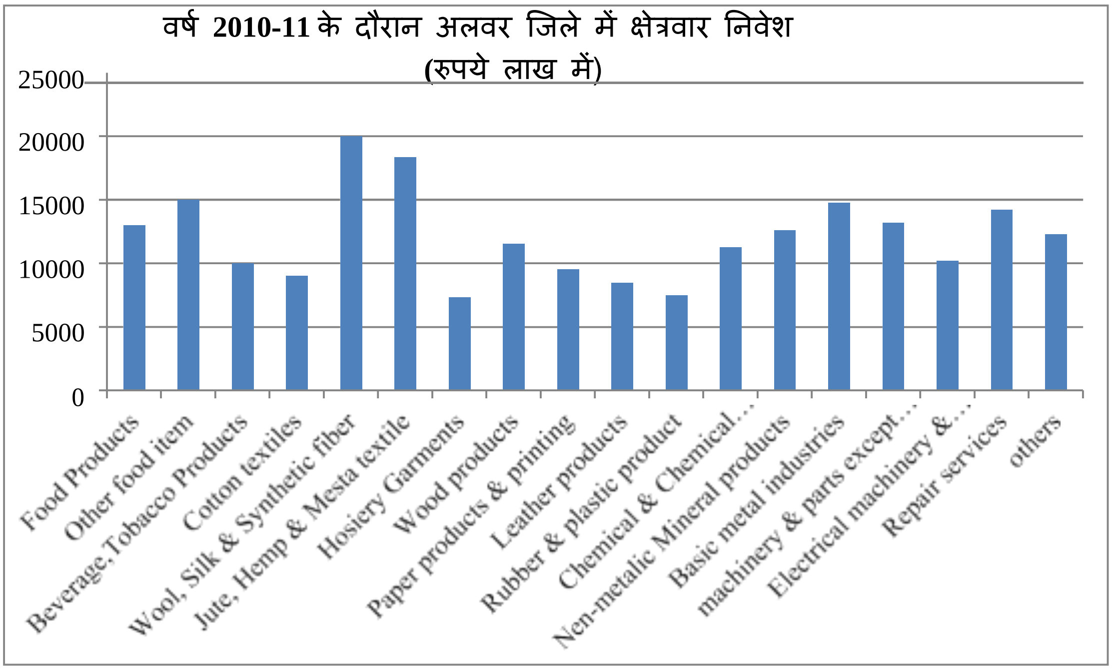

स्रोत: जिला औद्योगिक प्रोफाइल, अलवर जिला, डीसी एमएसएमई

4.3 औद्योगिक समूह

4.3.1 पृष्ठभूमि

उद्योग समूह स्थानीय और क्षेत्रीय विकास अनुसंधान और अभ्यास में सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं में से एक बन गए हैं। 1990 में प्रकाशित माइकल पोर्टर के "द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस" के भीतर उद्योग समूहों की जड़ें गहरी हैं। नब्बे के दशक के मध्य से नीति में धीरे-धीरे क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समूह आधारित दृष्टिकोण (सीबीए) में बदलाव आ रहा है। सरकारों और व्यवसाय द्वारा अपनाया गया सीबीए शहरों और क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में सुधार के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उद्योग समूहों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार और व्यवसायों द्वारा विभिन्न तरीकों से बढ़ती दिलचस्पी दिखाई है।

समूहीकरण में प्रतिद्वंद्वी फर्म और आपूर्तिकर्ता शामिल हैं जो बाहरी लेनदेन लागत को कम करने के तरीकों पर सहयोग करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के विकास में मदद करने के लिए नए व्यावसायिक अवसरों और बाजारों का विकास करते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास और सुधार के लिए अक्सर बड़े पैमाने पर निवेश और योजना की आवश्यकता होती है। संसाधन-विवश सेट-अप में, एक समूह रणनीति इन महत्वपूर्ण निवेशों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उत्पादन प्रक्रिया की अधिकतम दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे को उचित रूप से विकसित किया गया है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

ऊपर वाले चित्र का अनुवाद

खाद्य उत्पाद

अन्य खाद्य पदार्थ

पेय पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद

सूती वस्त्र

ऊन, रेशम और सिंथेटिक फाइबर

जूट, सन और मेस्टा कपड़ा

होजरी वस्त्र

लकड़ी के उत्पाद

कागज के उत्पाद और मुद्रण

चर्म उत्पाद

रबर और प्लास्टिक उत्पाद

रसायन और रासायनिक उत्पाद

गैर धात्विक खनिज उत्पाद

मूल धातु उद्योग

इलेक्ट्रिकल को छोड़कर मशीनरी और पुर्जे

विद्युत मशीनरी और उपकरण

मरम्मत सेवाएं

अन्य

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

एक क्लस्टर को भौगोलिक दृष्टि से समान, संबंधित या पूरक व्यवसायों के साझा बुनियादी ढांचे, बाजारों और सेवाओं के साथ एक भौगोलिक रूप से बाध्य एकाग्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें आम अवसरों और खतरों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) के अनुसार, एक औद्योगिक क्लस्टर 60 किमी के दायरे में संबंधित और पूरक व्यवसाय में 100 से अधिक इकाइयां होती हैं। परिभाषा केवल सांकेतिक है और यह काफी हद तक फर्मों के बीच संबंधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। मूल रूप से क्लस्टर प्राकृतिक या प्रेरित/कृत्रिम हो सकता है। प्राकृतिक क्लस्टर ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है जबकि; प्रेरित क्लस्टर सरकार की नीति का परिणाम है।

यूएनआईडीओ के अनुसार, 2004 में भारत में 388 औद्योगिक क्लस्टर थे। इन समूहों में फर्मों की अनुमानित संख्या 4.9 लाख है, जिसमें कुल 7.5 मिलियन रोजगार और कुल उत्पादन 1570 बिलियन रुपये है। क्लस्टर को इसके विकास जैसे प्राकृतिक या प्रेरित या निर्मित उत्पाद की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

बॉक्स 4.1: क्लस्टर आधारित विकास दृष्टिकोण

क्लस्टर रणनीति से पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, एक आर्थिक विकास रणनीति। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित और कुशल तरीका प्रदान करता है। क्लस्टर दृष्टिकोण को स्थानीय आर्थिक विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर, विकास एजेंसियों के अपने प्रयासों का समन्वय करने, सेवाओं के दोहराव से बचने और आर्थिक विकास के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने की अधिक संभावना है। क्लस्टर दृष्टिकोण और समन्वय भी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और सरकार के साथ रचनात्मक संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। वास्तव में, क्लस्टर दृष्टिकोण क्लस्टर के लिए अधिक सकारात्मक कारोबारी माहौल तैयार कर सकता है। यह माहौल मौजूदा फर्मों को बढ़ाने में मदद करता है और नए व्यवसायों को क्षेत्र में आकर्षित करता है।

क्लस्टर को लाभ

क्लस्टर रणनीति सार्वजनिक एजेंसियों को संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से निर्देशित करने की अनुमति देती है। व्यक्तिगत फर्मों की जरूरतों को पूरा करने वाले असंख्य कार्यक्रम बनाने के बजाय, सार्वजनिक प्रयासों को समान मुद्दों वाली कई फर्मों की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित करता है। उद्योग समूह दृष्टिकोण सार्वजनिक एजेंसियों को उद्योगों के साथ सीधे काम करने और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए रणनीति विकसित करने का अवसर देता है।

स्थापित और उभरते उद्योगों को लाभ

क्लस्टर रणनीति किसी दिए गए उद्योग या क्लस्टर की जरूरतों को महत्व देती है और उन जरूरतों को पूरा करने में अपने सार्वजनिक और निजी संसाधनों को केंद्रित करती है। उद्योग समूह उनकी प्राथमिक जरूरतों की पहचान करता है और उन्हें संबोधित करने के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के साथ काम करता है। इन जरूरतों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं उद्योग और फर्म, मुद्दों और चिंताओं को दूर करने के लिए आयोजित मंचों और बैठकों से भी लाभान्वित होते हैं। यह सभी उपयुक्त एजेंसियों की पहचान करने और उनके साथ काम करने से जुड़े समय और प्रयास को बचाता है। यदि क्लस्टर रणनीति राज्यव्यापी नीति का हिस्सा है, तो आर्थिक विकास के लिए राज्यव्यापी एजेंडा निर्धारित करने में समूहों की एक शक्तिशाली आवाज होती है।

4.3.2 एनसीआर में क्लस्टर

एनसीआर

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

में महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत हैं। ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल, सामान्य इंजीनियरिंग, पावरलूम, कालीन आदि के क्षेत्रों में 53 औद्योगिक क्लस्टर हैं। नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित कुल संख्या 15 लाख से अधिक है और कुल कारोबार 1000 अरब रुपये से अधिक है। ऑटोकंपोनेंट उद्योग में इकाइयों की सबसे बड़ी संख्या (25,900) है और यह सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है।

क्लस्टर की मौजूदा संख्या में, कपड़ा समूहों (9 क्लस्टर) का कुल कारोबार 21,561.32 करोड़ रुपये है। रोजगार के मामले में, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर (6 क्लस्टर) में 5,65,500 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि रबड़ और रसायन क्षेत्र में अधिकतम एकल क्लस्टर (11 क्लस्टर) हैं, जिनमें एनसीआर में कम से कम इकाइयाँ हैं, जिनका कारोबार 3,300 करोड़ रुपये से अधिक है। इसका तात्पर्य यह है कि उद्योग इकाइयाँ अन्य उद्योगों की तुलना में बिखरी हुई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में इकाइयाँ हैं लेकिन समूहों की संख्या कम है (तालिका 4.13, चित्र 4.18 और 4.19 देखें)।

एनसीआर में औद्योगिक क्लस्टरों की जिलेवार सूची अनुबंध-4.3 में दी गई है।

तालिका 4-13: एनसीआर में औद्योगिक क्लस्टर

क्लस्टर / उत्पाद	समूहों की संख्या	यूनिटों की संख्या	रोज़गार	कारोबार (रुपये करोड़)
ऑटो कंपोनेंट	6	25,900	5,65,500	63,897.2
रबड़ और रसायन	11	3,095	77,013	3,300.91
सामान्य इंजीनियरिंग	6	3,841	63,877	4,042.4
कपड़ा	9	15,965	4,94,116	21,561.32
अन्य	21	10,578	30,6,066	7,408.13
कुल	**53**	**59,379**	**15,06,572**	**10,0210**

चित्र **4.18:** एनसीआर में क्लस्टरों की संख्या: **2010-11**

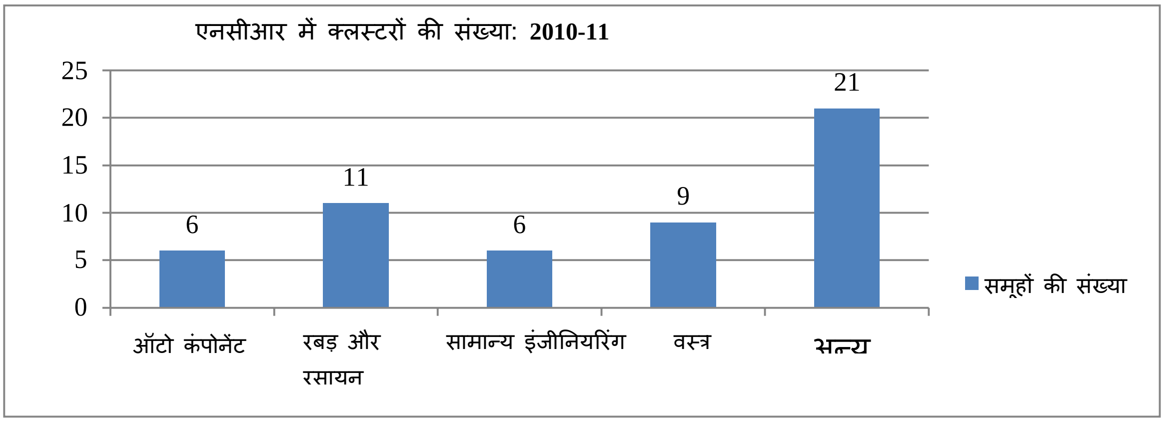

स्रोत: डीसी एमएसएमई.

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

चित्र 4.19: एनसीआर में औद्योगिक समूहों में रोजगार

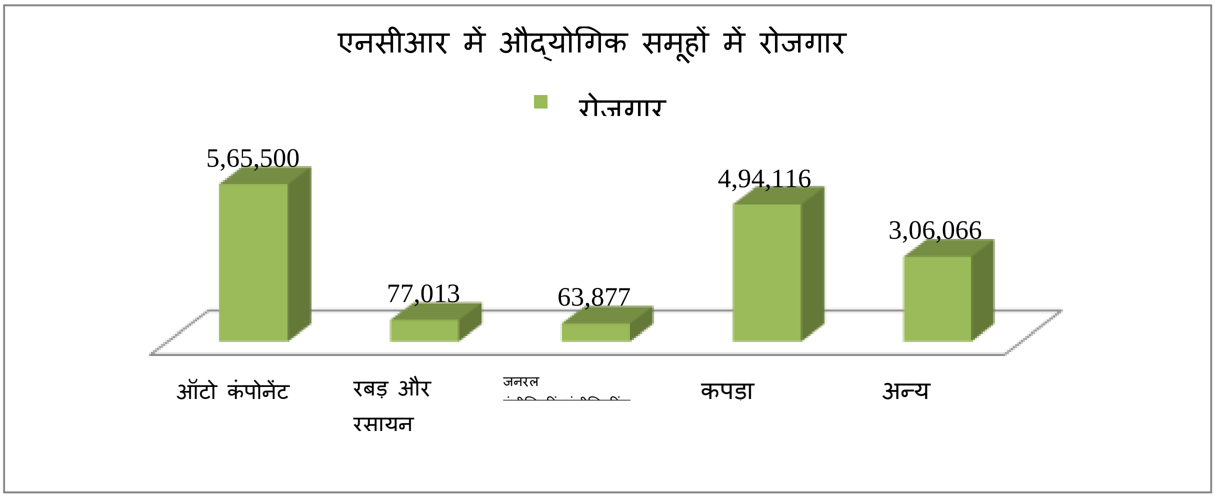

स्रोत: औद्योगिक अनुमान, डीसी एमएसएमई; क्लस्टर वेधशाला

4.4 महत्वपूर्ण क्लस्टर प्रोफाइल

4.4.1 विनिर्माण क्लस्टर प्रोफाइल

a) ओखला रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र

स्वतंत्रता के बाद, दिल्ली के परिधान उद्योग की प्राथमिक भूमिका सशस्त्र बलों और अन्य स्थानीय बाजारों की जरूरतों को पूरा करना था। दिल्ली में स्थित ओखला औद्योगिक क्षेत्र को बाद में रेडीमेड कपड़ों सहित विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए विकसित किया गया था। 1970 से 1990 के दौरान, उद्योग का विस्तार गोविंदपुरी, कालकाजी और तुगलकाबाद एक्सटेंशन जैसे आसपास के क्षेत्रों में हुआ। हालांकि, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एसएमई इकाइयों को मुख्य रूप से छोटी फैब्रिकेटिंग इकाइयां सहायता प्रदान कर रही हैं।

जैसे ही नोएडा अस्तित्व में आया, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फर्म ओखला से नोएडा में स्थानांतरित हो गए। इन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्मों के मालिकों ने अपने कारखाने ओखला में कपडे निर्माताओं को बेच दिए। जिसके परिणामस्वरूप, ओखला भारत में कपड़ा निर्माण के प्रमुख समूहों में से एक बन गया। भारत का 40% रेडीमेड परिधान निर्यात एनसीआर द्वारा किया जाता है, जिसमें से 40% ओखला औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है।

इसकी स्थापना के समय, ट्रेडल-संचालित प्रणाली के साथ साधारण सिलाई मशीनों का उपयोग करके परिधान उत्पाद बनाए गए थे। आधुनिकीकरण के बाद, अधिकांश इकाइयाँ बिजली से चलने वाली मशीनों में बदल गईं। समय के साथ इन्हें परिष्कृत, उच्च गति वाली आयातित मशीनों से बदल दिया गया। फैब्रिक-कटिंग को भी मैनुअल मोड से बिजली संचालित मशीनों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अधिकांश कढ़ाई का काम अभी भी ठेकेदारों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा मैन्युअल रूप से किया जा रहा है। मशीन कढ़ाई का काम धीरे-धीरे आम होता जा रहा है, खासकर संगठित क्षेत्र में, जो कम्प्यूटरीकृत, स्वचालित और अन्य परिष्कृत मशीनों के माध्यम से किया जाता है। कच्चा माल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से ग्रे कपड़े के रूप में खरीदा जाता है, जिसे ब्लीचिंग या डाइंग या क्लॉथ फिनिशिंग और

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

प्रोसेसिंग यूनिट्स द्वारा प्रिंट करके प्रोसेस किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और एनसीटी-दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण प्रकोष्ठ के हस्तक्षेप के कारण, कई ब्लीचिंग, रंगाई और परिष्करण इकाइयां उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे आसपास के राज्यों में स्थानांतरित हो गई हैं। इससे परिवहन लागत में वृद्धि हुई है जिससे उत्पादन की लागत और समय में वृद्धि हुई है।

क्लस्टर के विकास के लिए जिम्मेदार आवश्यक कारकों में से एक उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रवासी आबादी की उपलब्धता के कारण क्लस्टर में और उसके आसपास सस्ते श्रम की आसान पहुंच है। ओखला रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर का निर्यात बाजार समृद्ध है। यह विश्व के बाजारों में उनकी गुणवत्ता, आकर्षक डिजाइनों के साथ-साथ अन्य मूल्यवर्धन के कारण रेडीमेड कपड़ों की सोर्सिंग के लिए सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। प्राथमिक निर्यात गंतव्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेनेलक्स, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, यूरोपीय संघ के देश और कनाडा आदि हैं।

b) नोएडा रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

कपड़ा और तैयार वस्त्र नोएडा विकास नीति के लिए विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्रों में से थे। नोएडा की स्थापना उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत एक आधुनिक टाउनशिप विकसित करने का एक प्रयोग था। नोएडा के चरण -2 में एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र और एक होजरी परिसर शामिल है। क्लस्टर में 3,600 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 6,000 से अधिक कपडे की यूनिट्स हैं।

c) नोएडा सामान्य इंजीनियरिंग और ऑटो क्लस्टर, यूपी उप-क्षेत्र

जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर गौतमबुद्ध नगर जिले में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। नोएडा का सामान्य इंजीनियरिंग क्षेत्र प्रमुख निर्यातक नहीं है और मुख्य रूप से घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करता है। सामान्य तौर पर, इंजीनियरिंग क्षेत्र की ऑटोमोबाइल कंपोनेंट निर्माण फर्मों ने हाल के वर्षों में अपनी जड़ें जमा ली हैं। नोएडा में अधिकांश ऑटोमोबाइल पार्ट्स निर्माण फर्म घरेलू बाजार की मांग को पूरा करती हैं। मिंडा हफ प्राइवेट लिमिटेड और मदरसन सूमी सिस्टम्स जैसी कुछ ही कंपनियां निर्यात कर रही हैं। नोएडा में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट (ईपीसीएच) एसईजेड भी आ रहा है जो हस्तशिल्प खंड को पूरा करेगा।

d) पानीपत टेक्सटाइल क्लस्टर, हरियाणा उप-क्षेत्र

पानीपत नकली सूत का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है और इसे कम कीमत वाले कंबलों के उत्पादन के साथ-साथ हथकरघा कपास की दरी, बेड कवर, कुशन कवर, थ्रो, मैट आदि के निर्यात के लिए देश का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है।

पानीपत का उद्योग भारतीय सेना के लिए बैरक कंबल की 75% मांग को पूरा करता है। पानीपत वस्त्र उद्योग में आठ खंड, अर्थात् हथकरघा, बिजली करघा, कालीन, ऊनी और नकली सूत कताई, सूती धागे की कताई, ऊनी कंबल, कॉटन वेट प्रोसेसिंग और वूलेन वेट प्रोसेसिंग शामिल हैं।

क्लस्टर में लगभग 2000 इकाइयां हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 70,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती हैं। डीसी एमएसएमई के अनुमानों के अनुसार, हथकरघा पर काम करने वाली लगभग 1800 इकाइयाँ और पावरलूम के साथ 700 से अधिक इकाइयाँ काम कर रही हैं।

पानीपत कालीन उद्योग में लगभग 400 छोटी और मध्यम इकाइयाँ हैं जो पानीपत और उसके आसपास स्थित हैं और

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

लगभग 60,000 श्रमिकों को रोजगार देती हैं। इस उद्योग के लिए कच्चा माल बीकानेर, जोधपुर और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से आता है। इस उद्योग के लिए लगभग 2-3% कच्चा माल आयात किया जाता है। 90% से अधिक निर्मित कालीन निर्यात के लिए होते हैं और लगभग 10% उत्पादन घरेलू बाजारों के लिए होता है। उद्योग का कुल कारोबार 1500 मिलियन रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

पानीपत में लगभग 350 ऊनी और नकली सूत कताई इकाइयाँ हैं जो लगभग 30,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती हैं। इस उद्योग के लिए कच्चा माल तुलनात्मक रूप से सस्ते दरों पर यूरोपीय देशों से आयातित लत्ता के रूप में है, जिसे गार्नेट किया जाता है और नकली सूत में काता जाता है। हालांकि, कंबल उद्योग में कम मांग के कारण, यह क्षेत्र वर्तमान में तनाव में है।

लगभग 45 ओपन-एंड कॉटन कताई इकाइयाँ और पाँच-रिंग फ्रेम कॉटन कताई मिलें हैं, जो लगभग 25,000 श्रमिकों को रोजगार देती हैं। ओपन-एंड इकाइयों के लिए कच्चा माल रिंग फ्रेम इकाइयों से 85% अपशिष्ट कपास का निर्माण करता है और इसे दक्षिण भारत से प्राप्त किया जाता है।

कॉटन-वेट प्रोसेसिंग उद्योग में लगभग 350 रंगाई घर हैं, 75 मुद्रण इकाइयां पानीपत कपड़ा उद्योग को विभिन्न प्रकार की रंगाई प्रक्रियाओं के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।

e) फरीदाबाद जनरल इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर, हरियाणा उप-क्षेत्र

फरीदाबाद का औद्योगिक आधार एनसीआर की समग्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। फरीदाबाद की यह औद्योगिक संपत्ति लगभग 6,948 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें फोर्जिंग से लेकर ट्रैक्टर, क्लच असेंबली से लेकर लीफ स्प्रिंग्स तक कई तरह के इंजीनियरिंग उत्पाद हैं। इस जिले में प्रमुख औद्योगिक उत्पादन, मुख्य रूप से फरीदाबाद शहर का प्रतिनिधित्व करता है, ट्रैक्टर, स्टील री-रोलिंग, वैज्ञानिक उपकरण, बिजली करघे, कृषि उपकरण, जेसीबी क्रेन, आदि फरीदाबाद में 6,000 से अधिक हल्की इंजीनियरिंग कंपनियां (ज्यादातर ऑटो कॉम्पोनेन्ट व्यापार में), घरेलू उपकरण निर्माता और मशीन टूल्स में हैं।

फरीदाबाद में उद्योग तब शुरू हुआ जब 1960 के दशक में आयशर ट्रैक्टर्स और एस्कॉर्ट्स ने शहर में शॉप सेट अप किया। अधिकांश इकाइयाँ इन दोनों के सहायक के रूप में सामने आईं। अनुमान के अनुसार फरीदाबाद का औद्योगिक आधार 15 से अधिक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी), 1000 आईएसओ प्रमाणित उद्योगों और 300 मध्यम और बड़े उद्योगों के साथ फैली हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अन्य छोटी औद्योगिक इकाइयां भी हैं, जो शहर में आवासीय क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों से कार्य कर रही हैं।

फरीदाबाद-बल्लभगढ़ परिसर में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों की कुल संख्या लगभग 15,000 है। कॉम्प्लेक्स लगभग 500,000 श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और एशिया में 9वीं सबसे बड़ी औद्योगिक संपत्ति के रूप में रैंक करता है। इसका संयुक्त कारोबार लगभग 2,000 अरब रुपये होने का अनुमान है।

f) गुड़गांव ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर, हरियाणा उप-क्षेत्र

गुड़गांव 1980 की शुरुआत तक एक छोटा शहर था, लेकिन इसका विकास पिछले दशक के दौरान दिल्ली से निकटता के कारण बड़े पैमाने पर हुआ है। गुड़गांव 7 अरब डॉलर के ऑटो कंपोनेंट उद्योग के तीन प्रमुख निर्माण केंद्रों में से एक है। मारुति उद्योग लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर गुड़गांव में औद्योगिक विकास को प्रेरित किया है। मारुति उद्योग लिमिटेड की शुरुआत 1982 में भारत सरकार की एक संयुक्त उद्यम फर्म और एक

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

जापानी ऑटोमेकर, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के रूप में हुई थी। गुड़गांव क्लस्टर 1980 के दशक में मारुति के साथ शुरू किया गया एक प्रेरित क्लस्टर है।

g) मेरठ ऑटो पार्ट्स क्लस्टर, यूपी उप-क्षेत्र

मेरठ का ऑटो पार्ट्स उद्योग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों भागों का उत्पादन करता है। इस क्लस्टर में लगभग 5000 इकाइयां हैं, जिनमें से लगभग 95% यांत्रिक भागों से संबंधित हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, बड़ी संख्या में यूनिट्स की मरम्मत भी की जा रही है। इस क्लस्टर में लगभग 26,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। क्लस्टर का सालाना टर्नओवर 1,000 मिलियन रुपये है और इस टर्नओवर का 80% मैकेनिकल पार्ट्स यूनिट्स से आता है। प्रमुख उत्पाद ऑटो रबर के पुर्जे, ऑटो ब्रेक, ऑटो इंजन स्पेयर पार्ट्स, नट और बोल्ट, स्प्रिंग पिल्स आदि हैं। सभी इकाइयां या तो छोटी या सूक्ष्म प्रकृति की हैं और पूरे मेरठ शहर में फैली हुई हैं। क्लस्टर पिछले 5 वर्षों से सालाना 5% की दर से बढ़ रहा है। यह वृद्धि दर राष्ट्रीय विकास दर (10% वार्षिक वृद्धि दर रिपोर्ट की गई) से बहुत कम है। क्लस्टर अत्यधिक खंडित है और इसलिए बड़ी मात्रा में किसी एक वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है, जिससे विनिर्माण लागत और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं।

कर्मचारी मुख्य रूप से अकुशल हैं और गुणवत्ता का पालन कुल मिलाकर नहीं होता है। तकनीकी उन्नयन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अधिकांश इकाइयों में साधारण कटिंग और ड्रिलिंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। शॉप फ्लोर कार्यों में सुधार करने, गुणवत्ता प्रणालियों को प्रेरित करने और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्नत उपकरण लगाने की जरुरत है।

h) मेरठ पावरलूम क्लस्टर, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

क्लस्टर में 3,000 पावरलूम इकाइयाँ हैं जिनमें 30,000-35,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिकांश इकाइयाँ (लगभग 95%) सूक्ष्म पैमाने की इकाइयाँ हैं। क्लस्टर में लगभग 35,000-40,000 पावरलूम स्थापित हैं, जिनमें से केवल 65-70% ही संचालित हो रहे हैं। होम फर्निशिंग के लिए मुख्य उत्पाद ग्रे फैब्रिक और फैब्रिक हैं, जिनकी आपूर्ति दिल्ली, गाजियाबाद और पानीपत में स्थित व्यापारियों को की जाती है। क्लस्टर सालाना 400 करोड़ रुपये के सामान का उत्पादन करता है। अधिकांश अन्य पावरलूम समूहों की तरह, व्यापारी या मास्टर बुनकर बाजार को नियंत्रित करते हैं। परिवार की महिला सदस्य ज्यादातर जॉब वर्क के आधार पर कढ़ाई का काम करती हैं। कढ़ाई को पावरलूम क्लस्टर का सहायक माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पावरलूम सेक्टर में गिरावट देखी गई है और इसी तरह का परिदृश्य मेरठ में देखा जा सकता है। मेरठ में बहुत कम इकाइयाँ हैं जिनमें आधुनिक करघे हैं और पानीपत के पावरलूम क्लस्टर की तुलना में अपेक्षाकृत अक्षम हैं। इस समूह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि बुनकरों के पास सीमित बाजार संबंध हैं और इसलिए वे व्यापारियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। कारोबार बहुत कम है, और क्लस्टर को इसे और अधिक उत्पादक बनाने के लिए निरंतर मदद की जरुरत है।

i) मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर, यूपी उप-क्षेत्र

स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर में 3,500 इकाइयाँ हैं, जिनमें लगभग 70,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और सालाना 2,000 मिलियन रुपये के सामान का उत्पादन करते हैं। प्रमुख उत्पाद क्रिकेट, मुक्केबाजी दस्ताने, फुटबॉल, बैडमिंटन और लॉन टेनिस से संबंधित आइटम हैं। क्लस्टर में एसएमई और घरेलू इकाइयां दोनों शामिल हैं। एसएमई बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स में स्थित हैं, जबकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग इकाइयां पूरे शहर और आसपास के गांवों में फैली हुई हैं। क्लस्टर से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं फुलाने योग्य गेंदें, हॉकी स्टिक और गेंद, क्रिकेट बैट और गेंद, मुक्केबाजी उपकरण, मछली पकड़ने के उपकरण और विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

उपकरण हैं।

क्लस्टर पिछले कुछ वर्षों से 8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। कुछ इकाइयाँ जैसे कि बॉक्सिंग ग्लव्स बनाने वाली कंपनियां तुलनात्मक रूप से तेज दर से बढ़ रही हैं। मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री भारत के स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट में लगभग 25% का योगदान करती है।

क्लस्टर खेल के सामान के लिए केंद्र सरकार के संगठन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर (पीपीडीसी) से तकनीकी सहायता प्राप्त करता है।

क्लस्टर कंपनियां ज्यादातर मैन्युअल निर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग करती हैं। हालाँकि, विश्व स्तर पर अधिकांश खेल वस्तुओं का निर्माण यांत्रिक रूप से किया जाता है। क्लस्टर केवल कुछ खेलों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिससे खंड का एक बड़ा हिस्सा अपने डोमेन से बाहर हो जाता है।

बड़ी फैक्ट्रियों की संख्या नगण्य है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय खरीदार कभी भी क्लस्टर को बड़े ऑर्डर नहीं देते हैं। क्लस्टर को समान उत्पादों का निर्माण करने वाली मशीनीकृत इकाइयों से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है और आवश्यक निवेश करने के लिए क्लस्टर फर्म बहुत छोटी हैं। क्लस्टर में निर्मित वस्तुओं के मौजूदा सेट के भीतर तकनीकी उन्नयन की अपार संभावनाएं हैं। अन्य स्पोर्ट्स गुड सेगमेंट में विविधीकरण की पर्याप्त गुंजाइश है। क्लस्टर के विकास के लिए पहले ही कई प्रयास किए जा चुके हैं।

4.4.2 सर्विस क्लस्टर प्रोफाइल

a) एनसीटी-दिल्ली में आईटी और आईटीईएस

एनसीआर ने सॉफ्टवेयर विकास, वेब विकास, नेटवर्किंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी), दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली, ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम), ऑनलाइन कार्यालय स्वचालन, आदि के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर कंपनियों की उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। एनसीटी-दिल्ली ने सॉफ्टवेयर उत्पादन का एक समूह बन गया है, जो लगभग बंगलौर और मुंबई जितना ही महत्वपूर्ण है। धीमी शुरुआत के बाद, दिल्ली पिछले कुछ वर्षों में सॉफ्टवेयर उद्योग के साथ पकड़ बना रहा है और वर्तमान में इसमें लगभग उतनी ही संख्या में सॉफ्टवेयर कंपनी मुख्यालय हैं जितने अन्य सॉफ्टवेयर हब हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के अनुमानों से संकेत मिलता है कि सरकार और उद्योग द्वारा एक समन्वित कार्य योजना दिल्ली में सॉफ्टवेयर उद्योग को 450 अरब रुपये का वार्षिक कारोबार हासिल करने के लिए त्वरित गति से बढ़ने में सहायता कर सकती है।

एनसीटी-दिल्ली में बिक्री योग्य उच्च-गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, तकनीकी रूप से योग्य और पेशेवरों के प्रतिभाशाली पूल, मजबूत नेतृत्व उन्मुख कंपनियों, नियामक मदद, आगामी आईटी उद्यमियों के लिए विभिन्न ऊष्मायन सुविधाओं, बढ़ती घरेलू और वैश्विक बाजार की मांग का एक अंतर्निहित लाभ है। ये सभी कारक दिल्ली आईटी एसएमई खंड के विकास को गति देने में सहायक रहे हैं। हालांकि, इसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, फर्मों के लिए व्यवसाय, ज्ञान और तकनीकी नवाचार शुरू करना उचित है, क्योंकि बीपीओ और एप्लिकेशन प्रबंधन जैसे पारंपरिक विकास चालकों को कीमत और प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। एनसीटी-दिल्ली सरकार ने इस संबंध में कई उपाय किए हैं, जिसमें सबसे आधुनिक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ शास्त्री पार्क दिल्ली में पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना शामिल है। सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने और आईटी उद्योग और आईटी अवसंरचना के परिणामी विकास के उद्देश्य

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

से एक आईटी नीति भी तैयार की है। अन्य एनसीआर भाग लेने वाली राज्य सरकारें भी आईटी / आईटीईएस क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए पहल कर रही हैं।

ई-कॉमर्स डोमेन नाम पंजीकरण और संबंधित सुरक्षा मुद्दों, इंटरनेट पर विपणन और प्रचार, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और प्रमाणन एजेंसियों, टेली-बिलिंग और वेब होस्टिंग के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाली दिल्ली स्थित इकाइयों के लिए नवीनतम व्यापार मंच है। आईटी सक्षम सेवाएं जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कॉल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग, बैक-ऑफिस ऑपरेशंस, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), और राजस्व लेखा आदि हैं। जो शहर के लिए आला क्षेत्र माने जाते हैं। दिल्ली की नई सहस्राब्दी औद्योगिक नीति इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सॉफ्टवेयर विकास और आईटी-सक्षम सेवाओं में उच्च तकनीक और परिष्कृत इकाइयों की स्थापना पर जोर देती है।

4.5 क्लस्टरों का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

4.5.1 ऑटो और इंजीनियरिंग क्लस्टर

ताकत

- मांग संचालित उद्योग;
- स्थानीय बाजार में मजबूत उपस्थिति;
- सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता; तथा
- भौगोलिक दृष्टि से आदर्श स्थान पर स्थित (अंतिम उपयोगकर्ताओं के निकट)।

कमजोरी

- प्रौद्योगिकी मशीनरी और उपकरणों को न अपनाना;
- कच्चे माल की उपलब्धता और कच्चे माल की असंगत कीमतें;
- कम उपलब्धता कुशल श्रम; तथा
- अनुसंधान और विकास संस्कृति का अभाव।

अवसर

- बड़ी और नई ऑटो और इंजीनियरिंग कंपनियां एनसीआर में अपना परिचालन शुरू कर रही हैं; तथा
- एनसीआर में आगामी अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना।

धमकी

- चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा, जिसके पास अधिक उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकी आधार है; तथा
- अन्य देशों के लिए मूल्य आधारित प्रतियोगिता।

4.5.2 वस्त्र समूह

ताकत

- निर्यात बाजार में मजबूत उपस्थिति;
- घरेलू बाजार में भी वृद्धि हो रही है;
- कच्चा माल और संबद्ध वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं; तथा
- कुशल कर्मचारी की उपलब्धता।.

कमजोरी

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

- उच्च उत्पादन लागत;
- उत्पादन का पारंपरिक तरीका;
- तकनीकी विकास का निम्न स्तर;
- उच्च स्तरीय विनिर्माण दोष और अस्वीकृति; तथा
- गुणवत्ता और उत्पादकता के साथ समस्याएं।

अवसर

- टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं समाप्त हो रही हैं;
- नई तकनीक को अपनाना आसान होता जा रहा है;
- सरकारी योजनाएं और प्रोत्साहन; तथा
- अवसंरचना में सरकारी सहायता बढ़ाएँ

धमकी

- वैश्विक कारोबारी माहौल; तथा
- अन्य देशों के साथ मूल्य प्रतिस्पर्धा।

4.6 एनसीआर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परिभाषित किया है जो संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर माल के निर्माण या उत्पादन या सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसका विवरण तालिका 4.14 में दिया गया है।

तालिका 4-14: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण

उद्यम का प्रकार	माल के निर्माण या उत्पादन में लगे होना	सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे होना
	संयंत्र और मशीनरी में निवेश	उपकरण में निवेश
सूक्ष्म उद्यम	25 लाख रुपये से अधिक नहीं	10 लाख रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्यम	25 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
मध्यम उद्यम	5 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	2 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, *2006*

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते प्रवेश के साथ, एनसीआर में ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे गैर-प्रमुख क्षेत्रों में कॉर्पोरेट द्वारा निर्मित उत्पादों के आउटसोर्सिंग, उप-अनुबंध और सहायक के लिए अपार अवसर पैदा हुए हैं। एक जीवंत एसएमई क्षेत्र इन विकासों का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है।

एनसीआर में 1.0 लाख से अधिक एसएसआई और 15,000 से अधिक मध्यम और बड़े पैमाने की इकाइयां हैं (तालिका 4.15 देखें)। हरियाणा उप-क्षेत्र में, एसएसआई इकाइयों की अधिकतम संख्या गुड़गांव जिले में है और उसके बाद फरीदाबाद जिले में है। इसी तरह की प्रवृत्ति बड़े और मध्यम उद्यमों की संख्या में देखी गई है। उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में, एसएसआई और बड़ी और मध्यम इकाइयों की अधिकतम संख्या गाजियाबाद जिले में केंद्रित है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में पंजीकृत उद्योगों की अधिकतम संख्या है; हालाँकि उद्योगों की संख्या

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

को SSI और बड़ी और मध्यम इकाइयों में विभाजित नहीं किया गया है। राजस्थान उप-क्षेत्र में, एसएसआई इकाइयों की संख्या 464 थी, और बड़े और मध्यम उद्यमों की संख्या 87 थी। दिल्ली के एनसीटी के डीसीएमएसएमई औद्योगिक प्रोफाइल के अनुसार 2010-11 में एनसीटी-दिल्ली में 20,000 से अधिक इकाइयां हैं।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 4-15: एनसीआर में एसएसआई और बड़ी और मध्यम इकाइयों की संख्या: मार्च 2011

जिला / उप-क्षेत्र	एसएसआई इकाइयां	लघु उद्योग में नियोजित दैनिक कर्मचारियों की अनुमानित औसत संख्या	बड़ा और मध्यम	बड़े और मध्यम उद्योगों में रोजगार
मेरठ	8,184	48,280	13	3,325
बागपत	2,608	8,765	5	3,900
गाज़ियाबाद	लागू नहीं	17,221	लागू नहीं	72,749
गौतमबुद्ध नगर	9,521	77,260	359	1,87,572
बुलंदशहर	4,624	80,000	5	87
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र का योग	**24,937**	**2,31,526**	**382**	**2,67,633**
दिल्ली	20,648#	9,75,194	लागू नहीं	लागू नहीं
दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का योग	**20,648**	**9,75,194**	लागू नहीं	लागू नहीं
अलवर	464	1,12,554*	87	8,100
राजस्थान उप-क्षेत्र का योग	**464**	**1,12,554***	**87**	**8,100**
फरीदाबाद	17,111	4,500	180	1,600
पलवल	19	7,200	40	8,000
गुडगाँव	22,055	1,86,040	436	1,43,300
झज्जर	लागू नहीं	16,082	लागू नहीं	1,000
पानीपत	4,025	80,667	43	14,192
रेवाड़ी	1,229	9,313	141	21,000
रोहतक	4,746	लागू नहीं	15	2,820
सोनीपत	8,737	59,707	6	17,031
मेवात	26	800	16	1,200
हरियाणा उप-क्षेत्र का योग	**57,948**	**3,64,309**	**877**	**2,10,143**
कुल योग/एनसीआर	**1,03,997****	**15,71,029**	**1346****	**4,85,876**
* एमएसएमई में सृजित रोजगार				
** चूंकि, कुछ जिलों में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए तालिका में कुल कम दिखाई देता है। हालांकि पंजीकृत इकाइयों (एसएसआई और एलएंडएम दोनों) की वास्तविक संख्या अधिक होगी।				
# एमएसएमई				

स्रोत: संबंधित जिलों के जिलेवार औद्योगिक प्रोफाइल, डीसी एमएसएमई, *http://dcmsme.gov.in/*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था

5.1 पृष्ठभूमि

भारत की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 72% और कुल कर्मचारी का 77% प्रतिशत है। ऐसा लगता है कि ग्रामीण विकास के घटक समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं। 1970 के दशक तक, ग्रामीण विकास कृषि विकास का पर्याय था और इसलिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लगता है कि यह ध्यान मुख्य रूप से उद्योगपतियों के हितों द्वारा औद्योगीकरण को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त भाग निकालने के लिए प्रेरित किया गया है। समय के साथ, ग्रामीण विकास की इस छोटे धारक कृषि-केंद्रित अवधारणा में भारी बदलाव आया। 1980 के दशक की शुरुआत तक, विश्व बैंक ने इसे "... एक रणनीति के रूप में परिभाषित किया जो लोगों के एक विशिष्ट समूह-ग्रामीण गरीबों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई थी।" ऐसा प्रतीत होता है कि चार प्रमुख कारकों ने इस परिवर्तन को प्रभावित किया है जिससे ग्रामीण गरीबी की निरंतर गहराई के संबंध में चिंता बढ़ गई है। विकास की अवधारणा की व्याख्या पर विचारों के विकसित होने से एक अधिक विविध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय हुआ है जिसमें ग्रामीण गैर-कृषि उद्यम तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कारण से, ग्रामीण विकास से निपटने की रणनीति, गैर-कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण रूप से केंद्रित थी। भारत में ग्रामीण विकास की बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए, यह अनिवार्य है कि ग्रामीण विकास को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम बहु-आयामी दृष्टिकोण पर निर्भर हों। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि ग्रामीण विकास की पहचान योग्य व्यावसायिक विशेषताएं हैं, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों और कारीगर परिवारों में केंद्रित हैं।

एनसीआर के विभिन्न उप-क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के अलग-अलग रुझान दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- दिल्ली अपने सीमित भौगोलिक क्षेत्र और बढ़ते शहरीकरण के कारण ग्रामीण आर्थिक विकास में गिरावट दर्शाता है। नतीजतन, ग्रामीण आबादी में कमी आई है और ग्रामीण कर्मचारियों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ग्रामीण कार्यबल द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के प्रकार में भी पर्याप्त परिवर्तन हुआ है जो कृषि से सेवा उन्मुख व्यवसायों में एक प्रवृत्ति परिवर्तन को दर्शाता है। कुल कर्मचारी में ग्रामीण कर्मचारी के अनुपातिक योगदान में भी, इस कारण से, उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है। दूसरी ओर, उप-क्षेत्र में आईटी, आउटसोर्सिंग और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय के कारण सेवा क्षेत्र के उद्योगों में वृद्धि हुई है। दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में एक राजस्व गांव की चौड़ाई के हरित पट्टी को छोड़कर संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली के शहरीकरण का प्रस्ताव है।

हरियाणा उप-क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में एक मिश्रित प्रवृत्ति दिखाता है क्योंकि कृषि और गैर-कृषि प्रतिष्ठानों ने समान विकास प्रवृत्तियों को दिखाया है, इसके अलावा कई जिलों के अलावा गैर-कृषि प्रतिष्ठानों ने मोटे तौर पर शहरीकरण (गुड़गांव और फरीदाबाद) की ओर रुझान का संकेत दिया है। इन दो जिलों में कृषि भूमि में कमी आई है खासकर गुड़गांव में और कृषि उत्पादन में काफी कमी आई है। अन्य जिलों ने कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्शायी है जो ग्रामीण आर्थिक विकास की ओर झुकाव वाले कृषि रुझान को दर्शाता है। इसका एक मुख्य कारण पानीपत और रोहतक जिलों में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि है। कृषि के अलावा दूध और दुग्ध उत्पाद भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इस उप-क्षेत्र ने कृषि और गैर-कृषि संस्थानों में भी तुलनात्मक वृद्धि का अनुभव किया है, हालांकि उप-क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण के परिणामस्वरूप उत्तरार्द्ध वृद्धि हो रही है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

राजस्थान उप-क्षेत्र में श्रमिकों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है। पिछले वर्षों में कुल फसली क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हुई है, हाल के वर्षों में कुल उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के कारण बेहतर उत्पादन के लिए हुई है। इस प्रकार, राजस्थान उप-क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है।

5.2 ग्रामीण कार्यबल और एनसीआर में व्यवसाय

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण आबादी एनसीआर में कुल जनसंख्या का 37.41% है। ग्रामीण श्रमिक कुल ग्रामीण आबादी का 36.13 प्रतिशत है, जिसमें से 58.41% कुल ग्रामीण श्रमिकों में से किसान (39.87%) और कृषि मजदूर (18.54%) हैं (तालिका 5.2 देखें)। राजस्थान उप-क्षेत्र में ग्रामीण आबादी का अनुपात सबसे अधिक (82.19%) है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्रों में भी, काफी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों (क्रमशः 56.73% और 51.71%) में रहती है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का नगण्य हिस्सा (2.50%) है (तालिका 5.1 देखें)।

कार्यबल वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण कार्यबल का अनुपात राजस्थान उप-क्षेत्र में (87.09%) सबसे अधिक है, इसके बाद हरियाणा (57.10%), उत्तर प्रदेश (52.96%) और एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्रों में (2.33%) है (देखें तालिका 5.1 और चित्र 5.1)।

तालिका 5-1: 2011 में ग्रामीण जनसंख्या और कार्यबल

जिला	कुल जनसंख्या	ग्रामीण आबादी	ग्रामीण आबादी का %	कुल कार्य बल	ग्रामीण कार्य बल	ग्रामीण कार्यबल का %
उत्तर पश्चिम	36,56,539	2,13,950	5.85	1,188,545	67,492	5.68
उत्तर	8,87,978	17,746	2.00	296,446	5,278	1.78
उत्तर पूर्व	2,241,624	21,527	0.96	661,386	5,988	0.91
पूर्व	17,09,346	3,530	0.21	579,692	1,348	0.23
नई दिल्ली	1,42,004	0	0.00	59,541	लागू नहीं	0.00
केंद्रीय	5,82,320	0	0.00	2,07,374	लागू नहीं	0.00
पश्चिम	25,43,243	6,420	0.25	8,74,320	1846	0.21
दक्षिण पश्चिम	22,92,958	1,43,676	6.27	7,95,352	44,049	5.54
दक्षिण	27,31,929	12,193	0.45	9,24,393	4,226	0.46
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**1,67,87,941**	**4,19,042**	**2.50**	**5,587,049**	**1,30,227**	**2.33**
फरीदाबाद	18,09,733	3,70,878	20.49	579,229	1,06,758	18.43
गुडगाँव	15,14,432	4,72,179	31.18	5,44,716	1,58,462	29.09
रेवाड़ी	90,03,32	6,66,902	74.07	3,37,727	2,64,375	78.28
रोहतक	10,61,204	6,15,040	57.96	3,45,967	2,12,681	61.47
सोनीपत	14,50,001	9,96,637	68.73	5,23,179	3,76,188	71.90
पानीपत	12,05,437	6,50,352	53.95	4,12,318	2,21,931	53.83
झज्जर	9,58,405	7,15,066	74.61	3,26,534	2,53,833	77.74

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मेवात	10,89,263	9,65,157	88.61	2,89,964	2,58,721	89.23
पलवल	10,42,708	8,06,164	77.31	3,09,563	2,42,228	78.25
हरियाणा उप-क्षेत्र	**1,10,31,515**	**62,58,375**	**56.73**	**3,669,197**	**20,95,177**	**57.10**
	36,74,179	30,19,728	82.19	1,708,542	14,87,935	87.09
राजस्थान उप-क्षेत्र	**36,74,179**	**30,197,28**	**82.19**	**1,708,542**	**14,87,935**	**87.09**
बागपत	13,03,048	10,28,023	78.89	416,695	3,37,563	81.01

जिला	**कुल जनसंख्या**	**ग्रामीण आबादी**	**ग्रामीण आबादी का %**	**कुल कार्य बल**	**ग्रामीण कार्य बल**	**ग्रामीण कार्यबल का %**
बुलंदशहर	34,99,171	26,31,742	75.21	1,173,260	9,19,473	78.37
गौतमबुद्ध नगर	16,48,115	67,38,06	40.88	569,109	2,16,673	38.07
गाजियाबाद + हापुड़	46,81,645	15,19,098	32.45	1,520,538	4,96,077	32.63
मेरठ	34,43,689	16,84,507	48.92	1,090,539	5,43,366	49.83
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	**1,45,75,668**	**75,37,176**	**51.71**	**4,770,141**	**25,13,152**	**52.69**
एनसीआर	**4,60,69,303**	**1,72,34,321**	**37.41**	**15,734,929**	**62,26,491**	**39.57**

स्रोत: भारत की जनगणना *2011*, प्राथमिक जनगणना सार *2011*

2011 में एनसीआर उप-क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यबल का वितरण इंगित करता है कि एनसीआर में समग्र कार्यबल भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) 36% है, जबकि राजस्थान उप-क्षेत्र ने चार उप-क्षेत्रों में सबसे अधिक डब्ल्यूपीआर दर्ज किया है, इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र (33.48%), उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (33.34%) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली उप-क्षेत्र में (31.08%) है। राजस्थान उप-क्षेत्र में उच्च डब्ल्यूपीआर को ग्रामीण आबादी की अधिकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है (तालिका 5.2 और चित्र 5.1 देखें)।

तालिका 5-2: एनसीआर उप-क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यबल का वितरण

	किसान	किसानों का%	कृषि श्रमिक	कृषि श्रमिक का%	घरेलू उद्योग	घरेलू उद्योग का%	अन्य श्रमिक	अन्य श्रमिक का%	कुल कार्य बल	ग्रामीण डब्ल्यूपीआर
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	13,614	10.45	8,528	6.55	3,284	2.52	1,04,801	80.48	130,227	31.08
हरियाणा एक उप-क्षेत्र	7,69,412	36.72	3,94,428	18.83	57,078	2.72	8,74,259	41.73	20,95,177	33.48

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

राजस्थान उप-क्षेत्र	8,84,054	59.41	2,09,057	14.05	27,004	1.81	3,67,820	24.72	14,87,935	49.27
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	8,15,313	32.44	5,42,382	21.58	1,40,501	5.59	10,14,956	40.39	25,13,152	33.34
एनसीआर	**24,82,393**	**39.87**	**11,54,395**	**18.54**	**2,27,867**	**3.66**	**23,61,836**	**37.93**	**62,26,491**	**36.13**

स्रोत: भारत की जनगणना *2011*, प्राथमिक जनगणना सार *2011*

चित्र 5.1: 2011 में एनसीआर में ग्रामीण कार्यबल वितरण

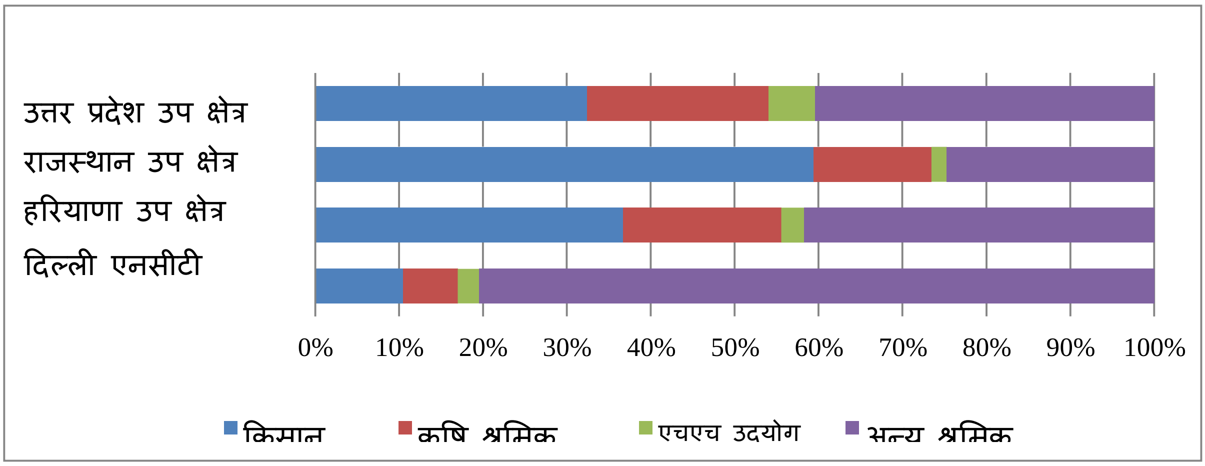

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, *2011*, भारत की जनगणना, *2011*, भारत सरकार

ग्रामीण कार्यबल में क्षेत्रवार वृद्धि के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 1971 से 2001 की अवधि के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात 44.3 प्रतिशत से घटकर 37.29 प्रतिशत हो गया, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात 18.98 प्रतिशत से बढ़कर 34.35 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में तृतीयक क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात 36.72 प्रतिशत से घटकर 28.37 प्रतिशत हो गया (तालिका 5.3 देखें)।

तालिका 5-3: एनसीआर में ग्रामीण कार्यबल का वितरण (1971, 1991 और 2001)

वर्ष /	1971		1991		2001	
श्रमिकों की श्रेणी	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत
किसान और खेतिहर मजदूर	16,72,667	42.99	26,11,535	33.78	36,13,413	33.76
पशुधन, वानिकी आदि	44,485	1.14	58,378	0.76	3,39,775	3.17
खनन और उत्खनन	6,457	0.17	13,884	0.18	38,098	0.36
उप-कुल प्राथमिक क्षेत्र	**17,23,609**	**44.3**	**26,83,797**	**34.71**	**39,91,286**	**37.29**
a) घरेलू उद्योग	1,66,572	4.28	1,28,661	1.66	7,73,216	7.22

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

b) घरेलू उद्योग के अलावा	4,64,125	11.93	12,81,140	16.57	11,68,879	10.92
निर्माण	1,07,937	2.77	3,54,049	4.58	17,34,125	16.20
उप कुल द्वितीयक क्षेत्र	**7,38,634**	**18.98**	**17,63,850**	**22.81**	**36,76,220**	**34.35**
व्यापार और वाणिज्य	4,14,000	10.64	11,37,207	14.71	7,94,641	7.42

वर्ष /	**1971**		**1991**		**2001**	
श्रमिकों की श्रेणी	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत
परिवहन, भंडारण और संचार	1,84,839	4.75	4,11,842	5.33	12,48,730	11.67
अन्य सेवाएं	8,29,850	21.33	17,34,993	22.44	9,92,787	9.28
उप-कुल तृतीयक क्षेत्र	**14,28,689**	**36.72**	**32,84,042**	**42.48**	**30,36,158**	**28.37**
कुल मुख्य श्रमिक	**38,90,932**	**100**	**77,31,689**	**100**	**1,07,03,664**	**100.00**
भागीदारी अनुपात	**27.4**		**29**		**34.97**	

स्रोत: भारत की जनगणना *1971, 1991* और *2001*

आर्थिक जनगणना 2005 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 15 लाख से अधिक श्रमिक गैर-कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। 3.34 लाख श्रमिकों के साथ हरियाणा उप-क्षेत्र में अधिकतम गैर-कृषि रोजगार है (तालिका 5.4 देखें)।

तालिका 5-4: ग्रामीण एनसीआर में गैर-कृषि रोजगार: 2005

जिला / उप क्षेत्र	कृषि*			गैर-कृषि			सभी		
	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल
मेरठ	39,150	11,602	50,752	30,750	28,720	59,470	69,900	40,322	1,10,222
बागपत	12,901	3,224	16,125	16,997	20,371	37,368	29,898	23,595	53,493
गाज़ियाबाद	1,774	1,177	2,951	24,002	24,433	48,435	25,776	25,610	51,386
गौतम बौद्ध नगर	6,735	369	7,104	14,487	33,471	47,958	21,222	33,840	55,062
बुलंदशहर	11,061	4,530	15,591	28,885	20,062	48,947	39,946	24,592	64,538
उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	**71,621**	**20,902**	**92,523**	**115,121**	**127,057**	**242,178**	**186,742**	**147,959**	**224,479**
पानीपत	931	1,188	2,119	16,368	38,809	55,177	17,299	39,997	57,296
सोनीपत	2,094	1,460	3,554	16,373	61,144	77,517	18,467	62,604	81,071
रोहतक	4,255	641	4,896	12,179	15,491	27,670	16,434	16,132	32,566
झज्जर	1,510	625	2,135	11,473	39417	50,890	12,983	40,042	53,025
रेवाड़ी	2,448	602	3,050	13,351	34858	48,209	15,799	35,460	51,259
गुडगाँव	6,875	1,721	8,596	26,076	115,790	1,41,866	32,951	1,17,511	1,50,462
फरीदाबाद	2,678	2,225	4,903	12,368	41,140	53,508	15,046	43,365	58,411
हरियाणा उप क्षेत्र	**20,791**	**8,462**	**29,253**	**108,188**	**346,649**	**312,971**	**128,979**	**237,600**	**333,628**

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**800**	**839**	**1,639**	**17,692**	**50,732**	**68,424**	**18,492**	**51,571**	**70,063**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**11,489**	**2,812**	**14,301**	**38,998**	**86,979**	**1,25,977**	**50,487**	**89,791**	**1,40,278**
एनसीआर	**104,701**	**33,015**	**137,716**	**279,999**	**611,417**	**623,573**	**384,700**	**526,921**	**628,170**

* पशुओं की खेती, कृषि सेवाएं, वानिकी, शिकार आदि।

स्रोत: आर्थिक जनगणना, *2005*

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में विभिन्न उप-क्षेत्रों में गैर-कृषि श्रमिकों की एकाग्रता को समझने के लिए, स्थान भागफल (एलक्यू) पर विश्लेषण किया गया था (तालिका 5.5 देखें)। यह देखा गया है कि गैर-कृषि क्षेत्र के रोजगार मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी और गुड़गांव और अलवर जिलों में अत्यधिक केंद्रित थे।

इसके अलावा, बागपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव और अलवर जिलों में ग्रामीण रोजगार की एकाग्रता है, जो एनसीआर (1.00) की तुलना में तीन गुना अधिक है। एनसीटी-दिल्ली ने 0.11 का निम्न एलक्यू दर्ज किया है जो ग्रामीण रोजगार की बहुत कम एकाग्रता को दर्शाता है।

फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में एलक्यू लगभग 1.00 के बराबर है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण रोजगार की एकाग्रता लगभग पूरे एनसीआर के बराबर है, जबकि उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के मेरठ और बागपत जिलों में कृषि में उच्च रोजगार एकाग्रता है। क्षेत्र (ओएई और स्थापना दोनों), जबकि बागपत और बुलंदशहर ने गैर-कृषि क्षेत्र में उच्च ग्रामीण रोजगार की सूचना दी। विभिन्न उप-क्षेत्रों में, राजस्थान उप-क्षेत्र ने ग्रामीण रोजगार (संयुक्त ओएई और प्रतिष्ठानों) की उच्चतम एकाग्रता की सूचना दी, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली उप-क्षेत्रों के एनसीटी का स्थान है।

तालिका 5-5: एल.क्यू. एनसीआर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार द्वारा व्यक्तियों की संख्या-2005

जिला	स्थान भागफल								
	कृषि			गैर-कृषि			सभी		
	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल
मेरठ	8.52	8.00	8.39	2.50	1.07	1.52	4.14	1.42	2.44
बागपत	8.49	6.73	8.07	4.18	2.30	2.89	5.36	2.52	3.58
गाज़ियाबाद	0.39	0.81	0.49	1.95	0.91	1.24	1.53	0.90	1.14
गौतम बौद्ध नगर	1.23	0.21	0.99	0.99	1.05	1.03	1.06	1.01	1.03
बुलंदशहर	4.73	6.14	5.07	4.62	1.47	2.46	4.65	1.71	2.81
उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	**3.87**	**3.58**	**3.80**	**2.32**	**1.17**	**1.54**	**2.74**	**1.30**	**1.84**
पानीपत	0.39	1.57	0.67	2.56	2.78	2.71	1.97	2.71	2.44
सोनीपत	0.89	1.98	1.15	2.61	4.47	3.88	2.14	4.34	3.52
रोहतक	2.57	1.23	2.25	2.75	1.60	1.96	2.70	1.58	2.00
झज्जर	0.91	1.20	0.98	2.59	4.07	3.61	2.13	3.93	3.26
रेवाड़ी	1.76	1.37	1.66	3.58	4.28	4.06	3.09	4.14	3.74

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

गुडगाँव	1.50	1.19	1.43	2.13	4.32	3.63	1.96	4.16	3.34
फरीदाबाद	0.54	1.43	0.76	0.94	1.43	1.28	0.83	1.43	1.21
हरियाणा उप क्षेत्र	**1.10**	**1.42**	**1.17**	**2.13**	**3.13**	**2.82**	**1.85**	**3.04**	**2.60**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**0.01**	**0.04**	**0.02**	**0.10**	**0.14**	**0.13**	**0.08**	**0.13**	**0.11**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**2.99**	**2.32**	**2.83**	**3.79**	**3.87**	**3.85**	**3.57**	**3.79**	**3.71**
एनसीआर	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

5.3 ग्रामीण एनसीआर में मंडी और विपणन अवसंरचना

निजी व्यापार भारत में कृषि उपज बाजारों पर हावी रहा है। बड़ी मात्रा में निपटने की आवश्यकता के साथ, निजी व्यापार, समय के साथ बाजारों के आकार और संरचना में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए काफी विस्तार हुआ है। कृषि उत्पाद विपणन श्रृंखला के भीतर विभिन्न माध्यमों से चलते हैं। विपणन चैनल किसानों से अंतिम उपभोक्ताओं तक उपज पहुंचाने में शामिल बाजार कार्यकर्ताओं के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं। विपणन चैनल की लंबाई बाजार के आकार, वस्तु की प्रकृति और उपभोक्ता स्तर पर मांग के पैटर्न पर निर्भर करती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम के तहत कृषि वस्तुओं की खरीद में सरकारी हस्तक्षेप, खाद्यान्न की खरीद, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस), एकाधिकार खरीद, वस्तुओं की खुले बाजार की खरीद ने दशकों से कृषि अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन किया है। सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा पारंपरिक रूप से हस्तक्षेप के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। सार्वजनिक और सहकारी एजेंसियों के प्रवेश ने मौजूदा विपणन चैनलों को बदल दिया और उनके माध्यम से विपणन की मात्रा के संदर्भ में उनका महत्व भी बदल दिया।

एनसीआर में 65 विनियमित बाजार और 74 सब-यार्ड और 282 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनमें हरियाणा उप-क्षेत्र में सबसे अधिक विनियमित बाजार और यार्ड हैं और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में सबसे अधिक कोल्ड स्टोरेज हैं। मेरठ में एनसीआर के सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज की संख्या सबसे अधिक है जबकि अलवर जिले में सबसे अधिक सब-यार्ड हैं (तालिका 5.6 देखें)

तालिका 5-6: एनसीआर में जिलेवार प्रमुख ग्रामीण बाजार, उप-यार्ड और कोल्ड स्टोरेज-2010

उप-क्षेत्र/जिले	नियंत्रित	उप-यार्ड	कोल्ड स्टोरेज
फरीदाबाद	6	4	3
गुडगाँव	8	7	3
झज्जर	2	3	-
मेवात	-	-	-
पानीपत	5	4	5
रेवाड़ी	2	6	-
रोहतक	3	4	4
सोनीपत	3	9	49
हरियाणा उप-क्षेत्र	**29**	**37**	**64**
अलवर/राजस्थान उप-क्षेत्र	**3**	**16**	**3**

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

बागपत	2	5	8
बुलंदशहर	9	6	34
गौतमबुद्ध नगर	4	1	22
गाज़ियाबाद	4	4	22
मेरठ	4	3	38
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	**23**	**19**	**124**
दिल्ली एनसीटी	**10**	**2**	**91**
एनसीआर	**65**	**74**	**282**

स्रोत: *http://rsamb.rajasthan.gov.in, http://agmarknet.nic.in*

राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एनसीआर घटक राज्यों में बड़े पैमाने पर भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं।

एनसीआर में एग्रीकल्चरल कमोडिटी बाजार भौगोलिक रूप से सीमित हैं और समय के साथ संरचना में ज्यादा बदलाव नहीं देखा है। कुल मिलाकर, एनसीआर में 23 फल और सब्जी मंडियां हैं, 49 अनाज मंडियां सबसे अधिक संख्या में बुलंदशहर जिले में स्थित हैं, जबकि चारा बाजार एनसीआर के हरियाणा उप-क्षेत्र और दिल्ली के एनसीटी तक सीमित है (तालिका 5.7 देखें)।

तालिका 5-7: एनसीआर में जिलेवार/उप-क्षेत्रवार मंडियां: 2010

क्रम संख्या	उप क्षेत्र	फल और सब्जी	चारा बाजार	मछली बाजार	अनाज बाजार	कपास बाजार	ऊन बाजार	डेयरी	फूल
हरियाणा उप-क्षेत्र									
1	फरीदाबाद	2	2	1	4				
2	गुडगाँव	1	1		6				
3	झज्जर	2			2				
4	मेवात				1				
5	पानीपत	1		1	5		1		
6	रेवाड़ी	1	1		2				
7	रोहतक	1	1		3	1			
8	सोनीपत	2	1		3				
राजस्थान उप-क्षेत्र									
1	अलवर	0							
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र									
1	बागपत				2				
2	बुलंदशहर	7			9				
3	गौतमबुद्ध नगर	1			4				
4	गाज़ियाबाद	1			4				
5	मेरठ	1			4				
दिल्ली उप-क्षेत्र									
1	दिल्ली	3		1				2	1
एनसीआर		**23**	**6**	**3**	**49**	**1**	**1**	**2**	**1**

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

स्रोत: उप-क्षेत्रवार संबंधित (एनसीआर) वेबसाइट और सांख्यिकीय हैंडबुक से

हरियाणा उप-क्षेत्र के अधिकांश जिले सब्जी उत्पादकों और उपभोक्ताओं को सीधे जोड़ने के लिए 90 के दशक के मध्य में स्थापित अपनी मंडी (हमारी बाजार) अवधारणा का पालन करते हैं। किसान-उत्पादक सीधे खरीदारों या उपभोक्ताओं को उपज की सुविधा प्रदान करते हैं। कृषि उपज मंडी समिति, जहां अपनी मंडी स्थित है, वहां जगह, पानी, शेड, काउंटर और तराजू जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

एनसीटी-दिल्ली में, आजादपुर फल और सब्जी बाजार एशिया का सबसे बड़ा फल और सब्जी बाजार है। इस उप-क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण सब्जी मंडियां ओखला और तिलक नगर में हैं। यह महत्वपूर्ण फलों और सब्जियों के राष्ट्रीय वितरण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। 1977 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्मित, विनियमित बाजार में लगभग 3664 कमीशन एजेंट / थोक व्यापारी हैं और विनियमन का उद्देश्य उत्पादकों / विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा के लिए व्यवस्थित विपणन सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी विपणन के लिए अनुकूल आर्थिक कानूनी और ढांचागत स्थितियों को सुनिश्चित करना है।

5.4 एनसीआर में कृषि प्रसंस्करण उद्योग

5.4.1 एनसीआर में वर्तमान स्थिति

कृषि-प्रसंस्करण उद्योग मुख्य घटक हैं और ग्रामीण उद्योगों का एक सबसेट है। ग्रामीण उद्योगों की कोई समान रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। हालाँकि, ग्रामीण उद्योग वे फर्में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण प्रौद्योगिकी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित कच्चे माल का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। कृषि प्रसंस्करण इकाइयों का जिलेवार वितरण तालिका 5.8 में दिया गया है।

तालिका 5-8: कृषि प्रसंस्करण के जिलेवार प्रमुख क्षेत्र

जिला	कृषि प्रसंस्करण इकाई का प्रकार
दिल्ली	गेहूं प्रसंस्करण, चावल प्रसंस्करण
बागपत	गेहूं, चावल
बुलंदशहर	चावल प्रसंस्करण, गन्ना प्रसंस्करण
गौतमबुद्धनगर	गेहूं, गन्ना और सब्जी प्रसंस्करण
गाज़ियाबाद	चावल प्रसंस्करण, गन्ना
मेरठ	चावल प्रसंस्करण, गन्ना
फरीदाबाद	गेहूं प्रसंस्करण
गुडगाँव	गेहूं प्रसंस्करण
झज्जर	सरसों का तेल निष्कर्षण, मसाले
मेवात	चना, जौ, सरसों का तेल निष्कर्षण
पानीपत	चावल प्रसंस्करण, अचार, गन्ना प्रसंस्करण, फल और सब्जी निर्जलीकरण
रेवाड़ी	सरसों का तेल निष्कर्षण, मसाले
रोहतक	गेहूं प्रसंस्करण, पशु चारा, गन्ना
सोनीपत	चावल प्रसंस्करण, फल और सब्जी प्रसंस्करण, मशरूम
अलवर	गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, खाद्य तेल निष्कर्षण

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन, *2015*

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

भारत, परिवर्तनशील जलवायु और मिट्टी के कारण, फलों और सब्जियों सहित बागवानी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता है, और बागवानी फसलों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र उत्पादन, खपत, निर्यात और विकास संभावनाओं के मामले में सबसे बड़ा है। सरकार ने व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कई वित्तीय राहतों और प्रोत्साहनों के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक उच्च प्राथमिकता का दर्जा बनाए रखा है। कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन का उद्देश्य फसल काटने से पहले या कटाई के बाद की बर्बादी, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि को कम करना है।

एनसीआर गन्ना, चावल और बागवानी उत्पादों जैसे कृषि उत्पादों के उत्पादन में बहुत समृद्ध है। राइस मिलिंग हरियाणा उप-क्षेत्र में पानीपत और सोनीपत जिलों और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों में प्रमुख उद्योगों में से एक है। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में लंबे अनाज वाले सुगंधित चावल का भी भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है। इस कारण से, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए पर्याप्त अवसर हैं। एनसीआर में विशेष रूप से पानीपत के आसपास ऐसी कई प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं। इसके अलावा, एनसीआर में निर्यात बाजार के विस्तार के लिए निवेश के प्रचुर अवसर हैं। कृषि-प्रसंस्कृत उत्पाद बाजार की मांग नए उत्पादों की बढ़ती स्वीकार्यता के साथ-साथ बाजार के विकास के प्रयासों से पूरी की जाएगी, जो कुछ फलों और सब्जियों के उत्पादों की मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण जरूरी है।

a) हरियाणा उप-क्षेत्र

हरियाणा उप-क्षेत्र को प्रचुर उपजाऊ भूमि के साथ एक कृषि प्रधान क्षेत्र होने का लाभ है। फलों और सब्जियों (नाशपाती वस्तुओं) के उत्पादन के लिए देश के आधार में इसका प्रमुख योगदान है। यह दिल्ली के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों और आसपास के शहरी समूहों में से एक के निकट होने का भौगोलिक लाभ प्राप्त करता है। जैसे, राज्य कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए एक बड़ी संभावना प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण शामिल है, लेकिन संबद्ध सेवा उद्योग भी शामिल है जो आवश्यक व्यवसाय विकास सेवाएं (बीडीएस) जैसे कि कोल्ड चेन, भंडारण, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, फलों और सब्जियों के उत्पादों का अलगाव और पैकेजिंग प्रदान करता है। राज्य ने राय (कुंडली, सोनीपत जिला) के पास हरियाणा उप-क्षेत्र में एक फूड पार्क के विकास की पहल की है; इसके साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए कुंडली में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना की है।

b) उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

राज्य ने कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बिजली और ब्याज मुक्त ऋण जैसे कई प्रोत्साहन दिए हैं। उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में बागवानी आधारित उद्योगों का पर्याप्त आधार है। एनसीआर में फूलों की खेती और सजातीय उद्योगों के विकास की जबरदस्त स्कोप है। मेरठ और गाजियाबाद जिलों में आम, लीची, मिर्च, दमिश्क गुलाब, ग्लेडियोली, आलू और अन्य सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी आधार बनने की क्षमता है।

कृषि और कृषि-उद्योग के बीच अंतर-निर्भरता कुल उत्पादन और मूल्य वर्धित के मामले में अच्छी तरह से स्थापित पाई गई थी। इस कारण से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उप-क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

c) राजस्थान उप-क्षेत्र

राजस्थान उप-क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की संभावनाएँ हैं। सरसों, बाजरा और ग्वार मेथी, धनिया और जीरा के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद इसबगोल और मेंहदी (मेहंदी), जौ, सोयाबीन, चना, कुल तिलहन, अरंडी और रबी दाल जैसे उत्पाद हैं। गुग्गल, अश्वगंधा, एलोवेरा आदि कुछ जड़ी-बूटियों के उत्पादन में भी राजस्थान का प्रमुख स्थान है। यह अलवर जिले और आसपास के क्षेत्रों में प्याज, टमाटर, मिर्च, लहसुन, केर और सांगरी का भी उत्पादन करता है।

5.4.2 5.4.2 एनसीआर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए प्रमुख चुनौतियां

एनसीआर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं:

a) शहरीकरण के दबाव और भूमि की बढ़ती लागत के कारण उत्पादन इकाई का आकार;
b) सीमित सिंचाई सुविधाओं और भूजल की उपलब्धता के कारण पर्याप्त जल आपूर्ति की उपलब्धता;
c) फलों और सब्जियों की कीमत में अक्सर विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट के क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव होता है;
d) एनसीआर में बागवानी पद्धतियां मानकीकृत नहीं हैं; तथा
e) खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ।

5.5 ग्रामीण एनसीआर में सरकारी कार्यक्रम

एनसीआर में कई ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम तालिका 5.9 में दिए गए हैं।

तालिका 5-9: आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम
A	**ग्रामीण रोजगार / आजीविका**
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
2	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिसे अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है)
3	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
4	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
B	**ग्रामीण संपर्क/अवसंरचना/आवास**
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
6	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)
7	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)
8	राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एनआरडब्ल्यूएसपी)
9	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

यूपी के बुलंदशहर जिले में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान उप-क्षेत्र ने मनरेगा के तहत अधिकतम 30.42 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, इसके बाद इसी अवधि के दौरान हरियाणा उप-क्षेत्र में मेवात जिले में कुल 13.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। एनसीआर के अन्य सभी जिलों में खर्च का आंकड़ा 10 करोड़ रुपये से भी कम है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

पीएमजीएसवाई के तहत, 2011-12 के दौरान राजस्थान उप-क्षेत्र के अलवर जिले (लगभग 300 करोड़ रुपये) में चार उप-क्षेत्रों में सबसे अधिक खर्च किया गया है, इसके बाद एनसीआर के यूपी उप-क्षेत्र के गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ और बागपत जिले हैं। (तालिका 5.10 देखें)

तालिका 5-10: एनसीआर के जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में 2011-12 के दौरान किए गए व्यय की स्थिति (रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	जिला/उप-क्षेत्र	पीएमजीएसवाई	आरजीजीवीवाई	मनरेगा	टीएससी#
A	हरियाणा उप-क्षेत्र				
1	फरीदाबाद	68.03	0	0.53	4.94
2	गुडगाँव	80.84	*	0.45	4.57
3	झज्जर	117.76	6.23	2.87	6.35
4	पानीपत	87.64	9.51	4.11	7.64
5	रेवाड़ी	83.97	11.09	2.16	6.67
6	रोहतक	99.14	5.54	2.76	4.52
7	मेवात	*	16.09	13.78	0.8
8	पलवल	*	*	3.32	*
9	सोनीपत	82.08	16.88	4.18	5.01
B	यूपी उप-क्षेत्र				
1	मेरठ	112.43	0	4.88	13.35
2	बागपत	106.29	0	6.38	11.87
3	गाज़ियाबाद	136.77	5.85	6.16	8.25
4	गौतमबुद्ध नगर	70.51	0	1.42	6.25
5	बुलंदशहर	116.64	17.49	30.42	17.29
C	राजस्थान उप-क्षेत्र				
1	अलवर	298.26	51.14	0	9.68
D	एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र				
1	दिल्ली के एनसीटी	*	*	*	*

* चिह्नित प्रविष्टियां दर्शाती हैं कि या तो कार्यक्रम संबंधित एनसीआर जिलों में नहीं चल रहा है या डेटा उपलब्ध नहीं है।

पीएमजीएसवाई-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, आरजीजीवीवाई-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, मनरेगा-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम; टीएससी-संपूर्ण स्वच्छता अभियान भी संपूर्ण स्वच्छता अभियान (अब स्वच्छ भारत अभियान)

5.6 एनसीआर ग्रामीण अर्थव्यवस्था: प्रमुख मुद्दे

एनसीआर में ग्रामीण क्षेत्रों की ख़ासियत के बावजूद, ग्रामीण उद्योगों के लिए एक अलग पहचान अभी तक संस्थागत नहीं हुई है। यह विशेष रूप से स्पष्ट है कि यह क्षेत्र लाखों श्रमिकों को रोजगार देने के अवसर प्रदान

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

करता है और यदि इसका उचित रूप से पालन किया जाता है तो यह गरीबी में कमी के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। यह उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और सहायक सेवाओं को शामिल करके उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग करके दूरस्थ / पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। उदाहरण के लिए, खादी और ग्रामोद्योग की गतिविधियाँ, यदि ठीक से विकसित की जाती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आबादी के पलायन को काफी हद तक रोकने में योगदान कर सकती हैं और इस प्रकार शहरीकरण की सामाजिक लागत को कम कर सकती हैं। यह स्थापित किया गया है कि ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से एनसीआर एक सजातीय इकाई नहीं है और चार उप-क्षेत्रों के अपने अद्वितीय ग्रामीण विकास मुद्दे हैं।

एनसीटी-दिल्ली के पास बहुत कम कृषि भूमि है। कृषि गतिविधियों के अभाव में, कई अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियाँ पैदा हो गई हैं। परिणामस्वरूप, अधिकांश कामकाजी आबादी, जो पहले कृषि संबंधी गतिविधियों में लगी हुई थी, अनौपचारिक क्षेत्र में लगी हुई है।

यह भी महसूस किया गया है कि एनसीआर में गैर-कृषि क्षेत्र एनसीआर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन उप-क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के बढ़ते शहरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण पिछले दशक में हरियाणा और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्रों में उनके ग्रामीण आर्थिक ढांचे में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं।

एक ओर, एनसीटी-दिल्ली ने पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण आबादी (और कार्यबल) के साथ-साथ कृषि और संबंधित प्रतिष्ठानों में कमी देखी है, दूसरी ओर हरियाणा और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र ग्रामीण आबादी (और कार्यबल) साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में वृद्धि की रिपोर्ट करते हैं। गुड़गांव और गाजियाबाद जिलों में, विशेष रूप से, गैर-कृषि संस्थानों में तेजी से वृद्धि देखी गई है।

क्षेत्र के विकास के संदर्भ में, एक समृद्ध बागवानी पृष्ठभूमि के बावजूद बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण अभी भी बहुत कम है। विशेष रूप से कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को अभी भी विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, दोनों लक्षित उत्पाद (वर्तमान में आलू को लक्षित) और कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के आकार (उत्पादन क्षेत्रों के पास छोटी इकाइयों को केवल बड़ी केंद्रीकृत इकाइयों को बढ़ावा देने के बजाय जोर दिया जाना चाहिए)) इस क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि बागवानी उत्पाद की कटाई के बाद की हानि कुल उत्पादन के 5% -39% के बीच होती है। कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समुचित कामकाज और विकास में एक और बड़ी बाधा एनसीआर के बाहरी इलाके में नियमित बिजली आपूर्ति की अनुपलब्धता है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

6. अनौपचारिक क्षेत्र

6.1 पृष्ठभूमि

भारत में, मजदूरी रोजगार कुल रोजगार का एक छोटा सा अंश है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के अनुमान के अनुसार, 1999-2000 में लगभग 90 लाख लोग बेरोजगार थे, जिनमें से लगभग 55 लाख व्यक्ति माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। एक समान रूप से गंभीर चिंता निम्न स्तर की उत्पादकता और आय के साथ काम करने वाले नियोजित व्यक्तियों की बड़ी संख्या है।

असंगठित क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनका रोजगार के मामले में एक बड़ा योगदान है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। पिछले वर्षों में, असंगठित क्षेत्र का महत्व और भूमिका इतनी बढ़ गई है कि इसका योगदान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में भी होता है।

एनसीआर में अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयों को तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहले प्रकार में सूक्ष्म और लघु इकाइयाँ होती हैं, और यह संगठित बड़े उद्योगों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। उनकी प्राथमिक भूमिका बड़े उद्योगों को उप-ठेकेदारों के रूप में सेवा देना है। उदाहरण के लिए, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में गोविंदपुरी मुख्य रूप से ओखला और नोएडा में गारमेंट इकाइयों को उप-ठेकेदार सेवाएं प्रदान करता है। इसी तरह, अन्य उप-ठेकेदार जैसे एनजीओ, स्वयं सहायता समूह और अन्य अनौपचारिक नेटवर्क भी एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में मौजूद हैं। दूसरे प्रकार में विशेष उत्पाद बनाने वाली इकाइयाँ शामिल हैं। उदाहरण के लिए; मिट्टी के बर्तनों और सिरेमिक के लिए खुर्जा, पीवीसी और प्लास्टिक के लिए त्रिनगर, केबल, प्लास्टिक और बर्तन के लिए विश्वास नगर, फैब्रिकेशन और धातु उत्पादों के लिए अलवर और लाइट इंजीनियरिंग और धातु उत्पादों के लिए सोनीपत। उदाहरण के लिए तीसरे प्रकार में सेवा क्षेत्र शामिल है; निर्माण श्रमिक, छोटे व्यापारी, फुटपाथ विक्रेता, अन्य घरेलू सेवा प्रदाता जो कपड़े धोने, परिवहन और घरेलू मदद आदि की सुविधा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की हिस्सेदारी का विवरण तालिका 6.1 में दिया गया है।

तालिका 6-1: अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का अनुमान

शुद्ध घरेलू उत्पाद में अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा: **2001-02**						
क्रम संख्या	उद्योग समूह	अनौपचारिक	अन्य	असंगठित	संगठित	कुल
1	कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना	25.5		25.5	0.9	26.4
2	खनन और उत्खनन	0.2		0.2	1.8	2.0
3	उत्पादन	1.6	3.4	5.0	8.4	13.4
4	बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति	0.1		0.1	1.0	1.0
5	निर्माण	3.9		3.9	2.5	6.4
6	व्यापार, होटल, रेस्तरां	9.3	2.5	11.9	3.8	15.6
7	परिवहन और संचार	3.3	0.6	3.9	2.8	6.7
8	अचल संपत्ति, वित्तीय सेवाएं और आवासों का स्वामित्व	2.6	2.9	5.4	7.6	13.0

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

9	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	1.3	1.3	2.6	12.8	15.4
	कुल	**47.7**	**10.7**	**58.5**	**41.5**	**100.0**

स्रोत: असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग, भारत

6.2 अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा

अनौपचारिक क्षेत्र या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था या ग्रे अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिस पर कर नहीं लगाया जाता है और न ही सरकार के द्वारा किसी भी तरह से इसकी निगरानी की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा उद्योग की कानूनी स्थिति पर आधारित होती है। कानूनी स्थिति पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है। असंगठित क्षेत्र से संबंधित निश्चित और सांख्यिकीय मुद्दों पर कार्य दल ने 'असंगठित क्षेत्र' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

> "असंगठित क्षेत्र में वे सभी अनिगमित निजी उद्योग शामिल होते हैं, जो स्वामित्व या साझेदारी के आधार पर उन व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व में होते हैं जो कुल दस से कम श्रमिकों के साथ संचालित वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और उत्पादन में लगे हुए हैं"।

असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) भी अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

> "असंगठित श्रमिक वे हैं जो असंगठित क्षेत्र या घरों में काम करते हैं। हालांकि, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा लाभ वाले श्रमिक नियम के अपवाद हैं। औपचारिक क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा लाभ के बिना बेरोजगार श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा हैं।"

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र पर ऊपर उल्लिखित परिभाषाओं का उपयोग मानक परिभाषा के रूप में किया जाता है। एनसीईयूएस असंगठित को अनौपचारिक से अलग नहीं करता है, और इन शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है।

अनौपचारिक, औपचारिक और घरेलू क्षेत्रों में अक्सर विभिन्न रोजगार की स्थिति या कार्य व्यवस्था होती है। रोजगार की स्थिति सुरक्षा और भेद्यता के महत्व का प्राथमिक संकेतक है। वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और उत्पादन में लगे व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व वाले असंगठित निजी उद्यम जो स्वामित्व या साझेदारी के आधार पर दस से कम श्रमिकों के साथ काम करते हैं, वे भी अनौपचारिक क्षेत्र का एक हिस्सा हैं।
श्रम पर प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आयोग (1966-69) ने असंगठित क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

> "वे श्रमिक जो रोजगार की आकस्मिक प्रकृति, अज्ञानता और निरक्षरता, संस्थानों के छोटे और बिखरे हुए आकार जैसे कुछ बाधाओं के कारण अपने सामान्य हित की खोज में खुद को संगठित करने में सक्षम नहीं हैं"।

अनौपचारिक क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम पैरामीटर श्रमिकों की संख्या है। कुछ अन्य कारक जो अनौपचारिक गतिविधि को परिभाषित करते हैं, वे हैं निवेश, टर्नओवर और बाजार का प्रकार। अनौपचारिक क्षेत्र, जो संगठित क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, अभी भी अपने वास्तविक अर्थों में आर्थिक गतिविधि की परिभाषा में पूरी तरह से एकीकृत नहीं है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

6.3 अनौपचारिक क्षेत्र पर डेटा

एनएसएसओ, जो समय-समय पर असंगठित उद्यमों का सर्वेक्षण करता है, के पास असंगठित क्षेत्र की पहचान के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं:

विनिर्माण क्षेत्र के मामले में, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा कवर नहीं किए गए उद्यमों को असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है।
सेवा क्षेत्र के मामले में, सरकार (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों) और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों को छोड़कर सभी उद्यमों को असंगठित माना जाता है।

एनएसएसओ ने 1999-2000 में एक अनौपचारिक क्षेत्र का सर्वेक्षण भी किया। एएसआई द्वारा कवर किए गए को छोड़कर स्वामित्व या साझेदारी के स्वामित्व के मानदंड वाले सभी गैर-कृषि उद्यमों को सर्वेक्षण के उद्देश्य से अनौपचारिक गैर-कृषि उद्यमों के रूप में माना गया था।

राष्ट्रीय लेखा संकलन के तहत, असंगठित क्षेत्र शब्द का प्रयोग अवशिष्ट उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, जो संगठित क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। हालांकि, संगठित क्षेत्र का कवरेज डेटा की उपलब्धता और विभिन्न प्रशासनिक स्रोतों की पहुंच के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न था।

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) दस या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले सभी संस्थानों को एक संगठित क्षेत्र के रूप में मानता है। रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959, केवल उन इकाइयों के लिए रोजगार रिटर्न जमा करना अनिवार्य बनाता है जो आमतौर पर 25 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को तीन मूल प्रकार के उद्यमों जैसे: स्वयं के खाता निर्माण उद्यम (ओएएमई), गैर-निर्देशिका विनिर्माण उद्यम (एनडीएमई) और निर्देशिका निर्माण उद्यम (डीएमई) में विभाजित किया गया है। क्षेत्रों के आधार पर विभाजित उद्यम ग्रामीण और शहरी हैं।

भारत में पंजीकृत और संगठित क्षेत्रों का आकार अक्सर छोटा होता है; बाकी आर्थिक गतिविधियाँ असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र की श्रेणी में आती हैं। विनिर्माण क्षेत्र के मामले में संगठित या औपचारिक की परिभाषा स्पष्ट है। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत सभी उद्यमों को संगठित या औपचारिक माना जाता है।

अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों का अनुमान आर्थिक जनगणना में उपलब्ध आंकड़ों को लेकर किया गया था।

चूंकि इन उप-क्षेत्रों के लिए एनएसएस डेटा उपलब्ध नहीं है, कार्यात्मक योजना अनुमान दो स्रोतों : (i) एनसीटी-दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र के लिए एनएसएस डेटा और (ii) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान उप-क्षेत्र के लिए आर्थिक जनगणना डेटा पर निर्भर करता है। अनौपचारिक क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए अवशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में आर्थिक जनगणना का उपयोग किया जाता है।

6.4 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में असंगठित विनिर्माण और अनौपचारिक सेवा क्षेत्र

6.4.1 पृष्ठभूमि

एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (2005-06) में लगभग 9.38% का योगदान देता है, जिसमें से 7% असंगठित क्षेत्र द्वारा और 2.38% संगठित विनिर्माण क्षेत्र से आता है। 2006-

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

2007 में एनएसएस सर्वेक्षण (62वें दौर) के अनुसार असंगठित विनिर्माण उद्यमों की कुल संख्या 1,00,740 इकाई थी। कुल उद्यमों में से, 20.30% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे और 79.70% एनसीटी-दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

6.4.2 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में असंगठित विनिर्माण क्षेत्र

पहनने वाले कपडे, ड्रेसिंग और रंगाई (एनआईसी 18) का निर्माण असंगठित विनिर्माण उद्यमों की कुल संख्या में 28.29% का योगदान देता है, इसके बाद फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का निर्माण (एनआईसी 28) 22.00% और फर्नीचर का निर्माण (एनआईसी 36) 7.25% है। योगदान देने वाले अन्य प्रमुख क्षेत्र खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ (5.86%), मोटर वाहन, आदि (5.31%) और मशीनरी और उपकरण (4.88%) हैं (तालिका 6.2 देखें)।

एनएसएस के आंकड़ों (2005-06) के अनुसार, असंगठित विनिर्माण उद्यमों द्वारा सृजित कुल रोजगार लगभग 4.82 लाख था।

तालिका 6-2: एनसीटी-दिल्ली में असंगठित विनिर्माण उद्यम

क्रम संख्या	उद्योग कोड	विवरण	उद्यम	प्रतिशत	रैंक
1	18	कपड़ों का निर्माण; फर की ड्रेसिंग और रंगाई	28,495	28.29	1
2	28	मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	22,165	22	2
3	36	फर्नीचर का निर्माण; एमएफजी एनईसी	7,300	7.25	3
4	15	खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों का निर्माण	5,907	5.86	4
5	34	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का निर्माण	5,354	5.31	5
6	29	मशीनरी और उपकरण का निर्माण	4,916	4.88	6
7	22	रिकॉर्डेड मीडिया का प्रकाशन, मुद्रण और पुनरुत्पादन	4,256	4.22	7
8	17	वस्त्र निर्माण	3,941	3.91	8
9	31	विद्युत मशीनरी और उपकरण का निर्माण	3,480	3.45	9
10	19	चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग: सामान, हैंडबैग, जूते आदि का निर्माण।	3,467	3.44	10
11	21	कागज और कागज उत्पादों का निर्माण	2,380	2.36	11
12	32	रेडियो, टेलीविजन और संचार उपकरण और उपकरण का निर्माण	2,179	2.16	12
13	25	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	1,862	1.85	13
14	35	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	1,676	1.66	14
15	20	लकड़ी के उत्पादों का निर्माण	1,239	1.23	15
16	26	अन्य गैर-धातु खनिज उत्पादों का निर्माण	683	0.68	16

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

क्रम संख्या	उद्योग कोड	विवरण	उद्यम	प्रतिशत	रैंक
17	33	चिकित्सा, प्रेसिजन और ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियां और घड़ियों का निर्माण	672	0.67	17
18	27	मूल धातुओं का निर्माण	603	0.6	18
19	24	रसायन और रसायन उत्पादों का निर्माण	164	0.16	19
20	30	कार्यालय, लेखा और उपकरण का निर्माण	1	0	20
		कुल	**1,00,740**	**100**	

स्रोत: दिल्ली में असंगठित विनिर्माण उद्यम, एनएसएस 62वां दौर, जुलाई 2005 - जून 2006

6.4.3 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में अनौपचारिक सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वोपरि योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। एनसीटी-दिल्ली में, सेवा क्षेत्र जीएसडीपी में लगभग 79% का योगदान देता है, जो 35% से अधिक आबादी को रोजगार देता है (तालिका 6.3 देखें)। आर्थिक जनगणना (2005) ने कहा कि लगभग 40% उद्यम स्वयं सेवा क्षेत्र का हिस्सा थे। स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) में 1980 से 2008-09 तक 13% की वृद्धि हुई है; हालांकि, इन अनुमानों में सेवा क्षेत्र के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र शामिल हैं।

कुल उद्यमों में से लगभग 89.04% शहरी क्षेत्रों में और 10.96% ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होते हैं। उद्यमों को सेवा क्षेत्र के संदर्भ में 'स्वयं का खाता उद्यम (ओएई)' और 'संस्थान' में वर्गीकृत किया गया है। सेवा क्षेत्र में कुल उद्यमों में से, स्वयं के खाते के उद्यमों का योगदान 61.51 प्रतिशत है, जबकि संस्थानों का योगदान 38.49% है (तालिका 6.3 देखें)।

तालिका 6-3: दिल्ली में अनौपचारिक सेवा क्षेत्र

क्षेत्र	खुद का खाता उद्यम	संस्थान	सभी	कुल %
ग्रामीण	18,184	8,060	26,244	10.96
शहरी	1,29,097	84,106	2,13,203	89.04
दिल्ली	1,47,281	92,166	2,39,447	100
कुल %	**61.51**	**38.49**	**100**	

स्रोत: दिल्ली में सेवा क्षेत्र के उद्यमों पर रिपोर्ट, एनएसएस 63वां दौर, जुलाई 2006 - जून 2007

अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के उद्यमों का सबसे बड़ा अनुपात संचार (18.4%) के क्षेत्र में है, इसके बाद रियल एस्टेट, किराये और व्यावसायिक गतिविधियों (17.23%) का स्थान है और सबसे कम हिस्सा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (0.43%) में देखा गया है (देखें। तालिका 6.4)।

तालिका 6-4: सेवा क्षेत्र में उद्यमों का श्रेणीवार वितरण

सारणीकरण श्रेणी	विवरण	उद्यमों की संख्या	कुल में % की हिस्सेदारी
H1	होटल	1,757	0.73%

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

H2	रेस्टोरेंट	28,498	11.9%
I1	स्टोर और वेयरहाउसिंग	0	0
I2	यंत्रीकृत सड़क परिवहन	21,519	8.99%

सारणीकरण श्रेणी	विवरण	उद्यमों की संख्या	कुल में % की हिस्सेदारी
I3	गैर-मशीनीकृत परिवहन, जल परिवहन और अन्य संबंधित गतिविधियाँ	26,065	10.89%
I4	संचार	44,054	18.4%
J1	बीमा और पेंशन फंडिंग को छोड़कर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान	1,035	0.43%
J2	बीमा और पेंशन फंडिंग और सहायक गतिविधियां	1,923	0.8%
K	अचल संपत्ति, किराए पर लेना एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ	2,958	17.23%
M	शिक्षा	41,246	5.69%
N	स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य	20,035	8.37%
O	अन्य समुदाय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियाँ	39,696	16.57%

स्रोत: दिल्ली में सेवा क्षेत्र के उद्यमों पर रिपोर्ट, एनएसएस *63*वां दौर, जुलाई *2006 -* जून *2007*

6.5 अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यम और रोजगार

6.5.1 अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम

एनसीआर स्तर पर, 2005 में 15.64 लाख उद्यम थे। कुल 8.30 लाख स्वयं के खाता उद्यम (ओएई) हैं, जिनमें से 0.58 लाख कृषि क्षेत्र में हैं और शेष 7.72 लाख गैर-कृषि क्षेत्रों में हैं।

उप-क्षेत्र स्तर पर, एनसीटी-दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों (7.58 लाख) की उच्चतम एकाग्रता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (3.96 लाख), हरियाणा (3.21 लाख) और राजस्थान उप-क्षेत्र का (0.89 लाख) हैं। क्षेत्र स्तर के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में, कुल उद्यमों का लगभग 99.47% (7,54,453) गैर-कृषि गतिविधियों में है, जबकि यह अनुपात 88.43% (3,50,200), 94.87% (3,04,660) है। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान उप-क्षेत्रों में क्रमशः 90.42% (80,952) हैं।

जिला स्तर पर, एनसीटी-दिल्ली के बाद, मेरठ जिले में उद्यमों की अधिकतम (1.19 लाख) संख्या है, इसके बाद गाजियाबाद जिले में (1.18 लाख) हैं। हरियाणा उप-क्षेत्र के झज्जर जिले में उद्यमों की संख्या सबसे कम (24,469) है। गौतमबुद्ध नगर जिले में भी कृषि क्षेत्र में ओएई की संख्या सबसे अधिक है (तालिका 6.5 देखें)।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एनसीआर में 2005 में उद्यमों की संख्या का विवरण क्रमशः अनुबंध-6.1 और अनुबंध-6.2 में दिया गया है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

तालिका 6-5: एनसीआर-2005 में प्रकार के अनुसार उद्यमों की संख्या

	कृषि			गैर-कृषि			सभी		
जिला	ओएई*	संस्थान*	कुल	ओएई*	संस्थान*	कुल	ओएई*	संस्थान*	कुल
मेरठ	19,080	4,562	23,642	62,171	33,576	95,747	81,251	38,138	1,1,9389
बागपत	7,535	1,410	8,945	23,748	7,841	31,589	31,283	9,251	40,534
गाज़ियाबाद	2,138	888	3,026	72,819	42,369	1,15,188	74,957	43,257	1,18,214
	कृषि			**गैर-कृषि**			**सभी**		
जिला	ओएई*	संस्थान*	कुल	ओएई*	संस्थान*	कुल	ओएई*	संस्थान*	कुल
गौतम बौद्ध नगर	4,035	267	4,302	27,572	15,590	43,162	31,607	15,857	47,464
बुलंदशहर	4,404	1,507	5,911	48,920	15,594	64,514	53,324	17,101	70,425
यूपी उप-क्षेत्र	**37,192**	**8,634**	**45,826**	**2,35,230**	**1,14,970**	**3,50,200**	**2,72,422**	**1,23,604**	**3,96,026**
पानीपत	699	378	1,077	26,393	15,280	41,673	27,092	15,658	42,750
सोनीपत	1,311	527	1,838	24,729	12,263	36,992	26,040	12,790	38,830
रोहतक	3,120	569	3,689	26,037	10,209	36,246	29,157	10,778	39,935
झज्जर	643	188	831	16,519	7,119	23,638	17,162	7,307	24,469
रेवाड़ी	1,371	257	1,628	16,383	10,774	27,157	17,754	11,031	28,785
गुडगाँव	3,583	597	4,180	35,853	26,079	61,932	39,436	26,676	66,112
फरीदाबाद	1,606	1,608	3,214	34,512	42,510	77,022	36,118	44,118	80,236
हरियाणा उप-क्षेत्र	**12,333**	**4,124**	**16,457**	**1,80,426**	**1,24,234**	**3,04,660**	**1,92,759**	**1,28,358**	**3,21,117**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**1,187**	**2,103**	**3,290**	**3,12,479**	**4,41,974**	**7,54,453**	**3,13,666**	**4,44,077**	**7,57,743**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**7,029**	**1,545**	**8,574**	**44,455**	**36,497**	**80,952**	**51,484**	**38,042**	**89,526**
एनसीआर	**57,741**	**16,406**	**74,147**	**7,72,590**	**7,17,675**	**14,90,265**	**8,30,331**	**7,34,081**	**15,64,412**

स्रोत: आर्थिक जनगणना *2005* (हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश)

*स्वयं का खाता निर्माण उद्यम (ओएएमई): एक उद्यम, जो नियमित रूप से नियोजित किसी भी काम पर रखे गए कर्मचारी के बिना चलाया जाता है, को स्वयं का खाता उद्यम कहा जाता है। यदि ऐसा कोई उद्यम विनिर्माण और/या मरम्मत गतिविधियों में लगा हुआ है, तो इसे ओन अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज (ओएएमई) कहा जाता है।

संस्थान : एक उद्यम को संस्थान तब कहा जा सकता है जब कम से कम एक कर्मचारी को नियमित रूप से काम पर रखा जाता है। एक उद्यम में भुगतान किए गए घरेलू सदस्य/नौकर/निवासी कर्मचारी को किराए पर लिया गया श्रमिक माना जाता है। संस्थानों को आगे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: गैर-निर्देशिका और निर्देशिका।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

6.5.2 अनौपचारिक क्षेत्र का रोजगार

एनसीआर स्तर पर 58.75 लाख कर्मचारी अनौपचारिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। घरेलू इकाइयों (स्वयं खाता उद्यमों) में कुल 10.70 लाख श्रमिक लगे हुए हैं, जिनमें से 1.20 लाख कृषि क्षेत्र में हैं और शेष 9.50 लाख गैर-कृषि क्षेत्रों में हैं।

उप-क्षेत्र स्तर पर, एनसीटी-दिल्ली में श्रमिकों की उच्चतम सांद्रता (35.56 लाख) है, इसके बाद हरियाणा (10.63 लाख), उत्तर प्रदेश (10.39 लाख) और राजस्थान (2.16 लाख) उप-क्षेत्र हैं। सेक्टर स्तर के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में, लगभग 99.66% (35,44,125) श्रमिक गैर-कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं, जबकि यह अनुपात हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों में क्रमशः 96.61% (10,27,044), 89.53% (9,30,442) और 92.79% (2,00296) है।

जिला स्तर पर, एनसीटी-दिल्ली के बाद, गौतमबुद्ध नगर जिले में अधिकतम (3 लाख से अधिक) श्रमिक हैं, इसके बाद फरीदाबाद जिले (2.76 लाख) और गाजियाबाद जिले (2.58 लाख) हैं। हरियाणा उप-क्षेत्र के रेवाड़ी जिले में सबसे कम श्रमिकों की संख्या 78,166 है। गौतमबुद्ध नगर जिले में भी कृषि क्षेत्र में ओएई की संख्या सबसे अधिक है।

कृषि क्षेत्र में ओएई में एनसीटी-दिल्ली में श्रमिकों की संख्या सबसे कम (2551) है। एनसीटी-दिल्ली में उनके उद्यमों में अधिकतम संख्या में किराए के व्यक्ति हैं (तालिका 6.6 देखें)।

2005 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एनसीआर में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों की संख्या का विवरण क्रमशः अनुबंध-6.3 और अनुलग्नक-6.4 में दिया गया है और आमतौर पर विभिन्न प्रकार के उद्यमों में काम करने वाले व्यक्तियों के हिस्से का विवरण अनुबंध-6.5 में दिया गया है।

तालिका 6-6: कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में रोजगार

जिला/उप-क्षेत्र	आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या								
	कृषि			गैर-कृषि			सभी		
	ओएई*	संस्थान*	कुल	ओएई*	संस्थान*	कुल	ओएई*	संस्थान*	कुल
मेरठ	43,046	14,152	57,198	80,947	1,19,815	2,00,762	1,23,993	1,33,967	2,57,960
बागपत	13,886	3,778	17,664	31,026	36,571	67,597	44,912	40,349	85,261
गाज़ियाबाद	3,084	2,431	5,515	87,309	1,65,277	2,52,586	90,393	1,67,708	2,58,101
गौतम बौद्ध नगर	10,958	1,140	12,098	35,889	2,58,591	2,94,480	46,847	2,59,731	3,06,578
बुलंदशहर	11,444	4,790	16,234	69,507	45,510	1,15,017	80,951	50,300	1,31,251
उत्तर प्रदेश कुल	**82,418**	**26,291**	**1,08,709**	**3,04,678**	**6,25,764**	**9,30,442**	**3,87,096**	**6,52,055**	**1,03,9151**
पानीपत	1,127	1,743	2,870	30,807	1,00,632	1,31,439	31,934	1,02,375	1,34,309
सोनीपत	2,431	2,175	4,606	28,797	98,125	1,26,922	31,228	1,00,300	1,31,528
रोहतक	4,964	1,713	6,677	30,280	55,981	86,261	35,244	57,694	92,938
झज्जर	1,608	771	2,379	19,187	71,403	90,590	20,795	72,174	92,969
रेवाड़ी	2,544	954	3,498	18,853	55,815	74,668	21,397	56,769	78,166
गुड़गाँव	7,007	2,184	9,191	43,441	2,04,672	2,48,113	50,448	2,06,856	2,57,304
फरीदाबाद	3,204	3,982	7,186	40,217	2,28,834	2,69,051	43,421	2,32,816	2,76,237

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

हरियाणा	22,885	13,522	36,407	2,11,582	8,15,462	10,27,044	2,34,467	8,28,984	10,63,451
दिल्ली एनसीटी	2,551	9,711	12,262	3,79,259	31,64,866	35,44,125	3,81,810	31,74,577	35,56,387
राजस्थान	12,292	3,267	15,559	54,848	1,45,448	2,00,296	67,140	1,48,715	2,15,855
एनसीआर	1,20,146	52,791	1,72,937	9,50,363	47,51,540	57,01,907	10,70,513	48,04,331	58,74,844

स्रोत: आर्थिक जनगणना *2005* (हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश)

वहां, एनसीआर के विभिन्न शहरों में अनौपचारिक गतिविधियां और उद्यम मौजूद हैं, जो हजारों प्रवासियों को स्वरोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान करते हुए तुलनात्मक रूप से सस्ती वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं।

मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और दिल्ली में सबसे अधिक कलात्मक कार्य हैं। चमड़े के जूते-उत्पाद, उपकरण, हाथ से बने आसन और कालीन, जरी का काम, हाथ से मुद्रित कपड़ा, और सीसा-आधारित सामान इन क्षेत्रों में प्रचलित कुछ सामान्य कारीगरी के काम हैं। मेरठ और गाजियाबाद दोनों में 10 कारीगर समूह हैं और दिल्ली और बुलंदशहर में 9 कारीगर समूह हैं।

झज्जर में केवल एक ऐसा समूह है जो घास, ईख और रेशे का है। जबकि झज्जर के ठीक आगे पलवल और फरीदाबाद में घास, पत्ती और ईख, पत्थर की जड़ाई और लकड़ी की जड़ाई और धातु के काम के दो समूह हैं।

रोहतक और रेवाड़ी में चार-चार कारीगर समूह हैं। रोहतक में धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तन हैं; पत्थर जड़ना और लकड़ी जड़ना कार्य प्रचलित हैं। इसका श्रेय रेवाड़ी में कपड़ा, हाथ की कढ़ाई, गहने, चमड़े के जूते और लकड़ी के जड़े कार्यों की पहले से मौजूद गतिविधियों को दिया जा सकता है।
कुछ काम ऐसे हैं, जो कुछ ही जगहों पर मौजूद हैं जैसे कि मेटल ज्वेलरी क्लस्टर केवल मेरठ में मौजूद है, कारपेट क्लस्टर केवल पानीपत में, दिल्ली में नकली ज्वेलरी और गाजियाबाद में हाथ से कपड़े की छपाई का काम चल रहा है।

6.6 निष्कर्ष

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक अस्थिर और तुलनात्मक रूप से कम आय अर्जित करते हैं, और बुनियादी सुरक्षा और सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं होती है। अनौपचारिक व्यवसायों में भी वृद्धि की संभावना का अभाव होता है, जिससे कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए नौकरशाही की नौकरियों में फंस जाते हैं। दूसरी ओर, अनौपचारिक क्षेत्र आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है और उन्हें अत्यधिक गरीबी से बचाता है। अनौपचारिक क्षेत्र को आवश्यक समर्थन और बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त नीति तैयार और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

7. नीति ढांचा

7.1 पृष्ठभूमि

भौतिक और वित्तीय चुनौतियों पर विचार करने के बाद, एनसीआर में आर्थिक गतिविधि की बदलती गतिशीलता को पहचानने की आवश्यकता है। एनसीआर में निवेश और प्रौद्योगिकी प्रवाह और औद्योगिक विकास की निगरानी की सुविधा के लिए आर्थिक गतिविधियों के विनियमन और प्रशासन के रूप में एक बड़ा बदलाव आया है। संवैधानिक राज्य सरकारों ने निम्नलिखित मूल उद्देश्य के साथ विभिन्न मात्रा के साथ काम किया है:

(i) विकास की जरूरतों और राज्यों और क्षेत्रीय उद्देश्यों के अनुरूप औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति और रणनीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन

(ii) औद्योगिक विकास की निगरानी

(iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति और संवर्धन

(iv) उद्यम स्तर पर विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहन और उसी के लिए नीति मानदंड तैयार करना

(v) संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना

(vi) उत्पादकता, गुणवत्ता और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना

7.2 भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम

7.2.1 मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया निवेश की सुविधा के लिए *2014* में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नया औद्योगिक आर्थिक विकास अभियान है*;* नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास को बढ़ाना, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, अधिक निजी निवेश लाना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। अभियान शून्य दोष शून्य प्रभाव के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ काम करने का प्रयास करता है जिसका अर्थ है कि भारत में विकसित और निर्मित उत्पाद दोषों से मुक्त हैं और पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। यह पहल अर्थव्यवस्था के *25* प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है*;* इनमें से कुछ क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जैव-प्रौद्योगिकी, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, विमानन, रक्षा आदि शामिल हैं।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) भारत में व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए जटिलता को कम करने और गति और पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए नए डी-लाइसेंसिंग और डीरेग्यूलेशन उपाय।

(ii) कनेक्टिविटी, नए युवा-केंद्रित कार्यक्रम और विशेष कौशल विकसित करने के लिए समर्पित संस्थानों का चिन्हित औद्योगिक गलियारों में विकसित किए जा रहे नए स्मार्ट शहरों और औद्योगिक क्लस्टरों की स्थापना द्वारा विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और नवाचार की क्षमता में वृद्धि करना।

(iii) उच्च मूल्य वाले औद्योगिक क्षेत्रों - रक्षा, निर्माण और रेलवे में वैश्विक भागीदारी के लिए 49% तक एफडीआई की अनुमति जैसे निवेश कैप और नियंत्रण को आसान बनाना।

(iv) रक्षा, वृक्षारोपण, बैंकिंग, फार्मा आदि के अलावा अन्य क्षेत्रों में ऑटो मार्ग के तहत 15 क्षेत्रों में एफडीआई

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मानदंडों को आसान बनाना।

(v) संयंत्र और मशीनरी में 1 अरब रुपये से अधिक का निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनियों को 15 प्रतिशत की दर से निवेश भत्ता (अतिरिक्त मूल्यह्रास)।

(vi) शुल्क वापसी, शुल्क छूट/माफ़ी योजनाओं, फोकस उत्पादों और बाजार योजनाओं के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) आदि में इकाइयों को प्रोत्साहन आदि।

(vii) केंद्र सरकार के अनेक अन्य प्रोत्साहन।

(viii) राज्य सरकार के प्रोत्साहन जैसे भूमि अधिग्रहण के लिए स्टांप शुल्क में छूट, वापसी या मूल्य वर्धित कर की छूट, बिजली शुल्क के भुगतान से छूट आदि।

परियोजनाएं

(i) औद्योगीकरण और नियोजित शहरीकरण को गति प्रदान करने के लिए 2014-2015 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार द्वारा पांच औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं की पहचान, योजना और शुभारंभ किया गया है। इन गलियारों में से प्रत्येक में, विनिर्माण एक प्रमुख आर्थिक चालक होगा और इन परियोजनाओं को 2022 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 16% से 25% करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

(ii) इन गलियारों के साथ-साथ, 2014-2015 के केंद्रीय बजट में 100 स्मार्ट शहरों के विकास की भी परिकल्पना की गई है। इन शहरों को नए कार्यबल को एकीकृत करने के लिए विकसित किया जा रहा है जो औद्योगिक कॉरिडोर के साथ बिजली उत्पादन करेगा और भारत के शहरी आवास परिदृश्य को कम करेगा।

(iii) सभी औद्योगिक कॉरिडोर के विकास को मिलाने और एकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्राधिकरण (एनआईसीडीए) की स्थापना की जा रही है।

7.2.2 स्किल इंडिया

स्किल इंडिया *2015* में शुरू की गई भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य *2022* तक *40* करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करना है। इन पहलों में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति *2015*, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) स्कीम और कौशल ऋण योजना शामिल हैं। कार्यक्रम के तहत, *31* संभावित क्षेत्रों का चयन किया जाता है, जिसमें व्यक्तियों को स्तर *1* से *8* श्रेणी में *1507* योग्यता पैक (क्यूपी) में प्रशिक्षित किया जाएगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्षेत्र विशिष्ट कौशल परिषदों का गठन किया जाता है और सैकड़ों प्रशिक्षण प्रदाताओं को सूचीबद्ध करके अखिल भारतीय स्तर पर कौशल विकास गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

(a) राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन देश में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों में एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करेगा।

मिशन में त्रि-स्तरीय, उच्च शक्ति वाली निर्णय लेने की संरचना है। इसके शीर्ष पर, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मिशन की शासी परिषद, समग्र मार्गदर्शन और नीति निर्देश प्रदान करेगी। कौशल विकास मंत्री की अध्यक्षता में

संचालन

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

समिति, संचालन परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करेगी। मिशन निदेशालय, कौशल विकास सचिव के साथ मिशन निदेशक के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकारों में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन, समन्वय और अभिसरण को सुनिश्चित करेगा। मिशन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुनिंदा उप-मिशन भी चलाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और प्रशिक्षण निदेशालय मिशन के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है, जो सभी तीन निर्णयों के स्तर के साथ समन्वय करता है और सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है।

(b) कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015

नीति का उद्देश्य देश के भीतर की जा रही सभी कौशल गतिविधियों को एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है, उन्हें सामान्य मानकों के अनुरूप बनाना और कौशल को मांग केंद्रों से जोड़ना है। उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों को निर्धारित करने के अलावा, विभिन्न संस्थागत ढांचे की पहचान करने का प्रयास किया जाता है जो अपेक्षित परिणामों तक पहुंचने के लिए वाहन के रूप में कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रीय नीति इस बात पर भी स्पष्टता और सामंजस्य प्रदान करती है कि देश भर में कौशल विकास के प्रयासों को मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं के भीतर कैसे जोड़ा जा सकता है। यह नीति कौशल विकास को बेहतर रोजगार योग्यता और उत्पादकता से जोड़ेगी।

(c) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

इस योजना का उद्देश्य अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके युवाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, जैसे - 'स्वच्छ भारत', 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'राष्ट्रीय सौर मिशन' आदि की मांग के अनुरूप होगा। उद्योग संचालित निकायों, अर्थात् सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) द्वारा तैयार मानकों (राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक - एनओएस और योग्यता पैक - विशिष्ट नौकरी भूमिकाओं के लिए क्यूपी) के खिलाफ प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य लगभग 1,500 करोड़ रुपये की कुल लागत से 24 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाना है।.

7.2.3 डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) द्वारा की गई है और इसे 2019 तक कई चरणों में लागू किया जाएगा। यह सरकारी विभागों और भारत के लोगों को एकीकृत करने की एक पहल है। इसका उद्देश्य कागजी कार्रवाई को कम करके नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना भी शामिल है। डिजिटल इंडिया के तीन मुख्य घटक हैं। इसमे शामिल है:

(i) डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण
(ii) सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना
(iii) डिजिटल साक्षरता।

7.3 एनसीआर और उप-क्षेत्रीय योजनाओं के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का नीतिगत ढांचा

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 आर्थिक परिदृश्य, परिवहन, दूरसंचार, बिजली, पानी, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, विरासत और पर्यटन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय भूमि उपयोग, आदि के परस्पर संबंधित क्षेत्रों का एक नीति दस्तावेज है। आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जो एक बंदोबस्त के विकास को नियंत्रित / चैनलाइज करता है।

एनसीआर भाग लेने वाली राज्य सरकारों को क्षेत्रीय योजना के व्यापक नीतिगत ढांचे के भीतर अपने संबंधित उप-क्षेत्रों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है। 2005 में एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2001 की अधिसूचना के बाद, भाग लेने वाली राज्य सरकारों ने अपनी संबंधित उप-क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार/अंतिम रूप दिया है। एनसीटी-दिल्ली के मामले में, बोर्ड ने निर्णय लिया कि दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान को उप-क्षेत्रीय योजना के रूप में माना जाए।

क्षेत्रीय योजना और उप-क्षेत्रीय योजनाओं की नीतियों और प्रस्तावों का विवरण अगले भाग में दिया गया है।

7.3.1 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021

क्षेत्रीय योजना-2021 में "भाग लेने वाले राज्यों के प्रभावी सहयोग के साथ एनसीआर के सामंजस्यपूर्ण, संतुलित और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अनुपात-आर्थिक विकास के लिए दिल्ली द्वारा उत्पन्न विकासात्मक आवेग और समूह अर्थव्यवस्थाओं के प्रसार का उपयोग करने" का प्रस्ताव है।

(a) क्षेत्रीय योजना-2021 के उद्देश्य

क्षेत्रीय योजना-2021 का उद्देश्य "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देना" के माध्यम से है:

(i) एनसीटी-दिल्ली के आर्थिक विकास आवेग को अवशोषित करने में सक्षम क्षेत्रीय बस्तियों की पहचान और विकास द्वारा भविष्य के विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार प्रदान करना।

(ii) ऐसी चिन्हित बस्तियों में संतुलित क्षेत्रीय विकास का मदद करने के लिए भूमि उपयोग पैटर्न के साथ अच्छी तरह से एकीकृत कुशल और आर्थिक रेल और सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (बड़े पैमाने पर परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करना।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया में होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।

(iv) शहरी ढांचागत सुविधाओं जैसे परिवहन, बिजली, संचार, पेयजल, सीवरेज, जल निकासी आदि के साथ एनसीटी-दिल्ली की तुलना में चयनित शहरी बस्तियों का विकास करना।

(v) अच्छी कृषि भूमि की रक्षा और संरक्षण और शहरी उपयोग के लिए अनुत्पादक भूमि का उपयोग करने के लिए तर्कसंगत भूमि उपयोग पैटर्न प्रदान करना।

(vi) जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना।

(vii) संसाधन जुटाने के मौजूदा तरीकों की दक्षता में सुधार करना और संसाधन जुटाने के नवीन तरीकों को अपनाना और निजी निवेश को वांछित दिशा में सुविधाजनक बनाना, आकर्षित करना और मार्गदर्शन करना।

(b) भविष्य के विकास के लिए नीति क्षेत्र

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय योजना-2021 ने चार नीति क्षेत्र प्रस्तावित किए हैं, अर्थात्- (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली, (ii) केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर), (iii) राजमार्ग कॉरिडोर क्षेत्र और (iv) शेष एनसीआर जिसके लिए निम्नलिखित विकास नीतियों की परिकल्पना की गई है (मानचित्र 7.1 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मानचित्र 7.1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नीति क्षेत्र

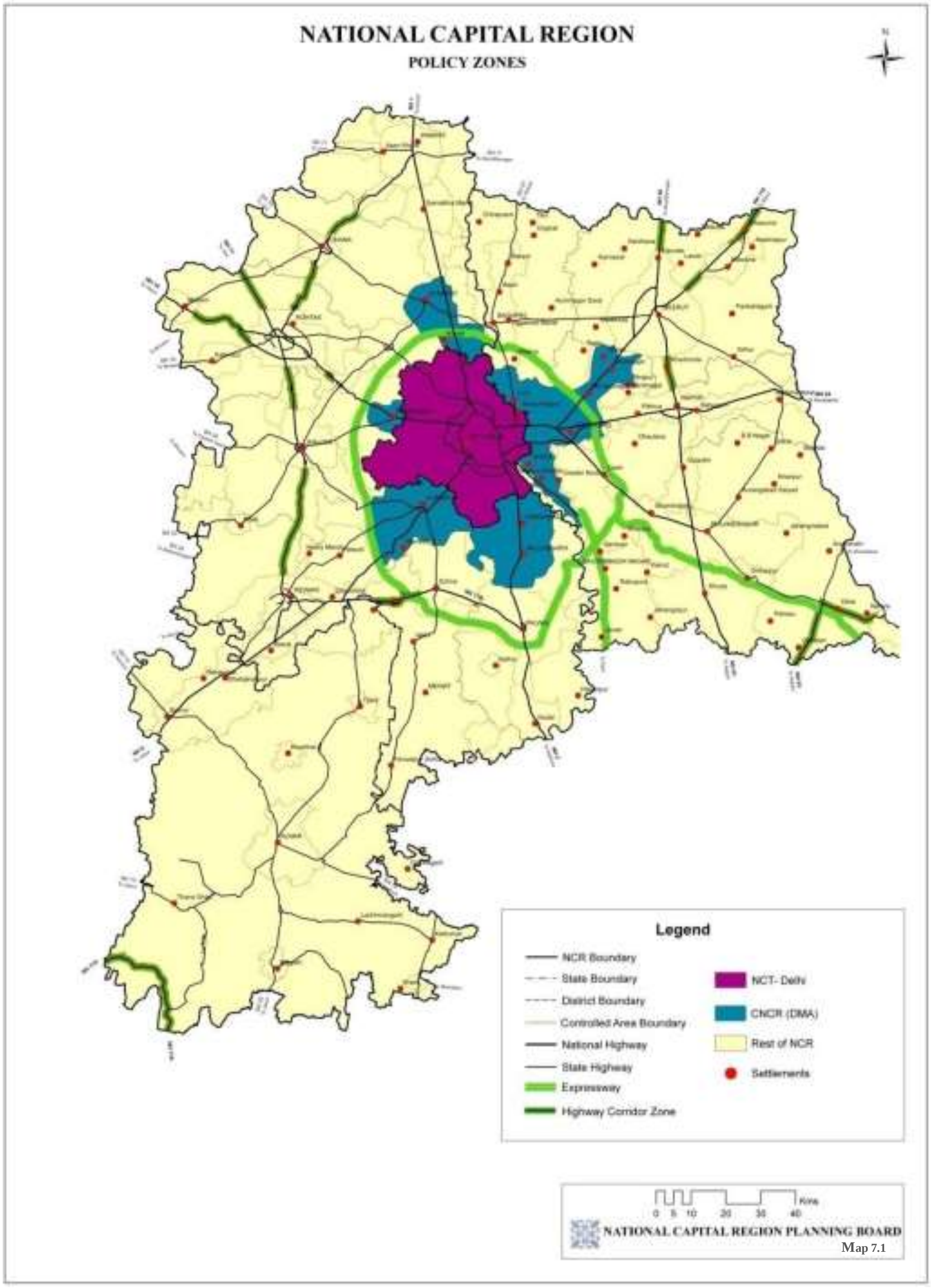

स्रोत: एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-*2021*

(i) एनसीटी दिल्ली

एनसीटी-दिल्ली के लिए बुनियादी नीति विकास योग्य भूमि और पानी की सीमा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय रूप से सतत विकास/पुनर्विकास हासिल करना है। इस क्षेत्र में कोई भी नई प्रमुख आर्थिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, जैसे उद्योग, थोक व्यापार और वाणिज्य, जिसके परिणामस्वरूप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो सकता है। केवल एनसीटी-दिल्ली की स्थानीय

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

ऊपर वाले चित्र का अनुवाद
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
नीति क्षेत्र
प्रमुख
एनसीआर सीमा
राज्य सीमा
जिला सीमा
नियंत्रित क्षेत्र की सीमा
राष्ट्रीय हाइवे
राज्य राजमार्ग
एक्सप्रेसवे
राजमार्ग गलियारा क्षेत्र
एनसीटी दिल्ली
एनसीआर (डीएमए)
बाकी एनसीआर
बस्तियां
राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड
मानचित्र 7.1

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

आबादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ii) केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर

सेंट्रल एनसीआर में गाजियाबाद-लोनी, नोएडा, गुड़गांव-मानेसर, फरीदाबाद-बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ और सोनीपत-कुंडली के निकटवर्ती शहरों के अधिसूचित नियंत्रित / विकास / विनियमित क्षेत्र और हरियाणा में रिज का विस्तार शामिल है।

सीएनसीआर द्वारा प्रस्तुत अवसरों को एनसीटी-दिल्ली के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए नौकरियों, आर्थिक गतिविधियों, व्यापक परिवहन प्रणाली, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे और पर्यावरण की गुणवत्ता के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली में स्थित सभी नई प्रमुख आर्थिक और गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियाँ इस क्षेत्र में नियोजित शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में और जहाँ उपयुक्त और आवश्यक हो, शेष एनसीआर में स्थित होनी चाहिए।

(iii) हाईवे कॉरिडोर जोन

मौजूदा नियंत्रित/विकास/विनियमित क्षेत्रों के बाहर इन राजमार्गों के साथ नियोजित और विनियमित विकास को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 1, 2, 8, 10, 24, 58 और 91 को दिल्ली में मिलाने के साथ राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) के दोनों ओर ग्रीन बफर सहित कम से कम 500 मीटर चौड़ा एक हाईवे कॉरिडोर जोन प्रस्तावित है। उपरोक्त के अलावा, एनएच 71, 71A, 71B, 119, 93, 235, 11A और एक्सप्रेसवे के साथ हाईवे कॉरिडोर जोन प्रस्तावित किए गए हैं।

हाईवे कॉरिडोर ज़ोन को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चित्रित और अधिसूचित किया जाएगा। हालांकि, इन क्षेत्रों की योजना बनाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र में अनुमति दी जा रही गतिविधियों को उचित हरित पट्टी, सर्विस रोड और राजमार्गों तक नियंत्रित पहुंच के माध्यम से राजमार्ग यातायात से अलग किया जाता है।.

(iv) शेष एनसीआर

शेष एनसीआर में, बुनियादी नीति शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के त्वरित विकास को सुगम बनाना है। इन क्षेत्रों में विकास को प्रेरित करने के लिए, विशेष रूप से पहचान की गई बस्तियों यानी मेट्रो केंद्रों और क्षेत्रीय केंद्रों में विकास को प्रेरित करने के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर (राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा) में बुनियादी ढांचे को पर्याप्त रूप से उन्नत किया जाना है। यह उन्हें आर्थिक और संबद्ध गतिविधियों का पता लगाने और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए और अधिक लुभावना बना देगा।

औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उप-क्षेत्रवार औद्योगिक नीतियों की चर्चा नीचे की गई है;

(c) एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियां और प्रस्ताव

एनसीआर के लिए आरपी-2021 ने आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से विकास की भविष्य की दिशाओं को दिशा देने के लिए निम्नलिखित नीतियों और प्रस्तावों का प्रस्ताव दिया है।

(i) यह देखा गया है कि एनसीआर के जीडीपी में मेवात का योगदान सबसे कम है और इसलिए इस जिले में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की जरूरत है।

(ii) एनसीआर में माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार कार्यबल के कौशल विकास के मुद्दों से बाधित

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

है। इसलिए, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान देने वाली नई परियोजनाओं की आवश्यकता है। इसे देखते हुए एनसीआर में भाग लेने वाले राज्यों को एनसीआर के सभी जिलों में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संस्थान खोलने के लिए पहल करने की आवश्यकता है।

(iii) एनसीआर में बैंकिंग सुविधाओं के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले भी ऐसे जिले हैं जहां बैंकिंग सुविधाओं की कमी है। हरियाणा उप क्षेत्र में मेवात और उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र में बुलंदशहर ऐसे दो जिले हैं, जहां अधिक वित्तीय समावेशन भारी अंतर ला सकता है। सॉफ्ट लोन और माइक्रो फाइनेंसिंग जैसी बैंकिंग सेवाओं का प्रावधान एनसीआर में आर्थिक आधार को और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, बशर्ते संभावित लाभार्थी इन सेवाओं से अवगत हों। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि बैंक प्रत्येक जिले में उपलब्ध सेवाओं के स्पेक्ट्रम के बारे में जागरूकता पैदा करें।

(iv) क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह अनुशंसा की जाती है कि एनसीआर में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एनसीआर में डीएमआईसी परियोजना के तहत प्रस्तावित निवेश क्षेत्र अर्थात् मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र (एमबीआईआर), खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (केबीएनआईआर) और दादरी-नोएडा- गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) और डीएफसी परियोजना विनिर्माण क्षेत्र दोनों को उत्पादन और रोजगार के मामले में बढ़ावा देंगे। ये परियोजनाएं विनिर्माण और सेवा आधार के विस्तार पर जोर देती हैं और कॉरिडोर के विस्तार को "वैश्विक विनिर्माण और व्यापार केंद्र" के रूप में विकसित करती हैं और इन्हें "मेक इन इंडिया" पहल के अनुरूप या उसके अनुरूप प्राथमिकता पर लागू करने की आवश्यकता है।

(v) एनसीआर के भीतर कनेक्टिविटी एनसीआर में आर्थिक गतिविधियों के आकार और प्रकृति दोनों में बदलाव के लिए प्रेरक शक्ति रही है। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना में पूरे क्षेत्र में विकास की संभावनाओं और आय में सुधार करने की क्षमता है, खासकर सीएनसीआर के बाहर के शहरों में। इसलिए, आरआरटीएस, कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे आदि जैसे क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन में तेजी लाने का प्रस्ताव है, जो एनसीआर में आर्थिक केंद्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

(vi) यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों में कृषि का प्रभुत्व है, इसलिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, हरियाणा उप-क्षेत्र में उद्योग और सेवा क्षेत्र का मिश्रण है। हरियाणा उप-क्षेत्र में गुड़गांव जिले ने आईटी और आईटीईएस के तेजी से विकास के कारण प्रति व्यक्ति आय के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। हरियाणा उप-क्षेत्र में पानीपत जिला भी तेजी से एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसे जिलों या क्षेत्रों में आवश्यक औद्योगिक बुनियादी ढांचे और सहायता सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए।

(vii) एनसीआर में महत्वपूर्ण संख्या में एमएसएमई क्लस्टर हैं। विशेष रूप से कपड़ा, ऑटो कॉम्पोनेन्ट, सामान्य इंजीनियरिंग, खेल के सामान आदि में इन समूहों के कुशल विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए एनसीआर भाग लेने वाले राज्यों द्वारा एक एकीकृत क्लस्टर विकास दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है। साथ ही, सभी एमएसएमई समूहों में अनौपचारिक कार्यबल के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की पहुंच होनी चाहिए।

(viii) यह देखा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी और ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों का एनसीआर के कारोबारी माहौल पर एक निश्चित प्रभाव पड़ेगा। यह अनुशंसा की जाती है कि उच्च कुशल

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

कार्यबल के लिए विशेष रूप से एकीकृत नीति के हिस्से के रूप में नैनो तकनीक का लाभ उठाने के लिए अनुरूप बुनियादी ढाँचा बनाया जाए। उत्पाद नवाचारों के लिए प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की मांग में और वृद्धि होगी। इसे देखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि एनसीआर भाग लेने वाले राज्यों द्वारा उत्पाद नवाचार चक्रों की छोटी अवधि के साथ तालमेल रखते हुए एक मजबूत अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सहायता प्रदान की जाए।

(ix) भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरुरत होती है। जहां भी संभव हो, सभी प्रकार के उद्योगों में सौर ऊर्जा बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में होनी चाहिए।

(x) प्रदूषण को कम करने के लिए भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों द्वारा अपने-अपने औद्योगिक क्षेत्रों में वायु, जल और भूमि संबंधी प्रदूषण के मुद्दों को बताने की जरुरत है।

(xi) पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए, भाग लेने वाले एनसीआर राज्य अपने संबंधित उप-क्षेत्र में पारंपरिक शिल्प समूहों में आवश्यक बुनियादी ढांचे और वातावरण का निर्माण कर सकते हैं।

(xii) जीडीपी और पीसीआई जैसे मापदंडों के जिला स्तर के साथ-साथ एनसीआर स्तर के विश्लेषण करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि भाग लेने वाले एनसीआर राज्य हर साल जारी दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य और जिला स्तर के जीडीपी और पीसीआई डेटा सीएसओ (राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी) द्वारा प्रकाशित करें। इस डेटा के विश्लेषण से साल दर साल आधार पर एनसीआर और उसके उप-क्षेत्रों के आर्थिक विकास और प्रदर्शन के स्तर को मापने में मदद मिलेगी।

7.3.2 उप-क्षेत्रीय योजनाएं

(a) हरियाणा उप-क्षेत्र-2021 के लिए उप-क्षेत्रीय योजना की नीतियां और प्रस्ताव:

अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण, औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास बफर जोन स्थापित करने, उपयुक्त स्थानों पर वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं प्रदान करने और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सर्विस हाउसिंग जैसे पहलुओं के लिए काम शुरू करने से पहले विशेष पहल की जानी चाहिए।

(i) उप-क्षेत्र के भीतर और साथ ही बाहर मांग को पूरा करने के लिए अनाज, दूध, सब्जियां, फल आदि जैसे कृषि / डेयरी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

(ii) ऐसे उत्पादों के प्रति राष्ट्रीय राजधानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जैविक उच्च मूल्य कृषि के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(iii) फूलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि उप-क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और रोहतक में प्रस्तावित कार्गो हवाई अड्डे के करीब है।

(iv) औद्योगिक संपदा स्थान विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि एचएसआईआईडीसी द्वारा सभी मौजूदा और प्रस्तावित औद्योगिक विकास मुख्य रूप से एनएच-44, एनएच-48 और प्रस्तावित केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए रोहतक और झज्जर, मेवात और पलवल जिलों के पश्चिमी भाग में औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाना है। अन्य जिलों की तुलना में इन जिलों में औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त भूमि के बड़े हिस्से की उपलब्धता भी एक सकारात्मक कारक है।

(v) एक क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए, पानीपत में औद्योगिक विकास की संभावना को रोहतक में चैनलाइज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि इस जिले की पानीपत के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है और इसमें उपयुक्त औद्योगिक भूमि है। अतिरिक्त औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए रोहतक में औद्योगिक बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

(vi) रेवाड़ी और मेवात जिलों में औद्योगिक विकास को सुगम बनाया जाना चाहिए।

(vii) माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार कौशल के मुद्दों से बाधित है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की शुरुआत के साथ, एमबीआईआर प्रस्तावों के माध्यम से रेवाड़ी जिले में औद्योगिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। एमबीआईआर द्वारा सृजित उभरती औद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए झज्जर जिले के विकास पर संतुलित क्षेत्रीय विकास पर विचार किया जा सकता है।

(viii) कर्मचारी के विकास के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान देने वाली नई परियोजनाओं की जरुरत है।

(ix) हरियाणा उप-क्षेत्र और एनसीआर के भीतर कनेक्टिविटी आर्थिक गतिविधियों के आकार और प्रकृति दोनों में परिवर्तन के लिए प्रेरक शक्ति रही है। उप-क्षेत्र और एनसीआर के भीतर प्रस्तावित आरआरटीएस और एमआरटीएस परियोजनाओं में पूरे उप-क्षेत्र में विकास की संभावनाओं और आय में सुधार करने की क्षमता है, विशेष रूप से उन शहरों में जो सीएनसीआर का हिस्सा नहीं हैं।

(x) उप-क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले भी ऐसे जिले हैं जहां बैंकिंग सुविधाएं या तो उपलब्ध नहीं हैं या नहीं ली गई हैं। सॉफ्ट लोन और माइक्रो फाइनेंसिंग जैसी बैंकिंग सेवाओं का प्रावधान इस क्षेत्र के आर्थिक आधार को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए बैंकिंग क्षेत्र को न केवल अपने नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए बल्कि मेवात जिले में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर देना चाहिए।

(xi) मेवात जिले में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा।

(xii) एनसीआर में प्रस्तावित डीएमआईसी परियोजना के तहत तीन निवेश क्षेत्रों में से एक हरियाणा उप-क्षेत्र अर्थात् मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र (एमबीआईआर) में है। RP-2021 के अनुसार, यह DFC परियोजना के साथ मिलकर उत्पादन और रोजगार दोनों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। इस प्रकार एमबीआईआर 2021 ई. तक 2.5 लाख तक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा।

(xiii) सभी शहरी केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम अनुशंसित भौतिक और सामाजिक सुविधाओं का प्रावधान आवश्यक है।

(xiv) लोगों को पूर्ण स्वच्छता और इसे प्राप्त करने के साधनों के बारे में जागरूक करने की निश्चित आवश्यकता है।

(xv) उप-क्षेत्र में दूरसंचार सुविधा में सुधार और स्मार्ट शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। ऐसे शहरों की योजना और विकास जो कार्य करने में सक्षम हैं और ऊर्जा और अन्य संसाधनों का संरक्षण करते हैं, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से प्रस्तावित विकास उच्च घनत्व और ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ होना चाहिए।

(xvi) राज्य और उप-क्षेत्र के सभी स्तरों में योजना विभागों में कर्मचारियों के मामले में संगठन की स्थापना में सुधार किया जाना चाहिए।

(xvii) पंचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप योजना बनाने/संशोधन/योजनाओं की समीक्षा करने की आवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए।

(xviii) कम विकसित क्षेत्रों को लाभ देने के लिए उप-क्षेत्र के विकसित क्षेत्रों के साथ एकीकृत, कम विकसित क्षेत्र के लिए विकास नीति बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(xix) उप-क्षेत्र में मेवात और पलवल जैसे निम्न मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) वाले अल्प विकसित क्षेत्र को विवेकपूर्ण ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए और इसे मौजूदा और प्रस्तावित विकास केंद्रों और आर्थिक केंद्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। क्षेत्रीय लिंकेज जो आरआरटीएस, डीएफसी, आदि के रूप में इंटर और इंट्रा हैं, इन दो जिलों के लिए प्रदान करने की जरूरत होगी।

(xx) गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में लक्षित निवेश में से कुछ को कम अनुकूल क्षेत्रों में बदलने की

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

आवश्यकता है, उदाहरण झज्जर और मेवात।

(b) उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र- 2021 के लिए उप-क्षेत्रीय योजना की नीतियां और प्रस्ताव

औद्योगिक विकास किसी क्षेत्र के आर्थिक स्वरूप को निर्धारित करने में उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक विकास विविध अर्थव्यवस्था और रोजगार उत्पन्न करता है।

(i) यूपी उप-क्षेत्र में, तीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण (अर्थात् नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे) और यूपीएसआईडीसी औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इसलिए इन अधिकारियों को इस अधिदेश को पूरा करना चाहिए। इस अधिदेश को पूरा करने के लिए इन प्राधिकरणों को उप-क्षेत्र में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने चाहिए।

(ii) बागवानी कौशल विकास आदि के संबंध में भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों और निधियों का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

(iii) उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, श्रम सामंजस्यपूर्ण संबंधों के लिए अनुकूल नीतियां और कम लागत वाले श्रमिक आवास, स्वास्थ्य बीमा और कल्याण जैसी सुविधाओं को उद्योगों के प्रवेश और निकास के लिए संतुलित नीतियों के साथ जोड़ना चाहिए।

(iv) उप-क्षेत्र में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय समावेशन पर जोर दिया जाना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या को कम करने की रणनीति प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना के माध्यम से लागू की जानी चाहिए, जब वे सफल होंगे।

(c) दिल्ली के लिए मास्टर प्लान की नीतियां और प्रस्ताव-2021

औद्योगिक विकास:

(i) हाई-टेक और कम मात्रा में उच्च मूल्य वर्धित उद्योगों को बढ़ावा देना, जो श्रम प्रधान नहीं हैं।

(ii) शहर के लोगों की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों के लिए आवश्यक मौजूदा उद्योगों के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करना।

(iii) गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के संबंध में पर्यावरण और अन्य मानदंडों के अनुसार सुधारात्मक उपाय करना जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(iv) भूमि उपयोग मानदंडों के अनुरूप न होने वाली औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करना और स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और प्रोत्साहन, और अन्य उपाय प्रदान करना।

(v) प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों और पर्यावरणीय विचार, अग्नि सुरक्षा नियमों और अन्य प्रासंगिक कारकों, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे सेवाओं के पहलू के पालन के अधीन घरेलू औद्योगिक इकाइयों की अनुमति के दायरे की समीक्षा करना।

नए औद्योगिक क्षेत्र:

एनसीटी-दिल्ली के ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को मौजूदा उद्योगों के पुनर्वास के उद्देश्य से और निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सीमित प्रकार के नए उद्योगों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाई जानी चाहिए:

(i) अनुमत उद्योगों को गैर-अनुरूप समूहों से स्थानांतरित करना जो नियमितीकरण/विकास के लिए पात्र

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

नहीं हैं; तथा

(ii) हाई-टेक उद्योगों के लिए ग्रीन फील्ड साइट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नई औद्योगिक गतिविधियों को हाई-टेक क्षेत्रों तक सीमित किया जाना चाहिए जैसा कि नीचे दिया गया है:

i) कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उद्योग और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिस्टम इंटीग्रेशन करने वाले उद्योग।
ii) पैकेजिंग
iii) कंप्यूटर और दूरसंचार सुविधाओं के इंटरफेस को एकीकृत और हेरफेर करने वाले उद्योग।
iv) दुनिया भर में फैले डेटाबेस या डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करके उपयोग की जानकारी की जरूरतों को पूरा करने वाले उद्योग।
v) सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न या सभी कॉम्पोनेन्ट के परिष्कृत परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाले उद्योग।
vi) इलेक्ट्रॉनिक सामान।
vii) टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सर्विस और मरम्मत।
viii) फोटो कम्पोजिंग और डेस्कटॉप प्रकाशन।
ix) टीवी और वीडियो कार्यक्रम का निर्माण।
x) टेक्सटाइल डिजाइनिंग और फैब्रिक टेस्टिंग आदि।
xi) जैव प्रौद्योगिकी।
xii) दूरसंचार और सक्षम सेवाएं।
xiii) रत्न और आभूषण।

(d) राजस्थान उप-क्षेत्र-2021 के लिए उप-क्षेत्रीय योजना की नीतियां और प्रस्ताव:

(i) राजस्थान उप-क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। अर्थव्यवस्था का विविधीकरण और आधुनिकीकरण आगे कई कारकों पर निर्भर करता है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के संदर्भ में, उप-क्षेत्र भी एनसीआर में प्रमुख रोजगार और धन पैदा करने वाले उप-क्षेत्रों में से एक होगा। यह महत्वपूर्ण है कि संभावित रोजगार सृजन गतिविधियों को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास प्राप्त करने के लिए उप-क्षेत्र में तर्कसंगत रूप से वितरित किया जाए। अनुशंसित प्रमुख नीतियां और प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

(ii) उप क्षेत्र कृषि उत्पादों और खनिज संसाधनों में समृद्ध है जो कृषि आधारित उद्योगों, पशुधन, खनिज आधारित उद्योगों, मांग आधारित और इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास के लिए अच्छा अवसर प्रदान करते हैं।

(iii) उप-क्षेत्र में व्यावसायिक संरचना में बदलाव आया है। यह स्थानांतरण उनकी पारंपरिक कृषि गतिविधियों से अन्य गतिविधियों जैसे उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, निर्माण आदि की ओर है। इस प्रवृत्ति को धीरे-धीरे औद्योगिक गतिविधियों की गति प्राप्त करने के तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। औद्योगीकरण ने पहले ही कब्जा कर लिया है और उप-क्षेत्र में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जो आर्थिक विकास का नेतृत्व कर रहे हैं। रीको भविष्य में उद्योगों के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण भी कर रहा है। इस प्रकार, उप-क्षेत्र के आर्थिक विकास में औद्योगिक गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उप-क्षेत्र में रोजगार सृजन में माध्यमिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

(iv) द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार कार्यबल के कौशल विकास के मुद्दों से बाधित है। इसलिए, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान देने वाली नई परियोजनाओं की आवश्यकता है।.

(v) आर्थिक गतिविधियों के आकार और प्रकृति दोनों में परिवर्तन के लिए संयोजकता प्रेरक शक्ति रही है। आरआरटीएस परियोजना में उप-क्षेत्र में विकास, आय और रोजगार में सुधार की क्षमता है।

(vi) सॉफ्ट लोन और माइक्रो फाइनेंसिंग जैसी बैंकिंग सेवाओं का प्रावधान क्षेत्र के आर्थिक आधार को बेहतर बनाने में मदद करता है बशर्ते कि संभावित लाभार्थी इन सेवाओं से अवगत हों। इसलिए, बैंकिंग क्षेत्र को न केवल अपने नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए बल्कि उपलब्ध सेवाओं के स्पेक्ट्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर देना चाहिए

(vii) डीएफसी, डीएमआईसीडीसी, कॉनकॉर और आरआरटीएस की परियोजनाओं का भी उप-क्षेत्र के आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित डीएमआईसी के तहत निवेश क्षेत्र अर्थात् खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (केबीएनआईआर) और डीएफसी परियोजना में आय और रोजगार के मामले में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की क्षमता है। ये परियोजनाएं विनिर्माण और सेवाओं के आधार के विस्तार पर जोर देती हैं और कॉरिडोर को "वैश्विक विनिर्माण और व्यापार केंद्र" के रूप में विकसित करती हैं।

(viii) क्षेत्र के संतुलित आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित बंदोबस्त पदानुक्रम में परिकल्पित सुविधाओं के अनुसार उप-क्षेत्र में विभिन्न बस्तियों का विकास किया जाएगा।

(ix) उप-क्षेत्र प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत जैसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, अजबगढ़-भानगढ़, सिलिसर झील, पांडुपोल, बालाकिला, आदि से संपन्न है। इसलिए, पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले पर्यटन स्थल के रूप में इसके विकास की काफी संभावना है।

7.4 उप-क्षेत्रों में आर्थिक विकास और प्रमुख परियोजनाओं के लिए भाग लेने वाली राज्य सरकारों की एनसीआर की नीतियां

7.4.1 एनसीटी-दिल्ली

(a) दिल्ली औद्योगिक नीति 2010

दिल्ली की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को वर्ष 2021 तक स्वच्छ, उच्च-प्रौद्योगिकी और कुशल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, भीड़भाड़ को कम करने, 'वॉक टू वर्क' को बढ़ावा देने, व्यापार को सरल बनाने, उद्योग परामर्श के निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्णय लेने और स्थिरता में पालन किया जा रहा है। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) औद्योगिक प्रोफ़ाइल को निम्न-कुशल से उच्च तकनीक और उच्च-कुशल में बदलने के लिए नीतिगत बदलाव आवश्यक है। नीति छह-आयामी रणनीति पर जोर देती है:

- औद्योगिक सम्पत्तियों के बेहतर ओ एंड एम के माध्यम से अवसंरचना विकास।
- सरलीकरण और ई-सक्षम करने के उपायों द्वारा व्यवसाय को सुगम बनाना।
- अन्य के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में ज्ञान आधारित उद्योगों को अनुमति देने जैसे कौशल विकास और अन्य प्रचार उपायों का समर्थन करना।
- पुनर्विकास योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से नए औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च-प्रौद्योगिकी और कुशल उद्योगों के क्लस्टर विकास को बढ़ावा देना।
- उच्च अवसंरचना विकास शुल्क के माध्यम से प्रदूषणकारी उद्योगों को हतोत्साहित करना।

(ii) सरकार की भूमिका प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया और परामर्श तंत्र के साथ अच्छा बुनियादी ढांचा, निवेशक

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

अनुकूल वातावरण प्रदान करना होगा।

(iii) परिष्कृत उद्योगों को बढ़ावा देना जो कम जगह, बिजली, पानी आदि के साथ उत्पादन का इष्टतम स्तर प्राप्त कर सकें।

(iv) गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा करना।

(v) प्रदूषण न करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर।

(vi) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आई.टी, आई.टी को बढ़ावा देने पर जोर। निवेश सीमा के बावजूद सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक उद्योगों को सक्षम करना।

(vii) आवासीय क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों को छोड़कर किसी भी नई औद्योगिक इकाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(viii) दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रखरखाव के लिए एकल एकीकृत एजेंसी। औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव में क्षेत्र के औद्योगिक संघ की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ix) निम्न-तकनीकी उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च-तकनीकी उद्योगों में रीसायकल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खतरनाक/अप्रिय उद्योगों के साथ-साथ बड़े/भारी उद्योगों को दिल्ली में अनुमति नहीं दी जाएगी।

(x) आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप मध्यम क्षेत्र में स्नातक होने वाले लघु उद्योगों को तकनीकी उन्नयन की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि कोई पर्याप्त विस्तार न हो और जहां विकास एक ही लाइन या संबद्ध लाइन में हो, और जहां उद्योग एक अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा हो।

(b) सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2000

एनसीटी दिल्ली सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशाल क्षमता को पहचानते हुए 2000 में आईटी नीति पेश की। नीति का उद्देश्य रोजगार, उत्पादकता, दक्षता और आर्थिक विकास के बढ़े हुए कारकों के नए रास्ते तलाशना है। सरकार ने कल्पना की थी कि दिल्ली देश में एक प्रमुख साइबर राज्य के रूप में उभरेगी और इसके नागरिक ई-नागरिक होंगे। निम्नलिखित 6 ई आईटी नीति की आकांक्षाओं को नियंत्रित करते हैं:

(i) ई-गवर्नेंस: सरकार को अपने नागरिकों को सक्रिय और कुशल सेवाएं देने में सहायता करने के लिए ई-गवर्नेंस का उपकरण।

(ii) समानता: सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा में सुधार, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्यों को प्राप्त करना।

(iii) शिक्षा: स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में आईटी के उपयोग को प्रोत्साहित करना इस प्रकार उद्योग में कौशल उन्नयन, ज्ञान और नौकरी की संभावनाओं को सक्षम बनाता है।

(iv) रोजगार: नई डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना।

(v) उद्यमिता: इन्क्यूबेशन इंजन को बाहर निकालना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना और राज्य के आर्थिक विकास में इसके योगदान को बढ़ाना।

(vi) अर्थव्यवस्था: राज्य में आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रशिक्षण, आईटी सक्षम सेवाओं, दूरसंचार, ई-कॉमर्स और संबंधित क्षेत्रों में निवेश और विकास को प्रोत्साहित और तेज करना।

(c) औद्योगिक स्थान योजना 2006

एनसीटी-दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2006 में एक औद्योगिक पुनर्वास योजना तैयार की, जिसमें 27,905 इकाइयों को बवाना, झिलमिल, नरेला, बादली, परपड़गंज और विभिन्न फ्लैट कारखानों में औद्योगिक भूखंडों या फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र घोषित किया गया। जुलाई 2009 तक, लगभग 17,801 इकाइयों ने पूरा भुगतान किया और

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया, और 16,667 ने भौतिक कब्जा कर लिया। हालांकि, केवल लगभग 5,000 इकाइयों ने साइट पर वास्तविक निर्माण कार्य शुरू किया है।

इसके अलावा, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 ने पुनर्विकास के अधीन, नियमितीकरण के लिए 70% से अधिक औद्योगिक एकाग्रता वाले 20 गैर-अनुरूपता समूहों को अधिसूचित किया। घरेलू उद्योग आवासीय क्षेत्रों में काम करना जारी रख सकते हैं।

(c) शिल्प क्षेत्र संवर्धन नीति

हथकरघा: बुनकरों को तकनीकी मार्गदर्शन, बुनकर सहकारी समितियों को ऋण और अनुदान, बचत-निधि-सह-बचत सुरक्षा योजना और समूह बीमा योजना का प्रावधान।

हस्तशिल्पः शिक्षुता योजना, कालीन बुनाई एवं प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से विभिन्न शिल्पों में शिल्पकारों को प्रशिक्षण, विपणन सहायता का प्रावधान, मास्टर शिल्पकारों को राज्य पुरस्कार, हथकरघा और हस्तशिल्प के बाजारों में हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देना।

7.4.2 हरियाणा

(a) औद्योगिक नीति 2005

उद्देश्य:

(i) आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में उद्योग को फिर से स्थापित करना।
(ii) राज्य के निवासियों के लिए धन की व्यवस्था करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
(iii) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना।
(iv) विशेष रूप से राज्य के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक फैलाव को सुगम बनाना।
(v) अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करना

रणनीति:

राज्य सरकार मिशन मोड दृष्टिकोण में एक समन्वित विकास रणनीति पर जोर देकर नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित रणनीति इस प्रकार है:

(i) ढांचागत पहलों के माध्यम से आर्थिक केंद्रों का विकास करना।
(ii) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
(iii) सामान्य रूप से राज्य में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करने वाली आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
(iv) विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक स्पिन-ऑफ क्षमता वाली मेगा परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
(v) प्रमुख उद्यमों के सहक्रियात्मक विकास के लिए प्रोत्साहन और ढांचागत सहायता प्रदान करते हुए क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना।
(vi) सेवा क्षेत्र विशेष रूप से पर्यटन, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं का विकास करना।
(vii) छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास और सहायता पर ध्यान देना। निर्यात-प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

0 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को सक्षम बनाना।

(viii) प्रशासनिक प्रक्रिया में निवेशक-केंद्रित दृष्टिकोण बनाना और आधुनिक तकनीकी और प्रबंधन समाधानों का उपयोग करके दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

(ix) भविष्य की कर्मचारी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योग और तकनीकी संस्थानों के बीच रणनीतिक संबंध स्थापित करके मानव संसाधन विकास बनाना।

(b) औद्योगिक नीति 2010

नई औद्योगिक नीति 2010, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और संभावित विकास को ध्यान में रखते हुए, ज्ञान आधारित और उच्च तकनीक उद्योगों, ऊर्जा के कुशल उपयोग, संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास के लिए व्यावहारिक पर्यावरण नीतियों के अलावा विनिर्माण क्षेत्र के आधार को और मजबूत करने पर विशेष जोर देती है। इन नीतिगत उपायों के माध्यम से प्राथमिक उत्पादों में निवेश और मूल्यवर्धन की गुंजाइश और संभावना को स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है। सुनियोजित बुनियादी ढांचे का विकास समग्र भविष्य के आर्थिक विकास की कुंजी है और इस पर सरकार का ध्यान जारी है। राज्य सार्वजनिक-निजी-भागीदारी की बढ़ी हुई भूमिका को पहचानता है और तदनुसार, नीति इस दिशा में एक अच्छी तरह से परिभाषित रोडमैप तैयार करती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को अपनाने से सेवाओं के वितरण में दक्षता और पारदर्शिता आती है, प्रक्रियात्मक देरी समाप्त होती है और लेनदेन लागत कम से कम होती है। नीति अनुमोदन और मंजूरी के आईटी सक्षम शासन के लिए एक पूर्ण स्विच-ओवर के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करती है।

उद्देश्य::

संभावित क्षेत्रों में केंद्रित और संरचित तरीके से निवेश आकर्षित करके उच्च, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास;

(i) सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना;
(ii) कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन और बढ़ी हुई रोजगार क्षमता;
(iii) आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में विनिर्माण क्षेत्र पर निरंतर जोर देना;
(iv) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उद्यमशीलता के अवसरों का सृजन करना;
(v) विशेष रूप से राज्य के औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक फैलाव की सुविधा;
(vi) पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर सतत विकास करना।

रणनीति:

(i) गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाना और बुनियादी ढांचे के अंतराल के मुद्दों को संबोधित करना, विकासशील एजेंसियों द्वारा उद्यमियों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि बैंक का निर्माण करना और भूमि मालिकों की चिंताओं को दूर करना, जिससे ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के बीच पुनर्वास और पुनर्वास पहल और आवश्यक कौशल विकसित करके जमीन का अधिग्रहण किया जाता है;

(ii) विशेष रूप से औद्योगिक बुनियादी ढांचे, बिजली, सड़कों और पुलों, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा क्षेत्रों, नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण, स्व-प्रमाणन और सूचना और संचार के उपयोग में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। सेवाओं की परेशानी मुक्त, समय पर डिलीवरी और एस्टेट प्रबंधन प्रक्रियाओं और उदारीकरण के

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

लिए प्रौद्योगिकी (आईसीटी);

(iii) उद्योग और संयुक्त परामर्शी ढांचे के लिए शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से संस्थागत सहायता तंत्र को मजबूत करना;

(iv) गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता, अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को मजबूत करना

(v) नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन और बढ़ी हुई रोजगार क्षमता है। राज्य में छोटे उद्योगों की वृद्धि भी अभूतपूर्व रही है। इनकी संख्या 1966 में 4500 से बढ़कर 2010 में 80,000 हो गई है। वे 8.7 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करते हुए प्रति वर्ष 4500 करोड़ रुपये के सामान का उत्पादन कर रहे हैं।

राज्य निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा:

(i) कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उद्योग
(ii) ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स
(iii) शिक्षा और कौशल विकास
(iv) इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
(v) जूते और सहायक उपकरण
(vi) हैंडलूम, होजरी, टेक्सटाइल और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग
(vii) स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल
(viii) फार्मास्युटिकल उद्योग
(ix) अनुसंधान एवं विकास और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज
(x) परिवहन नेटवर्क और सेवाएं
(xi) अपशिष्ट प्रसंस्करण और री-साइकिलिंग उद्योग

(c) कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

हरियाणा मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य को ध्यान में रखते हुए कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए कई प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना से आवश्यक जुड़ाव उपलब्ध होगा और क्षेत्र को सब्जी की खेती में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी।

(d) एमएसएमई और क्लस्टर विकास दृष्टिकोण

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ हैं, सरकार इस क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संस्थागत सहायता तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। हरियाणा उन कुछ राज्यों में से एक है जिसने औद्योगिक विकास की रणनीतियों में से एक के रूप में 'क्लस्टर विकास' पर ध्यान केंद्रित किया है। उद्योग के साथ साझेदारी में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये केंद्र अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में एमएसएमई की आम जरूरतों जैसे; प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता, उत्पादों का मानकीकरण, गुणवत्ता परीक्षण और अंकन सुविधाएं, उत्पादों की ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के साथ विपणन पहल आदि प्रदान करेंगे।

(e) सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000

राज्य सरकार ने आईटी, आईसीटी और आईटीईएस को निर्यात, रोजगार और धन सृजन की अपनी क्षमता को

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मान्यता देने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में पहचाना है। आईटी नीति 2000 का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की पारंपरिक वितरण प्रणाली को आईटी संचालित शासन प्रणाली से बदलना था। इस नीति का उद्देश्य हरियाणा के ई-संक्रमण में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सिस्टम ढांचे और सक्षम वातावरण प्रदान करके निजी डोमेन पहल को सुविधाजनक बनाना है। आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रौद्योगिकी पार्क और अन्य सहायक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की स्थापना में प्रोत्साहित किया है।

(f) एसईजेड नीति 2005

हरियाणा ने यह नीति विशेष आर्थिक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी शहरों, औद्योगिक पार्कों और औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आदि की स्थापना के लिए निजी तैनाती और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में भूमि अधिग्रहण की सुविधा के लिए तैयार की है। हरियाणा एसईजेड अधिनियम 2005 का उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ बड़े स्व-निहित औद्योगिक टाउनशिप को बढ़ावा देना और स्थापित करना है। इसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और परेशानी मुक्त वातावरण में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

(g) श्रम नीति 2006

श्रम कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और श्रम कल्याण को बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए श्रम नीति तैयार की गई है। हरियाणा की श्रम नीति 2006 औद्योगिक विवादों की रोकथाम और शीघ्र समाधान के लिए सुलह उपायों को मजबूत करने पर केंद्रित है। नीति के अनुसार, श्रम विभाग का उद्देश्य औद्योगिक दुर्घटनाओं, छंटनी, निकालना और हड़ताल से बचने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना है। नीति का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में भी काम करना है जिसमें श्रमिक और प्रबंधन दोनों अपनी कानूनी रूप से निर्धारित भूमिकाएँ निभाते हैं, जो बदले में राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देता है।

(h) निवेश प्रोत्साहन

राज्य घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोनों में निवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान कर रहा है:

(ii) पिछड़े क्षेत्रों में मेगा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन
(iii) 5 साल की अवधि के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास कर (एलएडीटी) से छूट।
(iv) पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहन
(v) निर्यात इकाइयों के लिए प्रोत्साहन
(vi) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन

(i) थीम पार्क

हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीति में, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विशिष्ट उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, रणनीतिक स्थानों पर विशेषीकृत औद्योगिक संपदाओं का विकास किया जाएगा। इसमे शामिल हैं :

(i) फूड पार्क

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

(ii) रत्न और आभूषण पार्क

(iii) परिधान पार्क

(iv) मुक्त उद्यम क्षेत्र

(j) प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं

(i) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी)

डीएमआईसी और डीएफसी का विकास राज्य में विशाल बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा और औद्योगिक/विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक बनेगा।

प्रस्तावित फरीदाबाद-पलवल औद्योगिक क्षेत्र दादरी में पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निकट स्थित होगा। फरीदाबाद, विशेष रूप से प्रकाश इंजीनियरिंग, बिजली के उपकरणों और ऑटो कॉम्पोनेन्ट उद्योगों की एक बड़ी एकाग्रता के साथ राज्य के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक है। फरीदाबाद-पलवल क्षेत्र में सड़क और रेल द्वारा अच्छी कनेक्टिविटी के फायदे हैं। देश भर के विभिन्न भीतरी इलाकों में उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और दिल्ली से निकटता के साथ, फरीदाबाद में निर्यातोन्मुख औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में निवेश की अच्छी संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में अपेक्षित विशिष्ट उद्योगों में लाइट इंजीनियरिंग, कास्टिंग और फोर्जिंग, विद्युत उपकरण, कपड़ा और परिधान शामिल हैं। इस क्षेत्र में एक एकीकृत लॉजिस्टिक होगा, जिसमें एक इनलैंड कंटेनर डिपो और वेयरहाउसिंग सुविधा के साथ एक ट्रक टर्मिनल होगा। फरीदाबाद-पलवल को आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक और अवकाश/मनोरंजन बुनियादी ढांचे के साथ एक एकीकृत टाउनशिप के रूप में भी विकसित किया जाएगा जिसे विशिष्ट निवेशक समूहों/देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है।

पहचान किए गए औद्योगिक क्षेत्र को एनएचडीपी कॉरिडोर, डीएफसी और हिंटरलैंड से जोड़ने वाले क्षेत्रीय लिंकेज का विकास:

सड़क संपर्क:

- एनएच-2, स्वर्णिम चतुर्भुज एनएचडीपी कॉरिडोर के साथ जुड़ाव।
- एनसीआर के प्रस्तावित पश्चिमी (कुंडली-मानेसर-पलवल) और पूर्वी (कुंडली-गाज़ियाबाद-पलवल) पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ लिंकेज।
- हिंटरलैंड के लिए राज्य राजमार्ग लिंक का विस्तार अर्थात गुड़गांव/रेवाड़ी-सोहना-पलवल लिंक और सोहना-अलवर-भरतपुर लिंक
- फीडर लिंक के विकास में राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों के साथ अपेक्षित ग्रेड सेपरेटर्स/फ्लाईओवर/इंटरचेंज और अंडरपास का विकास और क्षेत्र में निर्बाध माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही के लिए पहुंचने वाले सड़कों को भी शामिल किया जाएगा।

रेल लिंक:

प्रस्तावित फीडर रेल लिंक में दिल्ली-आगरा मेन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन और पश्चिमी डीएफसी को जोड़ना शामिल है। इस क्षेत्र को तुगलकाबाद और दादरी में डीएफसी टर्मिनलों द्वारा सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र को पीरथला जंक्शन पर डीएफसी से जोड़ने की संभावना है। फीडर रेल लिंक के विकास में जहां कहीं भी आवश्यक हो, ओवर ब्रिज/अंडरपास का निर्माण भी शामिल है ताकि लेवल क्रॉसिंग से बचा जा सके। फरीदाबाद और गुड़गांव, फरीदाबाद-पलवल के बीच एमआरटीएस कनेक्टिविटी विकसित करने से भी महत्वपूर्ण प्रभाव

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

पड़ेगा।

हवाई लिंक:

ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हवाई संपर्क के मुद्दे को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

उत्तर-पश्चिमी हरियाणा में कुंडली-सोनीपत निवेश क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है। यह क्षेत्र दादरी में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संरेखण से 50-100 किमी की दूरी के भीतर स्थित होगा। निकटतम प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली और पानीपत हैं, जो राज्य में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) रिफाइनरी का आधार है। इसे गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे के अलावा सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी कनेक्टिविटी की उपलब्धता का लाभ है।

प्रस्तावित निवेश क्षेत्र को दिल्ली से निकटता के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे के अलावा सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी कनेक्टिविटी की उपलब्धता का लाभ है। प्रस्तावित निवेश क्षेत्र को कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे द्वारा भी सेवा प्रदान की जाएगी। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के लिए मास्टर प्लान में विश्व-व्यापार शहर, बायो-साइंस सिटी, मेडी सिटी, लीजर सिटी, साइबर सिटी, लेदर सिटी और फैशन सिटी आदि के रूप में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना की गई है।

प्रस्तावित महत्वपूर्ण घटक हैं:

- निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयाँ / एसईजेड:

  उत्तर हरियाणा चमड़ा, कपड़ा/हथकरघा और कालीनों के निर्माण में दक्ष है। एक बड़ा औद्योगिक पार्क इन वस्तुओं के निर्यात को काफी बढ़ावा देगा।

- कृषि/खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र:

  राज्य से बड़े कृषि उत्पादन को ध्यान में रखते हुए और देश के उत्तरी क्षेत्र को पूरा करने के लिए, निवेश क्षेत्र में एक मेगा कृषि/खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रस्तावित है। यह मुख्य रूप से खाद्यान्न और बागवानी बाजार को पूरा करेगा और इसे थोक बाजार टर्मिनलों, नीलामी क्षेत्रों और अन्य बुनियादी ढांचे के साथ प्रदान किया जाएगा।

- नॉलेज हब/कौशल विकास केंद्र:

  कृषि-प्रसंस्करण, चमड़ा प्रौद्योगिकी, कालीन और कपड़ा उद्योग के साथ-साथ निवेश क्षेत्र के अन्य उद्योगों का समर्थन करने के लिए, एक ज्ञान केंद्र/कौशल उन्नयन केंद्र अनिवार्य होगा। इसे इस क्षेत्र में स्थापित करने की सलाह दी जाती है, जो राष्ट्रीय राजधानी के बहुत करीब है, इस प्रकार पर्याप्त "प्रशिक्षित" आबादी है।

- गोदाम के साथ ट्रक टर्मिनल::

  निवेश क्षेत्र के लिए परिवहन, पैकेजिंग और गोदाम/भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्विसिंग/मरम्मत, ट्रक पार्किंग, इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली और तीसरे पक्ष के रसद सहायता के साथ एक ट्रक टर्मिनल की परिकल्पना की गई है।

- एकीकृत टाउनशिप:

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

इस क्षेत्र को आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक और अवकाश/मनोरंजन बुनियादी ढांचे के साथ एक एकीकृत टाउनशिप प्रदान की जाएगी जिसे विशिष्ट निवेशक समूहों/देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है।

- फीडर रोड लिंक:

  पहचान किए गए निवेश क्षेत्र को एनएचडीपी, डीएफसी कॉरिडोर और हिंटरलैंड से जोड़ने वाले फीडर रोड लिंकेज के विकास में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल हैं:

  - कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे (वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) और एनएच-1 से कनेक्टिविटी।
  - सोनीपत-बहादुरगढ़-झज्जर को फोर-लेन ड्यूल कैरिजवे तक चौड़ा और मजबूत करना।
  - एनएच-72ए (रोहतक-पानीपत) को चार लेन के दोहरे कैरिजवे में बढ़ाना।

- फीडर लिंक के विकास में राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों के साथ-साथ अपेक्षित ग्रेड सेपरेटर/फ्लाईओवर/इंटरचेंज और अंडरपास का विकास और क्षेत्र में निर्बाध माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही के लिए पहुंच सड़कों को भी शामिल किया जाएगा।
- फीडर रेल लिंक:
  - दिल्ली-अंबाला मेन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से/को लिंक करना
  - फीडर रेल लिंक के विकास में जहां कहीं भी आवश्यक हो अंडरपास का निर्माण भी शामिल है ताकि लेवल क्रासिंग से बचा जा सके।

रेवाड़ी, भटिंडा और लुधियाना (पंजाब) के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित फीडर रेल लिंकेज के साथ रेवाड़ी-हिसार औद्योगिक क्षेत्र रणनीतिक रूप से स्थित होगा। यह उपयुक्त रसद बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आदर्श है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोड की हवाई संपर्क आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र और कुंडली-सोनीपत निवेश क्षेत्र को डीएमआईसी परियोजना के हिस्से के रूप में हरियाणा उप-क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है (मानचित्र 7.2 देखें)।

(ii) मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र

मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र (एमबीआईआर), दक्षिण-पश्चिमी हरियाणा में, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी-दादरी संरेखण के 50 किमी के भीतर स्थित होगा। निकटतम प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली और गुड़गांव हैं, जो देश का आईटी/ऑटोमोबाइल गंतव्य है। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, दिल्ली और मुंबई के बीच स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के निकट स्थित होने का प्रस्ताव है। निवेश क्षेत्र में संभावित उद्योग क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और आईटी/आईटीईएस शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि रेवाड़ी-मानेसर-बावल में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक 'ऑटो/ऑटोमोबाइल निवेश क्षेत्र' की भी योजना बनाई जा रही है। डीएमआईसी के तहत एमबीआईआर के घटकों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मानचित्र 7.2: डीएमआईसी-हरियाणा में प्रस्तावित विकास नोड्स के लिए स्थान मानचित्र

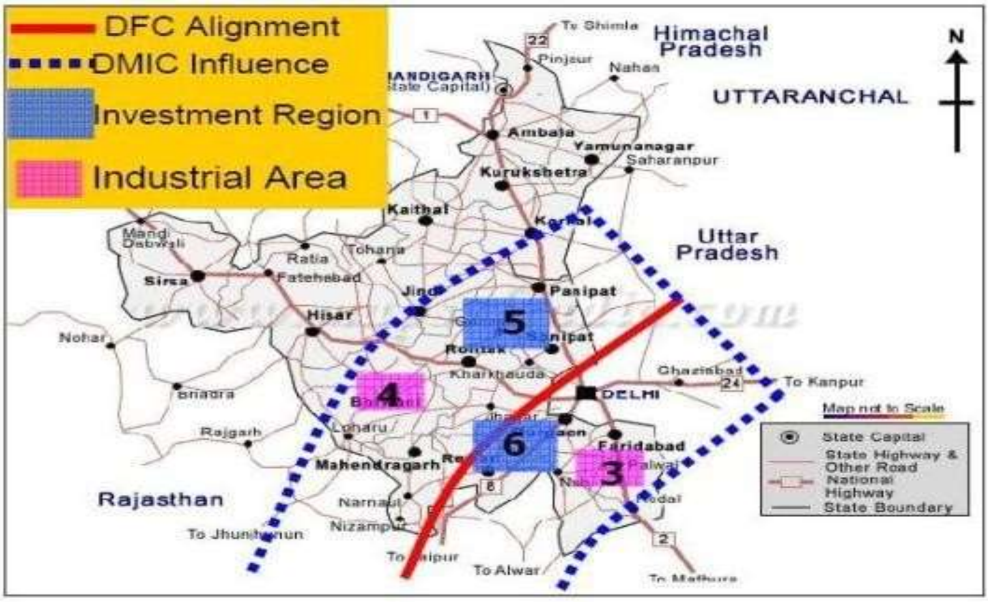

स्रोत: *http://delhimbaiindustrialcorridor.com/dmic-uttar-pradesh.php*

(iii) कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे

हरियाणा सरकार ने केएमपी एक्सप्रेसवे की आर्थिक क्षमता का दोहन करने के लिए खरखोदा और सांपला के लिए विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया है। खरखौदा में एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप होगी; सांपला में बायो-साइंस सिटी, साइबर-सिटी और मेडी-सिटी की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार के पास केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ-साथ पूरे राज्य में अन्य रणनीतिक स्थानों पर आर्थिक केंद्र विकसित करने की तीव्र योजना है (मानचित्र 7.3 देखें)।

केएमपी एक्सप्रेसवे का प्रभाव:

केएमपी एक्सप्रेस-वे का विकास एचएसआईआईडीसी द्वारा किया गया है। इस परियोजना में एक्सप्रेसवे के साथ रणनीतिक स्थानों पर आर्थिक केंद्रों के विकास की अभूतपूर्व क्षमता है। केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ एक ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना बनाई गई है, जिसमें नॉलेज सिटी, साइबर सिटी, बायो-साइंसेस और फार्मा-सिटी, मेडी-सिटी, फैशन सिटी, एंटरटेनमेंट सिटी, वर्ल्ड ट्रेड सिटी, लीजर सिटी, ड्राई पोर्ट सिटी, इको सिटी, स्पोर्ट्स सिटी आदि जैसे विभिन्न थीम शहरों की स्थापना के प्रावधान हैं।

ये शहर/हब संस्थागत, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अनुसंधान, आवासीय, रसद/माल ढुलाई गतिविधियों को पूरा करेंगे और 150 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैले होंगे। इन शहरों से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने की उम्मीद है और इन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में विकसित किया जाएगा।

मानचित्र 7.3: केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर परियोजनाएं

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

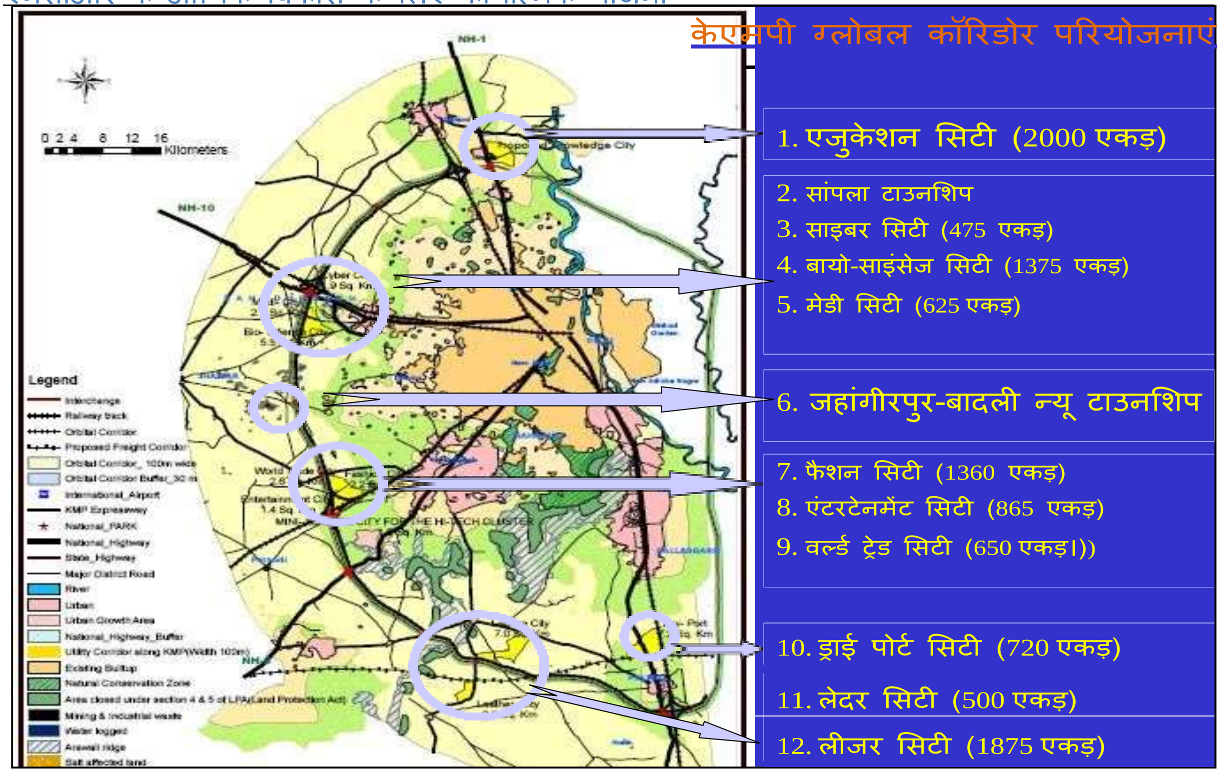

स्रोत: हरियाणा सरकार

(iv) औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी)

एचएसआईआईडीसी ने आधुनिक तर्ज पर मानेसर में एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है। यह एक बहुत ही सफल उपक्रम रहा है और उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा इसका स्वागत किया गया है। अगले पांच वर्षों में विकास को दोहराने और दो आईएमटी लगाने का प्रस्ताव है। ये टाउनशिप आईएमटी मानेसर के अनुभव पर आधारित हैं और इसमें बड़े उद्योगों के लिए परिसर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पार्कों, औद्योगिक भूखंडों, फ्लैट कारखानों, आवासीय कॉलोनियों, श्रम आवास, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों, मनोरंजन क्षेत्र, शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि शामिल हैं। उद्यमों को सुखद वातावरण में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़कें, सीवरेज, अपशिष्ट निपटान, बारिश के पानी का निपटान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। एनसीआर में तीन स्थानों अर्थात; रोहतक, खरखौदा और फरीदाबाद पर आईएमटी आ रहे हैं।.

(v) मॉडल टाउनशिप

एचएसआईआईडीसी द्वारा लगभग 5000 एकड़ क्षेत्र में गुड़गांव के निकट मानेसर में एक मॉडल टाउनशिप विकसित की जा रही है। एचएसआईआईडीसी 1200 एकड़ क्षेत्र में बावल में औद्योगिक विकास केंद्र भी विकसित कर रहा है। कुंडली में एक बहु-कार्यात्मक परिसर भी विकसित किया जा रहा है, जिसे राय-कुंडली बहु-कार्यात्मक परिसर के नाम से जाना जाता है, जहां एचएसआईआईडीसी द्वारा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, फूड पार्क, कोल्ड चेन कॉम्प्लेक्स विकसित किए गए हैं। एचएसआईआईडीसी ने गन्नौर के पास राय, बरही में औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास केंद्र (आईआईडीसी) भी विकसित किया है। एचएसआईआईडीसी ने आईआईडीसी की निरंतरता में 330 एकड़ के क्षेत्र में बरही (Ph-II) में भूमि का अधिग्रहण किया है। भूमि होजरी और कपड़ा प्रसंस्करण, बुनाई इकाइयों आदि के आवंटन के लिए उपलब्ध होगी। एचएसआईआईडीसी की गुड़गांव में रत्न और आभूषण पार्क के लिए अत्याधुनिक और उच्च सुरक्षा क्षेत्र विकसित करने की भी योजना है।

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम ने रोहतक और फरीदाबाद में दो औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित करने की योजना बनाई है। हरियाणा सरकार ने आईएमटी मानेसर, खरखोदा, जगाधरी, बरही और बावल के विस्तार सहित विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण पहले ही शुरू कर दिया है। आधुनिक टाउनशिप की तर्ज पर हरियाणा में आधुनिक परिवहन व्यवस्था के साथ सांपला, बादली-जहांगीरपुर और गनौर-समालखा में तीन नई टाउनशिप बनाने की योजना है। यह न केवल एनसीटी को कम करने में मदद करेगा बल्कि एनसीआर के विकास के लिए विकास इंजन भी बनेगा।

(vi) हरियाणा में वैश्विक कॉरिडोर

कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के साथ ग्लोबल कॉरिडोर का विकास, शीर्ष श्रेणी की बुनियादी सुविधाओं के साथ जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे, कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के साथ विकसित किए जाएंगे। इस कॉरिडोर में कई विशेष आर्थिक गतिविधियां होंगी, जो इसे विकास केंद्रित बनाएगी। एक्सप्रेसवे एसईजेड में औद्योगिक इकाइयों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हरियाणा उप-क्षेत्र के भीतर अन्य औद्योगिक सांद्रता के बीच मजबूत संबंधों को सक्षम करेगा।

- पानीपत-सोनीपत-कुंडली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर औद्योगिक कॉरिडोर।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर बहादुरगढ़-रोहतक औद्योगिक कॉरिडोर।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर गुड़गांव-मानेसर-बावल औद्योगिक कॉरिडोर।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1-ए पर फरीदाबाद-पलवल औद्योगिक कॉरिडोर।

(vii) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेडएस)

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सेज को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। एसईजेड में एफडीआई को भी बढ़ावा दिया जाता है। राज्य की नीति स्पष्ट रूप से डेवलपर्स द्वारा आवश्यक दायित्वों, प्रक्रिया और मंजूरी को स्पष्ट करेगी और केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) मार्ग, एनएच 10, एनएच 8 और एनएच 2 पर एसईजेड स्थापित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ावा देना है। उद्योग विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहां कहीं भी क्षमता मौजूद हो। हरियाणा में 63 स्वीकृत एसईजेड हैं (10 मार्च 2015 तक) यह देखा गया है कि आईटी / आईटीईएस क्षेत्र हरियाणा में प्रस्तावित एसईजेड की संख्या पर हावी है। इसके अलावा, अधिकांश परियोजनाएं गुड़गांव और फरीदाबाद में स्थित हैं; उप-क्षेत्र में चल रही कुछ परियोजनाओं में नॉलेज सिटी, साइबर सिटी, मेडी सिटी, बायो-साइंस सिटी, वर्ल्ड ट्रेड सिटी, फैशन सिटी, एंटरटेनमेंट सिटी, लीजर सिटी, साइबर सिटी, लेदर सिटी और ड्राई पोर्ट हैं।

(viii) झज्जर में पावर प्लांट

झज्जर में एक कोयला आधारित सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, जिसे इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। यह बिजली परियोजना एनटीपीसी द्वारा दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में निष्पादित की जा रही है। इस परियोजना की स्थापित क्षमता 3 X 500 मेगावाट है और इसकी लागत लगभग 82000 मिलियन रुपये है। वर्तमान में चरण-I के तहत 3X500MW क्षमता के बिजली संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सभी 3 इकाइयां चालू हैं। चरण-II के तहत भविष्य में 2x660 मेगावाट का प्रावधान है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

(ix) पानीपत में भारी उद्योग रासायनिक संयंत्र

पानीपत तेल रिफाइनरी के पास 30,000 करोड़ रुपये के निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए एक मेगा पेट्रो-केमिकल हब विकसित किया जा रहा है। एक तरफ, पेट्रोकेमिकल हब रिफाइनरी से फीडस्टॉक का उपयोग करने में मदद करेगा और दूसरी तरफ पॉलीमर उद्योग जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों की स्थापना की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप सहायक इकाइयों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।

(x) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सरकार के आंकड़ों के अनुसार। भारत में, कुल बारह अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICDs) हैं [गढ़ी हरसरू (गुड़गांव), गुड़गांव, पाटली (गुड़गांव), पियाला / असौती (पलवल), बावल (रेवाड़ी), बल्लभगढ़, पाली (रेवाड़ी), राय (सोनीपत) में), पांची गुजरां (सोनीपत), समालखा (पानीपत), जनोली और भंगोला (पलवल) में दो] और तीन कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) [फरीदाबाद, रेवाड़ी और कुंडली (सोनीपत)] जो हरियाणा उप क्षेत्र में कार्यान्वयन या कार्यात्मक हैं। यह देखा गया है कि उप-क्षेत्र में आईसीडी और सीएफएस की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो औद्योगिक उत्पादन और व्यापार संबंधी गतिविधियों के तेजी से विकास को दर्शाता है। कॉनकॉर 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से पानीपत में एक कोल्ड चेन कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रहा है। इससे राज्य से ताजे फलों और सब्जियों के विपणन और निर्यात में आसानी होगी और इससे राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

(k) परिणाम

एनसीआर का हरियाणा उप-क्षेत्र औद्योगिक और बुनियादी ढांचा निवेश के लिए एक उत्कृष्ट स्थान साबित हुआ। उप-क्षेत्र ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े व्यापारिक घरानों, विदेशी निवेशकों, अनिवासी भारतीय और लघु उद्यमियों से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया है। हरियाणा उप-क्षेत्र वर्तमान में देश में निर्मित दो-तिहाई यात्री कारों, पचास प्रतिशत ट्रैक्टर, साठ प्रतिशत मोटर साइकिल और पचास प्रतिशत रेफ्रिजरेटर का उत्पादन करता है। देश में हर चार में से एक साइकिल उप-क्षेत्र में निर्मित होती है। राज्य में पहले से ही विदेशी तकनीकी सहयोग के साथ 857 परियोजनाएं हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड, हीरो होंडा, मोदी अल्काटेल, एस्कॉर्ट्स, सोनी इंडिया, वीएक्सएल इंडिया, व्हर्लपूल इंडस्ट्रीज, विप्रो लिमिटेड, परफिटी इंडिया, डीसीएम, बेनेटन, टीडीटी कॉपर लिमिटेड, असाही इंडिया सेफ्टी ग्लास आदि। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ प्रमुख इकाइयाँ एचएमटी लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आईबीपीएल आदि हैं। इस समूह में नवीनतम जोड़ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पानीपत जिले में 4200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्थापित तेल रिफाइनरी है। पिछले 6 वर्षों में, हरियाणा उप-क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ 2962 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किए गए हैं, जो अनुमानित निवेश को उत्प्रेरित करेंगे। जो 250 बिलियन और 2 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करते हैं।

हरियाणा में समग्र नीति संरचना का उद्देश्य ढांचागत पहलों के माध्यम से आर्थिक हब विकसित करना और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। आईसीटी और खाद्य क्षेत्र के क्षेत्रों में अग्रणी प्रौद्योगिकियों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नीति मानती है कि इन नीतियों का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम विकसित स्थानों/मेवात जैसे क्षेत्रों में होगा। सेवा क्षेत्र विशेष रूप से पर्यटन, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में एनसीआर के हरियाणा उप-क्षेत्र में विकास की कुंजी है। छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास और समर्थन और निर्यात-प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

निवेश को प्रेरित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया में निवेशक-केंद्रित दृष्टिकोण है और आधुनिक तकनीकी और प्रबंधन समाधानों का उपयोग करके दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। क्षेत्र में निवेश का समर्थन करने के लिए, सरकार शिकायत और उपचार तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तात्कालिक कौशल प्रदान करने के लिए, विभिन्न नीतियों में भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग और तकनीकी संस्थानों के बीच रणनीतिक संबंध स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के साथ-साथ पूरे राज्य में रणनीतिक स्थानों पर आर्थिक केंद्र विकसित करने की भी योजना है। एचएसआईआईडीसी नई औद्योगिक संपदाओं/पार्कों के विकास और मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं के पर्याप्त विस्तार के लिए 20000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रहा है।

7.4.3 उत्तर प्रदेश

(a) औद्योगिक और सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 का उद्देश्य राज्य में व्यापक सुधार एवं अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना तथा नये अवसर सृजित करना तथा निवेश के नये रास्ते खोलना है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि राज्य के सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए न केवल उद्योग बल्कि व्यापार, वाणिज्य और सेवाओं के क्षेत्र में भी विकास की गति को तेज करने की आवश्यकता है, राज्य सरकार ने औद्योगिक और सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को मजबूत करने के अलावा औद्योगिक क्षेत्र के सभी क्षेत्रों जैसे भारी, मध्यम और लघु उद्योग के संतुलित, सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए स्थितियां बनाना है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, डिजाइन और पैकेजिंग और विपणन के मामले में पारंपरिक उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस नीति के तहत राज्य सरकार राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है। इसके अलावा, निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात योग्य उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक सुविधाजनक माहौल भी प्रदान किया जाता है। नीति के तहत, राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और राज्य को विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने का भी प्रयास करता है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, उद्यमियों और औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन को उचित प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। नीति निवेशकों को विभिन्न करों और शुल्कों से छूट के अलावा बुनियादी ढांचे पर विशेष प्रोत्साहन प्रदान करती है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

नीति त्वरित और परेशानी मुक्त प्रक्रियाओं के लिए एकल खिड़की नीति बनाए रखती है। आईटी, आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और कुछ सेवा क्षेत्र के लिए स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट; स्टाम्प शुल्क में छूट, प्राथमिकता के आधार पर भूमि, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण, निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत शुल्क में छूट, भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क से 50-100 प्रतिशत छूट से निवेश हेतु आदर्श वातावरण निर्मित करने में सहायता मिली है। साथ ही 5000 मिलियन रुपये से अधिक के निवेश के लिए केस-टू-केस आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। नीति का इरादा औद्योगिक और संबद्ध क्षेत्र में रोजगार को वर्तमान स्तर 8% से 15% तक बढ़ाने का है।

(b) सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2004

आईटी सेवा उद्योग की विशाल रोजगार सृजन क्षमता को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार आईटी-सेवाओं (हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर आधारित आदि) और आईटी-सक्षम सेवाओं (कॉल सेंटर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, बीपीओ, आदि) में लगी इकाइयों की स्थापना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगी और तकनीकी जानकारी, बुनियादी ढांचा, विपणन सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी इच्छुक है। पहल में आईटी गतिविधियों के लिए बजट, ई-गवर्नेंस के लिए आईटी पूल फंड, आईटी शहर, आईटी पार्क, एनआईसी बुनियादी ढांचा और हार्डवेयर उद्योगों को बढ़ावा देना शामिल है।

(c) एसईजेड नीति (2007)

एसईजेड को विकसित करने और औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2007 में एसईजेड नीति पेश की है। नीति का उद्देश्य करों में छूट प्रदान करना, विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का विकास करना और श्रम, बिजली और पर्यावरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों को युक्तिसंगत / छूट देना है।

(d) बायोटेक नीति 2004

उत्तर प्रदेश राज्य जैव प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने और किसानों के लिए समृद्धि प्राप्त करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने, सभी के लिए भोजन, अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण की इच्छा रखता है। नीति का मिशन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना, राज्य के सभी वर्गों को जैव प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करना और जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

(e) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नीति 2004

उत्तर प्रदेश देश में कृषि वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और सब्जियों, गेहूं, मक्का, गन्ना, आलू और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में फलों की कुछ सबसे स्वादिष्ट किस्में उगाई जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य में विविध कृषि जलवायु स्थितियां भी हैं, जो वर्ष भर विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए अनुकूल हैं।

(f) निवेश प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में उच्च औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानक, पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुविधाएं, अनुकूल नीति ढांचा और एक निवेशक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य आर्थिक गतिविधियों और उद्यमिता के पोषण में अपनी भूमिका को पहचानता है और उद्योग को पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर उच्च प्राथमिकता देता है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

(g) हाई-टेक नीति

हाई-टेक नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में हाई-टेक टाउनशिप का विकास करना है। इस तरह की हाई-टेक टाउनशिप का विकास न केवल रियल एस्टेट विकास क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा और रहने, काम और मनोरंजन के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और आकर्षक सौंदर्य वातावरण प्रदान करेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा।

(h) प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं

(i) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)

उप-क्षेत्र में डीएमआईसी परियोजना के कारण जिन महत्वपूर्ण उद्योगों को लाभ होने की संभावना है, उनमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और चमड़ा और कपड़ा सामान शामिल हैं। एक मेगा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र में और निवेश की सुविधा के द्वारा गाजियाबाद में औद्योगिक गतिविधियों में और सुधार किया जाएगा। गाजियाबाद में दो औद्योगिक संपदाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

जैव प्रौद्योगिकी एक आगामी उद्योग क्षेत्र है जिसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पास डीएमआईसी क्षेत्र में जोर देने की आवश्यकता है। आईटी / आईटीईएस / बायोटेक हब के साथ-साथ निवेश क्षेत्र के अन्य उद्योगों का समर्थन करने के लिए, एक ज्ञान केंद्र / कौशल उन्नयन केंद्र उद्योग को अधिक टिकाऊ आधार पर विकसित करने में मदद कर सकता है।

दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र और मेरठ-मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र को डीएमआईसी परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है (मानचित्र 7.4 देखें)।

मानचित्र 7.4: डीएमआईसी - उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित विकास नोड के लिए स्थान मानचित्र

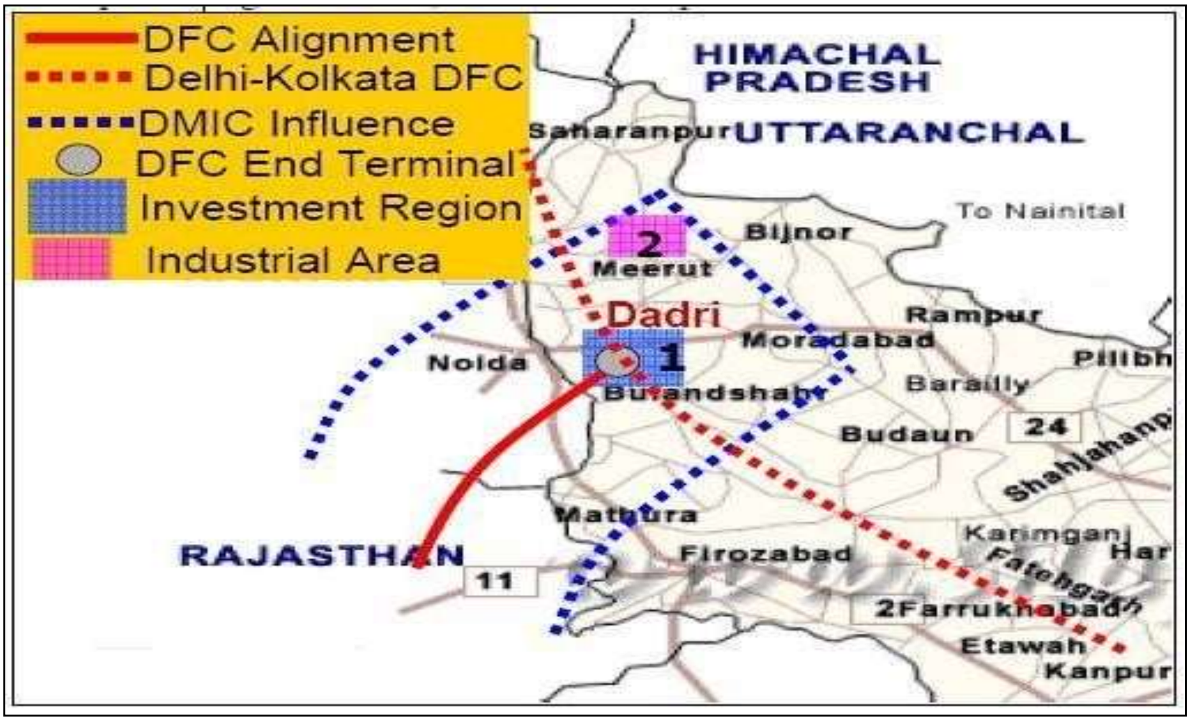

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

स्रोत: *http://delhimbaiindustrialcorridor.com/dmic-uttar-pradesh.php*

ऊपर वाले चित्र का अनुवाद

डीएफसी संरेखण

दिल्ली-कोलकाता डीएफसी

डीएमआईसी प्रभाव

डीएफसी समाप्ति टर्मिनल

निवेश क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश

उत्तरांचल

सहारनपुर बिजनौर मेरठ दादरी मुरादाबाद रामपुर पीलीभीत नोएडा बुलंदशहर बरेली बदायूं शाहजहांपुर मथुरा फ़िरोज़ाबाद करीमगंज फतेहगढ फर्रुखाबाद इटावा कानपूर राजस्थान

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र

दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब है। इस क्षेत्र की सड़क और रेल द्वारा शेष भारत से भी अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा, इसमें नोएडा शामिल है, जो पर्याप्त आईटी/आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के साथ केंद्रीय एनसीआर का हिस्सा है; गाजियाबाद, प्रकाश इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का केंद्र है; और ग्रेटर नोएडा, अच्छी तरह से विकसित सड़क नेटवर्क वाला शहर, गुणवत्तापूर्ण आवासीय वाणिज्यिक, मनोरंजक और संस्थागत क्षेत्रों के साथ अत्याधुनिक भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से दादरी के पास 3500 मेगावाट बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है।

इस निवेश क्षेत्र को दादरी जंक्शन के करीब स्थित होने का फायदा होगा, जहां मौजूदा दिल्ली-मेरठ-लखनऊ ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी के अलावा पूर्वी (दिल्ली-कोलकाता) और पश्चिमी (दिल्ली-मुंबई) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिलते हैं।

प्रस्तावित निवेश क्षेत्र के घटक

- ग्रेटर नोएडा में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड)।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी से दादरी में 3500 मेगावाट बिजली संयंत्र कार्यान्वित किया जा रहा है
- दो राष्ट्रीय राजमार्गों, एनएच-24 (दिल्ली-लखनऊ), एनएच-58 (दिल्ली-हरिद्वार-माना दर्रा) के साथ कनेक्टिविटी। एनएचडीपी के फेज-3A और 3B के तहत दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए फोर-लेन ड्यूल कैरिजवे को चौड़ा और मजबूत करने का काम किया जा रहा है।
- इस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रस्तावित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (गाजियाबाद-नोएडा-पलवल और कुंडली-गाजियाबाद) द्वारा भी सर्विस दी जाएगी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विनिर्माण क्षेत्र (इंजीनियरिंग / विद्युत उपकरण आदि) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दादरी-नोएडा-ग्रेटर नोएडा-गाजियाबाद में 400 वर्ग किलोमीटर में फैले एक 'सामान्य विनिर्माण निवेश क्षेत्र' की भी योजना बनाई जा रही है।

निवेश क्षेत्र के अन्य प्रस्तावित घटक

- निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयाँ / एसईजेड
- मौजूदा औद्योगिक सम्पदा का विस्तार
- कृषि/खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र
- आईटी/आईटीईएस/बायोटेक हब
- नॉलेज हब/कौशल विकास केंद्र
- इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब
- इंटीग्रेटेड टाउनशिप
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।
- एनएच-24 और एनएच-58 को लिंकेज प्रदान करना।
- गाजियाबाद-अलीगढ़-आगरा को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग का विस्तार।
- ग्रेटर नोएडा/दिल्ली और फरीदाबाद/एनएच2 और फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद और कुंडली-गाजियाबाद एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी।
- फीडर लिंक के विकास में राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों के साथ अपेक्षित ग्रेड

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

सेपरेटर्स/फ्लाईओवर/इंटरचेंज और अंडरपास का विकास और क्षेत्र में निर्बाध माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही के लिए पहुंच सड़कों को भी शामिल किया जाएगा।

प्रस्तावित फीडर रेल लिंक

- कंटेनर टर्मिनल और दादरी में वेस्टर्न डीएफसी के साथ लिंकेज।
- मेरठ-दादरी-गाजियाबाद, गाजियाबाद-अलीगढ़-हाथरस मार्ग का विस्तार।
- फीडर रेल लिंक के विकास में जहां कहीं भी आवश्यक हो अंडरपास का निर्माण भी शामिल है ताकि लेवल क्रासिंग से बचा जा सके।

(ii) मेरठ-मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र

प्रस्तावित मेरठ-मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 100 से 150 किमी की दूरी पर स्थित होगा। इस क्षेत्र की सड़क (एनएच-58 और अन्य राज्य राजमार्ग) और रेल (दिल्ली-मेरठ-लखनऊ/सहारनपुर) से राज्य और भारत के बाकी हिस्सों से अच्छी कनेक्टिविटी है।

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में सड़क और रेल द्वारा अच्छी कनेक्टिविटी की उपलब्धता का लाभ है। राज्य के समृद्ध कृषि क्षेत्रों में स्थित होने के कारण, यह क्षेत्र कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। यह क्षेत्र मेरठ और मुजफ्फरनगर के समृद्ध कृषि उत्पादों (आम, बासमती चावल, आलू और अन्य सब्जियां) के साथ-साथ राज्य के बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर और सहारनपुर के आसपास के जिलों से भी मिलता है। मेरठ खेल सामग्री के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा, मेरठ ऑटोमोबाइल, शराब, कागज, रसायन, चीनी, सूती धागे आदि में अन्य मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों और इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य उत्पादों और इंजीनियरिंग वस्तुओं में लघु उद्योगों का आधार है।

1 मिलियन से अधिक आबादी के साथ, मेरठ को भारत सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना के तहत शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1,120 करोड़ रुपये प्राप्त करने वाले देश के 63 प्रमुख शहरी समूहों में से एक के रूप में पहचाना गया है। इन निवेशों को 2012 तक लागू करने का प्रस्ताव है। मुजफ्फरनगर में लगभग 24 पेपर मिल, 6 चीनी मिल और 36 स्टील रोलिंग मिलें हैं जो इस क्षेत्र की संभावनाओं को दर्शाती हैं। दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी प्रस्तावित है, जिससे प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी की पेशकश की उम्मीद है। औद्योगिक क्षेत्र में डीएमआईसी के प्रमुख प्रस्तावित घटक निर्यातोन्मुख औद्योगिक इकाइयां/एसईजेड, मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विस्तार, कृषि/खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, वेयरहाउसिंग सुविधा के साथ ट्रक टर्मिनल और एकीकृत टाउनशिप हैं।

(iii) यमुना एक्सप्रेसवे

यमुना एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दो महत्वपूर्ण स्थलों - राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पर्यटन केंद्र आगरा को जोड़ता है। इन दोनों स्थानों में यातायात और आर्थिक विकास की उच्च क्षमता है। आगरा पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क द्वारा कोलकाता, मुंबई और जयपुर आदि से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे दिल्ली से इन सभी मार्गों को उच्च स्तरीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, खासकर जब आगरा शहर के आसपास प्रस्तावित रिंग रोड को लागू किया जाता है।

दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आसान पहुंच के भीतर प्रस्तावित ताज आर्थिक क्षेत्र और ताज इंटरनेशनल हब हवाई अड्डे के साथ आने वाले एक्सप्रेसवे के साथ, यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास को गति देगी।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली और आगरा को जोड़ने वाले उच्च घनत्व वाले महत्वपूर्ण यातायात गलियारों यानी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच -2) और कानपुर-अलीगढ़-खुर्जा-बुलंदशहर-गाजियाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले एनएच-91 के बीच स्थित है। एक्सप्रेसवे में बेहतर परिवहन और अन्य ढांचागत सुविधाएं प्रदान करके निवेश आकर्षित करने की एक बड़ी आर्थिक क्षमता है।

यमुना एक्सप्रेसवे ने एनसीआर के विभिन्न उपग्रह शहरों, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, फरीदाबाद के साथ अलीगढ़, मथुरा और आगरा के बीच कनेक्टिविटी प्रदान की है। मथुरा और आगरा प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल हैं।

एनएच-2 और एनएच-91 के साथ यमुना एक्सप्रेसवे और उन तीनों के बीच इंटरकनेक्टिविटी ने सड़कों का एक अच्छा नेटवर्क प्रदान किया है, जिसने निम्नलिखित क्षेत्रों में चौतरफा विकास के लिए एक विशाल क्षेत्र खोल दिया है:

- नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आने वाले विशाल शहरी समूह अपनी क्षमता के साथ अलीगढ़, मथुरा और आगरा तक आसानी से पहुंच सकेंगे।
- ताज इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट के साथ यमुना एक्सप्रेसवे के साथ ताज आर्थिक क्षेत्र सहित प्रस्तावित निर्यात संवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।
- सुरक्षित, कम यात्रा समय और क्षेत्र में पहुंच से यमुना एक्सप्रेसवे के साथ-साथ वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत मनोरंजन और आवासीय उद्देश्यों के लिए योजनाबद्ध तरीके से भूमि विकास में तेजी आएगी।

यमुना एक्सप्रेसवे वास्तव में नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक 6-लेन एक्सप्रेसवे का विस्तार है, इस प्रकार औद्योगिक और शहरी विकास के लिए यमुना नदी के पूर्वी तट पर विशाल भीतरी इलाकों को खोल रहा है और पर्यटन, मनोरंजन, अवकाश के लिए सम्मिलन और क्षेत्र में ज्ञान आधारित उद्योग प्रदान करता है। जीरो पॉइंट ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 165 किलोमीटर है।

(iv) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, कुल छह अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) हैं [दो लोनी (गाजियाबाद), सूरजपुर और दादरी (गौतम बुद्ध नगर), बुलंद शहर और मोदी नगर (गाजियाबाद) में] और पांच कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) [दादरी (गौतम बुद्ध नगर) में सभी पांच]] जो उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में कार्यान्वयन या कार्यात्मक हैं। उप-क्षेत्र में आईसीडी और सीएफएस की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो बढ़ते औद्योगिक उत्पादन और व्यापार संबंधी गतिविधियों का एक संकेतक है। लोनी, गाजियाबाद में आईसीडी की एकाग्रता सबसे अधिक है।

(i) परिणाम

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र देश में चौथा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यात के साथ उत्तर भारत के प्रमुख आईटी केंद्रों में से एक है। आईटी फोकस नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी फलफूल रहा है। हाल ही में नोएडा में आगामी लॉजिक्स टेक्नो पार्क भी शामिल किया गया है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.6 मिलियन वर्ग फुट है। पार्क की अनुमानित लागत 17.4 मिलियन डॉलर है। एचसीएल, मेंटर ग्राफिक्स और पटनी जैसी ब्लू-चिप कंपनियां

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

साइट के पूरा होने से पहले ही 75 प्रतिशत पर कब्जा कर चुकी हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, नोएडा, भारत में आईटी सेवाओं को आउटसोर्स करने वाली वैश्विक बड़ी कंपनियों के लिए एक प्रमुख आईटी / आईटीईएस गंतव्य के रूप में उभरने वाले एनसीआर में प्रमुख योगदानकर्ता है। यह उत्तर और मध्य भारत में अन्य सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए नोडल केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। यह ग्लोबल लॉजिक, ईएक्सएल, बिरलासॉफ्ट, इम्पेटस, एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, माउंट्रोनपीटीआई, फिशर, एडोब सिस्टम्स, टीसीएस, सीएससी, एचसीएल, एटीसी लैब्स, इंटररा, अग्रीया सॉल्यूशंस और ज़ान्सा जैसी कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों का घर है।.

नोएडा चमड़े के जूते और चमड़े के कपड़ों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। नोएडा हाई-एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है और इसमें फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) है। नोएडा में कुछ अधिसूचित और कार्यात्मक निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र हैं (तालिका 7.1 और 7.2 देखें)।

तालिका 7-1: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिसूचित निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र

ईपीजेड का नाम	स्थान	उत्पादों/सेवाओं का विवरण
अंसलआईटी सिटी एंड पार्क्स	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
ओएसई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
आचविस सॉफ्टेक	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
परफेक्ट आईटी सेज	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
यूनिटेक हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
गैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
जुबिलेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
सर्वमंगल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
आईवीआर प्राइम आईटी सेज प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस

तालिका 7-2: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कार्यात्मक एनईपीजेड

एनईपीजेड का नाम	स्थान	उत्पादों/सेवाओं का विवरण
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	नोएडा	बहु उत्पाद
एचसीएल प्रौद्योगिकी	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
मोजर बेयर एसईजेड	ग्रेटर नोएडा	गैर-पारंपरिक ऊर्जा
विप्रो लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस

7.4.4 राजस्थान

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

(a) औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति-2010

उद्योग और निवेश नीति का उद्देश्य निम्नलिखित है:

(i) व्यापार के माहौल में सुधार

- नियामक तंत्र का सरलीकरण और युक्तिकरण।
- उद्योग सलाहकार समिति की स्थापना।

(ii) उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का विकास

- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोष बनाना।
- लॉजिस्टिक पार्क विकसित करना।
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) का लाभ उठाना।
- विशेष निवेश क्षेत्रों का विकास करना।
- निवेश टाउनशिप और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण तंत्र सुनिश्चित करना।
- निवेश परियोजनाओं के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- गैस ग्रिड का विकास करना।
- प्रचुर मात्रा में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना

(iii) कौशल स्तर और रोजगार क्षमता बढ़ाना

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता के केंद्रों में अपग्रेड करना।
- ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के लिए "ट्रेन टू गेन" योजना।
- कौशल मानचित्रण और सर्वेक्षण।

(iv) भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना

- भूमि उपयोग परिवर्तन/रूपांतरण/लेआउट/भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाना।
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- एक भूमि बैंक बनाना और निवेश के लिए भूमि का लाभ उठाने के लिए नए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना।

(v) एमएसएमई विकास पर ध्यान दें

- 2008 में शुरू की गई एमएसएमई नीति के तहत एमएसएमई को प्रोत्साहन जारी रहेगा और व्यापक क्लस्टर विकास होगा।
- एसपीवी मोड में क्लस्टर विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना शुरू की जाएगी।
- भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना।
- गुणवत्ता सुधार के लिए संस्थागत मदद

(vi) प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देना

- आईटी और आईटीईएस सहित ज्ञान क्षेत्र।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

- रत्न और आभूषण।
- हस्तशिल्प और हथकरघा।

(b) आईटी और आईटीईएस नीति-2007

- सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी उपकरण के रूप में।
- ई-गवर्नेंस पहल।
- आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में निवेश के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
- जनसाधारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

(c) कृषि-प्रसंस्करण उद्योग और कृषि-व्यवसाय 2010 के लिए नीति

कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों और कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नीति, आपूर्ति श्रृंखला के विकास, बाजार विकास और विविधीकरण सहित कृषि-प्रसंस्करण और विपणन में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को संबोधित करना चाहती है।

उद्देश्य:

i. किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक लाभकारी कीमत देकर उनके नकद आय को बढ़ाना
ii. कृषि उपज में मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित करना और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना;
iii. कृषि-प्रसंस्करण और विपणन के आधुनिकीकरण के लिए नई तकनीकों और प्रथाओं को लाना;
iv. राज्य के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत राज्य ब्रांड का निर्माण करना; तथा
v. कृषि-प्रसंस्करण में निजी निवेश को आकर्षित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना

नीति, बागवानी सहित कृषि में मूल्य वृद्धि और हानि में कमी को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करती है; नई पोस्ट हार्वेस्टिंग तकनीकें शुरू करना; राज्य में उत्पादित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और कृषि प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों के विकास को प्रोत्साहित करना।

(d) प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

(i) खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र

डीएमआईसी परियोजना के हिस्से के रूप में, उत्तर-पूर्वी राजस्थान में खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के संरेखण से 50 किमी के भीतर स्थित होगा। यह निवेश क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के करीब स्थित है जो स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। राजस्थान सरकार ने शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोड़ के बीच 40,000 एकड़ में फैले एक वैश्विक शहर को विकसित करके निवेश क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं निर्धारित की हैं और 1 मिलियन आबादी को कवर करने की उम्मीद है।

खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र दिल्ली से 107 किमी की दूरी पर स्थित है। रिडकोर द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अलवर-दौसा लिंक (81 किमी) का चौड़ीकरण किया जा रहा है। तुलनात्मक रूप से कम कीमतों पर विशाल भूमि पार्सल की उपलब्धता उद्योग को लाभ प्रदान करती है। निवेश क्षेत्र में महत्वपूर्ण संभावित उद्योग क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, जैव प्रौद्योगिकी, आईटी/आईटीईएस और स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल हैं (मानचित्र 7.5 देखें)।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों/एसईजेड, आईटी/आईटीईएस/बायोटेक हब, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स आदि के साथ-साथ एक हवाई पट्टी और अन्य एकीकृत सुविधाओं वाले हवाई अड्डे के परिसर के साथ प्रदान करने का प्रस्ताव है जो व्यापार के लिए आने वाले लोगों की जरूरतों जैसे बैगेज चेक-इन, विदेशी मामलों के लिए विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकरण आदि को पूरा करेगा।

रेल और सड़क संपर्क:

पहचान किए गए निवेश क्षेत्र को एनएचडीपी से जोड़ने वाले फीडर रोड और रेल लिंकेज के मामले में, डीएफसी कॉरिडोर और हिंटरलैंड में निम्नलिखित विकास प्रस्ताव शामिल हैं:

- राष्ट्रीय राजमार्ग-8, स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर से जुड़ाव
- रेवाड़ी-अलवर- भरतपुर लिंकेज का विस्तार
- राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों के साथ अपेक्षित ग्रेड विभाजकों/फ्लाईओवरों/इंटरचेंजों और अंडरपासों का विकास और क्षेत्र में निर्बाध माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही के लिए पहुंच सड़कों को भी फीडर लिंक के विकास में शामिल किया जाएगा।
- अनन्य साइडिंग के माध्यम से पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी
- दिल्ली, मानेसर और नीमराना के बीच क्षेत्रीय एमआरटीएस लिंकेज का विकास

मानचित्र 7.5: डीएमआईसी-राजस्थान में प्रस्तावित विकास नोड्स के लिए स्थान मानचित्र

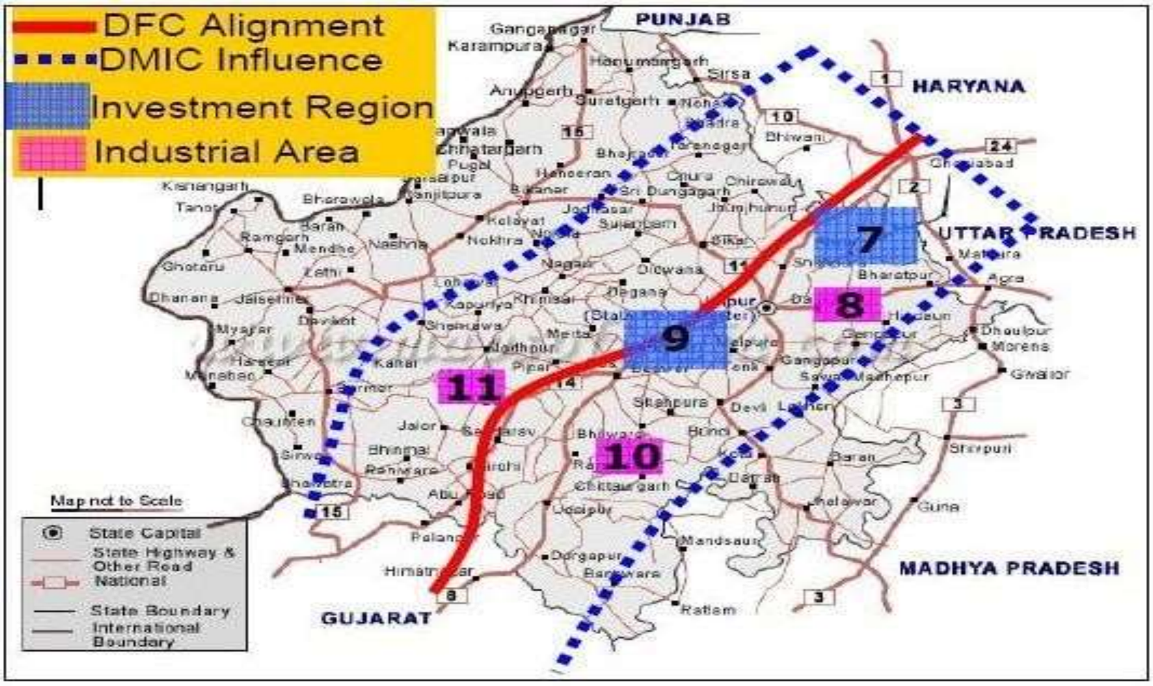

स्रोत: राजस्थान सरकार

(v) इनलैंड कंटेनर डिपो

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान उप-क्षेत्र में कुल दो इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) (भिवाड़ी और कठूवास और मानधन, अलवर जिले) हैं, जो अभी कार्यान्वयन के अधीन हैं या क्रियाशील हैं।

7.4.5 डीएमआईसी परियोजना के तहत जापान से निवेश वाली अर्ली बर्ड परियोजनाओं की सूची

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

- हरियाणा में एफटीडब्ल्यूजेड (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग ज़ोन) परियोजना: मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड
- उत्तर प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन) परियोजना: मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड

ऊपर वाले चित्र का अनुवाद

डीएफसी संरेखण
डीएमआईसी प्रभाव
निवेश क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्र
पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश गुजरात
मानचित्र मापन के लिए नहीं
राज्य की राजधानी
राज्य राजमार्ग और अन्य सड़क
राष्ट्रीय
राज्य की सीमा
अंतरराष्ट्रीय सीमा

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

- डीएमआईसी मानव संसाधन प्रशिक्षण परियोजना: परियोजना प्रस्ताव और योजना: टेक्नो ब्रेन कंपनी (तकनीकी रूप से सोनी कॉर्पोरेशन द्वारा सहयोग प्राप्त) कार्यान्वयन संगठन: विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और पुणे विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र द्वारा प्रचारित
- नीमराना जापान इन्वेस्टमेंट पार्क हिताची, नीमराना में कैप्टिव पावर प्लांट जापानी भाग लेने वाली कंपनियां
- नीमराना जेट स्ट्रीम लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट एनवाईके लाइन इंडिया और एनवाईके लॉजिस्टिक्स इंडिया
- अपशिष्ट वस्त्र और मोबाइल फोन रीसायकल परियोजना जापान पर्यावरण योजना (जेप्लान)

7.5 एनसीआर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण एनसीआर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अच्छी मात्रा को आकर्षित करने में सक्षम है और अतीत में काफी एफडीआई प्राप्त कर चुका है। अप्रैल 2000 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान, एनसीआर ने लगभग आकर्षित किया। 49.410 अरब डॉलर (249,023 करोड़ रुपये) एफडीआई; जो इसी अवधि के दौरान भारत के कुल एफडीआई का 20% से अधिक है। इसी अवधि के दौरान महाराष्ट्र ने सबसे अधिक, भारत के कुल एफडीआई का लगभग 29%, इसके बाद तमिलनाडु ने 7% से अधिक और कर्नाटक ने 6% से अधिक एफडीआई आकर्षित किया (तालिका 7.3 देखें)।

तालिका 7-3: अप्रैल 2000 से मार्च 2015 तक एनसीआर में एफडीआई इनफ्लो

क्रम संख्या	कवर किए गए राज्य	संचयी इनफ्लो (अप्रैल 2000 से मार्च 2015) करोड़ रुपये (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	कुल इनफ्लो का %
1	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	3,53,022 (73,118)	28.62
2	दिल्ली, यूपी और हरियाणा का हिस्सा	249023 (49410)	20.19
3	तमिलनाडु, पांडिचेरी	88,766 (17,014)	7.20
4	कर्नाटक	82,121 (16,120)	6.66
5	गुजरात	53,797 (11,041)	4.36
6	आंध्र प्रदेश	49,240 (10,015)	3.99
7	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14,627 (2,981)	1.19
8	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	6,360 (1,331)	0.52
9	राजस्थान Rajasthan	6,795 (1,264)	0.55
10	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	6,096 (1,216)	0.49
11	केरल, लक्षद्वीप	6,150 (1,211)	0.50

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

12	गोवा	3,867 (823)	0.31
13	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	2,444 (483)	0.20
14	ओडिशा	1,961 (3,98)	0.16
15	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	381 (84)	0.03
16	बिहार, झारखंड	267 (50)	0.02
17	जम्मू और कश्मीर	26 (4)	0.002

क्रम संख्या	**कवर किए गए राज्य**	**संचयी इनफ्लो (अप्रैल 2000 से मार्च 2015) करोड़ रुपये (मिलियन अमेरिकी डॉलर)**	**कुल इनफ्लो का %**
18	क्षेत्र इंगित नहीं किया गया	3,08,060 (61951)	24.97
उप योग		12,33,005 (2,48,512)	99.96
19	आरबीआई की एनआरआई योजना (2000-2002 से)	533 (121)	0.04
कुल योग		**12,33,538** **(2,48,633)**	**100.00**

स्रोत: एफडीआई सांख्यिकी, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2015/india_FDI_March2015.pdf

7.6 निष्कर्ष

एनसीआर में औद्योगिक और अन्य निवेश नीतियां शुरू में 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प और 1977 और 1980 के बाद के नीति वक्तव्यों में निहित थीं। इनमें से अधिकांश नीतियों ने माध्यमिक क्षेत्र पर जोर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 1982 में एनसीटी दिल्ली में 25% से बढ़कर 1999-2000 में लगभग 80% हो गया। 2000 के बाद, हालांकि, प्रवृत्ति उलट गई, माध्यमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 20% तक गिर गई और तृतीयक क्षेत्र 80% की हिस्सेदारी के साथ हो गया। इस प्रवृत्ति ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छलांग के कारण भारत के सेवा-क्षेत्र के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया।

अर्थव्यवस्थाओं का वैश्वीकरण, कम लागत वाले गंतव्यों के लिए आउटसोर्सिंग की प्राथमिकता और भारत के शिक्षित और अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारी के कारण भारत एक प्रमुख आईटी, आईटीईएस और आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में उभरा है। समय के साथ, आउटसोर्सिंग न केवल सॉफ्टवेयर में बल्कि इंजीनियरिंग, डिजाइन, परामर्श और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी एक ट्रेंड बन गई है। जबकि आईटी/आईटीईएस और वित्तीय सेवा क्षेत्र के विकास ने भारत में सेवा क्षेत्र के विकास का नेतृत्व किया, एनसीआर सेवा क्षेत्र में व्यापार और खुदरा और आईटी, आईटीईएस का वर्चस्व बना हुआ है। नतीजतन, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे एनसीआर के उप-क्षेत्र, दिल्ली से निकटता का लाभ उठाते हुए, एक आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग हब के रूप में विकसित हुए हैं।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

गुड़गांव मेट्रो रेल लिंक गुड़गांव में व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस तरह गुड़गांव को एनसीआर में एक महत्वपूर्ण विकास स्थान बना रहा है। यदि मेट्रो लाइन को मानेसर तक बढ़ा दिया जाता है, तो यह मानेसर के विकास को और गति देगा। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे भी निर्माणाधीन है। इसके निर्माण के बाद ये तीन स्थान हरियाणा उपक्षेत्र के प्रमुख विकास केंद्र होंगे।

इसलिए, 2000 के बाद एनसीआर के लिए पहले की निवेश और औद्योगिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि पिछली अधिकांश नीतियां बदलते आर्थिक परिदृश्य को संभालने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं थीं, जहां सेवाएं और तकनीकी प्रगति आर्थिक विकास की आधारशिला बन गई है। इसके अलावा, वैश्वीकरण और उदारीकरण ने नई चुनौतियों और अवसरों को जन्म दिया है, जिसके लिए औद्योगिक, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो कि अधिकांश नीतियों में परिलक्षित होता है।

8. मुद्दे और सिफारिशें

8.1 प्रमुख मुद्दे - पृष्ठभूमि

एनसीआर तेजी से एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है और 2005-06 से 2009-10 के दौरान लगातार कीमतों 2004-05), पर राष्ट्रीय स्तर पर 8.7% के एएजीआर के मुकाबले 11.2% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) के साथ भारत में सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। एनसीआर अर्थव्यवस्था सर्विस क्षेत्र द्वारा संचालित है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद (2007-08) का 67 प्रतिशत है। एनसीआर जीडीपी के मुख्य चालक मेक इन इंडिया के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक संयुक्त उद्यमों और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग से आना चाहिए। यह देखा गया है कि एनसीआर उप-क्षेत्रों में, हरियाणा उप-क्षेत्र अन्य उप-क्षेत्रों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न उप-क्षेत्रों की आर्थिक संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों में अभी भी कृषि गतिविधियों का प्रभुत्व है, जबकि हरियाणा उप-क्षेत्र औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का मिश्रण है। हरियाणा उप-क्षेत्र में गुड़गांव जिले ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई है, मुख्य रूप से आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के तेजी से विकास के कारण, जबकि हरियाणा उप-क्षेत्र में पानीपत जिला एक प्रमुख व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। दूसरी ओर, राजस्थान उप-क्षेत्र में अलवर जिला मुख्य रूप से कृषि-केंद्रित अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

एनसीआर अपनी स्थापना के बाद से विकास के विभिन्न चरणों से गुजरा है। 70 के दशक से इस सहस्राब्दी के अंत तक, दिल्ली के एनसीटी में बढ़ते प्रवासन विकास का महत्वपूर्ण मुद्दा था, जबकि 2000 के बाद एनसीआर के अन्य हिस्सों ने मजबूत आर्थिक चुंबक के रूप में विकास करना शुरू कर दिया है और महत्वपूर्ण विकास संबंधी चिंता अन्य क्षेत्रों को कैसे बनाया जाए, इस पर स्थानांतरित हो गई है। आर्थिक रूप से मजबूत एनसीआर एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2001 और बाद में एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की तैयारी के साथ एक एकीकृत योजना प्रक्रिया शुरू हुई। जैसा कि संकेत दिया गया है, वर्तमान में महत्वपूर्ण विकास मुद्दा सतत विकास सुनिश्चित करने के अलावा एनसीआर की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। मुख्य चुनौती इस तथ्य में निहित है कि एनसीआर में विकास विषम रहा है; पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि और संरचना के परिमाण के अंतर हैं जिन्हें दूर करने की जरुरत है।

आर्थिक गतिविधियों के विश्लेषण से पता चलता है कि खुदरा व्यापार न केवल एनसीआर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है बल्कि विनिर्माण के बाद रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आई है, एनसीटी-दिल्ली में विकास के मामले में, यह समग्र एनसीआर अर्थव्यवस्था में प्रमुख रोजगार उत्पान करने वाले

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

में से एक बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ने एनसीटी-दिल्ली, विशेष रूप से फरीदाबाद, नोएडा, आदि की सीमा से लगे शहरों में पर्याप्त एकाग्रता दिखाई है।

यह अध्याय एनसीआर के समग्र विकास के लिए मुद्दों का सार प्रस्तुत करता है और क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एनसीआर में भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जा सकने वाली परियोजनाओं के प्रस्ताव के अलावा सिफारिशें भी प्रदान करता है।

8.2 मुद्दे

8.2.1 एनसीआर में आर्थिक विकास के स्तर में व्यापक बदलाव

जीडीपी वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में असमानता में व्यापक भिन्नता है। 2009-10 में, एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र ने उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद (16,98,389.80 मिलियन रुपये) दर्ज किया है, इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र (8,66,730.30 मिलियन रुपये), उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (5,06,453.18 मिलियन रुपये) और राजस्थान उप-क्षेत्र (1,21,901.00 मिलियन रुपये) दर्ज किया है।

2004-05 से 2009-10 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के संदर्भ में, हरियाणा उप-क्षेत्र ने 11.7% (सीएजीआर) पर उच्चतम विकास दर दर्ज की थी, इसके बाद दिल्ली उप-क्षेत्र में 11.10% (सीएजीआर), राजस्थान उप-क्षेत्र 9.50% (सीएजीआर) और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र 8.78% (सीएजीआर), जबकि इसी अवधि के दौरान एनसीआर स्तर पर सीएजीआर 10.83% था।

2009-10 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में, एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र ने सबसे अधिक (98,262 रुपये) दर्ज किया है, इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र (74,457 रुपये), उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (35,036 रुपये) और राजस्थान उप-क्षेत्र (29,300 रुपये) है। हालांकि, 2004-05 के दौरान प्रति व्यक्ति आय का सीएजीआर हरियाणा उप-क्षेत्र (10.65%) में सबसे अधिक रहा है, इसके बाद एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र (9.00%), राजस्थान उप-क्षेत्र (7.17%) और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (6.53%) है।

उपरोक्त इंगित करता है कि जहां हरियाणा उप-क्षेत्र एनसीआर में सबसे तेज दर से बढ़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र और राजस्थान उप-क्षेत्र की विकास दर एनसीआर की तुलना में कम है।

एनसीआर अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी घट रही है; एक मजबूत तृतीयक क्षेत्र एनसीटी-दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में उभर रहा है। हालांकि, राजस्थान और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र अभी भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है [उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के एलक्यू में प्राथमिक क्षेत्र के लिए एलक्यू में परिवर्तन सकारात्मक (0.22) है और 2000-01 से 2005-06 के दौरान माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। राजस्थान उप-क्षेत्र के मामले में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है)। दूसरी ओर, एनसीटी-दिल्ली और हरियाणा उप-क्षेत्रों में, इसी अवधि के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जो इन दो उप-क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र के एलक्यू में कमी से स्पष्ट है। इसका श्रेय उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों में अपेक्षाकृत धीमी गति से शहरीकरण और औद्योगीकरण को दिया जा सकता है (तालिका 8.1 देखें)।

2005 में व्यक्तियों के एलक्यू का विवरण, ग्रामीण और शहरी उद्यमों के साथ-साथ जीडीपी (क्षेत्र-वार) के एलक्यू और 2000-01 से 2005-06 तक विकास दर का विवरण अनुलग्नक-8.1 में दिया गया है। स्थिर मूल्यों (1999-00) पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का एलक्यू क्रमशः अनुलग्नक-8.2 से

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

अनुलग्नक-8.4 में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और एनसीआर के लिए उद्यमों के प्रकार के आधार पर व्यक्तियों का एलक्यू क्रमशः अनुलग्नक-8.5 से अनुलग्नक-8.7 में दिया गया है।

T तालिका 8-1: एलक्यू जीडीपी 2000-01 और 2005-06

जिला / क्षेत्र	प्राथमिक			द्वितीयक			तृतीयक		
	LQ2000 -01	**LQ2005 -06**	परिवर्तन	**LQ2000 -01**	**LQ2005 -06**	परिवर्तन	**LQ2000 -01**	**LQ2005 -06**	परिवर्तन
मेरठ	2.51	3.31	0.80	1.08	0.88	-0.20	0.68	0.71	0.03
बागपत	4.22	4.28	0.06	0.44	0.56	0.11	0.63	0.70	0.07
गाज़ियाबाद	1.58	2.09	0.51	1.43	1.28	-0.15	0.71	0.72	0.01
गौतम बुद्ध नगर	1.35	1.04	-0.32	1.91	2.13	0.22	0.54	0.51	-0.03
बुलंदशहर	3.63	3.86	0.23	0.78	0.82	0.03	0.60	0.65	0.05
यूपी उप-क्षेत्र	**2.39**	**2.61**	**0.22**	**1.23**	**1.25**	**0.02**	**0.64**	**0.65**	**0.01**
पानीपत	1.47	1.38	-0.09	0.96	0.84	-0.12	0.93	1.01	0.08
सोनीपत	3.12	2.65	-0.47	0.81	1.07	0.26	0.68	0.72	0.04
रोहतक	2.29	2.77	0.48	1.00	0.84	-0.16	0.76	0.80	0.05
झज्जर	2.17	2.41	0.25	1.42	1.40	-0.02	0.60	0.62	0.02
रेवाड़ी	1.63	1.70	0.07	1.47	1.68	0.21	0.68	0.60	-0.08
गुड़गाँव	0.77	0.31	-0.45	1.56	1.51	-0.05	0.80	0.88	0.08
फरीदाबाद	1.06	0.98	-0.08	1.55	1.34	-0.21	0.75	0.86	0.10
हरियाणा उप-क्षेत्र	**1.43**	**1.22**	**-0.21**	**1.36**	**1.31**	**-0.05**	**0.77**	**0.83**	**0.07**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**0.12**	**0.11**	**-0.01**	**0.73**	**0.73**	**0.00**	**1.28**	**1.25**	**-0.03**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**2.43**	**3.02**	**0.59**	**1.11**	**1.11**	**0.00**	**0.68**	**0.65**	**-0.03**

स्रोतः एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन

8.2.2 कार्यबल

(a) एनसीटी-दिल्ली को छोड़कर सभी उप-क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न रोजगार

एनसीआर में कर्मचारी के वितरण के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि श्रमिकों का पर्याप्त हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है (राजस्थान उप-क्षेत्र ने सबसे अधिक 77 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया है, इसके बाद हरियाणा उप-क्षेत्र में 52%, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के साथ लगभग 48%) है।

2001 की जनगणना के अनुसार, एनसीआर में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में कुल 129.72 लाख

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल कामकाजी आबादी में, श्रमिकों का सबसे बड़ा अनुपात (45.02%) प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र (31.60%) और सबसे कम (24.86%) तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं। हरियाणा (57.93%), उत्तर प्रदेश (55.34%) और राजस्थान (79.96%) उप-क्षेत्रों में, अधिकांश कर्मचारी प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। द्वितीयक क्षेत्र के मामले में, एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में श्रमिकों की उच्चतम हिस्सेदारी (48.58%) दर्ज की गई है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (25.41%), हरियाणा (25.13%) और राजस्थान (12.07%) उप-क्षेत्र हैं।

2001 और 2011 में कृषि गतिविधियों (खेती करने वाले और खेतिहर मजदूरों) में लगे श्रमिकों के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि सभी उप-क्षेत्रों में, इन दो श्रेणियों में लगे श्रमिकों के अनुपात में कमी आई है (एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र के मामले में, अनुपात में नगण्य वृद्धि हुई है)। हालांकि, राजस्थान उप-क्षेत्र के मामले में, श्रमिकों का महत्वपूर्ण अनुपात (2011 में 65.30%) अभी भी इन दो श्रेणियों में लगा हुआ है (तालिका 8.2 देखें)।

तालिका **8-2:** खेती में लगे श्रमिक (खेती करने वाले और कृषि मजदूर

उपक्षेत्र	खेती में लगे मजदूर			
	2001		**2011**	
	संख्या	कुल श्रमिकों का %	संख्या	कुल श्रमिकों का %
एनसीटी दिल्ली उपक्षेत्र	53,204	1.22%	72,873	1.30%
हरियाणा उपक्षेत्र	972,007	38.63%	1,250,844	34.09%
उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र	1,110,693	38.00%	1,526,954	31.81%
राजस्थान उपक्षेत्र	1,033,649	70.83%	1,115,663	65.30%

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001 और 2011

गैर-कृषि गतिविधियों में श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, उप-क्षेत्रों में, विशेष रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, लघु उद्योगों (एसएसआई) का मदद करने के लिए एक सुविधाजनक कारोबारी माहौल बनाने की जरुरत है, जिसमें रोजगार सृजन के लिए बड़ी क्षमता है। यह स्पष्ट है कि केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली उप-क्षेत्र में लघु उद्योगों की तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि अन्य उप-क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का नेतृत्व बड़े पैमाने के उद्योगों ने किया है। इन उप-क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रभावी रोजगार नीति तैयार करने की जरुरत है।

(b) एनसीआर में मुख्य कार्यबल का असमान वितरण

मुख्य और सीमांत श्रेणियों में कार्यबल के वितरण का विश्लेषण इंगित करता है कि सीमांत श्रमिकों की एकाग्रता (एनसीआर में कुल सीमांत श्रमिकों के लिए उप-क्षेत्र में सीमांत श्रमिकों की हिस्सेदारी) उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (37.91%) में सबसे अधिक है, इसके बाद हरियाणा (29.75%), राजस्थान (21.16%) और एनसीटी-दिल्ली (11.18%) उप-क्षेत्र का स्थान है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के माध्यम से स्थिर रोजगार के अवसर प्रदान करने की जरुरत है, जो रोजगार सृजन में मदद करता है।

8.2.3 औद्योगिक विकास

केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले निकटवर्ती नगरों में आर्थिक गतिविधियों को तितर-बितर करने की नीतियों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों ने इन नगरों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया। प्रदूषण

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

फैलाने वाले और खतरनाक उद्योगों को एनसीटी-दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है; हालाँकि, इसमें निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं:

- अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में अपर्याप्त गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति;
- प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रभावी उपचार और निपटान के बुनियादी ढांचे का अभाव;
- तत्काल आसपास के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की सीमित उपलब्धता और जनशक्ति की सामान्य कमी;
- सामान्य सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली का अभाव, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को फलने-फूलने में कठिनाई होती है;
- भूमि अधिग्रहण और भूमि की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे; तथा
- एसईजेड/ईपीजेड योजना के अनुसार विकसित करने में असमर्थ।

एनसीआर में औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी विकास के लिए आवश्यक समग्र सुपर संरचना और कारोबारी माहौल में सुधार की जरूरत है।

8.2.4 ग्रामीण अर्थव्यवस्था

रुझान ग्रामीण आबादी में सामान्य कमी और ग्रामीण कार्यबल में बहुत मामूली वृद्धि दिखाते हैं। रुझान कृषि आधारित रोजगार से माध्यमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र (सेवा उन्मुख रोजगार) में प्रमुख आर्थिक चालक बनने के लिए एक बदलाव को भी प्रदर्शित करते हैं। जबकि एनसीटी-दिल्ली में ग्रामीण आबादी और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबंधित संस्थानों में कमी देखी गई है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्रों में विपरीत रुझान देखा गया है। यह इंगित करता है कि जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली में कार्यबल गैर-कृषि रोजगार की ओर बढ़ रहा है, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ अभी भी शेष उप-क्षेत्रों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई हैं।

(a) सीमित गैर-कृषि क्षेत्र रोजगार

एनसीआर के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार के विकल्प सीमित हैं। कृषि और गैर-कृषि संस्थानों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या का विश्लेषण इंगित करता है कि अधिकांश गैर-कृषि क्षेत्र का रोजगार हरियाणा उप-क्षेत्र (2005 में 3.13 लाख) में केंद्रित है, इसके बाद उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र (2005 में 2.42 लाख) है। इन दो उप-क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज कुल श्रमिकों की संख्या की तुलना में 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि संस्थानों में लगे श्रमिकों की संख्या नगण्य है (भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा उप-क्षेत्र और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रमिकों की संख्या क्रमशः 20.95 लाख और 25.13 लाख दर्ज की गई थी)।

(b) अपर्याप्त ग्रामीण आधारभूत संरचना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास मंडी और विपणन सुविधाओं के रूप में ग्रामीण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एनसीआर में अधिकांश मंडियां अभी भी विपणन की पारंपरिक प्रणालियों का पालन करती हैं और उनके पास अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और सहयोग प्रणाली है। उदाहरण के तौर पर सामान्य भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं हैं; जो संख्या में सीमित हैं और केंद्रीकृत हैं। इनमें से ज्यादातर एनसीटी-दिल्ली के आसपास के इलाके में हैं। यह किसानों द्वारा कृषि उपज की बिक्री में कमी की ओर ले जाता है और इसलिए, ग्रामीण आय की कम वृद्धि पर इसका सीधा असर पड़ता है।

(c) सीमित कृषि प्रसंस्करण सुविधाएं

पिछले कुछ वर्षों में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के फल और सब्जियों के उप-क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

हालांकि, कुल मिलाकर कृषि आधारित उद्योग बहुत सीमित हैं। वर्तमान में, चावल मिलों, खांडसारी और गुड़ (गुड़) बनाने वाली इकाइयाँ जैसे पारंपरिक कृषि-उद्योग एनसीआर में प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, पानीपत एनसीआर के उन स्थानों में से एक है जो अचार बनाने में कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धी होने के लिए इन इकाइयों का तकनीकी उन्नयन किया जाए। उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र और हरियाणा उप-क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी भाग अच्छी सिंचाई सुविधाओं के साथ कृषि उत्पादों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए संभावित क्षेत्र हैं।

8.2.5 अनौपचारिक क्षेत्र

अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार को मुख्यधारा में लाने की जरूरत है। इस क्षेत्र में कामगारों के खराब कौशल के कारण अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार को आम तौर पर कम वेतन मिलता है। कम कौशल के संभावित कारणों में कौशल-निर्माण सुविधाओं का लाभ उठाने के अवसर की कमी है। इसलिए, इस क्षेत्र में लगे अधिकांश परिवार पीढ़ियों से गरीबी चक्र से बचने में असमर्थ हैं। इस गरीबी चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यबल के मौजूदा कौशल में सुधार करना है।

टेलर-मेड तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो मौजूदा कार्यबल की आवश्यकताओं के अनुरूप है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में मौजूदा अनौपचारिक श्रमिकों को शामिल करके उनके कौशल उन्नयन के लिए एक तंत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से सेवाकालीन प्रकृति के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना भी अनिवार्य है। यदि श्रमिकों की वर्तमान पीढ़ी की आय में इस तरह से वृद्धि की जाती है, तो वे अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रशिक्षण में सहयोग करने की स्थिति में हो सकते हैं।

कटिंग, सिलाई कपड़ा, बढ़ईगीरी, वेल्डिंग, प्लंबिंग आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। परिधान उद्योग में अधिकांश डिजाइन कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के कौशल निर्माण से उन्हें वैकल्पिक रोजगार के लिए तैयार करने की भी संभावना है। महिलाओं को पापड़, मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाना सिखाकर वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के पारंपरिक साधन बहुत कम काम के हैं, क्योंकि वे परिवारों के लिए गरीबी के स्तर से स्थायी रूप से ऊपर उठने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं करते हैं। उद्योग की जरूरतों और संबंधित लोगों की सीखने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए नए कार्यक्रमों की आवश्यकता है। एनसीआर में कई मौजूदा क्राफ्ट क्लस्टर हैं। हालांकि, अपर्याप्त सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) हैं। इसी तरह, एक अन्य महत्वपूर्ण श्रेणी जिसमें बहुत बड़ी संख्या में अनौपचारिक रोजगार मौजूद हैं, वह है स्ट्रीट वेंडिंग। एनसीआर के प्रमुख विकास केंद्रों में स्ट्रीट वेंडर अनौपचारिक रोजगार का एक बड़ा हिस्सा हैं। उनकी आजीविका की निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक शहरी नियोजन तंत्र में पथ विक्रेताओं के साथ-साथ उनके स्थानों को एकीकृत करने की तत्काल जरुरत है।

8.2.6 जिला स्तर पर एक समान जीडीपी डेटा

वर्तमान में, जीडीपी डेटा को जिला स्तर पर एकत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि राज्य स्तर के जीडीपी डेटा को अलग करके प्राप्त किया जाता है। सीएसओ दृष्टिकोण के अनुसार जिला स्तर पर जीडीपी डेटा को कैप्चर करना एनसीआर के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति और विकास को समझने में अधिक मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा, यह अनुशंसा की जाती है कि बेहतर तुलना और अनुकूलता के लिए एनसीआर में जिला स्तरीय जीडीपी डेटा कैप्चरिंग एक समान होनी चाहिए।

8.3 उप-क्षेत्रवार मुद्दे

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

8.3.1 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र

एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र ने एनसीआर के अन्य उप-क्षेत्रों की तुलना में बेहतर जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और विभिन्न श्रेणियों में कार्यबल का वितरण दर्ज किया है। विकास दर और क्षेत्रीय रुझान बहुत बड़े शहरों के वैश्विक रुझानों के अनुरूप हैं। हालांकि, चिंता के कुछ बिंदु हैं, जो निम्न हैं:

a) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपर्याप्त सहायता प्रदान की गई;
b) औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे (सड़क, पानी, स्वच्छता आदि) का अपर्याप्त स्तर; तथा
c) शहरी केंद्रों में फलने-फूलने वाले शिल्प आधारित अनौपचारिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक नीति का अभाव।

8.3.2 हरियाणा उप-क्षेत्र

हरियाणा उप-क्षेत्र मुख्य रूप से तीन तरफ एनसीटी-दिल्ली से सटे होने के अपने स्थानीय लाभ और पिछले दशक में किए गए बुनियादी ढांचे के निवेश के कारण औद्योगिक विकास के तेज ट्रैक पर है। हालाँकि, अधिक संतुलित दृष्टिकोण के लिए निम्नलिखित पर ध्यान देने की जरुरत है:

a) कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त ग्रामीण बुनियादी ढांचा;
b) औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त स्तर;
c) उद्योगों के लिए बिजली की उपलब्धता की अपर्याप्त गुणवत्ता;
d) औद्योगिक शहरों में, विशेष रूप से बहादुरगढ़, फरीदाबाद, पानीपत आदि में प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर;
e) केएमपी एक्सप्रेसवे और कुछ एसईजेड जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर धीमी प्रगति;
f) एमएसएमई को अपर्याप्त समर्थन और प्रमुख औद्योगिक समूहों में संरचित क्लस्टर विकास कार्यक्रमों का अभाव; तथा
g) मेवात, झज्जर और रेवाड़ी जिलों में आर्थिक विकास के न्यूनतम स्तर के कारण, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है।

8.3.3 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

आर्थिक विकास के मामले में कम प्रगति की सूचना है। उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

a) मेरठ जैसे मौजूदा औद्योगिक समूहों के तकनीकी उन्नयन के लिए प्रभावी हस्तक्षेपों का अभाव, उनके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को प्रभावित करना;
b) मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में सहायता बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त स्तर, जिससे गाजियाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में वाहनों की भीड़ और प्रदूषण होता है;
c) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक व्यापक नीति का अभाव;
d) खुर्जा जैसे पारंपरिक शिल्प समूहों के लिए आवश्यक स्तर के सहायता का अभाव; तथा
e) गैर-कृषि गतिविधियों के विकास के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे की कमी।

सहगल फाउंडेशन द्वारा आयोजित अध्ययन का विषय "हरियाणा में मेवात क्षेत्र के पिछड़ेपन की पहचान करना: एक ब्लॉक स्तरीय विश्लेषण" है। जिसे अनुसंधान विभाग, नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है, भारत सरकार ने विभिन्न पहलुओं/मापदंडों जैसे कि शैक्षिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

वित, जीवन स्तर आदि में पिछड़ेपन के स्तर की पहचान की है। उक्त अध्ययन ने जिले के भीतर ब्लॉकों में पिछड़ेपन की टाइपोलॉजी को भी मैप किया है।

8.3.4 राजस्थान उप-क्षेत्र

राजस्थान उप-क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों के साथ कम विकास दर दर्ज की गई है। इस उप-क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

a) मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में खराब बुनियादी ढांचा (बिजली और पानी);

b) गैर-कृषि गतिविधियों के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा मुनासिब नहीं है; तथा

c) औद्योगिक विकास का विकास पड़ोसी उप-क्षेत्रों की तुलना में सीमित है।

8.4 नीति प्रतिक्रिया

8.4.1 पृष्ठभूमि

लंबे समय में एनसीआर के विकास के लिए चार मुख्य चालक, अर्थात् जनसंख्या, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी होंगे। उम्र, शहरीकरण और घर के बदलते आकार की दृष्टि से एनसीआर में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। इसका सीधा असर एनसीआर में जनशक्ति के प्रकार और स्तर और बाजार की मांग की संरचना पर पड़ेगा। शहरीकरण में वृद्धि से लंबवत जुड़े उद्योगों पर भी मूल इकाइयों के पास स्थित होने का दबाव पड़ेगा। एनसीआर में आवास, ऊर्जा, भोजन, पानी और परिवहन की मांग बढ़ेगी।

8.4.2 पर्यावरण प्रदूषण

तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण से दुर्लभ संसाधनों पर सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उपयोग किए जाने का दबाव बढ़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए, एनसीआर भाग लेने वाली राज्य सरकारों को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के उद्देश्य से उद्योगों और अन्य आर्थिक गतिविधियों के स्थान के लिए ठोस योजनाओं के साथ आने की आवश्यकता है।

8.4.3 उपसंविदा और प्रमुख संबंधों की प्रकृति बदलना

इनपुट सप्लायर्स और प्रमुख विनिर्माताओं के संबंधों में बदलाव आने वाला है। अगले 25-30 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र का व्यवहार विशेष प्रकृति का होगा। विभिन्न आकारों/रणनीतिक प्रकृति के उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा उनके जोखिम को कम करने के लिए बढ़ेगी। जोखिम को शक्तिशाली से कम शक्तिशाली और अधिक स्वतंत्र से आश्रित उद्योगों में पुनर्वितरित किया जाएगा। विशेष रूप से, एमएसएमई के आर्थिक अस्थिरता से अधिक प्रभावित होने की संभावना है। कम लागत, दक्षता और लचीलेपन की मांग बढ़ने की संभावना है। इसलिए, एमएसएमई नीतियों को इस तरह से उन्मुख करना आवश्यक है कि सिद्धांतों पर उनकी रणनीतिक निर्भरता को कम किया जा सके। एमएसएमई को उनकी लागत को कम करने में मदद करने के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उत्पादन में दक्षता और लचीलेपन में सुधार हो सके।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

[4] आपूर्ति और उत्पादन के लिए कम लीड टाइम जैसे मारुति उद्योग ने अपने विक्रेताओं के लिए मांग प्रोजेक्शन को 6 महीने से कुछ हफ्तों तक कम कर दिया जिसके परिणामस्वरूप कम समय के दौरान उच्च उत्पादन भिन्नताएं और छोटे विक्रेताओं के लिए काफी नुकसान/इन्वेंटरी होती हैं।

8.4.4 नैनो प्रौद्योगिकी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए, एनसीआर के प्रौद्योगिकी आधार को पूरी तरह से नया रूप दिया जा रहा है। अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। वर्तमान में, एनसीआर में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए काफी अच्छा आधार है। उद्योग और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास प्रदान करने के लिए ज्ञान केंद्रों को विकसित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं। राय (सोनीपत), रोहतक और ग्रेटर नोएडा अच्छे ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे और केंद्र स्थापित करने की जरुरत है।

8.4.5 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

योजना प्रक्रिया में हितधारकों को शामिल करने के लिए पीपीपी को स्थान और औद्योगिक नीतियों का एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित हाल के मुद्दों ने पीपीपी की आवश्यकता को और उजागर किया है। धीरे-धीरे, एनसीआर में आर्थिक गतिविधियों के मुख्य प्रदाता के रूप में सरकार की भूमिका एक सूत्रधार की होगी। पीपीपी व्यापार चक्र के प्रभाव को कम करने और टर्न-अराउंड समय को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

यह उम्मीद की जाती है कि जैव प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी और ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों का एनसीआर की अर्थव्यवस्था पर मजबूत प्रभाव पड़ेगा। बहुत कम समय में उत्पाद नवाचारों और गहन ज्ञान के आधार के लिए प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पाद नवाचार चक्र और कम हो जाएंगे।

विकास के लिए इन प्राथमिकताओं के इर्द-गिर्द भविष्य की नीति विकसित करने की जरूरत है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उप-क्षेत्रों के जिले, जो एनसीटी-दिल्ली से सटे हैं, औद्योगिक मोर्चे पर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन दोनों उप-क्षेत्रों के अन्य जिलों में भी अपार संभावनाएं हैं। 2000 के बाद एनसीटी-दिल्ली का औद्योगिक शासन, विशेष रूप से 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, एनसीआर की अर्थव्यवस्था की संरचना में परिलक्षित होता है। तत्काल परिणाम में से एक एनसीटी-दिल्ली के बाहर औद्योगिक समूहों का विकास है जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, आदि।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से एनसीआर घटक राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की मौजूदा औद्योगिक नीतियों ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल के विकास का प्रावधान किया है। उदाहरण के लिए, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क (एसआईटीपी) के लिए योजना में कपड़ा उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे की परिकल्पना विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा केंद्र सरकार के आंशिक समर्थन और निजी क्षेत्र के हितधारकों द्वारा की गई है। आवश्यक संगठनात्मक और व्यक्तिगत क्षमता प्रदान करने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह, केंद्र सरकार की योजनाओं (ऑटो कॉम्पोनेन्ट, खादय प्रसंस्करण, आदि) में सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास और सामान्य क्लस्टर विकास के लिए और एमएसएमई मंत्रालय की योजना का उपयोग एनसीआर में औद्योगिक समूहों के विकास के लिए

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

किया जा सकता है।

8.5 सिफारिशें

8.5.1 क्षेत्र-विशिष्ट सिफारिशें

मौजूदा आर्थिक गतिविधियों के विश्लेषण के साथ-साथ एनसीआर के विभिन्न उप-क्षेत्रों/जिलों/क्षेत्रों की संभावनाओं के आधार पर, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

(a) कृषि आधारित और खादय प्रसंस्करण उदयोग

- हरियाणा उप-क्षेत्र में खादय परीक्षण प्रयोगशालाएं।
- बागवानी उपज के लिए बुलंदशहर और झज्जर के क्षेत्र में फल और सब्जी प्रसंस्करण पार्क।

(b) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

- एनसीआर में अनुमोदित और परिचालन आईटी/आईटीईएस एसईजेड की संख्या के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित एसईजेड के संचालन के लिए उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप किए जाएं।
- एनसीटी-दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में सॉफ्टवेयर विकास (विशेषकर एनसीटी-दिल्ली के मामले में गहनता की आवश्यकता है)।

(c) ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स

- ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेट के लिए आईएमटी मानेसर और बावल में प्रेरित क्लस्टर (कुशल श्रमशक्ति और श्रमिकों के छात्रावास आदि जैसे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है)
- ऑटो-पार्क (जैसे अलवर में आगामी ऑटो-पार्क) और अनुसंधान संस्थानों (जैसे हरियाणा में आगामी राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण, अनुसंधान और विकास बुनियादी ढांचा परियोजना) के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज सहित सहायता बुनियादी ढांचे का पर्याप्त स्तर स्थापित किया जाना है।
- फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, मेरठ और अलवर के लिए ऑटो कंपोनेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट

(d) हथकरघा, होजरी, कपड़ा और वस्त्र निर्माण

- भारत सरकार की निर्यात योजना के लिए परिधान पार्क के तहत गुड़गांव एसईजेड और बरही (सोनीपत) में परिधान पार्क।
- पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन सेंटर।
- वस्त्रों के प्रचार के लिए गुड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र।
- अलवर जिले में टेक्सटाइल पार्क।
- फरीदाबाद और गाजियाबाद जिलों में रंगाई घर।
- ओखला में वस्त्र कौशल विकास केंद्र

(e) जूते, चमड़े के वस्त्र और सहायक उपकरण

- बहादुरगढ़, हरियाणा में चमड़े के विकास के लिए बुनियादी ढांचा।.

(f) सामान्य इंजीनियरिंग

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

- सामान्य इंजीनियरिंग के लिए बुनियादी ढांचा विकास (फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव)।

(g) रसद

- डीएफसी और डीएमआईसी परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्रों का हिस्सा शामिल है, यह अनुशंसा की जाती है कि इन उप-क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे रसद बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाए।

8.5.2 क्लस्टर विशिष्ट सिफारिशें

(a) ऑटो-कंपोनेंट (मेरठ, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा)

तकनीकी उन्नयन के लिए एक मजबूत आवश्यकता है। अधिकांश इकाइयों में साधारण कटिंग और ड्रिलिंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। चूंकि अधिकांश इकाइयां या तो सूक्ष्म या छोटी हैं, इसलिए मशीनों का पूर्ण स्वचालन नहीं हुआ है। उन्नत उपकरण शुरू करने, शॉप फ्लोर प्रथाओं में सुधार, गुणवत्ता प्रणालियों को प्रेरित करने और मानकीकरण को बढ़ावा देने की संभावना है।

(b) हथकरघा और पावरलूम (पानीपत और मेरठ)

क्लस्टर को डिजाइन, कार्यकर्ता के कौशल उन्नयन और बेहतर रंगाई प्रथाओं में इनपुट की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस क्लस्टर की मदद के लिए मौजूदा संस्थागत प्रणालियां हैं और अन्य विकास एजेंटों की भागीदारी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) योजना का लाभ उठाकर नई तकनीक के उपयोग को प्रेरित करने के लिए कम कुशल हो सकती है लेकिन क्लस्टर को बहुत लंबे समय तक मदद की जरुरत हो सकती है। यह देखते हुए कि इसका व्यावहारिक रूप से कोई प्रत्यक्ष बाजार संबंध नहीं है और अन्य समान समूहों की तुलना में कम उत्पादक है।

(c) खेल के सामान (मेरठ)

क्लस्टर में विनिर्मित वस्तुओं के मौजूदा सेट के भीतर तकनीकी उन्नयन की अपार संभावनाएं हैं। इससे भी बड़ी गुंजाइश नए खेल क्षेत्रों में विविधता लाने की है। इस प्रकार, इस क्लस्टर में उत्पादकता को बढ़ावा देने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। हालाँकि, विकास के लिए कई प्रयास पहले ही किए जा चुके हैं / चल रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए पहले से ही एक तकनीकी संस्थान समर्पित है।

(d) कपड़ा (ओखला, गुड़गांव)

मुख्य फोकस गुणवत्ता सुधार, तकनीकी उन्नयन, कौशल वृद्धि और उद्यमियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। निम्नलिखित नरम गतिविधियों का सुझाव दिया जाता है:

- रूम लेआउट और वर्कफ़्लो काटना;
- अनुत्पादक निर्माण;
- जनशक्ति प्रशिक्षण;
- प्रबंधन की गुणवत्ता; तथा
- उत्पादन सुधार योजना (प्रौद्योगिकी अपनाना)।

(e) सामान्य इंजीनियरिंग (फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव)

सामान्य इंजीनियरिंग क्षेत्र एनसीआर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उपरोक्त तीन स्थानों पर उद्योग प्रमुख एकाग्रता में मौजूद हैं। अधिकांश इकाइयाँ एमएसएमई प्रकृति की हैं और उन्हें विपणन पहल, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों में मदद की जरुरत है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

8.6 उप-क्षेत्रवार सिफारिशें

8.6.1 हरियाणा उप-क्षेत्र

2000 के बाद हरियाणा की अर्थव्यवस्था की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई है और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 1999-2000 में 41% से बढ़कर 2007-08 में 56% हो गई है। सेवा क्षेत्रों विशेष रूप से आईटी और आईटीईएस ने हरियाणा उप-क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे कुछ जिलों ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, उप-क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक सम्पदाओं, विशेषकर जहां प्रदूषणकारी उद्योग स्थित हैं, में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जिलेवार सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(a) गुड़गांव

गुड़गांव अधिक मूल्य वाले सेवाओं के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यह विश्लेषण में परिलक्षित होता है कि एनसीआर के सभी जिलों में इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गुड़गांव में कुछ प्रमुख क्षेत्र जिन्हें सुदृढ़ करने की जरुरत है वे हैं:

- गुड़गांव शहर की बेहतर इंट्रा-सिटी और इंटर-सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रेल और सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम प्रगति पर है। हालांकि, गुड़गांव को वित्तीय, बीमा, रियल एस्टेट और व्यापार सेवा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की जरुरत है।
- गुड़गांव का विनिर्माण आधार, विशेष रूप से कारों, मोटर-साइकिलों, ऑटोमोबाइल भागों, दूरसंचार उपकरणों, बिजली के सामान, सॉफ्टवेयर विकास, हार्डवेयर, खेल के सामान, रबर उत्पादों, रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में अतीत में सुधार हुआ है; हालांकि, एमएसएमई के लिए बिजली और महत्वपूर्ण सामान्य सुविधाओं के मामले में सहायता प्रणाली अपर्याप्त है। यह अनुशंसा की जाती है कि क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण कम से कम दो क्षेत्रों अर्थात् ऑटो कंपोनेंट और रेडीमेड गारमेंट्स में अपनाया जाए।

(b) फरीदाबाद

फरीदाबाद हरियाणा के सबसे पुराने औद्योगिक शहरों में से एक है। यह अनुशंसा की जाती है कि आवश्यक अवसंरचना प्रदान करके ऑटो पार्ट्स में थोक व्यापार के लिए बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित किया जाए। दिल्ली के साथ-साथ गुड़गांव और नोएडा/ग्रेटर नोएडा के निकट निकटता के अपने रणनीतिक स्थान के कारण, फरीदाबाद एक रियल एस्टेट गंतव्य के रूप में उभरा है क्योंकि निर्माण गतिविधियों में 1999-2000 से 2007-08 तक 17% की वृद्धि हुई है।

(c) सोनीपत

भूमि की उपलब्धता और सोनीपत की रणनीतिक स्थिति के साथ, बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां एनसीटी-दिल्ली से कुंडली और आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गईं। जिला, निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। जिला विभिन्न अत्याधुनिक ज्ञान क्षेत्रों में एनसीआर के लिए ज्ञान केंद्र

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

के रूप में काम करने के लिए तैयार है क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की है। एक खाद्य प्रसंस्करण ज्ञान केंद्र (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा निफ्टेम) पहले ही स्थापित किया जा चुका है। यह अनुशंसा की जाती है कि सोनीपत को ज्ञान और खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

(d) झज्जर

झज्जर में वर्तमान में व्यवसाय या औद्योगिक गतिविधियों का अभाव है। परंपरागत रूप से यह एक व्यापार और वाणिज्य केंद्र था, लेकिन इसके अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण तेजी से विकसित नहीं हो सका। हाल ही में झज्जर में एक बड़े बिजली संयंत्र की स्थापना से बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है। हाल ही में आने वाले बुनियादी ढांचे और निर्माण गतिविधियों के कारण, यह उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के लिए एक रणनीतिक स्थान बन गया है। महत्वपूर्ण ग्रामीण आधार को ध्यान में रखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि जिले में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के साथ-साथ एमएसएमई के लिए सहायक बुनियादी ढाँचा विकसित किया जाए। उद्यमिता विकास और अन्य सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के लिए एक प्रारंभिक बुनियादी ढांचा झज्जर जिले में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।

बहादुरगढ़, एनसीटी-दिल्ली के करीब होने के अपने स्थानीय लाभ के कारण, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि का अनुभव किया है, जो 1999-2000 की अवधि के दौरान एनसीआर के 7.5% के औसत के मुकाबले 17% की सीएजीआर से बढ़ी है। बहादुरगढ़ में सिरेमिक, कांच, रसायन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पादों की अच्छी संभावनाएं हैं। हरियाणा सरकार का उद्देश्य बहादुरगढ़ में फुटवियर उद्योगों को बढ़ावा देना है। केएमपी एक्सप्रेसवे जो बहादुरगढ़ के बहुत करीब है, से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की उम्मीद है और इससे बहादुरगढ़ की आर्थिक संरचना को बड़े पैमाने पर बदलने की उम्मीद है। यह अनुशंसा की जाती है कि इस क्षेत्र को एक प्रमुख सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच अच्छे रसद बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसे देखते हुए व्यापार और वाणिज्य केंद्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

(e) रोहतक

रोहतक रणनीतिक रूप से स्थित है और रेल और सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जिसमें कई तकनीकी और गैर-तकनीकी शैक्षणिक संस्थान हैं। हाल ही में, सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे फैशन डिजाइन और फिल्म निर्माण और प्रबंधन संस्थान के क्षेत्रों में अधिक तकनीकी शिक्षा सुविधाएं शुरू की हैं। सरकार ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में 'ग्रीन-फील्ड' गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। रोहतक का भविष्य प्रस्तावित नॉलेज सिटी के विकास में है। यह दूसरी पीढ़ी की आईटी और आईटीईएस सेवाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा स्थान हो सकता है और अत्याधुनिक आईटी और आईटीईएस स्थान बनने के लिए गुड़गांव के नक्शेकदम पर चल सकता है। केएमपी एक्सप्रेसवे के विकास से रोहतक जिले की अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा।

(f) पानीपत

पानीपत एक ऐतिहासिक शहर है और एनसीआर के अन्य शहरों से रेल और सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। शहर में हथकरघा और पावरलूम सहित वस्त्र उद्योग के कई उद्योग हैं। पानीपत का दरी, कालीन चटाई, टेबल कवर, बेड शीट, बेड कवर, पर्दा आदि उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत शहर दुनिया में नकली यार्न का सबसे बड़ा केंद्र भी है। इसमें प्रेरित रासायनिक पार्क स्थान की भी संभावना है। हालाँकि, जिले को पर्यावरणीय मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है क्योंकि औद्योगिक प्रदूषण

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

के लिए मौजूदा उद्योगों की उच्च क्षमता के कारण जिले में अधिकांश आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं हो सकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि मौजूदा हथकरघा और पावरलूम इकाइयों के तकनीकी उन्नयन के लिए उचित उपाय किए जाएं, ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। यह भी सिफारिश की जाती है कि अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, सामान्य सुविधा केंद्र प्रदान करके इन इकाइयों का उपयुक्त समूह स्थापित किया जाए

(g) रेवाड़ी

रेवाड़ी अन्य शहरों से रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान शहर है जहां शहर में बहुत सीमित लेकिन तेजी से आने वाली औद्योगिक गतिविधियां हैं। शहर व्यापार केंद्र और खुदरा बाजार के रूप में भीतरी इलाकों में कार्य करता है। जिले में स्थित दो बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास केंद्र धारूहेड़ा औद्योगिक परिसर और बावल विकास केंद्र हैं। इन दोनों स्थानों में भविष्य के औद्योगिक विकास में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि रेवाड़ी के रणनीतिक स्थान और मौजूदा और आगामी मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र के निकट निकटता को देखते हुए, एनसीआर में बड़े उद्योगों के सर्वोत्तम विकास के लिए रेवाड़ी जिले में भारी उद्योगों को आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(h) मेवात

भले ही जिला एनसीटी-दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह अविकसित रहा है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) द्वारा बनाई गई औद्योगिक संपदा का काफी हद तक कम उपयोग किया गया है। हालांकि, निकटवर्ती गुड़गांव जिले में पर्याप्त अचल संपत्ति गतिविधियों के कारण, मेवात जिले की भूमि की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। इससे आबादी के एक हिस्से के पास अचानक काफी पैसा हो गया है।

नियोजित रेवाड़ी-भिवाड़ी-पलवल रेलवे लाइन मेवात से होकर नूंह में इसके जिला मुख्यालय के पास से जायेगी। साथ ही, केएमपी एक्सप्रेसवे से भी मेवात की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यह अनुशंसा की जाती है कि मेवात जिले में सामाजिक-आर्थिक विकास की तुलनात्मक रूप से कम डिग्री के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय कम होने पर रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई और माध्यमिक क्षेत्र की गतिविधियों के विकास में हस्तक्षेप किया जाए। साथ ही मेवात जिले में मांस प्रसंस्करण उद्योगों की भी संभावनाएं हैं।

8.6.2 उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र

उत्तर प्रदेश सरकार उप-क्षेत्र में कई एसईजेड के विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश को गाजियाबाद, खुर्जा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जिले में साहिबाबाद और सूरजपुर सहित एनसीटी-दिल्ली के करीब औद्योगिक क्षेत्र होने का फायदा है। उप-क्षेत्र में आने वाले कुछ औद्योगिक पार्क और एसईजेड में नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और ग्रेटर नोएडा में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क शामिल हैं। डीएमआईसी परियोजना के हिस्से के रूप में, जिसमें गाजियाबाद-नोएडा-दादरी निवेश क्षेत्र आ रहा है, उप-क्षेत्र में रसद, माल ढुलाई और संबद्ध उद्योगों के लिए भी बड़ी संभावनाएं हैं। जिलेवार सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(a) गौतमबुद्ध नगर - नोएडा और ग्रेटर नोएडा

नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

औद्योगिक शहरों के रूप में उभरे हैं। बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग के कारण, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एक शैक्षिक पार्क के रूप में भी जाना जाता है। जिले में विशेष रूप से एफ 1 (फॉर्मूला वन) ट्रैक, यमुना एक्सप्रेसवे आदि के साथ एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनने की सभी विशेषताएं हैं। मौजूदा ज्ञान आधारित उद्योगों के साथ-साथ शहर की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उद्योग अनुसंधान एवं विकास में निवेश के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की जाती है कि विशेष रूप से एमएसएमई के लिए बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता में सुधार किया जाए।

(b) गाजियाबाद (हापुड़ सहित)

गाजियाबाद एक पुराना औद्योगिक शहर है और उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक औद्योगिक शहरों में से एक है। इस तथ्य के कारण कि औद्योगिक इकाइयां कुछ समय पहले स्थापित की गई थीं, यह अनुशंसा की जाती है कि इन औद्योगिक इकाइयों के तकनीकी उन्नयन के साथ-साथ औद्योगिक संपदाओं/समूहों के बुनियादी ढांचे में निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए सुधार किया जाए।

यह अनुशंसा की जाती है कि कृषि आधारित उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करके गाजियाबाद जिले में अधिक विकास केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। एक विकास केंद्र मोदीनगर हो सकता है, जो एक पुराना औद्योगिक शहर भी है जो अपनी चीनी मिलों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी सुविधा और बहुत अच्छा फल और सब्जी का आधार है। कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र को मदद मोदीनगर क्षेत्र को और अधिक टिकाऊ बनने में मदद कर सकता है।

हथकरघा और शिल्प क्षेत्रों में कौशल विकास सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं को साबित करके जिले में अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों को मदद देने की अपार संभावनाएं हैं। गाजियाबाद जिले का एक छोटा सा कस्बा पिलखुआ पारंपरिक कपड़ा वस्तुओं के निर्माण का केंद्र है और इसे कपड़ा निर्माण केंद्र के रूप में और विकसित किया जा सकता है।

हापुड़ गाजियाबाद जिले का एक प्रमुख मंडी शहर है। यह स्थान गेहूं प्रसंस्करण के लिए अपनी सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि अनाज और अनाज आधारित उत्पादों और आलू प्रसंस्करण इकाइयों की विशाल क्षमता को देखते हुए इसकी बहुत बड़ी संभावना है

(c) बुलंदशहर

बुलंदशहर जिले में तीन महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं अर्थात कृषि, दूध उत्पादन और चीनी मिट्टी की चीज़ें। यह अनुशंसा की जाती है कि जिले की कृषि-प्रसंस्करण और दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का दोहन करने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय किए जाएं। संसाधनों का उपयोग आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों के रूप में पनीर, घी और दूध पाउडर आदि उत्पादों को बनाने के लिए किया जाना चाहिए। यह भी अनुशंसा की जाती है कि जिला उत्पादन आधार का मदद करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन, फूड पार्क आदि के रूप में ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सहयोग किया जाए।

जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण केंद्र खुर्जा है, जो अपने मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध एक छोटा सा शहर है। पर्यावरण प्रदूषण के पहलू को संबोधित करने और पानी, सड़क आदि जैसे अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए इकाइयों के आधुनिकीकरण की जरुरत है, साथ ही खुर्जा में कुशल कर्मचारी की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान की जरुरत है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

सिकंदराबाद जिले का एक अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। हालांकि, बुनियादी ढांचे के विकास का स्तर अपर्याप्त है। इसमें दूध और डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण की उच्च क्षमता है।

(d) मेरठ

मेरठ एक औद्योगिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है; इसका एक अनुकूल कारण दिल्ली से इसकी निकटता है। यह शहर अपनी कैंची, हथकरघा कपड़े, सोने के गहने, खेल के सामान (विशेषकर क्रिकेट के सामान) के लिए प्रसिद्ध है। यह कई शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हालांकि, शहर में बुनियादी ढांचे और प्रतिस्पर्धी माहौल का अभाव है। यह अनुशंसा की जाती है कि मौजूदा इकाइयों में आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन किया जाए। यह भी सिफारिश की जाती है कि एमएसएमई को सहायता देने के लिए उपयुक्त सहायक बुनियादी ढांचे जैसे सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी), आदि की स्थापना की जाए। यह भी अनुशंसा की जाती है कि जिले में सॉफ्ट सपोर्ट प्रदान करने के साथ स्पोर्ट्स गुड्स पार्क, कैंची पार्क, हैंडलूम पार्क विकसित किया जाए।

(e) बागपत

बागपत का एक मजबूत कृषि आधार है और इस क्षेत्र में गुड़ (गुड़) बनाने का एक प्रमुख केंद्र है। जिले का उद्योग आधार अपेक्षाकृत छोटा है। जिले में भावी विकास संभावित क्षेत्रों में अनाज प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण और तेल मिल हैं।.

8.6.3 एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र

2000 के बाद से एनसीटी-दिल्ली की आर्थिक संरचना में बदलाव आया है। तेजी से शहरीकरण के कारण, एनसीटी-दिल्ली का कृषि आधार घट रहा है। एनसीटी-दिल्ली में महत्वपूर्ण विनिर्माण उद्योगों में रेडीमेड वस्त्र, रिकॉर्डेड मीडिया का प्रकाशन, मुद्रण और पुनरुत्पादन, विद्युत मशीनरी और उपकरण, रबर और प्लास्टिक उत्पाद, मूल धातु और गढ़े हुए धातु उत्पाद और मशीनरी और उपकरण शामिल हैं। इनमें से अधिकतर इकाइयां एमएसएमई प्रकृति की हैं। एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए मौजूदा सहयोग प्रणाली अपर्याप्त है। दिल्ली की नई औद्योगिक नीति के अनुसार प्रौद्योगिकी और उत्पादकता के क्षेत्रों में एमएसएमई को संभालने के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता है। कई शिल्प समूहों को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सीएफ़सी और अन्य नरम समर्थन की आवश्यकता होती है। चूंकि एनसीटी-दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकतम गैर-कृषि रोजगार हैं, इसलिए एनसीटी-दिल्ली के लिए एक उपयुक्त अनौपचारिक क्षेत्र नीति तैयार करने की जरुरत है।

8.6.4 राजस्थान उप-क्षेत्र

(a) अलवर

अलवर जिले में मुख्य चुनौती कृषि क्षेत्र पर इसकी भारी निर्भरता है। जिले में निर्माण गतिविधियों को बड़े पैमाने पर सहयोग करने की जरूरत है। राजस्थान सरकार द्वारा एनसीआर के राजस्थान उप-क्षेत्र के लिए तैयार की गई डीएमआईसी और उप-क्षेत्रीय योजना का अलवर की आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। भविष्य के गहन विकास के लिए अलवर में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों (i) भिवाड़ी टपूकड़ा-खुशखेड़ा परिसर, (ii) अलवर और (iii) शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ परिसर की पहचान की गई है। इन तीन क्षेत्रों में अगले दो दशकों में महत्वपूर्ण औद्योगिक निवेश शुरू होने की संभावना है। इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, भारी उद्योग

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

जैसे स्थानीय संसाधन आधारित गतिविधियों में सहयोग करने की जरुरत है। यह भी अनुशंसा की जाती है कि अलवर में ग्रीनफील्ड ऑटो और टेक्सटाइल क्षेत्र में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। आगे यह अनुशंसा की जाती है कि जिले में निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत सहयोगी बुनियादी ढांचे और अन्य सहायक सेवाओं के साथ प्रेरित क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

8.7 एनसीआर में भारी, मध्यम और लघु उद्योग, बीपीओ, आईटी क्षेत्र, वाणिज्य के स्थान

एनसीआर एक अंतर-राज्यीय क्षेत्र होने के कारण इसके वैधानिक कर दरों में व्यापक भिन्नताएं मौजूद हैं, साथ ही कच्चे माल और मशीनरी की खरीद पर निर्माताओं को दी जाने वाली कर रियायतें, बिजली, पानी और परिवहन आदि जैसी विभिन्न सेवाओं पर शुल्क दर लगाता है। यह भारी और लघु उद्योगों के स्थान और विनिर्माण गतिविधियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों के साथ-साथ प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध के कारण, तेजी से शहरीकरण के साथ-साथ एनसीटी-दिल्ली में सेवा क्षेत्र के आधार का विकास हुआ है। दोनों केन्द्रापसारक बल/पुश फैक्टर (प्रदूषणकारी उद्योगों को परिधि की ओर स्थानांतरित करना, आदि) और सेंट्रिपेटल फोर्स/पुल फैक्टर (आईटी/आईटीईएस क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व व्यापार और निवेश के अवसरों में नए रुझान) ने 'क्लीनर' एनसीटी-दिल्ली में सर्विस सेक्टर के विकास का नेतृत्व किया। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि एनसीटी-दिल्ली में उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों/सेवाओं एसएसआई, बीपीओ और आईटी/आईटीईएस पर विशेष जोर देने वाले हाई-टेक उद्योग स्थापित किए जाएं।

हरियाणा उप-क्षेत्र विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों और सेवा क्षेत्र जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र, वस्त्र, इंजीनियरिंग, वित्तीय सेवाओं, बीपीओ और रियल एस्टेट में एक प्रमुख विनिर्माण आधार के रूप में उभरा है। फरीदाबाद, गुड़गांव और पानीपत जैसे अधिकांश विनिर्माण क्षेत्रों के मौजूदा स्थान अचल संपत्ति की कीमतों में तेजी से वृद्धि, परिवहन, ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे, डीएमआईसी और प्रस्तावित मॉडल इंडस्ट्रियल टाउन/औद्योगिक एस्टेट्स/एसईजेड जैसी आगामी परियोजनाएं हरियाणा उप-क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करेंगी। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि अधिकांश विनिर्माण कार्यों विशेष रूप से मध्यम और भारी उद्योग को धीरे-धीरे रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, पलवल और मेवात जैसे क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है। एनसीटी-दिल्ली से सटे जिलों को बीपीओ, आईटी/आईटीईएस, ज्ञान-आधारित उद्योगों और एमएसएमई सहित उच्च तकनीक वाले उद्योगों के साथ धीरे-धीरे विकसित किया जाना चाहिए।

एनसीटी-दिल्ली में औद्योगिक नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप साहिबाबाद और सूरजपुर जैसे क्षेत्रों में कई उद्योग विकसित हुए हैं। हालांकि, बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे अन्य स्थान मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए अच्छे स्थान हैं। अब तक, कई बड़ी सॉफ्टवेयर और बीपीओ कंपनियों के आईटी/आईटीईएस और बीपीओ पहले से ही चालू हैं, जैसे कि एडोब सिस्टम्स, टीसीएस, इंटररा, एग्रीया सॉल्यूशंस, ग्लोबललॉजिक सीएससी, एचसीएल, ईएक्सएल आदि। विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में बेहतर उप-शहरी माहौल और दिल्ली से इसकी निकटता के कारण कई अन्य कंपनियों के नोएडा में उनके भारतीय शाखा कार्यालय हैं। इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आईटी / आईटीईएस, बीपीओ और आर एंड डी, जैव प्रौद्योगिकी आदि के साथ पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक बेल्ट के रूप में विकसित किया जा सकता है।

विशेष रूप से डीएमआईसी परियोजना की निकटता को देखते हुए राजस्थान उप-क्षेत्र में मध्यम और बड़े

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

उद्योगों के विकास की भी बड़ी संभावनाएं हैं।

महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों का विवरण तालिका 8.5 और मानचित्र 8.3 में दिया गया है।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

मानचित्र 8.1: जिलेवार आर्थिक केंद्र

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

ऊपर वाले चित्र का अनुवाद

आर्थिक केंद्र

पानीपत समालखा गोहाना गनौर सोनीपत खरखौदा बड़ौत बागपत खेकड़ा दुराला मेरठ मवाना महाम रोहतक कलानुअर बेरी बहादुरगढ़ झज्जर एनसीटी दिल्ली दिल्ली मोदीनगर गाज़ियाबाद मुरादनगर लोनी हापुड़ सिकंदराबाद बुलंदशहर अनूपशहर खुर्जा गौतमबुद्ध नगर नोएडा दादरी रबुपुर फरीदाबाद पलवल होडल मेवात फारुखनगर गुड़गांव पटौदी धारूहेड़ा रेवाड़ी बावल अलवर राजस्थान बेहरोर

प्रमुख

एनसीआर सीमा

आर्थिक केंद्र

तालिका 8-3: **महत्वपूर्ण मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक केंद्र**

स्थान	रोजगार		आय		नीति/योजनाएं		विशेष परियोजनाएं (डीएमआईसी/ एसईजेड)	क्लस्टर		अर्थव्यवस्था		आर्थिक केंद्र
	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित		मौजूदा	प्रस्तावित	मौजूदा	प्रस्तावित	
मेरठ	उच्च	मध्यम	कम	मध्यम	प्रभावी नहीं	क्लस्टर की एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का इस्तेमाल किया	हाँ	9 क्लस्टर	आधुनिकीकरण	स्थानीय गैर खेत	क्षेत्रीय	दौराला, मवाना, मेरठ
बागपत	उच्च	मध्यम	कम	मध्यम	प्रभावी नहीं	फूड पार्क योजना	-	-	-	स्थानीय खेत	क्षेत्रीय	बड़ौत, खेकड़ा, बागपत
गाज़ियाबाद	कम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	प्रभावी नहीं	क्लस्टर्स और क्राफ्ट की योजनाएं	-	2 क्लस्टर	पुनर्वास	क्षेत्रीय	राष्ट्रीय	मोदीनगर, लोनी, मुरादनगर, हापुड़, पिलखुवा
गौतम बुद्ध नगर	कम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	प्रभावी	क्लस्टर और क्राफ्ट की योजनाएँ	दादरी - नोएडा - गाजियाबाद निवेश क्षेत्र	5 क्लस्टर	आधुनिकीकरण	राष्ट्रीय	अंतरराष्ट्रीय	नोएडा, दादरी, दनकौर, रबूपुरा, देवर
बुलंदशहर	उच्च	मध्यम	कम	मध्यम		डीसी हस्तशिल्प योजना, फूड पार्क योजना	-	1 क्लस्टर	सामान्य सुविधाएँ	स्थानीय	क्षेत्रीय	सिकंदराबाद, अनूपशहर, बुलंदशहर, खुर्जा

पानीपत	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	प्रभावी नहीं	टेक्सटाइल पार्क, क्लस्टर विकास योजना	-	3 क्लस्टर	आधुनिकीकरण और स्थानांतरण	राष्ट्रीय	अंतरराष्ट्रीय	पानीपत, समालखा
सोनीपत	कम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	भोजन पार्क - बरही	-	-	-	-	स्थानीय	राष्ट्रीय	गोहाना, गनौर, सोनीपत, खरकौदा
रोहतक	उच्च	मध्यम	मध्यम	मध्यम	आरएंडडी कौशल में निवेश	नॉलेज सिटी और आईटी पार्क	-	-	-	क्षेत्रीय	राष्ट्रीय	महम, कलानुअर, रोहतक

स्थान	रोजगार		आय		नीति/योजनाएं		विशेष परियोजनाएं (डीएमआईसी/ एसईजेड)	क्लस्टर		अर्थव्यवस्था		आर्थिक केंद्र
					और मानसिक संस्थानों का प्रबंधन							
झज्जर	कम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	बहादुरगढ़ में लेदर पार्क	मौजूदा उद्योगों के लिए सीएफ़सी और अन्य सॉफ्ट इनपुट की आवश्यकता	एसईजेड प्रस्तावित	-	-	स्थानीय	राष्ट्रीय	बारी, बहादुरगढ़, झज्जर
रेवाड़ी	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम	बहुत प्रभावी औद्योगिक नीति	लॉजिस्टिक हब और व्यवसाय विकास सेवाएं	मानेसर - बावल ऑटो कंपोनेंट/ऑटोमोबाइल निवेश क्षेत्र	-	-	क्षेत्रीय	क्षेत्रीय	रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल
गुडगाँव	मध्यम		उच्च	उच्च	बहुत प्रभावी औद्योगिक नीति	ऑटो, टेक्सटाइल, उत्पाद प्रदर्शन केंद्रों के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्रों सहित उच्च मूल्य वर्धित और सेवा उद्योगों पर अधिक फोकस	-	4 क्लस्टर	आधुनिकीकरण और स्थानांतरण	अंतरराष्ट्रीय	अंतरराष्ट्रीय	फारुख नगर, पटौदी, गुड़गांव

फरीदाबाद	उच्च	उच्च	कम	मध्यम	औद्योगिक गतिविधियों के अतिप्रवाह के लिए सही नीति की जरूरत	केंद्र और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा विकास नीतियां	-	4 क्लस्टर	आधुनिकीकरण और स्थानांतरण	राष्ट्रीय	अंतरराष्ट्रीय	फरीदाबाद, पलवल, होडल

स्थान	रोजगार		आय		नीति/योजनाएं		विशेष परियोजनाएं (डीएमआईसी/ एसईजेड)	क्लस्टर		अर्थव्यवस्था		आर्थिक केंद्र
दिल्ली एनसीटी	मध्यम	Low	मध्यम	उच्च	सेवा और उद्योग आधार	मौजूदा नीतियों से नरम और कठोर इनपुट	-	12 क्लस्टर	आधुनिकीकरण और स्थानांतरण	अंतर्राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय	दिल्ली
राजस्थान	उच्च	उच्च	कम	मध्यम	नीतियां मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में काम करती हैं	गैर-कृषि गतिविधियों के लिए कौशल उन्नयन और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मौजूदा नीतियां विकसित की जाएंगी	खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश सामान्य विनिर्माण / ऑटोमोबाइल / ऑटो घटक निवेश क्षेत्र	-		स्थानीय	क्षेत्रीय	बहरोड़, अलवर

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन

8.8 थोक व्यापार का स्थान

एनसीटी-दिल्ली, एनसीआर का मूल, एनसीआर में व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा है, पारंपरिक रूप से हमेशा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए जाना जाता है। वितरण व्यापार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली में बुनियादी गतिविधियों में से एक है। राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र होने के कारण एनसीटी-दिल्ली की कार्यात्मक विशेषज्ञता के परिणामस्वरूप बैंकिंग गतिविधियों, गोदामों, परिवहन और संचार सुविधाओं आदि का भी ध्यान केंद्रित हुआ है। प्लास्टिक और पीवीसी सामान, रसायन, लकड़ी, खाद्यान्न, फूल, फल, सब्जियां, मसाले, लोहा और इस्पात और निर्माण सामग्री का थोक व्यापार पूरे एनसीआर और पूरे उत्तरी भारत में होता है।

जिन वस्तुओं को दिल्ली लाया जाता है, उनका प्रमुख हिस्सा दिल्ली के बाहर फिर से वितरित किया जाता है। दिल्ली से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं सब्जी और फल, ईंधन तेल, खाद्यान्न, लोहा और इस्पात हैं।

एनसीटी-दिल्ली में थोक व्यापार में पहले से ही गिरावट शुरू हो गई है जबकि वित्तीय सेवाएं, खुदरा व्यापार जैसी सेवाएं तेज गति से बढ़ रही हैं। एनसीआर के अन्य हिस्सों में, व्यावसायिक गतिविधियाँ काफी विकसित हैं। कुछ महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, खुर्जा और बुलंदशहर, हरियाणा उप-क्षेत्र में फरीदाबाद, पानीपत, रेवाड़ी, गुड़गांव, सोनीपत और रोहतक और राजस्थान उप-क्षेत्र में अलवर हैं; हालाँकि, एनसीटी-दिल्ली में व्यापार के संचालन के पैमाने में वृद्धि, उपरोक्त केंद्रों में दिल्ली को कम करना अनिवार्य हो गया है। चूंकि दिल्ली के विभिन्न मास्टर प्लान ने, विशेष रूप से गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, कुंडली और लोनी के केंद्रीय एनसीआर शहरों में स्थित स्पेस एक्सटेंसिव सामानों के लिए थोक व्यापार पर विकेंद्रीकरण की सिफारिश की है। विकेंद्रीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित स्थान निम्नानुसार हैं:

तालिका 8-4: थोक व्यापार के लिए प्रस्तावित स्थान

व्यापार सामग्री	स्थानों
अनाज	पानीपत, हापुड़ और कुंडली
फल और सब्जियां	पानीपत (सेब और सब्जियों के लिए); हापुड़ आलू और प्याज); कुंडली (आम और सब्जियां)
कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स	मेरठ और रोहतक
आयरन एंड स्टील ऑटो पार्ट्स	गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद
ईंधन तेल	रेवाड़ी

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

हार्डवेयर और निर्माण सामग्री	हार्डवेयर के लिए - गाजियाबाद, भवन निर्माण सामग्री के लिए- अलवर, धारूहेड़ा या भिवाड़ी

8.9 सुझाई गई परियोजनाएं

विभिन्न उप-क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं, मुद्दों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, कार्यात्मक योजना ने एनसीआर के लिए 61 औद्योगिक और ढांचागत विकास परियोजनाओं की पहचान की है (तालिका 8.5 देखें), जिसमें गुणवत्ता परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास केंद्र, उद्यमिता कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थान, डिजाइनिंग केंद्र, आईपीआर संस्थान, सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र आदि शामिल हैं। ये सभी सुझाई गई परियोजनाएं शून्य दोष शून्य प्रभाव के मेक इन इंडिया परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हैं और निजी निवेश, नए प्रवेशकों, रोजगार सृजन, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो घटकों, चमड़ा, कपड़ा, आईटी/आईटीईएस, हथकरघा और हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण आदि जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को प्रेरित करके अभियान के उद्देश्यों को पूरा करती हैं और देश को अतिरिक्त समय में एनसीआर को पर्यावरण के अनुकूल और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बदलती है।

चूंकि मेक इन इंडिया और स्किल्ड इंडिया एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों में उद्यमशीलता को प्रेरित करने और रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से प्रस्तावित परियोजनाओं के हिस्से के रूप में कौशल विकास केंद्र भी प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से पूरे क्षेत्र में रोजगार पैदा होने, ग्रामीण से शहरी प्रवास को सीमित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद है। यह अनुमान लगाया गया है कि कुल 36,600 और 424,800 का रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्रमशः सृजित किया जा सकता है। इस तरह, क्षेत्र में कुशल कार्यबल की एक महत्वपूर्ण कमी को क्षेत्र के भीतर से पूरा किया जा सकता है।

तालिका **8-5:** एनसीआर में प्रस्तावित औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

क्रम संख्या	स्थान	परियोजना क्षेत्र	परियोजना का शीर्षक	सांकेतिक निवेश (मिलियन रुपये)	अस्थायी रोजगार (प्रत्यक्ष)	अस्थायी रोजगार (अप्रत्यक्ष)
हरियाणा उप-क्षेत्र में औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं						
1	राय	खाद्य प्रसंस्करण	कृषि और खाद्य परीक्षण अनुसंधान केंद्र	500	50	1,000
2	बरही	पर्यावरण	रंगाई इकाइयों का आधुनिकीकरण	200	50	500

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

3	बरही	टेक्सटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर	वस्त्रों के लिए प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र	50	50	4,000
4	कुंडली	इन्फ्रास्ट्रक्चर	इकाइयों के लिए गैस की आपूर्ति	2,000	1,000	5,000
5	पानीपत	पर्यावरण	रंगाई घरों का आधुनिकीकरण	1,000	100	15,000
6	पानीपत	व्यापार एवं वाणिज्य	वस्त्रों के लिए आधुनिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र	1,500	1000	20,000
7	समालखा	फाउंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर	ढलाई के लिए आधुनिक सामान्य सुविधा केंद्र	200	50	100
8	रोहतक	नॉलेज सिटी	उद्योग लिंकेज के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता संस्थानों में सभी मौजूदा सुविधाओं का आधुनिकीकरण	1,000	100	1,000
9	रोहतक	जूते	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान	500	50	1,000
10	रोहतक	जूते	प्रदर्शनी-सह-प्रदर्शन केंद्र	500	100	1,000
11	रोहतक	बुनियादी ढांचे का उन्नयन	सभी व्यापारिक गतिविधियों जैसे कपड़ा व्यापार आदि का आधुनिकीकरण।	1,000	100	1,000
12	झज्जर	सामान्य सुविधा केंद्र	उद्योग सह सेवा केंद्र	500	100	1,000
13	फरीदाबाद	सामान्य इंजीनियरिंग	गुणवत्ता और परीक्षण केंद्र	750	100	15,000
14	फरीदाबाद	सामान्य इंजीनियरिंग	रिवर्स इंजीनियरिंग और सीएडी और सीएएम सेंटर	1,000	100	10,000
15	फरीदाबाद	कपड़ा	प्रोसेस हाउस आधुनिकीकरण	750	50	100

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

क्रम संख्या	स्थान	परियोजना क्षेत्र	परियोजना का शीर्षक	सांकेतिक निवेश (मिलियन रुपये)	अस्थायी रोजगार (प्रत्यक्ष)	अस्थायी रोजगार (अप्रत्यक्ष)
16	राय	खाद्य प्रसंस्करण	कृषि और खाद्य परीक्षण अनुसंधान केंद्र	1,000	50	500
17	राय	खाद्य प्रसंस्करण	खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना (दूध और आम)	5,000	100	10,000
18	गोहाना	खाद्य प्रसंस्करण	सब्जी पैक घरों के लिए बुनियादी ढांचा	100	100	10,000
19	मेवात	खाद्य प्रसंस्करण	सब्जी पैक घरों के लिए बुनियादी ढांचा	100	100	10,000
एनसीआर के हरियाणा उप-क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र की परियोजनाएं						
20	खरखोदा	अनौपचारिक क्षेत्र	पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास	100	100	10,000
21	पानीपत	रग्स इंफ्रास्ट्रक्चर	आसनों का प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केंद्र	100	100	20,000
22	झज्जर	अनौपचारिक क्षेत्र	उद्यमिता विकास केंद्र	500	50	1,000
23	झज्जर	सेवा क्षेत्र	सेवा क्षेत्र कौशल विकास केंद्र - बीपीओ और खुदरा बिक्री	500	50	1,000
24	मेवात	अनौपचारिक क्षेत्र	गैर औद्योगिक गतिविधियों में उद्यमिता विकास केंद्र	500	50	1,000
25	झज्जर	शिल्प	टोकरी शिल्प प्रशिक्षण और संसाधन केंद्र	50	25	5,000
एनसीआर के उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं						
26	मेरठ	खेल के सामान	क्रिकेट बैट इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर, मेरठ	100	100	6,000
27	मेरठ	ऑटो कंपोनेंट	ऑटो कंपोनेंट के लिए आधुनिक कॉमन फैसिलिटी पॉइंट	500	100	5,000
28	मेरठ	ट्रांसफॉर्मर और वोल्टेज नियामक	अनुसंधान डिजाइन और मानक केंद्र	500	50	1,000
29	गाज़ियाबाद	रासायनिक और रबड़	अनुसंधान और विकास केंद्र	1,000	100	1000
30	ग्रेटर नोएडा	जैव प्रौद्योगिकी	अनुसंधान एवं विकास और कौशल उन्नयन केंद्र	1,000	50	500

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

31	ग्रेटर नोएडा	आईपीआर	राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संस्थान	500	50	100
32	बुलंदशहर	खाद्य प्रसंस्करण	डेयरी विकास अनुसंधान संस्थान (करनाल और आनंद की तर्ज पर)	1,000	200	5,000
33	बुलंदशहर	खाद्य प्रसंस्करण	खाद्य प्रसंस्करण पार्क (दूध और आम)	5,000	5000	40,000
34	हापुड़	खाद्य प्रसंस्करण	सब्जी पैक घरों के लिए बुनियादी ढांचा	100	100	10,000
उत्तर प्रदेश एनसीआर के उप-क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र की परियोजनाएं						
35	मेरठ	कांच और लकड़ी के मोती	कांच और लकड़ी के मोतियों के लिए प्रशिक्षण और विपणन केंद्र।	20	50	1000

क्रम संख्या	स्थान	परियोजना क्षेत्र	परियोजना का शीर्षक	सांकेतिक निवेश (मिलियन रुपये)	अस्थायी रोजगार (प्रत्यक्ष)	अस्थायी रोजगार (अप्रत्यक्ष)
36	मेरठ	हथकरघा	हथकरघा डिजाइन और प्रौद्योगिकी केंद्र।	300	50	5000
37	खुर्जा	मिट्टी के बर्तन	आधारभूत संरचना उन्नयन परियोजना।	500	100	5000
38	गाज़ियाबाद	कालीन	आसनों के लिए डिजाइन और संसाधन केंद्र	500	100	10,000
39	बुलंदशहर	कढ़ाई	कढ़ाई के लिए डिजाइन और संसाधन केंद्र	500	100	5,000
40	पिलखुवा	छपाई	कपड़ा छपाई प्रशिक्षण और संसाधन केंद्र	500	100	10,000
एनसीआर के एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं						
41	एनसीटी-दिल्ली	कपड़ा	उद्योग ई-तैयारी केंद्र	500	20	500
42	एनसीटी-दिल्ली	कपड़ा	प्रशिक्षण और सहित वस्त्र सामान्य सुविधा केंद्र सेवा कर्मियों के लिए कौशल विकास	1,000	100	1,000
43	एनसीटी-दिल्ली	कपड़ा और कठिन सामान	डिजाइन सिटी सेंटर	1,000	300	1,500
44	एनसीटी-दिल्ली	रत्न और आभूषण	मौजूदा रत्न एवं आभूषण केंद्र का उन्नयन	500	100	5,000

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

45	एनसीटी-दिल्ली	बुनियादी ढांचा	मौजूदा का उन्नयन ओखला औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना चरण- I और II	1,000	5000	50,000
46	एनसीटी-दिल्ली	पर्यावरण	सामान्य बहिःस्राव उपचार औद्योगिक क्षेत्रों में संयंत्र	1,000	100	1,000
47	एनसीटी-दिल्ली	बुनियादी ढांचा	ओखला में बेहतर रसद सुविधाएं	1,000	25	1,000
48	एनसीटी-दिल्ली	बुनियादी ढांचा	औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर पार्किंग अवसंरचना	1,000	100	1,000
49	एनसीटी-दिल्ली	बुनियादी ढांचा	बेहतर लॉजिस्टिक ओखला और नरायणा में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए बुनियादी ढांचा	1,000	2,000	5,000
एनसीआर के एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र की परियोजनाएं						
51	एनसीटी-दिल्ली	प्रशिक्षण	पश्चिम ग्रामीण दिल्ली में उद्यमिता विकास केंद्र	1,000	1,000	5,000
52	एनसीटी-दिल्ली	प्रशिक्षण	पूर्वी दिल्ली में शिल्प विकास केंद्र	1,000	1,000	5,000
53	एनसीटी-दिल्ली	प्रशिक्षण	मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटो मैकेनिक आदि जैसे गैर-औद्योगिक ट्रेडों में कौशल विकास केंद्र।	500	1,000	5,000
54	एनसीटी-दिल्ली	प्रशिक्षण	जातीय खाद्य गुणवत्ता और मानक केंद्र	500	100	5,000
55	एनसीटी-दिल्ली	प्रशिक्षण	ग्रामीण और पुनर्वास कॉलोनियों में 10 आधुनिक परिधान सिलाई केंद्र	500	5,000	50,000
एनसीआर के राजस्थान उप-क्षेत्र में औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं						

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

क्रम संख्या	स्थान	परियोजना क्षेत्र	परियोजना का शीर्षक	सांकेतिक निवेश (मिलियन रुपये)	अस्थायी रोजगार (प्रत्यक्ष)	अस्थायी रोजगार (अप्रत्यक्ष)
56	अलवर	ऑटो कंपोनेंट	टूलींग और डाइ कॉमन फैसिलिटी सेंटर	1,000	500	5,000
56	अलवर	ऑटो कंपोनेंट	प्रौद्योगिकी और सीएडी, सीएएम प्रशिक्षण केंद्र	1,000	200	1,000
57	अलवर	कपड़ा	रेडीमेड गारमेंट पार्क	1,000	10,000	3,0000
एनसीआर के राजस्थान उप-क्षेत्र में औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं						
58	अलवर	कालीन	आसनों के लिए प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र	100	20	1,000
59	बासोद अलवर	जूते चमड़े	चमड़े के जूते के लिए संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र	100	20	1,000
60	गोलाका बस, अलवर	मूर्ति बनाना	मूर्ति निर्माण के लिए डिजाइन और प्रशिक्षण केंद्र	100	20	1,000
61	रामगढ़, अलवर	मिट्टी के बर्तन और टेरा कोट्टा	टेराकोटा के लिए आधुनिक सामान्य सुविधा केंद्र	100	20	1,000
	कुल			**46,320**	**36,600**	**4,24,800**

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

अनुलग्नक

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

अनुलग्नक 1. 1: आर्थिक और विकास संकेतक और जीडीपी अनुमानों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तरीके।

A. आर्थिक और विकास संकेतक

आर्थिक संकेतक देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा को समझने के लिए अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण आँकड़े हैं। यह नई आवश्यकताओं और सुधार के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों का अनुमान लगाने में मदद करता है। जीडीपी, पीसीआई, डब्ल्यूपीआर, औद्योगिक विकास आदि जैसे प्रमुख संकेतकों का उपयोग क्षेत्रों और जिलों की वर्तमान आर्थिक स्थितियों को समझने और तुलना करने के लिए किया गया है।

(i) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संकेतकों में से एक है जो अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न उत्पादन को उस अवधि में मापता है जो देश / क्षेत्र के समग्र आर्थिक स्वास्थ्य का न्याय करता है। जबकि, प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) देश/क्षेत्र के किसी व्यक्ति की औसत कमाई का माप है, अर्थात एक ही क्षेत्र या देश या अन्य देशों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की जीवन स्थितियों/मानकों और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अध्याय 2 में, हमने जीडीपी की तुलना की है और एनसीआर के सभी चार उप क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली के एनसीटी, हरियाणा उप-क्षेत्र, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र और राजस्थान उप-क्षेत्र और उनके संबंधित जिलों के लिए क्षेत्र की आर्थिक नब्ज का आकलन करने के लिए पीसीआई पर कब्जा कर लिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि एक विशिष्ट उप क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद एक सटीक तस्वीर को दर्शाता है जैसा कि दिल्ली के एनसीटी के मामले में है, जिसमें एनसीआर के सभी उप क्षेत्रों में अधिकतम जीडीपी है, लेकिन गुड़गांव और फरीदाबाद से पीछे है, जिनके पास एनसीटी की तुलना में अधिक पीसीआई है। क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की दिशा में प्रत्येक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योगदान को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रीय संरचना को लिया जाता है। यह समझने में मदद करता है कि कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है और इसका महत्व जो अध्याय 2 के खंड 2.3 में प्रदान किया गया है।

(ii) कार्यबल देश या क्षेत्र की काम करने वाली आबादी की मात्रा है जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है, जिसका मूल्य जीडीपी के रूप में प्राप्त होता है। अध्याय 3 एनसीआर में क्षेत्रों और क्षेत्रों में कार्यबल और इसकी संरचना की रूपरेखा तैयार करता है। कार्यबल भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) क्षेत्र या देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है, यह अप्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के रोजगार के स्तर को दर्शाता है। यह महसूस किया गया है कि कुल कार्यबल और डब्ल्यूपीआर साथ-साथ नहीं चलते हैं क्योंकि राजस्थान उप-क्षेत्र ने न्यूनतम कुल कार्यबल दर्ज किया है, लेकिन सभी उप-क्षेत्रों के बीच हमेशा अधिकतम डब्ल्यूपीआर है। इसके अलावा, तीन क्षेत्रों से संबंधित नौ श्रेणियों में कार्यबल का एक पृथक्करण अर्थात्; प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक; **2001** तक के सभी उप-क्षेत्रों का विवरण संबंधित उप-क्षेत्रों के अनुभागों के अंतर्गत दिया गया है। इससे उप-क्षेत्रों में संबंधित श्रेणी/क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार को समझने में मदद मिलेगी। हालांकि, 2011 के लिए इन श्रेणियों पर कार्यबल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; इसके बजाय डेटा चार प्रमुख श्रेणियों पर उपलब्ध है, अर्थात्; किसान, कृषि मजदूर, एचएच उद्योग के श्रमिक और अन्य श्रमिक; जो इन व्यापक शीर्षों के तहत कार्यबल का एक करीबी विचार देता है।

(iii) एनसीआर में इस्तेमाल किया गया एक अन्य संकेतक औद्योगिक विकास है, जो कि अध्याय 4 है, जो एनसीआर में उप-क्षेत्रवार और जिलेवार रोजगार और निवेश जैसे उद्योगों और उसके घटकों की

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

संख्या को दर्शाता है। इससे 2010-11 तक क्षेत्र के औद्योगिक स्वास्थ्य को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि तब तक तुलनीय आंकड़े उपलब्ध हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और बड़े उद्यमों में उद्योगों का वर्गीकरण जिला और क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों की संरचना और औद्योगिक क्षेत्र में उनके योगदान को समझने के लिए आवश्यक है। औद्योगिक क्लस्टर एक क्षेत्र में उद्योगों के विशिष्ट समूह की भौगोलिक एकाग्रता का एक उपाय है, इस प्रकार इस तरह की सांद्रता में इकाइयों, श्रमिकों और उत्पादन उत्पादन की संख्या को समझने में मदद करता है। एक क्षेत्र में अधिक समूहों की उपस्थिति अर्थव्यवस्था की उच्च प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है। एनसीआर में कुल **53** ऐसे औद्योगिक क्लस्टर हैं, जिनमें से अधिकतम संख्या रबर और रसायन **(11)** उद्योग में हैं, जबकि ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर में अधिकतम संख्या में इकाइयां **(25,900)** हैं, लेकिन अधिकतम श्रमिक टेक्सटाइल क्लस्टर **(494116)** में कार्यरत हैं।

(iv) क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्षमता अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका विवरण अध्याय 5 में दिया गया है, यह नए ग्रामीण उद्योगों, रोजगार सृजन, विपणन बुनियादी ढांचे का विकास आदि के संदर्भ में वर्तमान स्थिति और विकास की गुंजाइश का संक्षिप्त विवरण देता है। क्षेत्र में विशेष आर्थिक गतिविधि की एकाग्रता को दर्शाने के लिए गणना की गई स्थान क्वेशिएंट (एलक्यू); जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को समझने और क्षेत्रीय योजना प्रयासों का सहयोग करने के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। इसी प्रकार, क्षेत्र की अनौपचारिक क्षेत्र संरचना अगले अध्याय का अनुसरण करती है। इस क्षेत्र में उन गतिविधियों, इकाइयों और कामगार शामिल हैं जो औपचारिक रूप से सरकार के साथ पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन वे देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ-साथ रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दिल्ली एनसीटी और एनसीआर में अनौपचारिक क्षेत्र क्रमशः अध्याय 6 के खंड 6.4 और 6.5 में प्रदान किया गया है।

B. उपकरण

विशेषज्ञता की सरल गणना (स्थान भागफल) से लेकर इनपुट-आउटपुट आधारित तकनीकों तक आर्थिक गतिविधियों के महत्व को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। सूक्ष्म-स्तरीय क्लस्टर अनुप्रयोग आमतौर पर विशेष क्षेत्रीय हितों या नीतिगत चिंताओं से प्रेरित होते हैं। क्षेत्रीय उद्योग समूहों को रेखांकित करने का एक बहुत ही सामान्य साधन "स्थान भागफल" (एलक्यू) है। स्थान भागफल शेयरों का अनुपात है: क्षेत्रीय उद्योग, यानी राष्ट्रीय उद्योग पर कुल क्षेत्रीय रोजगार का हिस्सा, यानी कुल राष्ट्रीय रोजगार का हिस्सा। विशिष्ट होने के लिए, स्थान भागफल (एलक्यू) क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में किसी स्थान पर किसी विशेष उद्योग, क्लस्टर, व्यवसाय या उद्योग रोजगार की सांद्रता को मापने का एक उपाय है। इस प्रकार, यह क्षेत्रीय औसत की तुलना में स्थानीय की "अद्वितीय" विशेषताओं को प्रकट करता है।

1.0 का एलक्यू दर्शाता है कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग में रोजगार का उतना ही हिस्सा है जितना कि पूरे देश में। यदि स्थान भागफल 1.25 से अधिक है, तो इसे आमतौर पर किसी दिए गए क्षेत्र में क्षेत्रीय विशेषज्ञता के प्रारंभिक प्रमाण के रूप में लिया जाता है।

एलक्यू का उपयोग मुख्य रूप से गतिविधि के महत्व का पता लगाने के लिए किया जाता है और यह महत्व कैसे बदल जाता है। इस उपकरण का उपयोग प्राथमिक रूप से क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की बदलती प्रकृति को समझने के लिए किया जाता है।

C. 2

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

030-31 के लिए सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार का अनुमान

2030-31 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान मुख्य रूप से जिला स्तर पर 1999-2000 से 2007-08 (1999-2000 की कीमतों) तक सकल घरेलू उत्पाद की नौ श्रेणीवार चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि पर आधारित है। इसी प्रकार, रोजगार अनुमान दो स्तरों पर जनसंख्या वृद्धि पर आधारित होते हैं। स्तर एक 2001 की कार्यकर्ता की भागीदारी दर पर आधारित है और स्तर दो भविष्य की विकास दर के आधार पर अर्थव्यवस्था में संभावित संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण समायोजित भागीदारी दरों पर आधारित है।

जीडीपी अनुमान

सकल घरेलू उत्पाद का मापन और पूर्वानुमान किसी देश या क्षेत्र के आर्थिक विश्लेषण का एक अनिवार्य हिस्सा है। जीडीपी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, इसकी प्रति व्यक्ति आय को समझने में मदद करता है, और यह अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक स्थिति का भी पता लगाता है। जीडीपी की वृद्धि आर्थिक नीति निर्माण में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है।

ज्यामितीय विकास दर पद्धति, जहां उपलब्ध आंकड़ों (2004-05 से 2009-10) से प्रतिशत अवधि में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की गणना की गई है और इसका उपयोग सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों के लिए किया गया है।

विश्व बैंक के अनुसार, विकास दर की गणना के लिए तीन प्रमुख विधियों का उपयोग किया जाता है:

- कम से कम वर्ग विधि,
- घातीय वृद्धि दर विधि, और
- ज्यामितीय विकास दर विधि।

इन विधियों में, एक अवधि से दूसरी अवधि में परिवर्तन की दरों की गणना पहले की अवधि से आनुपातिक परिवर्तनों के रूप में की जाती है।

कम से कम वर्ग विधि: विकास दर गणना के लिए कम से कम वर्ग विधि जहां कहीं भी पर्याप्त लंबी समय श्रृंखला के लिए डेटा उपलब्ध है, नियोजित किया जाता है। (हमारे मामले में लंबे समय की श्रृंखला डेटा उपलब्ध नहीं है और इस पद्धति को लागू नहीं किया गया है)।

घातीय वृद्धि दर विधि: इस पद्धति का उपयोग कुछ जनसांख्यिकीय संकेतकों, विशेष रूप से श्रम शक्ति और जनसंख्या, आदि के लिए समय में दो बिंदुओं के बीच विकास दर की गणना के लिए किया जाता है। (यह विधि जनसांख्यिकीय संकेतकों के लिए सबसे उपयुक्त है और इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है)

[5] सीएजीआर एक विशेष अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि दर है। यह वार्षिक वृद्धि दर का एक ज्यामितीय औसत है। सीएजीआर का व्यापक रूप से उन मापदंडों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है जो जीडीपी की तरह गैर-रेखीय तरीके से बदलते हैं।

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

ज्यामितीय विकास दर विधि: ज्यामितीय विकास दर विधि असतत अवधियों में चक्रवृद्धि वृद्धि पर लागू होती है। इस पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से आर्थिक घटनाओं (हमारे मामले में जीडीपी) के लिए किया जाता है जहां विकास दर को केवल अंतराल पर मापा जाता है। वर्ष **2011, 2021** और **2031** जैसे अंतरालों के लिए अनुमान लगाने के लिए। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 5 आधारित पद्धति सबसे उपयुक्त है और अनुमानों के लिए इसका उपयोग किया गया है। सीएजीआर व्यवहार में अस्थिरता को दूर करता है और विशेष रूप से लंबी अवधि के लिए अनुमान लगाने के लिए हमें एक सरल संख्या प्रदान करता है।

अनुमान लगाते समय, किसी विशेष जिले के सकल घरेलू उत्पाद का सीएजीआर लेने और फिर एक्सट्रपलेशन करने के बजाय, किसी विशेष जिले के लिए 9 श्रेणियों में संबंधित गतिविधियों की जीडीपी को एक्सट्रपलेशन किया गया है और उन्हें जिले के कुल जीडीपी तक पहुंचने के लिए सारांशित किया गया है।

इसके बाद, किसी दिए गए डेटा में एनसीआर के विभिन्न घटकों के सकल घरेलू उत्पाद को उस वर्ष में एनसीआर के कुल सकल घरेलू उत्पाद पर पहुंचने के लिए जोड़ा गया है। गतिविधियों की नौ श्रेणियों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का एक्सट्रपलेशन स्वचालित रूप से एक विशेष प्रकार की गतिविधि के वजन को ध्यान में रखता है। इसलिए, प्रकृति में यथार्थवादी है।

सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 2004-05 की स्थिर कीमतों पर व्यावहारिक परिदृश्य के साथ बनाया गया है। भौतिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि, श्रम शक्ति में वृद्धि, मानव पूंजी विकास और तकनीकी प्रगति जैसे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनका भविष्य के सकल घरेलू उत्पाद को तय करने वाले कारकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।[6]

सूचना के प्रमुख स्रोत

सीएसओ द्वारा प्रकाशित चौथी और पांचवीं आर्थिक जनगणना: कृषि (फसल उत्पादन और वृक्षारोपण को छोड़कर) और गैर-कृषि के भीतर उद्यमशीलता इकाइयों की संख्या, आर्थिक विकास के संख्यात्मक संकेतक, उद्यमशीलता गतिविधियों का विवरण जैसे जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। पंजीकरण विवरण, स्थान, संचालन की प्रकृति, वित्त, संस्थानों की संख्या और इन प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की संख्या। अध्ययन में एनसीआर में गैर-कृषि गतिविधियों में अनौपचारिक क्षेत्र के आकलन के लिए 1998 और 2005 का उपयोग किया गया है।

सीएसओ द्वारा प्रकाशित एनएसएस रिपोर्ट: असंगठित सेवा क्षेत्र के उद्यमों (व्यापार के अलावा) की परिचालन और आर्थिक विशेषताओं पर विशेष रूप से इसकी संख्या, रोजगार, मूल्य वर्धित और इस क्षेत्र की अन्य आवश्यक विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट से उपलब्ध डेटा अनौपचारिक क्षेत्र, रोजगार और जनशक्ति से संबंधित अध्यायों में बहुत उपयोगी है।

राज्य स्तरीय आर्थिक सर्वेक्षण: संबंधित राज्यों के आर्थिक और सांख्यिकीय विभागों द्वारा प्रकाशित, रिपोर्ट का उपयोग जीडीपी और औद्योगिक विकास पर जानकारी एकत्र करने के लिए किया गया था।

जिला सांख्यिकीय हैंडबुक: जिला स्तरीय डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है (दिल्ली के एनसीटी को छोड़कर जहां राज्य स्तर पर जानकारी मुख्य रूप से विश्लेषण के लिए नियोजित होती है)

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

[6] *<http://data.worldbank.org/about/data-overview/methodologies>

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

अनुलग्नक 2. 1: वर्ष 2013-14 में भारत, राज्यों और एनसीआर की जीडीपी

वर्ष 20013-14 **के लिए वर्तमान मूल्य पर जीडीपी**			**वर्ष** 2013-14 **के लिए स्थिर** (2004-05) **कीमतों पर जीडीपी**		
रैंक	देश/राज्य	जीडीपी (करोड़ रुपये में)	रैंक	देश/राज्य	जीडीपी (करोड़ रुपये में)
	भारत	**1,04,72,807**		भारत	**57,41,791**
1	महाराष्ट्र	14,76,233	1	महाराष्ट्र	8,97,786
2	उत्तर प्रदेश	8,90,265	2	उत्तर प्रदेश	4,65,969
3	आंध्र प्रदेश	8,54,822	3	आंध्र प्रदेश	4,57,351
4	तमिलनाडु	8,54,238	4	तमिलनाडु	4,80,618
5	पश्चिम बंगाल	7,00,117	5	पश्चिम बंगाल	3,74,899
6	कर्नाटक	5,82,754	6	कर्नाटक	3,14,356
7	राजस्थान	5,13,688	7	राजस्थान	2,44,997
8	मध्य प्रदेश	4,50,900	8	मध्य प्रदेश	2,38,526
9	दिल्ली	4,04,576	9	दिल्ली	2,36,156
10	हरियाणा	3,83,911	10	हरियाणा	1,98,858
11	बिहार	3,43,054	11	बिहार	1,74,734
12	पंजाब	3,17,054	12	पंजाब	1,73,221
13	ओडिशा	2,88,414	13	ओडिशा	1,48,226
14	छत्तीसगढ	1,85,060	14	छत्तीसगढ	94,560
15	झारखंड	1,72,773	15	झारखंड	1,09,408
16	असम	1,62,652	16	असम	88,537
17	उत्तराखंड	1,22,433	17	उत्तराखंड	67,927
18	जम्मू और कश्मीर	87,319	18	जम्मू और कश्मीर	45,399
19	हिमाचल प्रदेश	82,585	19	हिमाचल प्रदेश	47,255
20	चंडीगढ़	29,076	20	चंडीगढ़	15,688
21	पुडुचेरी	21,061	21	पुडुचेरी	13,813
22	मेघालय	21,045	22	मेघालय	13,465
23	नगालैंड	17,749	23	नगालैंड	11,367
24	अरुणाचल प्रदेश	13,491	24	अरुणाचल प्रदेश	6,141
25	सिक्किम	12,377	25	सिक्किम	6,152
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,150	26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,220
लागू नहीं	गोवा	लागू नहीं	लागू नहीं	गोवा	लागू नहीं
लागू नहीं	गुजरात	लागू नहीं	लागू नहीं	गुजरात	लागू नहीं

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

लागू नहीं	केरल	लागू नहीं	लागू नहीं	केरल	लागू नहीं
लागू नहीं	मणिपुर	लागू नहीं	लागू नहीं	मणिपुर	लागू नहीं
लागू नहीं	मिजोरम	लागू नहीं	लागू नहीं	मिजोरम	लागू नहीं
लागू नहीं	एनसीआर	लागू नहीं	लागू नहीं	एनसीआर (2009-10)	**3,19,347.43**
लागू नहीं	त्रिपुरा	लागू नहीं	लागू नहीं	त्रिपुरा	लागू नहीं

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

अनुलग्नक 2. 2: **वर्ष** 2013-14 **में भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय**

वर्ष 2013-14 **के लिए वर्तमान मूल्य पर पीसीआई**			**वर्ष** 2004-05 **के लिए निरंतर मूल्य पर पीसीआई**		
रैंक	देश/राज्य	प्रति व्यक्ति आय (रु.)	रैंक	देश/राज्य	प्रति व्यक्ति आय (रु.)
	भारत	**74,380**		भारत	**39,904**
1	दिल्ली	2,19,979	1	दिल्ली	1,27,667
2	सिक्किम	1,76,491	2	पुदुचेरी	96,222
3	चंडीगढ़	1,56,951	3	सिक्किम	83,527
4	पुदुचेरी	1,48,784	4	चंडीगढ़	82,798
5	हरयाणा	1,32,089	5	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	72,716
6	महाराष्ट्र	1,14,392	6	महाराष्ट्र	69,584
7	तमिलनाडु	1,12,664	7	हरयाणा	67,317
8	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,07,418	8	तमिलनाडु	62,361
9	उत्तराखंड	1,03,349	9	उत्तराखंड	56,822
10	पंजाब	92,638	10	हिमाचल प्रदेश	54,494
11	हिमाचल प्रदेश	92,300	11	नगालैंड	49,963
12	आंध्र प्रदेश	88,876	12	पंजाब	49,411
13	अरुणाचल प्रदेश	84,869	13	आंध्र प्रदेश	46,788
14	कर्नाटक	84,709	14	कर्नाटक	45,024
15	नगालैंड	77,529	15	अरुणाचल प्रदेश	37,767
16	पश्चिम बंगाल	69,413	16	मेघालय	37,439
17	राजस्थान	65,098	17	पश्चिम बंगाल	36,527
18	जम्मू और कश्मीर	58,593	18	जम्मू और कश्मीर	31,054
19	मेघालय	58,522	19	राजस्थान	30,120
20	छत्तीसगढ़-गढ़	58,297	20	झारखंड	28,882
21	ओडिशा	54,241	21	छत्तीसगढ़	28,113
22	मध्य प्रदेश	54,030	22	मध्य प्रदेश	27,917
23	असम	46,354	23	ओडिशा	25,891
24	झारखंड	46,131	24	असम	24,533
25	उत्तर प्रदेश	37,630	25	उत्तर प्रदेश	19,234
26	बिहार	31,229	26	बिहार	15,650
लागू नहीं	गोवा	लागू नहीं	लागू नहीं	गोवा	लागू नहीं

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

लागू नहीं	गुजरात	लागू नहीं	लागू नहीं	गुजरात	लागू नहीं
लागू नहीं	केरल	लागू नहीं	लागू नहीं	केरल	लागू नहीं
लागू नहीं	मणिपुर	लागू नहीं	लागू नहीं	मणिपुर	लागू नहीं
लागू नहीं	मिजोरम	लागू नहीं	लागू नहीं	मिजोरम	लागू नहीं
लागू नहीं	त्रिपुरा	लागू नहीं	लागू नहीं	त्रिपुरा	लागू नहीं
	एनसीआर			एनसीआर (2009-10)	59,264

अस्वीकरण: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा इस कार्यात्मक योजना को तैयार करते समय सभी सावधानियां बरती गयी हैं, फिर भी किसी बिंदु पर हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों में अनुरूपता न पाए जाने पर अंग्रेजी दस्तावेज को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

अनुलग्नक 2. 3: वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक जीडीपी के सीएजीआर की गणना और 2011, 2016, 2021, 2026, 2031 के लिए जीडीपी का अनुमान

	स्थिर (2004-05) कीमतों पर वास्तविक जीडीपी							स्थिर (2004-05) कीमतों पर अनुमानित जीडीपी				
क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	सीएजीआर	2011	2016	2021	2026	2031
	जीडीपी (मिलियन रुपये में)	जीडीपी (मिलियन रुपये में)	जीडीपी (मिलियन रुपये में)	जीडीपी (मिलियन रुपये में)	जीडीपी (मिलियन रुपये में)	जीडीपी (मिलियन रुपये में)		जीडीपी (मिलियन में)	जीडीपी (मिलियन में)	जीडीपी (मिलियन में)	जीडीपी (मिलियन में)	जीडीपी (मिलियन में)
मेरठ	71,760.6	81,598.94	85,739.16	91,741.39	93,859.36	1,01,254.56	7.13	1,08,473	1,53,055	2,15,962	3,04,723	4,29,966
बागपत	29,072.7	28,550.69	30,675.61	32,878.24	34,721.48	38,426.16	5.74	40,631	53,703	70,980	93,817	1,24,000
गाजियाबाद+हापुड़	89,271.38	97,684.35	1,16,072.75	1,24,785.67	1,31,283.88	1,36,475.9	8.86	1,48,568	2,27,127	3,47,226	53,0830	8,11,521
गौतमबुद्ध नगर	73,533.04	75,276.19	1,17,301.88	1,26,289.94	1,31,113.97	1,41,557.06	14.00	1,61,369	3,10,649	5,98,025	11,51,247	22,16,243
बुलंदशहर	68,799.56	66,288.34	74,341.09	78,724.65	83,337.35	88,739.5	5.22	93,373	1,20,436	1,55,341	2,00,363	2,58,433
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	**3,32,437.28**	**3,49,398.51**	**4,24,130.49**	**4,54,419.89**	**4,74,316.04**	**5,06,453.18**	**8.78**	**5,50,941**	**8,39,334**	**12,78,687**	**19,48,022**	**29,67,724**
दिल्ली	10,03,245.2	11,04,060.7	12,40,795.8	13,79,608.6	15,57,910.9	16,98,389.8	11.10	18,86,963	31,94,432	54,07,842	91,54,914	1,54,98,318
एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र	**10,03,245.2**	**11,04,060.7**	**12,40,795.8**	**13,79,608.6**	**15,57,910.9**	**16,98,389.8**	**11.10**	**18,86,963**	**31,94,432**	**54,07,842**	**91,54,914**	**1,54,98,318**
अलवर	77,420.3	77,425.7	90,451.3	93,576.1	1,10,109.8	1,21,901	9.50	1,33,487	2,10,179	3,30,935	5,21,069	8,20,441
राजस्थान उप-क्षेत्र	77,420.3	77,425.7	90,451.3	93,576.1	1,10,109.8	1,21,901	9.50	1,33,487	2,10,179	3,30,935	5,21,069	8,20,441
फरीदाबाद	1,11,351.3	1,21,775.9	1,36,362.8	1,51,289.1	1,62,483.8	1,90,014.6	11.28	2,11,449	3,60,825	6,15,728	10,50,704	17,92,966
गुडगाँव	1,66,984.4	1,80,864	2,02,167	2,27,493.5	2,42,417.8	2,69,905.5	10.08	2,97,111	4,80,236	7,76,230	12,54,661	20,27,973
झज्जर	28,356.3	30,757.1	34,252.7	36,861.3	40,157	44,947.9	9.65	49,286	78,123	1,23,834	1,96,291	3,11,144

पानीपत	65,641	72,170.5	79,052.8	88,334.2	1,00,821.3	99,297.5	8.63	1,07,868	1,63,175	2,46,841	3,73,405	5,64,863
रेवाड़ी	43,623.8	47,154.9	51,646.3	56,206.5	60,465.4	65,930.6	8.61	71,608	1,08,224	1,63,564	2,47,201	3,73,606
रोहतक	32,447.2	34,565.7	37,592.9	40,120.7	41,930.8	47,052.3	7.72	50,683	73,496	1,06,578	1,54,551	2,24,118
सोनीपत	48,414.2	52,734.5	58,439.5	62,897.9	68,729.4	77,067.6	9.74	84,577	1,34,633	2,14,314	3,41,153	5,43,060
मेवात	NA	20,637.4	21,933.9	23,362.9	27,919.4	29,967.8	9.77	32,897	52,439	83,590	1,33,246	2,12,400
पलवल						42,546.5	NA	NA	NA	NA	NA	NA
हरियाणा उप-क्षेत्र	**4,96,818.2**	**5,60,660**	**6,21,447.9**	**6,86,566.1**	**7,44,924.9**	**8,66,730.3**	**11.77**	**9,68,771**	**16,90,082**	**29,48,453**	**51,43,760**	**89,73,610**
एनसीआर	**19,09,920.98**	**20,91,544.91**	**23,76,825.49**	**26,14,170.69**	**28,87,261.64**	**31,93,474.28**	**10.83**	**35,39,265**	**59,17,810**	**98,94,847**	**1,65,44,631**	**2,76,63,372**

स्रोत: योजना आयोग, updes.nic.in, *हरियाणा और दिल्ली के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग; और एसीडीएस अनुमान*

अनुलग्नक 2. 4: स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का क्षेत्रवार योगदान (रुपये मिलियन में) की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

क्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
प्राथमिक	7,633	7,827	7,673	7,549	7,676	7,675	7,406	7,409	7,134
द्वितीयक	1,00,817	1,11,293	1,07,871	1,24,232	1,24,448	1,50,117	1,67,832	1,79,558	1,87,879
तृतीयक	4,43,751	4,56,926	4,82,769	5,11,748	5,47,950	6,02,028	6,68,532	7,83,890	8,96,995
जीडीपी-एनसीटी दिल्ली	**5,52,201**	**5,76,046**	**5,98,313**	**6,43,529**	**6,80,074**	**7,59,820**	**8,43,770**	**9,70,857**	**10,92,008**
प्राथमिक	14,896	14,535	15,804	12,066	20,237	17,939	16,865	20,815	20,984
द्वितीयक	16,781	15,802	14,001	16,195	17,638	19,320	20,109	21,920	31,140
तृतीयक	21,604	21,683	21,407	22,108	24,261	26,161	27,295	31,540	41,451
जीडीपी-राजस्थान उप-क्षेत्र	**53,281**	**52,020**	**51,212**	**50,369**	**62,136**	**63,420**	**64,269**	**74,275**	**93,575****
प्राथमिक*	43,255	45,323	46,756	44,270	46,508	51,154	54,872	57,096	59,410
द्वितीयक*	91,077	97,664	1,06,578	1,13,300	1,25,539	1,40,025	1,56,879	1,71,792	1,88,123
तृतीयक*	93,986	1,28,788	1,46,565	1,63,675	1,79,952	2,01,663	2,35,574	2,74,645	3,20,195
जीडीपी-हरियाणा उप-क्षेत्र	**2,28,318**	**2,71,775**	**2,99,899**	**3,21,245**	**3,51,999**	**3,92,842**	**4,47,325**	**5,03,532**	**5,67,728**
प्राथमिक	59,312	63,851	61,988	64,404	66,114	70,179	70,268	75,013	75,704
द्वितीयक	79,195	74,492	74,721	75,287	79,039	90,215	96,886	1,09,306	1,22,705
तृतीयक	80,017	90,562	93,284	96,885	1,02,323	1,10,678	1,18,032	1,25,823	1,35,858
जीडीपी- यूपी उप क्षेत्र	**2,18,524**	**2,28,905**	**2,29,993**	**2,36,576**	**2,47,476**	**2,71,072**	**2,85,186**	**3,10,142**	**3,34,266**
प्राथमिक	1,25,096	1,31,536	1,32,221	1,28,289	1,40,536	1,46,947	1,49,410	1,60,333	1,63,231
द्वितीयक	2,87,870	2,99,251	3,03,171	3,29,014	3,46,619	3,99,446	4,43,059	4,82,576	5,29,846
तृतीयक	6,39,358	6,97,959	7,44,025	7,94,416	8,54,454	9,40,358	10,50,078	12,15,897	13,94,499
एनसीआर के स्थिर मूल्यों पर कुल जीडीपी	**10,52,324**	**11,28,746**	**11,79,417**	**12,51,719**	**13,41,609**	**14,86,751**	**16,42,547**	**18,58,806**	**20,87,577**
* इंगित करता है कि हरियाणा 2006 और 2007 में पिछले वर्षों के सीएजीआर पर डेटा का एक्सट्रपलेशन किया गया है									
** इंगित करता है कि राजस्थान में 2007 के आंकड़े 2004-05 के आधार मूल्य पर रहे हैं									

स्रोत: www.planningcommission.nic.in और http://updes.up.nic.in

अनुलग्नक 2. 5: 1999-2000 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

मुख्य क्षेत्र	श्रेणी	क्षेत्र / जिला	फरीदाबाद	गुड़गांव	झज्जर	पानीपत	रेवाड़ी	रोहतक	सोनीपत	हरियाणा उप-क्षेत्र	अलवर	राजस्थान उप-क्षेत्र	मेरठ	बागपत	गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	दिल्ली एनसीटी	कुल एनसीआर
प्राथमिक क्षेत्र	1	कृषि मजदूर, किसान, और पशुधन, वानिकी आदि	7,124	6,583	4,697	5,193	3,871	4,838	9,527	41,833	14,697	14,697	1,4623	8514	10,568	6,116	18,535	58,356	7,620	1,22,506
	2	खनन और उत्खनन	1,211	135	2	11	3	1	53	1,416	199	199	192	209	293	163	95	952	20	2,587
द्वितीयक क्षेत्र	3	उत्पादन, प्रसंस्करण	19,455	33,919	3,212	3,849	5,786	2,553	3,929	72,703	1,1613	11,613	11,768	1221	18,660	24,023	6,069	61,741	63,000	2,09,057
	4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	839	468	148	1,251	139	337	492	3,674	21,172	21,172	1,400	569	2,252	851	1,637	6,709	6,730	38,285
	5	निर्माण	3,595	1,428	1,558	1,745	1,138	1,514	1,917	12,895	3,050	3,050	3,450	606	3,827	748	2,106	10,737	31,080	57,762
तृतीयक क्षेत्र	6	व्यापार और वाणिज्य	13,902	15,173	905	9,767	3,179	1,374	2,635	46,935	10,542	10,542	6,266	2762	5,739	6,891	6,003	27,661	1,17,490	2,02,628
	7	यातायात, भंडारण और संचार	3,559.8	3,288	1,366	1,390	1,186	1,759	1,997	14,545.8	1,893	1,893	2,876	906	4,420	1,358	2,352	11,912	58,480	86,831
	8	वित्तपोषण, बीमा, रियल-एस्टेट और व्यवसाय सेवाएं	6,389	10,123	1,484	2,050	1,424	2,187	2,350	26,007	3,645	3,645	4,696	1544	6,347	2,474	3,384	18,445	1,78,080	2,26,177
	9	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	5,124	4,233	2,462	2,061	2,395	3,245	3,042	22,562	5,524	5,524	6,392	1999	6,731	2,455	4,403	21,980	89,720	1,39,786
	1 स 9	कुल जीडीपी	61,199	75,350	15,834	27,317	19,121	17,808	25,942	2,42,571	72,335	72,335	51,663	18330	58,837	45,079	44,584	2,18,493	5,52,220	10,85,619

स्रोत: *www.planningcommission.gov.in* और *www.delhiplanning.nic.in*

अनुलग्नक 2.6: वर्ष 2000-01 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

मुख्य क्षेत्र	श्रेणी	क्षेत्र / जिला	फरीदाबाद	गुड़गांव	झज्जर	पानीपत	रेवाड़ी	रोहतक	सोनीपत	हरियाणा उप-क्षेत्र	अलवर	राजस्थान उप-क्षेत्र	मेरठ	बागपत	गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	दिल्ली एनसीटी	कुल एनसीआर
प्राथमिक क्षेत्र	1	कृषि मजदूर, किसान, और पशुधन, वानिकी आदि	7,634	7,227	4,463	5,208	3,943	5,353	9,865	43,693	14,378	14,378	15,337	9,366	11,452	7,008	19,489	62,652	7,620	1,28,343
	2	खनन और उत्खनन	1,335	205	2	12	3	1	60	1,618	155	155	244	290	306	187	162	1,189	20	2,982
द्वितीयक क्षेत्र	3	उत्पादन, प्रसंस्करण	24,852	30,531	5,115	4,645	6,751	3,394	3,483	78,771	10,864	10,864	10,370	1,114	18,264	21,486	5,964	57,198	63,000	20,9,833
	4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	903	484	153	1,322	142	349	513	3,866	21,198	21,198	1,478	597	2,371	892	1,727	7,065	6,730	38,859
	5	निर्माण	3,983	3,348	1,364	1,743	1,177	1,551	1,857	15,022	2,119	2,119	3,409	599	3,588	720	1,910	10,226	31,080	58,447
तृतीयक क्षेत्र	6	व्यापार और वाणिज्य	16,808	18,345	1,095	11,809	3,844	1,662	3,186	56,749	10,104	10,104	6,842	2,842	7,924	7,629	6,771	32,007	1,17,490	2,16,349
	7	यातायात, भंडारण और संचार	4,205	3,809	1,576	1,613	1,362	1,997	2,331	16,893	2,085	2,085	3,416	1,121	5,321	1,701	2,900	14,457	58,480	91,914
	8	वित्तपोषण, बीमा, रियल- एस्टेट और व्यवसाय सेवाएं	7,633	14,899	1,592	2,123	1,516	2,365	2,528	32,656	3,792	3,792	5,274	1,728	7,260	2,819	3,669	20,750	1,78,080	2,35,278
	9	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	5,232	4,134	2,329	1,965	2,032	3,368	3,431	22,490	5,703	5,703	6,855	1,964	7,459	3,250	3,820	23,349	89,720	1,41,262
	1 स 9	कुल जीडीपी	72,585	82,982	17,689	30,438	20,770	20,039	27,255	2,71,757	70,397	70,397	53,224	19,620	63,945	45,692	46,412	2,28,893	5,52,220	11,23,267

स्रोत: www.planningcommission.gov.in और www.delhiplanning.nic.in

अनुलग्नक 2.7: वर्ष 2001-02 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

मुख्य क्षेत्र	श्रेणी	क्षेत्र / जिला	फरीदाबाद	गुड़गांव	झज्जर	पानीपत	रेवाड़ी	रोहतक	सोनीपत	हरियाणा उप-क्षेत्र	अलवर	राजस्थान उप-क्षेत्र	मेरठ	बागपत	गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	दिल्ली एनसीटी	कुल एनसीआर
प्राथमिक क्षेत्र	1	कृषि मजदूर, किसान, और पशुधन, वानिकी आदि	8,124	7,060	4,560	4,877	3,890	5,643	10,559	44,712	15,661	15,661	15,640	8,549	10,925	5,962	20,185	61,261	7,620	1,29,254
	2	खनन और उत्खनन	1,701	222	5	26	3	1	87	2,045	143	143	172	163	166	158	69	727	60	2,975
द्वितीयक क्षेत्र	3	उत्पादन, प्रसंस्करण	27,671	32,106	4,393	3,860	9,603	3,117	5,157	85,907	8,919	8,919	8,994	1,345	17,369	22,804	6,156	56,669	60,060	2,11,554
	4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	1,373	761	441	468	124	231	340	3,738	1,904	1,904	1,498	596	2,393	896	1,735	7,119	7,810	20,570
	5	निर्माण	4,190	2,825	1,596	2,577	1,306	2,002	2,440	16,934	3,178	3,178	3,951	637	3,490	829	2,027	10,935	40,000	71,046
तृतीयक क्षेत्र	6	व्यापार और वाणिज्य	18,836	20,559	1,227	13,234	4,308	1,862	3,571	63,597	9,274	9,274	6,817	2,764	7,822	7,949	7,258	32,610	1,31,480	2,36,960
	7	यातायात, भंडारण और संचार	4,892	4,318	1,891	1,856	1,576	2,305	2,667	19,505	2,333	2,333	3,568	1,173	5,566	1,785	2,985	15,076	66,990	1,03,904
	8	वित्त पोषण, बीमा, रियल-एस्टेट और व्यवसाय सेवाएं	8,912	19,752	1,686	2,270	1,590	2,565	2,704	39,480	4,039	4,039	5,614	1,819	7,773	2,999	3,832	22,036	1,91,780	2,57,335
	9	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	5,521	4,364	2,564	2,129	2,127	3,602	3,677	23,983	5,761	5,761	6,632	2,191	7,372	3,392	3,974	23,561	92,520	1,45,826
	1 से 9	कुल जीडीपी	81,219	91,968	18,362	31,297	24,526	21,327	31,201	2,99,900	51,212	51,212	52,887	19,236	62,876	46,773	48,221	2,29,993	5,98,320	11,79,425

स्रोत: www.planningcommission.gov.in और www.delhiplanning.nic.in

अनुलग्नक 2.8: वर्ष 2002-03 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

मुख्य क्षेत्र	श्रेणी	क्षेत्र / जिला	फरीदाबाद	गुड़गांव	झज्जर	पानीपत	रेवाड़ी	रोहतक	सोनीपत	हरियाणा उप-क्षेत्र	अलवर	राजस्थान उप-क्षेत्र	मेरठ	बागपत	गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	दिल्ली एनसीटी	कुल एनसीआर
प्राथमिक क्षेत्र	1	कृषि मजदूर, किसान, और पशुधन, वानिकी आदि	7,255	7,001	4,622	5,346	2,990	5,289	10,514	43,017	11,918	11,918	15,854	8,873	11,715	5,601	21,400	63,442	7,490	1,25,867
	2	खनन और उत्खनन	509	554	5	23	70	1	91	1,254	149	149	172	222	273	117	178	962	60	2,425
द्वितीयक क्षेत्र	3	उत्पादन, प्रसंस्करण	22,983	34,707	3,174	7,343	11,857	4,168	5,659	89,890	10,342	10,342	8,380	1,447	16,568	22,153	8,372	56,918	67,790	2,24,941
	4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	1,039	553	173	1,530	163	400	647	4,504	2,418	2,418	1,497	617	2,409	906	1,732	7,161	8,170	22,253
	5	निर्माण	4,612	3,302	1,998	2,471	1,456	2,222	2,846	18,906	3,434	3,434	3,237	647	4,451	855	2,019	11,208	48,270	81,818
तृतीयक क्षेत्र	6	व्यापार और वाणिज्य	4,612	3,302	1,998	2,471	1,456	2,222	2,846	18,906	3,434	3,434	3,237	647	4,451	855	2,019	11,208	48,270	81,818
	7	यातायात, भंडारण और संचार	5,616	4,919	2,158	2,086	1,792	2,636	3,051	22,258	2,567	2,567	3,953	1,234	6,029	1,930	3,245	16,392	73,400	1,14,617
	8	वित्तपोषण, बीमा, रियल-एस्टेट और व्यवसाय सेवाएं	10,819	24,755	1,806	2,478	1,702	2,772	2,957	47,288	4,339	4,339	6,100	1,978	8,456	3,251	4,082	23,868	2,04,850	2,80,345
	9	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	5,794	4,628	2,622	2,230	2,194	3,763	3,828	25,058	5,750	5,750	6,996	2,422	7,407	3,509	4,101	24,434	94,480	1,49,722
	1 स 9	कुल जीडीपी	63,239	83,721	18,554	25,977	23,680	23,471	32,438	2,71,080	44,351	44,351	49,425	18,086	61,758	39,177	47,149	2,15,594	5,52,780	10,83,805

अनुलग्नक 2.8: वर्ष 2002-03 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

स्रोत: *www.planningcommission.gov.in* और *www.delhiplanning.nic.in*

अनुलग्नक 2.9: वर्ष 2003-04 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

मुख्य क्षेत्र	श्रेणी	क्षेत्र / जिला	फरीदाबाद	गुड़गांव	झज्जर	पानीपत	रेवाड़ी	रोहतक	सोनीपत	हरियाणा उप-क्षेत्र	अलवर	राजस्थान उप-क्षेत्र	मेरठ	बागपत	गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	दिल्ली एनसीटी	कुल एनसीआर
प्राथमिक क्षेत्र	1	कृषि मजदूर, किसान, और पशुधन, वानिकी आदि	7,431	7,316	4,596	5,561	3,242	5,748	11,240	45,134	20,106	20,106	17,486	9,168	12,179	5,809	2,05,39	65,182	7,560	1,37,982
	2	खनन और उत्खनन	1,280	1	3	22	11	1	57	1,374	132	132	162	210	283	113	164	933	120	2,559
द्वितीयक क्षेत्र	3	उत्पादन, प्रसंस्करण	23,499	45,595	5,503	5,605	10,350	2,596	5,678	98,825	10,688	10,688	9,338	1,629	16,741	24,487	6,305	58,500	63,260	2,31,273
	4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	1,142	586	185	1,693	172	425	691	4,895	2,613	2,613	1,617	655	2,679	978	1,872	7,801	8,730	24,039
	5	निर्माण	5,234	4,063	2,117	3,101	1,708	2,500	3,095	21,818	4,292	4,292	3,910	743	4,728	1,026	2,331	12,738	524,60	91,308
तृतीयक क्षेत्र	6	व्यापार और वाणिज्य	21,659	23,640	1,411	15,217	4,953	2,141	4,106	73,126	10,722	10,722	7,248	2,956	7,843	8,167	7,254	33,467	1,45,280	2,62,594
	7	यातायात, भंडारण और संचार	6,616	5,756	2,519	2,428	2,066	3,048	3,567	26,001	2,947	2,947	4,350	1,397	6,688	2,172	3,691	18,297	84,630	1,31,875
	8	वित्तपोषण, बीमा, रियल-एस्टेट और व्यवसाय सेवाएं	11,618	30,370	1,897	2,573	1,762	2,946	3,116	54,284	4,467	4,467	6,253	1,997	8,860	3,407	4,135	24,651	2,20,980	3,04,382
	9	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	6,206	4,908	2,727	2,397	2,363	3,889	4,052	26,542	6,093	6,093	7,409	2,571	7,798	3,687	4,443	25,908	97,060	1,55,603
	1 सं 9	कुल जीडीपी	84,686	1,22,235	20,958	38,595	26,627	23,296	35,603	3,51,999	62,059	62,059	57,773	21,326	67,798	49,845	50,734	2,47,476	6,80,080	13,41,615

अनुलग्नक 2.9: वर्ष 2003-04 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

स्रोत: *www.planningcommission.gov.in* और *www.delhiplanning.nic.in*

अनुलग्नक 2.10: वर्ष 2004-05 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

मुख्य क्षेत्र	श्रेणी	क्षेत्र / जिला	फरीदाबाद	गुड़गांव	झज्जर	पानीपत	रेवाड़ी	रोहतक	सोनीपत	हरियाणा उप-क्षेत्र	अलवर	राजस्थान उप-क्षेत्र	मेरठ	बागपत	गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	दिल्ली एनसीटी	कुल एनसीआर
प्राथमिक क्षेत्र	1	कृषि मजदूर, किसान, और पशुधन, वानिकी आदि	9,131	8,457	5,231	6,361	4,577	5,944	10,082	49,782	16,645	16,645	17,687	9,702	13,234	6,029	22,341	68,993	7,620	1,43,039
	2	खनन और उत्खनन	1,189	1	3	69	10	1	100	1,372	219	219	202	262	345	162	217	1,187	60	2,839
द्वितीयक क्षेत्र	3	उत्पादन, प्रसंस्करण	25,618	49,839	5,990	6,055	11,291	2,797	6,163	1,07,753	13,349	13,349	8,232	1,643	18,314	32,486	6,660	67,335	70,660	2,59,097
	4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	1,210	627	198	1,787	185	456	733	5,196	2,450	2,450	1,664	678	2,737	1,012	1,939	8,030	9,900	25,575
	5	निर्माण	6,734	4,300	2,433	4,946	1,995	2,983	3,686	27,077	5,663	5,663	4,402	800	6,035	1,110	2,504	14,851	69,560	1,17,151
तृतीयक क्षेत्र	6	व्यापार और वाणिज्य	24,398	26,629	1,589	1,7141	5,580	2,412	4,625	82,374	1,2696	12,696	6,988	3,062	8,509	10,394	7,863	36,815	1,53,840	2,85,725
	7	यातायात, भंडारण और संचार	7,497	6,582	2,783	2,734	2,330	3,502	4,077	29,506	3,832	3,832	4,773	1,547	7,353	2,404	4,098	20,175	96,490	1,50,003
	8	वित्तपोषण, बीमा, रियल-एस्टेट और व्यवसाय सेवाएं	12,743	35,789	2,010	2,687	1,859	3,154	3,472	61,715	3,295	3,295	6,664	2,119	9,611	3,701	4,328	26,423	2,41,880	3,33,312
	9	समुदाय,	6,53	5,29	2,93	2,5	2,41	4,0	4,2	28,06	6,50	6,505	8,0	2,6	8,0	3,20	5,30	27,265	1,09,	1,71,6

		सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	8	8	7	27	8	92	59	9	5		23	57	80	5	0		810	49
	1 से 9	कुल जीडीपी	95,057	1,37,522	23,173	44,307	30,245	25,340	37,197	3,92,843	64,654	64,654	58,635	22,469	74,217	60,503	55,250	2,71,073	7,59,820	14,88,390

स्रोत: *www.planningcommission.gov.in* और *www.delhiplanning.nic.in*

अनुलग्नक 2.11: वर्ष 2005-06 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

मुख्य क्षेत्र	श्रेणी	क्षेत्र / जिला	फरीदाबाद	गुड़गांव	झज्जर	पानीपत	रेवाड़ी	रोहतक	सोनीपत	हरियाणा उप-क्षेत्र	अलवर	राजस्थान उप-क्षेत्र	मेरठ	बागपत	गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	दिल्ली एनसीटी	कुल एनसीआर	मुख्य क्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्र	1	कृषि मजदूर, किसान, और पशुधन, वानिकी आदि	6,998	4,266	6,039	6,131	6,928	5,326	6,663	9,931	52,281	17,747	17,747	19,651	8,462	15,536	6,286	18,902	68,837	7,410	1,46,274
	2	खनन और उत्खनन	2,309	1	1	110	53	13	1	104	2,591	193	193	245	337	431	173	245	1,431	0	4,215
द्वितीयक क्षेत्र	3	उत्पादन, प्रसंस्करण	27,725	53,460	6,551	1,467	6,603	12,363	1,949	6,733	1,16,851	12,069	12,069	8,820	1,734	19,932	36,005	7,018	73,509	77,020	2,79,449
	4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	1,586	851	623	650	653	176	316	545	5,399	2,332	2,332	1,688	687	2,713	1,026	1,967	8,080	10,200	26,011
	5	निमोण	7,233	4,902	2,917	2,842	4,924	2,690	3,580	4,443	33,531	4,689	4,689	4,821	896	5,676	1,212	2,692	15,297	806	54,323
तृतीयक क्षेत्र	6	व्यापार और वाणिज्य	23,930	31,503	2,028	259	25,712	5,488	1,742	5,398	9,6059	12,086	12,086	7,789	2,833	9,602	11,342	7,009	38,575	1,86,870	3,33,590
	7	यातायात, भंडारण और संचार	8,479	5,334	3,213	1,723	3,001	2,572	3,836	4,546	32,702	3,323	3,323	5,207	1,773	8,102	2,681	4,545	22,307	1,02,620	1,60,952
	8	वित्तपोषण, बीमा, रियल-एस्टेट और व्यवसाय सेवाएं	15,429	39,864	2,154	1,738	2,854	1,985	3,412	3,795	71,230	4,612	4,612	7,099	2,249	10,439	4,033	4,530	28,349	2,64,690	3,68,881

अनुलग्नक 2.11: वर्ष 2005-06 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

	9	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	6,532	3,762	2,99 6	2,423	2,769	2,709	3,997	4,569	29,75 7	5,970	5,970	8,459	2,818	8,578	3,326	5,620	28,801	1,14,3 50	1,78,87 8
	1 स 9	कुल जीडीपी	1,00,2 21	1,43,9 43	26,5 22	17,34 4	53,49 5	33,32 0	25,49 5	40,06 4	4,40,4 02	63,01 8	63,01 8	63,778	21,79 0	81,01 0	66,08 2	52,52 6	2,85,18 6	7,63,9 66	1,55,25 72

स्रोत: *www.planningcommission.gov.in* और *www.delhiplanning.nic.in*

अनुलग्नक 2.12: वर्ष 2006-07 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

मुख्य क्षेत्र	श्रेणी	क्षेत्र / जिला	फरीदाबाद	गुड़गांव	झज्जर	पानीपत	रेवाड़ी	रोहतक	सोनीपत	हरियाणा उप-क्षेत्र	अलवर	राजस्थान उप-क्षेत्र	मेरठ	बागपत	गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	दिल्ली एनसीटी	कुल एनसीआर
प्राथमिक क्षेत्र	1	कृषि मजदूर, किसान, और पशुधन, वानिकी आदि	6,977	3,967	6,297	7,270	5,617	7,028	10,000	46,912	20,535	20,535	20,274	10,031	15,673	6,277	21,051	73,306	7,410	1,48,163
	2	खनन और उत्खनन	2,572	1	1	68	16	1	116	2,726	280	280	290	383	525	216	293	1,707	0	4,713
द्वितीयक क्षेत्र	3	उत्पादन, प्रसंस्करण	29,414	57,680	7,380	7,226	14,034	1,863	7,367	1,24,636	13,475	13,475	10,886	2,393	20,135	35,737	9,213	78,364	82,700	2,99,175
	4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	1,763	940	792	586	183	313	555	4,957	2,159	2,159	1,908	778	3,087	1,162	2,213	9,149	10,700	26,965
	5	निर्माण	8,129	6,023	3,239	5,855	3,105	4,134	5,113	35,471	6,287	6,287	6,763	1,261	8,081	1,736	3,952	21,793	86,160	1,49,711
तृतीयक क्षेत्र	6	व्यापार और वाणिज्य	26,202	35,591	2,320	30,223	6,012	1,812	6,085	1,07,923	13,910	13,910	8,444	3,437	9,761	11,314	8,220	41,175	2,10,670	37,36,78
	7	यातायात, भंडारण और संचार	9,801	5,782	3,706	3,412	2,926	4,369	5,215	35,147	5,316	5,316	5,637	1,932	8,958	2,965	4,812	24,305	1,37,200	2,01,968
	8	वित्तपोषण, बीमा, रियल-एस्टेट और व्यवसाय	17,87	50,1	2,29	3,01	2,098	3,674	4,111	81,88	5,55	5,55	7,52	2,39	10,9	4,264	4,83	30,0	3,20,	4,37,

अनुलग्नक 2.12: वर्ष 2006-07 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

		सेवाएं	7	17	2	6				7	5	5	1	4	91		0	01	470	913
	9	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	6,802	3,689	3,096	2,909	2,765	4,139	4,890	28,225	6,759	6,759	8,607	2,895	9,170	3,684	5,985	30,342	1,15,550	1,80,875
	1 से 9	कुल जीडीपी	1,08,826	1,60,374	28,907	59,849	36,558	27,069	43,080	4,64,238	74,276	74,276	70,330	25,504	86,381	67,356	60,571	3,10,142	9,70,860	18,19,516

स्रोत: *www.planningcommission.gov.in* और *www.delhiplanning.nic.in*

अनुलग्नक 2.13: वर्ष 2007-08 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

मुख्य क्षेत्र	श्रेणी	क्षेत्र / जिला	फरीदाबाद	गुड़गांव	झज्जर	पानीपत	रेवाड़ी	रोहतक	सोनीपत	हरियाणा उप-क्षेत्र	अलवर	राजस्थान उप-क्षेत्र	मेरठ	बागपत	गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	दिल्ली एनसीटी	कुल एनसीआर
प्राथमिक क्षेत्र	1	कृषि मजदूर, किसान, और पशुधन, वानिकी आदि	6,956	3,690	6,567	7,628	5,924	7,414	10,070	47,688	20,011	20,011	20,015	9,999	16,060	6,602	21,584	74,260	7,130	1,49,089
	2	खनन और उत्खनन	2,865	0	1	88	21	1	130	2,993	971	971	254	342	481	183	183	1,443	0	5,408
द्वितीयक क्षेत्र	3	उत्पादन, प्रसंस्करण	31,207	62,234	8,312	7,907	15,931	1,781	8,060	13,4630	19,446	19,446	11,563	2,242	21,063	36,595	9,334	80,798	87,960	3,22,834
	4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	1,961	1,039	1007	525	190	310	564	5,174	3,566	3,566	2,246	910	3,598	1,357	2,551	10,663	12,440	31,843
	5	निर्माण	9,136	7,401	3,597	6,963	3,585	4,773	5,883	40,997	8,127	8,127	9,969	1,661	11,656	2,452	5,507	31,244	87,480	1,67,849
तृतीयक क्षेत्र	6	व्यापार और वाणिज्य	28,689	40,209	2,655	35,525	6,586	1,885	6,859	1,21,580	18,009	18,009	8,373	3,310	9,891	11,410	8,181	41,164	2,25,290	4,06,043
	7	यातायात, भंडारण और संचार	11,330	6,269	4,275	3,880	3,330	4,976	5,983	39,877	4,590	4,590	6,518	2,232	10,284	3,453	5,639	28,126	1,86,150	2,58,743
	8	वित्तपोषण, बीमा, रियल-एस्टेट और व्यवसाय सेवाएं	20,713	63,008	2,439	3,188	2,218	3,958	4,454	96,494	9,007	9,007	8,991	2,934	13,381	5,198	5,545	36,049	3,65,180	5,06,730
	9	समुदाय,	7,084	3,61	3,199	3,05	2,82	4,28	5,23	29,1	9,84	9,841	8,34	2,75	9,650	3,964	5,802	30,518	12,03	81,54

अनुलग्नक 2.13: वर्ष 2007-08 में एनसीआर की जीडीपी स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 1999-2000) रुपये मिलियन में

		सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं		7		6	3	5	4	44	1		7	5					7	0
	1 स 9	कुल जीडीपी	1,18,169	1,78,681	31,508	66,958	40,111	28,741	46,323	5,09,427	93,568	93,568	76,274	26,387	96,063	71,216	64,326	3,34,266	9,83,667	19,20,928

स्रोत: *www.planningcommission.gov.in* और *www.delhiplanning.nic.in* *आधार वर्ष *2004-05*

अनुलग्नक 3. 1: 2001 में एनसीआर में कुल कार्यबल का वितरण और भागीदारी दर

श्रेणी	1	2	3		4	5			6	7	8	9		1 से 9		
क्षेत्र	कृषि मजदूर	किसान	पशुपालन, वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	निर्माण, प्रसंस्करण			निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	अन्य सेवाएं		कुल कार्यबल	कुल जनसंख्या	भागीदारी दर
जिला						a) घरेलू उद्योग	b) घरेलू उद्योगों के अलावा	C) बिजली, गैस और बिजली				वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं			
फरीदाबाद	82,175	1,86,403	46,513	39,924	4,476	65,918	52,788	57,172	92,582	38,370	62,321	27,201	29,113	7,85,762	21,94,586	35.80
गुडगाँव	57,928	1,95,768	72,640	25,719	10,868	31,668	25,199	44,611	54,460	32,733	47,504	19,397	18,070	6,29,658	16,60,289	37.92
झज्जर	44,844	1,77,377	15,765	11,027	241	37,547	7,217	15,602	20,293	14,025	22,031	10,505	6,493	3,88,715	8,80,072	44.17
पानीपत	55,042	89,493	21,867	72,535	598	22,445	12,926	21,975	39,523	13,266	17,259	98,16	10,394	3,82,801	9,67,449	39.57
रेवाड़ी	44,441	1,48,218	21,187	11,481	858	12,622	11,837	15,437	21,410	9,703	17,297	10,018	4,939	3,33,622	7,65,351	43.59
रोहतक	45,462	1,43,314	14,530	13,379	295	21,377	6,158	21,724	34,225	16,835	25,553	16,602	7,981	3,71,073	9,40,128	39.47
सोनीपत	87,390	1,89,673	30,471	19,468	689	36,666	12,188	24,694	37,958	20,508	33,983	18,987	8,621	5,23,031	12,79,175	40.89
हरियाणा उप-क्षेत्र	4,17,282	11,30,246	2,18,955	1,93,533	18,025	2,28,243	1,28,313	2,01,215	3,00,451	145,440	2,25,948	1,12,526	85,611	34,14,662	86,87,050	39.31
बागपत	70,220	1,51,325	16,827	21,571	173	15,989	5,975	13,478	28,858	11,145	20,196	11,068	6,110	3,80,310	11,63,991	32.67
बुलंद शहर	1,95,852	4,19,885	1,40,583	82,754	417	38,343	22,806	41,351	98,260	32,489	60,295	21,461	19,330	11,73,805	29,13,122	40.29
गौतमबुद्ध नगर	34,338	93,015	13,884	20,839	850	17,772	16,761	21,637	37,036	16,594	59,172	12,950	16,917	3,63,814	12,02,030	30.27
गाज़ियाबाद	69,775	1,60,566	38,113	89,367	1,638	66,885	46,526	81,035	1,41,734	66,229	1,04,783	35,586	32,203	9,38,251	32,90,586	28.51
मेरठ	1,10,440	2,17,120	45,821	80,514	471	50,441	29,050	65,168	1,14,126	46,239	72,331	30,345	24,363	8,95,856	29,97,361	29.89

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	4,80,625	10,41,911	2,55,228	2,95,045	3,549	1,89,430	1,21,118	2,22,669	4,20,014	1,72,696	3,16,777	1,11,410	98,923	37,52,036	1,15,67,090	32.44
अलवर	1,28,442	9,05,207	82,083	45,703	4,992	43,016	16,809	45,810	70,538	37,133	34,937	29,883	14,778	14,58,686	29,92,592	48.74
राजस्थान उप-क्षेत्र	1,28,442	9,05,207	82,083	45,703	4,992	43,016	16,809	45,810	70,538	37,133	34,937	29,883	14,778	14,58,686	29,92,592	48.74
एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र	15,773	37,431	37,353	5,12,571	15,873	4,19,273	2,35,541	3,95,608	10,61,214	4,80,580	7,38,180	2,78,482	3,41,443	43,46,710	1,38,50,507	31.38
एनसीआर	10,42,122	31,14,795	5,93,619	10,46,852	42,439	8,79,962	5,01,781	8,65,302	18,52,217	8,35,849	13,15,842	5,32,301	5,40,755	1,29,72,094	3,70,97,239	34.97

स्रोत: जनगणना भारत *2001*

अनुलग्नक 3. 2: 2001 में एनसीआर में मुख्य कार्यबल का वितरण और भागीदारी दर

	जिला	कृषि मजदूर और किसान	पशुपालन, वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	a) घरेलू उद्योग	b) घरेलू उद्योगों के अलावा	C) बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ	कुल मुख्य कार्यबल	गैर श्रमिक	कुल जनसंख्या	मुख्य श्रमिकों की भागीदारी दर
हरियाणा	फरीदाबाद	1,64,734	25,824	33,334	3,891	59,911	49,091	44,210	84,524	35,777	58,619	25,711	24,037	6,09,663	14,08,824	21,94,586	27.78
	गुड़गाँव	1,54,526	37,961	21,173	8,952	26,230	23,658	33,868	49,280	30,132	45,582	18,298	14,984	4,64,644	10,30,631	16,60,289	27.99
	झज्जर	1,44,057	9,806	8,114	202	28,547	6,522	11,371	18,234	13,112	21,299	9,889	5,055	2,76,208	4,91,357	8,80,072	31.38
	पानीपत	93,658	9,662	60,470	569	13,861	11,383	18,235	35,880	12,472	15,912	9,152	7,759	2,89,013	5,84,648	9,67,449	29.87
	रेवाड़ी	96,647	11,504	7,393	758	8,820	11,064	11,027	19,166	9,003	16,304	9,439	3,730	2,04,855	4,31,729	7,65,351	26.77
	रोहतक	1,38,743	8,752	10,607	287	16,052	5,266	16,441	30,822	15,692	23,896	15,920	5,747	2,88,225	5,69,055	9,40,128	30.66
	सोनीपत	1,79,642	20,456	16,053	687	24,274	11,276	19,254	34,711	19,327	32,488	18,348	6,933	3,83,449	7,56,144	12,79,175	29.98
	हरियाणा उप-क्षेत्र	9,72,007	1,23,965	1,57,144	15,346	1,77,695	1,18,260	1,54,406	2,72,617	1,35,515	2,14,100	1,06,757	68,245	25,16,057	52,72,388	86,87,050	28.96
उत्तर प्रदेश	बागपत	1,66,204	11,349	17,275	153	11,131	4,952	10,368	25,523	10,131	17,133	10,494	5,149	2,89,862	7,83,681	11,63,991	24.90
	बुलंदशहर	4,07,211	62,779	47,823	380	30,124	17,062	30,616	81,039	29,197	45,536	19,713	15,228	7,86,708	17,39,317	29,13,122	27.01
	गौतमबुद्ध नगर	1,04,669	10,033	17,665	810	14,035	14,054	17,908	33,954	15,208	53,155	12,410	14,983	3,08,884	8,38,216	12,02,030	25.70
	गाज़ियाबाद	1,78,028	28,895	75,715	1,583	59,724	41,996	63,711	1,29,794	61,939	96,330	33,750	28,419	7,99,884	23,52,335	32,90,586	24.31
	मेरठ	2,54,581	33,238	66,004	422	43,550	24,730	50,364	1,05,644	42,454	66,542	28,742	20,895	7,37,166	8,55,494	29,97,361	24.59
	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	11,10,693	1,46,294	2,24,482	3,348	1,58,564	1,02,794	1,72,967	3,75,954	1,58,929	2,78,696	1,05,109	84,674	29,22,504	65,69,043	1,15,67,090	25.27
राजस्थान	अलवर	6,11,306	35,375	35,632	4,299	36,437	14,843	38,311	63,738	34,581	32,487	28,494	12,084	9,47,587	15,33,906	29,92,592	31.66
	राजस्थान	6,11,306	35,375	35,632	4,299	36,437	14,843	38,311	63,738	34,581	32,487	28,494	12,084	9,47,587	15,33,906	29,92,592	31.66

न	उप-क्षेत्र																
दिल्ली	दिल्ली क्षेत्र का योग	32,430	34,141	4,69,719	15,105	4,00,520	2,24,302	3,42,996	10,21,816	4,65,616	7,23,447	2,67,712	3,19,712	43,17,516	93,05,273	1,38,50,507	31.17
एनसीआर	एनसीआर में कुल श्रमिक	27,26,436	3,39,775	8,86,977	38,098	7,73,216	4,60,199	7,08,680	17,34,125	7,94,641	12,48,730	5,08,072	4,84,715	1,07,03,664	2,26,80,610	3,70,97,239	28.85

स्रोत: जनगणना भारत- 2001

अनुलग्नक 3. 3: 2001 में एनसीआर में सीमांत कार्यबल का वितरण और भागीदारी दर

	जिला	कृषि मजदूर और किसान	पशुपालन, वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	a) घरेलू उद्योग	b) घरेलू उद्योगों के अलावा	C) बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ	कुल सीमांत कार्यबल	गैर श्रमिक	कुल जनसंख्या	मुख्य श्रमिकों की भागीदारी दर
हरियाणा	फरीदाबाद	1,04,650	20,689	6,590	585	6,007	3,697	12,962	8,058	2,593	3,702	1,490	5,076	1,76,099	14,08,824	21,94,586	8.02
	गुडगाँव	92,263	34,679	4,546	1,916	5,438	1,541	10,743	5,180	2,601	1,922	1,099	3,086	1,65,014	10,30,631	16,60,289	9.94
	झज्जर	83,912	5,959	2,913	39	9,000	695	4,231	2,059	913	732	616	1,438	1,12,507	4,91,357	8,80,072	12.78
	पानीपत	46,539	12,205	12,065	29	8,584	1,543	3,740	3,643	794	1,347	664	2,635	93,788	5,84,648	9,67,449	9.69
	रेवाड़ी	1,01,902	9,683	2,372	100	3,802	773	4,410	2,244	700	993	579	1,209	1,28,767	4,31,729	7,65,351	16.82
	रोहतक	54,142	5,307	2,772	8	5,325	892	5,283	3,403	1,143	1,657	682	2,234	82,848	5,69,055	9,40,128	8.81
	सोनीपत	99,156	10,015	3,415	2	12,392	912	5,440	3,247	1,181	1,495	639	1,688	1,39,582	7,56,144	12,79,175	10.91
	हरियाणा उप-क्षेत्र	**5,82,564**	**98,537**	**34,673**	**2,679**	**50,548**	**10,053**	**46,809**	**27,834**	**9,925**	**11,848**	**5,769**	**17,366**	**8,98,605**	**52,72,388**	**86,87,050**	**10.34**
उत्तर प्रदेश	बागपत	62,716	5,478	4,296	20	4,858	1,023	3,110	3,335	1,014	3,063	574	961	90,448	7,83,681	11,63,991	7.77
	बुलंद शहर	2,08,477	77,804	34,931	65	8,219	5,744	10,735	17,221	3,292	14,759	1,748	4,102	3,87,097	17,39,317	29,13,122	13.29
	गौतमबुद्धनगर	24,733	3,851	3,174	40	3,737	2,707	3,729	3,082	1,386	6,017	540	1,934	54,930	8,38,216	12,02,030	4.57
	गाज़ियाबाद	56,079	9,218	13,652	100	7,161	4,530	17,324	11,940	4,290	8,453	1,836	3,784	1,38,367	23,52,335	32,90,586	4.20
	मेरठ	82,406	12,583	14,510	49	6,891	4,320	14,804	8,482	3,785	5,789	1,603	3,468	1,58,690	8,55,494	29,97,361	5.29
	यूपी उप-क्षेत्र	**4,34,411**	**1,08,934**	**70,563**	**274**	**30,866**	**18,324**	**49,702**	**44,060**	**13,767**	**38,081**	**6,301**	**14,249**	**8,29,532**	**65,69,043**	**1,15,67,090**	**7.17**
राजस्थान	अलवर	4,21,698	46,708	10,071	693	6,579	1,966	7,499	6,800	2,552	2,450	1,389	2,694	5,11,099	15,33,906	29,92,592	17.08

	राजस्थान उप-क्षेत्र	**4,21,698**	**46,708**	**10,071**	**693**	**6,579**	**1,966**	**7,499**	**6,800**	**2,552**	**2,450**	**1,389**	**2,694**	**511099**	**1533906**	**29,92,592**	**17.08**
दिल्ली	एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**9,009**	**3,212**	**30,529**	**768**	**18,753**	**11,239**	**52,612**	**39,398**	**14,964**	**14,733**	**10,770**	**21,731**	**2,27,718**	**93,05,273**	**1,38,50,507**	**1.64**
एनसीआर		**14,47,682**	**2,57,391**	**1,45,836**	**4,414**	**1,06,746**	**41,582**	**1,56,622**	**1,18,092**	**41,208**	**67,112**	**24,229**	**56,040**	**24,66,954**	**2,26,80,610**	**3,70,97,239**	**6.65**

स्रोतः जनगणना भारत- 2001

अनुलग्नक 3. 4: 2001 में एनसीआर में शहरी कार्यबल का वितरण और भागीदारी दर

	क्षेत्र	कृषि मजदूर	किसान	पशुपालन वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	उत्पादन, प्रसंस्करण			निर्माण	व्यापार और वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	अन्य सेवाएं		कुल श्रमिक	शहरी जनसंख्या	शहरी भागीदारी दर
उप-क्षेत्र	जिला						a) घरेलू उद्योग	b) घरेलू उद्योगों के अलावा	C) बिजली, गैस और पावर				वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ			
हरियाणा	फरीदाबाद	6,032	6,743	32,672	27,924	2,976	48,748	45,638	39,892	76,062	28,550	48,326	20,186	21,928	3,74,777	12,21,344	30.69
	गुडगाँव	3,280	3,724	3,000	8,144	288	7,318	10,374	11,216	27,460	10,248	19,014	9,472	7,220	1,12,326	3,69,004	30.44
	झज्जर	1,668	4,644	2,500	4,912	116	8,202	4,572	6,532	10,978	5,100	8,116	4,200	2,558	59,070	1,95,097	30.28
	पानीपत	1,246	1,463	2,072	53,990	388	6,190	9,246	11,040	27,638	7,446	9,284	5,566	6,094	87,285	3,92,080	22.26
	रेवाड़ी	1,329	1,370	752	2,960	48	2,762	3,322	3,762	11,440	3,208	5,202	2,888	1,614	37,649	1,36,174	27.65
	रोहतक	2,246	2,229	2,034	6,604	220	5,782	3,088	12,054	23,380	8,640	14,318	10,702	4,446	88,919	3,29,604	26.98
	सोनीपत	4,066	2,945	2,896	6,998	174	5,986	5,768	9,754	22,788	8,698	12,568	9,482	4,266	89,217	3,21,375	27.76
	हरियाणा उप-क्षेत्र	**19,867**	**23,118**	**45,926**	**1,11,532**	**4,210**	**84,988**	**82,008**	**94,250**	**1,99,746**	**71,890**	**1,16,828**	**62,496**	**48,126**	**8,49,243**	**29,64,678**	**28.65**
उत्तर प्रदेश	बागपत	4,516	9,644	1,702	6,286	68	3,744	1,760	4,998	14,428	4,430	6,086	3,668	2,190	57,166	2,29,432	24.92
	बुलंदशहर	13,284	12,589	4,488	25,074	250	12,228	7,476	13,476	51,520	15,654	26,510	8,986	6,800	1,73,011	6,74,458	25.65
	गौतमबुद्धनगर	2,990	4,491	3,204	11,464	500	7,692	9,436	13,142	25,696	10,924	39,882	7,010	11,002	1,35,469	4,49,415	30.14
	गाज़ियाबाद	7,510	10,014	7,588	56,212	1,348	42,470	32,486	48,040	1,06,694	50,764	77,148	25,746	21,178	4,29,638	18,16,415	23.65
	मेरठ	15,275	12,895	7,366	46,704	336	30,286	17,470	39,948	86,596	33,874	57,116	20,660	14,738	3,36,224	14,51,983	23.16
	यूपी उप-क्षेत्र	**43,575**	**49,633**	**24,348**	**1,45,740**	**2,502**	**96,420**	**68,628**	**1,19,604**	**2,84,934**	**1,15,646**	**2,06,742**	**66,070**	**55,908**	**11,31,508**	**46,21,703**	**24.48**
राजस्था	अलवर	2,133	9,662	5,928	13,088	222	13,016	5,974	12,460	31,378	12,058	16,882	11,528	5,118	1,26,359	4,34,939	29.05

न	राजस्थान उप-क्षेत्र	2,133	9,662	5,928	13,088	222	13,016	5,974	12,460	31,378	12,058	16,882	11,528	5,118	1,26,359	4,34,939	29.05
दिल्ली	एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	7,418	10,730	25,828	4,73,528	13,938	3,89,888	2,21,226	3,61,038	10,15,604	4,49,000	6,97,740	2,63,092	3,24,828	37,66,392	1,29,05,780	29.18
एनसीआर		53,126	70,025	56,104	6,32,356	16,662	4,99,324	2,95,828	4,93,102	13,31,916	5,76,704	9,21,364	3,40,690	3,85,854	50,24,259	1,79,62,422	27.97

स्रोत: भारत की जनगणना *2001*

अनुलग्नक 3. 5: 2001 में नौ श्रेणियों में एनसीआर में ग्रामीण कार्यबल का वितरण और भागीदारी दर

	क्षेत्र	कृषि मजदूर	किसान	पशुपालन वानिकी आदि	ग्रामीण उद्योग	खनन और उत्खनन	उत्पादन, प्रसंस्करण			निर्माण	व्यापार और वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	अन्य सेवाएं		कुल श्रमिक	शहरी जनसंख्या	शहरी भागीदारी दर
उप-क्षेत्र	जिला						a) घरेलू उद्योग	b) घरेलू उद्योगों के अलावा	C) बिजली, गैस और पावर				वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ			
हरियाणा	फरीदाबाद	76,143	179,660	13,841	12,000	1,500	17,170	7,150	17,280	16,520	9,820	13,995	7,015	7,185	3,79,279	9,73,242	38.97
	गुडगाँव	54,648	1,92,044	69,640	17,575	10,580	24,350	14,825	33,395	27,000	22,485	28,490	9,925	10,850	5,15,807	12,91,285	39.95
	झज्जर	43,176	1,72,733	13,265	6,115	125	29,345	2,645	9,070	9,315	8,925	13,915	6,305	3,935	3,18,869	6,84,975	46.55
	पानीपत	53,796	88,030	19,795	18,545	210	16,255	3,680	10,935	11,885	5,820	7,975	4,250	4,300	2,45,476	5,75,369	42.66
	रेवाड़ी	43,112	1,46,848	20,435	6,805	810	9,860	8,515	11,675	9,970	6,495	12,095	7,130	3,325	2,87,075	6,29,177	45.63
	रोहतक	43,216	1,41,085	12,025	6,775	75	15,595	3,070	9,670	10,845	8,195	11,235	5,900	3,535	2,71,221	6,10,524	44.42
	सोनीपत	83,324	1,86,728	27,575	12,479	515	30,680	6,420	14,940	15,170	11,810	21,415	9,505	4,355	4,24,916	9,57,800	44.36
हरियाणा उप-क्षेत्र		**3,97,415**	**11,07,128**	**1,76,576**	**80,294**	**13,815**	**1,43,255**	**46,305**	**1,06,965**	**1,00,705**	**73,550**	**1,09,120**	**50,030**	**37,485**	**24,42,643**	**57,22,372**	**42.69**
उत्तर प्रदेश	बागपत	65,704	1,41,681	15,125	15,282	105	12,245	4,215	8,480	14,430	6,715	14,110	7,400	3,920	3,09,412	9,34,559	33.11
	बुलंद शहर	1,82,568	4,07,296	1,36,095	57,680	195	26,115	15,330	27,875	46,740	16,835	33,785	12,475	12,530	9,75,519	22,38,664	43.58
	गौतमबुद्ध नगर	31,348	88,524	10,680	9,375	350	10,080	7,325	8,495	11,340	5,670	19,290	5,940	5,915	2,14,332	7,52,615	28.48
	गाज़ियाबाद	62,265	1,50,552	30,525	33,155	335	24,415	14,040	32,995	35,040	15,465	27,635	9,840	11,025	44,7287	14,74,171	30.34
	मेरठ	95,165	2,04,225	38,455	33,810	135	20,155	11,580	25,220	27,530	12,365	15,215	9,685	9,625	5,03,165	15,45,378	32.56
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र		**4,37,050**	**9,92,278**	**2,30,880**	**1,49,302**	**1,120**	**93,010**	**52,490**	**1,03,065**	**1,35,080**	**57,050**	**1,10,035**	**45,340**	**43,015**	**24,49,715**	**69,45,387**	**35.27**

राजस्थान	अलवर	1,26,309	8,95,545	76,155	32,615	4,770	30,000	10,835	33,350	39,160	25,075	18,055	18,355	9,660	13,19,884	25,57,653	51.61
राजस्थान उप-क्षेत्र		**1,26,309**	**8,95,545**	**76,155**	**32,615**	**4,770**	**30,000**	**10,835**	**33,350**	**39,160**	**25,075**	**18,055**	**18,355**	**9,660**	**13,19,884**	**25,57,653**	**51.61**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र		8,355	26,701	11,525	29,720	2,025	29,385	14,315	34,570	45,610	31,580	40,440	15,390	16,615	3,06,231	9,44,727	32.41
एनसीआर		**9,69,129**	**30,21,652**	**4,95,136**	**291,931**	**21,730**	**2,95,650**	**1,23,945**	**2,77,950**	**3,20,555**	**1,87,255**	**2,77,650**	**1,29,115**	**1,06,775**	**65,18,473**	**1,61,70,139**	**40.31**

स्रोत: भारत की जनगणना *2001*

अनुबंध 3.6: 2011 में मुख्य और सीमांत और ग्रामीण और शहरी में श्रमिकों का वितरण

	मुख्य श्रमिक					सीमांत श्रमिक					संयुक्त कुल (मुख्य + सीमांत)					कुल श्रमिक		
जिला/उप-क्षेत्र	किसान	कृषि श्रमिक	एचएच उद्योग	अन्य श्रमिक	कुल सीमांत श्रमिक	किसान	कृषि श्रमिक	एचएच उद्योग	अन्य श्रमिक	कुल सीमांत श्रमिक	किसान	कृषि श्रमिक	एचएच इंडस्ट्रीज	अन्य श्रमिक	कुल कार्यबल	ग्रामीण	शहरी	कुल कार्य बल
उत्तर पश्चिम	10,127	10,553	33,767	10,80,679	11,35,126	1,306	2,736	2,129	47,248	53,419	11,433	13,289	35,896	11,27,927	11,88,545	67,492	11,21,053	11,88,545
उत्तर	1,967	1,493	10,403	2,69,720	2,83,583	220	298	625	11,720	12,863	2,187	1,791	11,028	2,81,440	2,96,446	5,278	2,91,168	2,96,446
उत्तर पूर्व	1,738	1,893	27,587	5,91,225	6,22,443	497	513	3,151	34,782	38,943	2,235	2,406	30,738	6,26,007	6,61,386	5,988	6,55,398	6,61,386
पूर्व	805	2,841	18,432	5,32,948	5,55,026	351	253	1,109	22,953	24,666	1,156	3,094	19,541	5,55,901	5,79,692	1,348	5,78,344	5,79,692
नई दिल्ली	80	223	962	55,206	56,471	41	52	68	2,909	3,070	121	275	1,030	58,115	59,541		59,541	59,541
मध्य	463	511	10,342	1,84,662	1,95,978	134	90	560	10,612	11,396	597	601	10,902	1,95,274	2,07,374		2,07,374	2,07,374
पश्चिम	2,433	3,725	27,623	8,05,840	8,39,621	519	633	1,399	32,148	34,699	2,952	4,358	29,022	8,37,988	8,74,320	1,846	8,72,474	8,74,320
दक्षिण पश्चिम	7,832	5,277	16,956	7,19,930	7,49,995	1,901	2,476	1,658	39,322	45,357	9,733	7,753	18,614	7,59,252	7,95,352	44,049	7,51,303	7,95,352
दक्षिण	2,314	4,958	23,054	8,38,760	8,69,086	670	950	2027	51,660	55,307	2,984	5,908	25,081	8,90,420	9,24,393	4,226	9,20,167	9,24,393
दिल्ली एनसीटी	**27,759**	**31,474**	**1,69,126**	**50,78,970**	**53,07,329**	**5,639**	**8,001**	**12,726**	**2,53,354**	**2,79,720**	**33,398**	**39,475**	**1,81,852**	**5,332,324**	**55,87,049**	**1,30,227**	**54,56,822**	**55,87,049**
फरीदाबाद	23,654	19,382	27,869	4,24,411	4,95,316	4,051	9,906	4,417	65,539	83,913	27,705	29,288	32,286	4,89,950	5,79,229	1,06,758	4,72,471	5,79,229
गुडगाँव	44,429	15,725	16,002	4,11,285	4,87,441	11,617	11,372	2,226	32,060	57,275	56,046	27,097	18,228	4,43,345	5,44,716	1,58,462	3,86,254	5,44,716
रेवाड़ी	73,994	10,452	6,249	1,59,524	2,50,219	28,704	17,763	3,533	37,508	87,508	1,02,698	28,215	9,782	1,97,032	3,37,727	2,64,375	73,352	3,37,727
रोहतक	80,456	20,616	6,353	1,81,524	2,88,949	15,276	15,952	2,168	23,622	57,018	95,732	36,568	8,521	2,05,146	3,45,967	2,12,681	1,33,286	3,45,967
सोनीपत	1,10,262	54,040	12,405	2,20,056	3,96,763	32,082	47,693	5,779	40,862	1,26,416	1,42,344	1,01,733	18,184	2,60,918	5,23,179	3,76,188	1,46,991	5,23,179
पानीपत	61,474	36,191	12,485	2,28,866	3,39,016	10,646	26,167	3,339	33,150	73,302	72,120	62,358	15,824	2,62,016	4,12,318	2,21,931	1,90,387	4,12,318

झज्जर	86,313	19,433	6,520	1,34,191	2,46,457	26,076	25,412	2,734	25,855	80,077	1,12,389	44,845	9,254	1,60,046	3,26,534	2,53,833	7,2701	3,26,534
मेवात	81,608	25,426	4,034	93,110	2,04,178	22,629	29,852	1,989	31,316	85,786	1,04,237	55,278	6,023	1,24,426	2,89,964	2,58,721	31,243	2,89,964
पलवल	71,540	26,229	5,616	1,13,547	2,16,932	19,966	34,456	2,950	35,259	92,631	91,506	60,685	8,566	1,48,806	3,09,563	2,42,228	67,335	3,09,563
हरियाणा उप क्षेत्र	**6,33,730**	**2,27,494**	**97,533**	**19,66,514**	**29,25,271**	**1,71,047**	**2,18,573**	**29,135**	**3,25,171**	**7,43,926**	**8,04,777**	**4,46,067**	**1,26,668**	**2,291,685**	**3,669,197**	**20,95,177**	**15,74,020**	**36,69,197**
अलवर	6,08,718	95,586	21,588	4,53,569	11,79,461	2,90,173	1,21,186	12,974	1,04,748	5,29,081	8,98,891	2,16,772	34,562	5,58,317	1,708,542	14,87,935	2,20,607	17,08,542
राजस्थान उप क्षेत्र	**6,08,718**	**95,586**	**21,588**	**4,53,569**	**11,79,461**	**2,90,173**	**1,21,186**	**12,974**	**1,04,748**	**5,29,081**	**8,98,891**	**2,16,772**	**34,562**	**5,58,317**	**1,708,542**	**14,87,935**	**2,20,607**	**17,08,542**
बागपत	1,12,453	49,442	13,958	1,58,666	3,34,519	12,265	25,058	6,389	38,464	82,176	1,24,718	74,500	20,347	1,97,130	416,695	3,37,563	79,132	4,16,695
बुलंदशहर	2,92,901	13,6780	44,401	4,11,134	8,85,216	39,574	1,04,357	21,536	1,22,577	2,88,044	3,32,475	2,41,137	65,937	5,33,711	1,173,260	9,19,473	2,53,787	11,73,260
गौतमबुद्ध नगर	60,899	27,618	26,065	3,43,910	4,58,492	11,769	21,227	9,335	68,286	1,10,617	72,668	48,845	35,400	4,12,196	5,69,109	2,16,673	3,52,436	5,69,109
गाजियाबाद + हापुड़	1,39,829	83,227	63,604	9,66,251	12,52,911	19,039	40,453	20,068	1,88,067	2,67,627	1,58,868	1,23,680	83,672	11,54,318	15,20,538	4,96,077	10,24,461	15,20,538
मेरठ	1,75,944	1,12,247	48,232	5,54,387	8,90,810	20,124	41,748	14,864	1,22,993	1,99,729	1,96,068	1,53,995	63,096	6,77,380	10,90,539	5,43,366	5,47,173	10,90,539
उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	**7,82,026**	**4,09,314**	**1,96,260**	**24,34,348**	**38,21,948**	**1,02,771**	**2,32,843**	**72,192**	**5,40,387**	**9,48,193**	**8,84,797**	**6,42,157**	**2,68,452**	**29,74,735**	**47,70,141**	**25,13,152**	**22,56,989**	**47,70,141**
एनसीआर	**20,52,233**	**7,63,868**	**4,84,507**	**99,33,401**	**1,32,34,009**	**5,69,630**	**5,80,603**	**1,27,027**	**12,23,660**	**25,00,920**	**26.21,863**	**13,44,471**	**6,11,534**	**1,11,57,061**	**1,57,34,929**	**62,26,491**	**95,08,438**	**1,57,34,929**

स्रोत: भारत की जनगणना *2011* और एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन

अनुलग्नक 3.7: 2011 में कुल कार्यबल, जनसंख्या और ग्रामीण और शहरी में भागीदारी का वितरण

	कुल श्रमिक			जनसंख्या			डब्ल्यू पीआर		
जिलेवार/उप क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
उत्तर पश्चिम	67,492	11,21,053	1,188,545	2,13,950	34,42,589	36,56,539	31.55	32.56	32.50
उत्तर	5,278	2,91,168	2,96,446	17,746	870,232	8,87,978	29.74	33.46	33.38
उत्तर पूर्व	5,988	6,55,398	6,61,386	21,527	22,20,097	22,41,624	27.82	29.52	29.50
पूर्व	1,348	5,78,344	5,79,692	3,530	17,05,816	17,09,346	38.19	33.90	33.91
नई दिल्ली		59,541	59,541	0	1,42,004	1,42,004	0	41.93	41.93
मध्य		2,07,374	2,07,374	0	5,82,320	5,82,320	0	35.61	35.61
पश्चिम	1,846	8,72,474	8,74,320	6,420	25,36,823	25,43,243	28.75	34.39	34.38
दक्षिण पश्चिम	44,049	7,51,303	7,95,352	1,43,676	21,49,282	22,92,958	30.66	34.96	34.69
दक्षिण	4,226	9,20,167	9,24,393	12,193	27,19,736	27,31,929	34.66	33.83	33.84
दिल्ली एनसीटी	**1,30,227**	**54,56,822**	**55,87,049**	**4,19,042**	**1,63,68,899**	**1,67,87,941**	**31.08**	**33.34**	**33.28**
फरीदाबाद	1,06,758	4,72,471	5,79,229	3,70,878	14,38,855	18,09,733	28.79	32.84	32.01
गुडगाँव	1,58,462	3,86,254	5,44,716	4,72,179	10,42,253	15,14,432	33.56	37.06	35.97
रेवाड़ी	2,64,375	73,352	3,37,727	6,66,902	2,33,430	9,00,332	39.64	31.42	37.51
रोहतक	2,12,681	1,33,286	3,45,967	6,15,040	4,46,164	10,61,204	34.58	29.87	32.60
सोनीपत	3,76,188	1,46,991	5,23,179	9,96,637	4,53,364	14,50,001	37.75	32.42	36.08
पानीपत	2,21,931	1,90,387	4,12,318	6,50,352	5,55,085	12,05,437	34.12	34.30	34.20
झज्जर	2,53,833	72,701	3,26,534	7,15,066	2,43,339	9,58,405	35.50	29.88	34.07
मेवात	2,58,721	31,243	2,89,964	9,65,157	1,24,106	10,89,263	26.81	25.17	26.62
पलवल	2,42,228	67,335	3,09,563	8,06,164	2,36,544	10,42,708	30.05	28.47	29.69

हरियाणा उप क्षेत्र	**20,95,177**	**15,74,020**	**36,69,197**	**62,58,375**	**47,73,140**	**1,10,31,515**	**33.48**	**32.98**	**33.26**

	कुल श्रमिक			जनसंख्या			डब्ल्यू पीआर		
जिलेवार/उप क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
अलवर	14,87,935	2,20,607	17,08,542	30,19,728	6,54,451	36,74,179	49.27	33.71	46.50
राजस्थान उप क्षेत्र	**14,87,935**	**2,20,607**	**17,08,542**	**30,19,728**	**6,54,451**	**36,74,179**	**49.27**	**33.71**	**46.50**
बागपत	3,37,563	79,132	4,16,695	10,28,023	2,75,025	1,30,30,48	32.84	28.77	31.98
बुलंदशहर	9,19,473	2,53,787	11,73,260	26,31,742	8,67,429	34,99,171	34.94	29.26	33.53
गौतमबुद्धनगर	2,16,673	3,52,436	569,109	6,73,806	9,74,309	16,48,115	32.16	36.17	34.53
गाजियाबाद + हापुड़	4,96,077	10,24,461	15,20,538	15,19,098	31,62,547	46,81,645	32.66	32.39	32.48
मेरठ	5,43,366	5,47,173	10,90,539	16,84,507	17,59,182	34,43,689	32.26	31.10	31.67
उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	**25,13,152**	**22,56,989**	**47,70,141**	**75,37,176**	**70,38,492**	**1,45,75,668**	**33.34**	**32.07**	**32.73**
एनसीआर	**62,26,491**	**95,08,438**	**1,57,34,929**	**1,72,34,321**	**2,88,34,982**	**4,60,69,303**	**36.13**	**32.98**	**34.15**

स्रोत: भारत की जनगणना 2011 और एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन

अनुलग्नक 3.8: एनसीआर की जनसंख्या का अनुमान (लाख में)

	जनसंख्या						
जिले/उप-क्षेत्र	**2011** (वास्तविक)	**2016**	**2021**	**2026**	**2031**	**2036**	**2041**
मेरठ	34.44	37.10	39.92	42.96	46.22	49.74	53.52
बागपत	13.03	13.80	14.62	15.50	16.42	17.41	18.45
गाज़ियाबाद*	46.82	55.91	67.06	80.43	96.47	115.70	138.78
गौतमबुद्ध नगर	16.48	19.99	23.87	28.50	34.02	40.62	48.49
बुलंदशहर	34.99	38.39	41.13	46.23	50.74	55.68	61.10
यूपी उप-क्षेत्र	**145.76**	**165.19**	**186.60**	**213.62**	**243.87**	**279.15**	**320.34**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**167.88**	**177.56**	**188.18**	**199.45**	**211.38**	**224.03**	**237.44**
अलवर	36.74	40.51	44.98	49.95	55.46	61.59	68.39
राजस्थान उप-क्षेत्र	**36.74**	**40.51**	**44.98**	**49.95**	**55.46**	**61.59**	**68.39**
फरीदाबाद**	28.53	32.53	37.27	42.70	48.92	56.04	64.20
गुडगाँव	15.14	14.57	14.01	13.48	12.97	12.48	12.01
झज्जर	9.58	9.97	10.39	10.82	11.28	11.75	12.24
पानीपत	12.05	13.49	15.12	16.96	19.01	21.32	23.90
रेवाड़ी	9.00	9.73	10.56	11.47	12.45	13.52	14.68
रोहतक	10.61	11.26	11.98	12.74	13.55	14.41	15.33
सोनीपत	14.50	15.98	17.25	18.63	20.11	21.71	23.45
मेवात	10.89	11.74	12.64	13.62	14.67	15.81	17.03
हरियाणा उप-क्षेत्र	**110.30**	**119.27**	**129.22**	**140.42**	**152.96**	**167.04**	**182.84**
एनसीआर	**460.68**	**502.53**	**548.98**	**603.44**	**663.67**	**731.81**	**809.01**
* गाजियाबाद में हापुड़ शामिल है							
** फरीदाबाद में पलवल भी शामिल है							

स्रोत: भारत की जनगणना, *2011;* एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-*2021;* और एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन

अनुलग्नक 3.9: वर्तमान भागीदारी दर (2001) के आधार पर एनसीआर में कार्यबल का अनुमान (2021)

श्रेणी	1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्षेत्र	कृषि	खनन और उत्खनन	उत्पादन	C) बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार और वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ
फरीदाबाद	6,02,865	7,601	2,01,579	97,086	1,57,217	65,158	1,05,830	46,191	49,438
गुडगाँव	5,65,236	17,449	91,302	71,624	87,437	52,554	76,269	31,143	29,012
झज्जर	2,93,910	284	52,835	18,415	23,952	16,554	26,003	12,399	7,664
पानीपत	3,73,479	935	55,288	34,349	61,778	20,736	26,977	15,343	16,247
रेवाड़ी	3,10,984	1,184	33,757	21,305	29,549	13,392	23,872	13,826	6,817
रोहतक	2,76,038	376	35,077	27,675	43,600	21,446	32,552	21,150	10,167
सोनीपत	4,41,039	929	65,891	33,306	51,195	27,660	45,834	25,608	11,627
हरियाणा उप-क्षेत्र	**28,63,551**	**28,758**	**5,35,729**	**3,03,760**	**4,54,728**	**2,17,499**	**3,37,338**	**1,65,660**	**1,30,971**
मेरठ	6,04,494	627	1,05,865	86,790	1,51,992	61,581	96,330	40,413	32,446
बागपत	3,26,576	217	27,594	16,933	36,255	14,002	25,373	13,905	7,676
गाज़ियाबाद	7,29,189	3,338	2,31,116	1,65,138	2,88,834	1,34,965	2,13,533	72,519	65,625
गौतमबुद्धनगर	3,21,840	1,688	68,573	42,965	73,544	32,951	1,17,500	25,715	33,593
बुलंदशहर	12,13,513	603	88,437	59,804	1,42,109	46,987	87,202	31,038	27,956
यूपी उप-क्षेत्र	**31,95,610**	**6,474**	**5,21,586**	**3,71,630**	**6,92,734**	**2,90,487**	**5,39,937**	**1,83,591**	**1,67,297**
अलवर	17,45,670	7,503	89,919	68,854	1,06,021	55,812	52,511	44,915	22,212
राजस्थान उप-क्षेत्र	**17,45,670**	**7,503**	**89,919**	**68,854**	**1,06,021**	**55812**	**52,511**	**44,915**	**22,212**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**8,02,718**	**21,566**	**8,89,686**	**5,37,507**	**14,41,855**	**6,52,957**	**10,02,954**	**3,78,369**	**4,63,913**
एनसीआर	**86,07,549**	**64,301**	**20,36,91 9**	**12,81,750**	**26,95,338**	**12,16,754**	**19,32,741**	**7,72,535**	**7,84,393**

स्रोत: भारत की जनगणना, *2001* और एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन

अनुलग्नक 3.10: वर्तमान भागीदारी दर (2001) के आधार पर एनसीआर में कार्यबल का अनुमान (2031)

श्रेणी	1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्षेत्र	कृषि	खनन और उत्खनन	उत्पादन	बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार और वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ
फरीदाबाद	7,91,288	9,976	2,64,582	1,27,430	2,06,355	85522	1,38,906	60,628	6,48,90
गुडगाँव	5,86,166	18,095	94,683	74,277	90,675	54500	79,093	32,296	30,086
झज्जर	3,19,050	309	57,354	19,990	26,001	17970	28,227	13,460	8,319
पानीपत	4,69,552	1,175	69,510	43,185	77,670	26070	33,917	19,290	20,426
रेवाड़ी	3,66,578	1,396	39,792	25,114	34,831	15786	28,140	16,298	8,035
रोहतक	3,12,294	425	39,684	31,309	49,326	24263	36,828	23,927	11,503
सोनीपत	5,14,129	1,083	76,811	38,825	59,679	32244	53,430	29,852	13,554
हरियाणा उप-क्षेत्र	**33,59,057**	**32,460**	**6,42,416**	**3,60,130**	**5,44,537**	**256354**	**3,98,542**	**1,95,751**	**1,56,813**
मेरठ	6,99,963	726	1,22,585	1,00,497	1,75,997	71306	1,11,544	46,796	37,571
बागपत	3,66,771	244	30,990	19,017	40,718	15725	28,496	15,617	8,621
गाज़ियाबाद	10,48,990	4,802	3,32,476	2,37,563	4,15,508	194157	3,07,182	1,04,324	94,406
गौतमबुद्धनगर	4,58,711	2,406	97,736	61,237	1,04,820	46965	1,67,470	36,651	47,879
बुलंद शहर	1,46,13,86	726	1,06,501	72,020	1,71,136	56585	1,05,014	37,378	33,666
यूपी उप-क्षेत्र	**40,35,821**	**8,904**	**6,90,289**	**4,90,334**	**9,08,179**	**384738**	**7,19,705**	**2,40,766**	**2,22,144**
अलवर	21,52,527	9,252	1,10,876	84,901	1,30,730	68820	64,750	55,383	27,389
राजस्थान उप-क्षेत्र	**21,52,527**	**9,252**	**1,10,876**	**84,901**	**1,30,730**	**68820**	**64,750**	**55,383**	**27,389**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**9,01,674**	**24,225**	**9,99,363**	**6,03,768**	**16,19,602**	**733451**	**11,26,594**	**4,25,013**	**5,21,103**
एनसीआर	**1,04,490,79**	**74,841**	**24,42,944**	**15,39,133**	**32,03,048**	**1443364**	**23,09,591**	**9,16,913**	**9,27,448**

स्रोत: भारत की जनगणना, *2001* और एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन

अनुलग्नक 3.11: एनसीआर में कार्यबल का अनुमान (2021) (समायोजित भागीदारी दर)

श्रेणी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
क्षेत्र	कृषि	खनन और उत्खनन	उत्पादन	बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार और वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ	कुल जनसंख्या
फरीदाबाद	5,59,007	7,601	2,01,579	97,086	1,57,217	74,534	1,11,801	52,174	49,438	37,26,713
गुडगाँव	5,33,130	17,449	91,302	71,624	87,437	53,313	79,969	39,985	29,012	26,65,648
झज्जर	2,80,462	284	77,906	18,415	31,162	16,554	26,003	13,504	7,664	10,38,749
पानीपत	3,47,807	935	55,288	34,349	68,049	27,220	30,244	19,659	16,247	15,12,206
रेवाड़ी	2,85,200	1,184	52,815	21,305	42,252	13,392	26,407	15,844	6,817	10,56,295
रोहतक	2,51,505	376	59,882	27,675	59,882	21,446	35,929	23,953	10,167	11,97,642
सोनीपत	3,96,812	929	86263	33,306	86,263	27,660	47,445	34,505	11,627	17,25,268
हरियाणा उप-क्षेत्र	**26,53,922**	**28,758**	**6,25,036**	**3,03,760**	**5,32,263**	**2,34,118**	**3,57,800**	**1,99,624**	**1,30,971**	**1,29,22,521**
मेरठ	5,98,779	627	1,19,756	86,790	1,59,674	69,858	96,330	59,878	32,446	39,91,860
बागपत	3,07,096	217	29,247	16,933	43,871	21,935	25,373	21,935	7,676	14,62,364
गाज़ियाबाद	6,70,575	3,338	2,41,407	1,65,138	3,21,876	1,34,965	2,13,533	1,00,586	65,625	67,05,753
गौतमबुद्धनगर	2,86,429	1,688	95,476	42,965	95,476	47,738	1,17,500	35,804	33,593	23,86,911
बुलंदशहर	11,37,539	603	1,26,393	59,804	1,68,524	84,262	87,202	42,131	27,956	42,13,109
यूपी उप-क्षेत्र	**30,00,419**	**6,474**	**6,12,280**	**371,630**	**7,89,422**	**3,58,759**	**5,39,937**	**2,60,334**	**1,67,297**	**1,87,59,996**
अलवर	15,74,283	7,503	1,12,449	68,854	1,57,428	89,959	52,511	67,469	22,212	44,97,952
राजस्थान उप-क्षेत्र	**15,74,283**	**7,503**	**1,12,449**	**68,854**	**1,57,428**	**89,959**	**52,511**	**67,469**	**22,212**	**44,97,952**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**6,58,647**	**21,566**	**8,46,831**	**5,37,507**	**14,418,55**	**7,05,693**	**10,02,954**	**4,70,462**	**4,63,913**	**1,88,18,473**
एनसीआर	**78,87,272**	**64,301**	**21,96,595**	**12,81,750**	**29,20,969**	**13,88,529**	**19,53,202**	**9,97,889**	**7,84,393**	**5,49,98,943**

स्रोत: भारत की जनगणना, *2001* और एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन

अनुलग्नक 3.12: एनसीआर में कार्यबल का अनुमान (2031) (समायोजित भागीदारी दर)

श्रेणी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
क्षेत्र	कृषि	खनन और उत्खनन	उत्पादन	बिजली, गैस और पावर	निर्माण	व्यापार और वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ	कुल जनसंख्या
फरीदाबाद	7,33,722	9,976	2,64,582	1,27,430	2,06,355	97,830	1,46,744	68,481	64,890	48,91,482
गुडगाँव	5,52,871	18,095	94,683	74,277	90,675	55,287	82,931	41,465	30,086	27,64,354
झज्जर	3,04,452	309	84,570	19,990	33,828	17,970	28,227	14,659	8,319	11,27,600
पानीपत	4,37,277	1,175	69,510	43,185	85,554	34,222	38,024	24,716	20,426	19,01,204
रेवाड़ी	3,36,184	1,396	62,256	25,114	49,805	15,786	31,128	18,677	8,035	12,45,127
रोहतक	2,84,539	425	67,747	31,309	67,747	24,263	40,648	27,099	11,503	13,54,947
सोनीपत	4,62,572	1,083	10,0559	38,825	1,00,559	32,244	55,307	40,224	13,554	20,11,182
हरियाणा उप-क्षेत्र	**31,11,617**	**32,460**	**7,43,908**	**3,60,130**	**6,34,523**	**2,77,600**	**4,23,011**	**2,35,320**	**1,56,813**	**1,52,95,897**
मेरठ	6,93,346	726	1,38,669	1,00,497	1,84,892	80,890	1,11,544	69,335	37,571	46,22,309
बागपत	3,44,894	244	32,847	19,017	49,271	24,635	28,496	24,635	8,621	16,42,353
गाज़ियाबाद	9,64,670	4,802	3,47,281	2,37,563	4,63,041	1,94,157	3,07,182	144,700	94,406	96,46,698
गौतमबुद्धनगर	4,08,241	2,406	136080	61,237	1,36,080	68,040	1,67,470	51,030	47,879	34,02,008
बुलंदशहर	1369895	726	152211	72,020	2,02,947	1,01,474	1,05,014	50,737	33,666	50,73,685
यूपी उप-क्षेत्र	**37,81,046**	**8,904**	**8,07,088**	**4,90,334**	**10,36,232**	**4,69,197**	**7,19,705**	**3,40,437**	**222,144**	**2,43,87,052**
अलवर	19,41,195	9,252	1,38,657	84,901	1,94,120	1,10,925	64,750	83,194	27,389	55,46,272
राजस्थान उप-क्षेत्र	**19,41,195**	**9,252**	**1,38,657**	**84,901**	**1,94,120**	**1,10,925**	**64,750**	**83,194**	**27,389**	**55,46,272**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**7,39,842**	**24,225**	**9,51,226**	**6,03,768**	**16,19,602**	**7,92,688**	**11,26,594**	**5,28,459**	**5,21,103**	**2,11,38,346**
एनसीआर	**95,73,701**	**74,841**	**26,40,878**	**15,39,133**	**34,84,477**	**16,50,411**	**23,34,060**	**11,87,410**	**9,27,448**	**6,63,67,567**

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001 *और एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन*

अनुलग्नक 4. 1: एनसीआर में एसईजेड जहां एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक मंजूरी दी गई है

क्रम संख्या	एसईजेड का नाम	प्रकार
1	दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन	आईटी
2	दिल्ली राज्य औद्योगिक सूचना विकास निगम लिमिटेड	आईटी
3	दिल्ली राज्य औद्योगिक सूचना विकास निगम लिमिटेड	रत्न और आभूषण
4	हरियाणा टेक्नोलॉजी पार्क (सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड)	आईटी
5	मेसर्स उप्पल हाउसिंग लिमिटेड	मल्टी सर्विसेज
6	मेसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
7	डॉ. फ्रेश हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड।	आईटी/आईटीईएस
8	ओरिएंट क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	कपड़ा
9	एसोटेक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	आईटी / आईटीई
10	पायनियर अर्बन लैंड और	आईटी / आईटीई
11	इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	आईटी / आईटीई
12	डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड	आईटी / आईटीई
13	ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड	जैव प्रौद्योगिकी
14	सनसिटी हरियाणा एसईजेड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड	आईटी
15	मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड	आईटी
16	मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
17	एसेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
18	अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
19	बेंटेक्स टावर्स प्राइवेट लिमिटेड	मल्टी सर्विसेज
20	इरियो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग III लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस
21	रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड	मल्टी सर्विसेज
22	गुड़गांव इन्फोस्पेस लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
23	जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस
24	जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस
25	मोहन इंवेस्टमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
26	मायर इंडिया लिमिटेड	जैव प्रौद्योगिकी
27	रहेजा हरियाणा एसईजेड डेवलपर्स एसईजेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	इंजीनियरिंग
28	कैंटन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
29	यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
30	डीएस रीयलटर्स प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
31	सोहनाबिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस
32	मित्तल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
33	स्टारेक्स एसईजेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
34	परपेचुअल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
35	ग्रेसियस बिल्डकॉन प्राइवेट बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
36	गोल्डसौक इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड	जेम्स एंड ज्वेलरी

क्रम संख्या	एसईजेड का नाम	प्रकार
37	अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आईटी/आईटीई
38	वेलग्रोबिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस
39	सनवाइज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
40	प्रिमोजबिल्डवर्थ प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
41	एयरमिड डेवलपर्स लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
42	प्रोग्रेसिव बिल्डस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
43	अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण
44	मिकाडो रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस
45	ओरिएंट क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
46	एस्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण
47	बेस्ट ऑन हेल्थ लिमिटेड	जैव प्रौद्योगिकी
48	सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर / आईटीईएस
49	विप्रो लिमिटेड	आईटी/आईटीई
50	मोजर बियर इंडिया लिमिटेड	सौर ऊर्जा उपकरण/सेल सहित गैर-पारंपरिक ऊर्जा
51	अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
52	सीव्यू डेवेलपर्स लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
53	एचसीएल प्रौद्योगिकी	आईटी/आईटीईएस
54	एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेज	आईटी/आईटीईएस
55	ओएसई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	आईटी
56	पवित्रधाम कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
57	यूनिटेक इंफ्रा-कॉन लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
58	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (उत्तर प्रदेश एसआईडीसी)	कपड़ा
59	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (उत्तर प्रदेश एसआईडीसी)	चमड़ा
60	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (उत्तर प्रदेश एसआईडीसी)	इंजीनियरिंग सामान
61	परफेक्ट आईटी सेज प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
62	उप्पल आईटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर / आईटीईएस
63	आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस(
64	यूनिटेक हाई-टेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
65	उप्पल हाउसिंग लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर / आईटीईएस
66	सर्व-मंगल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर / आईटीईएस
67	गैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
68	जुबिलेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
69	मैक्स-डिजीइन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस

क्रम संख्या	एसईजेड का नाम	प्रकार
70	आईवीआर प्राइम आईटी सेज प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
71	डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
72	डायमंड आईटी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
73	सीबीएस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
74	गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
75	डायमंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	आईटी
76	आर.सी. इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
77	वेलग्रोइन्फोटेक प्राइवेट	आईटी/आईटीईएस
78	अर्शिया उत्तरी एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड	एफटीडब्ल्यूजेड
79	आनंदइन्फोएज प्राइवेट लिमिटेड	आईटी/आईटीईएस
80	अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर / आईटीईएस

अनुलग्नक **4. 2:** एनसीआर में औद्योगिक संपदा

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला/जोन	उप क्षेत्र
1	जीटी करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
2	राजस्थान उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
3	एस एम ए औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
4	एस एस आई औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
5	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
6	लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
7	उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
8	डी.एस.आई.डी.सी. - शेड नागलोई	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
9	मंगोल पुरी औद्योगिक क्षेत्र (डीडीए और डीएसआईडीसी दोनों)	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
10	बादली औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
11	नरेला औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
12	बवाना औद्योगिक क्षेत्र	उत्तर	एनसीटी-दिल्ली
13	ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I	दक्षिण	एनसीटी-दिल्ली
14	ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II	दक्षिण	एनसीटी-दिल्ली
15	ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट	दक्षिण	एनसीटी-दिल्ली
16	फ्लैट फैक्टरी परिसर ओखला	दक्षिण	एनसीटी-दिल्ली
17	मोहन कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट	दक्षिण	एनसीटी-दिल्ली
18	फ़्लैटेड फ़ैक्टरी कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान	दक्षिण	एनसीटी-दिल्ली
19	रानी झांसी रोड	दक्षिण	एनसीटी-दिल्ली
20	शाहजेदा बाग औद्योगिक क्षेत्र	दक्षिण	एनसीटी-दिल्ली
21	नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज-I	पश्चिम	एनसीटी-दिल्ली
22	नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज-II	पश्चिम	एनसीटी-दिल्ली
23	मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-I	पश्चिम	एनसीटी-दिल्ली
24	मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-II	पश्चिम	एनसीटी-दिल्ली
25	तिलक नगर औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम	एनसीटी-दिल्ली
26	कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम	एनसीटी-दिल्ली
27	डी. एफ.एल इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर	पश्चिम	एनसीटी-दिल्ली
28	नजफगढ़ रोड औद्योगिक क्षेत्र	पश्चिम	एनसीटी-दिल्ली
29	झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र	पूर्व	एनसीटी-दिल्ली
30	फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा	पूर्व	एनसीटी-दिल्ली
31	पटपड़ गंज औद्योगिक क्षेत्र	पूर्व	एनसीटी-दिल्ली
32	शाहदरा औद्योगिक क्षेत्र	पूर्व	एनसीटी-दिल्ली

33	फ्लैट फैक्टरी परिसर, झिलमिल, शाहदरा	पूर्व	एनसीटी-दिल्ली
34	सेक्टर-4 औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
35	सेक्टर-5 औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
36	सेक्टर-6 औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
37	सेक्टर-13 औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
38	सेक्टर-15ए औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
39	सेक्टर-24 औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
40	सेक्टर-25 औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
41	सेक्टर-27 ए औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
42	सेक्टर-27 बी औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
43	सेक्टर-27 सी औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला/जोन	उप क्षेत्र
44	सेक्टर-27 डी औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
45	सेक्टर-28 औद्योगिक क्षेत्र हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
46	सेक्टर-31 औद्योगिक क्षेत्र हुडा एचएसआईडीसी	फरीदाबाद	हरियाणा
47	सेक्टर-58 फेज-1 औद्योगिक क्षेत्र हुडा एचएसआईडीसी	फरीदाबाद	हरियाणा
48	सेक्टर-59 औद्योगिक क्षेत्र हुडा एचएसआईडीसी	फरीदाबाद	हरियाणा
49	हथीन औद्योगिक क्षेत्र एचजीडीए	फरीदाबाद	हरियाणा
50	ग्रामीण औद्योगिक प्रतिष्ठान/पीडब्लूएल डीआई हरियाणा	फरीदाबाद	हरियाणा
51	प्रगति विहार औद्योगिक क्षेत्र एमसीएफ	फरीदाबाद	हरियाणा
52	सेक्टर-58 फेज-II औद्योगिक क्षेत्र पलवल हुडा	फरीदाबाद	हरियाणा
53	उद्योग विहार गुड़गांव फेज I से VI सेक्टर 18 और डीआईसी	गुडगाँव	हरियाणा
54	सेक्टर-34-35	गुडगाँव	हरियाणा
55	आईएमटी मानेसर फेज-I	गुडगाँव	हरियाणा
56	आईएमटी मानेसर फेज-II	गुडगाँव	हरियाणा
57	आईएमटी मानेसर चरण III और IV	गुडगाँव	हरियाणा
58	सरकारी औद्योगिक क्षेत्र बहादुरगढ़	झज्जर	हरियाणा
59	एमआईई एस्टेट - I, एमआईई एस्टेट - II, बहादुरगढ़	झज्जर	हरियाणा
60	एचएसआईआईडीसी सेक्टर - 16 बहादुरगढ़	झज्जर	हरियाणा
61	एचएसआईआईडीसी सेक्टर - 17 बहादुरगढ़	झज्जर	हरियाणा
62	एचएसआईआईडीसी सेक्टर - 4बी बहादुरगढ़	झज्जर	हरियाणा
63	रोज़ का मेव औद्योगिक क्षेत्र	मेवात	हरियाणा
64	ग्रामीण औद्योगिक एस्टेट	पलवल	हरियाणा
65	हथिन इंडस्ट्रियल एस्टेट	पलवल	हरियाणा
66	औद्योगिक क्षेत्र, पानीपत	पानीपत	हरियाणा
67	सेक्टर-25 हुडा, फेज-I	पानीपत	हरियाणा
68	सेक्टर-25 हुडा, फेज-II	पानीपत	हरियाणा
69	सेक्टर -29 हुडा, फेज-I	पानीपत	हरियाणा
70	सेक्टर -29 हुडा, फेज-II	पानीपत	हरियाणा
71	एचएसआईडीसी समालखा	पानीपत	हरियाणा
72	धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र	रेवाड़ी	हरियाणा
73	बावल औद्योगिक क्षेत्र	रेवाड़ी	हरियाणा
74	बरही (पीएच -1)	सोनीपत	हरियाणा

75	बरही (फेज-II)	सोनीपत	हरियाणा
76	इंडस्ट्रियलएस्टेट, कुंडली	सोनीपत	हरियाणा
77	डीआईसी	सोनीपत	हरियाणा
78	राय इंडस्ट्रियल एस्टेट (फेज-I, सेक्टर-4)	सोनीपत	हरियाणा
79	राय इंडस्ट्रियल एस्टेट (फेज-II, सेक्टर -4)	सोनीपत	हरियाणा
80	बागपत औद्योगिक क्षेत्र	बागपत	उत्तर प्रदेश
81	यूपीएसआईडीसी आई/ए सिकंदराबाद	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश
82	यूपीएसआईडीसी आई/ए जंक्शन रोड खुर्जा	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश
83	सरकारी औद्योगिक एस्टेट खुर्जा	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश
84	यूपीएसआईडीसी *औद्योगिक क्षेत्र चोल	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश
85	यूपीएसआईडीसी आई/ए खुर्जा	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश
86	नोएडा फेज-I सेक्टर-1,11,16	गौतमबुद्धनगर	उत्तर प्रदेश
87	नोएडा, फेज-II 100/निर्यात औद्योगिक संपदा	गौतमबुद्धनगर	उत्तर प्रदेश
88	नोएडा-फेज-III, सेक्टर 57-64 औद्योगिक एस्टेट	गौतमबुद्धनगर	उत्तर प्रदेश
89	लोनी एस्टेट	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
90	साइट-1, बुलंदशहर रोड	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
91	साइट-2, लोनी रोड	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला/जोन	उप क्षेत्र
92	साइट-3, मेरठ रोड	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
93	साइट-4, साहिबाबाद	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
94	साउथ साइड जीटी रोड इंडस्ट्रियल एस्टेट	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
95	मसूरी गुलावटी रोड इंडस्ट्रियल एस्टेट	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
96	कवि नगर, सेक्टर-17, इंडस्ट्रियल एस्टेट	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
97	सेक्टर-22, मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एस्टेट	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
98	लोहा मंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
99	साइट-2, लोनी रोड हर्षा इंडस्ट्रियल एस्टेट	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
100	उद्योग कुंज औद्योगिक एस्टेट	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
101	गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट, परतापुर	मेरठ	उत्तर प्रदेश
102	स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एस्टेट	मेरठ	उत्तर प्रदेश
103	परतापुर औद्योगिक क्षेत्र	मेरठ	उत्तर प्रदेश
104	उद्योगपुरम औद्योगिक एस्टेट	मेरठ	उत्तर प्रदेश
105	एम.आई.ए अलवर	अलवर	राजस्थान
106	एमआईए एक्सटेंशन अलवर	अलवर	राजस्थान
107	एग्रो फूड पार्क, एम.आई.ए. एक्सटेंशन अलवर	अलवर	राजस्थान
108	एमआईए (दक्षिण और पूर्व), अलवर	अलवर	राजस्थान
109	खेरली औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
110	राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
111	खैरथल औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
112	थानागाज़ी औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
113	ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर	अलवर	राजस्थान
114	बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
115	सोतनाला औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
116	भिवाड़ी फेज I से IV	अलवर	राजस्थान
117	कुशाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
118	आईआईडी, सेंट्रल खुशखेड़ा	अलवर	राजस्थान
119	पाथेरी औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
120	चोपांकी औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
121	टपुकारा औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
122	शंजहांपुर औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
123	ईपीआईपी नीमराना	अलवर	राजस्थान
124	सारे खुर्द औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान
125	मंजारा पथ औद्योगिक क्षेत्र	अलवर	राजस्थान

स्रोत: डीसी एमएसएमई औद्योगिक प्रोफाइल; दिल्ली सरकार
http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_industry/Department+of+Industries/Home/FAQ/

अनुलग्नक 4. 3: एनसीआर में औद्योगिक समूहों की जिलेवार सूची

स्थान	उत्पाद	यूनिटों की संख्या	रोजगार (प्रत्यक्ष)	टर्नओवर (करोड़ में)
मेरठ	ऑटो कंपोनेंट्स	4,700	26,000	100
	बैंड इंस्ट्रूमेंट्स	433	8,500	20
	कांच और लकड़ी के मोती	3,000	15,000	0.7
	मिनी गैस सिलेंडर	160	7,500	100
	पावर लूम / कढ़ाई	3,000	30,000	40
	रबड़ उत्पाद	130	2,500	40
	कैंची	225	5,000	25
	खेल के सामान	3,500	70,000	200
	ट्रांसफार्मर और वोल्टेज नियामक	100	3,500	400
गाज़ियाबाद	रसायन	224	1,574	13,5.54
	इंजीनियरिंग उपकरण	635	7,400	340
	पिलखुवा टेक्सटाइल प्रिंटिंग	400	20,000	100
	प्लास्टिक की पैकेजिंग	150	10,000	350
बुलंदशहर	पॉटरी क्लस्टर खुर्जा	80	2,500	450
	खुर्जा सिरेमिक्स	600	50,000	200
नोएडा	रसायन	111	2,221	10,9.49
	ऑटो और इंजीनियरिंग आइटम	12,000	2,00000	50,000
	गारमेंट्स	6,014	94,736	3,200
	पैकेजिंग सामग्री	124	1,800	84.15
	प्लास्टिक उत्पाद	350	6,500	250
अलवर	ऑटो कंपोनेंट्स	200	19,500	250
एनसीटी-दिल्ली	ऑटो कंपोनेंट्स	1,500	50,000	297.2
	रसायन	339	3,562	337.02
	इंजीनियरिंग उपकरण	2,691	47,000	2,000.00
	खाद्य उत्पाद	432	1,939	594.28
	परिधान सहित कपड़ा	1,901	1,32,000	921.32
	कॉस्मेटिक और पैकेजिंग	240	7,200	100
	प्लास्टिक उत्पाद	746	16,478	54.22
	रबड़ उत्पाद	178	18,684	192.64
	सैनिटरी फिटिंग	100	9,00	30
	प्रिंटिंग और पैकेजिंग, नारायणा	450	5,000	400

गुडगाँव	ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग	5,000	2,60,000	10,000
	रबड़ और रसायन	472	11,619	907
	इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स	107	3,427	702
	रेडीमेड कपड़े	1,310	87,380	13,000
	चमड़ा और चमड़ा और फर उत्पाद, मानेसर	205	35,000	867
पानीपत	हथकरघा	1,800	23,000	
	पावरलूम	720	50,000	600
	कपास कताई और नकली यार्न	500	50,000	500
	कालीन	400	60,000	150
	होम फर्निशिंग क्लस्टर	85	2,800	465

स्थान	उत्पाद	यूनिटों की संख्या	रोजगार (प्रत्यक्ष)	टर्नओवर (करोड़ में)
	कपड़ा मशीनरी	28	477	32.4
	समालखा फाउंड्री क्लस्टर	30	1,200	95
फरीदाबाद	ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग	2,500	10,000	3,250
	रसायन	275	1,375	825
	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण	203	5,000	1,500
	कपड़ा	320	7,000	3,200.00
झज्जर	सामान्य इंजीनियरिंग	134	1,000	70
	जूते	125	12,400	1,560
सोनीपत	स्टेनलेस स्टील क्लस्टर- कुंडली	72	8,000	800
	रसायन	120	2,500	100
	सामान्य इंजीनियरिंग	150	3,000	100
	प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर, राय	110	4,400	165
स्रोत: क्लस्टर वेधशाला, एमएसएमई फाउंडेशन				

अनुलग्नक **6. 1:** एनसीआर शहरी क्षेत्रों में प्रकार के अनुसार उद्यमों की संख्या - **2005**

जिला/उपक्षेत्र	कृषि			गैर कृषि सभी			कुल		
	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल
मेरठ	2,409	749	3,158	42,249	25,836	68,085	44,658	26,585	71,243
बागपत	640	270	910	11,871	4,664	16,535	12,511	4,934	17,445
गाज़ियाबाद	891	444	1,335	52,186	34,595	86,781	53,077	35,039	88,116
गौतम बुद्ध नगर	1,623	184	1,807	18,446	13,689	32,135	20,069	13,873	33,942
बुलंदशहर	221	91	312	29,237	8,981	38,218	29,458	9,072	38,530
यूपी उप-क्षेत्र	**5,784**	**1,738**	**7,522**	**1,53,989**	**87,765**	**2,41,754**	**1,59,773**	**89,503**	**2,49,276**
पानीपत	127	176	303	12,420	10,495	22,915	12,547	10,671	23,218
सोनीपत	185	177	362	11,019	7,356	18,375	11,204	7,533	18,737
रोहतक	406	330	736	15,708	7,548	23,256	16,114	7,878	23,992
झज्जर	55	42	97	6,587	3,513	10,100	6,642	3,555	10,197
रेवाड़ी	80	48	128	4,787	5,630	10,417	4,867	5,678	10,545
गुडगाँव	58	43	101	15,147	12,288	27,435	15,205	12,331	27,536
फरीदाबाद	361	666	1,027	24,844	32,374	57,218	25,205	33,040	58,245
हरियाणा उप-क्षेत्र	**1,272**	**1,482**	**2,754**	**90,512**	**79,204**	**1,69,716**	**91,784**	**80,686**	**1,72,470**
एनसीटी दिल्ली उप-क्षेत्र	**841**	**1,872**	**2,713**	**2,97,081**	**4,31,569**	**7,28,650**	**2,97,922**	**4,33,441**	**7,31,363**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**473**	**181**	**654**	**13,106**	**11,809**	**24,915**	**13,579**	**11,990**	**25,569**
एनसीआर	**8,370**	**5,273**	**13,643**	**5,54,688**	**6,10,347**	**11,65,035**	**5,63,058**	**6,15,620**	**11,78,678**

स्रोत: आर्थिक जनगणना *2005* (हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश)

अनुलग्नक 6. 2: एनसीआर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार के अनुसार उद्यमों की संख्या- 2005

जिला/उपक्षेत्र	कृषि			गैर कृषि सभी			कुल		
	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल
मेरठ	16,671	3,813	20,484	19,922	7,740	27,662	36,593	11,553	48,146
बागपत	6,895	1,140	8,035	11,877	3,177	15,054	18,772	4,317	23,089
गाज़ियाबाद	1,247	444	1,691	20,633	7,774	28,407	21,880	8,218	30,098
गौतम बौद्ध नगर	2,412	83	2,495	9,126	1,901	11,027	11,538	1,984	13,522
बुलंदशहर	4,183	1,416	5,599	19,683	6,613	26,296	23,866	8,029	31,895
यूपी उप-क्षेत्र	**31,408**	**6,896**	**38,304**	**81,241**	**27,205**	**1,08,446**	**1,12,649**	**34,101**	**1,46,750**
पानीपत	572	202	774	13,973	4,785	18,758	14,545	4,987	19,532
सोनीपत	1,126	350	1,476	13,710	4,907	18,617	14,836	5,257	20,093
रोहतक	2,714	239	2,953	10,329	2,661	12,990	13,043	2,900	15,943
झज्जर	588	146	734	9,932	3,606	13,538	10,520	3,752	14,272
रेवाड़ी	1,291	209	1,500	11,596	5,144	16,740	12,887	5,353	18,240
गुडगाँव	3,525	554	4,079	20,706	13,791	34,497	24,231	14,345	38,576
फरीदाबाद	1,245	942	2,187	9,668	10,136	19,804	10,913	11,078	21,991
हरियाणा उप-क्षेत्र	**11,061**	**2,642**	**13,703**	**89,914**	**45,030**	**1,34,944**	**1,00,975**	**47,672**	**1,48,647**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**346**	**231**	**577**	**15,398**	**10,405**	**25,803**	**15,744**	**10,636**	**26,380**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**6,556**	**1,364**	**7,920**	**31,349**	**24,688**	**56,037**	**37,905**	**26,052**	**63,957**
एनसीआर	**49,371**	**11,133**	**60,504**	**2,17,902**	**1,07,328**	**3,25,230**	**2,67,273**	**1,18,461**	**3,85,734**

स्रोत: आर्थिक जनगणना *2005* (हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश)

अनुलग्नक 6. 3: एनसीआर शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों की संख्या -2005

जिला/उपक्षेत्र	कृषि			गैर कृषि सभी			कुल		
	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल
मेरठ	3,896	2,550	6,446	50,197	91,095	1,41,292	54,093	93,645	1,47,738
बागपत	985	554	1,539	14,029	16,200	30,229	15,014	16,754	31,768
गाज़ियाबाद	1,310	1,254	2,564	63,307	1,40,844	2,04,151	64,617	1,42,098	2,06,715
गौतम बुद्ध नगर	4,223	771	4,994	21,402	2,25,120	2,46,522	25,625	2,25,891	2,51,516
बुलंदशहर	383	260	643	40,622	25,448	66,070	41,005	25,708	66,713
यूपी उप-क्षेत्र	**10,797**	**5,389**	**16,186**	**1,89,557**	**4,98,707**	**6,88,264**	**2,00,354**	**5,04,096**	**7,04,450**
पानीपत	196	555	751	14,439	61,823	76,262	14,635	62,378	77,013
सोनीपत	337	715	1,052	12,424	36,981	49,405	12,761	37,696	50,457
रोहतक	709	1,072	1,781	18,101	40,490	58,591	18,810	41,562	60,372
झज्जर	98	146	244	7,714	31,986	39,700	7,812	32,132	39,944
रेवाड़ी	96	352	448	5,502	20,957	26,459	5,598	21,309	26,907
गुडगाँव	132	463	595	17,365	88,882	1,06,247	17,497	89,345	1,06,842
फरीदाबाद	526	1,757	2,283	27,849	1,87,694	2,15,543	28,375	1,89,451	2,17,826
हरियाणा उप क्षेत्र	2,094	5,060	7,154	1,03,394	4,68,813	5,72,207	1,05,488	4,73,873	5,79,361
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	1,751	8,872	10,623	3,61,567	31,14,134	34,75,701	3,63,318	31,23,006	34,86,324
राजस्थान उप-क्षेत्र	803	455	1,258	15,850	58,469	74,319	16,653	58,924	75,577
एनसीआर	**15,445**	**19,776**	**35,221**	**6,70,368**	**41,40,123**	**48,10,491**	**6,85,813**	**41,59,899**	**4,84,5712**

स्रोत: आर्थिक जनगणना 2005 (हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश)

अनुलग्नक 6.4: एनसीआर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों की संख्या-2005

जिला/उपक्षेत्र	कृषि			गैर कृषि			सभी		
	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल
मेरठ	39,150	11,602	50,752	30,750	28,720	59,470	69,900	40,322	1,10,222
बागपत	12,901	3,224	16,125	16,997	20,371	37,368	29,898	23,595	53,493
गाज़ियाबाद	1,774	1,177	2,951	24,002	24,433	48,435	25,776	25,610	51,386
गौतम बुद्ध नगर	6,735	369	7,104	14,487	33,471	47,958	21,222	33,840	55,062
बुलंदशहर	11,061	4,530	15,591	28,885	20,062	48,947	39,946	24,592	64,538
यूपी उप-क्षेत्र	**71,621**	**20,902**	**92,523**	**1,15,121**	**1,27,057**	**2,42,178**	**1,86,742**	**1,47,959**	**3,34,701**
पानीपत	931	1,188	2,119	16,368	38,809	55,177	17,299	39,997	57,296
सोनीपत	2,094	1,460	3,554	16,373	61,144	77,517	18,467	62,604	81,071
रोहतक	4,255	641	4,896	12,179	15,491	27,670	16,434	16,132	32,566
झज्जर	1,510	625	2,135	11,473	39,417	50,890	12,983	40,042	53,025
रेवाड़ी	2,448	602	3,050	13,351	34,858	48,209	15,799	35,460	51,259
गुडगाँव	6,875	1,721	8,596	26,076	1,15,790	1,41,866	32,951	1,17,511	1,50,462
फरीदाबाद	2,678	2,225	4,903	12,368	41,140	53,508	15,046	43,365	58,411
हरियाणा उप-क्षेत्र	**20,791**	**8,462**	**29,253**	**1,08,188**	**3,46,649**	**4,54,837**	**1,28,979**	**3,55,111**	**4,84,090**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**800**	**839**	**1,639**	**17,692**	**50,732**	**68,424**	**18,492**	**51,571**	**70,063**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**11,489**	**2,812**	**14,301**	**38,998**	**86,979**	**1,25,977**	**50,487**	**89,791**	**1,40,278**
एनसीआर	**1,04,701**	**33,015**	**1,37,716**	**2,79,999**	**6,11,417**	**8,91,416**	**3,84,700**	**6,44,432**	**10,29,132**

स्रोत: आर्थिक जनगणना 2005 (हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश)

अनुलग्नक 6. 5: एनसीआर -2005 में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों की संख्या का हिस्सा

	ग्रामीण									शहरी									सभी								
जिला/उप-क्षेत्र	आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या									आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या									आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या								
	कृषि			गैर-कृषि			सभी			कृषि			गैर-कृषि			सभी			कृषि			गैर-कृषि			सभी		
	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल
मेरठ	31.2	28.0	30.4	7.9	3.0	4.4	13.6	4.0	7.3	22.2	10.3	15.2	6.5	2.0	2.6	6.8	2.0	2.7	30.1	21.3	27.3	7.0	2.2	3.0	9.5	2.4	3.7
बागपत	10.3	7.8	9.7	4.4	2.1	2.8	5.8	2.4	3.5	5.6	2.2	3.6	1.8	0.4	0.6	1.9	0.4	0.6	9.7	5.7	8.4	2.7	0.7	1.0	3.4	0.7	1.2
गाज़ियाबाद	1.4	2.8	1.8	6.2	2.6	3.6	5.0	2.6	3.4	7.5	5.0	6.1	8.2	3.1	3.8	8.2	3.1	3.8	2.2	3.7	2.6	7.5	3.0	3.8	6.9	3.0	3.7
गौतम बौद्ध नाग	5.4	0.9	4.3	3.7	3.5	3.6	4.1	3.4	3.6	24.1	3.1	11.8	2.8	4.9	4.6	3.2	4.9	4.6	7.7	1.7	5.8	3.1	4.6	4.4	3.6	4.6	4.4
बुलंदशहर	8.8	10.9	9.3	7.4	2.1	3.6	7.8	2.5	4.3	2.2	1.0	1.5	5.2	0.6	1.2	5.2	0.6	1.2	8.0	7.2	7.8	6.0	0.8	1.7	6.2	0.9	1.9
यूपी उप-क्षेत्र	**57.1**	**50.4**	**55.4**	**29.7**	**13.3**	**18.0**	**36.4**	**14.8**	**22.1**	**61.6**	**21.7**	**38.2**	**24.5**	**10.8**	**12.8**	**25.3**	**10.9**	**13.0**	**57.6**	**39.6**	**51.9**	**26.2**	**11.2**	**13.8**	**29.7**	**11.6**	**15.0**
पानीपत	0.7	2.9	1.3	4.2	4.1	4.1	3.4	4.0	3.8	1.1	2.2	1.8	1.9	1.3	1.4	1.8	1.3	1.4	0.8	2.6	1.4	2.7	1.8	2.0	2.4	1.8	1.9
सोनीपत	1.7	3.5	2.1	4.2	6.4	5.8	3.6	6.3	5.4	1.9	2.9	2.5	1.6	0.8	0.9	1.6	0.8	0.9	1.7	3.3	2.2	2.5	1.8	1.9	2.4	1.8	1.9
रोहतक	3.4	1.5	2.9	3.1	1.6	2.1	3.2	1.6	2.2	4.0	4.3	4.2	2.3	0.9	1.1	2.4	0.9	1.1	3.5	2.6	3.2	2.6	1.0	1.3	2.7	1.0	1.3
झज्जर	1.2	1.5	1.3	3.0	4.1	3.8	2.5	4.0	3.5	0.6	0.6	0.6	1.0	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	1.1	1.2	1.1	1.7	1.3	1.3	1.6	1.3	1.3
रेवाड़ी	2.0	1.5	1.8	3.4	3.6	3.6	3.1	3.5	3.4	0.5	1.4	1.1	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	1.8	1.4	1.7	1.6	1.0	1.1	1.6	1.0	1.1
गुडगाँव	5.5	4.1	5.1	6.7	12.1	10.5	6.4	11.8	9.9	0.8	1.9	1.4	2.2	1.9	2.0	2.2	1.9	2.0	4.9	3.3	4.4	3.7	3.7	3.7	3.9	3.7	3.7
फरीदाबाद	2.1	5.4	2.9	3.2	4.3	4.0	2.9	4.3	3.9	3.0	7.1	5.4	3.6	4.1	4.0	3.6	4.1	4.0	2.2	6.0	3.4	3.5	4.1	4.0	3.3	4.1	4.0
हरियाणा उप-क्षेत्र	**16.6**	**20.4**	**17.5**	**27.9**	**36.2**	**33.8**	**25.1**	**35.5**	**32.0**	**11.9**	**20.4**	**16.9**	**13.4**	**10.2**	**10.6**	**13.3**	**10.2**	**10.7**	**16.0**	**20.4**	**17.4**	**18.2**	**14.6**	**15.3**	**18.0**	**14.7**	**15.3**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**0.6**	**2.0**	**1.0**	**4.6**	**5.3**	**5.1**	**3.6**	**5.2**	**4.6**	**10.0**	**35.7**	**25.1**	**46.7**	**67.6**	**64.6**	**45.9**	**67.4**	**64.3**	**1.8**	**14.6**	**5.9**	**32.6**	**56.9**	**52.7**	**29.3**	**56.4**	**51.3**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**9.2**	**6.8**	**8.6**	**10.0**	**9.1**	**9.4**	**9.8**	**9.0**	**9.3**	**4.6**	**1.8**	**3.0**	**2.0**	**1.3**	**1.4**	**2.1**	**1.3**	**1.4**	**8.6**	**4.9**	**7.4**	**4.7**	**2.6**	**3.0**	**5.1**	**2.6**	**3.1**
एनसीआर	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

अनुलग्नक 8. 1: स्थान भागफल और वृद्धि दर 2000-01 से 2005-06

																					विकास दर 2000-01 से 2005-06			
जिला / क्षेत्र	व्यक्तियों का एलक्यू -2005						एलक्यू जीडीपी 2000-01 और 2005-06									जीडीपी शेयर (2005-06)			2005 में शेयर		क्षेत्रीय जीडीपी			सीएजीआर
	ग्रामीण			शहरी			प्राथमिक			द्वितीयक			तृतीयक			प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक	संस्थान में व्यक्ति 2005		प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक	
	OAE	Est.	कुल	OAE	Est.	कुल	LQ2005-06	LQ2000-01	परिवर्तन	LQ2005-06	LQ2000-01	परिवर्तन	LQ2005-06	LQ2000-01	परिवर्तन	जीडीपी (स्थिर कीमतें)			कृषि	गैर कृषि				
मेरठ	3.66	1.09	1.96	1.84	0.54	0.73	3.31	2.51	0.79	0.88	1.08	-0.20	0.71	0.68	0.03	13.77	3.68	2.94	33.1	3.5	27.68	0.46	27.55	4.32
बागपत	4.74	1.92	2.87	1.54	0.29	0.48	4.28	4.22	0.06	0.56	0.44	0.11	0.70	0.63	0.07	6.09	0.80	1.00	10.2	1.2	-8.89	43.59	26.38	2.18
गाज़ियाबाद	1.35	0.69	0.91	2.20	0.82	1.02	2.09	1.58	0.51	1.28	1.43	-0.15	0.72	0.71	0.01	11.05	6.79	3.79	3.2	4.4	35.77	16.91	31.32	5.49
गौतम बुद्ध नगर	0.93	0.77	0.82	0.73	1.10	1.05	1.04	1.35	-0.32	2.13	1.91	0.22	0.51	0.54	-0.03	4.47	9.17	2.20	11.87.0	5.2	-10.25	65.56	38.84	7.66
बुलंदशहर	4.11	1.30	2.25	2.74	0.29	0.65	3.86	3.63	0.23	0.82	0.78	0.03	0.65	0.60	0.05	13.25	2.80	2.24	9.4	2.0	-2.58	21.60	26.48	2.68
यूपी उप-क्षेत्र	**2.43**	**0.99**	**1.47**	**1.69**	**0.73**	**0.87**	**2.61**	**2.39**	**0.22**	**1.25**	**1.23**	**0.02**	**0.65**	**0.64**	**0.01**	**48.62**	**23.24**	**12.17**	**62.9**	**16.3**	**10.05**	**30.06**	**30.33**	**4.78**
पानीपत	1.74	2.07	1.95	0.96	0.70	0.73	1.38	1.47	-0.09	0.84	0.96	-0.12	1.01	0.93	0.08	4.83	2.92	3.54	1.7	2.3	33.67	57.96	96.11	12.64
सोनीपत	1.90	3.30	2.82	0.85	0.43	0.49	2.65	3.12	-0.47	1.07	0.81	0.26	0.72	0.68	0.04	6.94	2.81	1.89	2.7	2.2	1.10	100.23	59.52	7.94
रोहतक	2.39	1.20	1.60	1.77	0.67	0.83	2.77	2.29	0.48	0.84	1.00	-0.16	0.80	0.76	0.05	4.61	1.40	1.34	3.9	1.5	24.44	10.39	38.28	6.04
झज्जर	1.89	2.99	2.61	0.74	0.52	0.55	2.41	2.17	0.25	1.40	1.42	-0.02	0.62	0.60	0.02	4.18	2.42	1.07	1.4	1.6	35.20	52.15	57.63	8.65
रेवाड़ी	2.73	3.15	3.00	0.63	0.41	0.44	1.70	1.63	0.07	1.68	1.47	0.21	0.60	0.68	-0.08	3.69	3.65	1.32	2.0	1.3	35.19	88.69	45.69	9.76
गुडगाँव	1.73	3.17	2.68	0.60	0.52	0.53	0.31	0.77	-0.45	1.51	1.56	-0.05	0.88	0.80	0.08	2.95	14.20	8.30	5.3	4.4	-42.60	72.32	95.36	12.46
फरीदाबाद	0.74	1.09	0.97	0.90	1.03	1.01	0.98	1.06	-0.08	1.34	1.55	-0.21	0.86	0.75	0.10	6.44	8.77	5.61	4.2	4.7	3.75	22.88	60.49	6.83
हरियाणा उप-क्षेत्र	**1.64**	**2.32**	**2.08**	**0.87**	**0.67**	**0.70**	**1.22**	**1.43**	**-0.21**	**1.31**	**1.36**	**-0.05**	**0.83**	**0.77**	**0.07**	**33.65**	**36.18**	**23.06**	**21.1**	**18.0**	**7.30**	**54.43**	**73.62**	**10.60**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**0.07**	**0.10**	**0.09**	**0.90**	**1.31**	**1.25**	**0.11**	**0.12**	**-0.01**	**0.73**	**0.73**	**0.00**	**1.25**	**1.28**	**-0.03**	**5.31**	**36.01**	**62.09**	**7.1**	**62.2**	**-1.94**	**34.88**	**31.76**	**7.79**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**3.16**	**2.89**	**2.97**	**0.68**	**0.41**	**0.45**	**3.02**	**2.43**	**0.59**	**1.11**	**1.11**	**0.00**	**0.65**	**0.68**	**-0.03**	**12.41**	**4.58**	**2.68**	**9.0**	**3.5**	**23.42**	**26.40**	**19.86**	**4.48**
एनसीआर	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**															**9.87**	**39.65**	**38.93**	**7.83**

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन

अनुलग्नक 8. 2: 2005-06 में एनसीआर में जीडीपी स्थिर मूल्यों (1999-00) के प्राथमिक क्षेत्र का एलक्यू और 2000-01 से 2005-06 तक एलक्यू में परिवर्तन

क्रम संख्या	प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ	कृषि			वानिकी और लॉगिंग			मत्स्य पालन			खनन और उत्खनन			कुल		
	जिला/उपक्षेत्र	**LQ2005-06**	**LQ2000-01**	परिवर्तन	**LQ2005-06**	**LQ2000-01**	परिवर्तन	**LQ2005-06**	**LQ2000-01**	परिवर्तन	**LQ2005-06**	**LQ2000-01**	परिवर्तन	**LQ2005-06**	**LQ2000-01**	परिवर्तन
1	फरीदाबाद	0.75	0.92	-0.17	0.85	7.92	-7.08	2.00	1.84	0.16	8.48	6.79	1.68	0.98	1.06	-0.08
2	गुडगाँव	0.32	0.76	-0.43	0.23	1.07	-0.83	0.70	1.49	-0.79	0.00	0.91	-0.91	0.31	0.77	-0.45
3	झज्जर	2.47	2.20	0.27	2.09	0.06	2.03	6.47	3.71	2.76	0.02	0.05	-0.03	2.41	2.17	0.25
4	पानीपत	1.42	1.50	-0.08	1.15	0.18	0.97	2.12	2.13	-0.01	0.36	0.16	0.21	1.38	1.47	-0.09
5	रेवाड़ी	1.74	1.65	0.08	1.80	0.08	1.72	2.36	1.91	0.45	0.14	0.07	0.07	1.70	1.63	0.07
6	रोहतक	2.84	2.33	0.51	2.64	0.02	2.62	6.20	4.42	1.78	0.01	0.01	0.00	2.77	2.29	0.48
7	सोनीपत	2.69	3.17	-0.48	2.70	0.95	1.75	5.81	4.62	1.19	0.95	0.81	0.14	2.65	3.12	-0.47
हरियाणा उप-क्षेत्र		**1.19**	**1.40**	**-0.22**	**1.11**	**2.57**	**-1.46**	**2.50**	**2.36**	**0.13**	**2.16**	**2.20**	**-0.04**	**1.22**	**1.43**	**-0.21**
1	अलवर	3.07	2.46	0.60	3.80	1.31	2.50	0.52	0.00	0.51	1.12	1.12	0.00	3.02	2.43	0.59
राजस्थान उप-क्षेत्र		**3.07**	**2.46**	**0.60**	**3.80**	**1.31**	**2.50**	**0.52**	**0.00**	**0.51**	**1.12**	**1.12**	**0.00**	**3.02**	**2.43**	**0.59**
1	मेरठ	3.37	2.53	0.84	3.42	1.98	1.44	0.51	0.33	0.18	1.42	1.70	-0.28	3.31	2.51	0.79
2	बागपत	4.27	4.24	0.03	3.66	6.37	-2.71	0.41	0.06	0.35	5.69	5.46	0.22	4.28	4.22	0.06
3	गाजियाबाद	2.07	1.55	0.51	3.13	2.06	1.07	2.20	1.51	0.69	1.96	1.77	0.19	2.09	1.58	0.51
4	गौतमबुद्धनगर	1.03	1.36	-0.32	1.35	1.77	-0.42	0.13	0.04	0.09	0.97	1.52	-0.55	1.04	1.35	-0.32
5	बुलंदशहर	3.96	3.73	0.23	3.19	1.51	1.68	0.86	0.51	0.35	1.71	1.29	0.42	3.86	3.63	0.23
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र		**2.64**	**2.41**	**0.22**	**2.83**	**2.24**	**0.59**	**0.96**	**0.61**	**0.34**	**1.85**	**1.92**	**-0.08**	**2.61**	**2.39**	**0.22**
एनसीटी		**0.11**	**0.12**	**-0.01**	**0.02**	**0.07**	**-0.05**	**0.22**	**0.60**	**-0.38**	**0.03**	**0.06**	**-0.03**	**0.11**	**0.12**	**-0.01**

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल पर अध्ययन

अनुलग्नक 8. 3: 2005-06 में एनसीआर में जीडीपी स्थिर कीमतों (1999-00) के द्वितीयक क्षेत्र का एलक्यू और 2000-01 से 2005-06 तक एलक्यू में परिवर्तन

क्रम संख्या	माध्यमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ	उत्पादन						बिजली, गैस और जल आपूर्ति			निर्माण			कुल		
	जिला/उपक्षेत्र	पंजीकृत			अपंजीकृत									कुल		
		LQ2005-06	**LQ2000-01**	परिवर्तन	**LQ2005-06**	**LQ2000-01**	परिवर्तन	**LQ2005-06**	**LQ2000-01**	परिवर्तन	**LQ2005-06**	**LQ2000-01**	परिवर्तन	**LQ2005-06**	**LQ2000-01**	परिवर्तन
1	फरीदाबाद	0.30	2.41	-2.11	0.75	0.74	0.01	0.97	0.69	0.28	0.92	0.87	0.05	1.34	1.55	-0.21
2	गुडगाँव	0.46	2.76	-2.29	0.27	0.46	-0.20	0.36	0.32	0.04	0.43	0.64	-0.21	1.51	1.56	-0.05
3	झज्जर	0.25	1.86	-1.61	0.99	0.99	0.00	1.43	0.48	0.96	1.40	1.22	0.18	1.40	1.42	-0.02
4	पानीपत	0.08	0.60	-0.52	1.12	1.31	-0.19	0.75	2.40	-1.66	1.17	0.91	0.27	0.84	0.96	-0.12
5	रेवाड़ी	0.42	2.18	-1.76	0.88	0.94	-0.06	0.32	0.38	-0.06	1.03	0.90	0.13	1.68	1.47	0.21
6	रोहतक	0.01	0.84	-0.83	1.29	1.09	0.20	0.76	0.97	-0.21	1.79	1.23	0.56	0.84	1.00	-0.16
7	सोनीपत	0.15	0.56	-0.42	1.00	0.97	0.02	0.83	1.04	-0.21	1.41	1.08	0.33	1.07	0.81	0.26
हरियाणा उप-क्षेत्र		**0.30**	**1.96**	**-1.66**	**0.71**	**0.80**	**-0.09**	**0.69**	**0.79**	**-0.10**	**0.92**	**0.88**	**0.05**	**1.31**	**1.36**	**-0.05**
1	अलवर	0.21	1.45	-1.25	0.57	0.54	0.03	2.26	2.29	-0.03	0.95	0.65	0.29	1.11	1.11	0.00
राजस्थान उप-क्षेत्र		**0.21**	**1.45**	**-1.25**	**0.57**	**0.54**	**0.03**	**2.26**	**2.29**	**-0.03**	**0.95**	**0.65**	**0.29**	**1.11**	**1.11**	**0.00**
1	मेरठ	0.10	1.18	-1.08	1.04	0.82	0.23	1.62	1.54	0.08	0.96	1.01	-0.05	0.88	1.08	-0.20
2	बागपत	0.04	0.15	-0.11	0.83	0.64	0.20	1.93	1.68	0.24	0.52	0.48	0.04	0.56	0.44	0.11
3	गाजियाबाद	0.24	1.86	-1.62	1.09	0.93	0.16	2.05	2.05	-0.01	0.89	0.89	0.00	1.28	1.43	-0.15
4	गौतमबुद्ध नगर	0.67	3.54	-2.87	0.48	0.56	-0.07	0.95	1.08	-0.13	0.23	0.25	-0.02	2.13	1.91	0.22
5	बुलंदशहर	0.07	0.37	-0.31	1.46	1.37	0.09	2.29	2.06	0.23	0.65	0.65	0.00	0.82	0.78	0.03
यूपी उप-क्षेत्र		**0.26**	**1.59**	**-1.33**	**0.99**	**0.89**	**0.09**	**1.73**	**1.71**	**0.02**	**0.68**	**0.71**	**-0.02**	**1.25**	**1.23**	**0.02**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र		**0.03**	**0.27**	**-0.24**	**1.20**	**1.18**	**0.02**	**0.80**	**0.70**	**0.09**	**1.17**	**1.21**	**-0.04**	**0.73**	**0.73**	**0.00**

स्रोत: आर्थिक प्रोफाइल पर अध्ययन

अनुलग्नक 8. 4: 2005-06 में एनसीआर में जीडीपी स्थिर कीमतों (1999-00) के तृतीयक क्षेत्र का एलक्यू और 2000-01 से 2005-06 तक एलक्यू में बदलाव

क्रम संख्या	जिला/उपक्षेत्र	व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट			रेलवे			यातायात			भंडारण			संचार			बैंकिंग एवं बीमा			रियल, डवेल बी.सेर और लीगल का स्वामित्व			सार्वजनिक प्रशासन			अन्य सेवाएं			कुल		
		LQ2005-06	LQ2000-01	Change	LQ2005-06	LQ2000-01	Change	LQ2005-06	LQ2000-01	Change	LQ2005-06	LQ2000-01	Change	LQ2005-06	LQ2000-01	Change	LQ2005-06	LQ2000-01	Change	LQ2005-06	LQ2000-01	Change	LQ2005-06	LQ2000-01	Change	LQ2005-06	LQ2000-01	Change	LQ2005-06	LQ2000-01	Change
1	फरीदाबाद	1.65	1.18	0.47	0.81	0.83	-0.03	1.16	0.80	0.37	1.27	1.06	0.22	0.49	0.40	0.09	0.33	0.35	-0.02	0.97	0.68	0.29	0.37	0.36	0.00	0.70	0.67	0.02	0.86	0.75	0.10
2	गुडगाँव	1.12	1.13	-0.01	0.30	0.39	-0.09	0.48	0.74	-0.26	0.16	0.62	-0.46	0.26	0.20	0.06	0.05	0.31	-0.26	2.18	1.49	0.69	0.20	0.32	-0.11	0.25	0.43	-0.18	0.88	0.80	0.08
3	झज्जर	0.39	0.32	0.07	1.40	1.58	-0.17	1.86	1.37	0.49	0.34	0.41	-0.07	0.43	0.33	0.10	0.25	0.31	-0.06	0.45	0.57	-0.12	0.81	0.87	-0.05	1.11	1.13	-0.02	0.62	0.60	0.02
4	पानीपत	2.45	1.98	0.47	0.98	1.29	-0.31	0.71	0.70	0.01	1.18	2.13	-0.95	0.30	0.27	0.03	0.22	0.30	-0.08	0.25	0.37	-0.12	0.39	0.44	-0.05	0.50	0.55	-0.05	1.01	0.93	0.08
5	रेवाड़ी	0.84	0.94	-0.10	2.23	2.67	-0.45	0.80	0.71	0.09	1.23	0.52	0.71	0.47	0.39	0.08	0.21	0.28	-0.07	0.31	0.43	-0.12	0.66	0.76	-0.11	0.76	0.78	-0.02	0.60	0.68	-0.08
6	रोहतक	0.35	0.42	-0.07	3.12	2.97	0.15	1.88	1.28	0.60	1.99	1.15	0.84	0.77	0.51	0.27	0.54	0.53	0.02	0.64	0.61	0.03	1.45	1.29	0.16	1.37	1.35	0.02	0.80	0.76	0.05
7	सोनीपत	0.69	0.60	0.09	1.38	1.52	-0.14	1.61	1.25	0.36	1.51	1.30	0.21	0.54	0.41	0.13	0.35	0.35	0.00	0.48	0.55	-0.08	0.87	0.89	-0.02	1.10	1.05	0.05	0.72	0.68	0.04
हरियाणा उप-क्षेत्र		**1.15**	**1.07**	**0.09**	**1.00**	**1.17**	**-0.17**	**0.98**	**0.88**	**0.09**	**0.89**	**0.99**	**-0.10**	**0.40**	**0.33**	**0.08**	**0.22**	**0.34**	**-0.12**	**1.14**	**0.85**	**0.29**	**0.48**	**0.54**	**-0.06**	**0.63**	**0.71**	**-0.08**	**0.83**	**0.77**	**0.07**
1	अलवर	0.98	1.00	-0.03	1.07	1.02	0.05	0.45	0.42	0.04	1.58	1.32	0.27	0.50	0.40	0.10	0.25	0.20	0.05	0.38	0.53	-0.14	0.82	0.81	0.01	0.86	0.91	-0.06	0.65	0.68	-0.03
राजस्थान उप-क्षेत्र		**0.98**	**1.00**	**-0.03**	**1.07**	**1.02**	**0.05**	**0.45**	**0.42**	**0.04**	**1.58**	**1.32**	**0.27**	**0.50**	**0.40**	**0.10**	**0.25**	**0.20**	**0.05**	**0.38**	**0.53**	**-0.14**	**0.82**	**0.81**	**0.01**	**0.86**	**0.91**	**-0.06**	**0.65**	**0.68**	**-0.03**
1.	मेरठ	0.62	0.66	-0.03	0.68	0.67	0.01	1.04	0.92	0.13	1.40	1.07	0.33	0.57	0.44	0.13	0.45	0.34	0.12	0.53	0.63	-0.10	1.19	1.14	0.05	1.18	0.96	0.22	0.71	0.68	0.03
2	बागपत	0.66	0.74	-0.08	0.82	0.75	0.07	0.92	0.74	0.18	0.90	0.81	0.09	0.69	0.49	0.20	0.55	0.38	0.17	0.39	0.47	-0.09	1.30	0.79	0.51	1.07	0.79	0.28	0.70	0.63	0.07
3	गाजियाबाद	0.60	0.63	-0.03	2.10	2.19	-0.09	1.12	1.03	0.09	2.40	2.36	0.04	0.65	0.53	0.12	0.41	0.32	0.09	0.71	0.80	-0.09	0.59	0.70	-0.11	1.14	1.04	0.10	0.72	0.71	0.01
4	गौतमबुद्ध नगर	0.88	0.85	0.02	0.98	1.17	-0.19	0.40	0.41	-0.01	0.14	0.15	-0.01	0.30	0.28	0.02	0.19	0.17	0.02	0.34	0.44	-0.10	0.27	0.28	-0.01	0.54	0.70	-0.16	0.51	0.54	-0.03
5.	बुलंदशहर	0.68	0.74	-0.06	1.04	0.97	0.07	1.13	0.88	0.25	1.43	1.31	0.11	0.52	0.38	0.14	0.31	0.22	0.09	0.44	0.56	-0.12	0.78	0.67	0.11	1.04	0.64	0.41	0.65	0.60	0.05
यूपी उप-क्षेत्र		**0.69**	**0.71**	**-0.02**	**1.23**	**1.26**	**-0.03**	**0.92**	**0.82**	**0.10**	**1.36**	**1.27**	**0.09**	**0.53**	**0.42**	**0.11**	**0.36**	**0.28**	**0.08**	**0.51**	**0.61**	**-0.11**	**0.74**	**0.72**	**0.02**	**0.99**	**0.85**	**0.14**	**0.65**	**0.64**	**0.01**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र		**1.03**	**1.08**	**-0.05**	**0.91**	**0.82**	**0.09**	**1.09**	**1.18**	**-0.09**	**0.88**	**0.87**	**0.01**	**1.55**	**1.60**	**-0.05**	**1.74**	**1.67**	**0.07**	**1.16**	**1.27**	**-0.11**	**1.40**	**1.34**	**0.06**	**1.22**	**1.20**	**0.02**	**1.25**	**1.28**	**-0.03**

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल पर अध्ययन

अनुलग्नक 8.5: एनसीआर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्‌यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों का एल. क्यू. 2005

जिला/उपक्षेत्र	आमतौर पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या								
	कृषि			गैर कृषि			सभी		
	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल
मेरठ	8.52	8.00	8.39	2.50	1.07	1.52	4.14	1.42	2.44
बागपत	8.49	6.73	8.07	4.18	2.30	2.89	5.36	2.52	3.58
गाज़ियाबाद	0.39	0.81	0.49	1.95	0.91	1.24	1.53	0.90	1.14
गौतम बौद्ध नगर	1.23	0.21	0.99	0.99	1.05	1.03	1.06	1.01	1.03
बुलंदशहर	4.73	6.14	5.07	4.62	1.47	2.46	4.65	1.71	2.81
यूपी उप-क्षेत्र	**3.87**	**3.58**	**3.80**	**2.32**	**1.17**	**1.54**	**2.74**	**1.30**	**1.84**
पानीपत	0.39	1.57	0.67	2.56	2.78	2.71	1.97	2.71	2.44
सोनीपत	0.89	1.98	1.15	2.61	4.47	3.88	2.14	4.34	3.52
रोहतक	2.57	1.23	2.25	2.75	1.60	1.96	2.70	1.58	2.00
झज्जर	0.91	1.20	0.98	2.59	4.07	3.61	2.13	3.93	3.26
रेवाड़ी	1.76	1.37	1.66	3.58	4.28	4.06	3.09	4.14	3.74
गुडगाँव	1.50	1.19	1.43	2.13	4.32	3.63	1.96	4.16	3.34
फरीदाबाद	0.54	1.43	0.76	0.94	1.43	1.28	0.83	1.43	1.21
हरियाणा उप-क्षेत्र	**1.10**	**1.42**	**1.17**	**2.13**	**3.13**	**2.82**	**1.85**	**3.04**	**2.60**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**0.01**	**0.04**	**0.02**	**0.10**	**0.14**	**0.13**	**0.08**	**0.13**	**0.11**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**2.99**	**2.32**	**2.83**	**3.79**	**3.87**	**3.85**	**3.57**	**3.79**	**3.71**
एनसीआर	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल पर अध्ययन

अनुलग्नक 8.6: एनसीआर शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों का एलक्यू-2005

जिला/उपक्षेत्र	कृषि			गैर कृषि			सभी		
	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल
मेरठ	5.74	2.94	4.17	1.71	0.50	0.67	1.80	0.51	0.69
बागपत	4.39	1.93	3.01	1.44	0.27	0.43	1.51	0.28	0.45
गाज़ियाबाद	1.93	1.44	1.66	2.15	0.77	0.97	2.14	0.78	0.97
गौतम बौद्ध नगर	5.24	0.75	2.72	0.61	1.04	0.98	0.72	1.04	0.99
बुलंदशहर	1.11	0.59	0.82	2.71	0.28	0.61	2.68	0.28	0.62
यूपी उप-क्षेत्र	**3.95**	**1.54**	**2.60**	**1.60**	**0.68**	**0.81**	**1.65**	**0.69**	**0.82**
पानीपत	0.56	1.23	0.93	0.94	0.65	0.69	0.93	0.66	0.70
सोनीपत	0.97	1.61	1.33	0.83	0.40	0.46	0.83	0.40	0.47
रोहतक	2.90	3.43	3.20	1.71	0.62	0.77	1.73	0.63	0.79
झज्जर	0.40	0.47	0.44	0.73	0.49	0.52	0.72	0.49	0.52
रेवाड़ी	0.47	1.34	0.96	0.62	0.38	0.41	0.61	0.38	0.42
गुडगाँव	0.20	0.53	0.39	0.59	0.49	0.50	0.58	0.49	0.50
फरीदाबाद	0.72	1.89	1.38	0.88	0.96	0.95	0.88	0.97	0.96
हरियाणा उप-क्षेत्र	**0.75**	**1.41**	**1.12**	**0.85**	**0.63**	**0.66**	**0.85**	**0.63**	**0.66**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**0.19**	**0.74**	**0.50**	**0.89**	**1.24**	**1.19**	**0.88**	**1.24**	**1.19**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**1.42**	**0.63**	**0.97**	**0.64**	**0.38**	**0.42**	**0.66**	**0.39**	**0.42**
एनसीआर	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल पर अध्ययन

अनुलग्नक 8. 7: एनसीआर में उद्यमों के प्रकार के अनुसार व्यक्तियों का एलक्यू-2005

जिला/उपक्षेत्र	कृषि			गैर कृषि			सभी		
	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल	ओएई	संस्थान	कुल
मेरठ	8.16	6.11	7.53	1.94	0.57	0.80	2.64	0.64	1.00
बागपत	7.96	4.93	7.04	2.25	0.53	0.82	2.89	0.58	1.00
गाज़ियाबाद	0.58	1.05	0.73	2.09	0.79	1.01	1.92	0.79	1.00
गौतम बौद्ध नगर	1.75	0.41	1.34	0.72	1.04	0.99	0.84	1.04	1.00
बुलंदशहर	4.26	4.06	4.20	3.27	0.43	0.90	3.38	0.47	1.00
यूपी उप-क्षेत्र	**3.88**	**2.82**	**3.55**	**1.81**	**0.74**	**0.92**	**2.04**	**0.77**	**1.00**
पानीपत	0.41	1.44	0.73	1.42	0.93	1.01	1.30	0.93	1.00
सोनीपत	0.90	1.84	1.19	1.35	0.92	0.99	1.30	0.93	1.00
रोहतक	2.61	2.05	2.44	2.01	0.74	0.96	2.08	0.76	1.00
झज्जर	0.85	0.92	0.87	1.28	0.95	1.00	1.23	0.95	1.00
रेवाड़ी	1.59	1.36	1.52	1.49	0.88	0.98	1.50	0.89	1.00
गुडगाँव	1.33	0.94	1.21	1.04	0.98	0.99	1.08	0.98	1.00
फरीदाबाद	0.57	1.60	0.88	0.90	1.02	1.00	0.86	1.03	1.00
हरियाणा उप-क्षेत्र	**1.05**	**1.42**	**1.16**	**1.23**	**0.95**	**1.00**	**1.21**	**0.95**	**1.00**
एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र	**0.04**	**0.30**	**0.12**	**0.66**	**1.10**	**1.03**	**0.59**	**1.09**	**1.00**
राजस्थान उप-क्षेत्र	**2.78**	**1.68**	**2.45**	**1.57**	**0.83**	**0.96**	**1.71**	**0.84**	**1.00**
एनसीआर	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

स्रोत: एनसीआर के आर्थिक प्रोफाइल पर अध्ययन